



# भारत की भाषा-समस्या

रामविलास शर्मा



राजकमल प्रकाशन

नयी दिल्ली पटना २२२

भारत सरकार द्वारा अपेक्षाकृत सस्ते मूल्यो पर उपलब्ध कराये गये कागज पर मुद्रित।

## प्रथम संस्करण की भूमिका

भाषा की समस्या मूलतः जातीय समस्या का ही एक अंग है। इस देश में अनेक भाषाएँ बोलनेवाली जातियाँ रहती हैं। इनसे मिलकर भारत राष्ट्र बना है। इस राष्ट्र में जातियों की सम्पर्क भाषा क्या हो, एक ही सम्पर्क भाषा हो या अनेक हो—यह समस्या का एक पक्ष है। कुछ लोग इस देश को उपमहाद्वीप कहते हैं, उनका मत है कि राष्ट्रीयता का भाव अंग्रेजों का विरोध करने से पैदा हुआ, वास्तव में यह देश राष्ट्र नहीं है क्योंकि यहाँ एक भाषा के बदले अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। इस तरह राष्ट्रभाषा की समस्या को विवेचने करते हुए राष्ट्र की व्याख्या करना आवश्यक हो जाता है, विशेषकर भारतीय राष्ट्रीयता के ऐतिहासिक विकास पर कुछ कहना आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रभाषा की समस्या विशुद्ध भाषा-विज्ञान की समस्या न होकर बहुजातीय राष्ट्र के गठन और विकास की ऐतिहासिक-राजनीतिक समस्या बन जाती है।

भारत की जातियों में हिन्दी-भाषी जाति मध्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। कुछ लोग इस जाति के अस्तित्व से ही इन्कार करते हैं। वे कहते हैं कि उत्तर भारत के पुराने जनपदों में रहनेवाले लोग स्वतन्त्र जातियाँ हैं; बुन्देलखण्ड, प्रवर्ध, ब्रजभाषा आदि हिन्दी की बोलियाँ नहीं हैं, वे हिन्दी से स्वतन्त्र भाषाएँ हैं। हिन्दी क्षेत्र में भाषा और बोलियों की यह समस्या हिन्दी-भाषी जाति के विकास की समस्या बन जाती है। इस विकास को मजबूत बिना भाषा और बोली के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। भाषा-समस्या का यह दूसरा पक्ष है।

इसी हिन्दी प्रदेश में बोलचाल की भाषा के आधार पर साहित्यिक भाषा के दो रूप—हिन्दी और उर्दू—विकसित हुए। उर्दू मुसलमानों की भाषा है या हिन्दुओं और मुसलमानों के मिलने में बनी, भारत में जो मुसलमान आये वे एक क़ौम के थे या कई क़ौमों के, उनकी एक भाषा थी या वे कई भाषाएँ बोलते थे, क्या हिन्दी का विकास हिन्दू राष्ट्रवाद के अम्युत्यन के कारण हुआ, क्या मुसलमानों की प्रलय क़ौम है, उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बनाया जा ~~नहीं~~ नहीं—

ये सभी प्रश्न हिन्दी-भाषी जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ जुड़े हुए हैं। भाषा-समस्या का यह तीव्रता पक्ष हुआ।

भारतीय जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने बहुजातीय राष्ट्र की विशेषताएँ पहचानें, इस राष्ट्र में हिन्दी-भाषी जाति की भूमिका पहचानें। इस दृष्टि से भारत की भाषा-समस्या का व्यापक महत्व है, इसमें किसी को सन्देह न होना चाहिए।

इस पुस्तक में पिछले तीस वर्षों में भाषा-समस्या पर लिखे हुए मेरे अधिकांश निबन्धों का संग्रह है। इससे पाठक देख सकेंगे कि इस अवधि में भाषा-समस्या के कौन से पक्ष, किस समय एक हिन्दी लेखक के मन को आन्दोलित करते रहे। इन वर्षों में मेरे विचार बदले हैं। लेखों में समस्या के विभिन्न पक्षों पर, अलग-अलग समय पर कम-ब्यादा जोर दिया गया है किन्तु मेरी तीन बुनियादी मान्यताओं में कोई अन्तर नहीं आया। पहली यह कि अंग्रेजी भारत की सभी भाषाओं पर साम्राज्यवादियों द्वारा लादी हुई भाषा है और उसका प्रभुत्व जल्दी-से-जल्दी खत्म करना चाहिए। दूसरी यह कि हिन्दी और उर्दू मूलतः एक ही भाषा हैं और आगे चलकर दोनों घुल-मिलकर एक होगी, बोल-चाल की भाषा के आधार पर एक ही साहित्यिक भाषा का विकास होगा। तीसरी यह कि बुन्देलखण्ड, प्रज, अवधी आदि हिन्दी की बोलियाँ हैं, स्वतन्त्र भाषाएँ नहीं हैं।

भारत की बहुजातीय राष्ट्रियता के बारे में, हिन्दी-भाषी जाति के विकास के बारे में, हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता और हिन्दी की जनपदीय बोलियों के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेरी मान्यताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।

भारतीय संविधान के अनुसार सन् '६५ में केन्द्र के राजकीय वाम-काज में अंग्रेजी का व्यवहार समाप्त हो जाना चाहिए था। स्वभावतः इस वर्ष मैंने जो लेख लिखे हैं उनका सम्बन्ध अंग्रेजी-हिन्दी अथवा अंग्रेजी बनाम भारतीय भाषाओं वाले विवाद से अधिक है। मेरे कुछ मित्रों ने मुझे याद दिलाया है कि सन् '४६ में मैं अनिवार्य राजभाषा का विरोधी था; अब हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए अन्य राष्ट्रवादियों की तरह दूसरों पर जोर-जबर्दस्ती से हिन्दी लादने का आन्दोलन कर रहा हूँ।

इन मित्रों की सेवा में निवेदन है कि जैसे मैं अनिवार्य राजभाषा का विरोधी सन् '४६ में था, वैसे ही आज भी हूँ। मैं किसी भी भाषा पर हिन्दी लादने का विरोध करता हूँ। मैं हिन्दी को सम्पर्क-भाषा बनाने के पक्ष हूँ, दूसरी भाषाओं के क्षेत्र में राजकीय और शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों में हिन्दी के व्यवहार के पक्ष में नहीं हूँ। सम्पर्क-भाषा को भी कुछ लोग हिन्दी का लादा जाना सम्मते हैं। मैं किसी भी प्रदेश की इच्छा के विरुद्ध उसके लिए हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाने का भी समर्थन नहीं करता। लेकिन मैं यह भी कहता हूँ, अंग्रेजी-प्रेमियों को हिन्दीभाषी प्रदेशों पर अंग्रेजी लादने का कोई अधिकार

नहीं है। अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के नेता नहीं चाहते कि केन्द्र में अंग्रेजी की जगह हिन्दी का चलन हो, उनकी इच्छा। वे केन्द्र में हिन्दी के अलावा अन्य भाषाओं का चलन कर सकते हैं। इसमें उन्हें अराजकता दिखायी देती हो तो अंग्रेजी ही चलायें लेकिन वे हिन्दीभाषियों को बाध्य नहीं कर सकते कि लोकसभा, राज्यसभा तथा केन्द्रीय राजकाज में वे भी अंग्रेजी का व्यवहार करें।

हिन्दी-भाषी जाति भारत की सबसे बड़ी जाति है। वह केन्द्र में अपने प्रतिनिधियों को हिन्दी लिखने-बोलने के लिए बाध्य करके अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म कर सकती है। १४ मार्च, सन् '६५ के 'धर्मयुग' में इस घाशय का मुभाव देखकर कम्युनिस्ट नेता श्री योगीन्द्र शर्मा ने लिखा था कि यह गृहयुद्ध की सलकार है।

मई, सन् '५८ के 'समालोचक' में मैंने लिखा था, "यदि हिन्दी-भाषी जनता संगठित हो, यदि वह अपने प्रदेश में हिन्दी को पूर्ण रूप में राजकाज की भाषा बनाये तो यह असम्भव है कि यह विशाल प्रदेश और बहुसंख्यक जनता सारे देश को अपने साथ खींचकर न ले चल सके।"

६ जनवरी, सन् '६३ के 'धर्मयुग' में मैंने लिखा था, "यदि समस्त हिन्दी-भाषी प्रदेश में शिक्षा-संस्थाओं, न्यायालयों, राजकीय कार्यों में हर स्तर पर हिन्दी का व्यवहार हान लगे, यदि विधान परिषदों के सदस्य प्रतिज्ञा करें कि वे अपना सार्वजनिक कार्य हिन्दी में ही करेंगे, यदि लोकसभा के सदस्य तय कर लें कि वे राजभाषा के रूप में हिन्दी का ही व्यवहार करेंगे, तो क्या इसमें किसी को सन्देह हो सकता है कि ममूचे राष्ट्र का वातावरण बदल जायेगा और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाते जरा भी देर न लगेगी।"

योगीन्द्र शर्माजी नोट कर लें, जिसे वह गृहयुद्ध की ललक र कहते हैं, वह बात काफी पुरानी है।

इस सण्ड में काफी लेख ऐसे हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और मार्क्सवादी लेखकों में घायमी बहस के लिए लिखे गये थे। सन् '४६ में जो लेख 'कम्युनिस्ट' पत्रिका में छपा था, उसके ऊपर लिखा था, 'बहस के लिए लेख'। मितम्बर, '६४ के 'न्यू एज' (मासिक) में हिन्दी और राष्ट्रीय एकता पर मेरा जो लेख छपा था, उस पर भी लिखा था, 'बहस के लिए लेख'। यह चताना इसलिए आवश्यक है कि पाठकों को यह भ्रम न हो कि मैंने अपने लेखों में जो बातें कही हैं, वे कम्युनिस्ट पार्टी की स्वीकृत मान्यताएँ हैं।

यद्यपि मैंने हिन्दी-उर्दू समस्या तथा हिन्दी क्षेत्र में भाषा और बोलियों के प्रश्न पर अनेक बार और काफी विस्तार में लिखा है, किन्तु मेरी स्थापनाओं का विरोध करनेवालों ने कभी भी मेरे तर्कों का खण्डन नहीं किया। इसके बदले वे मुँहजबानी मेरे बारे में अफवाहें फैलाते रहे हैं। इधर जव से अंग्रेजी का लेकर संपर्क तब हुआ है, वे उन अफवाहों को छापे के पृष्ठों में प्रकाशित भी करन लगे हैं। इन मित्रों ने निवेदन है कि पत्रवे देन में भाषा समस्या का समाधान नहीं

हा सकता है। तब का उल्टा सच में ही गीति।

भाषा-समस्या का घनिष्ठ सम्बन्ध राष्ट्रीय एकता से है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। जिस राष्ट्र में जितनी ही धातुगिक दृढ़ता होगी उतना ही वह हर तरह का तनाव और क्षोभ सह लेने की स्थिति में होगा। जिस देश की जोर और जनता में दृढ़ भाईचारा होता है, जिस जोर में नावकों और सैनिकों के बीच दृढ़ भाईचारा होता है जिस देश की राज्यसभा के योग्य मण्डित जनता की शक्ति होती है वह देश अक्षय्य होता है। भाषा-समस्या का सही समाधान राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करके उस अक्षय्य बना सकता है, भाषा-समस्या का सही समाधान लादा में सम्मिलित वेदा करके राष्ट्रीय एकता को कमजोर कर सकता है। इस तरह का सम्मिलित हर अवस्था में विघटनकारी होता है; दीर्घकालीन युद्ध की परिस्थितियों में वह विवेक रूप में अनुपयोगी साबित हो सकता है। हमारी राष्ट्रीय एकता हर परिस्थिति में हर तरह का तनाव सहन करके घट्ट बनी रहे, हमें सही प्रयत्न करना चाहिए।

इस तरह के कुछ लेख अंग्रेजी में प्रकाशित हुए थे; उनका यही अनुवाद दिया गया है। 'भाषा और राष्ट्रिय में पाकिस्तान' मसलत की एक बेहतर पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, उसका भी अनुवाद दिया गया है। अधिकांश लेख हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं और यही पत्रों वार संचालित किये गये हैं। कुछ लेख मेरे अन्य निबन्ध-संग्रहों में भी छुड़े हैं। अन्तिम तीन लेख इस संग्रह में पहली बार प्रकाशित हो रहे हैं। कुछ लेखों के अनावश्यक अंग काट दिए गये हैं, किन्तु उनकी बारी मुख्य स्थापना न बदले, मेरी दृष्टि में आज वह सही हो या उपन, इसका मैंने ध्यान रखा है। सन् '४६ जाने निबन्ध में मैंने अनिवार्य केन्द्रीय राजभाषा का विरोध किया था और कहा था कि हिन्दी को केन्द्रीय राजभाषा बनाने में बड़े पूँजीपतियों को लाभ होगा। यह स्थापना उस निबन्ध में रहने दी है यद्यपि बड़े पूँजीपतियों की भूमिका और केन्द्रीय राजभाषा के बारे में मेरे विचार बने नहीं हैं। मैं केन्द्रीय राजभाषा को अनिवार्य बना देने, दोनों दूम्हों की इच्छा के विरुद्ध उन पर लागने का विरोध हूँ किन्तु इस बात को आवश्यक और वाछनीय समझता हूँ कि भारत के विभिन्न दल हिन्दी को केन्द्रीय राजभाषा बनाने के लिए प्रयत्न करें, इन दलों के नेता ही जनमत के प्रतिनिधि बनते हैं, वे अपनी पार्टियों के केन्द्रीय दलरों में अंग्रेजी निकालें तो उन्हें अल्प भारतीय सम्पर्क के लिए पहले अपनी पार्टी में, फिर सामान्य-व्यवस्था में हिन्दी के व्यवहार की उपयोगिता दिखायी देने लगे।

भारत की राजनीतिक पार्टियों में मेरा सम्बन्ध कम्युनिस्ट पार्टी से रहा है। मैंने यह आवश्यक समझा कि खुद कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर अंग्रेजी का व्यवहार खत्म करने के लिए आन्दोलन किया जाय। इस आशय में कुछ बातें मैंने मित्रम्बर, सन् '६४ की 'न्यू एज' पत्रिका में लिखी थीं। यह पत्रिका भारतीय कम्युनिस्ट

पार्टी का मुखपत्र है। 'भाषा की समस्या—प्रति आवश्यक' और 'भाषा की समस्या और राष्ट्रीय विघटन' लेख 'जनशक्ति' में प्रकाशित हुए। 'जनशक्ति' भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार शाखा का मुखपत्र है। इसमें श्री योगीन्द्र शर्मा ने मेरी मान्यताओं का खण्डन करते हुए दो लेख लिखे। 'भाषा की समस्या और मजदूर वर्ग' तथा 'भारत की राजभाषा अंग्रेजी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा' उनके लेखों के प्रत्युत्तर हैं। ये भी 'जनशक्ति' में प्रकाशित हुए थे।

मैं 'जनशक्ति' के सम्पादक का कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख भारतीय नेता के विरुद्ध मेरे तीव्र खण्डनात्मक लेख छापे।

मेरे अनेक भाषा सम्बन्धी लेख 'धर्मयुग' में प्रकाशित हुए हैं जिससे मेरी बात हज़ारों ऐसे पाठकों तक पहुँची है जो मेरी पुस्तकों और लेखों से एकदम अपरिचित थे। इसके लिए मैं 'धर्मयुग' के सम्पादकों का कृतज्ञ हूँ। 'धर्मयुग' ने अंग्रेजी-विरोधी धान्दोलन में सक्रिय भाग लेकर सराहनीय कार्य किया है। उसका वीटनिक प्रेम थोड़ा कम हो जाय तो वह हिन्दी भाषा और साहित्य की और भी सेवा करे।

५ अक्टूबर, '६५

रामविलास शर्मा

## दूसरे संस्करण की भूमिका

१९६५ में राष्ट्रभाषा की समस्या नाम से मेरी एक पुस्तक छपी थी। बहुत दिन से यह अप्राप्य है। उसी का दूसरा संस्करण 'भारत की भाषा-समस्या' नाम में अब प्रकाशित हो रहा है। पुस्तक में भाषा-समस्या के अनेक पक्ष हैं। राष्ट्र भाषा की समस्या वाना पक्ष उनमें से एक है। पुस्तक का पुराना नाम प्रकाशक का दिया हुआ था। उसे बदलना मैंने ज़रूरी समझा।

भारत में विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले प्रायः सभी के लिए किसी एक भाषा का व्यवहार करें, यह समस्या का एक पक्ष है। हिन्दी-भाषी प्रदेश में हिन्दी और उर्दू दो भाषाओं के रूप में स्वीकृत न की जायें, हिन्दी प्रदेश की एक ही जातीय भाषा स्वीकार की जाय, विभिन्न जनपदों की उपभाषाएँ जातीय भाषा हिन्दी की तुलना में गौण स्थान पायेंगी, यह भाषा-समस्या का दूसरा पक्ष है। सारे देश के लिए हिन्दी को ही सम्पर्क भाषा बनाने की बात होती है और यही हमारी—हिन्दी प्रदेशवासियों की—जातीय भाषा भी है, इसलिए समस्या के ये दोनों पक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हीं दो पक्षों पर इस पुस्तक के अधिकांश निबन्ध लिखे गए हैं। इन दो पक्षों के अलावा तीसरा पक्ष उन भाषाओं का है जिन्हें जातीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं हुई अथवा जो राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए व्यवहार में नहीं आती। भारत में चार मुख्य भाषा-परिवार हैं, प्रायः, द्रविड, कोल और नाग।



सभी परिवारों में कुछ भाषाएँ ऐसी हैं जिन्हें अपना उपयुक्त स्थान नहीं मिला। आर्य भाषा-परिवार में ऐसी भाषाओं की संख्या कम है। इससे अधिक संख्या द्रविड भाषाओं की है और इनमें से अधिकांश द्रविड भाषाएँ ऐसी हैं जो अन्य द्रविड भाषा-क्षेत्रों से ही घिरी हुई हैं। ऊपर से देखने में लगता है कि विंध्याचल के दक्षिण में चार मुख्य द्रविड भाषाएँ हैं—तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड। प्रचार यह किया जाता है कि आर्यों ने उत्तर भारत जीतकर द्रविड़ों को दक्षिण भारत में ठेल दिया, द्रविड़ भाषाओं के क्षेत्र में इन भाषाओं की कोई अपनी समस्या नहीं है। किन्तु अधिकांश पिछड़ी हुई जातियों और कबीलों की द्रविड़ भाषाएँ आर्य-भाषा क्षेत्रों में नहीं हैं, वे द्रविड़ भाषा-क्षेत्रों में हैं। दक्षिण भारत के चार द्रविड़ भाषा-भाषी राज्यों में पञ्चीसों द्रविड़ भाषाएँ ऐसी हैं जो चार प्रमुख द्रविड़ भाषाओं से भिन्न हैं। भाषाविज्ञानी इनका अस्तित्व स्वीकार करते हैं, उनपर शोध कार्य किया जाता है, किन्तु उन्हें राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यों के लिए मान्यता प्रदान नहीं की जाती। इन भाषाओं का व्यवहार करने वालों का जातीय जीवन पुनर्गठित करना आवश्यक है। जहाँ आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर इकाई बन सके, वहाँ उनका राज्य बनाना चाहिए। जहाँ ऐसा संभव न हो, वहाँ बृहद् राज्यों के अन्तर्गत उनके स्वायत्त क्षेत्र कायम करने चाहिए।

कोल भाषा परिवार भारत का अत्यन्त प्राचीन भाषा परिवार है। यही एक ऐसा परिवार है जिसकी भाषाएँ बोलने वालों का भारत में कोई अपना राज्य नहीं है। इस परिवार की भाषाएँ बोलने वाले अंग्रेजों के विरुद्ध स्वाधीनता-संग्राम में लड़ चुके हैं। इनमें सन्थालों का वीरतापूर्ण संग्राम विशेष रूप से स्मरणीय है। ये लोग पश्चिम से पूर्व तक पूरे मध्यभारत में फैले हुए हैं। यदि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर इनका राज्य बन सके तो उसे अवश्य बनाना चाहिए, न बन सके तो बिहार, उड़ीसा और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में इनके स्वायत्त क्षेत्र कायम करने चाहिए। कोल भाषाएँ बोलने वाले लोग जातीय निर्माण की विभिन्न मञ्जिलों में हैं। इनके सामाजिक विकास की विविधता का विस्तृत अध्ययन करके इनकी भाषा-समस्या सुलझाने का प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ कोल शब्द के व्यवहार के बारे में दो बातें कहना आवश्यक है। इस शब्द का एक अर्थ सूअर होना है। इस कारण कुछ लोग इस शब्द को अपमान-जनक समझते हैं। इसके बदले वे मुण्डा शब्द का व्यवहार करना पसंद करते हैं। जिस कोल शब्द का अर्थ सूअर है वह कोल भाषा परिवार का ही है, इसमें मुझे संदेह है। यह शब्द यूरॉप की लियुथानियन भाषा में भी है और वहाँ भी उसका अर्थ सूअर है। इस लियुथानियन भाषा के लिए कहा जाता है कि इसमें इण्डोयूरोपियन परिवार के प्राचीन लक्षण अधिक सुरक्षित हैं।

11 सूअर के पर्यायवाची कोल शब्द को इण्डोयूरोपियन परिवार का प्राचीन माना जा सकता है। इससे भिन्न है दूसरा कोल शब्द जिसका अर्थ है

वीर पुरुष या वीरजवान । गण समाजों की यह परम्परा रही है कि उनकी भाषा में जो शब्द पुरुषत्व-सूचक होता है, उसी को गणसमाज का नाम मान लेते हैं । उत्तर भारत का पुरुष वंश प्रसिद्ध है । पुरुष शब्द उसी पुरु से बना है । नाग भाषा परिवार में नाग या नगा मूलतः नग शब्द है जिसका अर्थ है पुरुष । कश्मीरी, हिन्दी आदि भाषाओं में अब भी एक नग, दो नग का अर्थ होगा, एक मादमी, दो मादमी । कबीले का नाम बताने वाले कोल शब्द का अर्थ गौरव-पूर्ण है । उसे हीन समझकर छोड़ना न चाहिए । पर कोल शब्द के लिए मेरे आग्रह का मुख्य कारण इसका है । अवध से लेकर छोटा नागपुर तक जहाँ भी कोल जनो की वस्तिर्या रही हैं, वहाँ स्थानों के साथ यह नाम जुड़ गया है और उसका ऐतिहासिक महत्व है । बैसवाडे में एक गाँव कुलहा है । स्पष्ट ही इसका सम्बन्ध कोल जनो से है । छोटा नागपुर में हमने ठीक मिलता-जुलता एक स्थान है कोलहा । मेरा अनुमान है कि गढ़ा-कोला जैसे स्थानवाचक नामों में भी गढ़ के साथ दूसरा शब्द विशेष जनसमुदाय अर्थात् कोल जनो का सूचक है । कोल शब्द के सहारे भाषा-विज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास को अनेक सुविधियाँ सुलभाई जा सकती हैं । अतः मैं इसी शब्द का व्यवहार करता हूँ ।

✓ भारत में नागभाषा परिवार ही एक ऐसा परिवार है जिसकी भाषाएँ बोलने वाले लोगों ने अपने राज्य की भाषा को अंग्रेजी बताया है । अगामि, सेमा आदि गण अपने दैनिक जीवन में अपनी-अपनी गण भाषाओं का व्यवहार करते हैं । आपस में और दूसरों से सम्पर्क में आने पर वे एक प्रकार की हिन्दी का व्यवहार करते हैं जिसमें अनेक भाषाओं के तत्त्व आकर घुलमिल गये हैं । अंग्रेजी बहुत थोड़े लोग जानते हैं किन्तु ईमाई धर्म-प्रचारकों के प्रभाव से इनके राज्य का नाम नागालैण्ड है और इस राज्य की भाषा अंग्रेजी है । अन्य प्रदेशों की तरह यहाँ भी यह सत्य है कि जब नाग भाषाओं का अपना स्वत्व प्राप्त होगा, तब अंग्रेजी की स्थिति कमजोर होगी और वे लोग जो टूटीफूटी मिश्रित हिन्दी का व्यवहार करते हैं, उन्हें इस सम्पर्क भाषा को सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि छोटा नागपुर में कोल और द्रविड जन इसी प्रकार की टूटी फूटी मिश्रित हिन्दी का व्यवहार करते हैं । कोल भाषाओं को उनका स्वत्व प्राप्त होने के साथ साथ यह टूटी-फूटी हिन्दी भी सुदृढ़ सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होगी ।

यहाँ परिनिष्ठित भाषा और उसके अपरिनिष्ठित रूपों की चर्चा करना आवश्यक है । नागालैण्ड और छोटा नागपुर केवल दो ऐसे प्रदेश नहीं हैं जहाँ हिन्दी के अपरिनिष्ठित रूपों का चलन है । डॉ० सुनीति कुमार चाटुर्ज्या सन् १९२८ से बलकत की हिन्दी की बकालत करते रहे हैं । १८वीं सदी के अन्त में अंग्रेज तथा यूरोप के अन्य व्यापारी, उत्तर भारत और बंगाल के विभिन्न पक्षों के लोग, इसी हिन्दी से काम चलाते थे । दक्षिण भारत में एकही नाम से हिन्दी का एक रूप विख्यात है । वहाँ निश्चित लोग साहित्य में परिनिष्ठित

स्तर पर अंग्रेजी का स्थान लेती है या नहीं। १९४८ में पेरिस की एक सभा में डॉक्टर सुनीलकुमार चाटुर्ज्या ने भी हिन्दी को राष्ट्र सभ में स्थान देने की बात कही थी। किन्तु जब हिन्दी को केन्द्रीय राज्यभाषा बनाने का प्रश्न सामने आया, तो उन्होंने भाषा-आयोग के बहुमत से अलग अपनी विरोधी राय प्रकट की। यदि, भारत के प्रतिनिधि राष्ट्र सभ में हिन्दी का व्यवहार करें या किसी अन्य भारतीय भाषा में अपन विचार प्रकट करें तो सत्तार को पता चल जाए कि भारत अब अंग्रेजी और अंग्रेजों का अर्थ उपनिवेश नहीं रहा। तब राष्ट्र सभ की एक भाषा हिन्दी हो, यह माँग करत हुए अच्छा भी लगेगा। पर अभी तो भारत की लोक सभा में अंग्रेजी का बोलबाला है। जब भारत की लोक सभा में अंग्रेजी छापी हुई है, तब विश्वसंस्था राष्ट्रसभ में हिन्दी को स्थान देने की माँग कम किम मुँह से कर सकते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी को विश्वभाषा बनाने के प्रति राजनीतिज्ञों में जो गहरी दिलचस्पी पैदा हो गयी है, उसका कारण ही यह है कि लोग यह न पछें कि लोकसभा में और अखिल भारतीय सेवाओं में अंग्रेजी का चलन क्यों है।

भाषा की समस्या मात्र प्रशासन-सम्बन्धी समस्या नहीं है। इसका गहरा सम्बन्ध देश के जनतान्त्रिक आन्दोलन और देश की सुरक्षा से है। जनतन्त्र से जितना लाभ या हानि सम्पत्तिशाली लोगों को होती है, उससे अधिक लाभ या हानि श्रमिक जनता को होती है। भारत के सामाजिक विश्वास का यह अकाट्य तथ्य है कि हिन्दी प्रदेश से अलग, भिन्न प्रदेशों में, हिन्दी भाषी मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी है। जिन कारणों से हिन्दी प्रदेश के गरीब और मुफ्तम किसान अपना देश छोड़कर अफ्रीका, फीजी, मारीशस आदि द्वीपों, महाद्वीपों में कुलीगरी करने गये थे, उन्हीं कारणों से इनके भाई बंधु अपना प्रदेश छोड़कर बम्बई कसकत्ता जैसे बड़े नगरों में मजदूरी करने गये थे। कलकत्ते के मजदूरों में आधे से कुछ ज्यादा ही हिन्दीभाषी होंगे। इसी तरह बम्बई के मजदूरों में एक बहुत बड़ा हिस्सा हिन्दी मजदूरों का है। जिस तरह देश छोड़कर जान वाले हिन्दी मजदूरों ने अपनी भाषा को विश्वभाषा बनाया है, उसी तरह अपना प्रदेश छोड़कर जाने वाले, बंगाल महाराष्ट्र आदि में मजदूरी करने वाले, हिन्दी श्रमिकों ने अपनी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया है। हिन्दी के बिना अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरों का संगठन हो ही नहीं सकता। जनतन्त्र की एक अत्यन्त जागरूक शक्ति मजदूर हैं, इसलिए जो लोग जनतन्त्र की रक्षा की बातें करते हैं, उन्हें अविनाश भारत के सामाजिक जीवन से अंग्रेजी के व्यवहार को निकाल बाहर करना चाहिए।

दूसरी बात सुरक्षा की है। स्वाधीन भारत ने अभी किसी बड़े युद्ध का सामना नहीं किया, पर हो सकता है, निकट भविष्य में उसे ऐसे युद्ध का सामना करना पड़े। आधुनिक युद्ध की विशेषता यह है कि वह सैनिकों और असैनिक जनता में विशेष भेद नहीं करता। सैनिकों और असैनिक जनता

के सहयोग से ही युद्ध में सफलता मिलती है। युद्ध के मोर्चे पर चाहे घाघे बढना हो, चाहे सैनिक कारणों से पीछे हटना हो, दोनों स्थितियाँ में परस्पर सहयोग अपेक्षित होता है। यदि युद्ध दीर्घकाल तक चला या छापमार लड़ाई चलाने की नीवत आयी, तो जनता का सम्पर्क और सहयोग और भी अधिक अपेक्षित होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जनता और सेना, दोनों किसी एक भाषा का व्यवहार करके एक दूसरे की बात समझ सकें मने ही यह भाषा टूटी-फूटी हो, अपरिनिष्ठित हो, पर उसका कामचलाऊ होना बहुत जरूरी है। जनता के भलावा स्वयं सेना के भीतर अफसर और सिपाही के बीच जितना फासला कम होता है, उतना ही फौज भीतर में मजबूत होती है। यदि अफसर अंग्रेजी के रंग में रंगे होंगे तो उनके और साधारण सैनिकों के बीच में फासला ज्यादा होगा और उतना ही सेना की जुभाऊ शक्ति कम होगी। इसलिए अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त करना और उसकी जगह काम-चलाऊ हिन्दी का व्यापक प्रसार करना राष्ट्र के जीवन-मरण का प्रश्न है।

निस्सन्देह जो लोग अंग्रेजी के व्यवहार के आदी हैं, उन्हें इस भाषा का मोह छोड़ते थोड़ा कष्ट होगा। अपने दिल को हिम्मत बंधाने के लिए उन्हें यह बात याद कर लेना चाहिए कि १९वीं सदी में 'राजपूताना' में स्थित अंग्रेज अफसर वहाँ के राजाओं से हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार करते थे। राजा बलबन्तसिंह कालेज के हिन्दी अध्यापक डॉ० श्री मोहन द्विवेदी की देख-रेख में महेशचन्द्र गुप्त राजस्थान के प्रशासनिक 'कार्यों में हिन्दी का प्रयोग' (१८५७-१९७४) विषय पर शोध कार्य कर रहे हैं। उन्होंने १८५७ से पहले के और उसके बाद के भी काफी दस्तावेज इकट्ठे किए हैं। इन दस्तावेजों में वे पत्र हैं जो अंग्रेजों ने राजाओं को लिखे, इनके प्रतिरिक्त वे पत्र हैं जो राजाओं ने अंग्रेजों को लिखे, साथ ही ऐसे पत्र हैं जो राजाओं ने एक दूसरे को लिखे। यदि राजस्थान में १९वीं सदी में हिन्दी राजभाषा के रूप में काम आती थी और उसका व्यवहार हिन्दुस्तान के लोग ही नहीं, अंग्रेज भी करते थे, तो कोई कारण नहीं कि २०वीं सदी के अन्तिम चरण में अंग्रेजी प्रेमी भारतवासी अपना अंग्रेजी मोह त्यागकर हिन्दी का उपयोग न कर सकें।

राष्ट्रीय सुरक्षा के माथे राष्ट्रीय एकता का प्रश्न जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय एकता केवल हिन्दुओं और मुसलमानों की एकता नहीं है। पश्चिमी पाकिस्तान के धर्मान्ध लोगों ने पूर्वी बंगाल के लोगों की भाषा और जातीय सस्कृति की अवहेलना करके धर्म के नाम पर उन्हें दबाकर रखने का प्रयत्न किया। इसमें उन्हें सफलता न मिली। बचे हुए पाकिस्तान में आन्तरिक संघर्ष विकट रूप धारण कर रहा है और धर्म के नाम पर घपीलें जारी करके उस शान्त करना असम्भव हो गया है। यदि भारत में मूल सामाजिक समस्याएँ हल न की गईं, तो यहाँ भी भयानक अशान्ति फैल सकती है। राष्ट्रीय एकता विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले समुदायों की एकता भी है। इंग्लैण्ड की अंग्रेजी-भाषी जाति का

दो राज्यों में बाँट दीजिए तो क्या इससे इंग्लैण्ड की राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी ? विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले मिलकर राष्ट्रीय एकता मजबूत करें, इसके लिए जरूरी है कि कोई एक भाषा बोलने वाला समुदाय भी विभाजित न हो, वरन् आन्तरिक रूप से मजबूत हो। महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, केरल, गुजरात आदि प्रदेशों के लोगो ने भाषा व आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग की। केन्द्रीय सत्ता ने पहल विरोध किया, फिर वही माँग स्वीकार की। अंग्रेजो ने बम्बई और मद्रास प्रेसीडेन्सी नाम से जो बड़े-बड़े सूबे बनाये थे, उन्हें तोड़कर नये राज्य गठित किए गए। हिन्दी प्रदेश में इससे उल्टी स्थिति है। यहाँ प्रश्न बड़े राज्यों को तोड़कर छोटे राज्य बनाने का नहीं है। प्रश्न है अनेक हिन्दी-भाषी राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाने का। जनक प्रशासन विशारद आपत्ति करते हैं कि इतने बड़े राज्य का शासन चलाना बहुत कठिन होगा, इसलिए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य को भी दो-तीन टुकड़ों में बाँटना उचित होगा। जहाँ तक शासन चलाने का सम्बन्ध है, प्रागरा नगर-महापालिका एक शहर की नालियों की ही सफाई नहीं करा पाती, यदि हर मुहल्ले की एक-एक पालिका बना दी जाय, तो शायद यह शहर आदमियों के रहने लायक हो जाय। पर विश्वास नहीं है कि मुहल्ला पालिका भी मुहल्ले की सफाई करा सकेगी क्योंकि आदत यह है कि अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर के सामने डालो और हाजत रफा करने के लिए नालियाँ हैं—जिनमें गहराई बहुत ही कम है क्योंकि ठेकेदार कहता था, नालियाँ गहरी करें तो डजीनियर को पैसा वहाँ से देंगे। जनतंत्र की रक्षा करना, शासन तंत्र चलाना नये सिरे से सीखना है। प्रश्न छोटे-बड़े राज्यों का नहीं है। प्रश्न है शासन चलाने की योग्यता का। प्राजकल विकेन्द्रीकरण की काफी चर्चा है। केन्द्रबद्ध शक्ति और शक्ति का विकेन्द्रीकरण परस्परविरोधी बातें नहीं हैं, वे एक-दूसरे की पूरक हैं। भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्रीय योजनाएँ बनाना, राष्ट्रीय नीति निर्धारित करना केन्द्रीय शक्ति का काम है। इस राष्ट्रीय ढाँचे के भीतर नीतियों को कार्यरूप में परिणत करना, आवश्यकता-नुसार उनमें परिवर्तन करना राज्यों का काम है। विकेन्द्रीकरण का एक स्तर राज्य है। पर विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया इसी स्तर पर समाप्त नहीं हो जाती। लोग गाँव, ताल्लुका, तहसील, ब्लॉक आदि की बातें करते हैं। राज्य के बाद वाला स्तर जनपद का है। हिन्दी-भाषी प्रदेश में ब्रज, अवध, बुन्देलखण्ड, मिथिला, मगध आदि जनपद साफ पहचाने जाते हैं। मुख्य बोलियों के ऐसे विशेष क्षेत्र महाराष्ट्र, बंगाल, तमिलनाडु आदि प्रदेशों में भी हैं। इन्हीं को शासन का मूल आधार बनाना चाहिए, यही विकेन्द्रीकरण का दूसरा स्तर है। हमारे यहाँ जो कमिश्नरियाँ बनी हैं, उनमें जनपदों की सीमाओं का ध्यान नहीं रखा गया। जैम भाजपुरी क्षेत्र आधा बिहार में है और आधा उत्तर प्रदेश में, जैसे ब्रज क्षेत्र कुछ उत्तर प्रदेश में है और कुछ राजस्थान में, जैम बुन्देलखण्ड मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में विभाजित है, वैसे ही कमिश्नरियाँ जनपदों की सीमाएँ तोड़ती

हैं। जब कोई एक जनपद दो भलग राज्यों में विभाजित होगा, तब किसी एक ही कमिश्नरी के अन्तर्गत वह समुक्त कैसे होगा ?

बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आदि हिन्दी राज्यों को मिलाकर एक विशाल राज्य बनाना चाहिए। इस राज्य की इकाइयाँ उसके जनपद होंगे, विशेष बोलियों के क्षेत्र होंगे। प्रत्येक जनपद में कम से कम एक विश्वविद्यालय, एक भाषाशाला केन्द्र और उच्च न्यायालय की एक शाखा होनी चाहिए। तब हिन्दी प्रदेश का—देशी-विदेशी राजनीतिज्ञों द्वारा उलझाया हुआ—गोरखघन्घा कुछ सुलभ सबना है। अनेक राज्यों की विधान सभाओं पर जो बुरोहो दपया स्वर्च होता है, वह बचाकर विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। व्यापार के प्रसार में राज्य स्तर की चुग्री आदि की हवावटें दूर की जा सकेंगी। हिन्दी-भाषा जनता अपनी शक्ति पहचानेगी और राष्ट्र के जीवन में अपनी भूमिका निवाहेगी। विभिन्न राज्यों में बँटे होने से उसकी सांस्कृतिक एकता छिन्न भिन्न हो गयी है, वह फिर सुनबद्ध होगी। जनपद की राजकीय और सांस्कृतिक कार्यवाही की मूल इकाई बनाने से इस प्रदेश के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन को पुष्ट जनतांत्रिक आधार प्राप्त होगा। केन्द्रबद्ध शक्ति और विकेन्द्रीकरण के सिद्धान्तों का समन्वय होगा। अभी जहाँ सिद्धान्त-हीनता और नियमविहीन अव्यवस्था है, वहाँ सिद्धान्तिक आधार पर जातीय प्रदेश का पुनर्गठन होगा।

यह हिन्दी प्रदेश काफी बड़ा होगा किन्तु सोविषयत सभ के हसी क्षेत्र से और चीनी गणतंत्र के चीनी क्षेत्र में वह बढा न होगा।

अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर और औरंगजेब के समय में इस देश के भीतर जितनी भी राजनीतिक एकता काममें हुई है, उसका आधार हिन्दी प्रदेश की एकता रही है। हिन्दी प्रदेश को विभाजित रखकर राष्ट्रीय एकता की बातें करना प्रलाप माय है। हिन्दी प्रदेश की एकता मरने पड़ने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक है।

इस पुस्तक के दूसरे संस्करण में दो निबन्ध और जोड़ दिए हैं। एक निबन्ध हिन्दी के आधुनिक विकास-सन्दर्भ में अजभाषा की भूमिका है, दूसरा निबन्ध हिन्दीभाषी प्रदेश के बहुभाषाभाषी होने की समस्या से सम्बन्धित है।

१४ जून, १९७७

रामविलास शर्मा



## अनुक्रम

१. स्वदेशी भाषा और इतिहासी साहित्य	२१
२. राजनीतिक नेता और हिन्दी	२४
✓ ३. भाषा और राष्ट्रीयता	२६
४. भाषा और साहित्य में पाकिस्तान	२७
५. हिन्दी गद्य-शैली पर कुछ विचार	३१
६. राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दू राष्ट्रवाद	३८
७. हिन्दी का 'संस्कृतीकरण'	४४
८. उर्दू-साहित्य की सांस्कृतिक परम्परा	५०
९. भारत की भाषा-समस्या	६६
१०. जातीय भाषा के रूप में हिन्दी का प्रसार	८४
११. हिन्दी-उर्दू समस्या	९२
१२. भाषा और प्रान्तीयता	९९
१३. अनिवार्य राजभाषा का सवाल	१०२
१४. अंग्रेजी के हिमायती	१०८
१५. सोवियत क्रान्ति और भाषा-समस्या	११२
१६. अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी	११५
✓ १७. बहुजातीय राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाषा हिन्दी	१२१
१८. हिन्दी की व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ	१२६
१९. उर्दू की समस्या	१३१
२०. जातीय प्रतिद्वन्द्विता और हिन्दी	१३८
२१. राष्ट्रभाषा अंग्रेजी	१४४
२२. सोवियत संघ में भाषा-समस्या-समाधान	१५०
२३. हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता	१५३
२४. राष्ट्रीय एकता और अंग्रेजी	१५७
२५. राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय प्रभुत्ता	१६२



२६	हिन्दीभाषी प्रदेश में हिन्दी प्रचार की आवश्यकता	१६६
२७	सरकारी बोशवार और राष्ट्रभाषा	१७४
२८	कामपची कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम का मसौदा	१८१
२९	राष्ट्र, जाति और मार्क्सवाद	१८५
३०	'अन्तर्राष्ट्रीय' वैज्ञानिक शब्दावली	१९२
✓ ३१	संस्कृति और भाषा	१९४
३२	भाषा की समस्या—अति आवश्यक	१९८
३३	अंग्रेजी की सुरक्षा के लिए सघर्ष	२००
३४	भाषा की समस्या और राष्ट्रीय विघटन	२०५
३५	भाषा की समस्या और मजदूर वर्ग	२१२
३६	भारत की राजभाषा अंग्रेजी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा	२२५
३७	देश का विघटन और अंग्रेजी	२४२
३८	प्रगतिशील साहित्यकार और भाषा-समस्या के जनतांत्रिक समाधान	२५१
३९	हिन्दी के आधुनिक विकास-सन्दर्भ में ब्रजभाषा की भूमिका	२७७
४०	हिन्दीभाषी प्रदेश—बहुभाषाभाषी प्रदेश ?	२८६

## परिशिष्ट—१

१	भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उन्नीसवीं सदी में हिन्दी-आन्दोलन	३०१
२	गांधीजी और भाषा समस्या	३१५

## परिशिष्ट—२

१	प्रेमचन्द और भाषा-समस्या	३४५
२	उत्तर प्रदेश की सरकार और हिन्दी	३५३
३	भारत का भाषा-संकट	३५५

भारत की भाषा-समस्या



## स्वदेशी भाषा और अहिंसावादी साहित्य

हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के अनेक पदाधिकारी इस बार अपनी असाहित्यिकता के कारण एक विशेषता लिये हैं। साहित्य में जितने भी जन अधिक संख्या में दिलचस्पी लें, हमें उससे प्रसन्न होना चाहिए। परन्तु ये मैधावी हिन्दी-साहित्य के पास विद्यार्थी के रूप में नहीं आए। उसे जानने-पहचानने की उन्होंने चेष्टा नहीं की। राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करनेवाली अपनी प्रकृति के अनुसार उन्होंने हिन्दी-साहित्यको वी तरह-तरह के उपदेश दिए हैं। यदि वे हमारे साहित्य का सहृदयतापूर्वक अनुशीलन कर उसकी त्रुटियाँ साहित्यिकों को बताते तो उनके कार्य पर सबको हर्ष होता। पर उनकी असाहित्यिकता और साहित्य के अज्ञान का घोष उनके उपदेश की मधुर वाणी से मेल नहीं खाता।

सम्मेलन के सभापति ने, शायद अपने पूर्व राष्ट्रपति होने का स्मरण कर, कहा है—“सुविधा के विचार से हिन्दी को राष्ट्रभाषा हमने माना है।” फिर इस सुविधा के मार्ग में जो अड़चनें आएँ, उन्हें क्यों न हटाया जाए? आप कहते हैं—“हिन्दुस्तान में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, सिख बसते हैं और तो भी वह हिन्दुस्तान है। उसी प्रकार हिन्दी में सभी भाषाओं से उत्तम शब्द हम लेंगे और तो भी वह हिन्दी ही रहेगी।” जैस काप्रेस, राष्ट्र की एकता का प्रतीक, अपने भीतर सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि रखती है, वैसे हिन्दी तब तक राष्ट्रभाषा न होगी, जब तक उसमें सभी भाषाओं के प्रतिनिधि शब्द न होंगे। सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष श्री ब्रजलाल बियाणी ने इस बात को भली-भाँति समझा है और उस सबसे अधिक स्पष्ट रूप में कहा है—“हिन्दी-भाषा के प्रचार तथा सर्वप्रियता के लिए आवश्यक है कि उसका शब्द-भण्डार सब भाषाओं से लिए हुए शब्दों से भरा हो। हरेक प्रान्तवासी में हिन्दी के लिए समत्व पैदा होने के लिए हिन्दी के शब्दकोश में उसका भी हिस्सा होना आवश्यक है।” जब तक यह शब्दकोश न बने, तब तक इस भाषा की कल्पना करना बटिन है। अभी अन्य प्रान्तों के भिन्न भाषा भाषी हिन्दी ही सीखते थे, अब वे उसके साथ थोड़ी-थोड़ी सभी प्रान्तीय भाषाएँ सीखेंगे। हिन्दी बोलनेवाले, जिन्हें

तमिल, बन्नड, बँगला, मराठी, गुजराती आदि का ज्ञान नहीं—बीस देखकर शुद्ध हिन्दी बोलेंगे। यह भाषा हिन्दी होगी या और कुछ, इसे बाबा साहेब श्री कालेलकर ने अच्छी तरह समझा है। इस भाषा का अपना नामकरण करते हुए उन्होंने कहा है—‘स्वदेशी भाषा में हम बोलेंगे।’

भाषा-संस्कार के साथ इन हिन्दी के शुभेच्छुओं को हमारे साहित्य की उन्नति का भी ध्यान है। राजनीतिक सुविधाओं के लिए हिन्दी की आवश्यकता नहीं। बाबू राजेन्द्रप्रसाद के अनुसार “राष्ट्र का प्राण साहित्य होता है और उस साहित्य का निर्माणकर्ता समाज का बहुत बड़ा सेवक होता है।” तब हिन्दी-साहित्य की त्रुटियाँ दूर होनी ही चाहिए। काका कालेलकर के अनुसार आधुनिक साहित्य का पूर्व भाग दूसरों की नकल का फल है। “इस जमाने का हमारा प्रारम्भिक साहित्य अनुकरणरूप ही था और अनुकरण तो निष्प्राण ही हो सकता है।” ‘हमारे साहित्य’ में किन-किन साहित्यों की गणना है, नहीं मालूम, यदि हिन्दी की है तो उसके साथ अन्याय है। ‘इस जमाने का हमारा प्रारम्भिक साहित्य’ एक ऐसा गोल वाक्य है कि समय ठीक से निर्धारित नहीं हो सकता। फिर भी भारतेन्दु से लेकर आज तक जो नये युग का जीवन है, उसमें उत्पन्न किसी भाग के साहित्य पर ऊपर का आरोप लागू नहीं होता। अन्य साहित्यिक जागृतियों की भाँति हमारे यहाँ बाहरी साहित्यों के सम्पर्क से विचारों में नवीनता आई है, पुरानी रुढ़ियों का ध्वंस और नई धाराओं का निर्माण हुआ है। यदि यह अनुकरण है तो कोई भी जीवित साहित्य उससे नहीं बचा।

“पिछले थोड़े वर्षों में हिन्दी ने बँगला, मराठी, गुजराती आदि प्रान्तीय साहित्यों से अपना साहित्य कम समृद्ध नहीं किया है। आदान प्रदान में हिन्दी सिद्ध हो चुकी है। हम हिन्दी को जो कुछ देते हैं, वह उसे सशोधित कर देश के कोने-कोने में पहुँचा देती है।” किसी नवजाग्रत भाषा के साहित्य की ऊँचाई जल्दी आँकना आसान नहीं। जो कृतियाँ शीघ्र प्रसिद्धि पाती हैं, वे बहुधा पाठकों की पूर्व-निश्चित धारणाओं के बहुत-कुछ अनुकूल तथा कुछ-कुछ पुरानी रुढ़ियों का अवलम्ब लिये होती हैं। हिन्दी में अब भी इतने रुढ़िवादी हैं कि पक्के क्रान्ति-कारियों को उचित श्रेय या विज्ञापन नहीं मिला। जो हमारे यहाँ का वास्तविक मौलिक साहित्य है, उसकी समुचित छानबीन धीरे-धीरे ही सम्भव है। परन्तु वैसा करना उसकी ओर से आँख मूँदकर राय देने से सम्भव नहीं, उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा।

हिन्दी-भाषा में अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों के बहिष्कार के समान हमारे नेताओं ने हिन्दी साहित्य में अश्लीलता का दुःस्वप्न भी देखा है। गांधीजी का वश चले तो वह साहित्य-सम्मेलन से उस रस को त्याग्य ही मनवा दें। वश चले तो गांधीजी ब्रह्मचर्य द्वारा सबसे सन्तति-निग्रह करवा दें। परन्तु वश चले तो भी यह हानिकार होगा। समयानुकूल प्रकृति की पुकारों को न मानने से बुरा फल मिलता है। असाधारणों का नियम सब पर लागू नहीं हो सकता।

यदि साहित्य का सम्पर्क जीवन में रहेगा तो उसमें शृंगारी वर्णन अवश्य आएंगे । क्या हिन्दी, क्या संस्कृत, बड़े-बड़े सन्तों ने अपने साहित्य में जीवन का पूर्ण चित्र उतारने के लिए शृंगार का बहिष्कार नहीं किया । देखना केवल यह होता है कि यह शृंगार पवित्र मनोभावों का परिचायक तो नहीं है । हिन्दी के गुजरे साहित्य के लिए यह आरोप सही हो सकता है । तब यदि जिस रस का वर्णन करता था, चाहता था कि उसी के अनुकूल आचरण करने के भाव पाठक या श्रोता के मन में उत्पन्न हो । आधुनिक साहित्य में कलात्मक आनन्द की ओर अधिष्ठान है । किसी मूनी का चित्रण करके बस हमें मूनी बनने के लिए नहीं कहता । ममार के बड़े-मे-बड़े साहित्यिकों ने पाप को अपना विषय बनाकर अद्भुत कृतियों को जन्म दिया है । अतः, यदि स्त्री पुरुष के पारम्परिक मनोभावों और आकर्षण-प्रत्याकर्षण का स्वस्थ वर्णन हो तो वह साहित्य भी समाज को उठानेवाला होगा ।

बाबा कानेलाल की साहित्य-नियन्त्रण के सम्बन्ध में और किसी से कम चिन्ता नहीं । आज साहित्य पर न राजसत्ता का नियन्त्रण है, न धर्माचार्यों का । "जो लोग साहित्य का रस जानने हैं और समाज का हित चाहते हैं, इतिहास और आदर्श, दोनों की दृष्टि रखकर जो लोग समाज की प्रगति में मदद कर सकते हैं, ऐसे पुरुषों का ही नियन्त्रण साहित्य पर रहना चाहिए । दुःख के माध्यम कहना पड़ता है कि हमारे साहित्य-जगत् में मनमानी मर्यादों की कमी है ।" हमें बाबा साहब से सहानुभूति प्रकट करने की आवश्यकता नहीं, हमारे यहाँ आचार्य लोग अब भी अधिकांश प्यूरिटन प्रवृत्ति के हैं । यह सभी जानते हैं कि अक्षयता का कहीं आभास पाते ही वे धरती मिर पर उठा लेते हैं । परन्तु बाबा साहब को इन पर विश्वास नहीं । उन्हें आभास है, एक दिन साहित्यिक मासिक की बागडोर उनके हाथों में आएगी; तब वह इन उच्छृङ्खल व्यक्तियों को गिन-गिनकर पाँसी पर लटकाएंगे । — "भारतीय साहित्य परिषद् जब पूर्ण रूप से विकसित होगी, तब साहित्य-शुद्धि संभालने की जिम्मेदारी बानून या धर्मतन्त्र के हाथों में नहीं रहेगी, साहित्य ही अपने क्षेत्र को संभाल लेगा ।"

आदर्श साहित्य-निर्माण के लिए गांधीजी, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, बाबा साहब आदि सभी ने उपदेश दिए हैं । इन्हें देखकर कोई अपरिचित यही समझेगा कि हिन्दी में एकदम पतित और समाज का अहित करनेवाला साहित्य रचा जा रहा है । इसका उत्तर एक लेख में देना सम्भव नहीं । साहित्यिकों के नाम गिनाने की अपेक्षा उनकी कृतियों का सुचारु विवेचन अधिक श्रेयस्कर होगा । तब तब अपने नेताओं की शुभकामनाओं के लिए अनुग्रहीत होते हुए हम यही आशा करते हैं कि यदि उनका हमारे साहित्य से कुछ दिन और सम्पर्क रहा तो वे उसमें अपने अनेक सिद्धान्तों को कार्य-रूप में परिणत पाएँगे । (१९३६)

## राजनीतिक नेता और हिन्दी

राजनीतिक नेता लोग साहित्य पढ़ेंगे, इसकी आशा करना व्यर्थ जान पड़ता है। फिर भी साहित्य राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। नेताओं की राजनीति गंदली होने पर उसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ सकता है, विशेषकर जब थोड़ा-बहुत शासनाधिकार हाथ में होने से वे बालकों और नवयुवकों की शिक्षा के लिए उत्तरदायी भी हों। ऐसी दशा में शिक्षा और भाषा में हस्तक्षेप करने के पहले उन्हें साहित्य के विकास और उसकी मूलधारा का ज्ञान होना आवश्यक है। आज की भारतीय राजनीति समझौते पर निर्भर है। यह समझौता कभी 'इंडिया एक्ट' के लिए अंग्रेज सरकार से कुछ शर्तें मनवाकर होता है, कभी केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन में बँटवारा करने के लिए श्री जिन्ना से महात्मा गांधी और श्री जवाहरलाल नेहरू की बातचीत के रूप में प्रकट होता है। हमने हिन्दी-साहित्य में समझौता करना नहीं सीखा। हम समझौता नहीं, एका करते में विश्वास रखते हैं और यह एका एक स्वतन्त्र अविभाजित राष्ट्र की भूमि पर ही हो सकता है। जो प्रान्तीयता और साम्प्रदायिकता लेकर आगे बढ़ता है, वह राष्ट्रीयता का द्रोही है, उससे एक राष्ट्र-प्रेमी समझौता कैसे कर सकता है? इस उग्र राष्ट्रीयता की भावना में राजनीतिज्ञ हिन्दी-साहित्य में शिक्षा ले सकते हैं। हमारे साहित्य का उद्भव ही एक विदेशी साम्राज्यवाद के प्रतिरोध से हुआ था और सदियों तक देश की भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे साहित्यिकों ने इस विदेशी साम्राज्यवाद से मोर्चा लिया है। यह मोर्चा नये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भी जारी रहा है। इस दासता में भी हमने अंग्रेजी को क्यों नहीं अपनाया? इसलिए कि हमारी भाषा हमारी राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक है। अरबी और फारसी के विरुद्ध इसी तरह तुलसीदास और भूपण ने हिन्दी की पताका ऊँची रखी, इसलिए कि समाज के जीवित रहने का अर्थ हिन्दी का जीवित रहना भी था। यद्यपि हिन्दी का रूप बदलता रहा है, लेकिन उसकी एकता नष्ट नहीं हुई। गुलाम देशों की यह मनोवृत्ति रही है कि वे विदेशी संस्कृति और भाषा को जल्दी अपना लेते हैं क्योंकि उनका अपना सामाजिक

जीवन नहीं के बराबर होता है। ज्ञान्ति के पूर्व के रूस में वहाँ के शिक्षित और धनी वर्गों में इसी प्रकार पेंच भाषा का बोलबाला था। रूसी भाषा को लोग गैबार्क और ग्र्यगाम्भीर्य में हीन समझते थे। यदि वहाँ के साहित्यिक इस कृतिसत मनोवृत्ति के सामने सिर झुका देते तो आज का रूसी-साहित्य वहाँ होता ? हमारे देश में भी अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करने लोग अपनी शिक्षा का परिचय देना आवश्यक समझते हैं। जो बाबू वर्ग इंग्लिशतानी में बातचीत करता है, वह इसलिए कि अपनी भाषा में विचार करने की उसमें अक्षमता है। उसकी भाषा तीन कौड़ी की होती है और भाव दो कौड़ी के। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए कुछ लोगो ने अंग्रेजी, अरबी, फारसी—सभी से शब्द भर लेने की सलाह दी है। जहाँ नये नये अर्थों के शब्द खोजने पड़ें, वहाँ संस्कृत से न लेकर उन्होंने अंग्रेजी से लेने को कहा है। माना अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द खुद उसके घर के हों, उसने उन्हीं लैटिन और ग्रीक से उधार न लिया ही। ग्रीक और लैटिन के शब्द अंग्रेजी की चलनी में छनते हुए हिन्दी में आएँ, उन्हें स्वीकार है, संस्कृत से हम शब्द लें, उन्हें स्वीकार नहीं।

जा भारत की जलवायु में पना है, उस भारत की भाषा और संस्कृति अपनाती होगी, उसे भारत की ही महत्ता का स्वप्न देखना पड़ेगा। भारतीय भाषाओं को अभारतीय ढाँच में ढालने की चेष्टा पुरानी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति का एक अवशिष्ट चिह्न है, हम उससे किसी प्रकार सम्झौता नहीं कर सकते। जिस तरह हम भारत की भूमि में अन्न जल ग्रहण करते हैं, उसी तरह उसकी भाषा भी। जब हम देश का प्रेम करना सीखेंगे, तब उसकी भाषा से भी प्रेम करेंगे। न हम देश-प्रेम में विगी में सम्झौता करना चाहते हैं, न भाषा प्रेम में। देश-प्रेम और भाषा प्रेम दो अलग वस्तुएँ नहीं, एक है। (१९३६)



## भाषा और राष्ट्रीयता

इसी साल अभी अगस्त के महीने में श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कलकत्ता में महाजाति भवन का शिलान्यास करते हुए बताया है कि बंगाल ने भारतवर्ष के नये अभ्युत्थान में किस प्रकार योग दिया है। बंगाली भाषा, साहित्य, कला और संगीत—सभी का उन्होंने उल्लेख किया। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर भी अभिमान प्रकट किया कि विदेशी सभ्यता का स्वागत करने में बंगाल सर्वप्रथम था। अंग्रेजी समाचारपत्रों में उनका वाक्य इस प्रकार छपा था—“Bengal led India in welcoming European culture to her heart” यूरोप की सभ्यता अपनाने में बंगाल भारत का अग्रणी था। विदेशी सभ्यता विदेशी शासन के ही साथ हमारे देश में आई है। स्वाभाविक था कि राष्ट्र-प्रेमी व्यक्तियों ने विदेशी शासन के समान उस सभ्यता से भी अपने-आपको दूर रखा। परन्तु बंगाल में ऐम ख्यातनामा व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने उत्थान के लिए अंग्रेजी शिक्षा को आवश्यक समझा। उस शिक्षा के प्रसार के साथ बंगाल के नये साहित्य का उदभव भी हुआ। इसलिए अनेक बंगाली अपने साहित्य पर गर्व करते हुए उस शिक्षा पर भी गर्व करते हैं। फिर भी गुलामी गुलामी है, उस पर अभिमान करना किसी की शोभा नहीं देता।

बंगाली विद्वानों के हृदय में विदेशी शिक्षा और सभ्यता के प्रति यह भावना कितनी दृढ़ता से घर कर गई है, इसका एक और प्रमाण देखिए। बंग-साहित्य-सम्मेलन के सभापति सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० सुनीतिकुमार चटर्जी ने इसी बात का उल्लेख कर कहा था—“ऊनविंश शतके इंग्रेजों ने अनुगामी बंगाली इंग्रेजी शिक्षा को भारत के गुरुस्थानीय छिल। और यही नहीं कि केवल घटनाचक्र में पड़कर अंग्रेजों के अनुगामी बंगाली को अंग्रेजी शिक्षा लेनी पड़ी हो, बंगाल के अन्यतम भाषातत्त्वविद् डा० चटर्जी ने उसी शिक्षा की आवश्यकता बतलाते हुए कहा है—“इंग्रेजी के बाद दिया गया कौन भाषा के ताहार स्थाने बसाइते गेले ग्रामादेर मानसिक क्षति घटिते।” इतना बड़ा चढ़ा अंग्रेजी के प्रति इनका प्रेम है कि उसके स्थान पर अन्य किसी भाषा को रखने से मानसिक क्षति की संभावना है। ऐम शब्द उसी व्यक्ति के मुँह में निकल सकते हैं जिसकी परमुखापेक्षिता चरम सीमा को पहुँच चुकी हो। (१९३६)

## भाषा और साहित्य में पाकिस्तान

राष्ट्रभाषा को लेकर बहुत दिनों से विवाद चल रहा है। हिन्दीभाषी कहते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा होगी। उरदू भाषी लोग बंगला को राष्ट्रभाषा बनाने में लगे हुए हैं। उर्दू भाषी लोग उर्दू का भारत की 'आम फ़हम' और 'मुस्तार्ज ज़बान' मानते हैं। कांग्रेस के नेता कहते हैं, देश की 'कॉमन लैंग्वेज' हिन्दुस्तानी है। हिन्दुस्तानी नाम की कोई भाषा है या उस भाषा की अभी जन्म लेना है, यह स्पष्ट नहीं है।

राष्ट्रभाषा के बारे में इनकी बातें सुनकर लगता है कि हमारा भी एक राष्ट्र है। राष्ट्र के गठन के समय में कोई अडचन नहीं है, इंग्लिश राष्ट्रभाषा की समस्या उतनी महत्वपूर्ण हो गई है। किन्तु कुछ दिनों में देश में एक 'पाकिस्तान' की चर्चा होने लगी है। कांग्रेसियों को देखते में लगता है कि 'पाकिस्तान' हम-परिहास का विषय बना हुआ है। आश्चर्य की बात यह है कि जिन्होंने देश के अन्दर एक नये पाकिस्तान की रूपना भी है, वे उर्दू की भी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं।

मुस्लिम लोग के नेता यह आन्दोलन करते हैं कि कांग्रेसी नेता उर्दू के शत्रु हैं और उनका उद्देश्य केवल हिन्दी-प्रचार करना है। हमारे पहले मुस्लिम लोग के यही नेता कहते थे कि देश की राष्ट्रभाषा उर्दू है। अब उर्दू-प्रचार में अड़चनें देखकर या अड़चनों की कल्पना करते उन्होंने तय कर लिया है कि उनकी भाषा राष्ट्रभाषा न होगी, इसलिए राष्ट्र भी वापस न रहेगा। तब यह पाकिस्तान की चर्चा बोरा राजनीतिक आन्दोलन है या उसका और भी कोई आन्तरिक महत्व है? पाकिस्तान का 'गुल' खिलते देखकर अनेक मुसलमानों का चिन्तन चल हो उठा है। इस भारत-उद्यान में यह 'गुल' क्या अत्यन्त तुच्छ और निरुप्य खाद्य पदार्थ ही नहीं खिला है? साहित्य और भाषा में मुसलमानों ने जो आन्दोलन छेड़ दिया है, उसे देखकर लगता है कि इन विप्लव की जड़ें धरती में बहुत गहरी चली गई हैं।

मध्य भारत में बहुत दिनों से हिन्दी और उर्दू का विवाद चलता रहा है। लगनऊ और दिल्ली को मुस्लिम संस्कृति का केन्द्र कहा जाता है। इस कारण

देश के इस भाग में दरबारी सभ्यता के साथ भारत की एक अन्य व्यापक और अधिक प्राचीन सभ्यता का सघर्ष स्वाभाविक हो गया। किन्तु हिन्दीभाषी समझते हैं कि इस तरह का सघर्ष उन्हीं के साहित्य में पाया जाता है, अन्य प्रांतों में भाषा-सम्बन्धी कोई समस्या है, ऐसा उन्हें नहीं माना जाता। किन्तु वर्तमान काल में अन्य प्रांतों में भी भाषा को लेकर सघर्ष चल रहा है, वह सघर्ष चाह तोड़ हो, चाहे धीमा हो, उसके अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता। बंगला के हास्य-रसात्मक पत्रों में भाषा को उर्दू का नया लिवास पहनाने की बात लेकर अनेक व्यंग्य प्रकाशित हुए हैं। किन्तु मौलवी फजलुलहक का मन्त्रि-मण्डल कायम होने के बाद बंगला भाषा को विवृत करने की चेष्टा और जोरों से होने लगी है। अब वह चर्चा हास-परिहास का विषय नहीं रह गई। देश में आन्दोलन द्वारा उसका प्रतिहार आवश्यक हो गया है।

बंगाल-साहित्य-सम्मेलन में डॉ० मुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय ने इस बारे में कई बातें कही हैं। उन सब पर विचार करने से भाषा समस्या की गम्भीरता समझ में आ जाती है। आजकल के अरबी फारसी प्रेमी अनेक मुस्लिम नेताओं की तुलना में भारत के आदि मुस्लिम आश्रमणकारी भी इतने साम्प्रदायिक नहीं थे। डॉ० चट्टोपाध्याय ने कहा है, “वे बुतशिकन या मूर्तिध्वसी थे, किन्तु जवान-शिकन या भाषा-ध्वसी वे नहीं थे।” उन्होंने कलमा मूल भाषा में प्रकाशित न करके उसका अनुवाद देशी भाषाओं में प्रकाशित किया था। किन्तु आज साम्प्रदायिकता इतनी प्रबल हो गई है कि कलमा तो दूर निहार, साहित्य को कलमे की भाषा में लिखने का प्रयत्न हो रहा है।

तुर्की में अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार हुआ, फारसी से अरबी शब्दों का बहिष्कार हुआ, यह सब साम्प्रदायिक मुस्लिम नेताओं को दिखाई नहीं देता। वे ‘पैन इस्लामिज्म’ की बातें करते हैं। किन्तु अन्य मुस्लिम देशों की राह छोड़कर उन्होंने अपनी नई राह पकड़ी है, यह बात वे भूल जाते हैं। भाषा के अलावा भावों में भी साम्य होता है। भारत के साम्प्रदायिक नेता, भाव और भाषा दोनों ही क्षेत्रों में, अन्य स्वाधीन मुस्लिम राष्ट्रों से एकदम अपरिचित हैं। डॉ० चट्टोपाध्याय ने बंगाल में यह भाषा-ध्वसी कुचेष्टा देखकर सखेद कहा है, ‘पश्चिम के मुसलमान लेखकों में अन्धाधुन्ध भाषा में अरबी फारसी शब्द भरने की प्रवृत्ति को रोकने की बात चली है। क्या केवल बंगला भाषा में उस रीति को नया रूप देकर ग्रहण किया जायगा और पाँच करोड़ से ऊपर जनता की दुर्लभ भाषागत एकता को स्वेच्छा से विनष्ट कर दिया जायगा?’

मध्य भारत में उर्दू को सहज और सरल बनाने के लिए उम अरबी फारसी के शब्द जाल में मुक्त करने के लिए आन्दोलन हो रहा है। इस आन्दोलन के सूत्रधारों में अनेक प्रगतिशील लेखक हैं। वे कोशिश कर रहे हैं कि साहित्य यथाम्भव जन-साधारण के लिए बोधगम्य हो। लाक्षणिक सुबाध साहित्य रचने के लिए उम अरबी फारसी के कठिन शब्द जाल से मुक्त करना ही होगा।

सभी लोग प्रयत्न करते हैं कि उनकी भाषा का प्रसार हो। किन्तु अन्य साम्प्रदायिकता का जाल अरबी फारसी के शब्द समेटकर बहुसंख्यक जनता के लिए भाषा को दुर्बोध बना देता है। इस तरह का प्रयत्न मुस्लिम साम्राज्य के वैभव के दिनों में न हुआ था। आज वह प्रयत्न इतना समर्थ क्यों हो गया है ?

मुस्लिम साम्राज्य में पुराने हिन्दी-साहित्य का चरम विकास हुआ था। तुलसीदास, सूरदास आदि कवि उसी युग में हुए थे। और उस युग के साहित्यिक थे रहीम, रसखान जैसे मुसलमान कवि। वे हमारे देश के, हमारी भाषा के कवि हैं। क्या उनकी रूपाति किसी भी मुसलमान लेखक के चाहने योग्य नहीं है ? सर इकबाल का हम नाम सुनते हैं। रहीम के दोहे और रसखान के छन्द गांवों के हिन्दू और मुसलमान दोनों के ही कंठ में बसे हुए हैं। क्या वह लोकप्रियता पाकिस्तान के जन्मदाता के लिए दुष्प्राप्य नहीं है ? मुस्लिम साम्राज्यकाल में मुस्लिम साहित्यकार अपनी भाषा में अपना कोई स्मृतिचिह्न न चाहते थे। साम्राज्य का नाश होने पर अनेक लोगों के हृदय में यह इच्छा हुई कि बीते वैभव का एक सांस्कृतिक चिह्न सुरक्षित कर लिया जाय। उर्दू भाषा का विकास तभी सम्भव हुआ जब मुस्लिम साम्राज्य का अघ पतन आरम्भ हो गया। उस युग के साहित्य में सामाजिक और राजनीतिक पतन के अनेक लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। जन-साधारण की भाषा छोड़कर दरबारी साहित्यकारों ने एक नई दरबारी भाषा का आविष्कार किया। उसे खूब मार्जित करके उन्होंने उसे अपना सांस्कृतिक चिह्न मान लिया। भाषा में ऊपरी चमक दमक थी। किन्तु उस भाषा में देश के प्राणों की गूंज नहीं थी। कविता का प्रधान गुण हो गया चमत्कार-प्रदर्शन। उस चमत्कार-प्रदर्शन की भाषा हुई उर्दू। इस चमत्कार-प्रियता ने ही सर्वनाश की राह दिखाई। इस सर्वनाश से कोई भी 'चमत्कार' उनका उद्धार न करेगा, यह बात उनके दिमाग में नहीं आई। ईरान की पतनकालीन साहित्यिक परम्परा को अपनाकर मुसलमान दरबारी कवियों ने अपने साहित्य का विकास किया। आज अरबी फारसी शब्दों का मोह त्यागने की बात आने पर उन्हें लगता है कि उनके गौरव का इतिहास नष्ट हो जायगा। मुस्लिम साम्राज्य के वैभवकाल में मुसलमान साहित्यकारों ने लोकभाषा का व्यवहार करके कितनी शक्ति प्राप्त की, यह बात इनके दिमाग में पैठती ही नहीं।

देश में जो लोग पाकिस्तान चाहते हैं, वे पाकिस्तान लेकर भी सन्तुष्ट न होंगे। वे अब भी विगत साम्राज्य की मधुर स्मृति में निमग्न हैं। उनकी समझ में उस स्मृति के साथ अरबी-फारसी शब्दों से लदी हुई भाषा का कोई आध्यात्मिक सम्बन्ध है। इसलिए राजनीति में जो पाकिस्तान के समर्थक हैं, वे भाषा का भी विभाजन करने को तैयार हैं। वे सोचते हैं कि उनकी नई भाषा समय बीतने पर देश की अन्य भाषाओं पर अपना आधिपत्य कायम कर लेगी। इसीलिए अरबी-फारसी सत्त्वृति को आधार बनाकर उन्होंने भागत की अनेक भाषाओं में विष्णुस-कार्य आरम्भ कर दिया है।

हमने अरबी, फारसी या अन्य विदेशी शब्दों का बहिष्कार किया हो, ऐसा नहीं है। हिन्दी-साहित्य की लाक्षप्रिय और धर्मग्रन्थ के समान पूजनीय पुस्तक रामायण में अनेक विदेशी शब्द हैं। हिन्दी के किसी भी उत्तरदायी साहित्यकार ने कभी यह नहीं कहा कि हमारी भाषा केवल संस्कृत शब्दों के लिए समर्थ बनेगी। लेकिन अम्याभाविक रूप से हिन्दी में अपरिचित शब्द भरने में विरामयम भग होगा, यह बात भूलना न चाहिए। भारत की अधिकांश भाषाओं का एक सामान्य सांस्कृतिक आधार है। चाहे परिश्रम में लोण हिंदी, बँगला, मराठी आदि भाषाएँ समझ लें, कारण यह कि इन भाषाओं में बहुत से शब्द सामान्य हैं। देश की एका के सूत्र में बांधन के लिए भाषा की यह एकता प्रधान माधन है। अपनी बुद्धि से अनेक जन इस एका पर आधारित कर रहे हैं किन्तु जितना आधार चरेगा, उतना ही देश की भाषाओं का परस्पर साम्य-बोध और भी दृढ़ होगा। तभी देशवासी इस राष्ट्रघातक प्रयत्न को समूल नष्ट कर देंगे। (१९४१)

## हिन्दी गद्य-शैली पर कुछ विचार

आज से लगभग सत्तर वर्ष पहले भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने नये हिन्दी गद्य की व डाली थी। वैसे ब्रजभाषा से भिन्न नई हिन्दी लिखने का प्रयास और भी हुंले आरम्भ हो गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि अब तक नये हिन्दी गद्य सौ वर्ष बीत चुके हैं और अब इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि आदर्श गद्य के लिए हम एक साफ-सुथरी शैली बना सकें हैं या नहीं। हिन्दी गद्य विकास में जो दो-तीन मार्ग-चिह्न स्पष्ट दिखाई देते हैं, उनमें सबसे पहले तो आधुनिक हिन्दी के जन्मदाता भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र और उनके सहयोगियों ने हिन्दी गद्य-शैली पर एक अभिष्ट छाप डाली है। इस शैली पर विचार करते हुए हमें सभी आलाचक मानते हैं। पहली तो यह कि इसमें एक ऐसी जिन्दादिली का बाद के गद्य में प्रायः नहीं मिलती। दूसरी यह कि इस भाषा में परिष्कार की जरूरत है और अपने तात्कालिक रूप में वह शैली आज ग्रहण नहीं की जा सकती।

इन दोनों बातों पर कुछ ठहरकर विचार करना आवश्यक है। भारतन्दु-युग के लेखकों की शैली में जिन्दादिली क्या है और बाद के गद्य में वह लोप क्यों हुआ है? इसका कारण कुछ लोग यह बतलाते हैं कि भारतेन्दु और उनके सहयोगी बहुत गम्भीर चीजें न लिखते थे। इसलिए उनकी शैली में हँसी-मजाक की आड़ में ज्यादा रहनी थी। आगे चलकर हमारी शैली में भाव-गाम्भीर्य आया और इसलिए यह ज़रूरी हो गया कि इस गहराई में जिन्दादिली डूब जाय। एक बात ध्यान देने की यह है कि भारतन्दु-युग के लेखक इस पीढ़ी के लेखकों की तुलना में संस्कृत के अधिक निपट थे। उनके सामने हिन्दी गद्य की कोई विकसित परम्परा न थी और इसलिए होना तो यह चाहिए था कि संस्कृत के शब्दों का भरमार से उनकी शैली में भिन्न बन जाती, लेकिन हुआ इसके उल्टा ही। इसके बिना यह बात भी सही नहीं है कि उस युग में गम्भीर आलोचना नहीं लिखी गई। उस युग के साहित्य में जो जिल्दों में सैकड़ों सुन्दर आलोचनात्मक निबन्ध आज भी सुरक्षित हैं। (यानी जहाँ उन्हें रहीं में बेच नहीं डाला गया या जिल्दों में दीमक नहीं रग गया।) उनका मकलन करके अब नये विभी ने उन्हें प्रकाशित

नहीं किया, इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे प्रकाशकों को है। उन निबन्धों में आज के बहुत ही मामूली आलोचनात्मक निबन्धों की तुलना की जाय तो दोनों की शैली का भेद मालूम हो जायगा। उस समय के अधिबन्त लेखक यह कोशिश करते थे कि कठिन और दुरूह बातों को भी आमानी में समझा दें। आज के काफी लेखकों की यह कोशिश होनी है कि साधारण बातों को भी असाधारण शब्दावली में प्रस्तुत करके अपने निबन्धों को गम्भीर बना दें।

यह सही है कि भारतेन्दु-युग की गद्य-शैली में परिष्कार की जरूरत थी। लेकिन यह जरूरत इतनी बड़ी नहीं जितनी कि लोग समझने हैं। बालकृष्णभट्ट के निबन्ध, भारतेन्दु के नाटकों में वार्तालाप, राधाचरण गोस्वामी के प्रहसन—इनमें बहुत परिष्कार की गुंजाइश नहीं है। उसके अलावा जो परिष्कार आप करेंगे, वह कुछ शब्दों को लेकर होगा, वाक्यरचना, शब्दों के चुनाव, शैली के प्रवाह आदि में इसमें ज्यादा अन्तर न पड़ेगा। यानी भारतेन्दु-युग का कोई सचेत लेखक व्याकरण की दो-चार अनुद्वियाँ बराता हुआ गद्य लिखता तो उसकी जिन्दादिली में ज्यादा पर्व न पड़ता। इसलिए जिन्दादिली का सबसे साहित्य का हल्कापन नहीं है। अगर ऐसा हो तो हल्केपन के डर में कोई भी जिन्दादिल लेखक साहित्य की दुनिया में पैर ही न रखे।

भारतेन्दु-युग की गद्य-शैली पर छोड़ा और विचार करने में उसकी कुछ ऐसी विशेषताएँ सामने आती हैं जो बाद के गद्य में, विशेषकर सन् '२० से सन् '४० तक के गद्य में, कम मिलती हैं। पहली विशेषता यह है कि इन लेखकों के मन में शब्दों का चुनाव करते हुए किसी तरह के निषेध का विचार आड़े नहीं आता। द्विवेदा-युग में हमारे भीतर एक निषेध-भावना घर कर गई थी—एक शब्द को हम जानते हैं, बातचीत में उसका प्रयोग भी करते हैं लेकिन गद्य में उसे लिखें या न लिखें, यह प्रश्न बार-बार लेखकों के सामने आता था। भारतेन्दु-युग के लेखकों ने नई हिन्दी का रूप सँवारते हुए बँगला और संस्कृत की ओर भी ध्यान दिया, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उन्होंने उस बोलचाल की भाषा पर दिया जो नित्य ही उनके कानों में पड़ती थी। भारतेन्दु-युग की गद्य-शैली का आधार बोलचाल की भाषा है। उस समय के निबन्धों को पढ़िये तो यह नहीं लगता कि उन्हें किसी ने लिखा है। ऐसा मालूम होता है कि लेखक हमसे बातें कर रहा है और हम छापे के अक्षरों में भी उसकी आवाज सुनते जाते हैं। द्विवेदी-युग में परिष्कार के बहाने गद्य-शैली का आधार बदल दिया गया। अनेक लेखकों ने बोलचाल की भाषा से बार-बार बचने की कोशिश करते हुए शुद्ध साहित्यिक हिन्दी को अपनी शैली का आधार बनाया।

बोलचाल की भाषा को आधार बनाने से ही भारतेन्दु-युग के लेखक अपनी शैली में एक बहुत ही बलवती आहिवा शक्ति पैदा कर सके थे। वे जिस शब्द को भी चाहते थे, उसे हिन्दी में पचा लेते थे। इस तरह वे फारसी, अरबी और अंग्रेजी के शब्दों का ही रूपांतर न कर लेते थे बल्कि हिन्दी और संस्कृत का भेद मानते

हुए संस्कृत शब्दों का रूपान्तर भी कर लेते थे। हमारी ग्रामीण भाषाओं में यह प्रवृत्ति है कि संस्कृत के शब्द अपने सरल तद्भव रूप में काम में लाये जाते हैं। भारतेन्दु-युग के लेखकों ने अपनी शैली में इस प्रवृत्ति को उभारा। उन्होंने तद्भव शब्दों का बहुलापन में प्रयोग किया, इसके अनायास ग्राम-भाषाओं से भी जहाँ तक हो सका शब्द सीधे और इस तरह नई हिन्दी को समृद्ध किया। आगे चलकर यह प्रवृत्ति बदल गई। संस्कृत शब्दों के तद्भव रूप पर जोर देने के बड़ने हम तद्भव शब्दों को भी तत्सम रूप देने लगे।

यहाँ पर हिन्दी-भाषा के मौलिक विकास पर दो शब्द कहना अमंगल न होगा। ५० धर्मनाथ भा अक्सर कहते सुने जाते हैं—“मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है परन्तु संस्कृत-गर्भित होने के कारण हिन्दी देश के अधिकांश भाग में बोली और समझी जाती है।” इस तरह की बातें मभा-ममाज में आये दिन हम दूसरों के मुँह से भी सुना करते हैं। यह बिल्कुल सही है कि हिन्दुस्तान के अधिकांश भाग में हिन्दी बोली और समझी जाती है। देश की ओर किसी भाषा को यह गौरव प्राप्त नहीं है। लेकिन ‘हाथ बगन को भारभी क्या?’ बलवत्ता की हरीसन रोड या बम्बई के परेल में उन लोगों की बोली मुनिशे जिन्होंने हिन्दी को वास्तव में यह गौरव दिया है। इनकी बोली हुई हिन्दी का रूप ५० धर्मनाथ भा की संस्कृत-गर्भित अ-मातृभाषा हिन्दी से बहुत भिन्न है। भा महोदय के लिए शक्य है कि मातृभाषा न होते हुए भी वह हिन्दी को उसके किसी भी रूप में बोल लेते हैं लेकिन जो लोग हिन्दी को मातृभाषा मानते हैं, उन्हें तो अपनी भाषा के उस रूप की रक्षा करनी चाहिए जो सचमुच उनके आये दिन के व्यवहार में प्रकट होता है।

संवत् १०० से लेकर संवत् २००० तक हिन्दी का विकास किस प्रकार हुआ है? हिन्दी-भाषा की भागीरथी हिमालय में समुद्र की ओर बही है या समुद्र से हिमालय की ओर? गोस्वामी तुलसीदास, भारतेन्दु और प्रेमचन्द ने हिन्दी के संस्कृत रूप को संवारा है या उसके प्राकृत रूप को? यदि यह दावा सच होता कि भारतीय भाषाओं की एकता का आधार संस्कृत के तत्सम शब्दों का समान रूप से प्रयोग है तो बँगला, गुजराती, हिन्दी, मराठी आदि-आदि भाषाओं का अलग-अलग विकास बिल्कुल अस्वाभाविक होता। इतिहास की माँग कुछ और थी, भाषा विज्ञान के प्राचायों की माँग कुछ दूसरी है। गुजराती, मराठी, बँगला, हिन्दी आदि भाषाओं का अलग-अलग विकास इसलिए हुआ है कि इन भाषाओं ने अपने प्राकृत रूप को संवारा है। उन्होंने तत्सम शब्द भी लिए हैं और साहित्य-रचना में विशेष रूप से लिये हैं लेकिन बँगला, हिन्दी या मराठी की जानीयता, उसका विशेष रूप, उसका बोवपन या वह भवेगपन जिसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास ने किया था, संस्कृत शब्दों के प्रयोग के कारण नहीं है। भाषा की भागीरथी प्राकृत रूप समुद्र की ओर ही बह रही है, संस्कृत रूप हिमालय की ओर नहीं। हिमालय की बर्फें धूल-धूलकर जब सजल बन



"आतिर थाप रमणी हैं न ? जिग दिन थाप कमल-नृगुम के समान यम-मान सामाजिक पानी की तह से ऊपर उठ आएंगी, उग दिन यह कह देगी कि त्यागवाद महान् नहीं हो सकती । जिग त्याग का झिंदोरा पीटा जा रहा है वह या तो समाज में इस समय जो धर्म प्रचलित है उस धर्म के भय से बिया जा रहा है या वह समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने के लिए किया जाता है । सारे दान पुण्य, सत्कर्म बड़े जानेवाले यामें इन्ही दो कारणों के परिणाम हैं । सारा सामाजिक संगठन अर्थज्ञानिक नहीं है । जो चीज वैज्ञानिक नहीं है, वह महान् हा ही नहीं सकती । मिस विमना, इस युग के दो सबसे बड़े तत्त्ववेत्ता हैं—कार्लिन और कार्ल मार्क्स । दोनों ग्रहणवादी हैं ।"

चाईस साल की लहकी के धीरज की प्रशंसा करनी होगी । लगभग पूरा पृष्ठ सुन जाती है और एक बार भी उस चौकीम माल के युवक को नहीं टोरती । नीतिराज ने भी, मालूम होता है, कालेज में हिन्दी के नाटक ही पढ़े हैं । इसलिये विमना से कहता है—"आतिर थाप रमणी हैं न ।' क्या ही अच्छा हो कि कालेज के लड़के सहपाठिनी विद्याधिया के लिए ऐसे ही सुन्दर शब्दों का प्रयोग किया करें । 'सामाजिक पानी की तह' से ऊपर उठाना भी कमात है । एक वाक्य में नीतिराज सर्वनामों का प्रयोग भूल गया है इसलिए 'जो धर्म प्रचलित है उस धर्म के भय से,'—बार-बार धर्म की दुहाई देने लगता है । 'समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करना' आदि ऐसे टुकड़े हैं जो नाटक की वाक्य रचना में ठूँठ-जैसे खड़े हैं । नीतिराज ने कार्लिन और कार्ल मार्क्स को ही पानी नहीं दिया, बोलचाल की हिन्दी पर भी पानी फेर दिया है ।

नाटकों में इस तरह की शैली ज्यादा दिन नहीं चल सकती । पाठ्य-क्रम में शामिल करने पर भी इस तरह के नाटक हिन्दी के रंगमंच का उद्धार नहीं कर सकते ।

मालोचना में गम्भीर चिन्तन के नाम पर हर तरह की वाक्य-रचना क्षम्य समझी जाती है । एक उदाहरण देना ही काफी होगा । 'सामाजिक शक्ति के संगठन में परस्पर-विरोधी शक्तियों का संघर्ष होता है, साहित्य उसका सजीव चित्रण कर यह स्पष्ट कर देता है कि उसमें वह शक्ति रूप से भाग ल रहा है और यह कि वह सामाजिक संगठन एक स्थिर वस्तु नहीं है, बल्कि गतिमान और परिवर्तनशील है ।' इस बात को और भी सरल ढंग से कहा जा सकता था और इस तरह का वाक्य रचने के लिए गम्भीर चिन्तन की दुहाई नहीं दी जा सकती । वाक्य के व्यंग्योपन का कारण गम्भीर चिन्तन नहीं, अंग्रेजी के 'that' का भद्दा अनुवाद है 'यह कि वह' ।

संक्षेप में हिन्दी की गद्य शैली को सँवारने के लिए वाक्य-रचना पर ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है । लिखते समय हम वाक्यों का सुनते भी जाएँ या तिल गने पर उन्हें जोर से पढ़कर सुनें सुनाएँ जिससे कि उनका अस्वाभाविक प्रवाह तुरन्त मालूम हो जाय और हम उनमें आवश्यक सुधार कर सकें । इसके

मिलावा मसार की हर भाषा के पुष्ट गद्य का आधार ग्राम जनता की बोलचाल की भाषा रही है। हमें अपनी गद्य शैली को सबल और समर्थ बनाने के लिए फिर यही आधार कायम करना है। ऐसा करने से हिन्दी भारत की दूसरी भाषाओं से दूर न जा पड़ेगी। यह भय इसलिए पैदा होता है कि हम भारतीय भाषाओं के विकास को ही गलत समझ बैठते हैं। यह विकास मस्कृत की ओर नहीं लौट रहा है बल्कि तद्भव रूपों को अपनाता हुआ भाषा के प्राकृत रूप की ओर बढ़ रहा है—प्राकृत, अपने मौलिक और व्यापक अर्थ में। भारतन्दु और प्रेमचन्द की शैली इसी विकास की ओर सकेत करती है। हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता हिन्दी बोलती है या उसे समझती है। लेकिन हम अपनी गद्य-शैली को उस जनता के बोलने समझनेवाले रूप से बहुत दूर ले आए हैं। इस तरह हिन्दी लोकप्रिय नहीं बन सकती। मादरता फैलने पर यह गद्य शैली बदलेगी। नई पीढ़ी के लेखकों पर विशेष रूप से यह भार है कि वे अपनी शैली को इस तरह गढ़ें कि शिक्षा-प्रसार में उसमें सहायता मिले और देश की कोटि-कोटि जनता के सम्पर्क से वे स्वयं भी अपनी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाएँ।

(१९४७)

## राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दू राष्ट्रवाद

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की माँग कुछ नई नहीं है। भारतेन्दु ने केवल अब तक इस माँग का आधार यही रखा है कि हिन्दी जनता की भाषा है; बोलने, लिखने और समझने में यह सरल है, हिन्दुस्तान की अधिकांश जनता अभी भी उसे बोलती और समझती है। अपनी माँग को पुष्ट करने के लिए हिन्दी-भाषियों ने जनता को अपनी कसौटी बनाया था। उन्होंने राष्ट्रभाषा की समस्या का जनतात्रिक ढंग से ही सुलझाने का प्रयत्न किया था। लेकिन इधर कुछ वर्षों से यह परिस्थिति बदल रही है। साहित्य-सम्मेलन के मंच से हिन्दी-हिन्दुस्तान का नाग लगाकर अपनी भाषा के प्रसार का गंभीर करने और उसके सङ्गठन विकास को रोकने का प्रयास किया गया है। एक तरफ तो हम गवर्नर के साथ कहते रहे हैं कि हिन्दी आम जनता की भाषा है जिसके बोलने-वाले सभी जातियों और धर्मों के लोग हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रीयता के नाम पर साम्प्रदायिकता का जहर फैलानेवाला यह नया हिन्दू राष्ट्रवादी दल भाषा को धर्म के साथ जोड़कर हिन्दी को जनता की भाषा के पद से हटा देना चाहता है। ऊपर से देखने में मालूम होता है कि ये हिन्दू राष्ट्रवादी हिन्दी के समर्थक हैं, जो उसका प्रसार और विकास चाहते हैं, वास्तव में इनके बड़ा शत्रु हिन्दी का कोई दूसरा नहीं हो सकता। राष्ट्र की तरह भाषा का विकास भी जनतात्रिक आधार पर होता है, जनता की उपेक्षा करके फासिज्म को आधार बनाने पर राष्ट्र की तरह भाषा का भी सत्यानाश होना अनिवार्य है। हिन्दी का सत्यानाश करना तो विघाता के लिए भी बठिन होगा। विघाता की इच्छाओं के एकमात्र टीकाकार ये हिन्दू-राष्ट्रवादी उनके विकास में कुछ देर के लिए बाधा जहर डाल सकते हैं।

राष्ट्रभाषा के साथ हिन्दू-राष्ट्रवाद के गठबन्धन को सबसे ताज़ी मिसाल श्री रविशंकर शुक्ल की लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है—‘हिन्दीवालो, सावधान !’ ‘इस्लाम खतरे में है’ की तरह लेखक ने हिन्दू-धर्म खतरे में है, कहकर हिन्दीवालों को सावधान करने की चेष्टा की है। जहाँ-जहाँ ‘इस्लाम

'नरें मे है' का नारा लगाया गया है, वही-वही गाबिन हो चुका है कि इस्लाम  
 बदले किसी की जमीन-जायदाद ही गलतरे में यो जिंगे बचाने के लिए यह  
 नरें की घटी बजाई गई थी। इस बहाने जायदाद की हिजाजत हा नही पाती  
 और जनता इस ठग विद्या को पहचानकर जायदाद की जंग गरके ही हम मेनो  
 । लेकिन ने इतिहास की गांधी न मानकर मुले-धाम धर्मग्रन्थता को आदर्श  
 मानकर समके पीछे चलने की मिथारिग की है। प्रत्येक हिन्दू-राष्ट्रवादी ऊपर  
 स जिन्ना का विरोधी होने हुए भी हृदय में उसी की अपना आदर्श मानता है।  
 कांग्रेस और देश के स्वाधीनता सपना के बारे में यह लोग के प्रतिनिध्यावादी  
 नेताओं के समान ही भूठा प्रचार करता है। रविगजर पुक्क का अभियोग है  
 कि कांग्रेस ने हिन्दुओं के माथ 'घोर विश्वासपात्र किया है।' (हिन्दी-ज्ञान,  
 माधवान'; परिशिष्ट, पृ० ६७)। हिन्दुओं का विश्वासपात्रता कोई हिन्दू  
 जिन्ना ही हो सता या लेकिन लेकिन के दुर्भाग्य से 'हिन्दुओं का ऐसा कोई नेता  
 नहीं है जो मि० जिन्ना से टक्कर ल गये।' (उप०) हिन्दुओं में ऐसा नेता पैदा  
 करने के लिए जरूरी है कि हर हिन्दू के हृदय में राष्ट्रीयता की परम्परा को  
 निमल कर दिया जाए। इसलिए कांग्रेसी नेताओं के लिए लेकर ने यह दावा किया  
 है कि उन्होंने 'जन्म-भर मनसा, बाबा और बर्मणा यह सिद्ध करने को चेष्टा  
 की है, और और भी कर रहे हैं, कि वे हिन्दू नहीं हैं।' (उप०) कांग्रेस पर  
 अहिन्दू होने का अभियोग लगाने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि कांग्रेस की प्रेरणा  
 से जो जनवादी परम्परा कायम हुई है, उसमें निहित स्त्राओं की रक्षा की जाए।  
 इस हिन्दू प्रेम के पीछे पूँजीवाद और जमींदारी प्रथा का प्रेम छिपा हुआ है जो  
 लेखक ने इस तरह की दलीलें पेश कराता है—पं० नेहरू को हिन्दुस्तान के नाम  
 से चिढ़ है क्योंकि उसमें हिन्दू नाम जुड़ा हुआ है। इसलिए वह चाहते हैं कि  
 देश को 'इंडिया' ही कहा जाए और इस मामले में गांधीजी 'उनकी पीठ थपथपा  
 रहे हैं' (परिशिष्ट, पृ० ६८)। पं० नेहरू के भाषणों को जनता भी सुनती है  
 और वह अच्छी तरह जानती है कि वे इंडिया शब्द का प्रयोग क्यों हैं या  
 हिन्दुस्तान का। लेकिन फासिज्म का आधार झूठ होना है और हिन्दू-राष्ट्रवाद  
 एक फासिस्ट विचारधारा है।

हिन्दू और मुस्लिम प्रतिप्रियावादी एक-दूसरे के कितने निकट हैं, इसकी  
 एक मिमाल देखिए। दोनों ही नेहरू-सरकार की एक हिन्दू सम्प्रदायवादी सरकार  
 के रूप में चलना करते हैं। फर्क इतना ही है कि मुस्लिम प्रतिप्रियावादी उसे  
 हिन्दू सरकार पहने से ही मानते हैं और उनके हिन्दू भाई उसे ऐसी बनाना  
 चाहते हैं। पुक्कजी कहते हैं कि 'हमारा सत्तार नेहरू सरकार को हिन्दू सरकार  
 बनाना और गमभूता है—जबकि वास्तव में अर्थात् अन्त में वह हिन्दू सरकार  
 नहीं है। ऐसी भाति का कारण नहीं रहने या भविष्य में उत्पन्न होने दिया जा  
 सकता। (उप०) सारे सत्तार में चर्चिन और उनके पिछू ही ऐसा प्रचार  
 करते हैं और बी० बी० गो० दुनिया-भर में विज्ञापित करती है कि पं० नेहरू

को हिन्दू सरकार मुसलमानों का नाश कर देना चाहती है। लेकिन मसाल में सब चर्चित, पीरोज खाँ नून या उनके हिन्दू नन्हाल (रविशंकर शुक्ल जैम) ही नहीं है। दुनिया का हर जनतन्त्रवादी न तो नेहरू सरकार को एक हिन्दू सम्प्रदायवादी सरकार मानता है और न उसे होन देना चाहता है।

हिन्दू राष्ट्रवाद की खुली घोषणा इस प्रकार है—

‘हिन्दुस्तान एक हिन्दू राष्ट्र हो जिसका राज-धर्म हिन्दू धर्म हो और जिसमें सब प्रमुख पदों पर हिन्दुओं और प्रमुस्लिमों की नियुक्ति हो। ऐसा कोई व्यक्ति जो स्पष्ट रूप से हिन्दू धर्म न मानता हो, हिन्दुस्तान सरकार का प्रधान नहीं हो सकता।’ (उप०) स्पष्ट रूप से हिन्दू धर्म मानने का मतलब क्या है? यह कि जो मुसलमानों को हिन्दुस्तान में रहने दे, वह पूरा हिन्दू नहीं है। “इस्लाम धर्म के किसी अनुयायी को हिन्दुस्तान में नागरिकता के अधिकार नहीं मिल सकते” और “अल्पसंख्यक के किसी भूटे नाम पर पाकिस्तान के फिफथ कॉलम को स्वच्छन्द नहीं छोड़ा जा सकता” (पृ० ६६)। यह है सच्चे हिन्दूपन की कमीटी! अगर सही नीति धर्मान्ध है तो क्या हम नहीं हो सकते? अगर वे एक बार बुद्धि में गिरे हैं तो हम सो बार गिरेंगे। हिन्दू राष्ट्रवाद की बीरता इसी प्रकार की है।

इस हिन्दू राष्ट्रवाद की भाषा के शब्दों में लागू करना मुश्किल नहीं है। जैसे हिन्दुस्तान का हर मुसलमान पाकिस्तान का फिफथ कॉलम है, वैसे ही हिन्दी में आया हुआ अरबी-फारसी का हर शब्द फिफथ कॉलम है, जिसे निकाल बाहर करना चाहिए। बात कुछ बहुत मौलिक नहीं है क्योंकि मराठी में भी सावरकर भी यह काम कर चुके हैं। उन्हें सफलता कितनी मिली है, यह मराठी का कोई अक्षर उठाकर देख लीजिए।

कठिनाई तब पैदा होती है जब जनता के व्यवहार का प्रश्न सामने आ जाता है। हिन्दू राष्ट्रवादियों के दुर्भाग्य से इस देश की जनता हिन्दू-मुसलमान शब्दों की पहचान नहीं कर पाती। फल यह होता है कि इस जनता से प्रेरणा पाने वाले कवि और लेखक भी हिन्दू-मुस्लिम शब्दों का भेदभाव भूल जाते हैं। इसलिए हिन्दू राष्ट्रवाद के इन आचार्यों ने जनता का भगडा ही खतम कर दिया है। आपने लिखा है—‘जनता तो भेड़ों के झुंड के समान है, उसे नेताओं ने जिधर हाँक दिया उधर चल दी’—‘जनता को पेटभर खाने और तनभर कपड़े के सिवाय किसी और चीज की चिन्ता नहीं होती।’ (मूल पुस्तक, पृ० ८५)।

यह तर्क भी अधिक मौलिक नहीं है। जब हिन्दुस्तान में आजादी का आन्दोलन चला, तब अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने भी यही दलील पेश की थी कि हिन्दुस्तान की आम जनता को तो खाने-पहनने से मतलब है, कुछ थोड़े से असन्तुष्ट लोगों ने उसे आजादी का नाम लेना सिखा दिया है। अगर उन्हें पकड़कर जेल में बन्द कर दिया जाय तो वह आजादी का हल्ला भी एक दिन में खत्म हो जाएगा, इस विचार के अनुसार जनता को भेड़ और अपने

को भेड़िया समझनेवालों ने काम भी किया लेकिन उमरा फन क्या हुआ, इसे सारी दुनिया जानती है। श्रीमान् रविवर शुक्ल जनता को 'लंग्रेज वांग्म' करने के फेर में स्वयं जनता की शक्ति से 'मनवांग्म' हो गये हैं। लेकिन अंग्रेज बहादुर की शक्ति पर आपका विश्वास भ्रष्ट है। भारतीय जनता तो अपनी भाषा के प्रति कभी जागरूक नहीं रही लेकिन 'भना हो अंग्रेज बहादुर का जिनने फारसी को हटाकर प्रान्तीय भाषाओं को प्रतिष्ठित किया' (पृ० ५८)। गोया साहें मँवाले ने हिन्दी का सर्वनाश करने के लिए कुछ उठा रखा था और उनकी चलाई हुई शिक्षा-प्रणाली के लिए हिन्दुस्तानियों को उनकी श्रुतज्ञ होना चाहिए। अपनी जनता को माली कि वह भड़ है और अंग्रेज के उठा लिए शाबाशी कि वह इन्माफ़सन्द है—यह है हिन्दू राष्ट्रवाद का सच्चा रूप।

हिन्दी-भाषी जनता को भेड़ियाघसान बनारस इस लेखक ने हिन्दी के बड़े-से-बड़े साहित्यिकों को भी उसमें शामिल कर लिया है। यह हिन्दी के लिए एवं की बात है कि उनके बड़े-बड़े साहित्यकारों ने बोलचाल की भाषा को अपना आधार बनाया है। रविवर शुक्ल की ममक में इस बोलचाल की भाषा को अपनाने का मतनव है उर्दू कोष को अपनाना। लिखा है—“उर्दू कोष केवल हिन्दी शब्द-सागर में ही नहीं समाया हुआ है, वह व्यवहार में भी बहुत हद तक हिन्दी पत्रों और पुस्तकों के पन्नों पर विद्यमान है, और हिन्दी के बड़े-से-बड़े साहित्यिकों की बोलचाल में भी विद्यमान है, बल्कि यों कहिए, बोलचाल में और भी अधिक प्रबल रूप से विद्यमान है” (पृ० ३)। इस बोलचाल के स्तर से वचन के लिए आपने यह बाबा-वाक्य प्रमाण रूप में रखा है—“वण्णगतेऽपि प्राणं याचनी न वदेत्।” और टीका की है—“संस्कृत की इस अक्षर पीढ़ी में आज हिन्दी है। आज हिन्दी को वही काम करना है जो संस्कृत ने, पाली ने और अपभ्रंश ने किया है” (पृ० ६)। संस्कृत की अक्षरता से अपभ्रंश कैसे पैदा हो गई, अपने अद्भुत भाषा विज्ञान का प्रकाश इस प्रश्न पर भी डाल देते तो हिन्दीवाले और सावधान हो जाते।

लेखक को हर जगह हिन्दी हारती हुई और उर्दू जीतती हुई दिखाई देती है। उर्दू की जीत का कारण उसका विमुद्धतावाद यानी हिन्दी शब्दों के बहिष्कार की प्रवृत्ति बताई गई है। अब उस विमुद्धतावाद को हिन्दी में लागू करने का हठ किया गया है। वास्तव में हार न हिन्दी रही है, न उर्दू, हार रहे हैं दोनों तरफ के विमुद्धतावादी जो दोनों को बोलचाल के असी फीसदी शब्दों के आधार पर नजदीक आते देखकर हाय हाय करके छाती पीट रहे हैं। उनका यह काम उचित भी है क्योंकि दोनों के पास आने की वे बिल्कुल नहीं रोक पाते। लेखक ने कई जगह ऐसे शब्दों की सूची बनाई है जिन्हें वह हिन्दी से निकाल देना चाहता है। पृ० २२-२३ पर ऐसे शब्दों की सूची देखने लायक है। इसमें तलाश, सूरख, वजन, शोरगुल, पैदावार, दाग, दर्द, रोशनी, हजम करना, सख्त, नजदीक, मेहमान, कमरबन्द, बीबी, दिल, बिताव, मन्दर, तरफ, इन्कार,

खरीदना, आवाज देना, खून जैसे शब्द हैं जिन्हें हिन्दू संस्कृति के लिए घातक बताया गया है। पाठक स्वयं सोचें कि हिन्दी भाषा को इन शब्दों से छतरा है या रविशंकर धुवल जैसे उसके समर्थकों से।

इन शब्दों के हिन्दी पर्यायवाची तो और भी मनोहर हैं ! किताब के लिए केवल 'पोथी' लिखना चाहिए और बीबी के लिए 'बहू'।

हिन्दीवालों को सावधान करनेवाले इन सज्जन से अगर कोई पूछे कि क्या आपने यह 'पोथी' अफीम खाकर लिखी थी तो कोई बेजा सवाल न होगा। ऐसे एक-दो नहीं पचीसो शब्द हैं जिन्हें आपने हिन्दी से निकालने की सलाह दी है लेकिन जो दूसरी जगह आपके 'लैंग्वेज कान्सस' दिमाग पर भी सवार हो गए हैं। मिसाल के लिए पृ० ३३ पर आप 'किला' शब्द निकाल देने की सलाह देते हैं लेकिन पृ० १५६ पर हिन्दी शत्रुओं का मुकाबला करने के लिए 'किने' की ही शरण ले बैठे हैं।

इसी सूची में आपने 'बच्चा' शब्द भी रखा है जिसे हिन्दी से आप विदेशी समझकर निकालना चाहते हैं। पाठकों को ऐसी अपार मूर्खता पर विश्वास न हो तो इस पुस्तक के पृ० ३४ की दूसरी लाइन देख लें। लेकिन बाहरे बच्चों, शाबाश ! पृ० १७६ पर जब लेखक महाशय हिन्दी रक्षा सभ स्थापित करने में लगे थे, तभी आठवीं पंक्ति में तुम भी आ कूदे ('हिन्दी जनता में प्रबल आन्दोलन किया जाय कि वह अपने बच्चों को... ' इत्यादि)। इसी तरह 'आबादी' का आप विरोध करते हैं लेकिन पृ० २५ पर अवध को 'आवाद' करते हैं। आदत आपको पसन्द नहीं लेकिन पृ० २७ पर आप खुद उसके 'आदी' दिखाई देते हैं। जादू वह जो सिर पर चढ़कर खोने और वह आपके ही नहीं, हिन्दी-उर्दू दोनों के विशुद्धतावादियों के सिर पर चढ़कर बोलता है। जितना ही बोलचाल के शब्दों से पर भाड़ते हैं, उतना ही वे चिपकते जाते हैं।

पृ० ४०-४१ पर एक दूसरी सूची है, उन शब्दों की जो बोलचाल में प्रचलित नहीं हैं। इनमें बगावन, कुर्बानी, गद्दार, हिमायत, उस्ताद, हमदर्दी, नाराज, नापुश, सर्दी जैसे शब्द भी हैं। पूछना चाहिए कि आप किस देश के रहने-वाले हैं जो इन शब्दों को बोलचाल का नहीं समझते। आपका दुराग्रह कितना बड़ा हुआ है, यह इस बात में जाहिर है कि आपने 'देशदूत' जैसे पत्र और वेदव बनारसी जैसे लेखक को भी—जिन पर हिन्दी उर्दू के मामले में उदार होने का कलक कभी नहीं लगाया जा सकता—उर्दू परस्तों की पंक्ति में बिठा दिया है।

आप पर प्रतिक्रियावादी होने का आरोप लगाया जायगा, यह आप पहले से ही जानते हैं। इसलिए पृ० ८३ पर आपने गर्व से घोषणा की है—'२ में एक बार नहीं सौ बार प्रतिक्रियावादी कहलाना स्वीकार है।' उसके बाद यह भी मुक्तकठ से स्वीकार किया है कि 'ये सब बातें पुनरुत्थान की भावना से प्रेरित हैं।' (उप०) बोलचाल के शब्दों के आने से आप भाषा का कृत्रिम मानते हैं, अधिक संस्कृतनिष्ठ होने से हिन्दी स्वाभाविक हो जायगी। (पृ० ८८-८९)

एक सुझाव मार्क का है। अगले प्रान्तीय चुनाव के लिए हिन्दी जनता को अभी से तैयार करना चाहिए। (पृ० १७६)। राष्ट्रवादी मुसलमानों और बाग्रेम के नेताओं पर यह विपक्षजन उस चुनाव की तैयारी का ही एक अंग है। ऐम लोगो की कमी नहीं है जो देश को जनतन्त्र की तरफ बढ़ने से रोककर साम्राज्यवाद की पाली-पोसी हुई व्यवस्था बायम रखना चाहते हैं। इनके प्रचार म एक ऐसी हिन्दी को स्थान दिया गया है जिसका भारत की जनता स यथा-सम्भव कम सम्बन्ध है। जितना सम्बन्ध हिन्दू राष्ट्रवाद का हिन्दू जनता स है, उतना ही हिन्दी के इन समर्थकों का हिन्दी से है। कलम पकड़ते चार दिन नहीं हुए कि तुलसीदास, भारतन्दु और प्रेमचन्द—सभी की परम्पराएँ उलटने को तैयार है। मानो ईश्वर के यहाँ से हिन्दी की जायदाद का बँनामा कराके लौटे है। हिन्दी के उस एक बड़े लेखक का नाम बताइए जिसने इन सिद्धान्तों को मानकर रचना की हो। भाषा के निर्माता कुछ अन्धे प्रतिक्रियावादी नहीं हो सकते। उसके निर्माता हिन्दुस्तान के करोड़ों किसान, मजदूर और साधारण लोग हैं जिनकी बोलचाल की भाषा से आपको असली खतरा दिखाई देता है। हिन्दी बोलनेवालों ने जिन शब्दों को अपना लिया है, उन्हें तमाम मुसलमानों को कल करके भी हिन्दी से नहीं निकाला जा सकता। यह सस्कृति की राम-दुहाई जनता के भय से उत्पन्न हुई है क्योंकि एक बार अंग्रेजी से टक्कर लेने के बाद यह जनता उनके देसी नक्कालों स डरकर चुप रहनेवाली नहीं है। जिस समय हिन्दी-उर्दू के कथित हिमायती एक-दूसरे को कोसते रहे हैं, उस समय यही जनता खेतों, खलिहानों और बारखानों मे एक मिली जुली भाषा गढ़ती रही है जिसकी उपेक्षा करना दोनों म से किसी के लिए भी सम्भव नहीं है। हिन्दी प्रमर है, इसलिए कि वह अपनी स्वाधीनता के लिए लड़नेवाली जनता की सजीव भाषा है।

(१९४८)



# हिन्दी का 'संस्कृतीकरण'

बहुत से लोगो का विचार है कि सस्कृत ने मृत भाषा का रूप इसलिए ले लिया कि पंडिता ने उसे व्याकरण के नियमो से जकड़ दिया था। परन्तु व्याकरण और भाषा की सजीवता में कोई ऐसा अन्तर्विरोध नहीं दिखाई देता कि सस्कृत की मृत्यु के लिए व्याकरण को दोषी ठहराया जाय। अपर आज की जीवित भाषाओ को लें तो देखेंगे कि वे व्याकरण से कम अनुशासित नहीं हैं और किसी हद तक तो उनके व्याकरण में ऐसी विशेषताएँ मौजूद हैं जो सर्वबुद्धि को स्वीकार ही नहीं होतीं। कौन नहीं जानता कि अंग्रेजी-व्याकरण बारह साल पढ़ने के बाद भी भाषा में अनुद्धियाँ रह जाना एक साधारण बात है। फिर भी अंग्रेजी ससार की सबसे सजीव भाषाओ में है। सस्कृत की अपेक्षा उसमें स्वच्छन्दता वहीं कम है। सस्कृत वाक्य-रचना में आप शब्दों का हेर-फेर कर सकते हैं—'एतद् मम पुस्तकम्' को मम, पुस्तकम्, एतद् किसी भी शब्द से प्रारम्भ करके लिख सकते हैं। लेकिन अंग्रेजी में 'दिस इज माई बुक' को 'इज दिस माई बुक' लिखकर देखिये, कितना अन्तर हो जाता है। और कही बुक माई इज दिस' लिख दीजिये, तब तो वाक्य का कचूमर ही निकल जायगा। छोटे बच्चे अंग्रेजी सीखते हुए अक्सर इस तरह की वाक्य-रचना करते हैं। और बच्चे ही क्या, बालिग भी हिन्दी से अंग्रेजी शुरू करते हैं, तो प्रारम्भ में यही गलती करते हैं। अगर कोई समझे कि 'राम रामी रामा' की रटन्त से अंग्रेजी ही अच्छी तो उसे हिन्दी के 'राम से, राम में, राम पर' आदि रूप याद रखने चाहिए और बिहारी भाइयो की 'ने' सम्बन्धी कठिनाई को न भूल जाना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि सस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी दोनों से सरल है और इसलिए उसे राष्ट्रभाषा बना देना चाहिए। ऊपर की बातें कहने का उद्देश्य यह है कि सस्कृत के मृत भाषा बनने का कारण व्याकरण नहीं कुछ और है। दरअसल सस्कृत कुछ गिने-चुने शिक्षितों की भाषा रह गई थी और लोक-प्रचलित भाषा से इतनी दूर चली गई थी कि आम जनता के लिए वह दुर्लभ हो गई थी। उसका व्याकरण कितना भी सरल किया जाता, वह 'जीवित'

भाषा का पद न पा सकती थी। अक्सर अनेक ग्राम-भाषाओं का व्याकरण सस्कृत से कम कठिन नहीं होता, बल्कि उससे भी अधिक गहन और विस्तृत होता है, फिर भी ग्रामीण बच्चे बिना सूत्र घोड़े हुए ही व्याकरण के अनुसार नित्य वाक्यरचना करते रहते हैं। फ्रांस और स्पेन के कुछ भागों में 'वास्क' नाम की ऐसी बोली आज भी प्रचलित है। उसका व्याकरण लैटिन से भी दुरूह बनाया जाता है लेकिन लैटिन सस्कृत के पद को प्राप्त हुई और वास्क अब भी जीवित है। वास्क के लिए एक कहानी प्रचलित है कि पुदा ने शैतान पर पफा होकर उसे वास्क-व्याकरण याद करने के लिए भेजा। सात साल तक परिश्रम करने के बाद भी शैतान कोरा-का-कोरा ही वापस लौटा।

व्याकरण की कठिनाई नहीं भाषा सीखनेवालों को महसूस होती है। जो उसे नित्य-प्रति बोलत हैं, उनके लिए व्याकरण 'सीखने' का प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार बोश देखकर भी कोई हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी में बातें नहीं करता। काफी दिन तक बोश-निर्माण में परिश्रम करने के बाद अधिकांश लोग यह समझ गये हैं कि हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी की समस्या का चाहे जो हल हो, वह कम से-कम बोश-निर्माण से हल नहीं हो सकती।

लेकिन बोशकार भला यह कब माननेवाले हैं। उनके लिए अमर-बोश पहले है, कालिदास बाद का। उनका लिये भाषा के बोलनेवाले बाद को हैं, उनकी बोश रचना पहले है। जनता क्या बोलनेगी, वैज्ञानिक, डाक्टर, वकील, राजनीतिक नेता, आदि-आदि किन शब्दों का प्रयोग करेंगे, इस अदेश से दुबले बोशकार मोटे-मोटे बोशों का निर्माण करने में लगे हैं। बोश-रचना में ऐसे शब्द नहीं रखे जाते जो व्यवहार में आते हैं बल्कि ऐसे शब्द गढ़कर रखे जाते हैं जो व्यवहार में लाय जायेंगे। अगर 'जनता' की समझ और व्यवहार का जिक्र कीजिये तो जनता की मूल्य और अधिशित बहुर भाषा के क्षेत्र से उसे निवाल बाहर किया जाता है और बोशकार दत्तचित्त होकर फिर अपने शब्द-निर्माण में लग जाते हैं।

छोटे से बड़े तक अनेक पंडित-महापंडित कई वर्षों से इस कार्य में लगे हैं। हिन्दी में लगे हैं और उर्दू में लगे हैं और इनके साथ बंगला जैसी अन्य भाषाओं में भी लगे हैं। इस हिसाब से हम इसे 'भारतीय साहित्य का बोश-युग' कह सकते हैं।

बोशकार अपने निर्दोष कार्य में लगे रहते और उनके एकांत चिन्तन में बाधा देने की कोई जरूरत नहीं अगर उनकी बोश-रचना आम जनता पर लादी जाने को न होती। जब उनके इस कार्य को सरकारी या अर्द्ध-सरकारी सरक्षण मिल जाता है, तब यह सतरा पैदा हो जाता है कि कचहरी डाकखान में हमें ऐसे वागज-पत्र पढ़ने की मिलेंगे जिन्हें समझने के लिए भारी-भरकम वाक्य साथ लेकर चलना पड़ेगा।

बल्कना कीजिये, एक 'अपसंज्ञित' व्यक्ति अपने 'अपसंज्ञक' पर अभियोग

लगाता है और 'अपसर्जक' या मित्र 'अपचय' करता है। आप भदासत में 'प्रत्याख्यान' करते हैं। वकील 'अत्यय की अभ्युक्ति' करता है। इतने ही में एक 'अपनयन' का मुरदमा और पेग होता है लेकिन मुकदमे का 'लग्न' हो जाता है या वह 'विवृष्ट' हो जाता है। आपका 'अभिवर्त्ता' 'अपय-पत्रक' देता है जिसमें फिर 'व्ययन विवरण' होता है। इसके बाद 'पुनर्वाद के अत्यय' की नीयत आती है और तब 'अपचारक' से कहा जाता है कि 'इस वाद का व्यय बाद के परिणाम का अनुमरण करेगा।'

यदि आप हिन्दी-प्रेमी हैं, तो इन शब्दों पर कुछ देर तक विचार कीजिए। यदि अंग्रेजी और हिन्दी पर्यायवाची शब्दों के बिना आप इनका मतलब समझ लेंगे तो 'बीर सराहीं तोहि' हमें कहना पड़ेगा। ऊपर के शब्द उस बोझ में निये गये हैं जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार और टिहरी राज्य की सहायता से नागरी प्रचारिणी सभा तैयार कर रही है। बानगी के तौर पर कुछ शब्द २ जून, १९४८ की 'अमृत बाजार पत्रिका' में छपे हैं। यदि नागरी-प्रचारिणी सभा एसी ही हिन्दी का प्रचार करना चाहती है तो उसे लोगों को धोखे में न डालकर अपना नाम बदल डालना चाहिए।

इसमें मशय है कि ये शब्द संस्कृत में भी उसी अर्थ में प्रयुक्त होते हैं जो कोशकारों को अंग्रेजी के आधार पर अभीष्ट हैं। यह संस्कृत और हिन्दी दोनों के माय अन्वय है। इस तरह की भाषा को यू० पी० सरकार, टिहरी राज्य और नागरी-प्रचारिणी सभा तीनों मिलकर और उन-जैसे दस पाँच नहीं चला सकते, क्योंकि ये शब्द जनता के गले से उतरेंगे नहीं। कोशकार भले ही आज जनता को अशिक्षित कहकर उसकी बोलचाल की भाषा की उपेक्षा करें, लेकिन यह कोश-भाषा आखिर बुलबाना तो उसी जनता से है!

हिन्दी के इस 'संस्कृतीकरण' से हिन्दी का राष्ट्रभाषा बनना तो दूर, उसका प्रान्तीय भाषा के रूप में भी लोकप्रिय रहना कठिन हो जाएगा। यह हिन्दी की मजा करना नहीं, उसका गला घोटना है। हर हिन्दी-प्रेमी को इसका विरोध करना चाहिए।

यह बात नहीं है कि संस्कृत से शब्द लेना एकदम बन्द कर देना चाहिए। लेकिन शब्द लेना एक बात है, भाषा को संस्कृतमय बना देना दूसरी बात। इन कोशकारों की नज़र में हिन्दी का कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। उसमें जो कुछ है और होना चाहिए, वह केवल संस्कृत का! इनके लिए मध्यकाल से लेकर अब तक केवल सांस्कृतिक पतन ही होता आया है और जितनी जल्दी सतयुग की ओर लौट चलें, उतना ही अच्छा। यह हठधर्म कुछ नया नहीं है। जब गोस्वामी तुलसीदास ने 'रामचरितमानस' रचा था और पंडितगण उनकी रचना को 'भदेस' कहकर हँसते थे, तब से यह क्रम चला आ रहा है। यूरोप में इस प्रकार लैटिन के आगे 'वल्गर टग' का मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन वही 'भदेस' भाषाएँ समार की सबसे समृद्ध भाषाएँ बन गईं। वह पद हिन्दी भी प्राप्त

करेगी, लेकिन कोश-रचना और संस्कृतीकरण के रास्ते पर चलकर नहीं।  
ऊपर की कोश निमित्त शब्दावली सरल शब्दों में भी लिखी जा सकती है।  
लेकिन कोश-प्रेमियों का कहना है कि सरल शब्दावली पारिभाषिक कहाँ हुई !  
इस तरह हिन्दी को इतना पारिभाषिक बनाया जाएगा कि वह 'भाषा' न रहकर  
केवल 'परिभाषा' रह जाएगी !

हैदराबाद के स्वनामधन्य निजाम साहब उर्दू के लिए ऐसे ही कोश बनवा  
चुके हैं। उनसे उर्दू कितनी लोकप्रिय हुई है, इस बात पर हिन्दी-प्रेमियों को  
विचार करना चाहिए।

'सारे देश में समझी जाए'—इस बहाने हर भाषा के बठमुल्ले अपनी भाषा  
की जान लेने पर तुले हुए हैं।

पश्चिमी बंगाल की अत्यन्त प्रगतिशील सरकार के 'स्वराष्ट्र विभाग' ने  
गरवारी कामों के लिए 'व्यवहार्य परिभाषा' का पहला भाग प्रकाशित किया  
है। सरकार की तरफ से छपी हुई चीज है, इसलिए उसमें भ्रष्टाचारी की  
गुजाइश भी कम है। आप 'परिभाषा' का जो मतलब लगाते हो, बग सरकार  
ने उसका अर्थ 'शब्दावली' लिया है, यह याद रखें।

इसके रचयिताओं में डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी का प्रसिद्ध नाम भी है।  
भूमिका में बताया गया है कि 'हिस्साब' शब्द प्रचलित होते हुए भी उसकी जगह  
गणन' और 'गणन' से 'गणनिक' और 'महागणनिक' शब्द रचे गये हैं। रवीन्द्र-  
नाथ के बंगाल में यह सलित पदावली रची जा रही है। इसी प्रकार 'भद्रालत'  
शब्द का भी सम्मानपूर्ण नहीं, 'not dignified enough' समझा गया है। इस-  
लिए उसकी जगह 'धर्माधिकरण' सजाया गया है, जिसका नाम सुनते ही  
अपराधियों के छक्के छूट जाएँ।

भूमिका में भाषा विज्ञान की यह अपूर्व बात भी कही गई है—'Bengali,  
Hindi, Marathi and the rest now depend upon Sanskrit—they  
are not free to utilise their own basic elements' यानी बँगला,  
हिन्दी, मराठी वगैरह को खुद अपने भीतर से शब्द निर्माण करने की छूट नहीं  
है। उन्हें संस्कृत का ही मुँह जाहना पड़ेगा।

हिन्दुस्तान में भाषा विज्ञान न कितनी प्रगति की है, यह ऊपर के इस एक  
वाक्य से प्रकट है, जिस पर डॉ० सुनीति कुमार चटर्जी के हस्ताक्षर हैं।

नागरी प्रचारिणी के कासकारों की सेवा में हम इस बगीच 'परिभाषा' से  
कुछ शब्द पेश करत हैं। आप लोग प्रलग-अलग न जाने क्यों परिश्रम कर रहे हैं,  
हिन्दी बँगला जब दोनों संस्कृत से लेती है, तब उनमें भेद कहाँ रहा ? घ्राट्टे के  
शब्द-कोष पर हिन्दी, बँगला लिखकर क्यों नहीं चालू कर देते ? बानगी दल्लिए  
ग्यासपाल, महा व्यावहारिक (सज्ञा है, विशेषण न समझ लीजिएगा !),  
स्थपति, भावित्रनार, कूपी धावक (यह बातल धोनेवाला है !), आत्ययिक,  
चक्रचर नियामक, दोहवर्धन आधिकारिक (डैरी से सम्बन्ध है), दुष्कृति विमर्स

हिन्दी का संस्कृतीकरण /

विभाग, उप-आयुक्तक, उप-प्रादेशिक परिवहन महाध्यक्ष, उप-भारतयाध्यक्ष, एप-अधिकर्ता, साहित्य-उपदेष्टा, धूमोत्पात परिदसंक, साधित्र रक्षक, लेख्य-प्रापक, राजस्व-करणिक, विक्रयिक, विनिष्ट-मुद्रितक-उपदेष्टा, परियाण-करणिक अवर, अन्त शुक्ल श्रुत्यक, शिल्प व मभरण मन्त्रक, राष्ट्रमृत्यानियोगाधिकार, कन्या प्रणिधि, तूर्ण पत्र (एक्सप्रेस बिट्टी) इत्यादि ।

इस शब्दावली के निर्माता जानते हैं कि उसे बंगाल में कोई न समझेगा । इसलिए नीजवानों को आदेश दिया गया है कि जितना समय अंग्रेजी सीखने में लगाते हों, उसका चौपाई भी मातृभाषा (यानी संस्कृत) सीखने में लगाओ तो वे अपरिचित शब्द उतने अपरिचित न रह जाएंगे ।

इन बोशकारों के लिए सबसे अच्छी मजा यही है कि इनसे इन्हीं के बनाये हुए कोश याद कराये जाएँ । जहाँ मूलें वहाँ फिर याद करने की ताकीद कर दी जाय । जब हिन्दी, बँगला आदि के बोशकार अपने अपने कोश या सम्मिलित महाकोश याद कर डालें तभी वह कोश जनता तक पहुँचे, उमके पहले नहीं ।

हिन्दी का संस्कृतीकरण पारिभाषिक शब्दों को लेकर ही नहीं है । साधारण साहित्य में, दैनिक और मासिक पत्रों आदि में भी तत्सम शब्दों को इसलिए भरा जाता है कि इससे हिन्दी सुबोध हो जाएगी—युद्ध हिन्दी बोलनेवालों के लिए नहीं बल्कि दूसरी भाषाओं के बोलनेवालों के लिए । मिसाल के लिए, शायद बंगाल के लोग संस्कृत-बहुल हिन्दी को बोलचाल की खिचड़ी भाषा से ज्यादा अच्छी तरह समझ सकेंगे । देखना चाहिए कि बोलचाल की बँगला में तत्सम शब्दों का अनुपात कैसा रहता है । इस पर डा० सुनीतिकुमार चटर्जी से ज्यादा कौन अधिकारी विद्वान राय दे सकता है ? बँगला भाषा की उत्पत्ति और विकास पर लिखे हुए अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ के पहले भाग में उन्होंने यह मत प्रकट किया है—

‘In Modern Bengali, the Colloquial has a surprisingly small ‘percentage of Sanskrit words’ (The Origin and Development of the Bengali Language, Vol 1, p 221) यानी बोलचाल की बँगला में संस्कृत शब्दों की तादाद असाधारण रूप से कम है ।

हिन्दी पाठक इस वाक्य पर कुछ देर तक विचार करें । जिन ग्रन्थ भाषा-भाषियों की दुहाई देकर हिन्दी को बिगाड़कर उसे संस्कृतमयी बनाया जा रहा है, वे स्वयं बंगाल जैसे प्रान्त में भी संस्कृत शब्दों का कम-से-कम प्रयोग करते हैं ।

पारिभाषिक शब्दों की समस्या बोलचाल की भाषा के नियमों को तोड़कर हल नहीं की जा सकती । बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी और फारसी के शब्द भी आते हैं और संस्कृत से भी आते हैं । लेकिन धार्य संस्कृति के जोग में शुद्धतावादी केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों को लेने पर तुले हुए हैं । वे यह भूल जाते हैं कि स्वयं संस्कृत दूसरी भाषाओं से शब्द लेकर समृद्ध होती रही थी ।

इस बात को मुनीति बाबू भी मानते हैं। उपर्युक्त पुस्तक में लिखा है—“The Aryan speech has been borrowing words from the Dravidian ever since the former came to India”—(Ib, p. 178) अर्थात् “आर्यों की भाषा हिन्दुस्तान में आने के बाद से ही द्रविड भाषाओं से बग़रब शब्द उधार लेती रही है।” लेकिन ‘देववाणी’ भन्ने शब्द लेती रही हो, देववाणी के बज्जुगी समयक जोरो से हृदय-वपाट बन्द निये हैं कि वही विदेशी हवा लगने से उनका देवत्व ख़डित न हो जाय।

भगर कोई कहे कि इन्ग्लिश टैक्म इन्फेक्टर, वारंट, वर्रेमी, गाज़ियन, रिपोर्ट, रिमीवर, ममन, गब-जज आदि अंग्रेज़ी के प्रचलित शब्दों को ग्रहण कर लेना चाहिए और उनकी जगह नये शब्द न गढ़ने चाहिए तो यह राष्ट्रभाषा के प्रति द्रोह कहा जाएगा। लेकिन इन्हीं शब्दों को मुनीति बाबू ने अपनी पुस्तक में ‘typical naturalised English Words’ (पृ० ६४५-६८) कहा है। ये शब्द बँगला के अपने शब्द मान लिये गए हैं और यही नहीं, इनके साथ एन्जि-वीनन, वेस्टिंग-हम, कॉसिल, गिरीमेंट (एपीमेंट), नोटिंग, बर्ज्राइस (बुर्ज्रा), मरगिज, रजिस्ट्री, निवर, हाफ साइड आदि शब्द भी बँगला की स्वीकृत सम्पत्ति माने गये हैं। लेकिन बँगला की ‘व्यवहार्य परिभाषा’ उठाकर देखिए तो इन्हीं शब्दों या इन जैसों के बदले हा० मुनीतिनुसार और उनके सहयोगी नये-नये भारी भरकम शब्द गढ़ते दिखाई देंगे और खूद बंगालियों की समझ में न आने पर उनसे कहेंगे कि अपनी मातृभाषा सीखने में कुछ समय लगाओ।

इसी तरह अपनी पुस्तक के पृ० २१७ (खंड १) पर उन्होंने बेंलेट, सेनेटरी, प्रिटर, गजट, टाइमटेबल, रोमास, रोमाटिक, बलासिक, ट्रेजिक, कॉमिन, फ्रांट, पब्लिशरिज्म, साइस, प्रोटोप्लाज्म, प्लोस्टोसीन, लॉ, प्लॉट, केमिस्ट्री, फिजिक्स आदि शब्दों के लिए लिखा है कि वे ‘are being bodily adopted at the present day,’ यानी वे जैसे-वे तैसे बँगला में भ्रवतार ले रहे हैं। लेकिन मजाल क्या कि वही मुनीति बाबू अब इनके लिए सस्वृत की किसी धातु से नया शब्द न गढ़ लें।

अपनी पुस्तक के पृ० २१२ (खंड १) पर उन्होंने यह भी लिखा था कि बँगला के मुसलमान लेखक ज्यादातर भाषा में आगे आ रहे हैं, इसलिए फारसी, अरबी के शब्दों का बँगला में आना बिल्कुल स्वाभाविक होगा (‘will be in the nature of things’) लेकिन ‘व्यवहार्य परिभाषा’ में इन स्वाभाविक रूप से आये हुए शब्दों को ढूँढ़ने के लिए अब आपकी खुदचीन की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह पूँजीवादी नेता चुनाव में किये हुए वादों को मन्नी बनने पर मूल जाते हैं, वैसे ही ‘रिवाइवलरिज्म’ के जोश में (‘आर्य सस्कृति के मोह में’) मुनीति बाबू जैसे भाषा वैज्ञानिक खुद अपने बनाये हुए सिद्धान्तों को मूल गए हैं। यह पूँजीवादी संस्कृति के हास का चिह्न है, उसके उत्थान का नहीं। यह रास्ता बँगला और हिन्दी की उन्नति नहीं, उनकी अवनति का है। (१९४८)

## उर्दू-साहित्य की सांस्कृतिक परम्परा

हिन्दी उर्दू की समस्या वा एक पटलू उनके साहित्य की परम्परा वा भी है। हिन्दी और उर्दू एक भाषा हैं, या एक भाषा की दो शैलियाँ हैं वे आगे चलकर मिलेंगी या उनमें से एक ही रह जाएगी आदि मसला को पेश करते हुए और उनका हल खोजते हुए इन दोनों की सांस्कृतिक परम्परा का सवाल भी उठाया जाता है।

उर्दू की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्परा क्या है ? यह परम्परा हिन्दी की साहित्यिक और सांस्कृतिक परम्परा से वहाँ तक अलग है ? क्या दोनों की कोई सामान्य परम्परा भी है जिसे आगे विकसित किया जा सकता है ?

इन प्रश्नों का जवाब देने से हिन्दी उर्दू की समस्या को सही तौर से पेश करने और उसे हल करने में सहायता मिलेगी।

### १

उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा के बारे में एक मत यह है कि वह विदेशी है, उसी की वजह से देश के बँटवारे की नौबत आई (या वह परम्परा भी बँटवारे का एक कारण है), इस परम्परा से हिन्दी का कोई सम्झौता नहीं हो सकता और दरअसल उस परम्परा को, चूँकि वह राष्ट्रघोषी है जल्दी से जल्दी खत्म कर देना चाहिए।

इस मत को हिन्दी साहित्य सम्मेलन के नये सभापति सेठ गोविन्ददास ने बड़ी धूमधाम से पेश किया है। इसी मत को श्री राहुल सावृत्पायन, श्री सम्पूर्णानन्द, श्री पुरुषोत्तमदास टडन आदि सज्जन भी पेश कर चुके हैं। सठ गोविन्ददास ने उस पेश करने में धूमधाम के अलावा किसी मौनिकता का खिस्सा नहीं दिया। इसलिए यहाँ पर श्री पुरुषोत्तमदास टडन के शब्दों को उद्धृत करना ज्यादा अच्छा होगा। टडनजी सम्मेलन के प्राण हैं। सम्मेलन के सालाना सभापति जो मत प्रकट करते हैं उनमें इन प्राणों की ध्वनि ही गूँजती रहती है।

सम्मेलन के पैंतीसवें अधिवेशन में टडनजी ने उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा

पर ये विचार प्रकट किये थे :

“उर्दू कवियों की जो कविताएँ हुईं, वे अरब और ईरान के सहजीव को प्रतीक थीं। उर्दू कविताएँ हमें अपने नगर, अपने देश, अपने गली-बूचो की ओर ले जाने के बजाय, ईरान और अरब के नगर तथा गली-बूचो की ओर ले जाती हैं। उसकी सांस्कृतिक परम्परा हमारे देश की, हमारी मिट्टी से निकली हुई जो सृष्टि है, उसके विपरीत है।

“उर्दू कवियों के रूपको में उर्दू कविता का सांस्कृतिक प्रयत्न स्पष्ट दिखाई पड़ता है। उनकी कविताओं में यदि बीर की उपमा दी जाती है तो हस्तम, सोहराब, अफ़ासियाब को याद किया जाता है, वही पर आपको भीम, भर्जुन, आदि की उपमा नहीं मिलेगी। नदी की उपमा जब आती है तो उन्हें अरब की, मेसोपोटामिया की और ईरान की नदियाँ याद आती हैं। पर्वत की याद होती है तो उन्हें ईरान के पहाड़ों की याद आती है, हिमालय पर्वत की याद नहीं आती। फलों में उनको ‘नगित’ की याद आती है। पक्षियों में उनको बुलबुल दिखाई पड़ता है, अपने देश के जो सुन्दर और अच्छे पक्षी हैं, उनकी चर्चा नहीं करते। उनका यह प्रयत्न था कि लखनऊ की गलियाँ ‘अश्व’ बन जाएँ। ‘अश्व’ ईरान का एक नगर है। सहर जो कि लखनऊ का कवि था उसका एक गौर ‘फसाना अजायब’ में यह है—‘बुलबुले शीराज को है रस’ नासिख का शुरू। अश्वों इसने किये हैं, लखनऊ के कूचे और गलियाँ’। कहने का तात्पर्य यह है कि उर्दू का सांस्कृतिक क्रम पृथक्वाद है और उसका परिणाम यह हुआ है कि जैसे-जैसे उर्दू का विकास हुआ, वैसे-वैसे सांस्कृतिक पृथक्ता बढ़ती गई। जहाँ-जहाँ उर्दू का साम्राज्य था, वहाँ वहाँ पृथक्वाद का विशेष बल था, जैसे उत्तर-प्रदेश और पंजाब में।”

(हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, पैंतीसवें अधिवेशन का विवरण, प्रयाग, पृ० ७१-८०)

यह सब कहने का सीधा मतलब यह है कि उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा अलग-अलग पैदा करती रही है, इसलिए उसे खत्म कर देना चाहिए। आगे जब टडन जी कहते हैं कि “मुझे उर्दू कविता अच्छी लगती है” तब उनसे पूछा जा सकता है कि इस राष्ट्र विरोधी कविता के अच्छा लगने का पाप आप जैसे विशुद्ध भारतीयता प्रेमी से कैसे हो गया? अगर उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा हिन्दुओं और मुसलमानों में फूट डालती है तो इस बारे में दो मत नहीं हो सकते कि ऐसी परम्परा को खत्म कर देना चाहिए। ऐसी परम्परा तो फूटपरस्तों की ही अच्छी लग सकती है।

२

उर्दू साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालने से पहली चीज यह दिखाई देती है कि उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा परिवर्तनशील रही है। जो परम्परा जोक या दाग की थी, वही परम्परा ज्यो-की-त्या जोश या बृशन चन्दर की नहीं हैं। हमें



देखना चाहिए कि यह परम्परा पहले क्या थी और उसमें कौन-कौन-सी खास तन्दीलियाँ हुई हैं ।

जिस तरह हम भारतेन्दु के पहले की हिन्दी कविता को मोटे तौर पर रीति-कालीन कविता कहते हैं, उसी तरह हाली के पहले की उर्दू कविता को मोटे तौर पर हम रीतिकालीन कविता कह सकते हैं ।

इस ज़माने की उर्दू कविता पर दरबारी मस्बूति की जबर्दस्त छाप है । उसके भावों और भाषा पर सामन्ती मस्कृति की छाप है । यह सामन्ती मस्कृति साहित्य में ईरानी साहित्य की परम्परा को अपनाती थी । उसने ईरानी साहित्य में प्रचलित उपमाओं, रूपकों वगैरह को अपने साहित्य में सजाने की कोशिश की ।

हर देश के रीतिकालीन साहित्य में—उम्र समय के साहित्य में जब उद्योग-धन्यों के विकास से सामन्ती ढाँचा खत्म नहीं हुआ—बात कहने के ढंग पर ज्यादा जोर दिया जाता है, भावों और विचारों की मौलिकता पर कम जोर दिया जाता है । हिन्दी की रीतिकालीन कविता, बिहारी और देव की रचनाओं में यह शैली हम देख सकते हैं । यही बात उर्दू की रीतिकालीन कविता पर भी लागू होती है ।

आगे चलकर रीतिकालीन परम्परा ज्यादा साथ नहीं देती । उसमें चाह भीम और अर्जुन का गुणगान हा, चाहे सोहराब और अप्पासियाब का, उस परम्परा से नाता तोड़ना ही होता है । हिन्दी की रीतिकालीन परम्परा में रामायण और महाभारत के वीरों की कमी नहीं थी, फिर भी खड़ी बोली के कवियों ने उस परम्परा का जोरों से विरोध किया और छायावादी कवियों ने उससे नाता तोड़कर एक नई परम्परा को जन्म दिया । उर्दू साहित्य में भी उसकी रीतिकालीन परम्परा अब निर्जीव परम्परा हो गई है । उर्दू-साहित्य उससे बहुत आगे बढ़ चुका है । रीतिकालीन परम्परा का विरोध करने और उससे नाता तोड़ने पर खुद उर्दू के लेखकों और कवियों ने ज़ार दिया है ।

जैसे हिन्दी में भारतेन्दु से पहले की सभी रीतिकालीन कविता ऐसी नहीं है, जिसे उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाय, उसी तरह उर्दू की रीतिकालीन कविताओं में बहुत-सा हिस्सा सांस्कृतिक परम्परा का अंग बनकर सुरक्षित रहेगा । उर्दू के बहुत-से पुराने कवियों की ऐसी संकड़ो पक्तियाँ हैं जो अपनी उक्ति चातुरी की वजह से बार-बार उद्धृत की जाती हैं और अब उन्होंने बोलचाल में कहावती की जगह ले ली है । मसलन—

बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का  
जा चोरा तो इक कतरए खूँ न निकला ।

• • •

जमीने चमन गुल खिलाती है क्या-क्या,  
बदलता है रंग आस्माँ कैसे-कैसे ।

• • •

न जोरे सिकन्दर न है कग्र दारा,  
मिटे नामियो के निशाँ कैंते-कैंसे।

अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएँगे,  
मर के भी चैन न पाया तो क्रिधर जाएँगे।

हूँखरते दाग जहाँ बँठ गये बँठ गये  
और होंगे तेरी महफिन से उभरनेवाले।

इस तरह की पक्तियाँ बोलचाल में इस तरह आती हैं कि उन्ह हिन्दुस्तानी (खड़ी बोली) बोलनेवाली जनता की सांस्कृतिक परम्परा का एक अंग कहा जा सकता है।

हाली से पहले की उर्दू कविता की देन इतनी ही नहीं है। हाली से पहले भी बहुत-से कवियों ने रीतिकालीन परम्परा से बँधे न रहकर अपना नया रास्ता बनाया था। इन कवियों में गालिव का नाम सबसे पहले आता है जिनके व्यक्तित्व की छाप उनकी रचनाओं पर इस तरह पड़ी है जिस तरह अपने व्यक्तित्व की छाप डालना किसी भी रीतिकालीन कवि के लिए मुमकिन नहीं है। गालिव ने अपने जीवन के बारे में बड़े दर्द से लिखा है। इस तरह का दर्द दूसरों की रचनाओं की नकल करने से नहीं पैदा होता। इटली के महान् कवि दान्ते ने जिस तरह अपने जीवन की अपार वेदना अपने महाकाव्य में उड़ेल दी थी, उसी तरह गालिव के शेर उस जमाने के वातावरण के प्रति क्षोभ, खिन्न और वेदना में डूबे हुए हैं।

गालिव के जमाने में बहुत-से लोग इल्म की शायरी करते थे। वे फारसी साहित्य की उपमाएँ और रूपक लेकर अपनी रचनाओं को संवारने की कोशिश करते थे। इन सब में फारसी साहित्य से प्रभावित होते हुए भी गालिव एक महान् प्रतिभाशाली कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं।

गालिव की पचीसों पक्तियाँ साधारण बोलचाल में बराबर उद्धृत की जाती हैं। मिसाल के लिए—

हमको मालूम है जन्नन की हकीकत लेकिन,  
दिल के खुश करने को गालिव य' खयाल अच्छा है।

उनको देखे से जा आ जाती है मुँह पर रीनक,  
वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है।

वर्ज की पीते थे मय लेकिन समझते थे कि हाँ,  
रग लायेगी हमारी फाकामस्ती एक दिन।

रगो मे दौडने फिरने के हम नही कायल,  
जो भ्रांख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है ।

न था कुछ तो खुदा था कुछ न होता तो खुदा होता,  
डुबोया मुझको होने ने न होता मैं ता क्या होता ।

मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि भासां हो गईं ।

दर्द का हृद स गुजरना है दवा हो जाना ।

है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ,  
वरना क्या बात कर नही आती ।

अनेक हिन्दी लेखकों की रचनाओं में गालिब के शेर उद्धृत किये जाते हैं । उग्रजी की शायद ही कोई पुस्तक, शायद ही कोई लेख हो जिगम गालिब के शेर उद्धृत न किये गये हो । निरालाजी ने जहाँ-तहाँ गालिब के शेर उद्धृत ही नहीं किये, उन पर 'प्रबन्ध पद्य' में लिखा भी है । गालिब की रचनाएँ किस तरह हिन्दी लेखकों की सांस्कृतिक परम्परा बन गई हैं, इसकी एक मिसाल निरालाजी के जीवन में मिलती है । निरालाजी को अपने जीवन में जो मुसीबतें उठानी पड़ी हैं, जो अपमान सहने पड़े हैं और जिस तरह विरोधियों के मुकाबले में अपने आत्मविश्वास को अडिग रखना पड़ा है, उससे गालिब की रचनाओं से उन्हें एक आन्तरिक सहानुभूति पैदा हो गई थी । मैंने उन्हें पचीसो बार इन पक्तियों को गाते सुना है और आखिरी बार अभी पिछले साल बनारस में जब वह काफी अस्वस्थ थे, उन्हें फिर गालिब के शेर गुनगुनाते सुनकर काफी ताज्जुब भी हुआ कि इनके मन की दुनिया में और बहुत-से उलटफेर हुए, लेकिन गालिब, रवीन्द्रनाथ और तुलसीदास—ये तीन महाकवि अपनी जगह अब भी कायम है ।

रहिये अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो,  
हमसखुन कोई न हो और हमजवाँ कोई न हो ।  
वेदरो दीवार-सा इक घर बनाना चाहिए,  
कोई हमसाया न हो और पासवाँ कोई न हो ।  
पड़िये गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार  
और अगर मर जाइये तो नौहर्वाँ कोई न हो ।

जब श्री पुरपोस्तमदास टंडन उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा को विदेशी और राष्ट्र-विरोधी बहकर उस पर हमला करते हैं, तब हम यह सोचने पर मजबूर होते हैं कि हिन्दी की सांस्कृतिक परम्परा को 'निराला' की देन महान् है या श्री टंडन की । निराला की देन महान् है और इसीलिए महान् है

कि उनके हृदय में वह सकीर्ण साम्प्रदायिकता नहीं थी जिसका परिचय श्री टडन ने बार बार दिया है। सकीर्ण हृदय से महान् सांस्कृतिक परम्परा का कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता।

मालिव के बाद पुरानी उदू कविता में दूसरे महान् रचनाकार मीर हैं। मीर की बहुत सी रचनाओं में रीतिकालीन परम्परा से साफ नाता टूटा हुआ दिखाई देता है। कौन सा रीतिकालीन कवि अपने घर का इस यथार्थ ढंग से विर्णन करेगा।—

लोनी लग लग के झड़ती है माटी,  
आह क्या उम्र बेमजा काटी।  
भाड़ बाँधा है मेह ने दिन रात,  
घर की दीवारें हैंगी जैसे पात।  
घाउ में काँपते हैं जो थरथर,  
उन पर रहा रहे कोई क्योकर।

मीर की भी अनेक पक्तियाँ कहावतों का दर्जा पा चुकी हैं, जैसे ये—

शाम से कुछ बुझा सा रहता है,  
दिल हुआ है चिराग मुफलिस का।

हाली से पहले जिन लोगों ने रीतिकालीन परम्परा से नाता तोड़ा, उनमें नजीर का नाम महत्वपूर्ण है। नजीर के काव्य में लोक-गीता, कहावतों और लोक-संस्कृति को जो स्थान दिया गया है उससे आज भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नजीर जनता के कवि थे। इन्होंने आम जनता की जिन्दगी के बारे में बड़ी सजीव रचनाएँ की हैं। इनकी भाषा के बारे में श्री ब्रजरत्नदास ने लिखा है

‘इनकी भाषा दखी थी और उसे विलापनी बनाने का कभी इन्होंने प्रयत्न नहीं किया। इनका चलती भाषा पर पूरा अधिकार था और फारसी तथा अरबी के कोशों से चुन चुनकर अपनी भाषा को लद्दू बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसा विषय चुना, वैसी ही भाषा ली और वैसे ही वास्तविकता से उसका चित्रण भी कर डाला।

(उर्दू साहित्य का इतिहास, बनारस, स० १९६१, पृ० १८२)

नजीर की बहुत सी रचनाओं पर सूफीपन का रंग है। दरअसल उनकी कविता की जड़ें उस जमाने के समाज में दूर तक चली गई थी। वह आदशवादी कवियों की तरह गरीबी का गुणगान नहीं करते बल्कि इन्सान की बेमुसीबतें बयान करते हैं जो गरीबी के सबब से उस पर आती हैं। लिखा है—

जब आदमी के हाल पर आती है मुफलिसी,  
किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी  
प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी

उर्दू साहित्य की सांस्कृतिक

भूखा तमाम रात सुलाती है मुकलिसी,  
ये दुख वो जाने जिस पे कि आती है मुकलिसी ।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में देश के अन्दर नई राष्ट्रीय चेतना विकसित होने लगी । हिन्दी-साहित्य में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने किस तरह देशभक्तिपूर्ण कविताओं की परम्परा चलाई, इसे सभी लोग जानते हैं । उस समय की राष्ट्रीय चेतना पर पुनर्स्थानवाद का भी रंग चढ़ा हुआ था । भारतेन्दु बाबू ने आर्य जाति के प्राचीन गौरव के गीत गाये । हाली ने मुसलमानों के बीते वैभव के स्वप्न देखे । फिर भी हाली और भारतेन्दु—दोनों ने ही यह अनुभव कर लिया था कि देश की उन्नति हिन्दू-मुसलमानों के मेल से और उनको मिली-जुली राष्ट्रीय चेतना से ही हो सकती है । हाली ने देश पर लिखा था—

ऐ वतन ऐ मेरे बहिश्ते घरी  
बया हुए तेरे आसमाँ ओ जमी  
रात और दिन का थो समाँ न रहा  
वो जमी और वो आसमाँ न रहा ।

हिन्दू मुस्लिम-एकता पर लिखा था—

तुम अगर चाहत हो मुल्क की खैर,  
न किसी हमवतन को समझो गैर ।  
हो मुसलमाँ इसमें या हिन्दू  
बौद्ध भज्जव हो कि या ब्राह्मो,  
सबको मीठी निगाह से देखो ।  
समझो आँखों की पुतलियाँ सबको ।  
हिन्द में इत्तफाक होता अगर  
खाते गैरो की ठोकरें क्योंकर ?

प्राधुनिक हिन्दी साहित्य के आरम्भ-काल में जैसे सामाजिक कुरीतियों पर बहुत सी रचनाएँ की गईं, उसी तरह उर्दू-साहित्य में भी समाज-सुधार पर बहुत-सी चीजें लिखी गईं । बीसवीं सदी में आकर साहित्य का मतलब मुख्य रूप से कविता नहीं रहता; उसके दूसरे रूप कहानी, उपन्यास आलोचना वगैरह भी फलने-फूलने लगते हैं । इस नए जमाने का हिन्दी-उर्दू साहित्य और भी नजदीकी सांस्कृतिक परम्पराएँ बनाता हुआ चलता है ।

हिन्दी उपन्यासों में देवकीनन्दन खत्री के ऐयारी उपन्यासों के बाद हम प्रेमचन्द के सामाजिक समस्याओं वाले उपन्यासों तक पहुँचते हैं । उर्दू में प० रतननाथ सरगार के 'फिमान-ए-आज़ाद' में आगे बढ़ते हुए हम फिर प्रेमचन्द तक पहुँचते हैं । प्रेमचन्द ने उर्दू और हिन्दी में सामाजिक समस्याओं वाले उपन्यासों की नींव डाली । प्रेमचन्द ने हिन्दी-उर्दू की सांस्कृतिक परम्पराओं का मिलकर एक होना साहित्य की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है । उससे जाहिर होता है कि सांस्कृतिक परम्परा की जड़ें सामन्ती साहित्य से ज्यादा मौजूदा सामाजिक

जिन्दगी में धँसी होती हैं। प्रेमचन्द के जमाने में एक नई परम्परा गढ़ी जा रही थी जिसके तत्त्व इस्लाम या हिन्दू-धर्म से न लिये जाकर देश के सामाजिक और राजनीतिक आन्दोलनों से, समाज की नई प्रगति से, वर्गों के नये सम्बन्धों से लिये जा रहे थे। प्रेमचन्द ने हिन्दी और उर्दू में जो नई परम्परा डाली, वह गुणात्मक रूप से साहित्य की पुरानी परम्परा से भिन्न थी। वह दाग, जीव, बिहारी, पचावर की परम्परा से ही भिन्न न थी, वह हाली और भारतेन्दु की परम्परा से भी बाकी अलग थी। प्रेमचन्द साहित्य के विकास की वह मजिल थे जो अपने में सुधारवादी राष्ट्रीयता खत्म करके नये प्रगतिशील साहित्य की तरफ इशारा करती है।

प्रेमचन्द एक नई परम्परा को इसलिए जन्म दे सके कि हमारे समाज में नये परिवर्तन हो रहे थे, उसमें नई आशाएँ, नये उद्देश्य लेकर नये आन्दोलन चल रहे थे।

हिन्दी-उर्दू साहित्य में प्रेमचन्द की परम्परा इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सृष्टि रचने का काम मनुष्य का सामाजिक जीवन करता है। यह सामाजिक जीवन बदलता रहता है, इसलिए सृष्टि की धारा भी बदलती रहती है। सामाजिक जीवन के मुजावले में धर्म-सम्प्रदाय, मत मतान्तरों के संस्कार बहुत ही बमजोर साबित होते हैं, और सृष्टि पर उनका असर कम-से कम होता जाता है।

प्रेमचन्द खुद इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते थे कि सामन्त-जान की सांस्कृतिक परम्परा खत्म हो रही है और नये जमाने की एक नई परम्परा कायम हो रही है। वह जानते थे कि दोनों के उद्देश्य, दोनों के साहित्यिक रूप, दोनों के सौन्दर्य-सम्बन्धी मानदण्ड अलग-अलग हैं।

पुरानी साहित्यिक परम्परा के बारे में उन्होंने लिखा था—

“हमारे साहित्यकार कल्पना की एक सृष्टि खड़ी करके उसमें मनमाने तिलिम्म बाँधा करते थे। वही किसान-ए-अजायब की शास्तान थी, कहीं बीस्ताने खयाल की और कहीं चन्द्रकान्ता सन्तति की। इन आख्यानों का उद्देश्य केवल मनोरंजन था और हमारे अद्भुत रस—प्रेम की तृप्ति...”

“क्या हिन्दी और क्या उर्दू—बस्ता में दोनों की एक ही हालत थी...ऐसे पतम के काल में लोग या तो आशिकी करते हैं या अध्यात्म और वैराग्य में मन रमाते हैं।

“बस्ता का नाम था और अब भी है, सङ्कुचित रूप-युजा का, रावद योजना का, भाव-निबन्धन का। उसके लिए कोई पादर्श नहीं है, जीवन का कोई ऊँचा उद्देश्य नहीं है—भक्ति, वैराग्य, अध्यात्म और दुनिया से विनारावशी उसकी सबसे ऊँची वरूपनाएँ हैं। हमारे उस बलाकार के विचार से जीवन का चरम लक्ष्य वही है। उसकी दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं कि जीवन-मग्न में वह सौन्दर्य का परमोत्कर्ष देखे।”

(लखनऊ, प्रगतिशील लेखक सम्मेलन में सभापति पद से दिये गये भाषण से)  
 इस परम्परा को प्रेमचन्द खत्म कर रहे थे। उन्होंने माफ़ माँग की थी कि  
 साहित्य के पुराने मानदण्डों को बदला जाय। उन्होंने कहा था—

“हमें सुन्दरता की कसौटी बदलनी होगी। अभी तक यह कसौटी अमीरी  
 और विनाशिता के ढग की थी। हमारा कलाकार अमीरों का पल्ला पकड़े रहना  
 चाहता था— उसकी निगाह अन्त दूर और बँगलो की ओर उठती थी। भोपड़े  
 और खंडहर उसके ध्यान के अधिकारी न थे। उन्हें वह मनुष्यता की परिधि  
 के बाहर समझता था। कभी उनकी चर्चा करता भी था तो उनका मजाक  
 उड़ाने के लिए।” (उप०)

प्रेमचन्द का हर शब्द उनके सच्चे जनवादी हृदय से निकला है, जो समाज  
 के नये विकास के लिए, साहित्य की परम्परा बदलने के लिए जोर से ललकारता  
 है।

“यदि साहित्य ने अमीरों के याचक बनने को जीवन का सहारा बना लिया हो,  
 और उन भ्रान्दोलनों, हलचलों और क्रान्तियों से बेखबर हो जो समाज में हो  
 रही हैं—अपनी ही दुनिया बनाकर उसमें रोता और हँसता हो तो इस दुनिया  
 में उसके लिए जगह न होने में कोई अन्वयाय नहीं है।” (उप०)

प्रेमचन्द के ये प्रभावशाली शब्द—उनके हृदय के ये सच्चे उद्गार—बतलाते  
 हैं कि साहित्य की जो परम्परा धार्मिक अन्धविश्वासों, साम्प्रदायिक विद्वेष  
 और भेदभाव, सामन्ती रुढ़ियों और प्राचीनतावाद को अपना आधार बनाती  
 है, वह खत्म हो जाती है। साहित्य की वह परम्परा जो समाज के गतिशील  
 जीवन को, उसके क्रान्तिकारी वर्गों को, जनता के संघर्षों को अपना आधार  
 बनाती है, वह जीवित रहती है और वही परम्परा जीवित रह सकती है।  
 प्रेमचन्द ने हिन्दी-उर्दू में इसी परम्परा को जन्म दिया था।

कुछ लोगों के मन में सक्ता पैदा हो सकती है कि प्रेमचन्द ने तो यह सब  
 काम हिन्दी में किया था, उसका जिक्र उर्दू साहित्य के सिलसिले में क्यों किया  
 जा रहा है? ऐसे पाठकों की सेवा में प्रेमचन्द के ये शब्द अर्पित हैं—

“मेरा सारा जीवन उर्दू की सेवकाई करने गुजरा है और आज भी मैं  
 जितनी उर्दू लिखता हूँ, उतनी हिन्दी नहीं लिखता।”

(प्रेमचन्द कुछ विचार, पृ० १६१)

हिन्दी-उर्दू के लिखनेवालों का सामाजिक वातावरण आम तौर से एक-सा  
 रहा है, इसलिए उनकी साहित्यिक परम्परा के उतार-चढ़ाव उसके मोड़ और  
 नई दिशा में प्रवाह भी मिलते-जुलते रहे हैं। हिन्दी में ऐतिहासिक परम्परा  
 का विरोध किया गया। उर्दू में भी उस परम्परा का विरोध किया गया। हिन्दी  
 में राष्ट्रीय कविता का युग आया, चवबस्त और इकबाल यह युग उर्दू कविता  
 में भी लाये।

हिन्दी-कविता में छायावाद के नाम से नई रोमांटिक कविता का युग

भाषा। इस तरह की रोमांटिक कविता का युग उर्दू में भी प्रायः।

गुनझार में कोयल की गदा गूँज रही है,  
बोहसार में पुरखोर हवा गूँज रही है,  
कुनबुल में जुनूखेज फजा गूँज रही है,  
मैदान में घनघार घटा गूँज रही है,  
बरसात है, बरसात है, बरसात है,  
बरसात !

छायावादो कविता के उत्तरकान में जैसे हिन्दी में कुछ कवियों ने निराशा  
रुज और प्रवेलपन के गीत गाये, वैसे ही उर्दू में—

शहर की रात और मैं नाशाद ओ नाशारा फिर्ह,  
जगमगाती जागती सदकों पे आवारा फिर्ह,  
शहर की बस्ती है बस तक दरबदर मारा फिर्ह,  
ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ।  
यह रूपहनी छाव यह आकाश पर तारों का जाल,  
जैसे सूफी का तमधवर, जैसे आशिक का खयाल,  
आह लेकिन कौन जाने कौन समझे जी का हाल,  
ऐ गमे दिल क्या करूँ, ऐ वहशते दिल क्या करूँ।

हिन्दी में जैसे कुछ कवियों ने प्राचीनतावाद को ऐसा साधन बनाया है कि  
साहित्य का पानी उतर जाय, उसी तरह उर्दू में भी अलगाव और फूट पैदा  
करनेवाले, इस्लाम में उर्दू का नाता जोड़नेवाले, मुसलमानों को अलग जाति  
और उर्दू को अरब और ईरान की सस्कृति में मिलानेवाले शायर भी हुए हैं।  
लेकिन उनकी वजह में उर्दू साहित्य को साम्प्रदायिक समझना उतनी ही बड़ी  
अक्लमन्दी होगी, जितनी किप्लिंग की वजह से अंग्रेजी साहित्य को साम्राज्य-  
वादी समझना।

श्री पुरुषोत्तमदास टंडन का कहना है कि उर्दूवाले राम, कृष्ण, अर्जुन वगैरह  
का नाम लेना अपनी सस्कृति के खिलाफ समझते हैं। अगर ऐसा है तो नजीर  
ने 'कन्हैया का बालपन' क्यों लिखा? और लिखा तो ऐसी को जाति-बाहर क्यों  
नहीं कर दिया गया? नजीर ने लिखा है—

मारो मुनो ये दधि के लुटैया का बालपन,  
मो मधुपुरी नगर के बर्मा का बालपन,  
मोहल-स्वरूप नृत्य करैया का बालपन,  
घन-वन के खाल गोएँ खरैया का बालपन,  
क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन।

नजीर ने दीवाली पर लिखा था—

हर इक मकान में जला फिर दिया दिवाली का,  
हर इक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का,



मभी के दिल मे समा भा गया दिवाली का,  
 किसी के दिल को मजा खुश लगा दिवाली का,  
 भजब बहार का है दिन बना दिवाली का ।

होली पर दूसरे सुर-ताल मे लिखा था—

जब फागुन रंग भूमकते हो तब देख बहारें होली की,  
 और डफ के शोर खडकते हो तब देख बहारें होली की ।

नये युग के कवियों मे सागर निजामी ने कृष्ण के वांसुरी बजाने इत्यादि पर लिखा है—

अथ गोपाल भूमकर बसरी बजाओ फिर ।  
 बसरी के कंफ से दिल को गुदगुदाओ फिर,  
 प्रेम और प्रीति की, रीति को जगाओ फिर

° ° °

खुद ही तुम कमल बनो, खुद ही मुसकराओ फिर,  
 बूयगुल के रूप मे, सबके पास जाओ फिर,  
 बसरी बजाओ फिर दो जहाँ पै छाओ फिर,  
 अथ गोपाल भूमकर बसरी बजाओ फिर ।

यहाँ पर भजवर इलाहाबादी का जिक्र करना उचित होगा, जिनके ढेरों घोर अनेक हिन्दी लेखकों की रचनाओं मे उद्धृत किये हुए मिलेंगे । उनके बहुत-से घोर कहावतों का दर्जा पा गये हैं—

खीचो न कमानों को न तलवार निकालो,  
 जब तोप मुकाबिल हो तो भखबार निकालो ।

° ° °

कीम के गम मे डिनर खाते है हुक्काम के साथ,  
 रज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ ।

भजवर की नजर अवसर धार्मिक आस्था और पुरानी तहजीब पर रहती है । वह अंग्रेजियत के खिलाफ हैं लेकिन उसके बदले एक नई जनवादी संस्कृति का नक्शा उनके सामने नहीं है । उनके जमाने की सीमाएँ भी थी । फिर भी प्राचीनतावादियों पर कैसा व्यंग्य किया है । —

पेट भसख है किलकीं मे  
 दिल है ईरान और टर्की मे ।

प्राचीनतावाद और कट्टरतावाद के खिलाफ बहुत-से उर्दू कवियों ने लिखा है । यही सबब है कि वह अपने यहाँ एक जनवादी और प्रगतिशील परम्परा कायम कर सके हैं ।

मुस्लिम प्राचीनतावादियों पर व्यंग्य करते हुए जोश ने लिखा है—

भा ही नहीं सकता मेरे मुँह लालाए बुझदिल । (यानी बुझदिल लाला मेरी बराबरी नहीं कर सकता ।)

मैं पाक, वो नापाक, मैं गोरा हूँ, वो काला,  
 क्या उसका मेरा जिक्र, वो देशी मैं विदेशी,  
 मैं मिस्र की मस्जिद, वो बनारस का शिवाला,  
 गंगा की हर एक लहर में गलीदा है पस्ती,  
 दजले की हर एक मौज में खसा है हिमाला ।

(प्राचीनतावादी मोलाना फर्माते हैं कि गंगा की लहरों में पस्ती है और  
 दजला की मौजों में हिमालय का नजारा है ! )

जोश ने लिखा है कि शतान मोलवी को यो फंसा लेता है—

यही कह कह के राह करता है गुम  
 कि खुदा के हो खानदान से तुम ।

प्राचीनतावाद के विरोध के फलस्वरूप हिन्दू-मुस्लिम-एकता पर उर्दू कवियों  
 ने बहुत सुन्दर रचनाएँ की हैं ।

इकबाल ने लिखा था—

आ गैरियत के पदों एक बार फिर उठा दें,  
 बिछुड़ो को फिर मिला दें, नक़्शे दुई मिटा दें ।  
 सूनी पड़ी हुई है मुद्दत से दिल की बस्ती  
 आ एक नया शिवाला, इस देश में बसा दें ।  
 दुनिया के तीरथों में ऊँचा हो अपना तीरथ,  
 दामाने आसमाँ में उसका कलस मिला दें ।  
 हर सुबह उठके गाएँ मतर वो मीठे-मीठे,  
 सारे पुजारियों को मय पीत की पिला दें ।  
 शक्ती भी शान्ती भी भक्तों के गीत में है  
 धरती के बासियों की मुक्ती पिंगीत में है ।

यह याद रखना चाहिए कि हिन्दू-मुस्लिम-एकता की अड़िग और पक्की  
 नींव जनतंत्र ही है, भावुकता के आधार पर कायम की हुई एकता, सिर्फ  
 ईश्वर-भ्रूला का नाम लेकर कायम की हुई एकता टिकाऊ नहीं हो सकती ।  
 बहुत कांग्रेसी नेता एकता का दम भरते थे, आज वे प्राचीनतावाद और हिन्दू  
 सम्प्रदायवाद के भक्त नजर आते हैं । कारण यह है कि किसान मजदूरों के  
 आन्दोलन का विरोध करके, उनके सवर्ण को अपने लिए काल समझकर कोई  
 भी एकता का हिमायती नहीं हो सकता । उसे एकता अपने लिए एक खतरा  
 मालूम होने लगती है । इकबाल भी इस एकता को छोड़कर सम्प्रदायवाद की  
 तरफ झुक गये थे ।

उर्दू में अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ बहुत काफी और बहुत जोरदार  
 कविताएँ लिखी गई हैं । इन पर एक नजर डालने से ही जाहिर हो जाता है  
 कि यह आरोप कितना झूठा है कि उर्दू के कवियों को अपने देश से प्रेम नहीं  
 है । जोश ने खास तौर से साम्राज्य विरोधी आन्दोलन पर बहुत सुन्दर पक्तियाँ

लिखी हैं।

सन्दन मे बादशाह मगामत के राजगद्दी पाने पर जोश ने हिन्दुस्तान के बारे मे लिखा था—

किश्वरे हिन्दोस्ता मे रात को हगामे गाव,  
करवटें रह-रह के लेता है फजा मे इनकलाव,  
गर्म है सोजे बगावत मे जवानों का दिमाग,  
घ्रांधियां भाने को है ऐ बादशाही के चिराग

° ° °

आपके ऐवान मे रक्सा हैं लपटें ऊद की,  
हिन्दियो की मांस से आती है बू बारूद की।

साम्राज्यविरोधी आन्दोलन पर जोश ने लिखा था—

क्या हिन्द का जिन्दा काँप रहा है गूँज रही हैं तकरीरें,  
उकताए है शायद कुछ कैदी और तोड़ रहे हैं जजीरें।

° ° °

क्या उनको खबर थी, ओठों पर जो कुपल लगाया करते थे,  
एक रोज इसी खामोशी मे टपकेंगी दहकती तकरीरें,  
सँभलो कि वो जिन्दा गूँज उठा, भपटो कि वो कैदी छूट गये,  
उठठो कि वो बैठी दीवारें, दोड़ो कि वो टूटो जजीरें।

ईस्ट इंडिया कम्पनी के फर्जन्दो से कहा था—

इब कहानी बकत लिखेगा नये मजमून की  
जिसकी मुखी को जरूरत है तुम्हारे खून की।

जोश का साम्राज्य-विरोध १५ अगस्त, सन् '४७ के बाद गुमराह हो गया है। आजकल वह 'आजकल' के संपादक है। वह उन लोगों में है जो अपनी जनता का साथ छोड़कर उस दल के साथ जा मिले हैं जो हिन्दुस्तान को साम्राज्यवादी खेमे के साथ बाँधे हुए है।

३

उर्दू पर यह दोष लगाया जाता है कि उसमें फारसी की दस पाँच बहरें ही काम मे लाई जाती है और हिन्दी के हजारो छन्दो के भण्डार को अछूता छोड़ दिया गया है।

यहाँ पर पहले तो यह याद रखना चाहिए कि उर्दू की बहरें अब सिर्फ उर्दू तक सीमित नहीं रही। हिन्दी में बहुत-से कवियों ने उन्हें अपना लिया है और उनमें बरोक रचनाएँ करते हैं। इस तरह की रचनाएँ वे कवि भी करते हैं, जो प्राचीनतावाद के उपासक हैं, जैसे दिनकर।

धुंधली हुई दिशाएँ, छाने लगा कुहासा,  
बुझली हुई शिक्षा ने, भाने लगा धुमाँसा,

कोई मुँह बता दे, क्या आज हो रहा है,

मुँह को छिपा निमिर मे, क्यों तेज रो रहा है।

इसके अलावा फारसी की बहरो और हिन्दी के छन्दो में उतना फर्क नहीं है जितना कुछ लोग समझते हैं। श्री हरिदास शर्मा ने अपने 'उर्दू साहित्य के इतिहास' (पृ० १६) में लिखा है—“उर्दू में इस्तेमाल होनेवाले कुछ छन्दों के नाम ये हैं—सुमेरु, विधाता, विहारी, शास्त्र, धीमूपवर्षा, मुजगप्रमात, पारारो, हरिगीतिका, आनन्दवर्द्धक, दिग्पाल, भुजगी, चौपाई आदि। इससे यह तो बाहिर ही होता है कि छन्दों के लिहाज से हिन्दी-उर्दू की सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच कोई गहरी न पट सजनेवाली खाई नहीं है।

छायावादी कवियों ने—छासकर निरालाजी ने—जिम तरह मुक्तछन्द लिखने की प्रथा डाली थी, उसी तरह उर्दू में बहुत से कवियों ने भी मुक्तछन्द में रचनाएँ की। लेकिन जो चीज हिन्दी उर्दू कवियों को सबसे ज्यादा नजदीक लाती है, वह उनके गीत हैं। उर्दू कवि एक अरसे में गीत लिखते आये हैं। प्रगतिशील कवियों ने जो गीत लिखे हैं वे रोमांटिक गीतों के तग दापरे से निकलकर आम जनता के गले में रम चुके हैं। ऐसे गीत एक दो नहीं, सैकड़ों हैं। उर्दू साहित्य का यह पहलू उसका सबसे लोकप्रिय और जनवादी रूप हमारे सामने लाता है। इन गीतों की सांस्कृतिक परम्परा एक ऐसी शक्तिशाली और प्रगतिशील परम्परा है जो हिन्दी-उर्दू के बाकी भेदभाव को दूर करने में बहुत बड़ी मदद करेगी। इन गीतों को देखने से पता चलता है कि जब हम जनता के सवर्ण, उसकी मुसीबतों, आशाओं और आदशों का लेकर साहित्य रचते हैं तब प्राचीनतावाद के तमाम अलगाव पैदा करनेवाले रूप आपस आपस खत्म हो जाते हैं। हमारी जनता की सत्कृति एक है। हमारा साहित्य जितना ही जनता के नजदीक आता है, उतना ही उसकी सांस्कृतिक परम्परा प्राचीनता से मुँह मोड़कर अपने नये मौजूदा जमाने में तख्त चुनती है। जनता की यह सबल सांस्कृतिक परम्परा पुराने जमाने की सत्कृति से सिर्फ व चीजें खींची है जो उसमें धार्मिक अन्धविश्वास और भेदभाव पैदा करने के बदले उसे एकता, आजादी और जनसत्ता के नजदीक ले जाती हैं और जनवादी भावनाओं को मजबूत करती हैं।

उर्दू के कवियों ने हमारे जन-आन्दोलन को जो गीत दिये हैं उनमें मखदूम मुहीउद्दीन का गीत— यह जग है जगे आजादी आजादी के परचम के तले मजदूर वर्ग का अपना गीत है। बंगाल के अकाल पर धार्मिक का यह गीत लोकप्रिय हो चुका है—

पूरब देस में दुग्गी बाजी फँसा दुख का जाल,  
दुख की घगनी कौन बुझाये सुख गये सब ताल,  
जिन हाथों ने माती रोले आज वही कगाल,  
रे माथी आज वही कमाल।

भूला है बगाल ।

भूला है बगाल रे साथी, भूला है बगाल ।

इसी तरह मजाज का गीत 'बोल अरी ओ घरती, बोल, राजसिंहासन डाँवाडोल' मली सरदार जाफरी के कई गीत, प्रेम धवन का 'घरे भब भागो, लन्दन जाओ' उर्दू में एक ऐसी परम्परा की नींव डाल चुके हैं जिसे हम हिन्दी-उर्दू की मिली-जुली परम्परा कह सकते हैं।

प्राधुनिक उर्दू कविता उन तमाम रूपों और कल्पनाओं से पीछा छुड़ा चुकी है जिन्हें श्री रघुपतिसहाय पिराक ने 'सदा बहार और सदा सोहाग' कहा था। उन्होंने भारतेन्दु से लेकर निराला तक हिन्दी-साहित्य के तमाम विकास पर जो बहारी फेर दी थी, उससे हिन्दी को उर्दू के नजदीक लाने में मदद न मिल सकती थी। इसके अलावा हिन्दी के तमाम विकास पर कीचड़ उछालने के बाद उन्होंने आदर्श रूप से जो दोर पेश किये थे और पुराने रूपों के शाश्वत सौन्दर्य की जो व्याख्या की थी, वह एक प्रतिज्ञावादी काम था, जिसका विरोध करना जरूरी था। पुराने रूपों और प्राचीनतावाद का विरोध जिन तरह उर्दू के नये कवियों ने—खास तौर से प्रगतिशील कवियों ने—किया है, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जाय, थोड़ी है। इस सिलसिले में मिर्ते हुसैन का लेख विशेष ध्यान देने योग्य है जिसमें उन्होंने इकबाल की जनतन्त्र-विरोधी धारणाओं की आलोचना की थी। यह लेख 'नया अदब' में छपा था (जब 'नया अदब' लखनऊ से निकलता था)। जिस तरह हिन्दी की प्रगतिशील कविता पर यह तोहमत लगाई जाती है कि उसने प्राचीन संस्कृति से नाता तोड़ लिया है, वह छिछली राजनीतिक और प्रचारात्मक हो गई है वगैरह, उसी तरह उर्दू की प्रगतिशील कविता पर भी आरोप लगाए जाते रहे हैं। इनका जवाब देते हुए एहतेशाम हुसैन ने बहुत-कुछ लिखा है और उन्होंने उर्दू में नई तरह की आलोचना को आगे बढ़ाया है। उर्दू की आलोचना, उसके नाटक, कहानियाँ, उपन्यास आज उसी तरह नये रास्ते पर चल रहे हैं जिस तरह हिन्दी-साहित्य के ये रूप। उपन्यासों और कहानियों का सम्बन्ध अवाम की जिन्दगी से होता है, इसलिए इनमें प्राचीन रूपों, अलंकारों वगैरह का असर नहीं के बराबर होता है। हिन्दी के बहुत से पाठक 'हंस' में कृशनचन्दर की कहानियाँ, स्केच पढ़ चुके होंगे। खास तौर से रुद्रदत्त भारद्वाज पर उनका स्केच, 'तीन गुड्डे' नाम की कहानी यह जाहिर करती है कि उर्दू-साहित्य मौजूदा जिन्दगी से अपनी विषयवस्तु चुनकर एक मिली-जुली जनवादी परम्परा गढ़ रहा है।

उर्दू की नई कविता में पुरानी व्यवस्था का विरोध और जनतन्त्र की तरफ बढ़ने की स्वादिष्ट पग-पग पर मिलती है। उर्दू कविता में देश-विदेश की महत्वपूर्ण घटनाओं, जन आन्दोलनों की गहरी छाप है। रूस पर हिटलरों हमला, लाल फौज का वीरतापूर्ण सभ्राम, बर्लिन की जीत, हिन्दुस्तान में क्रिष्ण-

मिशन का घाना, देश का बँटवारा, साम्प्रदायिक दंगे, गांधीजी की हत्या, आजाद हिन्दुस्तान मे जनता के आन्दोलनो का दमन, नये जन सघर्ष, इन सभी की तसवीरें उर्दू कविता मे मिलेंगी । इनसे स्पष्ट हो जाता है कि उर्दू की सांस्कृतिक परम्परा को आज वही घटना-क्रम, वही सामाजिक परिस्थितियाँ, वही जन-सघर्ष रच रहे हैं जो हिन्दी की सांस्कृतिक परम्परा रच रहे हैं । (१९४६)

## भारत की भाषा-समस्या

### भाषा-समस्या का सामान्य महत्व

भाषा-समस्या मजदूर वर्ग, उसकी पार्टों, तमाम श्रमिक जनता और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लेनिन के शब्दों में, "भाषा मानवीय सम्पर्क का सबसे महत्वपूर्ण साधन है" (जातियों के आत्मनिर्णय का अधिकार)।

भाषा-समस्या का महत्व सामाजिक विकास की मजिलों में अलग-अलग होता है।

पूँजीवाद से पहले सामन्ती और कबीलाई सामाजिक सम्बन्ध विभिन्न जनसमूहों को एक ही जाति (नेशन) में सगठित होने से रोकते हैं, इसलिए वे आधुनिक भाषाओं के विकास में भी बाधा डालते हैं। वस्तुगत रूप से पूँजीवाद किसी जाति के गठन में प्रगतिशील भूमिका पूरी करता है, इस तरह वह आधुनिक भाषाओं के विकास में भी प्रगतिशील भूमिका पूरी करता है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जातीय समस्या और भाषा-समस्या में बड़ा गहरा सम्बन्ध है, किसी जाति के सामाजिक विकास तथा उस विकास के सांस्कृतिक प्रतिबिम्ब में गहरा सम्बन्ध है। यह सांस्कृतिक प्रतिबिम्ब सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है।

लेनिन के अनुसार "समस्त संसार में सामन्तवाद पर पूँजीवाद की अन्तिम विजय का युग जातीय आन्दोलनों के साथ जुड़ा रहा है। इन आन्दोलनों का आर्थिक आधार यह है कि बिकाऊ माल की पैदावार को पूर्ण विजयी बनाने के लिए पूँजीपतियों के हाथ में घरेलू बाजार आ जाना चाहिए, उनके अधिकार में राजनीतिक रूप से एकताबद्ध प्रदेश होने चाहिए जहाँ के लोग एक ही भाषा बोलते हों, इस भाषा के विकास में और साहित्य में उसके व्यवहार को सुनिश्चित करने में जो भी अड़चनें आती हैं, उन्हें दूर करना होता है।"

पूँजीवादी सामाजिक विकास की आवश्यकताएँ, बड़े पैमाने पर जातियों के आत्मनिर्णय का अधिकार, व्यापार-सम्बन्ध कायम करने की आवश्यकताएँ,

परलू वाजार को सुगुणवस्थित करने की आवश्यकताएँ सक्षेप में यह कि जातीय पैमाने पर पूँजीवादी सामाजिक सम्बन्धों के गठन की आवश्यकताएँ भाषा की एकमूर्तता और उसके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। भाषा की एकता और विकास के बिना आधुनिक जानियों का विकास असम्भव है।

'मार्क्सवाद तथा जातीय और औपनिवेशिक समस्या' नाम की पुस्तक में स्तालिन ने बताया है कि जो जातियाँ पूँजीवादी विकास में पिछड़ गईं, जिन्हें बहुजातीय पूँजीवादी राष्ट्र में राज्य बनाने के अधिकार नहीं मिले, उनका उत्पीड़न उन बड़ी जातियों के पूँजीपतियों ने किया जो पूँजीवादी विकास में आगे रही थी। जारसाही रूस में गैर रूसी जातियों की भाषाओं का दमन किया गया। अपनी भाषा का व्यवहार करने के लिए सघर्ष जातीय आन्दोलन का मुख्य अंग बन गया। उत्पीड़ित जाति के पूँजीपति सभी वर्गों को अपने हितों के लिए एकजुट करने का प्रयत्न करते हैं। भाषा-समस्या को लेकर भी उनकी यही नीति रहती है। किन्तु भाषा की समस्या उत्पीड़ित जाति के मजदूर वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्तालिन के अनुसार "तातार या यहुदी मजदूर को सभा और भाषाओं में अपनी भाषा का व्यवहार करने की सुविधा न दी जाय, यदि उसके स्कूल बन्द कर दिए जाएँ तो उसके बौद्धिक विकास की कोई सम्भावना न रहेगी," (मार्क्सवाद तथा जातीय और औपनिवेशिक समस्या)। मजदूर वर्ग के हित में है कि वह स्कूलों, भाषणों, अखबारों आदि में अपनी भाषा के व्यवहार के लिए लड़े।

स्तालिन ने यह भी बताया है कि उत्पीड़न से पूँजीपतियों के लिए यह आसान हो जाता है कि मजदूर वर्ग को यह मुलावा दें कि उसके और पूँजीपतियों के हित एक हैं। जातीय समस्या मुख्य सामाजिक प्रश्नों से लोगों का ध्यान हटा देती है। भाषा-समस्या से भी पूँजीपति इस प्रकार लाभ उठाते हैं और लोगों को क्रान्ति के रास्ते से हटा देते हैं।

समाजवादी क्रान्ति के बाद जातियों का नया स्वाधीन विकास आरम्भ हुआ। सोवियत संघ में जातियाँ स्वायत्त सत्ता के अधिकारों का व्यवहार में ला सकें, इसके लिए अपनी भाषा के विकास और व्यवहार का प्रश्न फिर सामने आया। स्कूलों, अदालतों, सरकारी संस्थाओं आदि में अपनी भाषा के व्यवहार के बिना कोई भी जाति सोवियत स्वायत्त शासन को समझी रूप नहीं दे सकती।

समाजवादी क्रान्ति के बाद भी सोवियत संघ में पूँजीवाद के अवशेष बने रहे। यह अवशेष इस बात से जाहिर हुए कि जातीय समस्या को लेकर छोटी और बड़ी दोनों ही तरह की जातियों में अंध-राष्ट्रवाद के रुझान दिखाई दिए। एक तरफ तो सोवियत संघ में ऐसे लोग थे जो कहते थे कि उर्बेनी नाम की कोई जाति ही नहीं है; इन लोगों का विचार था कि बोल्शेविक पार्टी कृत्रिम रूप से इस जाति को गढ़कर खड़ा कर रही है। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि समाजवाद की जीत के बाद सब जातियाँ मिलकर एक ही जादीबी,



## भारत की भाषा-समस्या

### भाषा-समस्या का सामान्य महत्व

भाषा-समस्या मजदूर वर्गों, उसकी पार्टी, तमाम श्रमिक जनता और प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लेनिन के शब्दों में, "भाषा मानवीय सम्पर्क का सबसे महत्वपूर्ण साधन है" (जातियों के आत्मनिर्णय का अधिकार)।

भाषा-समस्या का महत्व सामाजिक विकास की मंजिलों में अलग-अलग होता है।

पूँजीवाद से पहले सामन्ती और कबीलाई सामाजिक सम्बन्ध विभिन्न जनसमूहों को एक ही जाति (नेशन) में संगठित होने से रोकते हैं, इसलिए वे आधुनिक भाषाओं के विकास में भी बाधा डालते हैं। वस्तुगत रूप से पूँजीवाद किसी जाति के गठन में प्रगतिशील भूमिका पूरी करता है, इस तरह वह आधुनिक भाषाओं के विकास में भी प्रगतिशील भूमिका पूरी करता है।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि जातीय समस्या और भाषा-समस्या में बड़ा गहरा सम्बन्ध है, किसी जाति के सामाजिक विकास तथा उस विकास के सांस्कृतिक प्रतिबिम्ब में गहरा सम्बन्ध है। यह सांस्कृतिक प्रतिबिम्ब सामाजिक विकास को भी प्रभावित करता है।

लेनिन के अनुसार "समस्त ससार में सामन्तवाद पर पूँजीवाद की अन्तिम विजय का युग जातीय आन्दोलनों के साथ जुड़ा रहा है। इन आन्दोलनों का आर्थिक आधार यह है कि बिकाऊ माल की पैदावार को पूर्ण विजयी बनाने के लिए पूँजीपतियों के हाथ में घरेलू बाजार आ जाना चाहिए, उनके अधिकार में राजनीतिक रूप से एकताबद्ध प्रदेश होने चाहिए जहाँ के लोग एक ही भाषा बोलते हों, इस भाषा के विकास में और साहित्य में उसके व्यवहार को सुनिश्चित करने में जो भी अड़चनें आती हैं, उन्हें दूर करना होता है।"

पूँजीवादी सामाजिक विकास की आवश्यकताएँ, बड़े पैमाने पर जातियों के आत्मनिर्णय का अधिकार, व्यापार-सम्बन्ध कायम करने की आवश्यकताएँ,

परन्तु बाइर को मुख्यस्थित करने की आवश्यकताएँ सक्षेप में यह कि जातीय पैमाने पर पूँजीवादी सामाजिक मन्त्रियों के गठन की आवश्यकताएँ भाषा की एकसूत्रता और उसके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाती हैं। भाषा की एकता और विकास के बिना आधुनिक जातियों का विकास असम्भव है।

'मार्क्सवाद तथा जातीय और औपनिवेशिक समस्या' नाम की पुस्तक में स्तालिन ने बताया है कि जो जातियाँ पूँजीवादी विकास में पिछड़ गईं, जिन्हें बहुजातीय पूँजीवादी राष्ट्र में राज्य बनाने के अधिकार नहीं मिले, उनका उत्पीड़न उन बड़ी जातियों के पूँजीपतियों ने किया जो पूँजीवादी विकास में आगे रहीं थी। जारशाही रूस में गैर रूसी जातियों की भाषाओं का दमन किया गया। अपनी भाषा का व्यवहार करने के लिए संपूर्ण जातीय आन्दोलन का मुख्य अंग बन गया। उत्पीड़ित जाति के पूँजीपति सभी वर्गों को अपने हितों के लिए एकजुट करने का प्रयत्न करते हैं। भाषा समस्या को लेकर भी उनकी यही नीति रहती है। किन्तु भाषा की समस्या उत्पीड़ित जाति के मजदूर वर्ग के लिए भी महत्वपूर्ण है। स्तालिन के अनुसार "तातार या यहूदी मजदूर को मरना और भाषाओं में अपनी भाषा का व्यवहार करने की सुविधा न दी जाय, यदि उसके स्कूल बन्द कर दिए जाएँ तो उसके बौद्धिक विकास की कोई सम्भावना न रहेगी," (मार्क्सवाद तथा जातीय और औपनिवेशिक समस्या)। मजदूर वर्ग के हित में है कि वह स्कूलों, भाषणों, अखबारों आदि में अपनी भाषा के व्यवहार के लिए लड़े।

स्तालिन ने यह भी बताया है कि उत्पीड़न में पूँजीपतियों के लिए यह प्रामाण्य हो जाता है कि मजदूर वर्ग को यह मुलावा दें कि उसके और पूँजीपतियों के हित एक हैं। जातीय समस्या मुख्य सामाजिक प्रश्न से लोगों का ध्यान हटा देती है। भाषा-समस्या से भी पूँजीपति इस प्रकार लाभ उठाते हैं और लोगों को ज़ान्ति के रास्ते से हटा देते हैं।

ममजवादी ज़ान्ति के बाद जातियों का नया स्वाधीन विकास आरम्भ हुआ। सोवियत संघ में जातियाँ स्वायत्त सत्ता के अधिकार को व्यवहार में ला सकें, इनके लिए अपनी भाषा के विकास और व्यवहार का प्रश्न फिर सामने आया। स्कूलों भेदाहतों, सरकारी संस्थाओं आदि में अपनी भाषा के व्यवहार के बिना कोई भी जाति सोवियत स्वायत्त शासन को प्रमत्ती रूप नहीं दे सकती।

समाजवादी ज़ान्ति के बाद भी सोवियत संघ में पूँजीवाद के अवशेष बने रहे। यह अवशेष इस बात से जाहिर हुए कि जातीय समस्या को लेकर छोटी और बड़ी दोनों ही तरह की जातियों में अथवा राष्ट्रवाद के प्रभाव दिखाई दिए। एक तरफ तो सोवियत संघ में ऐसे लोग थे जो कहते थे कि उन्हें नाम की कोई जाति ही नहीं है; इन लोगों का विचार था कि बोल्टोविक पार्टी कृत्रिम रूप से इस जाति को गढ़ा कर रही है। दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि समाजवाद की जीत के बाद सब जातियाँ मिश्रित हो जाएँगी,

उनकी भाषाएँ आपस में घुल-मिल जाएँगी और सबकी एक ही सामान्य भाषा होगी। गैर रूसी जातियों में कुछ लोग ऐसे थे जो यह माँग करते थे कि उनकी जाति के मजदूरों की संस्कृति को रूसी मजदूर वर्ग की संस्कृति के प्रभाव से मुक्त रखा जाय। इस प्रकार समाजवादी क्रान्ति के बाद भी विभिन्न रूपों में अध-राष्ट्रवाद का खतरा बना रहा।

मजदूर वर्ग को भाषा-समस्या का दोहरा महत्व समझना चाहिए। मजदूर-वर्ग के घटने राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भाषा-समस्या का महत्व है, साथ ही क्रान्ति के विरुद्ध पूँजीपति वर्ग उसका उपयोग मजदूरों को भटकाने के लिए भी करता है।

पूँजीवाद में पहले के समाज में मुख्य कर्तव्य यह होता है कि सामन्ती विघटन के खिलाफ भाषा की एकता के लिए संघर्ष किया जाय। आगे बढ़ी हुई जातियों के सर्वहारा वर्ग का कर्तव्य है कि वह पिछड़े लोगों को जातिरूप में सुगठित होने में मदद दे।

जहाँ जातियाँ औद्योगिक विकास की मजिलें पार कर चुकी हैं लेकिन जिन्हें अपनी भाषा का व्यवहार करने की आजादी नहीं है वहाँ उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही तरह की जातियों के मजदूर वर्ग का कर्तव्य यह है कि जनवादी क्रान्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जातीय भाषा के व्यवहार के अधिकार के लिए संघर्ष करें। पूँजीवाद पर मजदूर वर्ग की विजय के पहले और बाद को—दोनों ही स्थितियों में—इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भाषा-समस्या को लेकर छोटी और बड़ी—दोनों ही तरह की—जातियों में अध-राष्ट्रवादी रुझान पैदा न हो।

यह हुआ भाषा समस्या का सामान्य महत्व।

## भारत में भाषा-समस्या का विशेष महत्व

ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भारत की तमाम जनता संघर्ष करती रही है—सबसे पहले भाषा-समस्या का महत्व इस संघर्ष के सन्दर्भ में है।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अंग्रेजी को अनिवार्य राजभाषा के रूप में भारत पर इसलिए लादा कि वह जनता का शोषण कर सके। इस प्रकार उसने भारत की अनेक जातियों की भाषाओं की प्रगति में बाधा डाली। स्वाधीनता-संग्राम के दौरान भारतीय जनता ने यह माँग बराबर पेश की कि शिक्षा-संस्थाओं, अदालतों, शासनतंत्र आदि में अंग्रेजी की जगह उसकी भाषा का चलन हो। जातीय प्रदेशों में अंग्रेजी की जगह वहाँ की भाषाओं का व्यवहार हो, जनता के लिए यह अब भी ज्वलन्त प्रश्न बना हुआ है और अगस्त, सन् १९४७ के राजनीतिक परिवर्तन के बाद यह समस्या अभी कहीं हल होती नहीं दिखाई देती।

हिन्दुस्तानी क्षेत्र तथा समस्त भारत की राजभाषा हिन्दी, उर्दू अथवा हिन्दुस्तानी हो—इस सन्दर्भ में भारत की भाषा समस्या विशेष महत्वपूर्ण हो

गई है। सबसे बड़ा विवाद समस्या के इसी पक्ष को लेकर हुए हैं। प्रमुख सामाजिक समस्याओं से जनता का ध्यान हटाने में उच्च वर्गों के पास हिन्दी-उर्दू समस्या सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक साधन रही है। साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए इस समस्या का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। भारत और पाकिस्तान में चरम प्रतिक्रियावादी धरम हित साधने के लिए इस समस्या का उपयोग करते हैं।

भारत-जैसे बहुजातीय देश में धनिवार्य राजभाषा का प्रश्न महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुजातीय पूँजीवादी राज्यों से देखा जाता है कि इस तरह की धनिवार्य राजभाषा राजनीतिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में दूसरी भाषाओं के व्यवहार पर रोक लगाती है और कभी-कभी उनके इस अधिकारों को एकदम अस्वीकार करती है। भारत के बड़े पूँजीपतियों से अन्य जातियों और जनसमूहों का कोई सम्बन्ध है, उसे देखते हुए राष्ट्रभाषा का प्रश्न अपना वर्ग-महत्व रखता है।

कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ लोग मिली-जुली बोलीयाँ बोलते हैं। वहाँ सामन्ती सम्बन्ध छन्न भी कायम हैं। वहाँ के जातीय प्रदेश में टकसाली जातीय भाषा का विकास अभी तक नहीं हो पाया। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश जहाँ पहाड़ी बोलियाँ बोली जाती हैं ऐसे ही इलाके हैं।

भाषा-समस्या बचीली और पिछड़े हुए जातीय गुटों के लिए महत्वपूर्ण है। विभिन्न पूँजीवादी गुट इनका शोषण करते हैं। उन्हें अपनी भाषाओं के व्यवहार करने का अधिकार नहीं है। उनकी भाषाओं का अस्तित्व ही अस्वीकृत कर दिया जाता है।

इतनी बातों से ही स्पष्ट हो जाता है कि मजदूर वर्ग और उसकी पार्टों को भाषा-समस्या पर कौी ध्यान देना चाहिए।

### ब्रिटिश साम्राज्यवाद और राजभाषा के रूप में अंग्रेजी की भूमिका

शिक्षा और संस्कृति के मामलों में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नीति यह रही है कि ग्राम जनता की अज्ञान और पिछड़ेपन की दशा में रखा जाय। सामन-व्यवस्था के लिए क्लर्कों की फौज तैयार करने के लिए साम्राज्यवाद ने अंग्रेजी की पढाई धनिवार्य कर दी और उसे शिक्षा का धनिवार्य माध्यम बनाया। पदचाल्य विचारधारा के सम्पर्क से भारतीय भाषाओं और साहित्य को जो भी लाभ हुआ, वह अप्रत्यक्ष रूप से हुआ; वह नाम साम्राज्यवादियों की भाषाओं के विपरीत था। इस बात का प्रचार वे बराबर करते रहे कि भारत भाषाओं का अज्ञायवर्ध है और उसमें जो भी एकता है, वह इसलिए कि अंग्रेजी ने 'लिगुमा प्राकृत' की भूमिका पूरी की है। यूरोप के अनेक प्रसिद्ध भाषाशास्त्रियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की यह स्थापना मान ली, इसलिए भी कि अपने उपनिवेशों में वे भी यही खेल खेल रहे थे।

भारतीय जनता ने माँग की कि शिक्षा, अदालत, बचहरी, ग्रामन इत्यादि

मे अंग्रेजी की जगह अपनी अपनी भाषा को । यह विमर्शपूर्ण माँग थी । राष्ट्रीय नेताओं ने भाषा की जाती को कि मन् १९४७ में घोषणा पाने के बाद इस माँग को वे पूरा करेंगे । लेकिन विभिन्न कारणों से वे उसे पूरा नहीं कर सके । सत्रों पटना कारण तो यह है कि अक्सर ये नेता स्वयं अंग्रेजी में डूबे होते हैं । उन्हीं भारतीय भाषाओं के विकास के लिए प्रायः कुछ भी नहीं किया । दूसरा कारण यह है कि वे विभिन्न जातीय भाषाओं में मस्तिष्क के गहराई से नीति पर रत रहे हैं, जिससे कि आम जनता के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में भाग न ले सके । जब हम मस्तिष्क-गर्भा भाषा पर लोग हैंते हैं और उनकी होंसी उचित ही है, तब वे एक गहरा अंधकार अंग्रेजी की शरण में लौट आते हैं और कहते हैं कि अंग्रेजी अभी पाँच या दस साल और चलने दी जाय । दस साल तक उद्योग-धन्यों का राष्ट्रीयकरण न होगा, वैसे ही पाँच या दस साल तक आम जनता की उच्च शिक्षा, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यवाही उसकी अपनी भाषा में न होगी ।

कुछ विद्वान् हिन्दी के ही मस्तिष्क-करण की माँग नहीं कर रहे हैं । बँगला जैसी भाषा में भी वही विद्वान् उसी मस्तिष्क-करण की माँग कर रहे हैं और उनका उद्देश्य भी वही है । कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल की सरकार ने उच्चकोटि के विद्वानों की एक समिति बनाई जिसमें प्रसिद्ध भाषाविद् डा० सुनीतिकुमार चटर्जी भी थे । इस समिति का यह काम मीठा गया था कि वह शासन में व्यवहार के लिए बँगला में पारिभाषिक शब्दावली बनाए । हम शब्दावली की भूमिका में उन उच्चकोटि के विद्वानों ने कुछ प्रचलित शब्दों को प्रस्वीकृत कर दिया क्योंकि उनकी समझ में वे शब्द वाक्यी गरिमायुक्त नहीं हैं । उनके यहाँ उन्होंने ऐसा शब्द रखा है जो जन माधारण की समझ में नहीं आते, जो कभी-कभी समाधारण जनो की समझ में नहीं आते । इसलिए पारिभाषिकी निर्माताओं ने बंगाली जनता के देश-प्रेम को गलतवारा है कि जैसे वे अंग्रेजी का अध्ययन करते रहें हैं वैसे ही मातृभाषा के अध्ययन को भी अधिक समय दें ।

केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें जनता की इस माँग को पूरा नहीं कर पा रही कि शिक्षा संस्थाओं में बचहरी, प्रदानत, सरकारी दफतरी आदि में जनता की भाषाओं का व्यवहार हो । शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की विरासत कायम है ।

पूँजीवादी सामन्ती औपनिवेशिक व्यवस्था भारतीय भाषाओं के पूर्ण विकास को रोकती है । शासक वर्ग जनता को या तो अंग्रेजी की शरण लेने को कहते हैं या भारतीय भाषाओं का ऐसा मस्तिष्क-करण करते हैं कि वे लोगों को दुर्बोध हो जाएँ ।

### अनिवार्य राजभाषा का सवाल

विभिन्न प्रदेशों में अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं का व्यवहार हो,

यह सही माँग है और मजदूर वर्ग को इसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन अंग्रेजी की जाह सारे देश में एक ही भाषा का चलन हो, यह माँग उस जनतांत्रिक माँग से भिन्न है। अंग्रेजों ने सारे भारत पर अंग्रेजी लादी—यह साम्राज्यवादी कार्य था। उसका स्थान एक भारतीय भाषा ले ले, यह बात जनतांत्रिक और न्यायपूर्ण न होगी। फिर भी पूँजीवादी नेता हिन्दी उर्दू या हिन्दुस्तानी और अंग्रेजी को भी अनिवार्य राजभाषा बनाने का कार्य करते रहे हैं।

भारत की एम्पुनिस्ट पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में कहा गया है कि बड़े पूँजीपति महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु आदि प्रदेशों के आत्मनिर्णय के अधिकार को नहीं मान रहे। 'हिन्दुस्तान टाइम्स' ने ६ दिसम्बर, १९४८ के अंक में लिखा है कि ब्रिटिश 'सम्पर्क' की कुछ विरासत सुरक्षित रहनी चाहिए जैसा कि हार्दिकोटों में केन्द्रीय भाषा का ही चलन होना चाहिए और विभिन्न प्रान्तों में एक ही केन्द्रीय भाषा का चलन न होने से उच्च शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ेगी। इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों के हार्दिकोटों और उच्च शिक्षा-महाविद्यालयों में एक ही केन्द्रीय भाषा के चलन की माँग करके बड़े पूँजीपति जातियों के पूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास में बाधा डालते हैं।

भारत के बड़े पूँजीपति चाहते हैं कि अंग्रेजों की जगह देश के शोषक बन जाएँ, यह सम्भव न हो तो विदेशी मालिकों के साथ मिलकर शोषण में हिस्सा बँटाएँ। जब तक साम्राज्यवाद में समझौता नहीं हुआ था, तब तक वे भाषायी झगड़ों—अर्थात् वहाँ के पूँजीपतियों—के आत्मनिर्णय का अधिकार मानते थे। विदेशी मालिकों की छत्रछाया में जहाँ एक बार उनका अधिकार राज्यसत्ता पर हो गया, वहाँ उन्होंने राष्ट्रवाद, एकता, केन्द्र आदि के नाम पर अपने वादे तोड़ना प्रारम्भ कर दिया। भारत के बड़े व्यापारी सारे भारत के लिए एक राष्ट्रभाषा या राजभाषा की चर्चा बराबर करते रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा वे अपने हित में बाजार को सुदृढ़ कर सकेंगे और दूसरी जातियों के पूँजीपतियों को निकाल सकेंगे।

जो लोग हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी बोलते या लिखते हैं, उन्हें बड़े पूँजीपतियों की महत्वाकांक्षाओं से दिलचस्पी नहीं हो सकती। वे बिनाकुल न चाहेंगे कि किसी भारतीय भाषा के पूर्ण और स्वतन्त्र विकास में बाधा डाली जाय। बड़े पूँजीपति उनकी साम्राज्य विरोधी भावना से लाभ उठाना चाहते हैं। वे पूछते हैं अंग्रेजी जाय, उसकी जगह कौन-सी भाषा ले?

धामनता प्रदर्शय चाहती है कि अंग्रेजी उन पर न लदी रहे जैसे वह अब तक लदी रही है। बड़े पूँजीपति इस बात को जानते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अंग्रेजी जाय। लेकिन वे लोगों को यह सोचने का मौका नहीं देते कि उसकी जगह कौन लेगा? बजाय यह कहने के कि जब अंग्रेजी जायगी तब प्रत्येक भारतीय भाषा को अपने स्वत्व प्राप्त होंगे, वे पूछते हैं, कौन-सी एक भाषा अंग्रेजी की जगह लेगी। इस तरह सवाल को पेदा करके वे जनता को

गुमराह करते हैं।

जो लोग चाहते हैं कि हम तरह के सवाल जनताधिकार ढंग से हल किये जाएँ, वे सच पहले हर जाति का यह हक मानेंगे कि हर स्तर पर वह अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक बायों में अपनी भाषा का व्यवहार कर सके और इस अधिकार पर कोई भी रोक न लगनी चाहिए।

रूस के पूँजीवादी-सामन्ती राज्य में बोल्शेविक पार्टी ने माँग की थी कि अनिवार्य राजभाषा का चलन बन्द किया जाय। उसने हर जाति को राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी भाषा के व्यवहार की पूरी छूट दी। बोल्शेविक पार्टी पर यह आरोप लगाया गया कि उसकी नीति व्यावहारिक है। लेनिन ने इस आरोप का उत्तर देते हुए लिखा, "हर जाति के राष्ट्रवादी पूँजीपतियों की दृष्टि में सर्वहारा का सारा काम जातीय समस्या के सन्दर्भ में हवाई होता है। सर्वहारा जन हर तरह के राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं, इसलिए वे 'हवाई' समानता की माँग करते हैं। वे माँग करते हैं कि सिद्धान्ततः किसी को थोड़े से भी विशेषाधिकार न मिलें।"

पूँजीपति भाषा समस्या का व्यावहारिक समाधान पेश करते हैं। वे कहते हैं कि इतनी भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें छपवाने से व्यर्थ का खर्च होता है। तमाम उच्च न्यायालयों और विश्वविद्यालयों में एक ही केन्द्रीय भाषा का चलन होना चाहिए। मजदूर वर्ग इस तरह की व्यावहारिकता को स्वीकार नहीं कर सकता।

सोवियत संघ में रूसी अनिवार्य राजभाषा नहीं है। प्रधान सोवियत में हर एक को अपनी भाषा में बोलने का अधिकार है और मध्य गैर-रूसी भाषाओं में दिये हुए भाषणों के अनुवाद की माँग कर सकते हैं। सोवियत संघ के प्रजातन्त्रों में रूसी की पढाई स्कूलों और कालेजों में अनिवार्य है। इसमें कोई बुराई नहीं है। जातियों की मर्जों के खिलाफ रूसी की पढाई अनिवार्य नहीं की गई। भारत में यदि सभी जातियों से बराबर संख्या में जनवादी ढंग से चुने हुए प्रतिनिधि शिक्षाक्रम में किसी स्तर पर किसी एक भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य करना चाहे और किसी जाति के प्रतिनिधि इसका विरोध न करें तो इस तरह की अनिवार्य शिक्षा में कोई दोष नहीं है। मुख्य बात यह है कि कोई भाषा किसी जाति पर उसकी इच्छा के विरुद्ध लादी न जानी चाहिए।

बहुजातीय पूँजीवादी राष्ट्र में जातियों का उत्पीड़न हाता है, उसमें अनिवार्य राजभाषा बड़े पूँजीपतियों के हित साधन का कारण बनती है। उससे विभिन्न जातियों की श्रमिक जनता में एकता नहीं पैदा होती बल्कि परस्पर वैमिष्ट उत्पन्न होता है। हम नहीं चाहते कि कोई एक भाषा अंग्रेजी की जगह ले। विदेशी साम्राज्यवाद ने हमारे ऊपर अंग्रेजी ला दी थी। हम नहीं चाहते कि किसी भारतीय भाषा के पूर्ण विकास पर कोई देशी साम्राज्यवादी रोक लगाएँ। बड़े पूँजीपति उन जातियों के अधिकार नियन्त्रित करते हैं जो कमोबेश

धार्मिक विकास कर चुकी है; जो जातियाँ पिछड़ी हुई हैं, उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को ये बड़े पूंजीपति धक्का दे रहे हैं। वे उनसे कहते हैं तुम्हारी अपनी कोई भाषा नहीं है; जो भाषा हम तुम पर ला दें वही तुम्हारी भाषा होगी। इस नीति का हम विरोध करेंगे।

बहुजातीय देश में समाजवादी सत्ता स्थापित होने पर उत्पीड़ित जातियों की भाषाओं को नया जीवन प्राप्त होता है। उनकी भाषाएँ और सस्कृतियाँ नई शक्ति पाकर लहलहा उठती हैं। समाजवाद आने पर विभिन्न जातियों की भाषाएँ मुरझाकर खरम न हो जाएँगी और बड़ी जाति की भाषा उनकी जगह न ले लेगी। इसलिए बहुजातीय समाजवादी राज्य में भी एकमात्र अनिवार्य राज-भाषा का चलन न होगा।

सोवियत संघ में रूसी भाषा सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है। वह गैर-रूसी जातियों की मातृभाषा तभी बन सकती है, जब उनका रूसीकरण हो जाय। स्तालिन ने बताया है कि तमाम दुनिया में समाजवादी क्रान्ति की विजय हो जाने के बाद भी भाषा और सस्कृति के भेद रहेंगे। इससे स्पष्ट है कि भविष्य में जनता का राज कायम होने पर भी सारे देश में केवल एक ही भाषा बोली जाय, ऐसा न होगा। देश में जनता का राज कायम नहीं हुआ। इसलिए खतरा यह है कि जातियों की समानता का सिद्धान्त ऊपर से मान लिया जाय और प्रमल में उसका उल्लंघन किया जाय। इसलिए भारत में अनिवार्य राज-भाषा के रूप में या सारे देश की एकमात्र सामान्य भाषा के रूप में हिन्दी स्वीकार न की जाएगी।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिक प्रस्ताव में दूसरी पर हावी होने-वाले बड़े पूंजीपतियों का उल्लेख है जो केरल, महाराष्ट्र, आन्ध्र आदि के आत्म-निर्णय के अधिकार का विरोध करते हैं। ये बड़े पूंजीपति मुख्यतः मारवाडी हैं। बिड़ला, डालमिया, सिंघानिया, गोयन्का आदि जिन्होंने भारत में अपना जाल बिछा रखा है, इसी जाति के हैं। इनमें अन्य पूंजीपति भी शामिल हैं जो मारवाडी नहीं हैं। बिड़ला, गोयन्का आदि की मातृभाषा हिन्दी नहीं राजस्थानी है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने सामन्तवाद को सुरक्षित रखा। ये सज्जन अपने घरेलू बाजार को सुगठित करके पूंजीपति नहीं बने; धारम्भ से ही अपने व्यापार और उद्योग धन्धों का प्रसार वे अन्य प्रदेशों में करते रहे, यही कारण है कि इन्होंने राजस्थानी के लिए कुछ नहीं किया लेकिन हिन्दी पत्र निकालने में वे पूंजी लगाते हैं। उनकी नीति में दक्षिण तथा अन्यत्र लोग हिन्दी को अपने ऊपर हावी होनेवाली जाति की भाषा समझने लगे हैं। अंग्रेज और उनके हाली-मवाली भाषा-समस्या को लेकर विभिन्न जातियों में द्वेष फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं। जातीय विद्वेष की जो अग्नि वे भड़का रहे हैं, उससे इन भाषाओं में परस्पर आदान-प्रदान का क्रम भग होता है और बहुत-से धन्धे हिन्दी राष्ट्रवादी यह समझने लगे हैं कि और सब उनकी भाषा सीखेंगे, वे किसी की भाषा



बड़े पूँजीपतियों की नीति हिन्दी को अनिवार्य राजभाषा बनाने की है। इसके विपरीत प्रान्तीय पूँजीपति कहते हैं कि उनके विरोधी भाषायी साम्राज्यवाद कायम करना चाहते हैं। और वे अपनी जाति को आत्मनिर्णय का पूरा अधिकार देने की बात कहते हैं, बसतों कि इस प्रश्न पर मजदूर वर्ग उनके झूठे व नीचे आ जाय। प्रान्तीय पूँजीपति जब इस तरह के दावे करते हैं, तब उनका पर्दाफाश करना चाहिए।

प्रान्तीय पूँजीपतियों की नजर पड़ोसी इलाकों पर है। बिहार के आदिवासी इलाकों के लिए बंगाल और बिहार के पूँजीपतियों में भगडा है। बम्बई और मद्रास किसके हिस्से में होंगे, इसको लेकर भगडे हैं। श्री पट्टाभि सीनारमैया श्री ब० भा० मुशी के भाषायी साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे हैं। लेकिन हैं दोनों एक ही धौली के चट्टे-वट्टे।

सभी जातियों की श्रमिक जनता मजदूर वर्ग के नेतृत्व में केन्द्रीय और प्रान्तीय दोनों तरह के पूँजीपतियों तथा जमींदारों के खिलाफ संघर्ष करके हारति के लिए स्वतन्त्रतापूर्वक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास का अधिकार सुनिश्चित कर सकती है। यही तरीका है कि बड़े पूँजीपति दूसरा पर अनिवार्य राजभाषा न लाद सकेंगे और सभी जातियों की भाषाओं को विकसित होने का पूरा अवसर मिलेगा।

## हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी समस्या

समस्या यह है कि हिन्दुस्तानी प्रदेश की भाषा हिन्दी, उर्दू या हिन्दुस्तानी में बोल-सी है या तीनों हैं या इनमें कोई दो हैं।

हिन्दी केवल हिन्दुओं की भाषा नहीं है, मुस्लिम जनता भी हिन्दी बोलती है। उर्दू भी केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है। बुनियादी तौर से हिन्दी-उर्दू एक ही भाषा हैं। दोनों का आधार जनसाधारण की बोलचाल की भाषा है। इस बोलचाल की भाषा के सहारे के बिना न तो हिन्दी का एक वाक्य लिखा जा सकता है, न उर्दू का। उर्दूवाले कहते हैं, उनकी भाषा आम जनता की जवान है। वे ठीक कहते हैं, इस अर्थ में कि जनता की भाषा के बिना उर्दू का एक वाक्य नहीं लिखा जा सकता। हिन्दी उर्दू में भेद उनके बोलचाल के रूप में नहीं है, भेद है उनकी उच्च स्तरीय शब्दावली में। बोलचाल की एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। उनके भेद का कारण यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अन्तर्गत हमारे देश की जातियों का विकास विषम रूप में हुआ है।

विदेशी पूँजी ने भारतीय सामन्तवाद को अपना दोस्त बनाया। उसने भारतीय उद्योग धन्यों का विकास रोका, आम जनता का भुरी तरह शोषण किया और उसे अशिक्षित रखा, जमींदारों का वर्ग बनाकर अपने लिए सहायक तैयार किये, यहाँ की भाषाओं के विकास को भरसक रोका और जनता पर

विदेशी भाषा नादी और उड़े पूँजीपतियों ने सौदा पक्का किया कि मिलकर देश का शोषण करें।

इस कारण ग्राम जनता सस्कृति के क्षेत्र में अपनी एकता का प्रभाव पूरी तरह न डाल सकी। पाश्चात्य शिक्षा, भाषा और साहित्य में बुद्धिजीवियों को जो भी प्रेरणा मिली हो, ग्राम जनता अपने साम्राज्य विरोधी, सामन्त-विरोधी, पूँजीवाद विरोधी दृष्टिकोण का प्रभाव सस्कृति पर नहीं डाल पाई। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने रायगाहबो, रायबहादुरो, खानबहादुरो आदि की सेना तैयार कर ली और ये हिन्दी-उर्दू के नेता बन गए। इनके साम्राज्य-भरस्त दृष्टिकोण का प्रभाव भाषा के विकास पर भी पड़ा। ब्रिटिश साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष रूप से तथा अपने सहायकों के जरिये अप्रत्यक्ष रूप से भाषा और सस्कृति के मामलों में दखल देता रहा। भाषा और साहित्य में वह धार्मिक विद्वेष भड़काता रहा। ग्रियर्सन का मत था कि इस्लाम के साथ उर्दू दूर-दूर तक फैली, उन्हे इस बात का ध्यान न रहा कि भारत में इस्लाम के प्रवेश के बहुत दिनों बाद उर्दू का विकास आरम्भ हुआ। ग्रियर्सन ने यह नहीं बताया कि इस्लाम के साथ उर्दू भारत में ही क्यों आई, मिस्र, अलजीरिया, तुर्की या इस्लाम के घर अरब में क्यों नहीं पहुँची?

ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने सामन्तवाद का पोषण किया। सामन्ती वर्ग की विशेष विचारधारा है पुनरुत्थानवाद। इसके प्रभाव से धार्मिक और साम्प्रदायिक रूढ़ान मजबूत हुए हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत की हर जाति को ब्रिटिश मूबा और देशी राज्यों में बाँट दिया। इस कारण जातियों की सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता दुर्लभ करने में सफल हुई।

भारत के नेता जब दुर्लभ तरीके से साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे, तब वे भाषा और सस्कृति को धर्म से परे मानते थे। वे कहते थे कि नागरी और फारसी लिपि में लिखी जानेवाली हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा होगी। वे साम्राज्यवाद से समझौता करने और जनवादी शान्ति के विरोध के रास्ते पर चले। साम्राज्यवाद के खिलाफ जनता में जहाँ क्रान्तिकारी उभार आया, उन्होंने उसे दबाया। उन्हें भय था कि विदेश साम्राज्य के ख़ात्मे के साथ वही उनकी शोषण-व्यवस्था भी ख़त्म न हो जाय। कांग्रेस के भीतर और बाहर उन्होंने विमानों और मजदूरों के वर्ग संगठन बनाने का विरोध किया। किसानों और मजदूरों की एकता ही राष्ट्र की एकता को मजबूत कर सकती है, देश की हर जाति की भाषा और सस्कृति की एकता को मजबूत कर सकती है।

इस नीति के कारण राष्ट्रीय नेता राष्ट्र के साम्राज्यवादी विभाजन में ही समझौदार नहीं हुए, वे अपने अन्दर भी अन्ध राष्ट्रवादी रूढ़ान पालते रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ जैसी फागिस्ट संस्थाओं से सहर्ष करने का दिखावा करते हुए वे उस तरह की प्रवृत्तियों को कांग्रेस के अन्दर ही पुष्ट करते रहे हैं। वे सामान्य सस्कृति और सामान्य भाषा की मीठी मीठी बातें भूल गए और

चरम साम्प्रदायिक दृष्टान्तों का समर्थन करने लगे हैं। वे भाषा-विवाद जैसी चीजों का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि जनता जनतन्त्र और समाजवाद के लिए सघर्ष करना बन्द कर दे। भाषा-विवाद और प्रान्तों के विभाजन से सम्बन्धित झगड़े उनके हाथ में ऐसे प्रस्न हैं जिनसे जनता का ध्यान मुख्य सामाजिक समस्याओं से हटा दिया जाय। सामन्ती-पूँजीवादी शोषण पायम रखने के लिए वे जनता में फूट डालनेवाले साम्राज्यवाद के तमाम दाँव-पेंच इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यह आशा करना व्यर्थ है कि वे इन समस्याओं को हल करने में रत्तीभर सहायता करेंगे। भारत में मजदूर वर्ग और उसके साथी किसान और मध्य वर्ग के लोग हर जाति की सामान्य ससृष्टि और सामान्य भाषा का निर्माण करेंगे।

कानपुर या आगरा की एक ही मिल में काम करनेवाले हिन्दू और मुसलमान मजदूर क्या दो भाषाएँ बोलते हैं? उनकी भाषा एक है। उत्तर प्रदेश के किसान भी एक ही भाषा बोलते हैं और एक दूसरे की धात समझते हैं। अपने दफ्तरो और मुहल्लों में मध्यमवर्गीय कामकाजी लोग आपस में एक ही भाषा बोलते हैं। हर प्रदेश में हिन्दू और मुसलमान मजदूरों की भाषा एक है, हिन्दू और मुसलमान किसानों की भाषा एक है, मध्य वर्ग के कामकाजी हिन्दुओं और मुसलमानों की भाषा एक है। इस भाषा में स्थानीय भेद होते हैं किन्तु घर्भ के आधार पर भेद नहीं पैदा होता। जब बोलचाल की भाषा साहित्य और उच्च सांस्कृतिक कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है, तब उसकी शब्दावली में भेद पैदा हो जाता है।

हिन्दी-उर्दू बुनियादी तौर से एक हैं किन्तु अपने साहित्यिक रूपों में भिन्न हैं, यह अन्तर्विरोध सामाजिक अन्तर्विरोध का ही परिणाम है। साम्राज्यवाद ने सामन्तवाद कायम रखा और पूँजीवादी वर्ग में हिन्दू-मुस्लिम आधार पर भेद डाला। पूँजीवादी नेताओं की समझौतापरस्ती के कारण साम्राज्यवादी नीति सफल हुई। यह कहना कि बोलचाल की भाषा से उच्च शिक्षा और ससृष्टि के सभी कार्य सम्पन्न किए जा सकते हैं, सामाजिक विकास के वास्तविक अन्तर्विरोध से आँखें मूँद लेना है।

हिन्दी और उर्दू को हिन्दू धर्म और इस्लाम से सम्बद्ध नहीं किया जा सकता। उर्दू में ईरान और अरब की साहित्यिक परम्परा का अनुसरण है, उसकी साहित्यिक शब्दावली अरबी और फारसी के आधार पर रची गई है। हिन्दी की साहित्यिक शब्दावली का आधार संस्कृत है और वह भारत की साहित्यिक परम्परा का अनुसरण करती है। दोनों की ही साहित्यिक परम्परा में सामान्य जनवादी तत्व विद्यमान हैं और इन्हीं के आधार पर भविष्य में सामान्य साहित्यिक भाषा का विकास होगा। जो विशुद्ध धार्मिक तत्व हैं, वे विलीन हो जाएँगे, पुरानी गाथाएँ, वेद-कथाएँ आदि सामान्य सांस्कृतिक परम्परा का अंग बन जाएँगी। हिन्दी और उर्दू में आज जो परस्पर-भिन्न साहित्यिक परम्पराएँ

दिखाई देती है, वे एक ही साहित्यिक भाषा और सामान्य साहित्यिक परम्परा के विकास में दुर्लभ बाधा नहीं हैं। जनसाधारण की उच्च सांस्कृतिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए (अर्थात् उन्हें दर्शन, राजनीति, धर्मशास्त्र आदि की शिक्षा देने के लिए) जनवादी आन्दोलन की बढ़ती के साथ दोनों के बीच का फासला दूर होगा।

बोलचाल की भाषा में केवल सस्कृत के या केवल घरकी फारसी के शब्द नहीं होते। साहित्यिक शब्दावली में शुद्धता की रक्षा न की जा सकेगी। राहुलजी ने संविधान का 'मसौदा' लिखा है जबकि डॉ० रघुवीर ने मसौदे के लिए 'प्रारूप' लिखा है। कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य की भाषा और जनता की भाषा में भेद भन्तर रहेगा। यह भेद उच्च वर्गों और जनसाधारण की सस्कृति का भेद प्रकट करता है। जनतन्त्र और समाजवाद की और प्रगति के साथ यह भेद भी मिट जाएगा। प्रगतिशील लेखक जब जन-संघर्षों को धागे बढाने के लिए साहित्य रचते हैं, तब यह भेद खत्म हो जाता है या कम हो जाता है।

उदारपथी पूँजीवादी नेता हिन्दी-उर्दू को मिलाने में असफल हुए। वे यह न जानते थे कि दोनों में भेद क्या है। उन्होंने इस समस्या का सम्बन्ध आम जनता की सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रगति से नहीं जोड़ा, उन्होंने यह नहीं देखा कि इस समस्या का सम्बन्ध जनता की निरक्षरता दूर करने से है, जनसाधारण के लिए साहित्य और सस्कृति सुलभ करने से है, ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के सहयोगियों ने बुद्धिजीवियों में जो पुनरुत्थानवादी रुझान पैदा किये हैं, उनसे संघर्ष करने से हैं।

साम्प्रदायिक अनुपात लागू करने से (अर्थात् मुसलमानों आदि के बितने एम० एल० ए० होंगे, यह निश्चित करने में) हिन्दू-मुस्लिम समस्या हल न हो सकती थी। इसी तरह फारसी और सस्कृत के कोशों से बिसी निश्चित अनुपात के अनुसार शब्द लेकर मिलाने से सामान्य साहित्यिक भाषा का विकास न हो सकता था।

दो लिपियों में लिखी जानेवाली हिन्दुस्तानी भाषा समस्या का कोई हल प्रस्तुत नहीं करती। दोनों लिपियों में यदि शब्दावली भिन्न है, तो हिन्दुस्तानी नाम देने से बेहिसाब भगड़े बढ़ते हैं। हिन्दी और उर्दू में आज वास्तविक भेद है। यह भेद खत्म करके तुरन्त हिन्दुस्तानी नहीं गड़ी जा सकती। इसलिए अभी कुछ समय तक हिन्दी और उर्दू दोनों का चलन स्वीकार करना चाहिए जिससे कि स्वाभाविक रीति से दोनों मिलकर एक हो जाएँ।

### पारिभाषिक शब्दावली की समस्या

लोग कहते हैं कि भारतीय भाषाएँ सस्कृत से उत्पन्न हुई हैं। इसलिए हिन्दी का जितना ही सस्कृतीकरण होगा, वह सारे भारत में उतनी ही सुबोध और लोकप्रिय होगी। पिछले पाँच सौ वर्षों का इतिहास बतलाता है कि भार-

तीस भाषाओं में असंस्कृत रूप निरन्तर विकसित होते गये हैं। ये रूप लोकप्रिय हैं, इसमें ज़रा भी संदेह नहीं। कहा जाता है कि बँगला में संस्कृत शब्द सबसे ज्यादा हैं। 'बँगला भाषा का उद्भव और विकास' नामक ग्रन्थ में डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने लिखा था, "आधुनिक बँगला के बोलचाल वाले रूप में संस्कृत शब्दों का अनुपात आश्चर्यजनक रूप से कम है" (खण्ड १, पृ० २२१)। कारण यह है कि "तद्भव शब्दों का सम्बन्ध आधे दिन के जीवन से है और भाषा में, कहना चाहिए, सबसे ज्यादा थम इन्हीं को बरन्ध पड़ता है।" (उप०, पृ० १६७-६८)

संस्कृत के शब्द अपने तद्भव रूप में सुरक्षित रहते हैं। गुदतावादों के लिए ये शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। न केवल बँगला में बरन् उन तमाम भारतीय भाषाओं में, जो संस्कृत से सम्बद्ध हैं, तमाम शब्दों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम है। गम्भीरकरण द्वारा हिन्दी को लोकप्रिय बनाने की माँग गलत है और लोगों को उसका विरोध करना चाहिए। उर्दू को फारसी-गर्भित करना उर्दू के लिए हानिकारक है और उर्दू-प्रेमियों को उसका विरोध करना चाहिए।

इसका यह अर्थ नहीं है कि हिन्दी-उर्दू संस्कृत-फारसी से शब्द न लें। यह कार्य विवेक से, बोलचाल की भाषा की प्रकृति पहचानते हुए करना चाहिए। इसमें भाषा समृद्ध होगी और उसका लोकप्रिय रूप नष्ट न होगा। नये शब्द बढ़ने और उधार लेने के अलावा, बोलचाल की भाषा की रचनात्मक क्षमता को भूल न जाना चाहिए। हिन्दी-उर्दू की उच्च शब्दावली में अंग्रेजी शब्दों का प्रवेश भी बिलकुल बन्द न करना चाहिए।

कई लोग पारिभाषिक शब्दों के छोटे-बड़े कोश बना रहे हैं। वे कहते हैं कि जो शब्द प्रचलित हैं, वह पारिभाषिक नहीं हो सकता। सविधान के अनुवादक श्री धनश्याम सिंह गुप्त ने लिखा है, "सभी भाषाओं में लोक-प्रचलित शब्द अर्थ की दृष्टि से स्थिर और अनिश्चित होते हैं" "हर विशेष विषय की अपनी विशेष शब्दावली होती है और लोक-प्रचलित भाषा से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता।" (भारतीय संविधान का प्रारूप, १९४८)

अज्ञानी हिन्दी पाठक की सहायता के लिए डॉ० रघुवीर ने सविधान के मसौदे के अन्त में शब्द-सूची दे दी है। इस सूची से बहुत अच्छी तरह पता चल जाता है कि पारिभाषिक तथा लोक-प्रचलित शब्दावली में किस तरह का सम्बन्ध है। शब्द-सूची के पहले तीन पृष्ठों में इस तरह के अंग्रेजी शब्द दिये हुए हैं—

ओपन, फायर-आर्म, प्रॉडिट, अलाउस, ऐक्ट, वारंट, ऐडवोकेट, मीटिंग, सीट, क्लेम, आर्टिनेन्स, आर्टिकल, लाइसेंस, ग्रांट, प्रैक्टिस, फ्री, मेपटी, एजेण्ट, इंजीनियरिंग, रेलवे, भाइनर इत्यादि। ये शब्द अंग्रेजी में ही लोक-प्रचलित नहीं, उनमें से बहुतों को इस देश के अशिक्षित लोग भी समझते हैं। अधिपत्र, अधिष्ठान, अधोमार्ग क्या हैं? वारंट, सीट और रेलवे!

• यदि अंग्रेजी के लोक-प्रचलित शब्द उस भाषा में पारिभाषिक माने जा सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि उस नियम का पालन हिन्दी में न किया जाय। कठिन शब्दावली का फल यह होगा कि जनसाधारण शिक्षा और सस्कृति से दूर रहेंगे। दुःख की बात यह है कि डॉ० रघुवीर के बनाये हुए बहुत-से शब्दों को उच्च शिक्षा पाये-हुए लोग भी नहीं समझते। इस जड़ता को भारत के प्राचीन गौरव और राष्ट्रीय एकता के नाम पर न्यायपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। अपनी शब्द-सूची की भूमिका में डॉ० रघुवीर ने लिखा था, “हमने भौगोलिक ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी भारत की एकता का ध्यान रखा है। भारत के दीर्घकालीन गौरवमय अतीत में जो कुछ उपयोग्य था, उसे हमने आत्मसात् कर लिया है।”

वास्तव में उन्होंने जो कुछ किया है, वह इसका ठीक उलटा है। उन्होंने वे तमाम शब्द छोड़ दिये हैं, जो न केवल हिन्दी-भाषी प्रांतों में वरन् दक्षिण भारत तथा अन्यत्र समझे जाते हैं। ये शब्द उनके लिए पारिभाषिक नहीं हो सकते क्योंकि इनमें लोकप्रियता का दाग लग गया है। उन्होंने वे तमाम शब्द छोड़ दिये हैं जो अतीत में जनता के परस्पर सम्पर्क के कारण प्रचलित हो गये हैं। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने डॉ० रघुवीर की आलोचना की है और उनके अनुवाद के बदले अपना अनुवाद प्रस्तुत किया है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि नये शब्द आवश्यक हैं और वे या तो दूसरी भाषाओं से लिये जायेंगे या प्राचीन भाषाओं के शब्दों, धातुओं के आधार पर गढ़े जायेंगे। जो लोग इन शब्दों का व्यवहार करेंगे, उनकी आवश्यकताएँ ध्यान में रखी जायें तो यह कार्य ज्यादा सन्तोषजनक ढंग से सम्पन्न होगा। सबसे पहले उन शब्दों का संग्रह करना चाहिए जिनका व्यवहार विभिन्न देशों के लोग पहले से ही कर रहे हैं। इसके बाद सस्कृत, फारसी या अंग्रेजी से आंख मूंदकर शब्द न लेने चाहिए वरन् इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे बोलचाल की भाषा की प्रकृति के अनुकूल हैं या नहीं। ग्रीक और लैटिन के आधार पर बनाये हुए जो अंग्रेजी के शब्द यूरोप की अन्य भाषाओं में प्रचलित हैं, उन्हें विदेशी होने के कारण ही न छोड़ देना चाहिए। आवश्यकतानुसार उनकी जगह लोकप्रिय हिन्दुस्तानी शब्दों को दी जा सकती है।

हिन्दी-उर्दू की उच्च स्तरीय सांस्कृतिक शब्दावली देर में घुल-मिलकर एक होगी, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा की तरह हिन्दी-उर्दू की पारिभाषिक शब्दावली भी एक दिन मिलकर एक होगी, इसमें खरा भी सन्देह नहीं है।

## लिपि का प्रश्न

लिपि भाषा का अभिन्न अंग नहीं है। यूरोप की अनेक भाषाएँ लैटिन वर्णमाला का व्यवहार करती हैं। किन्तु इससे वे मिलकर एक नहीं हो जाती। भारत में हिन्दी और मराठी की लिपि प्रायः एक-सी है, फिर भी दोनों भाषाओं

मे बहुत अन्तर है। इस दृष्टि से लिपि का प्रश्न गौण है। फिर भी लिपि-भेद होने से हिन्दी-उर्दू के बीच का फासला बड़ा है। यदि हिन्दी के पाठक उर्दू से और उर्दू के पाठक हिन्दी से परिचित होते तो यह फासला इतना न बढ़ा होता। एक लिपि होने से उन्हें निकट लाने और मिलाने में सुविधा होगी।

एक लिपि की स्वीकृति स्वेच्छा में ही हो सकती है। फिर भी मजदूर वर्ग को आन्दोलन करना चाहिए कि एक ही लिपि का चलन हो जिसमें हिन्दी-उर्दू जल्दी-से-जल्दी घुल-मिलकर एक हो सकें। यह लिपि कुछ संशोधनों के साथ देवनागरी ही हो सकती है।

## पिछड़ी हुई जातियों की भाषाओं का प्रश्न

भारत में मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु आदि सुविकसित भाषाओं के अलावा दालिया के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ किसी बोली ने विकसित होकर अभी भाषा का रूप नहीं लिया। इस तरह के क्षेत्रों में राजस्थान है। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनके लिए मड़ोमी प्रान्तों के पूँजीपतियों में आपस में झगडा है। बिहार के आदिवासी इलाका के लिए बगाली और बिहारी पूँजीपतियों में झगडा है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ लोग अभी आदिम समाज-व्यवस्था में ही रह रहे हैं। मध्यप्रदेश और राजस्थान के आदिवासी न अपना, न अपनी भाषाओं का विकास कर पा रहे हैं। इनकी भाषाओं के विकास की बात कोई हवाई सैद्धान्तिक प्रश्न नहीं है। यह उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का प्रश्न है। जनवादी आन्दोलन और मजदूर वर्ग को उनके राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए।

## हर बोली या भाषा के लिए एक प्रजातन्त्र का सवाल

महापंडित राहुल सांकृत्यायन कुछ समय पहले तक यह माँग करते रहे हैं कि उन प्रदेशों में प्रजातन्त्र कायम किया जाय जहाँ भवधी, ब्रजभाषा, बुन्देलखण्डी आदि का चलन है। उनके चरणचिह्नो पर श्री शिवदानसिंह चले (देखिए उनकी पुस्तक 'प्रगतिवाद' में 'जनपद आन्दोलन' नामक निबन्ध), श्री व्योहार राजेन्द्र सिंह, श्री बनारसीदास चतुर्वेदी आदि जनपद-आन्दोलनों में योग देते रहे हैं। प्रश्न यह है कि भवधी, ब्रजभाषा बुन्देलखण्डी आदि बोलियाँ हैं या भाषाएँ, उनके बोलनेवाले हिन्दुस्तानी जाति के अन्तर्गत हैं या भिन्न-भिन्न स्वतन्त्र जातियों के रूप में विकसित होंगे। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इनमें से हर एक के लिए प्रजातन्त्र या प्रान्त बनना चाहिए।

गाँवों में किसान भवधी, ब्रज आदि का व्यवहार करते हैं। शहरों के मजदूर, खास तौर से मिलों और कारखानों के श्रान्िक आपस में खड़ी बोली का व्यवहार करते हैं। बानपुर में उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, गोंडा और छपरा तक से मजदूर आते हैं। लखनऊ, आगरा और झाँसी के लोका वर्कशॉप, कार-

खाना आदि में इसी तरह विभिन्न क्षेत्रों के मजदूर काम करते हैं। जो किसान सीधा गाँव से आकर मजदूर बना है, वह अपनी गाँव की बोली बोलता है और उसके साथी उसकी बात समझ लेते हैं। कुछ समय बाद वह शहर की बोली—खड़ी बोली—सीख लेता है और अपने साथियों से इसी में बात करता है, यद्यपि घर पर वह अपनी गाँव की बोली का ही व्यवहार करता है।

हिन्दुस्तानी प्रदेश के मजदूर वर्ग में अवधी, ब्रज आदि बोलनेवाले लोग हैं। इनका सामान्य परिवेश और सामान्य आर्थिक सम्बन्ध उन्हें एक सामान्य भाषा बोलने पर मजबूर करते हैं। यह भाषा खड़ी बोली या हिन्दुस्तानी होती है। अखबारों में पढ़ी लिखने के लिए, इस्तहारी के लिए भर्त्सी, भांगरा, कानपुर और लखनऊ के मजदूर बुन्देलखण्डी, ब्रजभाषा या अवधी का व्यवहार नहीं करते। ये मजदूर हिन्दी-उर्दू का ही व्यवहार करते हैं और उनकी बोलचाल में कोई भेद नहीं होता। शहरों के मध्यवर्ग का भी यही हाल है।

खड़ी बोली और फारसी के सघर्ष में खड़ी बोली (उर्दू) की विजय हुई। कविता में ब्रजभाषा का व्यवहार हो या खड़ी बोली का, इस सघर्ष में खड़ी बोली (हिन्दी) की विजय हुई। भारतेन्दु भोजपुरी क्षेत्र के थे, प्रतापनारायण मिश्र अवध के, राधाचरण गोस्वामी ब्रज के, इन सबने यद्य के लिए खड़ी बोली को अपनाया। यह विकास उन्नीसवीं सदी में हुआ किन्तु उसका आरम्भ पहले ही चुका था। इस विकास का कारण या पूँजीवाद का विकास। भारत में पूँजीवाद उन्नीसवीं सदी में आरम्भ नहीं हुआ। व्यापारी पूँजीवाद उन सीधे-गरीबों के साथ शुरू हुआ जो अपने साथ खड़ी बोली मुदूर हैदराबाद ले गये। ब्रिटिश पूँजीवाद में टक्कर होने पर भारतीय पूँजीवाद के सहज विकास में बाधा पड़ी लेकिन वह रुक नहीं गया। पूँजीवाद के विकास के साथ हम मिले और कारखानों में मजदूरों को खड़ी बोली बोलते देखते हैं। पैदात में जहाँ सामन्ती सम्बन्ध अब भी दृढ़ हैं, वहाँ भाषायी एकीकरण का यह काम पूरा नहीं हुआ। मध्यवर्ग पूँजीवादी विकास का ही परिणाम है और किसानों की अपेक्षा यह वर्ग खड़ी बोली को अधिक अपनाता है। इसी कारण हिन्दी-उर्दू लेखकों में ऐसे लोग हैं जो घर में खड़ी बोली में अलग अलग बोर्ड बोली भी बोलते हैं। श्री भूमिलीशरण गुप्त घर में बुन्देलखण्डी, श्री राहुल साहू व्यायन भोजपुरी, श्री शिवमगलसिंह 'सुमन' और अली सरदार जाफरी अवधी बोलते हैं, या पहले बोलते थे।

इसका अर्थ यह है कि उपर्युक्त बोलियों के बोलनेवाले पूँजीवाद के विकास के साथ एक ही जाति में संगठित हुए हैं, एक ऐसे स्थायी जन समुदाय के रूप में गठित हुए हैं जिसकी सामान्य भाषा है और सामान्य आर्थिक जीवन है। यह विकास पूरा नहीं हुआ। सामन्ती सम्बन्ध अभी बने हुए हैं। इसीलिए हिन्दुस्तानी प्रदेश में भाषा और बोली का प्रश्न भी हमारे सामने आता है। खड़ी बोली



‘भाषा’ बनी, ब्रज, अवधी आदि ‘बोलियाँ’ रही। यह प्रक्रिया अनोखी नहीं है। जिन देशों में भी सामन्ती सम्बन्धों की जगह पूँजीवादी सम्बन्ध विकसित हुए हैं, वहाँ इसमें मिनती-जुलती प्रक्रिया देखने को मिलती है। लन्दन के आस-पास की अंग्रेजी, पेरिस के आस-पास की फ्रांसीसी, मास्को के आस-पास की रूसी सामाजिक सम्पर्क और साहित्य की भाषा बनी। अंग्रेजों में वेल्श जैसी भाषा अंग्रेजी के मुकाबले और फ्रांस में प्रोवांसाल जैसी समृद्ध साहित्यिक भाषा फ्रांसीसी के मुकाबले बोली की हैसियत ही पा सकी।

समाज में किसान या मजदूर वर्ग के कुछ हिस्से अपनी बोली छोड़ते नहीं हैं या टकसाली भाषा के साथ उमका भी व्यवहार करते हैं, तो यह भारत में होनेवाली कोई अद्भुत क्रिया नहीं है। फ्रांस जैसे विकसित पूँजीवादी देश में भी बोलियों का अस्तित्व है। भाषाविद वान्द्राई ने ब्रैतो बोली के बारे में लिखा है “मछुओ में, तराई के नमक बनानेवालों में, स्नेट-मजदूरों और घुमन्तू सौदागरों में ब्रैतो का व्यवहार अब भी होता है और कोई नहीं कह सकता कि कब तक होता रहेगा” (वान्द्राई, भाषा, लन्दन, १९३१, पृ० २८६)। मेइये के अनुसार इसी प्रकार फ्रांस और स्पेन में वास्क का व्यवहार होता है। इसलिए इसमें आश्चर्य न होना चाहिए कि हिन्दुस्तानी प्रदेश में टकसाली भाषा के अलावा भी अनेक बोलियों का चलन बना हुआ है।

भाषा और बोली का भेद केवल भाषागत भेद नहीं है, वह सामाजिक भेद भी है। किसी समय हमारे यहाँ ब्रजभाषा और फ्रांस में प्रावांसाल समृद्ध साहित्यिक भाषाएँ थी। पूँजीवाद के विकास के साथ दिल्ली, मेरठ तथा पेरिस के आस-पास की बोलियों को व्यापारी दूर-दूर तक ले गये। बोलियों ने भाषा का रूप लिया। जिन क्षेत्रों में अवधी, ब्रज आदि बोलियाँ अभी बोली जाती हैं, उनकी टकसाली भाषा खड़ी बोली है। इस टकसाली भाषा के कारण—साम्राज्यवाद और पूँजीवाद के बावजूद—यहाँ की जनता सीमित विकास कर सकी है। इन क्षेत्रों के मजदूर टकसाली भाषा यानी खड़ी बोली के जरिये एक-दूसरे के निकट आते हैं। इस तरह इस टकसाली भाषा का विकास जनवादी क्रान्ति की विजय के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है ‘जनयुग’ और ‘नया जमाना’ अवधी, ब्रजभाषा आदि में निकाले जाएँ तो इससे मजदूरों की एकता दृढ़ होगी। मैंने ‘जनयुग’ के लेख अवधी में उल्था करके उन्नाव और रायबरेली के किसानों को सुनाये हैं, यह देखने के लिए कि उनकी शब्दावली में कितना परिवर्तन करना पड़ता है। व्याकरण-रूपों को छोड़कर १८ फीसदी शब्दावली वही रहती है। ये बोलियाँ एक-दूसरे के इतना निकट हैं कि यदि एक ही लेख—खास तौर से अखबारी लेख—का उल्था उनमें करें तो १८ फीसदी इबारत एक-सी होगी। ये बोलियाँ मुहावरों, सुन्दर अर्थ-व्यंजक शब्दावली और अलंकृत वचनों में समृद्ध हैं। टकसाली भाषा के लेखक इनसे बहुत-कुछ सीख सकते हैं। इनमें अछूता खजाना है जिसे अपनाने से टकसाली भाषा की

व्यंजना-शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ेगी । लेकिन इसका यह अर्थ विलुप्त नहीं है कि इनका व्यवहार करनेवालों को हम स्वतन्त्र जातियाँ मान लें ।

श्री राहुत साठुत्यायन तथा अन्य लोगों की यह माँग कि अक्की, ब्रज, मुन्देलखण्डी आदि को विभिन्न जातियों की टक्काली भाषा माना जाय, प्रति-क्रियावादी माँग है । यह माँग केवल सामन्ती वर्गों के हित में है जो इस तरह एक पतनशील व्यवस्था की रक्षा करना चाहते हैं । इस माँग से हिन्दुस्तानी प्रदेश के मजदूरों की एकता में बाधा पड़ती है ।

हर बोली के लिए एक प्रजातन्त्र या प्रान्त बनाने का सवाल नहीं है । सोवियत संघ में ६० से ऊपर भाषाएँ हैं, प्रजातन्त्र इनसे बहुत कम है । अक्की, ब्रज आदि विभिन्न जातियों की भाषाएँ होती, तो भी उनके लिए हर जगह प्रजातन्त्र कायम न किये जाते । वे बोलियाँ हैं, इसलिए उनमें से हरेक के लिए प्रजातन्त्र बनाने की माँग विशेष रूप से हास्यास्पद है । ओरछा के महाराज जनपद आन्दोलन में खास दिलचस्पी लेते रहे हैं, यह बात आकस्मिक नहीं है ।

भारत में भाषा समस्या के ये कुछ मुख्य पहलू हैं । (१९४६)

## जातीय भाषा के रूप में हिन्दी का प्रसार

जातीय भाषा बनने से पहले हिन्दी या खड़ी बोली एक जनपद की भाषा थी। ब्रज, अवध, बुन्देलखण्ड आदि जनपदों में ब्रज, अवधी, बुन्देलखण्डी आदि भाषाएँ बोली जाती थी। इन जनपदों में रहनेवाले छोटी-बड़ी रियासतों में बैठे हुए थे। वे सब किसी जाति में संगठित न हुए थे और इसीलिए एक जातीय भाषा के रूप में उनके पास आपसी व्यवहार की कोई भाषा न थी। कुछ पढ़े-लिखे लोग सस्कृत से काम चलाते थे लेकिन उसे आम जनता न तो समझती थी, न बोलती थी।

तब के समाज की दो विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं। एक तो यह कि समाज चार वर्गों में बँटा हुआ था जिनके अन्तर्गत सैकड़ों जात-विरादरियाँ थी। दूसरी यह कि गाँव बहुत-कुछ खुदमुस्तार थे, ऊपर से आधी तूफान निकलते रहें, ये छोटे-छोटे पचापती राज अपनी जगह बदस्तूर कायम रहते थे।

तेरहवीं-चौदहवीं सदी में सामन्ती समाज का यह ढाँचा ढीला पड़ने लगा था, वर्णव्यवस्था शिथिल हो रही थी और लोग अपने खानदानी पेशे छोड़कर नये पेशे अपनाने लगे थे। तुर्कों के हमलों से यह ढाँचा और कमजोर पड़ा हालाँकि उसे तोड़नेवाली ताकतें उसके भीतर ही पैदा हो रही थी। तिलक जो हिन्दी और फारसी दोनों जानता था और अबुलहसन और महमूद गजनवी की सेवा में रहा था, एक नाई का लड़का था। ग़ुलाम नाम का एक बनिया परिवार राजा से किला छीनकर इल्तमश से लड़ा था (कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ़ इंडिया, खण्ड ३, पृ० ५३)। गुजरात में तगी चमार ने दिल्ली के बादशाह के खिलाफ विद्रोह की अगुआई की। हेमू, जिसने अकबर का मुकाबला किया था, बनिया था। अकबर का चित्रकार दसवन्त बहार था। रामानन्द के शिष्यों में कबीर जुलाहा, रैदास चमार और सेना नाई थे। कबीर के उत्तराधिकारी धरमदास बनिया थे। दादू के लिए कहा जाता है कि वह मोची थे। उनके शिष्य सुन्दरदास बनिया थे और मलूखदास खत्री थे। इस तरह की और भी मिसालें दी जा सकती हैं। इससे नतीजा यही निकलता है कि सस्कृति पर अब ब्राह्मण-

पुरोहिताँ का इजारा टूट रहा था, राज्य और धरती पर क्षत्रियो का अधिकार ढीला पड़ रहा था ।

तुर्क बादशाहों ने बाजार, तोलने के बाँट, सिक्को आदि के बारे में जो सुधार किये, उनसे सौदागरों को फायदा पहुँचा । इस जमाने में नई-नई महियाँ और नये-नये शहर आबाद हुए । फीरोज तुगलक के लिए कहा जाता है कि उसने फीरोजाबाद, फतहाबाद, फीरोजपुर, बदायूँ, जोनपुर आदि शहर बसाये । शेरशाह के जमाने में पटना शहर फिर व्यापार का केन्द्र बना । उसके समय में जो सब्जें और नहरें तैयार हुईं, उनसे व्यापार बढ़ा । शेरशाह ने सराएँ बनवाई धार्मिक उदारता की नीति बरती, और खास बात यह कि राज्य और किसान के बीच सीधा सम्बन्ध कायम किया । पहले गाँव का मुखिया मालगुजारी तय करता था, उसका वह हक छिन गया । इस तरह एक तरफ तो सौदागरी और व्यापार के केन्द्रों के तीर पर शहर बढ़ती पर थे, दूसरी तरफ गाँवों की खुद-मुस्तारी पर पाबन्दी लगी । अकबर ने बारूद का महत्व समझा । राज्य में शान्ति कायम रखने के लिए अपने खाम तौर से बारूद का भरोसा किया । सामन्ती युग के तीर-कमान और तलवार पुरानी चीजें बनत जा रह थे । अकबर ने सारे राज्य में एक-सी मुद्रा-व्यवस्था चलाकर व्यापार की बढ़ती में मदद की । तनम्बाह के लिए जागीरें दी लेकिन मालगुजारी बर्गरह तय करने का हक जागीरदारों को नहीं दिया । कभी-कभी उन्हें जागीर से दूर भी तैनात कर दिया जाता था । इस तरह सामन्तों और जागीरदारों की ताकत कम हुई । धार्मिक मामलों में अकबर ने उदार नीति बरती ।

मुगल बादशाहों को खुद भी व्यापार से दिलचस्पी थी । अकबर खुद व्यापार करता था । लखनऊ यूनिवर्सिटी के डॉ० पत के अनुसार गुजरात, आगरा और कश्मीर के बढ़िया उद्योगों का इजारा उसके हाथ में था । शाहजहाँ ने नील का व्यापार अपने हाथ में रखा था और मनोहरदास को राज्य से उधार रकम देकर व्यापार करने की आज्ञा दी थी और मुनाफे में हिस्सा लेता था । नूरजहाँ को भी नील और जरी के वस्त्रों के व्यापार में दिलचस्पी थी । बादशाहों के भाई-भतीजे सौदागरी से धन कमाते थे । मुगल राज्यसत्ता की घामदनी का जरिया सिर्फ जमीन न थी, बल्कि व्यापार भी था ।

व्यापार की उन्नति से पुराने जनपदों का चलगाव दूर हुआ । पटना, बनारस, इनाहाबाद, आगरा और दिल्ली ऐसे केन्द्र बन गये जिनके चारों तरफ एक बीसी बाजार कायम हुआ । यात्री मानरीके के अनुसार सन् १६४० में आगरा की आबादी छ. लाख थी । मार्क्स ने भारतीय इतिहास पर अपनी पुस्तक में लिखा है कि अकबर के जमाने में दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा शहर था । जो नया बाजार कायम हुआ, उसके सबसे बड़े केन्द्र आगरा और दिल्ली ही थे ।

ब्रिटेन में हिन्दुस्तानी कपड़े की माँग बढ़ने से यहाँ का रोजगार और चमका । सत्रहवीं सदी के पहले हिस्से में आगरा से विलायत कपड़ा भेजा जाता

था और यह कपड़ा अवध से बनकर आता था। इस तरह ब्रज और अवध एक बाजार में संगठित हुए। खुद अवध में दरियावाद और खैरावाद अपने उद्योगों के लिए मशहूर हुए। इसी तरह पटना, बनारस, लखनऊ बर्ग रहने आस-पास के देहात को अपनी तरफ ममेटा और उनका पुराना अलगाव बहुत-कुछ दूर किया। फ्रांसीसी यात्री बनियर ने जिन मुगल कारखानों का जिक्र किया है, मुमकिन है कि वे पूंजीवादी पैदावार की पहली मजिल रहे हों। बहरहाल जुलाहा को सौदागर पेशगी रुपया देते थे और उनसे तैयार माल लेते थे। पेशगी लेने पर जुलाहा अपने माल पर अधिकार खो देता था। पेशगी के जरिये सौदागर उसकी श्रमशक्ति खरीद लेता था। यह पैदावार का पूंजीवादी तरीका था। सन् १८४४ में एंगेल्स ने अपनी पुस्तक 'इंग्लैंड के मजदूर वर्ग की दशा' में लिखा था "मशीनें चालू होने से पहले कच्चे माल की कानूनी और धुनने का काम मजदूर के घर पर होता था।" सत्रहवीं सदी में यह सिलसिला यहाँ भी कायम था। लेनिन ने मिखाइलोव्स्की को जवाब देते हुए बतलाया था कि सत्रहवीं सदी में आपसी विनिमय की बढ़ती से, बिकाऊ माल के चलन के धीरे-धीरे तेज होने से, और छोटे-छोटे बाजारों के एक बड़े बाजार में सिमटने से इसी जाति का निर्माण हुआ। सत्रहवीं सदी में इसी तरह हमारे यहाँ भी हिन्दुस्तानी जाति का निर्माण शुरू हुआ था।

भाषा और साहित्य के क्षेत्र में हम जनपदों का एक-दूसरे के नजदीक आना और उनका अलगाव दूर होना देखते हैं। 'रामचरितमानस' अवधी में लिखा गया है, लेकिन ब्रज, भोजपुरी आदि के इलाकों में भी वह अपनाया जाता है। यही नहीं, गोस्वामीजी ब्रज और अवधी दोनों में कविता करते हैं और उनकी भाषा में एक से अधिका बोलियों के शब्द और प्रयोग देखे जा सकते हैं। उधर ब्रजभाषा की कविताएँ—मीरा, मूर, रसखान और रहीम की रचनाएँ दूर देहात तक पहुँच रही थीं। खड़ी बोली में भी खुसरो, कबीर आदि रचनाएँ करने लगे थे। रहीम ने किसी की खड़ी बोली में ही गाते मृत्कर लिखा था—भुक्-भुक् मतवाला गावना रेवता था।

दक्खिन में खड़ी बोली का अलग विकास हुआ, गद्य और पद्य दोनों में यह प्रदेश मुख्यतः तेलुगुभाषी था और खड़ी बोली यहाँ कम तादाद के लोगो की भाषा थी। उत्तर की भाषा पर उमका असर कुछ देर से पड़ा।

शहरो में व्यापार और विनिमय के लिए जिस भाषा का उपयोग होता था, वह भाषा खड़ी बोली या हिन्दी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि देश-विदेश के जो लोग काम-काज के लिए दिल्ली या आगरा आते थे, वे यही भाषा सीखते थे। ग्रियर्सन ने लिखा है कि "उन दिनों के कुछ अंग्रेज सौदागर नि सन्देह घडल्ले से हिन्दुस्तानी बोल सकते थे..." (लिम्बिस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सप्ट १, पृ० २)। और इतिहासकार सरदेसाई ने लिखा है कि इतालवी यात्री मनुचची ने शिवाजी में, बिना किसी दम्पतियों की मदद के, उर्दू में

बातचीत की। फारसी के दबाव की वजह से यह भाषा पहले-पहल दक्खिन में फूली-फली।

हिन्दुस्तान में जो तुर्क, पठान, ईरानी, उजबक आदि जातियों के लोग आये, वे वहाँ किसी नई भाषा को जन्म न दे सकें। उनके बहुत-से शब्द वहाँ वालों ने ले लिये, उनके प्रत्यय लगाकर कुछ नये शब्द भी गढ़े—जैसे पागलताना, झफीमची (झीर पिछले दिनों जगवाड़) बगैरह। लेकिन हमारी भाषा की व्याकरण व्यवस्था, उनके मूल शब्द-भण्डार में कोई भारी तबदीली नहीं हुई। तुर्कों, पठानों, ईरानियों, उजबकों आदि के आने से पहले भी हिन्दी भाषा थी, उनके हिन्दुस्तानी बन जाने के बाद भी रही। इसलिए बादशाहों के लफ्फों में नई जवानों गढ़न की कल्पना भ्रामक है।

बाहर से आनेवाले लोगों के शब्दों से हमारी भाषा और समृद्ध हुई लेकिन उसने अपने जातीय रूप की रक्षा की। भाषा के बारे में शेरशाह और अकबर की नीति अंग्रेजों की तरह अनुदार नहीं थी। शेरशाह ने तो फारसी के साथ हिन्दी में काम बाँट करने की हिदायत दे रखी थी।

प्रजभाषा अरबी, खड़ी बोली आदि सभी न हिन्दुस्तानी जाति के निर्माण में मदद दी। हमारी जाति का चरित्र सषणों द्वारा और पक्का हुआ। इन सषणों के दो पहलू थे, एक तो जातीय, दूसरा जनवादी। यानी एक तरफ तो यहाँ के लोग बिदली आततायियों के खिलाफ लड़े, दूसरी तरफ वे सामन्ती उत्पीड़न के खिलाफ, वण व्यवस्था और पुरोहितों-सामन्तों के विषय अधिकारों के खिलाफ भी लड़े। भाँस्त आन्दोलन में ये दोनों पहलू मौजूद हैं। जुलाह और किसान इस आन्दोलन को शक्ति देनेवाले हैं। सोदागर उसके सहायक हैं, हिन्दू और मुसलमान, सूफी और सत्त दानों उसमें शामिल हैं। भक्ति-आन्दोलन एक जातीय और जनवादी आन्दोलन है। क्या उस समय हिन्दुओं और मुसलमानों की दो संस्कृतियाँ थीं ? कुछ धार्मिक भेदभाव जरूर था लेकिन दो संस्कृतियाँ नहीं थीं। जायसी, रासबान, रहीम, बालम, सोख, पजनेस बगैरह की वही संस्कृति थी जो गूर, मीरा, तुलसी, नन्ददाम, दादू, रैदास आदि की थी। यह संस्कृति जातीय और जनवादी थी, इसीलिए कबीर को हिन्दू और मुसलमान दोनों अपनाते के लिए तैयार थे। दरवारा की संस्कृति अलग थी। मुसल राज्यसत्ता इस जनवादी संस्कृति को आश्रय देनेवाली न थी।

हिन्दुस्तान के लोग सामन्ती डाँचा खत्म करके अपनी जातीय राज्यसत्ता कायम कर बैठे लेकिन तभी अंग्रेजों की दखलान्दाजी से उनकी ऐतिहासिक प्रगति में बाधा पड़ी।

अन्तीमवी सदी में अंग्रेजों ने हिन्द प्रदेस को अपने अधिकार में लिया। हिन्दुस्तान में ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनसे फायदा उठाकर उन्होंने भाषा और संस्कृति के मामलों में दखल देना और वहाँ के लोगों में फूट डालना शुरू किया।

महाराष्ट्र, आन्ध्र, बंगाल, पंजाब आदि में वे परिस्थितियाँ न थीं जो हिन्दी-भाषी इलाके में थी। महाराष्ट्र में शिवाजी एक जातीय रियासत कायम कर चुके थे। वैसे कोई कोशिश यहाँ न हुई थी। शिक्षा का कोई मिला-जुला जातीय क्रम निश्चित न था, मुस्लिम-पंडितों के हाथ में अब भी शिक्षा की जिम्मेदारी थी। इस धार्मिक शिक्षा की वजह से दो लिपियों का प्रयोग होता था और भाषा की एकता के हिसाब से सब जगह एक ही लिपि का चलन न था। मुगल साम्राज्य के उखड़ने के बाद नवाबों के अड़्डे ज्यादातर हमारे इलाके में रहे। बंगाल, महाराष्ट्र, आन्ध्र, वगैरह इनसे अपेक्षाकृत मुक्त रहे। हैदराबाद में उर्दू के अतिरिक्त तेलुगु भाषा में कुछ तबदीली हुई, लेकिन उस हद तक नहीं कि तेलुगु में हिन्दी उर्दू की तरह दो धाराएँ चल पड़ें।

अंग्रेजों ने जिस अलग-अलग से फायदा उठाया और उसे गहरा बनाया, वह यहाँ की धार्मिक शिक्षा और सामन्ती पिछड़ेपन की वजह से था। बहूत-से राज-दरबारों में ब्रज भाषा के आगे नयी जातीय भाषा हिन्दी की पूछ न थी, नवाबों के यहाँ खड़ी बोली के लोकप्रिय रूप और जनवादी कविता की कद्र न थी। इस तरह खड़ी बोली में दो धाराएँ चल निकली—एक तो लोकप्रिय धारा, दूसरी सामन्ती के आश्रयवाली धारा। कुछ कवियों ने साधारण भाषा के शब्दों के बहिष्कार की नीति अपनायी जिससे उनकी शैली बोलचाल की भाषा से अलग मालूम होने लगी।

अंग्रेजों ने इस भेद को और गहरा किया। गिलग्राइस्ट ने हिन्दुओं और मुसलमानों की अलग भाषाओं के सिद्धान्त की रचना की। रिजले ने धर्म के आधार पर दो कौम गढ़ी और ग्रियर्सन ने भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में फूट के उसूल को धार्मिक रूप दिया। सर सैयद ने लश्करो में नयी भाषा बनने की तजवीज पेश की। इकबाल ने मुस्लिम कौम और मुस्लिम संस्कृति का नारा लगाया। ये सब साम्राज्यवादी विषय के फल थे।

अंग्रेजों के राज में गाँवों की पुरानी व्यवस्था तो टूटी लेकिन उन्होंने सामन्तवाद और सामन्ती संस्कृति को मजबूत भी किया। इसी जर्जर सामन्ती संस्कृति पर उन्होंने अपनी तहजीब का ताज रखा। हिन्दीभाषी इलाके को उन्होंने कई सूबों में बाँटा, यहाँ ताल्लुकदारों और नवाबों को पाला-पोसा, और भाषा के मामले में जातीय उत्पीड़न का एक नया तरीका निकाला। कभी हिन्दुओं को दबाया, मुसलमानों को उभारा, कभी हिन्दुओं को उभारा और मुसलमानों को दबाया। कचहरी, मदालत और पुलिस में वह जबान चलाई कि बिस्तर कभी समझ ही न सके और उसे ठगने और लूटने में उन्हें आसानी हो। इस तरह एक तरफ उर्दू की धारा बही, दूसरी तरफ हिन्दी की। फिर भी भाषा के बुनियादी शब्दों और मूल व्याकरण-व्यवस्था के बिना कोई भी धारा आगे न बढ़ सकती थी।

हिन्दी उर्दू का भेद उन्नीसवीं सदी में पहले नगण्य है। उन्नीसवीं सदी में

अंग्रेजी राज कायम होता है और तभी यह भेद गहरा होता है। इसलिए उस भेद के लिए सबसे ज्यादा अंग्रेज ही जिम्मेदार हैं। अगर सूफियो और सन्तो की परम्परा जिम्मेदार होती तो इस तरह की दो धाराएँ बगल, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह में भी बढ़ती दिखाई देती। वहाँ नहीं दिखाई देती, यह इस बात का प्रमाण है कि हिन्दी-उर्दू का भेद अस्थायी है, जो जनता के स्वाधीनता-आन्दोलन की बढ़ती के साथ कम होते-होते मिट जाएगा। आखिर अभी सौ साल भी तो इस पार्श्व को नहीं हुए।

हिन्दीभाषी इलाके में सामन्ती अवशेष कायम रखकर, हिन्दी-उर्दू के सवाल में साम्प्रदायिकता उभारकर, एक ही भाषा की दो धाराएँ बहाकर और दोनों पर अंग्रेजी लादकर, आम जनता को अशिक्षित रखकर अंग्रेजों ने हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को भारी नुकसान पहुँचाया है।

फिर भी हर जगह उनकी मनचीती नहीं हुई। हिन्दुस्तानी जनता ने आमानी में उनका जुग्रा स्वीकार नहीं किया। १८५७ में दिल्ली, मेरठ, बानपुर, भँसी आदि गहरों के और अवध, भोजपुरी, बुन्देलखण्ड आदि जनपदों के वीरों ने अंग्रेजों के दाँत खट्टे कर दिए। अगर अंग्रेजों को हिन्दुस्तानियों से ही मदद न मिलती तो देश का इतिहास ही दूसरा होता। हमारे साहित्यकारों ने जनवादी सस्कृति की परम्परा को निवाहा। हिन्दी उर्दू के जेखको के सहयोग को अंग्रेज खत्म नहीं कर पाए। भारतेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, जो आधुनिक हिन्दी के निर्माता हैं उर्दू के भी लेखक थे। प्रेमचन्द ने उस परम्परा को और आगे बढ़ाया।

कांग्रेस और लीग के नेताओं ने कान्तिवारी जन-आन्दोलन का तो विरोध किया, लेकिन साम्राज्यवादियों की स्वाधीनता-योजना स्वीकार की। भारतीय जनता से भय खाकर अंग्रेजों ने अपना झुंडा और अपनी कौज तो टूटा ली लेकिन अपने पूँजीवादी पजे देश में और भी गढ़ा दिए।

अंग्रेजी पूँजी का हित इस बात में है कि बँटवारे के बाद कायम की हुई दोनों रियासतें आपस में लड़ें या उनमें तनातनी रहे जिससे कि लोगों का ध्यान छिपे हुए सुटेरों की तरफ न जाय। इसके लिए उन्होंने दगे कराए, कश्मीर को लड़ाई कराई और साम्प्रदायिक दलों के जरिए तनातनी कायम रखी।

साम्प्रदायिकता से फायदा उठाकर पाकिस्तान के शासकों ने वहाँ की भाषाओं को दबाया और उन पर उर्दू लादी। हिन्दुस्तान के साम्प्रदायिकों ने कहा कि अब तो उर्दू पाकिस्तान गई और यहाँ उसकी बात करना भी राष्ट्र-द्रोह है। राजपि टडन और महाशक्ति राहुन ने इस विपक्षी प्रचार का नेतृत्व किया। उत्तर भारत के सूबों में हिन्दी ठीक ही, राजभाषा घोषित की गई, लेकिन उर्दू के व्यवहार और शिक्षा आदि में तरह-तरह के झड़गे लगाये गए।

हिन्दी के कुछ लेखक इस परिस्थिति को सन्तोषजनक समझते हैं। लेकिन उर्दू को दबाने से हमारी जातीय भाषा के विकास में बाधा पड़ती है, इसलिए



इस परिस्थिति को संतोषजनक कैसे कहा जा सकता है? उर्दू में पौत्रप्रिय साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। उगमे बोलचाल के मुहावरों का निबन्धा हुआ रूप ही नहीं है, हमारी भाषा और साहित्य का इतिहास उसके बिना अधूरा रहेगा। इसलिए अपनी जानि के सांस्कृतिक इतिहास के लिए, अपनी जातीय भाषा के विवास के लिए मैं उर्दू के दवाने का विरोध करता हूँ।

कांग्रेसी नीति के गिलाफ उर्दू के कुछ लेखकों ने विधान की सहायता लेते हुए इलाकाई जवान का सवाल उठाया है। हिन्दी में अलग उर्दू का कोई अलग इलाका नहीं है हालाँकि उर्दू या हिन्दी को अपनी एकमात्र साहित्यिक भाषा समझनेवाले लोग हैं। इसलिए उर्दू के पढ़ने-पढ़ाने और उसे व्यवहार में लाने में जो भी बाधाएँ आती हैं, उन्हें दूर करने के लिए आवाज बुलन्द करना सभी जनवादियों का कर्तव्य है। उसे अलग इलाकाई जवान मानना गलत है।

हिन्दीभाषी इलाके की जनता के लिए किसानों में शिक्षा का सवाल भाषा की समस्या के साथ जुड़ा है। किसानों को ग्राम शिक्षा किस लिपि में दी जाय? अगर किसानों को एकजुट करना है, उनकी राजनीतिक चेतना को विकसित करना है, उनके आन्दोलन को राष्ट्रीय आन्दोलन की घुरी बना देना है तो ग्राम शिक्षा के लिए दो लिपियाँ रखना हाज़िराब होगा। इसलिए मेरी राय है कि देवनागरी लिपि के जरिये ग्राम जनता में शिक्षा के प्रचार पर जोर देना चाहिए।

अंग्रेजों ने १८५७ से सदा लेकर हमारे इलाके को सबसे ज्यादा टुकड़ों में बाँटा है। सदियों से एक साथ रहनेवाले आगरा और दिल्ली भी अलग हो गए। हिन्दीभाषी इलाका एक होना चाहिए। इसके बारे में यह कहना भी नहीं चल सकता कि बड़े सूबे का छोटे सूबों में हम बाँटना चाहते हैं। यहाँ सवाल छोटे टुकड़ों को मिलाकर बड़ा सूबा बनाने का है। अलग-अलग प्रांतीय सभाएँ और हुकूमतें चलाने का खर्च बचेगा, व्यापार और उद्योग धंधों की तरक्की में मदद मिलेगी। हमारा सांस्कृतिक आन्दोलन पूरे प्रदेश में जातीय पैमाने पर चलेगा और भाषा भी अपना जातीय रूप निखार सकेगी।

किसान-आन्दोलन की बढ़ती के लिए यह आवश्यक है कि बोलियों में साहित्य रचा जाय। अभी भी वह रचा जा रहा है। लेकिन हर जनपद के लिए अलग सूबा या प्रजातन्त्र बनाने की माँग करना जातीय प्रदेश के बँटवारे को दूसरे रूप में कायम रखना है। इससे सावधान रहना चाहिए।

हिन्दीभाषी लेखकों का हित इस बात में है कि वे भाषावार प्रान्त-निर्माण के आन्दोलन का समर्थन करें, दूसरों की मर्जी के खिलाफ उन पर हिन्दी भाषा लादने का विरोध करें। इससे दूसरी भाषाओं के लोग उनकी जातीय एकता के आन्दोलन का समर्थन करेंगे। उन्हें इस भ्रम में कि संस्कृत-गर्भित होने से हिन्दी दक्षिण में ज्यादा समझी जाएगी, अपनी भाषा को बिगड़ने न देना चाहिए। संस्कृत-गर्भित हिन्दी के पक्षपाती साहित्य-सम्मेलन ने दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार का काफ़ी अहित किया है। वहाँ पर हिन्दी का प्रचार किया है

‘दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा’ ने जिसकी नीति सम्मेलन में भिन्न है ।

हिन्दीभाषी इलाका भारत का सबसे बड़ा जातीय इलाका है। सख्या के विचार से हिन्दुस्तानी जाति दुनिया की तीन-चार सबसे बड़ी जातियों में गिनी जाएगी। ऋग्वेद और महाभारत की रचना इसी प्रदेश में हुई है। यही की नदियों के किनारे वाल्मीकि और तुलसी ने अपने अनुष्टुप और चौपाइयाँ गाई हैं। तानसेन और यँयाज राँ, हाली, भीर, अकबर, गालिब, भारतेन्दु, प्रेमचन्द, निराला यही के रत्न हैं। ताजमहल और विदेवनाथ के मन्दिर यही के हाथों ने गढ़े हैं। आल्हा और बजली ने सैकड़ों साल तक यहीं का आवाज गुंजाया है। अठारह सौ सत्तावन में यही की धरती हिन्दुओं और मुसलमानों के खून से सींची गई है। जिन दिन यह विशाल हिन्दी प्रदेश एक होकर नये स्वाधीन जनजीवन का निर्माण करेगा, उस दिन इसकी मरुति एशिया का मुख उज्ज्वल करेगी। किसानों और मजदूरों की एकता जा जाता की एकता की धुरी है, वह दिन निकट लाएगी। हिन्दी और उर्दू के लेखकों को इस जनता के हितों को ध्यान में रखकर अपनी जातीय परम्परा के अनुसार लोकप्रिय भाषा और जनवादी साहित्य के विकास में योग देना चाहिए ।

(१९५३)

## हिन्दी-उर्दू समस्या

अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति का तनाव दूर करने के लिए शान्ति प्रेमी जनता जोर-जबर्दस्ती के बदले समझौते की बातचीत का रास्ता पसन्द करती है। भारतीय शान्ति-आन्दोलन के नेताओं ने भी तीसरा महायुद्ध की तैयारियाँ रोकने के लिए समझौते की बातचीत चयन पर जोर दिया है।

मेरा विचार है हिन्दी-उर्दू समस्या को लेकर जो तनाव पैदा किया गया है, उसे दूर करने के लिए भी समझौते की बातचीत चलाना और छुरेबाजी को प्रोत्साहन न देना श्रेयस्कर हो सकता है।

पिछले दिनों उर्दू प्रेमियों की तरफ से उर्दू को क्षेत्रीय भाषा के रूप में मानने और उसी लिए क्षेत्रीय भाषा के अधिकार माँगने के बारे में आन्दोलन हुआ था। उस आन्दोलन के जवाब में कुछ हिन्दी प्रेमियों की तरफ से भी आन्दोलन हुआ और लखनऊ में उर्दू प्रेमियों के सम्मेलन के अवसर पर एक उर्दू-प्रेमी को एक हिन्दी प्रेमी ने छुरा मारकर उस अस्पताल भेज दिया।

आप मानेंगे कि टैंक और ऐटम बम का खतरा न होने पर भी लखनऊ जैसे शान्तिप्रेमी नगर में यह कांड होना जाहिर करना है कि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय तनाव दूर करने के लिए वमबाजी का रास्ता बुरा बताया जाता है, वैसे ही भाषा की समस्या हल करने के लिए छुरेबाजी का रास्ता भी बुरा समझा जाना चाहिए।

उत्साहवादी करनेवाले आन्दोलन अक्सर अर्द्ध सत्यो को लेकर चलते हैं। इसमें शक नहीं कि बहुत-से उर्दू-प्रेमियों में सम्प्रदायवादी भी हैं, और पहले भी रहे हैं। लेकिन इस बात को लेकर अर्द्ध सत्यप्रेमी सज्जन यह नतीजा निकालते हैं कि सभी उर्दूवाले सम्प्रदायवादी हैं, उर्दू का जन्म ही सम्प्रदायवाद से हुआ है। पाकिस्तान का जन्म भी उर्दू के कारण हुआ है (भले ही पूर्वी पाकिस्तान के लोग उर्दू को राजभाषा बनाने के खिलाफ लड़े हों) और इसलिए जितना ही जल्दी उर्दू को मिटाया जाय, उतना ही अच्छा।

इसमें भी शक नहीं कि हिन्दी प्रेमियों में बहुत से सम्प्रदायवादी हैं और पहले भी रहे हैं। लेकिन इस बात से उर्दू-प्रेमियों के अर्द्ध सत्यप्रेमी यह नतीजा निकालते

है कि सभी हिन्दी प्रेमी सम्प्रदायवादी हैं, हिन्दी का जन्म ही सम्प्रदायवाद से उर्दू के मोठे सरल शब्दों को निवालकर उनकी जगह सस्कृत के कवच-परधर भरकर हुआ है। हिन्दी को बिहार या उत्तर प्रदेश की राजभाषा बना दिया गया है, यह हिन्दी प्रेमियों की साम्प्रदायिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है।

इसी तरह हिन्दी-खेमे के अर्द्ध सत्यप्रेमी उर्दू-विरोध को राष्ट्रीयता की पहली शर्त मानते हैं। यह उर्दू-विरोध जल्द ही मुस्लिम-विरोध का रूप ले लेता है और उसका वापदा करनेवाली 'दलीलें' दी जाती हैं जिन्हें सुनकर मालूम होने लगता है कि जनता की भूलमरी, भ्रमशिता, भ्रमकाल और भ्रममार्ग का एकमात्र कारण उर्दू है।

उधर उर्दू-खेमे के अर्द्ध-सत्यप्रेमी उर्दू को हिन्दी से और दूर खींचकर, हिन्दुस्तानी जनता के सांस्कृतिक इतिहास से और दूर ले जाकर, इस्लाम से उर्दू का सम्बन्ध अपनी समझ में और पक्का करके, भ्रमगाव की भावना को और मजबूत करते हैं। समूची हिन्दुस्तानी जनता कैसे साधारण होकर अपनी मिली-जुली सस्कृति, अपना मिला-जुला लिखित साहित्य आगे बढ़ाएगी, अवधी, ब्रज, बुन्देलखण्डी, भोजपुरी आदि से हम अपनी भाषा के लिए क्या लेंगे, कैसे उसे सोलह करोड़ के लिए सुलभ बनाएंगे ये समस्याएँ उनके लिए हैं ही नहीं। उल्टा वे किसी महा अश्लील पत्रिका की बित्री का हवाला देकर पूछेंगे, 'कहिए, आपके यहाँ कोई पत्रिका इतनी बिकती है?' या अपने बड़प्पन की डींग हाँकेंगे, 'हमने जितना क्या हासिल किया है उतना किसी ने किया ही नहीं है।'

उर्दू खेमे के ये अर्द्ध-सत्यप्रेमी आशा और निराशा के बीच झूलते खाते हैं। कभी तो वे उर्दू के अजर-अमर होने की बात सोचकर गद्गद हो उठते हैं और कभी उसका विनाश निश्चित समझकर बैसे ही उदास और परेशान हो जाते हैं।

किसी जिले या सूबे को ध्यान में रखकर हिन्दी-उर्दू की समस्या स्थायी रूप से हल नहीं की जा सकती। यह समस्या सभी हल होगी जब हम हिन्दी प्रेमी और उर्दू-प्रेमी दोनों समूची हिन्दुस्तानी जाति के राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन की समस्या के सन्दर्भ में उस पर विचार करेंगे। सवाल यह है कि जैसे तेलुगु, मराठी, तमिल या कन्नड़ भाषाएँ बोलनेवाले अपने अपने प्रदेश में अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन करने के लिए उठ खड़े हुए हैं या उठ खड़े हो रहे हैं, वैसे ही क्या हिन्दुस्तानी लोग भी मुगल और ब्रिटिश राज के अपने भ्रमगाव को खत्म करके एक जातीय प्रदेश में अपने राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन के लिए उठेंगे? या वे अपनी सामान्य समस्याएँ भ्रम-भ्रम अपने जिले और सूबों में ही उलझाते-मुलझाते रहेंगे?

अभी पिछले दिनों भाषावार प्रान्त बनाने के सिलसिले में जो सम्मेलन हुआ, उसमें और भाषाओं के प्रतिनिधियों ने तो अपने जातीय झुकावों के पुनर्गठन की बात उठाई लेकिन हिन्दुस्तानी प्रदेश का सवाल वहाँ उठा ही नहीं। इसका सबब यह है कि हिन्दुस्तानी जनता का प्रदेश और जातियों के प्रदेश से बड़ी ज्यादा

बैठा हुआ है, यहाँ भी जातीय चेतना ४१ वभी हिन्दी-उर्दू विवाद से, कभी भोज-पुरी या मैथिली प्रान्त के आन्दोलन से, वभी बिहारी-बंगाली फसाद से सही रूप में विकसित होने नहीं दिया गया।

हिन्दी-उर्दू समस्या को लेकर जो लोग साम्प्रदायिक प्रचार करते हैं, वे हिन्दुस्तानी जनता की जातीय चेतना पर सबसे पहले प्रहार करते हैं।

हिन्दी-उर्दू के अर्द्ध-सत्यप्रेमी हिन्दुस्तानी जाति के प्रदेश का सवाल, उसके राजनीतिक और सास्कृतिक पुनर्गठन का सवाल नहीं उठाते, यह बात आकस्मिक नहीं है। वे सारे हिन्दुस्तान में हिन्दी फैलाने के लिए कटिबद्ध हैं, लेकिन जब दक्षिण के लोग उनसे पूछते हैं—हिन्दी किस प्रदेश की भाषा है, तो वे बगलें भाँकने लगते हैं।

यह बात आकस्मिक नहीं है कि हिन्दी खेमे के कुछ अर्द्ध-सत्यप्रेमी हिन्दुस्तानी जाति के इलाके को 'बोलियों के आधार पर ग्यारह हिस्सों में बाँट देने का प्रचार करते हैं। 'भाषा' के आधार पर वे प्रान्त-निर्माण की बात नहीं करते वरन् 'बोली' के आधार पर एक जातीय प्रदेश के बहुत-से टुकड़े करने की बात करते हैं।

समूचे हिन्दुस्तानी प्रदेश को ध्यान में रखते हुए हिन्दी-उर्दू समस्या पर विचार किया जाय, तो ये परिणाम निकलते हैं—

१. जहाँ तक साधारण जनता की बोलचाल का सम्बन्ध है, हिन्दी-उर्दू का कोई भेद नहीं है।

२. हिन्दी-उर्दू का भेद लिखित भाषा के मामिले में उठता है।

३. उर्दू को लिखित भाषा के रूप में काम में लानेवाले लोग आम तौर से सम्प्रदायवादी नहीं हैं। वास्तव में कुछ हिन्दू सम्प्रदायवादी भी लिखित भाषा के रूप में उर्दू का प्रयोग करते हैं। उर्दू का प्रयोग करनेवाले सब मुसलमान ही नहीं, गैर मुसलमान भी हैं।

४. लिखित भाषा के लिए जो लोग हिन्दी का प्रयोग करते हैं, उनकी संख्या उर्दू का प्रयोग करनेवालों से ज्यादा है। इससे नतीजा यह निकलता है कि हिन्दुस्तानी प्रदेश में एक 'सांस्कृतिक अल्पमत' लिखित उर्दू का प्रयोग करता है।

५. व्यवहार में इस सांस्कृतिक अल्पमत की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता रहा है, जैसे फिल्मों में हिन्दी लिपि के साथ उर्दू का प्रयोग, अनेक गैर-साम्प्रदायिक संगठनों का उर्दू पत्र निकालना (जिनमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है)।

हिन्दी खेमे के अर्द्ध-सत्यप्रेमी यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उर्दू एक सांस्कृतिक अल्पमत के काम में आनेवाली लिखित भाषा है। वे इस सत्य को दोहराकर कि जनता की भाषा यानी 'बोलचाल की भाषा' एक है, इस बात से इन्कार करते हैं कि लिखित भाषा में आज भेद है और उर्दू एक सांस्कृतिक अल्पमत की ज़रूरतें पूरी करती है।

इमलिए वे हिन्दी को राजभाषा बनाकर उर्दू के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहते हैं जिससे लिखित भाषा के एकीकरण का सवाल एक दूसरे से सीखकर, कुछ आपस में आदान प्रदान करके हल न हो, बल्कि एक लिखित रूप को दबाकर हो।

उर्दू खेमे के अर्द्ध-सत्यप्रेमी यह मानने में इन्कार करते हैं कि समूचे हिन्दूस्तानी प्रदेश में उर्दू का व्यवहार एक लिखित भाषा के रूप में एक सांस्कृतिक अल्पमत करता है। वे यह मानने से इन्कार करते हैं कि सवाल सांस्कृतिक अल्पमत की लिखित भाषा की रक्षा करने, उसके उपयोग की सुविधाएँ देने का है। वे सभी राजराज के लिए दोनों लिपियों के चलन की बात कहते हैं, कभी उसे क्षेत्रीय भाषा मानकर उसके लिए दिल्ली, भोपाल और लखनऊ का 'क्षेत्र' ढूँढ़ने लगते हैं।

उर्दू खेमे के ये दोस्त हवीकन पहचानने में गलती करते हैं, जिससे हिन्दी-खेमे के सम्प्रदायवादी ही मजबूत होत हैं, उर्दू की रक्षा और उसके व्यवहार की सुविधा देने का असली प्रश्न टल जाता है।

लिखित भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग हमारे प्रदेश के बहुसंख्यक लोग करते हैं। इमलिए उनकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है कि एक ही लिखित भाषा के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ तैयार करने में मदद दें। इस काम में एक बाधा यह प्रचार है कि लिखित भाषा के रूप में उर्दू को दबाने से हमारी भाषा-समस्या सुलभ जाएगी। जो लोग इस तरह का प्रचार करते हैं, वे अर्द्ध-सत्य का सहारा लेकर लिखित उर्दू के सामन्ती साहित्य, उसकी ईरानी परम्पराओं का हवाला तो देते हैं लेकिन लिखित उर्दू के जनवादी और लोकप्रिय साहित्य के बारे में खामोश रहते हैं या गरासर भूठा प्रचार करते हैं।

सन् '४७ के बाद हिन्दी खेमे के सम्प्रदायवादियों ने नये सिरे से जोर मारा है। राजनीतिक जीवन से उलझे होने पर कुछ सज्जन भाषा को लेकर सम्प्रदायवाद का प्रचार करने लगे। कुछ मित्रों को यह भ्रम है कि ऐसे लोग केवल भाषा के मामले में सम्प्रदायवादी हैं, बाकी मामलों में असम्प्रदायिक और जनवादी हैं।

इस तरह की धारणा बनाते हुए बहुत सतर्क रहना जरूरी है।

सन् '४७ में—भारत विभाजन के बाद—राहुलजी ने हिन्दी-उर्दू समस्या के सिलसिले में ही कहा था—

“इस्लाम को भारतीय बनना चाहिए—उनका भारतीयता के प्रति यह विद्वेष सदियों से चला आया है सही, किन्तु नवीन भारत में कोई भी धर्म भारतीयता को पूर्णतया स्वीकार किये बिना फल-फूल नहीं सकता।”

बात थी उर्दू की, नतीजा निकला कि “उनका भारतीयता के प्रति यह विद्वेष सदियों से चला आया है,” यानी मुसलमान मूलतः राष्ट्र-विरोधी हैं।

और 'आज की राजनीति (१९५०) में राहुलजी ने हिन्दी-उर्दू समस्या

के सिलसिले में ही लिखा था—

“इस्लाम ने जो भी कहा हो किन्तु मुसलमानों ने अपने को देश की धारा का अंग मानने से सदा इन्कार किया।”

बात थी उर्दू की, नतीजा निरला कि मुसलमानों ने अपने को इस देश की धारा का अंग ही न समझा।

घोर भी, उसी पुस्तक में राहुलजी कहते हैं—

“इस्लाम का भारतीयकरण करना ही हितकर होगा। मौलाना आजाद की यह मनोवृत्ति यदि भारतीय मुसलमानों में रही, तो उनकी भक्ति तथा महानुभूति हमेशा भारत की अपेक्षा पाकिस्तान के साथ रहेगी। यह भावना भारतीय मुसलमानों को छिपा पचमागी बनाकर छोड़ेगी।

यदि मुसलमान पचमागी बन रहे हैं तो उनके साथ व्यवहार भी वही होगा जो देशद्रोहियों के साथ होता है। हिन्दू मुस्लिम दंगे कराने के लिए इसमें क्यादा क्या कहा जा सकता है? आप कहेंगे, यह तो भाषा सम्बन्धी मनोवृत्ति को लेकर लिखा गया है।

मान लिया, भाषा-सम्बन्धी मनोवृत्ति को लेकर लिखा गया है, लेकिन इस किताब में युधिष्ठिर नाम का पात्र—जो राहुल उवाच की जगह सूत्रधार का काम करता है—कहता है, आप कुरान को उठाकर किसी धर्म के प्रमुख ग्रन्थ से मिलाकर देख लीजिए, वह हर तरह से मित्रकोटि का जंजेरा।”

अब आप पता लगाएँ कि दुनिया के तमाम मुसलमानों के धर्मग्रन्थ से हिन्दी उर्दू समस्या का क्या सम्बन्ध है।

देखिए, राहुलजी का केवल भाषा के मवाल पर सम्प्रदायवादी होना अक्ल ठीक करने के कंस मुन्दर नतीजे तक पहुँचता है।

हमारे अनक शुभ विचार रखनेवाले भाइयों ने राहुलजी का विरोध करना तो दूर उनकी पीठ थपथपाई कि आप वास्तव में प्रगतिशील विचारक हैं। उनका खयाल था कि राहुलजी का पर्दाफाश करने में समुक्त मोर्चा टूट जाएगा (राहुलजी की नीति से उन्हें समुक्त मोर्चे के लिए कोई भय न था), इसलिए कभी तो वे उनके भाषा सम्बन्धी प्रचार को आदर्श कहते रहे, कभी चुप रहे और कभी घेरे जाने पर बाले कि राहुलजी को सम्प्रदायवादी कहने से क्या होता है, सभी हिन्दी लेखक जैसा ही सोचते हैं।।।

इस अवसरवादी नीति को, साम्प्रदायिकता को, तरह देन का नतीजा यह हुआ कि राहुल जी के चरणचिह्न पर चलनेवाले और ‘प्रगतिशील’ लेखक भी आगे आ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बनाने के आन्दोलन के सिलसिले में ‘उत्तर प्रदेश भाषा समिति’ लखनऊ ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नाम एक आवेदन पत्र छपवाया था। इसमें कहा गया था—

"हम इस प्रदेश की भाषा के बंटवारे और भाषा की बीटार जनता में फूट डालन की विपरीत साम्प्रदायिक नीति का घोर विरोध करते हैं। यह प्रवृत्ति जन विरोधी, राष्ट्रीयता-विरोधी और देशद्रोही है।"

जब कोई प्रवृत्ति 'देशद्रोही' करार दी जाएगी, तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा ? आन्दोलन-पत्र न ऐसा वातावरण तैयार करने की कोशिश न की जिसमें हिन्दी-उर्दू लेखक बैठकर समस्या पर विचार करते और उसे सुलभाने की कोशिश करते। उर्दू-प्रेमियों न क्षेत्रीय भाषा के लिए जैसे हिन्दी लेखकों से सलाह माँगी कि वे बिना आन्दोलन छोड़ दिया था और उर्दू की रक्षा की सही माँग का क्षेत्रीय भाषा की गलत माँग से उलझा दिया था, वैसे ही और उसमें पचास बरस आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश भाषा समिति ने इन उर्दू प्रेमियों की कोशिश का देशद्रोह करार दे दिया।

इससे खुले सम्प्रदायवादियों ने फायदा उठाया और छुरेबाजी के लिए वातावरण पैदा कर लिया।

अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों की तरह भाषा-सम्बन्धी मामलों में भी उक्तावे की नीति के बदन सुनह-समझौते की बातचीत चलाना क्यों जरूरी है।

आन्दोलन-पत्र पर भाषा समिति के मन्त्री की हैसियत से सुप्रसिद्ध प्रगति-शील कलाकार मंगलाल के दस्तखत हैं।

मंगलालजी यह प्रद्व-मत्य मानकर कि हिन्दुस्तानी जनता की एक भाषा है, उसके दो लिखित रूपों को प्राज्ञ की आवश्यकता को सिर्फ एक लिपि-रूप रख-कर तुरन्त खत्म कर देना चाहते हैं। उनके विचार से हिन्दी-उर्दू के प्रादान-प्रदान का सवाल नहीं है। समझा-बुझाकर एक लिपि चलाने का सवाल नहीं है। सवाल है दो में से एक ही रूप रखकर समस्या को हल करने का। हिन्दी-उर्दू की समस्या को जोर-जबर्दस्ती से हल करने का ममयंत्र करते हुए मंगलाल जी कहते हैं—

"दमन और जबर बड़े अप्रिय शब्द हैं। हम इन शब्दों को सदा ही अपने विरोधियों के गले मढ़ते हैं। लेकिन किसी भी नियम या अनुशासन को दमन और जबर कह दिया जा सकता है। अनिवार्य शिक्षा भी एक प्रकार का दमन और जबर है और पैदावार के माधनों का राष्ट्रीयकरण तो बहुत बड़ा दमन और जबर बताया जाएगा।"

(‘नया पथ’—सितम्बर, १९५३)

वहाँ राष्ट्रीयकरण, वहाँ हिन्दी-उर्दू समस्या। पहले तो भारत में पैदावार के माधनों के राष्ट्रीयकरण का सवाल ही नहीं उठता और जहाँ उठता है या उठा है, वहाँ कामचोर वर्गों की मिलिशिन खत्म करने को उठा है। क्या जो लोग लिखित भाषा के लिए उर्दू काम में लाते हैं, कामचोर वर्गों के लोग हैं ? मंगलालजी की उपमा ही जाहिर करती है कि उन्होंने कामचोर वर्गों की वास्त-

हिन्दी उर्दू ,



विक्रम समरया मुलाकर (और ये वर्ग लिखित भाषा के लिए हिन्दी-उर्दू दोनों का प्रयोग करते हैं ।) तमाम उर्दू-प्रेमियों को—या लिखित भाषा के लिए उर्दू-प्रयोग की सुविधा चाहनेवालों को—कामचोर-वर्ग बना दिया है और उन्हें अधिकारहीन करने का फैसला कर लिया है ।

अनिवार्य शिक्षा का चलन करने पर दमन और जबरन जनता पर नहीं होता बल्कि उन कामचोर वर्गों पर होता है जो जनता को निरक्षर रखते हैं । राष्ट्रीयकरण में जो व्यवहार कामचोर वर्गों के साथ होता है, उसकी तुलना जनता को अनिवार्य शिक्षा देने से करके यशपालजी ने जनता और शोषक वर्गों का भेद मुला दिया है ।

जब तक हमारे कुछ लेखक यह प्रचार करते रहेंगे कि जोर-जबर्दस्ती से हल करने पर लिखित भाषा की एकता कायम हो जाएगी, तब तक वह एकता उतनी ही दूर चली जाएगी, जनता में फूट डालनेवाले भाषा के सबाल को प्रेम से इस्तेमाल करेंगे और इस सबसे हिन्दुस्तानी जनता के राजनीतिक और सांस्कृतिक पुनर्गठन का सबाल—हिन्दी प्रदेश के एकीकरण का सबाल—खटाई में पड़ा रहगा ।

यह समझना भूल होगी कि सभी हिन्दी-लेखक राहुलजी या यशपालजी की तरह सोचते हैं ।

अगस्त, १९५३ की 'अवन्तिका' ने सम्पादकीय नोट में इस बारे में लिखा है ।

'अवन्तिका' उर्दू को किसी क्षेत्र की अलग भाषा नहीं मानती । लेकिन वह उस स्वदेशी भाषा मानती है, राहुलजी की तरह अरब जेहादियों का कीर्ति-स्तम्भ नहीं । वह उसके विकास में बाधा देने का विरोध करती है, जोर जबर्दस्ती से राष्ट्रीयकरण या इस्लाम के भारतीयकरण का सबाल नहीं उठाती ।

इससे यह परिणाम निकलता है कि उसका पैदा करनेवाला वातावरण खत्म करके अगर हिन्दी-उर्दू के जनवादी लेखक इस समस्या को सुलझाने बैठें तो ऐसा हल निकल सकता है, जिसमें किसी के साथ जबरन भी न हो और क्रमशः हमारे हिन्दुस्तानी प्रदेश में एक लिखित भाषा के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी तैयार हो जाएँ ।

(१९५३)

## भाषा और प्रान्तीयता

इस बार गमियो में जब कलकत्ता गया तो लगा, शहर कुछ बदला-सा है। बँगला-भाषी मित्र बँगला छोड़कर ग्राम तौर से दूसरी भाषा में बात न करते थे। कुछ लोगों ने यह शिकायत भी की कि बस या ट्राम में किसी बंगाली बड़कटर से हिन्दी में टिकट माँगे तो वह टिकट न देगा या उपेक्षा दिखलाएगा, दफतरो में हिन्दी बोलकर काम कराने जाओ तो बीस बिसुवे काम होगा नहीं। एकाध साहित्य प्रेमी ने कहा, “आप जो कुछ हिन्दी भाषण में कहते हैं, उसे प्रेसीजी में भी कहें, हम उसमें बँगला साहित्यकारों और प्रोफेसरों को भी गुलाएँगे, उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि हिन्दी में क्या है।”

एक बँगला भाषी हिन्दी-प्रचारक मित्र ने कहा, “आपके यहाँ से कुछ लोग आकर हमारा काम चौपट कर जाते हैं। यहाँ आकर रहते हैं, ‘बँगला में है क्या ? रबीन्द्रनाथ ने जो कुछ लिया है, वहीर से।’ घरे बाबा, आप लोग हिन्दी हिन्दी क्या चिल्लाते हो ? है क्या आपकी हिन्दी में ? और हिन्दी-प्रचार तो हम राजा राममोहन राय के समय से कर रहे हैं जब आपके यहाँ लोग हिन्दी-प्रचार का नाम भी न जानते थे।”

एक चौहत्तर वर्ष के श्रान्तिकारी, विचारक और लेखक ने पूछा, “हिन्दुस्तान के भविष्य के बारे में क्या सोचते हो ?” मैंने कहा, “इस प्रश्न का उत्तर तो मुझसे अच्छा आप दे सकते हैं। मेरी समझ में हमारा भविष्य उज्ज्वल है।” उन्होंने कहा, “गृह-युद्ध होवाला है।” पूछा, “किसमें ?” मेरे मन में आया, शायद मजदूर-पूँजीपतियों की लड़ाई की बात सोचते होंगे। लेकिन वह बोले, “हिन्दुस्तानियों और बंगालियों में युद्ध होगा।” सुना था, कुछ दिन पहले बंगाली और हिन्दुस्तानी ट्राम-मजदूरों में झगडा हो चुका था। प्रत्यक्ष रूप से प्रसमियों और बंगालियों के दंगों की बात भी पढ़ चुका था। इसलिए गृह-युद्धवाली बात मैं हँसकर टाल न सका।

कलकत्ता की लगभग आधी जनता हिन्दुस्तानी है। यहाँ के मागवाही व्यापारी आपस में राजस्थानी बोलते हैं लेकिन शिक्षा, भाषण, प्रकाशन आदि

के लिए हिन्दी ही काम में लाते हैं। एक ओर तो ये बड़े बड़े व्यापारी हैं, दूसरी ओर अवधी, भोजपुरी, मैथिली आदि बोलनेवाले पूर्वी हिन्दीभाषी प्रदेश के लोग हैं जो ज्यादातर मेहनत-मजूरी के सहारे जिन्दगी बसर करते हैं। शाम को अपने डेरो पर डोल-मँजीरा या खँजरी या हुड्डुवा लेकर ये अपने लोकगीत गाते हैं। बँगला और हिन्दीभाषी भद्रजन समान रूप में इन्हे ग्रन्थ और ग्रन्थसूत समझकर इनसे प्रायः घृणा करते हैं। इनके भलावा बहुत-से अध्यापक और लेखक हैं, जिनमें से अधिकांश का उद्देश्य कलकत्ता आकर पैसा कमाना है, साहित्य-सेवा करना नहीं।

ऐसी स्थिति में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, यह भाषा लोगो के मन में बड़ी जल्दी पैदा होता है। इसका नतीजा यह होता है कि देश की विभिन्न जातियाँ आपस में मित्रता बरतने के बदले एक-दूसरे से बैर मानने लगती हैं, एक-दूसरे से सीखने के बदले अपने बड़प्पन की डींग हाँकने में सारा समय लगा देती हैं। जहाँ तक साहित्य का सम्बन्ध है, यहाँ की जातियाँ एक-दूसरे से सहयोग करके ही उसे सँवारती रही हैं और आगे भी उसे सँवार सकती हैं। सूर और तुलसी के युग में यहाँ के सांस्कृतिक आन्दोलन बराबर एक प्रदेश के बाहर के लोगो को भी प्रभावित करते रहे हैं। यदि ये व्यापक आन्दोलन न होते तो न सूर के पद रचे जाते, न चण्डीदास के। इसी तरह आधुनिक काल में देशभक्ति की जो लहर सारे देश में फैल गई, उसमें अनेक जातियो के लेखको का हाथ था। इसलिए किंगी भी भाषा के साहित्य पर गर्व करते हुए उसके प्रेमियो को यह न भूल जाना चाहिए कि उसका विरास दूसरो के सहयोग से ही सम्भव हुआ है और उसमें मिलती-जुलती विशेषताएँ दूसरो के साहित्य में भी हैं।

जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, वास्तविक स्थिति यह है कि बंगाल आदि राज्यों में बँगला-जैसी समृद्ध भाषाएँ भी वहाँ के राजकाज की भाषाएँ नहीं बनीं। अंग्रेजी का बोलबाला अब भी है और तनाव अंग्रेजी और देशी भाषाओ के बीच नहीं, हिन्दी और यही की दूसरी भाषाओ के बीच है। हिन्दी-प्रेमियों का हित इस बात में है कि बँगला आदि भाषाएँ राजकाज के लिए अपने देश में पूरी तरह काम में लाई जाएँ। जब तक अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में वहाँ की भाषाएँ अपने पूर्ण अधिकार नहीं पाती तब तक उनके बीच हिन्दी भी पूरी तरह परस्पर व्यवहार का माध्यम नहीं बन सकती। इससे विपरीत उन्हें डर रहेगा कि हिन्दी हमारी जगह छीनना चाहती है।

इधर शिक्षा के माध्यम को लेकर जो विवाद चल पड़े हैं, उनसे परिस्थिति और बिगड़ गई है। कई जगह यह प्रचार किया गया है कि किसी भाषा-विशेष के बदले हिन्दी ही शिक्षा का माध्यम बनेगी। तर्क यह होता है, हर जगह हिन्दी शिक्षा का माध्यम न होगी तो विश्वविद्यालय आपस में ज्ञान विनिमय न कर सकेंगे, विज्ञान की उन्नति न हो सकेगी, देश की सांस्कृतिक एकता टूट जायगी, इत्यादि। इस स्थिति से लाभ उठाकर अंग्रेजी-भक्त कहते हैं—“यह सब बहस

बैकार है, सबसे भली अंग्रेजी, इससे नया ज्ञान भी मिलेगा, पारिभाषिक शब्द  
 गढ़ने की समस्या भी न रहेगी और भारत की एकता भी बनी रहेगी।" इसपर  
 कुछ विश्वविद्यालय इस और काफी सरगर्मी दिखा रहे हैं। विभिन्न भाषा-  
 सेवों में जितना ही यहाँ की भाषाओं के हक मारे जाएंगे, उतना ही अंग्रेजी  
 उनके गिर पर सवार रहेगी, यह बात असंदिग्ध है। आवश्यकता इस बात की  
 है कि देश की भाषाएँ समान अधिकार पाकर विस्तृत हो और इनके बोलन-  
 वाले अन्तर्जातीय व्यवहार के लिए हिन्दी अपनाएँ, माहित्य के क्षेत्र में बढप्पन  
 की होड़ लगाने के बदले भारतीय साहित्य की सामान्य विशेषताओं को भी  
 पहचानें और एक-दूसरे से सीखने की बात मोचें। यद्यपि कुछ पढ़े-लिखे लोगों  
 और घनी जनों में जातीय द्वेषभाव काफी बड़ा हुआ है, तथापि जनसाधारण  
 में परस्पर प्रेम और देशभक्ति के भाव कितने दृढ़ हैं, इसका एक प्रमाण गोसा  
 का सत्याग्रह है। इस छोटे-से प्रदेश को मुक्त कराने के लिए बंगला, मराठी,  
 पंजाबी, हिन्दी आदि अनेक भाषाएँ बोलनेवाले नौजवानों ने अपने प्राणों की  
 बाजी लगा दी। किसी ने यह सोचकर भाषा-पीछा नहीं किया कि गोसा के  
 लोगों की भाषा तो कौकणी या मराठी है, हम उनके लिए क्यों जान दें। पन्द्रह  
 अगस्त के बाद देश में जो व्यापक प्रदर्शन हुए वे भी इसी जातीय सहयोग और  
 देश-प्रेम के सूचक हैं। जनसाधारण में यह भाईचारे का भाव देश की बहुत बड़ी  
 सांस्कृतिक निधि है। यही वह शक्ति है जो देश को जातीय द्वेष के मार्ग से  
 हटाकर प्रेम, समानता और सहयोग के मार्ग पर ले जायगी। इसके बिना न  
 तो समूचे देश का विकास सम्भव है, न किसी जाति-विशेष का। (१९५५)

## अनिवार्य राजभाषा का सवाल

भारत के संविधान में राजभाषा से सम्बन्धित धाराओं को स्वीकृत हुए चार वर्ष से ऊपर हो गए । जो कमीशन हिन्दी के व्यवहार के बारे में राष्ट्रपति के सामने अपने सुझाव रखेगा, वह भविष्य में बनेगा । किन्तु कुछ विद्वान् राजनीतिज्ञ उस भाषायी क्रान्ति की सम्भावना से घबरा उठे हैं जिसके जनक वे स्वयं थे । उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने पटना में भारतीय हिन्दी परिषद् के अधिवेशन में कहा था “अगर अंग्रेजी हटाने पर बहुत जोर दिया जायगा तो इसमें हिन्दी को लाभ नहीं हानि होगी, राष्ट्रीयता लुप्त हो जायगी, प्रादेशिक भावनाएँ प्रबल होगी, भारत के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे ।” ऐसा लगता है कि अंग्रेजी की स्थिति को जरा-सा भी धक्का लगने पर देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है । एक अन्य राज्यपाल, मद्रास में श्री श्रीप्रकाश ने संस्कृत को भारत की राजभाषा बनाने की बात कही है ।

स्पष्ट है कि संविधान की भाषा-सम्बन्धी धाराएँ स्वीकृत करने के बाद भी कांग्रेसी नेता भाषा समस्या का अन्तिम समाधान पेश नहीं कर चुके ।

सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में जनता की भाषाओं के व्यवहार के लिए सघर्ष स्वाधीनता और जनतन्त्र के लिए होनेवाले सघर्ष का ही एक अंग है । रवीन्द्रनाथ और भारती जैसे कवियों ने बंगला और तमिल के गौरव गीत गाये । जनता ने मँकाले की भाषा-नीति का विरोध किया, जिसका उद्देश्य विदेशी साम्राज्यवादियों की चाकरी करनेवाले बुद्धिजीवी तैयार करना था । ब्रिटिश शासकों ने कोशिश की कि जनता की भाषाएँ दबाई जाएँ, उन पर अंग्रेजी लादी जाय, और जनता की एकता नष्ट कर दी जाय । साम्राज्यवादियों का स्वप्न रिजले की पुस्तक ‘द पीपुल ऑफ इंडिया’ में इस तरह प्रकट हुआ है, “यह सम्भव है—यद्यपि सम्भावना दूर भविष्य की है—कि शायद अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्रभाषा बनेगी ।”

प्रारम्भिक दिनों में कांग्रेस के नेताओं की भाषा अंग्रेजी थी । किन्तु १९२० के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन की प्रगति के बाद भारतीय भाषाएँ

राजनीतिक मंच पर अग्रसर होने लगी। लेकिन भारतीय भाषाओं की यह प्रगति नेताओं को हमेशा अच्छी नहीं लगी। उनमें से कुछ चक्रवर्ती सम्राटों के गौरवमय इतिहास का स्वप्न देखते हैं जब पुरोहितों की सहायता से वर्ण-व्यवस्था वाले समाज में सत्सूत का बोलवाला था। कुछ अन्य नेता 'डूबते की तिनके का सहारा' की मसल चरितार्थ करते हुए अंग्रेजी का दामन थामे हुए हैं।

कांग्रेसी नेताओं ने जब हिन्दी को राजभाषा के लिए मान्य किया, तब तक सत्ता प्राप्त किये उन्हें चार वर्ष हो गए थे। लेकिन इस फैसले के साथ उन्होंने यह भी सुनिश्चित कर लिया कि सभी सरकारी कामों के लिए अगले पन्द्रह साल तक अंग्रेजी का व्यवहार होगा। इस प्रकार अंग्रेजी का चलन उन्होंने बीस साल के लिए पकड़ा कर लिया। संविधान को लागू हुए पाँच साल भी नहीं बीते कि हमें उपदेश सुनने की मिलने लगे हैं कि अंग्रेजी को हटाना खतरनाक है। पन्द्रह साल के बाद पार्लियामेंट यानून बनाकर अंग्रेजी का चलन बनाये रह सकती है। कांग्रेसी नेताओं की यह मशा नहीं थी कि अंग्रेजी हटाने के लिए जमकर कोशिश करें। उन्होंने स्पष्ट ही अपने सामने यह सम्भावना रखी थी कि पन्द्रह साल के बाद भी अंग्रेजी जारी रहेगी, शायद उसके अगले पन्द्रह साल तक भी जारी रहेगी, हो सकता है कि इसके आगे भी जारी रहे। संविधान-सभा में बहस की तमाम सरगमियों के पीछे यह निर्मम निश्चय साफ दिखाई देता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की हानि करते हुए अंग्रेजी को अनिवार्य राजभाषा के रूप में चालू रखा जाय। श्री नेहरू ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि "आप इस बात को प्रस्ताव में चाहे लीखें, चाहे न लीखें, अंग्रेजी नाज़मी तौर से भारत में बहुत महत्वपूर्ण भाषा बनकर रहेगी जिसे बहुत लोग सीखेंगे और शायद उन्हें उसे जबरन सीखना होगा।" लोग इन तमाम बर्षों में अंग्रेजी जबरन सीखते आये हैं। अब उनके सामने एकमात्र यह सम्भावना पेश की गई है कि अंग्रेजी के बिना हमारी कला और विज्ञान का पतन हो जायगा और देश का विघटन होगा, उसका नाश हो जायगा।

अंग्रेजी की विशेषाधिकार वाली स्थिति इस बात से और दृढ़ हो गई है कि उसका व्यवहार सुप्रीम कोर्ट और प्रत्येक हाईकोर्ट की कार्यवाही में, पार्लियामेंट या विधानसभाओं में पेश होनेवाले हर बिल के लिए होगा और बिल का अंग्रेजी रूप ही अधिकारी रूप माना जायगा। यदि राज्यपाल या राज्यप्रमुख की आज्ञा से किसी बिल, ऐक्ट या आर्डिनैंस के लिए हिन्दी का व्यवहार किया जायगा तो अंग्रेजी रूप ही अधिकारी रूप माना जायगा। भारतीय जनता के लिए इससे अधिक अपमानजनक दूसरी बात हो नहीं सकती। अंग्रेजी के मुक्ताबले में तमाम भारतीय भाषाओं को नीचा दर्जा संविधान ने ही दे रखा है।

संविधान में यह लिख दिया गया है कि पन्द्रह वर्ष तक भारत की भाषा-नीति में कोई भी परिवर्तन न होगा। संविधान ने राज्यों को इसके लिए भी बाध्य किया है कि वे एक-दूसरे से केवल हिन्दी या अंग्रेजी में ही पत्र-व्यवहार

करें। अपनी सरकारी कायवाही में विशेष कानून बनाये बिना कोई राज्य अंग्रेजी की जगह अपनी भाषा का व्यवहार नहीं कर सकता। नतीजा यह है कि लगभग सभी राज्यों में सारा सरकारी काम अंग्रेजी में होता है। इस प्रकार यह विदेशी भाषा न केवल अखिल भारतीय स्तर पर अनिवार्य राजभाषा बनी हुई है वरन् विभिन्न राज्यों में भी अनिवार्य राजभाषा बनी हुई है।

भारत के कुछ ब्रिटिशोधी अनिवार्य राजभाषा के रूप में हिन्दी का ता विरोध करते हैं लेकिन अंग्रेजी जो सब पर हावी है और जिसे खास अधिकार मिले हुए है उससे बारे में चुप रहते हैं। ये लोग समझते हैं कि ग्राम जनता पिछड़ी हुई है, इसलिए अंग्रेजी पढ़े लोगो का काम है उस पर शासन करना और जनता का काम है शासित होना। कहा जाता है कि अंग्रेजी के बिना देश की आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति बन्द हो जायगी। लेकिन ग्राम जनता के सहयोग के बिना किसी तरह की प्रगति नहीं हो सकती, न आर्थिक न सांस्कृतिक।

भाषा के आधार पर राज्या के पुनर्गठन का विरोध करने से अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रखने में मदद मिलती है। एक ही राज्य में अनेक जातियों के रहने से उनमें से कोई भी अपना राजकाज अपनी भाषा में नहीं कर सकती। जातीयता के आधार पर जब तक लोग अपने राज्यों में पुनर्गठित न हागे, तब तक अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त न होगा।

ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के मुखपत्र तन्दा के इक्वॉनोमिस्ट ने लिखा था "भारत की संविधान सभा ने गरम बहस के बाद तय किया है कि हिन्दी के राजभाषा बनने से पहले अभी पन्द्रह साल तक अंग्रेजी राजभाषा और बनी रहेगी। इससे पता चलता है कि भारत के राजनीतिज्ञ यथार्थ का सामना करने को तैयार हैं और समझौता स्वीकार करते हैं। उनके इस रवैये की बहुत सी मिसालें आजादी के बाद मिल चुकी हैं।"

इस साम्राज्यवादी पत्र और राज्यपाल श्री मुशी के यथार्थ दर्शन में काफी समानता मालूम होती है।

जहाँ तक अंग्रेजी के प्रभुत्व का सवाल है, हम वही हैं, जहाँ सन् '४७ में थे। यह प्रभुत्व और दृढ़ ही हुआ है। इसी यथार्थ यही है जिसका दर्शन ग्राम जनता आये दिन करती है, इस यथार्थ को बदलना है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, सुब्रह्मण्य भारती, वीरेर्शलिंगम वल्लत्तोल आदि महान् साहित्यकारों ने जो सघर्ष प्रारम्भ किया था, उसे तब तक जारी रखना चाहिए जब तक अंग्रेजी को हटाकर भारतीय भाषाओं को उनके उचित अधिकार न दिला दिये जाएँ। यह सघर्ष हमारे राष्ट्रीय चरित्र, राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान की सुरक्षा के लिए सघर्ष है, यह समानता और परस्पर सहयोग के आधार पर भारतीय जनता की एकता को दृढ़ करने के लिए सघर्ष है।

भारत में पूँजीवादी राष्ट्रवाद की लपटें उठ रही हैं। उत्तर दक्षिण के

लोग भीम और दुर्पोषण के समान एक-दूसरे पर प्रहार करने को उद्यत दिखाई देते हैं। सविधान-सभा की बहस में श्री एल० के० मैत्र, श्री गाढगिल, श्री रामलिंगम् चेट्टियार, श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी, श्री शंकरराव देव आदि ने हिन्दी के प्रभुत्व से भय की बात की। श्री श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कहा था, “भारतीय सविधान में एक धारा बना देने से आप सब लोगो को बाध्य नहीं कर सकते कि वे एक ही भाषा को स्वीकार कर लें।” उन्होंने यह भी कहा था, “दुर्भाग्य से लोगों में यह भय है और कई जगह उस भय का भ्रमली रूप भी दिखाई देता है। इन जगहों में लोगों को अपनी भाषाओं के व्यवहार की उतनी सुविधा भी नहीं दी गई जितनी घुणित विदेशी राज्य में भी उन्हें प्राप्त थी।”

सविधान में हिन्दी को राजभाषा का पद दिया गया है, किन्तु इस राजभाषा का कार्यक्षेत्र क्या है? अंग्रेजी ने राजभाषा बनकर प्रादेशिक भाषाओं के बहुत-से अधिकार छीन लिये थे। विभिन्न राज्यों को स्वायत्त शासन के काफी अधिकार दिये बिना अंग्रेजी की जगह हिन्दी को देने का मतलब है, दूसरी भाषाओं के अधिकार नियन्त्रित करना। सविधान में हिन्दी के विकास की बात कही गई है, अन्य भाषाओं का उल्लेख नहीं है। इस तरह की मनोवृत्ति से भारत की विभिन्न जातियों में मैत्री और भाईचारा न बढेगा।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम में कहा गया है, “देश की एकता के नाम पर एक प्रदेश की भाषा हिन्दी को सभी जातियों और राज्यों के लिए उनकी भाषाओं का अहित करते हुए, अनिवार्य राजभाषा बना दिया गया है, इसलिए अहिन्दी जातियाँ अनिवार्य राजभाषा के रूप में हिन्दी का विरोध करती हैं और माँग करती हैं कि उनकी भाषाओं को सभी सरकारी कामों में इस्तेमाल किये जाने की सुविधा दी जाय।”

भाषावार राज्य-निर्माण का आन्दोलन जोर पकड़ रहा है। यह स्पष्ट है कि जातीयता के आधार पर जो नये राज्य गठित होंगे, उनमें राजकाज की भाषाएँ प्रादेशिक भाषाएँ होगी। जो लोग दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार करते रहे हैं, वे इस बात को समझते हैं। उन्होंने कहा है कि अपने-अपने प्रान्ता में प्रादेशिक भाषाएँ ज्ञान विज्ञान और राजकाज की भाषाएँ बन जाएँगी, सभी हिन्दी सचमुच राष्ट्रभाषा बनेगी।

माक्सवाद दूसरों की इच्छा के विरुद्ध किसी भाषा को अनिवार्य राजभाषा बनाने का विरोध हमेशा करता रहा है। लेकिन वह एक या अधिक भाषाओं के माध्यम द्वारा विभिन्न जातियों के परस्पर सम्पर्क कायम करने का समर्थक भी रहा है। लेनिन ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया था कि स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट में इटालियन भाषी प्रतिनिधि फ्रैंच बोलते हैं और कहा था, “ऐसा वे किसी बर्बर पुलिस कानून के कारण डडे के भय से नहीं करते (स्विट्जरलैंड में ऐसा कोई कानून नहीं है) वरन् केवल इसलिए कि किसी भी जनतन्त्र के सम्य नागरिक उस भाषा का व्यवहार करना उचित समझते हैं जिसे बहु-



सह्यक जनता समझती हो।”

सोवियत सघ के राष्ट्रपति कालीनिन ने गैर-रूसी जातियों में राजनीतिक प्रचारको से कहा था, “यह बहुत जरूरी है कि गैर-रूसी जातियों के सैनिक रूसी भाषा सीखें। रूसी भाषा सीखे बिना फौज में काम नहीं चल सकता। हमारे फौजी वायदे-वानून रूसी में होते हैं। इसी भाषा में फौजी हुक्मनामे जारी किये जाते हैं और रूसी में ही सिपाहियों की बर्मान होनी है। सोवियत सघ में रूसी सभी जनो की सम्पर्क-भाषा है।”

लेनिन ने जातीय समस्या पर लिखते हुए कहा था, “आर्थिक सम्पर्क की आवश्यकताएँ स्वयं बता देंगी कि किसी देश में बहु-मह्यक लोगों को किस भाषा के सीखने से व्यापार आदि में सुविधा होगी।” अंग्रेजों के आने से पहले भारत में व्यापार का अभाव न था। अनुभव से साबित हो गया है कि कौन-सी भाषा सीखने से बहु-मह्यक जनता को लाभ होता है। यह हिन्दुस्तानी जाति की भाषा है। सोलहवीं-ग्यारहवीं सदियों में ही व्यापार की उन्नति होने पर यह भाषा देश के विभिन्न और सुदूर प्रदेशों तक पहुँच रही थी। न केवल भारत के व्यापारी यह भाषा सीखते थे वरन् विदेशी सौदागर भी, अंग्रेजों की श्रेष्ठता पर ध्यान न देकर, यही भाषा सीखते थे। यही कारण है कि इटली के यात्री मनुस्ची ने शिवाजी से हिन्दुस्तानी में बातचीत की थी। महाराष्ट्र और तमिल में हिन्दी में कविना रचनेवालों का अस्तित्व इस भाषा की लोकप्रियता का प्रमाण है। इसलिए यह समझना गलत है कि अंग्रेजों के बिना न राष्ट्रीय आन्दोलन होता, न राष्ट्रीय एकता होती। अंग्रेजों ने देश के एकीकरण में बाधा डाली, इस एकीकरण में हिन्दुस्तानी जाति की भाषा महत्वपूर्ण भूमिका पूरी कर रही थी। वैष्णव कवियों ने सांस्कृतिक स्तर पर जनता की एकता को दृढ़ किया। उन्नीसवीं सदी के समाज सुधारकों और धर्म-प्रचारकों ने अपने कार्य के लिए इस भाषा को अपनाया। यह स्वाभाविक था, क्योंकि सच्चा की दृष्टि से सम्भवतः चीनी जाति को छोड़कर हिन्दुस्तानी जाति मसार की सबसे बड़ी जाति है। इस कारण भारत की विभिन्न जातियों में आर्थिक और सांस्कृतिक सम्पर्क के लिए उसका व्यापक व्यवहार हुआ।

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी अनिवार्य राजभाषा का विरोध करती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि वह राष्ट्रीय एकता का मूल्य नहीं समझती, या उस एकता को दृढ़ नहीं करना चाहती। कम्युनिस्ट पार्टी पूरी तरह अनुभव करती है कि राष्ट्रीय स्वाधीनता की सुरक्षा और देश की आर्थिक प्रगति के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न राज्यों और प्रदेशों की जनता की एकता और परस्पर भाईचारा दृढ़ किया जाय। स्वभावतः प्रश्न उठता है कि जिन लोगों की मातृ-भाषाएँ अलग-अलग हैं, वे किस भाषा में परस्पर बातचीत करें। भारत की ठोस परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कहा जाएगा कि यह भाषा हिन्दी ही हो सकती है। यह प्रश्न अभी भी चालू है। इसलिए अपनी मदुरा कांग्रेस में

कम्युनिस्ट पार्टी ने यह स्पष्ट कहा है कि अनिवार्य राजभाषा को लागू करने का विरोध करते हुए भी पार्टी चाहती है कि हिन्दी विभिन्न राज्यों की जनता तथा उनकी सरकारों के बीच परस्पर सम्पर्क का साधन अधिकाधिक बने । (१९५४-५५)

## अंग्रेजी के हिमायती

अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है और उसे इस पद पर बनाए रखने में भारत के राष्ट्रीय लेखकों ने काफी योग दिया है। उपन्यास, कविता, राजनीति, विज्ञान—किस पर वे नहीं लिखते ? किस पर वे नहीं बोलते ? अभी तक साहित्य और संस्कृति का अन्तर्राष्ट्रीय इतिहास नहीं लिखा गया, लिखे गये हैं विश्व, महाद्वीपों, राष्ट्रों या जातियों के इतिहास। यदि कभी अंग्रेजों ने अपनी भाषा का महत्व पहचाना और उसका अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक इतिहास लिखा तो उन्हें इन भारत के अंग्रेज अदीबों को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा।

पिछले दिनों एक अंग्रेजी पत्र के 'कॉलमनिस्ट'—'अदीब'—ने भारतीय भाषाओं के बारे में रोचक विचार प्रकट किए हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी की सी व्यंजक शक्ति किसी भारतीय भाषा में नहीं है; इसलिए भावुकता छोड़कर अंग्रेजी की शरण जाना ही उचित है। यह बात कितनी सही है, इसे 'अदीब' के साथ इन पत्रियों का लेखक भी अनुभव कर रहा है। 'कॉलमनिस्ट' का पर्यायवाची हिन्दी में मिलता नहीं है, उधर अंग्रेजी शब्द को ज्यो-वा-त्यो लिखने में खतरा यह है कि अगले हिन्दीभाषी उसे अपभ्रंश बनाकर 'कलमनष्ट' न कर दें। हिन्दी के पाठक ऐसे जाहिल हैं कि उनमें से कुछ 'अदीब' का अर्थ अदब लगा लें, तो भी आश्चर्य नहीं। लेकिन इतना तो उन्हें मालूम ही होना चाहिए कि अदीब अंग्रेजी का शब्द नहीं है, हिन्दुस्तान का न सही, एशिया का तो है। अंग्रेजी के लेखक होते हुए भी 'अदीब' ने अपने लिए एशियाई उपनाम चुना, इस पर दो महीने बाद दिल्ली में होनेवाले एशियाई लेखक-सम्मेलन को उन्हें बधाई देनी चाहिए।

हिन्दी की व्यञ्जना-शक्ति कितनी सीमित है, इसके उदाहरणस्वरूप 'अदीब' ने इलियट की दो पक्तियों का अनुवाद दिया है—

हम खोखले हैं।

हमारे अन्दर भूसा भरा हुमा है।

महाकवि इलियट को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब हिन्दी के पाठक

उनकी रचनाओं में ऐसे महान् विचार प्रकट होते देखकर आधुनिक अंग्रेजी कविता के बारे में क्या सोचेंगे, जो सोचेंगे, उससे भारत-ब्रिटेन-मैत्री कैसे दृढ़ होगी और भारत में अंग्रेजी साहित्य-रचना का भविष्य क्या होगा, इस तरह की समस्याएँ सभी चिन्तकों को चिन्तित कर सकती हैं। इलियट की महान् कल्पना—हम खोखले हैं, हमारे अन्दर भूसा भरा हुआ है।—‘अदीब’ के अनुसार हिन्दी के अनुवाद में सत्य बात कहते हुए भी हास्यास्पद हो जाती है। वास्तव में सत्य कभी-कभी हास्यास्पद हो ही जाता है, यद्यपि हिन्दी में हास्य रस को उतना ही उच्च स्थान दिया गया है जितना अन्य रसों को। सहृदयों की तो साधारणीकरण द्वारा यहाँ भी रस निष्पत्ति में आपत्ति न होगी।

इलियट—जैसे कवियों का उल्लेख करते हुए ‘अदीब’ ने पूछा है कि इनसे हिन्दी, बँगला या तमिल कैसे बुलवाएँ ? बहुत ही अदब से कहना चाहता हूँ कि बँगला या तमिल में बुलावाने की जरूरत क्या है। राष्ट्रभाषा हिन्दी ही उन सब की बोलियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए काफी है। फिर आपने हमारे प्रयोगवादियों की बोली नहीं सुनी ? इतने दिन इलियट के भूँस में हिस्सा बँटाकर जो बत्स आनन्दमय स्वर में रँभाते रहे हैं, उनकी रागिनी पर आपने कान नहीं दिया ? माना कि ‘हम खोखले हैं’ और अंग्रेजी की मूल पक्तियों का अनुवाद करना कठिन है, लेकिन उसी काव्य-परम्परा की इस एक पक्ति का भाप ही अंग्रेजी में अनुवाद कर डालिए—“मैं ही मरघट का वह रिरियाता कुत्ता।”

‘अदीब’ ने क्या ही सुन्दर विचार प्रकट किया है—

A language is not a donkey ! भाषा गधा नहीं है। गधे तो भाषा के बोलने और लिखनेवालों में होते हैं। भाषा को ठोकर मारो, चाहे पुचकारो, कोई लाभ न होगा। लेकिन वह क्रिया भाषा के बोलने या लिखनेवालों के साथ करो, अवश्य फल देगी। मेरी समझ में भारत में अंग्रेजी के लेखकों के प्रति हमारी राष्ट्रीय नीति पुचकारने की है और भारतीय भाषाओं के लेखकों को ठोकर मारने की। मैं इस नीति की सफलता चाहता हूँ।

और इस नीति में बुरा क्या है ? भारत के लोगो ने अपनी भाषाएँ छोड़कर अभी तक अंग्रेजी नहीं अपना ली—जैसे कि जारसाही रूस के अभिजात वर्ग ने फ्रांसीसी भाषा अपना ली थी—इस सक्तीयता को क्या कभी धमा किया जा सकता है ? रूसी लेखक गोगल ने एक नगर की सम्प्रान्त महिलाओं के बारे में लिखा था—“रूसी भाषा का संस्कार करने और उसे ऊँचा उठाने के लिए उन्होंने अपने शब्द भण्डार के आधे शब्द बहिष्कृत करके उनकी जगह फ्रांसीसी शब्द रख लिये थे।”

भाप स्वीकार करेंगे कि दिल्ली और बम्बई—जैसे नगरों के सज्जन—अर्थात् वास्तव में शिक्षित सज्जन—उन रूसी महिलाओं से बाजी मार ले गए हैं।

सम्प्रान्त रूसी समाज के पाठकों के लिए गोगल ने लिखा था—“इनके”

मुँह से कभी कोई सभ्य रूसी शब्द सुनने को नहीं मिलता । फ्रांसीसी, जर्मन और अंग्रेजी शब्दावली का प्रवाह उनके मुँह से फूट पड़ता है । उनका उच्चारण भी तरह-तरह का होता है । वे फ्रांसीसी बोलते हैं तो नाक से, और थोड़ा तुतलाते हुए । अंग्रेजी बोलते हैं तो चिड़ियों की तरह, दुरुस्त बहचहाते हुए । और जब बोलते हैं तब चिड़ियों-जैसे दिखाई भी देते हैं । वे उन पर हँसते हैं, जो चिड़ियों-जैसा मुँह नहीं बना पाते । वे रूसी में कुछ नहीं लिखते । उनकी देशभक्ति इसमें प्रकट होती है कि वे ग्रीष्म-निवास के लिए रूसी शैली में भोपड़ी बनवा लें ।”

लेकिन अब शिमला, मसूरी, नैनीताल आदि में अंग्रेजी शैली के ‘कॉटेज’ होने के कारण भारत के अन्तर्राष्ट्रीयतावादियों के लिए हिन्दुस्तानी ढंग की भोपड़ी बनाना भी आवश्यक नहीं । यहाँ भी वे रूसियों से आगे हैं ।

गोगल की शिष्यायत है कि उस समय के सम्भ्रान्त विद्वान् रूसी भाषा के लिए स्वयं तो कुछ न करते थे, लेकिन यह माँग अवश्य करते थे कि रूसी भाषा परिष्कृत और समृद्ध हो जाय, वह अपने परिष्कृत और समृद्ध रूप में आसमान से उतरे और उनका काम इतना ही हो कि जीम निवालकर उसे गप कर लें ।

लेकिन ‘अदीब’ की यह माँग नहीं है कि हिन्दी या अन्य भारतीय भाषाओं को समृद्ध किया जाय । उनकी माँग यह है कि भारतीय भाषाओं के बदले अंग्रेजी में ही सारा काम होता रहे । यहाँ भी भारत के सम्भ्रान्त विद्वानों ने जारघाही रूस के सम्भ्रान्त विद्वानों की पीछे छोड़ दिया है ।

‘अदीब’ ने चेतावनी दी है कि अंग्रेजी का सहारा न लिया तो पुल टूटने लगेंगे और दूसरी-तीसरी-चौथी पंचवर्षीय योजनाएँ असफल हो जाएँगी । यह चेतावनी एकदम सामयिक है । अभी हिन्दी को केन्द्रीय राजकाज की भाषा बनाने की बात ही चली है कि हैदराबाद राज्य में दो बार पुल टूट चुके हैं और जनता की भारी क्षति हुई है । जब चर्चा का ही यह फल है, तब व्यवहार में आने पर हिन्दी से कौन-सी क्षति न होगी, आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं ! इसी तरह योजनाओं के सम्बन्ध में भी । घूस और रिश्वत का बाजार गर्म है । योजना पूरी हो नहीं पाती कि घूस-गबन की जाँच के लिए समिति बैठाना आवश्यक हो जाता है । जब तक हिन्दी का पूर्ण बहिष्कार नहीं हो जाता, तब तक हर योजना की व्यवहार में लाने के माय साथ घूस और रिश्वत की जाँच के लिए पहले से ही एक समिति बना देनी चाहिए । इससे सिद्ध हो जाएगा कि योजनाओं द्वारा पैसा खानेवालों का हिन्दी से कितना गहरा सम्बन्ध है ।

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का सम्मान बढ़ रहा है । राष्ट्रीय जीवन में भी अंग्रेजी का बैसा ही प्रभुत्व रहे तो अधिका, बेकारी, बाढ़, मुसमरी आदि की समस्याएँ तुरन्त हल हो जाएँ और ५० नेहरू की गृहनीति में भी चार चाँद लग जाएँ । अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में ‘पंचशील’ का शब्द जरूर चल पड़ा है । यह ‘पंचशील’ या और किसी तरह का नील उन अंग्रेजो-अमरीकियों को पसन्द नहीं

है, जिनकी अपनी भाषा अपनेकी है। हम सबका स्वाम्य देना चाहिए। हमने  
 गिना था कि हमने क्या दिया होगा कि हम के प्रभावकी भाषा में तो अपने मातृ  
 हिन्दी कोनेवाला हुआ कि भाषा में। स्पष्ट है कि मातृभाषा देना के साथ-  
 नीतिगत अपनेकी के अपने हिन्दी की प्रथम देना है। हमने जो लोग राष्ट्रीय  
 और अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत द्वारा अपनेकी के अपने हिन्दी के व्यवहार पर  
 जोर देने हैं, वे जान में या अनजान में हमी बहुत-से गहराये कर रहे हैं।

'मद्रीड' की भाषा जिन मातृभाषा है कि उन्हें हिन्दी में व्यवहारकी भाषा  
 की गन्ध मिल गई। जिनकी भाषा जिनकी हीन हो गई है वह हिन्दी की प्राथमिक  
 भाषा गन्धने लगे हैं। यद्यपि विशाल-मातृभाषी युद्धों हिन्दी में काफी विजयी  
 हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने हमसे भीतर युद्धों तो नहीं की लगी। हमने  
 हिन्दी और हमी की तरह अन्य भारतीय भाषाओं में भी व्यवहारकी भाषा में,  
 तो आश्चर्य क्या? अब अपनेकी की देना। हमने द्वारा अपने कम जाना जा  
 है जिनमें विशाल-मातृभाषी काम है और हम भी लगे लगे कामका की गन्ध  
 हम हो जायेंगे। हमारा विचार है कि प्राचीन भारत में गन्ध न जो प्रगति  
 की थी, वह भी अपनेकी के कारण। भाषा भट्ट में व्यवहार गन्धकी भाषा पड़ी  
 होगी। हमारा ज्ञान का श्रेष्ठ भारत की दिया जाता है, लेकिन हम श्रेष्ठ में  
 नेमकी भाषा भी हम है, यह बहुतों की नहीं मान्य। पाणिनि न अपना  
 व्यवहार किया और प्राथमिक भाषा-विज्ञान के विकास में उस व्यवहार की  
 महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की जाती है। दुर्भाग्य से पाणिनि पर नेमकी भाषा के  
 प्रभाव की सोच किसी भी डॉक्टर के उम्मीदवार ने अभी तक नहीं की।  
 जर्मनी, दक्षिण, प्राग, हम आदि देशों में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई है, हमारा कारण  
 यह है कि वहाँ की भाषा अपनेकी में अपना हुई है। न अपना हुई होगी, तो वहाँ  
 का साथ वैज्ञानिक कार्य अपनेकी के माध्यम में होता होगा। न होता होगा, तो  
 वह विद्युत् वैज्ञानिक कार्य भी न होगा। जिन तरह भी विचार करें, भाषा पर  
 स्वीकार किए बिना न रहेंगे कि संसार में वैज्ञानिक प्रगति अपनेकी द्वारा ही हुई  
 है। मुना है कि मनुष्य नष्ट में जो प्राणी रहते हैं, वे भी अपनेकी बोलते हैं।  
 हमारी ही शरीर-विचारकों ने रेडियो पर उनके बोलचाल की है। हम प्रकार  
 अपनेकी का महत्व विश्वव्यापी ही नहीं, सृष्टिव्यापी है।

अतः ! 'मद्रीड' के हम निष्कर्ष से सहमत होना ही होगा कि किसी राष्ट्र  
 के जीवन में इस, तो या हठार वरु भी क्या है, मोचने-विचारने और भाषा-  
 पीछा देने के लिए समय की कमी नहीं है। तब तक आइए, हम हम गन्ध का  
 जग करें—

हम बोलते हैं !

हममें भूया भग हुआ है !

## सोवियत क्रान्ति और भाषा-समस्या

आज से चालीस साल पहले ससार की महान् समाजवादी क्रान्ति की विजय ने पिछड़े हुए बहुजातीय देशों के सामने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का एक नया आदर्श रखा। यह विकास पिछड़ी हुई जातियों की भाषाओं के माध्यम से ही सम्भव था। इसलिए सामाजिक विवास की समस्याओं के साथ समाजवादी क्रान्ति ने भाषा-समस्या हल करने का भी एक नया मार्ग हमें दिखलाया।

अभी सो साल न बीते थे जब रूस का अभिजात वर्ग रूसी को पिछड़ी हुई भाषा मानता था; वह अपने सांस्कृतिक जीवन में अधिकतर फ्रांसीसी भाषा का व्यवहार करता था। हमारे देश में भी अनेक विद्वान् हिन्दी ही नहीं, भारत की सभी भाषाओं को पिछड़ी हुई मानते हैं। इसलिए केन्द्रीय राजकाज के लिए वे बहुत दिनों तक अंग्रेजी का व्यवहार उचित समझते थे। रूस के नेताओं ने अपने राजनीतिक पत्र फ्रांसीसी के बदले रूसी में ही प्रकाशित किये थे; रूसी उनके राजनीतिक जीवन की भाषा थी। गैर-रूसी इलाकों के नेता वहाँ की भाषाओं का व्यवहार करते थे। इसलिए रूसी को पिछड़ी हुई भाषा मानकर सत्रमण काल के लिए अनेक वर्षों तक फ्रांसीसी भाषा के व्यवहार का प्रस्ताव उन्होंने नहीं रखा। रूसी जनता के लिए उन्होंने तुरन्त रूसी भाषा को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया। आज तो लोग मानते हैं कि रूसी ससार की समृद्ध भाषाओं में है लेकिन यह स्थिति १९१७ में न थी। तोल्स्तोय, चेखव, गोर्की आदि कुछ उपन्यासकार अवश्य हो गए थे, जैसे भारत में रवीन्द्रनाथ, भारती, प्रेमचन्द, शरत्चन्द्र, इकबाल आदि कवि और कथाकार हो गए हैं। लेकिन फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की तुलना में वैज्ञानिक शिक्षा की पुस्तकें उसमें कहीं थी ? यह तर्क दिया जा सकता था कि किसी भी विषय की समुचित शिक्षा के लिए रूसी भाषा पर्याप्त नहीं है, इसलिए जब तक वह समृद्ध न हो जाय तब तक केन्द्रीय राजकाज फ्रांसीसी में होना चाहिए। लेनिन के नेतृत्व में स्वाभिमानि रूसी जनता ने अपनी पिछड़ी कहलानेवाली, अभिजात वर्ग द्वारा उपेक्षित

भाषा में ही अपना सारा राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्य प्रारम्भ किया। भारत में जहाँ भाषा और शिक्षा की हजारों वर्ष पुरानी परम्परा है (सिन्धु घाटी के जन भी लिखना-पढ़ना जानते थे) वहाँ आज यह दयनीय स्थिति है कि देश की सभी भाषाओं को पिछड़ा हुआ मानकर अनेक वर्षों के लिए अंग्रेजी के व्यवहार का समर्थन किया जाता है।

खैर, रूसी में तो रवीन्द्रनाथ, प्रेमचन्द की तरह तोल्स्तोय और गोर्की जैसे विश्वविख्यात लेखक थे। वैज्ञानिक शब्दावली में फ्रेंच के मुकाबले में रूसी भले ही पिछड़ी रही हो, कथा-साहित्य में हिन्दी और बंगला की तरह रूसी समृद्ध थी। किन्तु बेलोरूसी, उक्रेनी, जाज़ियाई आदि भाषाओं में तो इतने बड़े नाम न थे। सोवियत राज्यसत्ता ने उन्हें भी अपने-अपने क्षेत्र में राजकाज की भाषा बनाया। इनसे भी गर्द-गुजरी अजरबैजानी, ताजिक, कज़ाक आदि भाषाएँ थी जिनमें मौखिक साहित्य ही अधिक प्रचुर था। ये भी राजकाज की भाषा बनी। इनसे भी 'पिछड़ी हुई' चुकचो, बुर्यात, मंगोल, चेरकास, समोयेद आदि भाषाएँ थीं जिनकी स्थिति भारत के अनेक आदिवासी जनो की भाषाओं से भी गर्द-बीती थी। इनको भी विकसित होने का मौका मिला। आज उनमें व्याकरण, कोश, विज्ञान, कथा-साहित्य, काव्य—सभी-कुछ है। हमारे देश में भाषा-समस्या के विवेचन में आदिवासियों की भाषाओं की चर्चा करने का अभी चलन नहीं है।

सोवियत संघ में वही भी यह दलील नहीं दी गई कि भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं, इसलिए चालीस साल तक, उनके व्याकरण और शब्दकोश तैयार होने तक, उनकी जगह रूसी भाषा का व्यवहार होगा। भाषा जनता के लिए है, जनता भाषा के लिए नहीं है। हमारे देश में जनता की आवश्यकताओं को देखकर भाषा-समस्या हल नहीं की जाती, अंग्रेजी से हमारे जो काम हो जाते हैं, वे भारतीय भाषाओं से होंगे या नहीं, यह समस्या पहले आती है। पारिभाषिक शब्दावली इस तरह गढ़ी जाती है मानो वह जनता के काम आने के लिए नहीं, उसकी जीभ और तालू का व्यायाम कराने के लिए है! पूँजीवादी और समाजवादी दृष्टिकोणों में यही अन्तर है। यदि भारत में साधारण जनता सामन के कामों में भाग ले, यदि उसके अपने जन-संगठन राज्यसत्ता का वास्तविक आधार हो, अर्थात् यदि इस जनवादी देश में जनता का राज सचमुच हो तो क्या यह कल्पना की जा सकती है कि एक दिन भी यहाँ अंग्रेजी से काम चलेगा?

नवम्बर क्रान्ति ने मानवता के उद्धार और विकास का नया मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चलकर नवनिर्माण का आदर्श हमारे सामने रखा। इस निर्माण में एक वर्ग दूसरे का शोषण और उत्पीड़न नहीं करता; उसमें एक जाति 'फ्री वर्ल्ड' के लुटेरों की तरह दूसरी जाति को दबाकर उसकी भाषा और सभ्यता को पैरो तले नहीं रौंदती। मानव-समाज जाति और वर्गों के रूप में ही संगठित हुआ है। वर्ग मिल जले पर भी जाति बनी रहती है, ~~इस~~



समृद्ध थी। इंग्लैंड में ऐंम साहित्यकार भी वे जो फ्रांसीसी में रचना करके प्रसार देना चाहते थे। किन्तु इतिहास ने लैटिन और फ्रांसीसी में लिखे हुए इनके न्यों को कूड़े के ढेर में फेंक दिया जहाँ वे अब केवल अनुसन्धानकर्ताओं के काम आते हैं।

अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान पर शासन किया, अंग्रेजों के देश पर भी रोमनों और ग्रीकों ने शासन किया था। किसी समय इंग्लैंड के अभिजात वर्ग पर फ्रांसीसी भाषा का वैसा ही रोब मालूम था जैसा आज के समनर-गोत्रीय भारतवासियों पर अंग्रेजी का है। किन्तु लैटिन या फ्रांसीसी को अधिक समृद्ध मानकर अंग्रेज जनता ने उस राष्ट्रभाषा न मान लिया। उसके साहित्यकारों अपनी भाषा का समृद्ध किया और उसे यूरोप की नवीन और प्राचीन भाषाओं की पाँति में सम्मानप्रद भासन दिलाया। अंग्रेजी समृद्ध होने के बाद राजभाषा नहीं बनी, राजभाषा होने के बाद वह समृद्ध हुई। वह लैटिन और फ्रांसीसी भाषाओं की तुलना में समृद्ध हुई जिनके हिमायती उसके उचित भासन से उसे टूटाना चाहते थे।

अंग्रेज शासकों ने यहाँ की जनता के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास को रोक दिया। उन्होंने यहाँ की भाषा के ऊपर साम्राज्य की तरह अंग्रेजी को प्रतिष्ठित किया। अंग्रेजी भाषा को अंग्रेज-प्रेमी भारतवासियों के पूर्वजों ने विधान-सभा में प्रस्ताव पारित करके स्वीकार न किया था। वह अंग्रेज भारतवासियों द्वारा लादी हुई भाषा थी। ससार में अंग्रेजी का बोलबाला मिल्टन और शेक्सपियर के कारण नहीं हुआ, उसका प्रसार करनेवाले क्लाइव और डलहौजी की विरादरी के थे। उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में अंग्रेजी का प्रसार करनेवाले वे आक्रमणकारी थे जिन्होंने वहाँ के आदिवासियों के नरमेघ रचाये थे, जिनका मिल्टन और शेक्सपियर से इतना ही सम्बन्ध था कि दोनों ही अंग्रेजी बोलते थे (कैसी अंग्रेजी बोलते थे, यह प्रश्न छोड़ दीजिए)। यदि समृद्धि के बल पर कोई भाषा अंग्रेजी की तरह 'विश्वभाषा' बनती तो पाणिनि और कालिदास की भाषा मृत भाषा न कहलाती, दान्ते, गेटे, तोल्स्टोय की भाषाएँ भी विश्वभाषा बन जातीं। अंग्रेजी के समर्थक उसके प्रसार के लिए मिल्टन और शेक्सपियर का नाम लेते हैं, उस ब्रिटिश साम्राज्य की कहानी भूल जाते हैं जिसमें कभी सूर्यास्त न होता था और अर्नेस्ट जोन्स के शब्दों में जिसकी घरती पर कभी रक्त न सूखता था।

अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी अपनी प्रिय विश्वभाषा के पक्ष में जितनी दलील देते हैं उनमें एक भी ऐसी नहीं है जो पहले 'लिबरल' राजनीति-विचारकों ने न दी हो। ये 'लिबरल' भद्दे अंग्रेजी राज और अंग्रेजी भाषा के मामले में अत्यन्त उदार थे, हिन्दुस्तानी जनता के राज और हिन्दी भाषा के बारे में अत्यन्त अनुदार थे। वे अंग्रेजी राज को प्रगतिशील मानते थे, अंग्रेजों को भारतीय अराजकता दूर करके यहाँ न्याय और शान्ति की व्यवस्था कायम करनेवाला

मानते थे। कभी हतनी ही थी कि अंग्रेज उच्च पदों पर इन्हें नियुक्त न करते थे। भारतीय जनता के आन्तिकारी आन्दोलन से जस्त ये उदारपन्थी महानुभाव नौकरियों में रियायतें पाने के लिए परम प्रगतिशील अंग्रेज शासकों के सामने प्रार्थना-मन्त्र पेश करने में महान् गौरव अनुभव करते थे। उन्हीं की परम्परा निवाहनेवाले ये वर्तमान 'निबरल' हैं जिनके लिए अंग्रेजी के राजभाषा न रहने से राष्ट्र छिन्न-भिन्न हो जाएगा, देश में गृहयुद्ध छिड़ जाएगा, हिन्दीवाले सब नौकरियाँ हथिया लेंगे, विद्वत् सभ्यता से धातान प्रदान के द्वार बन्द हो जाएँगे, इत्यादि। अंग्रेजी के चले जाने से बहुसंख्य हिन्दू अल्पसंख्यक मुसलमानों और अछूतों को खा डालेंगे—राउड डेबुल कांफ़ेंसों में जैसे ब्रिटिश प्रधानमन्त्री यह दलील पेश करते थे, वैसे ही स्वाधीन भारत के ये 'निबरल' अंग्रेजी के बारे में कहते हैं, अंग्रेजी गई नहीं कि हिन्दीवाले सारी नौकरियाँ हथिया लेंगे, उत्तरवाले दक्षिण पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे, अहिन्दी भाषाओं का नाम-निशान मिट जाएगा। यह बात नहीं है कि राउड डेबुल कांफ़ेंसों के दिनों में सम्प्रदायवादी रुढ़िवादो हिन्दू नहीं थे जो अछूतों को गुलाम बनाकर रखना चाहते, जो मुसलमानों को अपना दास समझते थे। किन्तु इनसे अछूतों और मुसलमानों की रक्षा करने के लिए यह भावश्यक न था कि हिन्दू-अहिन्दू सभी अंग्रेजों की शरण जाते। आज भी ऐसे हिन्दी प्रेमी हैं जो अहिन्दी भाषाओं को दबाकर हिन्दी को वही स्थान देना चाहते हैं जो अंग्रेजी को प्राप्त था। इनसे अहिन्दी भाषाओं की रक्षा करने का मार्ग यह नहीं है कि हम अंग्रेजी की शरण में जाएँ।

अंग्रेजी को राजभाषा बनाये रखने के पक्ष में उदारपन्थियों की दलीलों का खडन देशभक्त भारतवासियों ने ही न किया था, वरन् उनका खडन भारत प्रेमी अंग्रेजों ने भी किया था। उदाहरण के लिए उदार-हृदय सी० एफ० ऐण्ड्रूज न 'द टू इंडिया' नाम की अपनी पुस्तक में लिखा था—“अभी तक अंग्रेजी भाषा को समझनेवाले मुट्ठी-भर बुद्धिजीवी ही हैं किन्तु यह उभरती हुई साधारण भाषा जो हिन्दुस्तानी कहलाती है, उत्तर और मध्यभारत में पचीस करोड़ जनता द्वारा आसानी से समझी जाती है, दक्षिण में भी जहाँ द्रविड भाषाएँ बोली जाती हैं, उत्तर की इस भाषा से लोग थोड़ा-थोड़ा परिचित हो गए हैं। यहाँ मद्रास प्रेसीडेन्सी के इस तिरुपत्तूर आश्रम में जब मैं लोगों की बातचीत सुनता हूँ तो उत्तर के उन संस्कृत शब्दों को पहचान लेता हूँ जो उमिल में घुल मिल गए हैं। कल एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया था, उससे जब मैंने अंग्रेजी में बातचीत करने की कोशिश की तो उसने कहा, 'बुपा करके हिन्दुस्तानी में बातचीत कीजिए'। और जब मैं उस भाषा में बोला तो वह मेरी बात आसानी से समझ गया।”

सी० एफ० ऐण्ड्रूज की यह पुस्तक १९३६ में प्रकाशित हुई थी, तब से दक्षिण में हिन्दी पढ़नेवालों और हिन्दी समझनेवालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। अंग्रेजी पढ़नेवालों और अंग्रेजी समझनेवालों की संख्या उसी अनुपात में नहीं

बढ़ी। अंग्रेजी के समर्थक अब भी मुट्ठी-भर बुद्धिजीवी ही हैं।

भारत प्रेमी ब्रिटिश महिला ऐनी बेसेंट ने 'इंडिया वाउण्ड और फ्री' में राजभाषा अंग्रेजी के विरुद्ध अपनी अन्य किसी रचना से यह कथन उद्धृत किया था—“जब मैंने ने अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया था, तब वह भारत के महान् साहित्य को घृणा की दृष्टि से देख रहा था। उसने यह अनुभव किया था कि अंग्रेजी शिक्षा पर जोर देकर वह विशाल जनता को अज्ञान के हवाले कर रहा था। रीढ़ी के बदले वह पत्थर दे रहा था। लड़के शिक्षा पाते थे और अपने देश की श्रेष्ठ कृतियों से अपरिचित रहते थे। वे अंग्रेजी में बतृता भाव सकते थे अपनी मातृभाषा में नहीं। किसी देश में राष्ट्रीयता के भाव नष्ट करने का इससे अधिक कुशल उपाय नहीं है कि एक विदेशी भाषा को उच्च वर्गों की भाषा, कानून और अदालतों की, बँनेजों की भाषा बना दिया जाय और सरकारी नौकरियों के लिए उस विदेशी भाषा की जानकारी आवश्यक कर दी जाय।”

ऐनी बेसेंट का कथन जितना युक्तिपूर्ण तब था, उतना ही आज भी है। अंग्रेजी के जाने के बाद साम्राज्यवाद से भारतीय जनता का अन्तर्विरोध समाप्त नहीं हो गया। इन्दोनेशिया, पाकिस्तान, मिस्र, सीरिया आदि एशिया के देशों में साम्राज्यवाद अपने मित्रों की तलाश में है जिनकी सहायता से वह इन देशों के आन्तरिक जीवन में हस्तक्षेप करे। इसलिए भारतीय जनता की राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने की ओर हमें सचेत रहना चाहिए।

ऐनी बेसेंट ने 'इंडिया वाउण्ड और फ्री' में उपर्युक्त कथन उद्धृत करने के बाद लिखा था, “मैं यही कहना चाहूँगी कि इंग्लैंड ने बहुत-कुछ, यद्यपि पूरी तरह नहीं, उसी शिक्षा नीति का अनुसरण किया था जिसे पोलैंड में रूस ने लागू किया था। स्कूलों में पोलिश भाषा में शिक्षा देना बन्द करा दिया गया था और वहाँ रूसी का वैसे ही प्रयोग होता था जैसे यहाँ अंग्रेजी का। सभी देशों के तानाशाह एक-दूसरे से मिलते जुलते हैं।”

आज उसी तरह कुछ अंग्रेजी प्रेमी सज्जन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी को उच्चतर स्थान देना चाहते हैं। इससे भारतीय भाषाओं की कितनी क्षति होती है, इसकी ओर वे ध्यान नहीं देते। अंग्रेजी भाषा के आधुनिक 'लिबरल' हिमायतियों से एण्ड्रूज और बेसेंट के विचारों की तुलना कीजिए तो पता चल जायगा कि इन भद्रजनों का दृष्टिकोण कितना प्रतिक्रियावादी है। राज्यसत्ता जनता के लिए है, जनता राज्यसत्ता के लिए नहीं है, यह सत्य उनकी समझ से परे है। वे राज्यतन्त्र को उसी पुराने नौकर-शाही ढंग से चलाना चाहते हैं जिसमें नौकरशाह जनता के नौकर न होकर उसके शाह होते थे। यह युग जनतन्त्र का है, जनता अधिक-से-अधिक शासन-तन्त्र में भाग लेगी। शासनतन्त्र जनता के उत्पीड़न का यन्त्र न होकर उसकी सेवा का माध्यम बनेगा। इस शासनतन्त्र में जनता अपनी भाषाओं द्वारा और केन्द्रीय

राजकाज में हिन्दी द्वारा ही भाग ले सकती है। अंग्रेजी चाहे जितनी समृद्ध हो और हिन्दी चाहे जितनी दरिद्र हो, राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का भविष्य अन्ध-कारमय है हिन्दी का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल। अंग्रेजी के समर्थक इतिहास की प्रगति से युद्ध कर रहे हैं, इसलिए उनकी पराजय निश्चिन है।

राजभाषा की समस्या किसी भाषा के समृद्ध होने की कसौटी पर नहीं अन्ध-हल हुई है, न यहाँ होगी। सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की आवश्यकताओं ने अनेक बुद्धिजीवियों को भारतीय भाषाएँ अपनाने पर पहले भी बाध्य किया था, आगे भी करेंगी। इन आवश्यकताओं में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं ने इजाजत किया है। राष्ट्रीय आत्म सम्मान का निर्वाह शायद देश में इतना आवश्यक नहीं होता जितना विदेश में। अखबारों के अनुसार स्वाधीन भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी में प्राग्ज्योतिषपुर में कहा था, "मैं अंग्रेजी का पक्षपाती हूँ। मैं चाहता हूँ कि न केवल भारत में अंग्रेजी पढ़ी जाय बल्कि उसकी शिक्षा का और भी प्रसार हो। लेकिन मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि कोई अंग्रेजी को भारत की राष्ट्रभाषा बहे। मैं चाहता हूँ कि लोग इस बात पर ध्यान दें। यह कहना कि अंग्रेजी एक राष्ट्रीय भाषा है, सत्य के विरुद्ध है। यह झूठ है। मैं नहीं समझता कि यह दलील कैसे दी जा सकती है। यह बात विचारणीय है कि हम कब तक अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं या व्यावहारिक कारणों से अंग्रेजी और हिन्दी दोनों को काम में लाते हैं।"

इसके बाद अखबारी विवरण के अनुसार "श्री नेहरू ने कहा कि विदेश मन्त्री की हैसियत से अंग्रेजी देशों को कागज पत्र भेजते हुए वह बड़े असमंजस में पड़े कि जिन देशों में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, उन्हें अंग्रेजी में लिखे हुए कागज पत्र कैसे भेजे जाएँ। दुनिया अंग्रेजी बोलनेवाले देशों से बड़ी है। बड़े असमंजस की बात थी। उन्होंने अंग्रेजी में कागज भेजना बन्द कर दिया। अब वह सदा उन्हें हिन्दी में भेजते थे, उनकी सुविधा के लिए अंग्रेजी में अनुवाद साथ रहता था लेकिन मूल हिन्दी में होता था। जब उन्हें रूस या चीन से कोई खरीद मिलती या, तो वह हमेशा रूसी या चीनी में होता था। हो सकता है, साथ में अंग्रेजी में अनुवाद भी रहता हो। कुछ भी हो वह वह यह रहे थे कि दुनिया के सामने भारत में यह घोषित करना बड़ी अजीब बात थी कि भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी है। इस 'कल्पना से ही मेरा सिर चकरा उठता है'।"

अंग्रेजी प्रेमियों के दुर्भाग्य से दुनिया अंग्रेजी-भाषी देशों से बहुत बड़ी है। इस अंग्रेजी विहीन दुनिया में साठ करोड़ आबादी का महादेश चीन है। इसमें समार के छठे भाग में फैला हुआ समाजवादी सोवियत देश है। सोवियत संघ, चीन और भारत में जो भाषा न चले, उसे विश्वभाषा नहीं कहा जा सकता। इन तीन देशों से एशिया और यूरोप का अधिकांश भाग घिरा हुआ है। इनके साथ अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की बिना लीजिये, यूरोप से जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन

और पूर्वी यूरोप के देशों को भी गिन लीजिये तो पता चल जाएगा कि अंग्रेजी का विश्वभाषा होना कितना सार्थक है ।

अस्तु, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही कारणों से अंग्रेजी को राजभाषा का पद छोड़ना होगा । जो लोग भारतीय जीवन के कल्पित या वास्तविक अन्तर्विरोधों के कारण अंग्रेजी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित रखना चाहते हैं, वे लिबरलो, अंग्रेज-भक्तों, अल्पसंख्यकों के उन तथाकथित प्रतिनिधियों का अनुसरण करते हैं जो अंग्रेजी राज को आवश्यक बताकर, अंग्रेजों को न्यायवर्ती बनाकर पराधीनता के बन्धनों को दृढ़ करते रहे थे । भारतीय जनता की राष्ट्रीय भावना इन भारतवासियों के अंग्रेजी-प्रेम पर अवश्य विजय पायेगी । (१९५८)

## बहुजातीय राष्ट्रीयता और राष्ट्रभाषा हिन्दी

विश्वविद्यालयों की शिक्षा और राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में भाषण करते हुए समाचारपत्रों के अनुसार दिल्ली में श्री हुमायूँ कबीर ने कहा कि हिन्दी-भाषी लोग जब हिन्दी को राजभाषा बनाने पर जोर देते हैं, तब कम-से-कम अशत उनके मन में यह कामना रहती है कि वे सार्वजनिक जीवन और नौकरियों के मामले में अहिन्दी-भाषियों के मुकाबले में फायदे में रहेंगे।

देश ने अब इतनी प्रगति कर ली है कि कोई भी माँग जातीय स्वायं से परे नहीं समझी जा सकती। हिन्दीभाषी जनता हिन्दी को राजभाषा बनाने की माँग करती है तो यह भी नौकरियाँ पाने के लिए। अहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी के एक प्रचारक महात्मा गांधी भी थे। पता नहीं, नौकरी पाने की किस छिपी हुई कामना से उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए प्रचार किया था।

श्री कबीर ने कहा कि देश की सभी मुख्य भाषाओं को समानता का दर्जा मिले तो परस्पर शका और संघर्ष की भावना दूर हो जाय। यह बहुत नेक सलाह है और हम उसका समर्थन करते हैं। किन्तु विभिन्न भाषाओं के बोलनेवालों में जो संघर्ष और मतभेद दिखाई देता है, उसका कारण भाषा ही नहीं है, हिन्दी भाषा तो और भी नहीं। पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में जातीय एकीकरण के लिए प्रबल आन्दोलन उठा। इसका कारण भाषा न थी; हिन्दी भाषा और भी नहीं। बम्बई को लेकर गुजरात-महाराष्ट्र में, अलग राज्य (अथवा प्रान्त) बनाने की माँग थी है, उसका कारण हिन्दी नहीं है। इस तरह के और बहुत-से झगड़े हैं जिनका सम्बन्ध जातीय प्रदेशों के एकीकरण, सीमा निर्धारण, उद्योगीकरण आदि से है। इन सारे मतभेदों को भाषा-सम्बन्धी विवाद के छाते में नहीं ढाला जा सकता। इनसे स्पष्ट है कि देश में राष्ट्रीय एकता को बमजोर करनेवाले जातीय मतभेद के जो चक्क चल रहे हैं, उनसे हिन्दी का उन्नत कम सम्बन्ध है। राष्ट्रीय एकता के लिए यद्यपि हिन्दी से नहीं है बल्कि इस जातीय विद्वेष और अलगवा की भावना से है। तमिलनाडु में तमिल राजभाषा है किन्तु वहाँ का एक दिन इस प्रदेश को भारत से

अलग करने की माँग करता है। उत्तर में वश्मीर और दक्षिण में तमिलनाडु—इन दो प्रदेशों में कुछ दलों का भारत से अलगाव के नारे लगाना परिस्थिति की गम्भीरता की सूचना देता है।

यह बात सही है कि एक आदर्श जनतन्त्र में किसी भाषा को विशेषाधिकार न मिलने चाहिए। किन्तु यह बात सही नहीं है कि हिन्दी को राजभाषा बनाने के विरोधी अंग्रेजी के विशेषाधिकारों के बारे में घुप रहे, उन्हें सिर झुकाकर स्वीकार कर लें, अंग्रेजी को अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व-भाषा कहकर उन विशेषाधिकारों की रक्षा करें, इससे उनके जनवादी अन्तःकरण को जरा भी कष्ट न हो, किन्तु हिन्दी के विशेषाधिकार प्राप्त करने की सम्भावना मात्र से वे आसमान सिर पर उठ लें। यह मनोवृत्ति मुस्लिम लीग के उन नेताओं की याद दिलाती है जो बहुसंख्यक हिन्दुओं के शासन-भय से अंग्रेजी राज की शरण लेते थे।

भारत एक बहुजातीय राष्ट्र है। राष्ट्रीयता और बहुजातीयता—इन दो पक्षों में से एक को भी भुलाना घातक होगा। जो लोग राष्ट्र का यह अर्थ लगाते हैं कि उसमें एक ही भाषा बोलनेवाले रहते हों, वे भारतीय राष्ट्रीयता के विकास को आँखों से ओझल कर देते हैं। शताब्दियों से यहाँ विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाले लोग रहते आये हैं। बाज यह तथ्य और भी स्पष्ट है—प्राचीन अतीत की समस्याओं की तरह अस्पष्ट और विवादास्पद नहीं, वर्तमान के ज्वलन्त सत्य के समान असदिग्ध है। इन जातियों की सीमारेखाएँ कोई मिटाना भी चाहे तो वह सफल न होगा। उनकी समानता, भाईचार, परस्पर सहयोग और एकता के बल पर ही राष्ट्रीय एकता दृढ़ हो सकती है।

साथ ही भारत देश एक राष्ट्र है, 'सब वॉन्टीनेन्ट' (उप-महाद्वीप) नहीं है। यहाँ सोवियत देश की तरह मजदूर वर्ग द्वारा सत्ता प्राप्त करने के बाद विभिन्न जातियों द्वारा स्वेच्छा से सघ बनाने का प्रश्न नहीं उठता। भारत विभिन्न जातियों द्वारा निर्मित सघ नहीं है, वह ऐतिहासिक विकासक्रम में संगठित एक राष्ट्र है। भारतीय जनता में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास विश्व इतिहास की अभूतपूर्व घटना है। समाजवादी सत्ता कायम होने से पहले इस तरह की बहुजातीय राष्ट्रीयता का विकास किसी देश में नहीं देखा गया। चीन में गैर-चीनी जातियों की स्थिति हमारे यहाँ के कोल-भिलों की दशा से मिलती जुलती थी। वहाँ उस तरह की बहुसंख्यक गैर-विकसित गैर-चीनी जातियाँ नहीं रह गईं जैसी भारत में गैर-हिन्दी जातियाँ हैं। यूरोप के पूँजीवादी देशों ने जो बहुजातीय राष्ट्र कायम किये, उनमें शामक जाति सभिन्न सभी जातियाँ दासों की स्थिति में होती थी।

भारतीय राष्ट्र की एकरा की भावना अंग्रेजों की देन नहीं है, वह अंग्रेजों के आने से बहुत पहले की है। यह धार्मिक भावना मात्र नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध एक ही धर्म से नहीं रहा। धार्मिक सहनशीलता और उदारता के कारण यहाँ प्राचीन काल से अनेक धर्म—अनीश्वरवादी धर्म तक—पल्लवित होते रहे

किन्तु यह देश बौद्धो, जैनो या हिन्दुओं का राष्ट्र नहीं माना गया। यह एकता केवल भौगोलिक नहीं है। यहाँ के राज्यों की, विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों की सीमाएँ देश से बाहर उत्तर-पश्चिम में दूर तक फैली रही हैं। यदि भौगोलिक एकता नियामक कारण होती तो भारत-विभाजन की नीबट न आती। भौगोलिक और धार्मिक कारण भी रहे हैं किन्तु मुख्य कारण है यहाँ की जातियों का सामान्य इतिहास, उनकी सांस्कृतिक समानताएँ, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में उनका परस्पर सम्बद्ध और मिला-जुला विकास। इस ऐतिहासिक आधार पर ही यहाँ की राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ है।

मार्क्सवाद ने जानियों के विकास पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है। लेनिन और स्तालिन के अनुसार जातियाँ पूँजीवाद के अन्त्युदय-काल की देन हैं। किन्तु मार्क्सवाद की किसी पुस्तक में भारत-जैसी बहुजातीय राष्ट्रीयता के विकास की व्याख्या नहीं मिलती। कुछ लोग यात्रिक ढंग से यहाँ की परिस्थितियों पर मार्क्सवाद लागू करते हुए इस परिणाम पर पहुँचे थे कि यहाँ हर जाति अपनी सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न विधान सभा बनाये, फिर ये विधान सभाएँ यहाँ अपना सघ निर्मित करें। इस तरह के विचारकों के अनुसार सन् सत्तावन की राज्यक्रान्ति में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था, कारण यह कि राष्ट्रीयता का आधार रेल-तार थे जिनका पूरी तरह चलन न हुआ था। भारतीय इतिहास की वास्तविकता पर ध्यान दिए बिना यह कभी समझ में न आयेगा कि माधवजी सिन्धिया ने पेशवा को मुगल बादशाह का नायब क्यो घोषित किया, १८५७-५८ में देश के विशाल भाग की जनता शाही झण्डे के नीचे क्यो लड़ी, झाँसी में 'मुल्क बादशाह का, अमल रानी लक्ष्मीबाई का' की डुगी क्यो पीटी गई। सी० एफ० ऐण्ड्रुज जैसे विदेशी लेखकों ने ज्यादा सचाई से लिखा था कि अंग्रेजों ने आने के बाद राष्ट्रीय चेतना दृढ़ भले हुई हो, वह विद्यमान पहले से थी।

वर्तमान काल में जातियों की एकता और समानता की जो समस्या हमारे सामने है, उसका घनिष्ठ सम्बन्ध इस राष्ट्रीय चेतना के ऐतिहासिक विकास से है। हम जातीय समस्या और भाषा की समस्या को अपना इतिहास भुलाकर हल करेंगे या उसे राष्ट्रीयता के सन्दर्भ में हल करेंगे? राष्ट्रीयता के सन्दर्भ को भुलाकर जब हम उसे हल करते हैं, तब सीमान्त पर साम्राज्यवादी अड्डे कायम होते हैं। दस साल में एक बार भी आम चुनाव नहीं होता, जनतन्त्र के बदले धर्म-विशेष का राज्य कायम किया जाता है। लाखों की तादाद में नर-नारी बेघर-भार होकर खुद तबाह होते हैं और देश के अर्थतन्त्र का सकट में डाल देते हैं। यह जातीय अलगवाह बहुत जल्दी साम्राज्यवादी घट्यन्त्र का अंग बन जाता है। जिन उप-निवेशों पर साम्राज्यवाद ने शासन किया है, उन्हें वह स्वाधीन नहीं देखना चाहता। एक साम्राज्यवादी ताकत गई तो दूसरी उसे हड़पने को तैयार रहती है। अलगवाह का नारा राष्ट्रीय एकता को कमजोर करनेवाला और साम्राज्यवाद तथा युद्ध की ताकतों को शहजोर करनेवाला है।



इसलिए जातीय समस्या और भाषाओं के समान अधिकारों की समस्या राष्ट्रीय एकता के सन्दर्भ में हल करनी होगी ।

भारत में प्रत्येक भाषा को अपने क्षेत्र में राजकीय और सांस्कृतिक कार्यों में पूर्ण अधिकार प्राप्त होने चाहिए । साधारण हिन्दी जनता, हिन्दी का शिक्षित वर्ग और लेखक इस स्थिति के पक्ष में हैं । हिन्दी-पत्रों में यह बार-बार कहा गया है कि हिन्दी किसी भाषा के अधिकार नहीं छीनना चाहती; अहिन्दी-भाषी जातियों के परस्पर व्यवहार के लिए अंग्रेजी की जगह हिन्दी होनी चाहिए ।

कई शताब्दियों से देश की विशेष परिस्थितियों के कारण हिन्दी अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा बनती रही है । उत्तर भारत में केन्द्रबद्ध मुगल शासन का होना, यहाँ आगरा जैसे व्यापार के बड़े-बड़े केन्द्रों का निर्माण, उन्नीसवीं सदी से पूर्व ही यहाँ के लोगों का विभिन्न प्रदेशों में फैलना ऐसे ही कारण थे । अंग्रेज व्यापारी भी उस समय अपनी सुविधा के लिए हिन्दी सीखते थे । वर्तमान काल में दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सर्वत्र ऐसे व्यापारी और पूँजीपति मिलेंगे जिनकी सांस्कृतिक भाषा हिन्दी है । हिन्दी के प्रसार का एक बहुत बड़ा कारण कलकत्ता-बम्बई जैसे केन्द्रों में लाखों 'हिन्दुस्तानी' मजदूरों का निवास है । इन बड़े-बड़े नगरों के अतिरिक्त प्रत्येक जातीय प्रदेश में अल्पसंख्यकों के रूप में हिन्दुस्तानी मिलेंगे । विशाल आंध्र में हैदराबाद और उसके आस-पास हिन्दुस्तानियों का भारी जमावड़ा है । अहिन्दी प्रदेशों में इस प्रकार हिन्दी की अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा बनाने में सुविधा मिली है ।

इसके अतिरिक्त सीलोन रेडियो और विविध भारतीय (और पाकिस्तान रेडियो भी) की कृपा से फिल्मी संगीत द्वारा देश के चारों कोनों तक रोज शाम-सवेरे हिन्दी गूँजती रहती है । कभी इन फिल्मी गानों की फरमाइश करनेवालों के नाम सुनिए । जितने हिन्दी-भाषी प्रदेश के होते हैं, उतने ही अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के । स्वयं गायकों और गायिकाओं में एक अच्छी संख्या अहिन्दी कलाकारों की रहती है । विशाल हिन्दी-भाषी प्रदेश फिल्मों के लिए सबसे अच्छा बाजार है । ये व्यावसायिक परिस्थितियाँ बूढ़ों के न चाहने पर—और शायद उनके न जानने पर भी—हिन्दी को राष्ट्रभाषा बना रही हैं ।

इनके सिवा हिन्दी भाषा, लिपि और साहित्य की कुछ विशेषताएँ हैं जो इस कार्य में सहायता करती हैं । हम यहाँ उनका उल्लेख नहीं करते ।

हिन्दी अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा बन रही है, जनसाधारण के लिए अभी भी वह ऐसी भाषा है । वह केन्द्रीय राजकाज की भाषा भी जल्दी बन सकती है । इसमें एक बाधा है हिन्दी-भाषियों का असंगठन, उनमें जातीय चेतना की कमी । हिन्दी-भाषी प्रदेशों के राज्यों में भी हिन्दी अभी पूरी तरह राजकाज की भाषा नहीं बनती है । दक्षिण के लोगों की यह आपत्ति अनुचित नहीं है कि पहले अपने घर में हिन्दी को राजभाषा बना लो, फिर उसे सारे देश की राष्ट्रभाषा बनाना । यदि हिन्दी भाषी जनता संगठित हो, यदि वह अपने प्रदेश में हिन्दी



## हिन्दी की व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ

हिन्दी की व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयों से कुछ अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी इतना परेशान हैं कि वे कभी कभी उसके चलरत्ता-बम्बई जैसे नगरी में कुछ अहिन्दी-भाषियों द्वारा व्यवहृत रूप को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने की बात करते हैं। इनमें राजनीतिक नेताओं के अलावा कुछ प्रसिद्ध भाषा-वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने यथेष्ट गम्भीरता से यह प्रस्ताव रखा है। अंग्रेजों के सम्पर्क में आने-वाले हिन्दुस्तानी खानसामा भी अंग्रेजी का एक सरल रूप काम में लाते थे जो साहब और उनके बीच की सांस्कृतिक आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए पर्याप्त होता था। कुछ देशों के कुलियो आदि ने इसी तरह अंग्रेजी को सरल करके अपना काम निवाला है। लेकिन इस देश में न तो हिन्दी भाषी जनता अंग्रेज साहबों की स्थिति में है, न अहिन्दी-भाषी जनता कुलियो और खानसामाओं की। इस कारण जो लोग हिन्दी के तथाकथित सरल व्याकरण विहीन रूप को अपनाने की बात करते हैं, वे अपने ओर हिन्दी-भाषियों के प्रति अन्याय ही करते हैं। यहना न होगा कि खानसामा-अंग्रेजी को भारत की लिगुआ-प्राज्ञा या विश्वभाषा बनाने की बात नहीं की जाती। इसके विपरीत इस कोटि के राष्ट्रभाषा-प्रेमी अंग्रेजी-शिक्षा का स्तर गिरने से नितान्त व्यथित रहते हैं और आए दिन इस स्तर को उठाने के लिए नये-नये उपाय भी सुझाया करते हैं। यह बात भी कम मनोरंजक नहीं है कि एक ओर वे हिन्दी के दरिद्र होने की, उसमें उच्च कोटि के साहित्य के अभाव की घोषणा करते हैं, दूसरी ओर व्याकरण की कठिनाइयों से मुक्त हिन्दुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाने का 'जनताधिक' सुझाव भी देते हैं।

अंग्रेजी भाषा में व्याकरण-सम्बन्धी कठिनाइयाँ कम नहीं हैं। डेढ़ सौ साल से लगातार अंग्रेजी पढ़ने के बाद भी इस भाषा की सीखने का स्तर जो गिरता नज़र आ रहा है, उसका कारण विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिभा के अलावा उस भाषा की खूबियाँ भी हैं। किन्तु अंग्रेजी-प्रेमी देशभक्त अपनी प्रिय भाषा की व्याकरणगत कठिनाइयों से जरा भी विचलित नहीं होते, उन्हें शिकायत है हिन्दी की कठिनाइयों से। इनमें भी सारे फसाद की जड़ उनकी समझ में हिन्दी का लिग-

भेद है ।

हिन्दी शब्दों की लिंग-सम्बन्धी कठिनाई वास्तविक है । यह कठिनाई आहन्दी-भाषियों के लिए ही नहीं है, भोजपुरी आदि पूर्वी बोलियों के क्षेत्रों में हिन्दी बोलने-वालों के लिए भी यह कठिनाई विद्यमान है । इतिहासकारों का कहना है कि एक बार दिल्ली के क्लेअरमेंट 'खारा पानी' कहनेवालों को पछाँह का समझकर छोड़ दिया गया, 'खारी पानी' कहनेवालों को पूरब का मानकर उन्हें तलवार के घाट उतार दिया गया । इस कठिनाई में ऐसे नतीजे भी निकल सकते हैं ।

भाषा का निर्माण किसी अकादमी में नहीं होता, न उसका व्याकरण बनाने का काम राजनीति विचारद्वारा करते हैं, वरना यह कठिनाई दूर हो जाती । सस्कृत के महान् व्याकरण भी, जो भाषा की व्यवस्थित करने में अपना सानी नहीं रखते, इस कठिनाई से पार न पा सके । शत्रु पुल्लिङ्ग, मित्र नपुंसक लिंग । वृक्ष जैसा जड़ पदार्थ पुल्लिङ्ग, हृदय चैना तरल और गतिशील पदार्थ नपुंसक लिंग । पाशु (घृत्), परगु, इषु (बाण) जैसा निर्जीव पदार्थ पुल्लिङ्ग है, शरीर और शीर्ष जैसे मजीव पदार्थ नपुंसक लिंग हैं ।

इस देश के सांस्कृतिक इतिहास में सस्कृत का जो महत्त्व रहा है, उसे सभी लोग जानते हैं । भारत की भाषाओं पर उसका जो व्यापक प्रभाव पड़ा है, वह भी किसी ने छिपा नहीं है । सस्कृत शब्दों की लिंग-सम्बन्धी कठिनाई से उसके प्रसार में कोई बाधा नहीं पड़ी । सम्भव है, कुछ सज्जन कहें कि इस कठिनाई के कारण ही वह मृत भाषा हुई । यदि ऐसा होता तो सस्कृत भाषी प्रदेश की भाषाएँ—जिनमें हिन्दी सर्वोपरि है—इस कठिनाई से मुक्त होती ।

सस्कृत के समान यूरोप की भाषाओं और सस्कृति पर प्राचीन यूनान की भाषा—वहाँ अनेक भाषाएँ थी, हमारा तात्पर्य एथेन्स की भाषा से है—का प्रभाव पड़ा । किसी समय वह भूमध्य सागर के तट पर फैले हुए अनेक यूनानी उपनिवेशों के कारण एक विशाल भूभाग में फैल गई थी । इस भाषा में अरस्तू और अफलातून जैसे विचारकों ने, सोफोक्लीज, यूरिपिदीज जैसे नाटककारों ने, हेराक्लितस जैसे दार्शनिकों ने अपनी रचनाएँ की जिनके आधार पर यूरोप की सस्कृति का प्रासाद निम्न हुआ । इस भाषा में गेनोस (सस्कृत जन) नपुंसक है किन्तु दिमोस (जनता) पुल्लिङ्ग है । थूरा (द्वार), माखइरा (तलवार), अकन्या (काँटा) जैसी वेश्या चीजें स्त्रीलिंग हैं । यदि आप कहें ये आकारान्त हैं, इसलिए स्त्रीलिंग हैं तो देखिए म्नीमा (समाधि), ओइको दोइमा (भवन) आदि नपुंसक लिंग हैं । नेत्रोस् (शव) तो पुल्लिङ्ग है, पाइदिओन् (गिफ्त) नपुंसक लिंग है ।

प्राचीन यूनानी के समान और भी बड़े पैमाने पर लैटिन व्यवहार में आई । वह शताब्दियों तक इटली ही नहीं, यूरोप की धार्मिक और सांस्कृतिक भाषा रही । इसमें भी यूनानी भाषा की तरह लिंगभेद वर्तमान था । अग्नि के लिए दो शब्द हैं, 'इन्केण्डियम्' और 'इग्निस्', पहला नपुंसक, दूसरा पुल्लिङ्ग है । जनता के लिए दो शब्द हैं, गेन्स् (जन) और पोपुलुस्; पहला स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिङ्ग । इम्पेर

(वर्षा), टूरिस् (मीनार), मारे (मगुद्र) तीनों को स्वभावतः नपुसक लिंग होना चाहिए किन्तु ये त्रयस्तु पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुसक लिंग हैं। अकीला (बाज) और अग्रिकोला (कृपक) देखने में एक-से आकारान्त शब्द हैं किन्तु पहला स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग।

लैटिन की उत्तराधिकारिणी भाषाओं में फ्रांसीसी भाषा भी है। वह यूरोप में अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा रही है। उसमें घर के लिए दो शब्द हैं, मँजों, बातीमाँ, पहला स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग। इसी प्रकार धरती के लिए टैयर और पेयी, मार्ग के लिए रूत और शर्म शब्दों में पहला स्त्रीलिंग है, दूसरा पुल्लिंग। फ्रांसीसी लोग पर्वत जैसी विशाल वस्तु (मोताञ्ज) को स्त्रीलिंग विज्ञापित करते हैं, पुस्तक जैसी छोटी चीज (लीब्र) को पुल्लिंग।

यूरोप के एक विशाल प्रदेश में व्यवहृत फ्रांसीसी की तरह एक हृद तक अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा जर्मन है। उसमें संस्कृत के समान ही लिंगभेद है। परधर (श्टाइन), वृक्ष (बाउम), जूता (शू) जैसे निर्जिव पदार्थ पुल्लिंग हैं, जनता (फोल्क), नारी (इसके लिए एक शब्द फ्राइप भी है), लडकी (मैडचेन) आदि सजीव वस्तुएँ नपुसक लिंग हैं। संस्कृत के समान जर्मन में तीनों लिंग विद्यमान हैं और शब्द के अर्थ या रूप से उन्हें पहचानना आसान नहीं है।

संसार के छोटे भाग में फैले हुए सोवियत संघ की अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा रूसी है। इसमें भी संस्कृत और जर्मन की तरह तीनों ही लिंग हैं। अधिकतर निर्जिव पदार्थ नपुसक लिंग होते हैं किन्तु पुस्तक (क्नीगा), होटल (गस्ती-नित्सा), पुस्तकालय (बिब्लियोतेका) आदि शब्द स्त्रीलिंग हैं। यद्यपि शब्दों के रूप से उनका लिंग पहचाना जा सकता है, फिर भी इस विषय में नियमों के अनेक अपवाद हैं।

प्राचीन काल से आज तक संसार की अनेक और प्रमुख भाषाएँ शब्दों में लिंगभेद करती रही हैं। यह भेद वास्तविक न होकर—शब्दों द्वारा विज्ञापित वस्तु के लिंग का अनुसरण न करके—बहुधा शब्दों के रूप के अनुसार होता है। शब्दों का रूप देखकर उसका लिंग निश्चित करना सदा सरल नहीं होता। इस सम्बन्ध में कुछ मोटे नियमों का पालन किया जाता है किन्तु उनके अपवादों की संख्या कम नहीं है। भाषा संसार के पदार्थों, मनुष्य के व्यवहार और चिन्तन की अभिव्यजना के लिए ही विकसित हुई है। वह इस भौतिक जगत् और मनुष्य के भौतिक जीवन से विलग होकर विकसित नहीं हुई। उसकी जड़ें इसी भौतिक जीवन और जगत् में हैं। किन्तु भाषा भौतिक जगत् से मनुष्य का सम्बन्ध विज्ञापित करने का साधन ही नहीं है। जैसे मगीत में विभिन्न प्रदेशों की जातियों को स्वरो का विशेष सामग्रस्य, उनका विशेष आरोह-अवरोह पसन्द आता है, वैसे ही भाषा के क्षेत्र में विभिन्न जातियाँ शब्दों के साथ विशिष्ट रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करती हैं। एक ही वस्तु के लिए विभिन्न भाषाओं के पर्यायवाची शब्दों में लिंग-सम्बन्धी अन्तर होता है। एक ही भाषा में किसी वस्तु के लिए भिन्न लिंगवाले पर्याय-

बाकी शब्दों का प्रयोग देखा जा सकता है। दूसरों के लिए इस वैचित्र्य के कारण भाषा कठिन हो जाती है किन्तु उनके बोलनेवालों के लिए इस वैचित्र्य का रागात्मक मूल्य है। भाषा के समस्त ऐतिहासिक विकास के फलस्वरूप यह विभिन्नता उत्पन्न होती है। वह भाषा की सजीव परम्परा का अंग होनी है। उसे समाप्त करना वैसे ही असम्भव है जैसे मुहावरों का समाप्त करना। मुहावरों की तरह लिंग भेद सीखना होता है। अन्तर्जातीय व्यवहार की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए भाषा के रूप को न तो आज तक कहीं बदला गया है, न अब बदला जा सकता है। अन्य भाषाओं और जातियों के सम्पर्क में आने से भाषा में परिवर्तन होते हैं। किन्तु इन परिवर्तनों का सम्बन्ध व्याकरण से सबसे कम होता है। ग्रन्थों ने ससार की अनेक भाषाओं में शब्द लिये हैं—वास्तव में जर्मन या रूसी की तुलना में उसकी अपनी पूँजी नगण्य है—किन्तु उसके व्याकरण में कितना परिवर्तन हुआ है? उसने शब्द दूसरों के लिए किन्तु व्याकरण के रूप अपने रखे। उसका शब्द-भण्डार जितना मिश्रित है, उसका व्याकरण उतना ही अपेक्षाकृत विमुक्त।

खड़ी बोली ने अरबी-फारसी में संकड़ो शब्द लिये, उसका उर्दू रूप विकसित हुआ। कुछ विद्वानों का विचार है कि बाहर से आनेवाले मुसलमान यहाँ की भाषा समझते न थे, उनकी अपनी भाषाओं और यहाँ की बोलियों—अथवा खड़ी बोली और फारसी—के मिश्रण से फौजी नेमो और बाजारा में उर्दू का जन्म हुआ। बाहर से आनेवाले गुजलमानों की भाषा क्या थी, एक थी या एक से अधिक थी, बंगाल, ब्रह्मी, पंजाब, केरल आदि प्रदेशों में मुसलमान यहाँ की भाषा वैसे समझते लगे, इन प्रश्नों का विवेचन न करके हम केवल इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे कि उर्दू की जन्म देनेवाले मुसलमानों को यहाँ का शब्द-भण्डार स्वीकार करने में चाहे जो कठिनाई हुई हो, खड़ी बोली के व्याकरण-रूपों को उन्होंने सप्रेम स्वीकार कर लिया। इन रूपों में लिंग-भेद भी है। ऐसा नहीं हुआ कि लिंग-सम्बन्धी कठिनाई दूर करके बाहर से आनेवाले मुसलमानों ने खड़ी बोली को अपनाया हो। उन्होंने यहाँ की व्याकरण-परम्परा को—जैसे सीपना शब्दों को ग्रहण करने से ज्यादा कठिन था—स्वीकार किया। भारत की अनेक भाषाएँ—जैसे बंगला—शब्द-भण्डार की दृष्टि से हिन्दी के जितना निरट हैं, उतना उर्दू नहीं है। यदि बाहर से आनेवाले मुसलमान यहाँ के लिंग सम्बन्धी भेद सीख सकते थे तो शब्द-भण्डार की इतनी समानता रहने पर बंगाली मिला उनसे क्यों पार नहीं पा सकते? इस कारण 'भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी' में डॉ॰ सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित सुझाव अभी तक अप्राप्त रहा है 'परन्तु यदि ये व्याकरण-विषयक बिगिष्टताएँ, जो बाकी के भारतवासियों के लिए वास्तविक कठिनाइयाँ बन रही हैं कम कर दी जायें, जैसा कि पूर्वी हिन्दीवालों तथा विद्वारियों ने किया है (२१), तो संस्कृतनिष्ठ प्रचलित हिन्दुस्थानी, एक अत्यन्त सहज, सुबोध तथा ओजपूर्ण भाषा बन जाती है। इस सहज बनी हुई हिन्दुस्थानी का

हिन्दी की व्याकरण सम्बन्धी कठिनाइयाँ / १

सारा व्याकरण एक पोस्टकार्ड पर लिखा जा सकता है। 'बाजारू हिन्दुस्थानी' के सदृश सुगठित तथा ओजपूर्ण भाषा को हाट बाजार से, जहाँ पर कि उसने स्वतन्त्र, अनवरुद्ध जीवन-प्रवाह पण्डितों की घृणा की परवाह न करते हुए अनवरत रूप से बहा चला जा रहा है, उठाने की आवश्यकता है। हमें उसे आदरपूर्ण आन्तर्जातिक या आन्तर्देशिक भाषा के इतने उच्च स्तर तक उठाना होगा कि वह कम-से-कम सार्वजनिक सभा-सम्मेलनों आदि में प्रयुक्त होने योग्य बन जाय। इसमें साहित्य का सृजन बाद में हो सकता है—आगे चलकर होगा ही (१)। परन्तु वह सारी भविष्य की बात है। अभी हाल के लिए हमें एक द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकृत किया जा सकता है, जिससे सर्वसाधारण को परिचित हो जाने के लिए कहा जा सकता है। यह उसी भाँति फारसी-युक्त उर्दू तथा नागरी-हिन्दी के साथ साथ प्रयुक्त होती रहेगी, जैसे आज होती है।”

अस्तु परिणाम यह निकला कि हिन्दी की लिंग-सम्बन्धी कठिनाइयाँ दूर करके उसे सरल नहीं बनाया जा सकता। जिस तरह खानसामा-अंग्रेजों को राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला उसी तरह अहिन्दी-भाषी प्रदेशों में कुछ लोगों द्वारा व्यवहृत हिन्दी के टूटे फूटे रूप को देश के राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवहार की भाषा नहीं बनाया जा सकता। यह सही है कि हिन्दी-भाषियों को दूसरों की त्रुटियों पर हँसना न चाहिए, वरन् भाषा-सम्बन्धी अपने प्रयोगों के प्रति उन्हें अधिक सचेत होना चाहिए। साथ ही यह भी सही है कि कुछ अहिन्दी-भाषी मिन हिन्दी की व्याकरण सम्बन्धी कठिनाइयों को दुर्लक्ष्य बतलाकर, उन्हें दूर करके भाषा को सरल करने का सुझाव देकर अन्तर्जातीय व्यवहार की भाषा-समस्या हल नहीं कर सकते। धैर्य, उदारता और परिश्रम से ही इस कठिनाई पर विजय प्राप्त हो सकती है।

(१९५८)

## उर्दू की समस्या

प्रधानमन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस की कार्य-कारिणी तथा अन्य राजनीतिक सस्थाओं ने पिछले दिनों उर्दू के संरक्षण की समस्या की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया है। उनके वक्तव्यों का यह मूल्य है कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण समस्या पर ध्यान केन्द्रित किया है जिसके प्रति साधारणतः हिन्दी-भाषी जनता उदासीन हो गई थी। इससे सिद्ध यह होता है कि भारत के साम्राज्यवादी विभाजन में जो अनेक समस्याएँ नहीं सुलझी, उनमें उर्दू की भी एक समस्या है। दुर्भाग्य से इन वक्तव्यों में यह नहीं बतलाया गया कि उर्दू के आरक्षण या दमन के लिए उत्तरदायी कौन है विभाजन के बाद यह समस्या अब भी क्यों घनी हुई है, उर्दू के संरक्षण के लिए कौन में उपाय किये जाने चाहिए, इत्यादि। संक्षेप में स्थिति यह है कि भावुकता के अलावा वैज्ञानिक स्तर पर इस समस्या के बारे में इन वक्तव्यों में कुछ नहीं कहा गया।

एक समय था जब कांग्रेस का नेतृत्व हिन्दी-उर्दू को मूलतः एक भाषा मानता था, उनमें अनावश्यक संस्कृत और अरबी शब्द भरने का विरोधी था, हिन्दुओं और मुसलमानों की मिली-जुली भाषा को कौमी जवान कहता था और उसे राजभाषा बनाने पर जोर देता था। आज स्थिति बदल गई है। कौमी जवान की बात करना तो महापाप है, जो सबसे प्रगतिशील बात कही जा सकती है, वह यह कि उर्दू को दबाया न जाय। और कौमी जवान के राष्ट्रभाषा बनने का सवाल नहीं, शुद्ध राष्ट्रभाषा हिन्दी भी राजभाषा नहीं बन पाई, सारे देश में नहीं बन पाई, और अपनी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश—तथा अन्य हिन्दीभाषी राज्यों—में भी वह राजभाषा नहीं बन पाई।

देश के राष्ट्रीय नेताओं ने साम्प्रदायिक समस्या को हल किया साम्प्रदायिक माँगों को स्वीकार करके। साम्प्रदायिकता के आधार पर किये हुए समझौते के बृक्ष में राष्ट्रीयता के पत्र न लगें तो इसमें आश्चर्य क्या? उर्दू का नाम गुनते ही बहुत-से हिन्दी-प्रेमी स्वभावतः परेशान हो उठते हैं। आतिर इन्ही समस्याओं को हल करने के लिए तो पाकिस्तान बना और यह उर्दू का खेड़ा अब भी बना हुआ है।



उर्दू-प्रेमियों ने अलग परेगान होकर बीभी जवान की इलाकाई जवान बनाने के लिए दस्तखत टक्कठें किये। उन्होंने उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में अंग्रेजों को हटाने के लिए आन्दोलन करना जरूरी नहीं समझा। न उन्होंने इस आन्दोलन की नीति निर्धारित करने के लिए हिन्दी प्रेमियों में सलाह-मसविदा किया। इसलिए वैधानिकता का जामा पहनने पर भी यह एक सीमित साम्प्रदायिक आन्दोलन ही रहा।

उर्दू के सम्बन्ध में अनेक गलत धारणाएँ हिन्दी-प्रेमियों और उर्दू-प्रेमियों दोनों के मन में बनी हुई हैं। इन पर संक्षेप में विचार करना आवश्यक है।

एक धारणा यह है कि मुसलमानों ने यहाँ आकर उर्दू का एक प्रकार का धार्मिक प्रेम है, वे उसे अपने धर्म और विशेष सभ्यता की भाषा समझते हैं। बहुत-से हिन्दू इस धारणा को स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि में मुसलमान कभी हिन्दुस्तानी नहीं बना, इसलिए उर्दू भी 'अरब जेहादियों का नीतिस्तम्भ' है। हिन्दुओं और मुसलमानों में जो चरम साम्प्रदायिकतावादी हैं, वे उसके प्रति एक-सा ही प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। यहाँ दृढ़ बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि अनेक साम्राज्यवादी भाषा-वैज्ञानिकों का भी यह मत रहा है कि उर्दू इस्लाम की भाषा है।

यदि उर्दू इस्लाम की भाषा है तो पूर्वी बंगाल के मुसलमान बंगला क्यों बोलते हैं? उन्होंने उर्दू के एकमात्र राजभाषा बनाये जाने के विरुद्ध संघर्ष क्यों किया? बंगाल के अलावा केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कश्मीर आदि प्रदेशों के मुसलमान घर में उर्दू क्यों नहीं बोलते? और हिन्दुस्तान-पाकिस्तान से बाहर तुर्की, ईरान, इराक आदि राष्ट्रों में उर्दू क्यों नहीं बोली जाती?

स्पष्ट है कि सत्तार में एक हिन्दुओं की भाषा, एक मुसलमानों की भाषा, एक बौद्धों या ईसाइयों की भाषा नहीं है। भाषाओं का निमाण और विकास धर्म के आधार पर नहीं हुआ। धार्मिक विचारधाराओं के कारण उनके लिखने-बोलने-वालों ने उनमें कुछ नई विशेषताएँ पैदा कीं, वह दूसरी बात है। भाषा का सम्बन्ध जातीयता से है, किसी जाति के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास से है। जाति और धर्म एक वस्तु नहीं है। ईरानी, इरानी, तुर्की जातियाँ इस्लाम धर्म मानती हैं किन्तु इनकी भाषाएँ अलग-अलग हैं। इसी प्रकार भारत की विभिन्न जातियों की अपनी-अपनी भाषाएँ हैं, उन जातियों के प्रदेशों में हिन्दू-मुसलमान दोनों ही उन भाषाओं को बोलते हैं, उनमें अपना सांस्कृतिक काम-काज करते हैं। उर्दू का व्यवहार कहाँ के मुसलमान करते हैं? सबसे पहले हिन्दी-भाषी प्रदेश के, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्यप्रदेश आदि के। कारण यह कि उर्दू यदि कहीं की जातीय भाषा है तो हिन्दी भाषी प्रदेश की है। इसके बाद कलकत्ता, हैदराबाद, बम्बई जैसे नगरों में मुसलमानों की बस्तियाँ हैं जो अपने मूल प्रदेश से वहाँ पहुँचे हैं या जिनके गुरुकुल पहले कभी पहुँचे थे। इनके बाद

कश्मीर आदि प्रदेशों के मुसलमान हैं जिनकी मातृभाषा कश्मीरी है या अन्य कोई भाषा है और जो उर्दू भी जानते हैं और उसे काम में लाते हैं।

धर्म के आधार पर उर्दू की रक्षा की बात करना या उसे इस्लाम की भाषा समझकर उसका नाश करने की बात सोचना एक अवैज्ञानिक और प्रतिक्रियावादी कार्य है।

उर्दू इस्लाम की भाषा है, इस धारणा में भिन्न एक दूसरी स्थापना है जो प्रगतिशील और राष्ट्रीय समझी जाती है। वह यह है कि उर्दू हिन्दुओं और मुसलमानों के मेल से बनी है। दूसरे शब्दों में उर्दू केवल इस्लाम की भाषा नहीं, वह इस्लाम और हिन्दू धर्म दोनों की भाषा है। यह स्थापना देखने में प्रगतिशील मालूम होती है क्योंकि वह राष्ट्रीयता के लिए आवश्यक हिन्दू-मुस्लिम-एकता की ओर सचेत करती है। इस स्थापना का सहारा लेकर ही अनेक राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने भाषा-समस्या को हल करने का प्रयत्न किया था और उसमें असफल भी हुए थे।

यदि हिन्दुओं और मुसलमानों के मिलने से उर्दू बनी होती तो बम्बई से बलुचता तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जातीय प्रदेश में उर्दू ही बोली जाती, बंगला, मराठी, कश्मीरी, मलयालम आदि भाषाओं का अस्तित्व ही न होता। उर्दू एक विशेष जातीय प्रदेश की भाषा है, भारत के सभी जातीय प्रदेशों की नहीं। उसे मातृभाषा के रूप में काम में लानेवाले वही लोग हैं जो हिन्दी-भाषी प्रदेश के निवासी हैं या यहाँ से जाकर दूसरे प्रदेशों में बस गए हैं। हिन्दी-उर्दू एक ही जातीय प्रदेश की भाषा है, इसीलिए उनका बोलचाल का रूप एक-सा है या प्रायः एक-सा है।

भारत में जो मुसलमान आये उनमें कोई पश्तो बोलता था, कोई तुर्की, कोई अरबी, कोई फारसी। उनकी भाषाएँ कम से कम तीन भिन्न परिवारों की हैं। तुर्की, अरबी, फारसी एक दूसरे से भिन्न भाषा-परिवारों की हैं। यदि उर्दू का निर्माण हिन्दुओं-मुसलमानों के मिलने से होता तो उसमें तुर्की के उतने ही शब्द होते जितने फारसी के। या इस्लाम धर्म का सम्बन्ध विद्वेग रूप में अरबी से जोड़ा जाय तो उर्दू में तुर्की फारसी का बहिष्कार और अरबी सस्कृत का बराबर सम्मिश्रण होना चाहिए था। बाहर से आनेवाले मुसलमानों ने राजभाषा के लिए अरबी नहीं, फारसी को चुना। उनका धर्मग्रन्थ अरबी में है, फारसी में नहीं। फारसी पर अरबी का प्रभाव है, फिर भी वह मूलतः भारत-यूरोपीय परिवार की भाषा है और अरबी की अपेक्षा वह सस्कृत के अधिक निकट है। मुसलमान सामन्तों ने अरबी को राजभाषा क्या नहीं बनाया? इस पद के लिए उन्होंने फारसी को क्यों चुना? इसलिए कि वे सामन्त अनेक बर्बरताओं के बावजूद मुस्लिम लोग के नेताओं से अधिक उदार थे। फारसी को चुनने में धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक कारण प्रधान थे। मानविक दृष्टि से ईरान समृद्ध राष्ट्र था, मध्य एशिया और मध्यपूर्व के देशों पर ईरानी सभ्यता की छाप थी। बाहर से आनेवाले मुसलमान यह छाप

अपने साथ लाए थे। मुगल सम्राटों के यहाँ दरबारियों में काफी ईरानी होते थे; फारसी बोलचाल की भाषा थी। इस कारण मुगल राज्यसत्ता में फारसी का बोलबाला रहा।

मुसलमान सामन्तों ने राजभाषा में रचनाएँ की, अनेक सूफियों ने अवधी में काव्य लिखे, रमखान और रहीम जैसे कवियों ने ऐसी सरस कविताएँ लिखी कि वे आज भी गाँवों में लोगों की जवान पर रहे। हिन्दी भाषी प्रदेश सबाहर कश्मीरी, पंजाबी, बंगला आदि भाषाओं और उनके साहित्य-माहित्य के उत्थान और विकास में मुसलमानों ने महत्वपूर्ण योग दिया। आजकल बहुत-से हिन्दू-मुसलमान इन बातों को याद करना पसन्द नहीं करते। उनसे एक अनचाहा परिणाम निकलता है कि मुगल शासनकाल में फारसी के राजभाषा रहते हुए भी यहाँ की जातीय भाषाओं ने अभूतपूर्व उन्नति की और इस उन्नति में मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ था। हिन्दू साम्प्रदायिकों को यह निष्कर्ष पसन्द नहीं है क्योंकि उनके अनुसार मुसलमानों ने भारत का कभी अपना देश नहीं समझा, फिर वे यहाँ की भाषाओं और उसके साहित्य की उन्नति में योग कैसे दे सकते थे? मुस्लिम साम्प्रदायिकों को यह निष्कर्ष पसन्द नहीं है क्योंकि जातीय भाषाओं के विकास के इस चौखटे में उनकी उर्दू-मध्यन्धी धारणाएँ फिट नहीं होती।

तब उर्दू का विकास क्या साम्प्रदायिक कारणों से हुआ? या उर्दू हमारी जातीय भाषा थी और उसके मुकाबले में हिन्दी का विकास साम्प्रदायिक कारणों से हुआ?

उर्दू का बोलचालबाना रूप वही था प्रायः वही है जो हिन्दी का है। इस रूप का एक नाम खड़ी बोली है। इस बोलनेवाले हिन्दू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई अनेक धर्मों के लोग हैं। इस रूप को न तो मुसलमानों ने जन्म दिया, न उसे अवध और बिहार में फैलाने में एकमात्र उन्होंने भाग लिया। फारसी के राजभाषा रहने के कारण इस खड़ी बोली में फारसी के सँकड़ो शब्द आये। फारसी के माध्यम से सँकड़ा अरबी शब्द भी खड़ी बोली में आये। उर्दू के समर्थकों का कहना है कि उर्दू को संवारने और निखारनेवाले हिन्दू भी थे। यह बात सही है। इन मित्रों को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि उर्दू को संवारने में हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों ने हिस्सा लिया, फिर भी खड़ी बोली का एक दूसरा रूप हिन्दी क्यों विकसित हुआ? प्रेमचन्द जैसे देशभक्त उर्दू प्रेमी लेखकों ने हिन्दी-सेवा क्यों की?

बहुत से उर्दू-प्रेमियों की यह धारणा है कि एक अच्छी खासी मुश्तक़ा जवान बन गई थी, हिन्दीवालों ने एक साम्प्रदायिक आन्दोलन चलाया और अरबी-फारसी के मीठे शब्दों की जगह संस्कृत के भारी-भरकम शब्द रखकर एक नकली जवान गड़ती। उसी साम्प्रदायिक भाषा को अब लोग राष्ट्रभाषा कहने लगे हैं। हिन्दुओं की साम्प्रदायिकता और विश्वासघात के कारण उर्दू का गला घोंटा जा रहा है।

ये मित्र दो चीजें भूल जाते हैं। खड़ी बोली में अरबी फारसी के शब्दों की आमद हिन्दुओं और मुसलमानों के मिलन का परिणाम नहीं बल्कि यहाँ फारसी

के राजभाषा बनाये जाने का परिणाम है। फारसी यहाँ के किसी प्रदेश की भाषा नहीं, न वह बाहर से आनेवाले सभी मुसलमानों की भाषा थी, न वह भारत के हिन्दुओं और मुसलमानों के मेल से बनी हुई भाषा थी। ईरान के प्रति अपनी सांस्कृतिक गुलामी के कारण उन सामन्तों ने उसे राजभाषा बनाया जिनकी मातृ-भाषा तुर्की या कोई अन्य गैर-फारसी भाषा थी। फारसी को राजभाषा बनाना यहाँ की भाषाओं के साथ अन्याय करना था। इस अन्याय में मुसलमानों के साथ अनेक हिन्दू सामन्त और उनके आश्रित वर्गचारी भी शामिल थे। किसी विदेशी भाषा को राजभाषा बनाना जातीय उत्पीड़न का एक रूप है। इस तरह के जातीय उत्पीड़न में पूँजीपति ही नहीं, उनमें पहले सामन्त भी भाग ले चुके हैं। इस उत्पीड़न में बहुत-से हिन्दू शामिल हुए किन्तु इनके विपरीत बहुत-से हिन्दू अपनी पहले से चली आती हुई भाषा या भाषाओं के लिए लड़े भी। उन्होंने फारसी के बढ़ते प्रज या अवधी के रचनाएँ कीं। इन हिन्दुओं के साथ बहुत-से मुसलमान भी थे। सामन्त वर्ग और जनसाधारण—इन दोनों की सांस्कृतिक नीति अलग-अलग थी। सामन्त वर्ग मुख्यतः ईरानी संस्कृति का मुँह जोड़ता था, जनसाधारण अपनी भाषा और लोक संस्कृति के विकास में लगा हुआ था।

अंग्रेजों ने अंग्रेजी बादकर जातीय उत्पीड़न को और तीव्र किया। अंग्रेजी और फारसी राजभाषाएँ रहीं लेकिन दोनों के उत्पीड़न में अन्तर था। फारसी एशिया की ही और हमारे पड़ोस की एक भाषा थी। उसे राजभाषा बनानेवाले हिन्दी या ब्रज में कविताएँ करते थे, यहाँ की भाषाओं को प्रोत्साहन देते थे विशेष रूप से संगीत में उन्होंने यहाँ की समूची परम्परा को अपना लिया। उर्दू की तरह संगीत में अरबी-फारसी तानों से लदी हुई शैली का चलन न हुआ। राजभाषा अंग्रेजी की तुलना में राजभाषा फारसी का उत्पीड़न बहुत सीमित था।

सामन्तकाल में शिक्षा का काम पुरोहित वर्ग के हाथ में रहता है। इसलिए शिक्षा के नाम पर संस्कृत या अरबी-फारसी की पढ़ाई होती रही। इस कारण शिक्षित वर्ग में फारसी पढ़े लागे दर्शन, साहित्य आदि की विशिष्ट शब्दावली के लिए फारसी से शब्द लेने लगे। नौकरी के लिए फारसी या उर्दू की जानकारी आवश्यक होती थी, इसलिए हिन्दू-मुसलमान दोनों काफी सख्या में फारसी-उर्दू सीखते थे। किन्तु यह हिन्दू-मुस्लिम-एकता विशेष आर्थिक और सामाजिक कारणों से पैदा हुई थी, इसलिए वह टिकाऊ न हुई।

उर्दू ने दर्शन, साहित्य, राजनीति आदि के लिए, या सम्य व्यवहार के लिए केवल अरबी-फारसी से शब्द लिये। उसके बोलचाल के रूप में तो हिन्दी शब्दों की भरमार थी लेकिन सम्य व्यवहार के रूपों में—‘तशरीफ लाइये, नोश परमाइये’ वाले रूपों में—और साहित्य में जो नये शब्द आये, वे सब-के-सब अरबी-फारसी थे। इस तरह उर्दू के बोलचाल के रूप में तो भाषा की जातीय परम्परा कायम रही लेकिन उसके सांस्कृतिक रूप में वह नष्ट हो गई।

उर्दू ने अपने इस नये विकसित रूप को दो घाटाओं से अलग कर लिया।

एक तो वह हिन्दी की बोलियों—अवधी, ब्रज, बुन्देलखण्डी, मोजपुरी और खड़ी बोली के ही ग्रामीण रूप—से बहुत दूर चली गई। दूसरे, वह भारत की अन्य भाषाओं—बंगला, मराठी, गुजराती आदि—की सामान्य विशेषताओं से दूर जा रही। संस्कृत के कठिन शब्दों के नाम पर उसने उन तमाम शब्दों का बहिष्कार करना शुरू किया जो भारत की अन्य सभी भाषाओं की सामान्य निधि हैं। इस तरह उर्दू-प्रेमियों ने यहाँ के हिन्दी-भाषियों से ही अलग-अलग पैदा नहीं किया वरन् बंगला आदि भाषाएँ बोलनेवाले मुगलमानों से भी अलग-अलग पैदा कर लिया।

इसीलिए हिन्दी का आन्दोलन जोर पकड़ता गया, हिन्दू-मुस्लिम-एकता का सीमित आधार रहने पर भी उर्दू अपना स्थान सुरक्षित रखने में सफल न हुई और प्रेमचन्द, बालमुबन्द गुप्त, प्रतापनारायण मिश्र, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, पद्मसिंह शर्मा आदि अनेक लेखकों ने उर्दू से परिचय और प्रेम होते हुए भी हिन्दी की सेवा की। हिन्दी के प्रति गलत धारणाओं के कारण उर्दू प्रेमी सज्जन हिन्दी के सहयोग में कोई आन्दोलन नहीं चला सके। देश के विभाजन के बाद अब उनमें उर्दू को कौमी जवान बनाने का साहस नहीं रहा, उन्होंने पत्नी के कारण उसे इलाकाई जवान बनाने का नारा दिया। उर्दू को पहने-पहाने और उसके व्यवहार के लिए सुविधाएँ होनी चाहिए, हम इस माँग का समर्थन करते हैं। किन्तु अपने बोलचाल के रूप में वह किसी विशेष इलाके की जवान नहीं है, इलाकाई जवान का नारा जातीय अलग-अलग और विघटन का नारा है, इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश और अन्य हिन्दी-भाषी राज्यों से अंग्रेजी जाय, उसकी जगह हिन्दी को राज्यभाषा बनाया जाय, हिन्दी के साथ अल्पसंख्यकों—जिनमें मुसलमानों के साथ कुछ हिन्दू भी गिने जाएँगे—की भाषा के रूप में उर्दू का संरक्षण किया जाय, इस आधार पर हिन्दी-उर्दू-प्रेमी अब भी एक मंच पर संयुक्त आन्दोलन कर सकते हैं।

आगे चलकर क्या होगा ? उर्दू रहेगी या मिट जायगी ? उर्दू का बोलचाल वाला रूप मिट नहीं सकता, क्योंकि वह कुछ शिक्षित व्यक्तियों तक सीमित नहीं है। यह रूप हिन्दी के बोलचाल वाले रूप जैसा है और हिन्दी-लेखक उसे अपनाकर हिन्दी को समर्थ बना सकते हैं। उर्दू का साहित्यिक रूप हिन्दी को काफी प्रभावित कर सकता है, अभी भी कर रहा है। अनेक हिन्दी-कवियों की छन्द-योजना और शैली पर उर्दू का प्रभाव देखा जा सकता है। यह प्रभाव कितना अधिक पड़ता है, यह उर्दूवालों पर भी निर्भर है। उर्दू-लेखक जितना ही अपना सीमित दायरा छोड़कर अपना साहित्य जनता के लिए लिखेंगे और देवनागरी के माध्यम से उस तक पहुँचायेंगे, उतना ही वे हिन्दी के विकास में प्रभावित कर सकेंगे।

हमारी ममक में उर्दू से प्रभावित होकर हिन्दी का बोलचाल वाला रूप पुष्ट होगा और हिन्दी में प्रभावित होकर उर्दू के 'सम्य' अरबी-फारसीवाले रूप में काफी परिवर्तन होगा। यह कहना आवश्यक है कि उर्दू में काफी देशभक्तिपूर्ण

और जनमानस साहित्य है। शाश्वती के कारण साहित्य की विषयवस्तु नहीं बदल जाती। हिन्दी-प्रेमी काफी उर्दू-साहित्य पढ़ते हैं, उर्दू-प्रेमियों को इस विषय में उनमें होड़ करनी चाहिए।

उर्दू की रक्षा करना और उसकी स्वस्थ विवेकताओं से सीखना हिन्दी के हित में है। उसकी बोलचाल का रूप, कहावतें और मुहावरे हमारी भाषा की सम्पत्ति हैं। सैकड़ों शेर या उनमें टुकड़े कहावतों का रूप ले चुके हैं। वे हमारी सांस्कृतिक सम्पत्ति का अंग हैं। उर्दू में अरबी फारसी के शब्द होने में उनमें लिखने-गोलने-वाले देशद्रोही नहीं हो जाते।

दरी दीवार पे हमरत से नजर करते हैं।

खुश रहो अहनेवतन हम तो सफर करते हैं ॥

इस तरह वे शेर उन लोगों में गुणगुनाये थे जिन्होंने अपना रक्त देकर अपनी देशभक्ति प्रमाणित की थी। हमारा उद्देश्य हिन्दीभाषी प्रदेश की सांस्कृतिक एकता को दृढ़ करना, उसके साहित्य को जनता के हित में विकसित करना है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हिन्दी-उर्दू प्रेमी एक दूसरे के निकट आएं, यहां अंग्रेजी की जगह अपनी भाषा प्रतिष्ठित करें और उसमें विकास में मिल-जुलकर योग दें।

स्वर्गीय परसिद्द शर्मा ने अपने 'हिन्दी, उर्दू, हिन्दुस्तानी' वाले प्रसिद्ध भाषण में हिन्दी उर्दू की एकता के सम्बन्ध में कहा था, "कुटुम्ब के बंटवारे की तरह भाषा का यह बंटवारा भी कुटुम्ब-जलह और सम्पत्ति-विनाश का कारण है, बहुत-से सम्पन्न घराने बंटवारे की बदौलत टुकड़े-टुकड़े होकर बिगड़ गये, राज-परिवार भिखारी बन गये यदि हिन्दी-उर्दू दोनों समुक्त परिवार की दशा में आ जाएं, तो फिर इसकी साहित्य सम्पत्ति का सत्कार की कोई भाषा मुकबला न कर सके।" इसमें सन्देह नहीं कि हमारे प्रदेश के हिन्दुओं, मुसलमानों तथा अन्य धर्मवालों में रचनात्मक प्रतिभा की कमी नहीं है। उर्दू किसकी सेवा करेगी? पाकिस्तान के पंजाबियों, बंगालियों, पठानों और सिंधियों की या अपने प्रदेश के लोगों की? यह युग जनतन्त्र का है। हिन्दी उर्दू एक ही जनता की सेवा करेंगी, इसलिए उनका समुक्त परिवार बनना अनिवार्य है। (१९५८)

## जातीय प्रतिद्वन्द्विता और हिन्दी

देश के स्वाधीन होने के बाद जातीयता का भाव तेजी से बढ़ा है। हम गुजराती हैं, बंगाली हैं, मलयाळी या आन्ध्र हैं—अपने प्रदेश, भाषा और सस्कृति से सम्बन्धित इस भाव को हम जातीयता का भाव कहते हैं। कुछ वर्ष पहले पढ़े-लिखे लोगो की बातचीत में एक शब्द अक्सर सुनाई देता था —‘प्रोविन्शल’। जब हम किसी को अपनी भाषा और साहित्य की वेहद बड़ाई करते देखते थे तो कहते थे —ये लोग बड़े प्रोविन्शल होते हैं।

अपनी भाषा, जाति, प्रदेश, उसकी सस्कृति आदि पर गर्व करना बुरी बात नहीं है। इन अनेक जातिगो से ही भारत राष्ट्र की रचना हुई है। इन प्रदेशो की विभिन्न सस्कृतियों से मिलकर ही भारतीय सस्कृति का निर्माण होता है। इसलिए अपने प्रदेश और उसकी सस्कृति को भुलाकर राष्ट्रीयता और भारतीय सस्कृति की बात करना सम्भव नहीं है।

इससे एक परिणाम यह भी निकलता है कि अपनी भाषा और उसके साहित्य को ही श्रेष्ठ समझने का फल देश की प्रगति के लिए हानिकर हो सकता है। हम एक दूसरे से सीखकर, मिल जुलकर आगे बढ़ने के बदले जातीय प्रतिद्वन्द्विता में फँस जाएँगे और अपनी शक्ति का काफी भाग अपनी जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने में व्यय करेंगे। अन्त जातीयता के इस खतरे को स्वीकार करते हुए यह मानना होगा कि उचित मात्रा में जातीयता की चेतना विकास के लिए आवश्यक है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि हिन्दी-भाषियों में—विशेषकर पढ़े-लिखे मध्यवर्ग के लोगो में—यह जातीयता का भाव उचित मात्रा में विद्यमान है या नहीं।

जातीयता की बात चलने पर कुछ मित्र कहते हैं—हिन्दी राष्ट्रभाषा है, हम सारे राष्ट्र की बात सोचते हैं, किसी प्रदेश के बारे में सोचने की सकीर्णता क्यों दिखाएँ ?

देश की परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो हिन्दी-भाषियों में न चाहने पर भी जातीयता का भाव उभार रही हैं। इनमें एक उल्लेखनीय परिस्थिति अहिन्दी-भाषियों से हमारा सम्पर्क है। यातायात के साधनो के विकसित होने और आर्थिक कारणो

से हजारों आदिमियों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाता पड़ता है या अपने प्रदेश में ही अन्य भाषाएँ बोलनेवालों से मिलना पड़ता है। इस जातीय प्रतिद्वन्द्विता का एक बहुत बड़ा केन्द्र बलबत्ता है। इस नगर में हिन्दी का घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। 'भारत मित्र' और 'मतयास' जैम पत्र यहीं से निकले हैं, निराला और उग्र जैसे लेखक यहीं अपनी साहित्य साधना कर चुके हैं। आज भी हिन्दी भाषा और साहित्य की प्रगति में बलबत्ता की भूमिका नगण्य नहीं है। यहाँ आकर हिन्दी-भाषी व्यक्ति को यह बार-बार सुनने को मिलता है कि वह हिन्दुस्तानी है। हिन्दी-भाषी प्रदेश के लिए 'हिन्दुस्तान' शब्द का प्रयोग काफी पुराना है। हिन्दी-भाषियों की चेतना में यह शब्द सारे देश का वाचक ही रहा है। हिन्दी-भाषी प्रदेश का कोई विशेष नाम प्रचलित नहीं है। इस नाम के अभाव में हिन्दी-भाषी जाति का अस्तित्व मिट नहीं जाता। अन्य जातियों के सम्पर्क में आने से हिन्दी भाषी व्यक्ति को विवश होकर सोचना पड़ता है कि उसकी जाति क्या है। ऐसी परिस्थिति में अपनी जातीयता से सम्बन्धित कुछ बातें स्मरण रखना आवश्यक है।

सबसे पहले हिन्दी भाषी जनता में जातीय चेतना के अपेक्षाकृत अभाव पर ध्यान देना चाहिए। जिस समय सारे देश में भाषा के आधार पर प्रान्त अथवा राज्य निर्माण की चर्चा चलती रही है, हमारे प्रदेश में अनेक राज्यों को मिलाकर विशाल हिन्द प्रदेश के गठन का आन्दोलन नहीं चला। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश को ही विभाजित करने का बात कुछ राजनीतिज्ञों में सुनाई दी। अन्यत्र भाषाओं के आधार पर प्रान्त-निर्माण करने से—विशेषकर दक्षिण में—छोटे राज्यों का चित्र सामने आना था। किन्तु हिन्दी भाषियों को एक प्रदेश में समूहित करने से अनेक राज्यों में एक बड़ा राज्य बनता था। विभाजन के बदले स्पष्ट ही देश की एकता दृढ़ होती थी। किन्तु इस ओर किसी राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं दिया। यह स्थिति हमारे प्रदेश में जातीय चेतना के अपेक्षाकृत अभाव का प्रमाण है।

इस स्थिति के अनेक कारण हैं। हिन्दी-भाषी प्रदेश असाधारण रूप से विशाल है। उसमें भारत के किसी भी भाषा-क्षेत्र की तुलना में बोलियों की संख्या अधिक है। इस क्षेत्र में ब्रज, अवधी और मैथिली जैसी बोलियाँ हैं जिनका अपना विशाल साहित्य भण्डार है। अनेक लोगों के मन में अब भी यह दुविधा है कि ये बोलियाँ दरअसल बोलियाँ हैं या हिन्दी से स्वतन्त्र भाषाएँ हैं। यातायात के साधनों का समुचित विकास न होने और उद्योग घन्धों और व्यापार में हमारे प्रदेश के अनेक भागों के पिछड़े रहने से यह जातीय एकता का भाव विशृंखल-सा रहा है। इन बोलियों की समस्या के अलावा हमारे यहाँ हिन्दी-उर्दू की विशेष समस्या रही है। बोलचाल की भाषा के दो शिष्ट या साहित्यिक रूप होने से जातीय गठन में बाधा पड़ती रही है। एक ही दिशा में बढ़ने के बदले सांस्कृतिक शक्तियाँ दो दिशाओं में बँट गई थी। ये परिस्थितियाँ अब धीरे धीरे बदल रही हैं।

इस प्रदेश के इतिहास के बारे में दो-चार बातें उल्लेखनीय हैं। संस्कृत भाषा और साहित्य से हमारे प्रदेश का घनिष्ठ जातीय सम्बन्ध है। भाषाशास्त्र की दृष्टि



संस्कृत से जितना सम्बन्ध हिन्दी और उसकी बोलियों का है उतना अन्य भारतीय भाषाओं और उसकी बोलियों का नहीं। संस्कृत साहित्य के विशाल भण्डार में भारत के सभी प्रदेशों के विद्वानों ने अपनी ज्ञानराशि संचित की है। फिर भी इस साहित्य के अधिकांश भाग की रचना उन लोगों ने की है जो वर्तमान हिन्दी-प्रदेश के निवासी थे। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश के साहित्य के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है।

आगे चलकर तुर्की बोलनेवाली अनेक जातियाँ यहाँ आईं। पश्तो, फारसी आदि अन्य विदेशी भाषाएँ बोलनेवाले जन भी यहाँ आये। एक-दो पीढ़ी के बाद वे अपनी पूर्व जातीयता खोकर यहाँ के लोगों में घुल मिल गए। इसका एक रोचक प्रमाण बाबर-वंश में तुर्की भाषा का गायब होना है। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी किन्तु उसके वंशज घर में तुर्की न बोलते थे। फारसी उनकी मातृभाषा नहीं, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षत्र में व्यवहार के लिए स्वीकार की हुई वह एक विदेशी भाषा थी—यद्यपि यह एशिया की ही भाषा थी और संस्कृत से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध था। सभी मुसलमानों की भाषा फारसी नहीं थी—यह तथ्य स्मरण रखना चाहिए। भारत के विभिन्न भाषा क्षेत्रों में मुसलमानों की वही भाषा थी जो वहाँ के हिन्दुओं या अन्य धर्मवालों की थी। इसलिए यह समझना कि हिन्द-प्रदेश के मुसलमान किसी फारसी बोलनेवाली जाति के थे अथवा उनकी भ्रमल जातीयता आज तक सुरक्षित है, सही नहीं है।

तीसरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य १८५७ के स्वाधीनता संग्राम से सम्बन्धित है। भारतीय जातियों का परस्पर सम्बन्ध सौ वर्ष पहले आज से भिन्न था। १८५७ में आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से हिन्द-प्रदेश भारतीय जीवन की घुरी था। सन सत्तावन का स्वाधीनता-संग्राम हिन्द-प्रदेश तक सीमित नहीं था। पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, हैदराबाद आदि प्रदेशों में भी संघर्ष हुए किन्तु मुख्य समरभूमि दिल्ली, झाँसी और शाहाबाद के विशाल त्रिकोण से सम्बद्ध थी, इसमें सन्देह नहीं। सन् सत्तावन के संग्राम की मुख्य शक्ति हिन्द-प्रदेश की हिन्दू-मुसलमान जनता थी। अंग्रेज साम्राज्यवादियों ने यहाँ के नगरों को उजाड़ डाला, यहाँ का व्यापार नष्ट कर दिया, भयंकर नरसंहार द्वारा उन्होंने यहाँ की जनता को वस्तु और आनन्दित करने में कुछ उठा न रखा। तब से जातीय संतुलन बदल गया। सस्या में विशाल होने पर भी आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से हमारी जाति बहुत-कुछ पिछड़ी रही। यह स्थिति धीरे-धीरे बदल रही है।

भारत की अनेक समृद्ध भाषाओं की तुलना में हिन्दी गद्य का विकास विलम्ब से हुआ। खड़ी बोली का सिष्ट और सुसंस्कृत रूप पहले उर्दू के माध्यम से सामने आया। यदि हिन्दी गद्य का स्वतन्त्र विकास न होता, यदि उर्दू वास्तव में हमारी जातीय भाषा की भूमिका पूरी कर पाती तो हमारा गद्य-साहित्य आज बहुत समृद्ध होता। किन्तु हिन्दी शब्दों के बहिष्कार और फारसी-अरबी से ज्यादा शब्द उधार लेने के कारण उर्दू का विकास भारत की अन्य भाषाओं से अलग एक

निराली दिशा में हुआ। उर्दू में केवल दरबारी साहित्य नहीं है, खड़ी बोली के इस साहित्यिक रूप में राष्ट्रीय भावना और नये युग की चेतना प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। फिर भी शब्द-भण्डार की विविधता के कारण वह हमारे जनपदों की बोलियों से दूर होती गई और हिन्दी गद्य का विकास अनिवार्य हो गया। यह प्रसन्नता की बात है कि उर्दू की बहुत सी पुस्तकें देवनागरी अक्षरों में छप रही हैं और हिन्दी साहित्य से सम्बन्धित बहुत सी पुस्तकें उर्दू में निकली हैं। इससे हमारी भाषा के दोनों साहित्यिक रूप एक-दूसरे के निकट आते हैं और एक मिली-जुली साहित्यिक भाषा की ओर बढ़ने की सम्भावनाएँ उत्पन्न होती हैं।

जातीय प्रतिद्वन्द्विता का सामना करने के लिए यह आवश्यक है कि हिन्दी के सरल और मुहावरेदार रूप को ज्यादा-से-ज्यादा काम में लाया जाय। विशेष रूप से कथा साहित्य में भाषा का साफ-सुधरा रूप आना जरूरी है। हिन्दी कथाकार जान बूझकर कठिन भाषा नहीं लिखते। लेकिन सरलता ही काफी नहीं है। बाल-मुकुन्द गुप्त और प्रेमचन्द की शैली ही की तरह भाषा इतनी आकर्षक होनी चाहिए कि पाठक स्वतः उसकी ओर खिंचें। सम्स्कृत शब्दावली का प्रयोग करने से सारे भारत में हिन्दी लोकप्रिय हो जाएगी—यह धारणा कथा साहित्य पर निगाह डालने से मिथ्या साबित होती है। हिन्दी और अहिन्दी-प्रदेशों में उन्हीं कथाकारों की रचनाएँ अधिक पढ़ी जाती हैं जो सरल और मुहावरेदार भाषा लिखन में सबसे आगे हैं।

आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास विलम्ब से हुआ, फिर भी यह विकास असाधारण वेग से हुआ है। पिछले साठ-सत्तर वर्षों में हिन्दी ने प्रेमचन्द जैसे उपन्यासकार, निराला जैसे कवि, प्रसाद जैसे विचारक, कवि और नाटककार, बालमुकुन्द गुप्त जैसे व्यंग्य-लेखक, हरिश्चन्द्र और बालकृष्ण भट्ट जैसे पत्रकार, महावीरप्रसाद द्विवेदी जैसे आलोचक और सम्पादक, बृन्दावनलाल वर्मा जैसे ऐतिहासिक उपन्यासकार उत्पन्न किए हैं। इन सबकी रचनाएँ न केवल हिन्दी साहित्य धरन भारतीय साहित्य के इतिहास में उल्लेखनीय रहेंगी। साठ-सत्तर वर्ष की छोटी अवधि में हिन्दी साहित्य की कुछ जातीय विशेषताएँ उभरकर सामने आती हैं। इनमें प्रमुख विशेषता है जिन्दादिली। भारतेन्दु युग के साहित्यकारों की जिन्दादिली का कहना ही क्या? भयानक कठिनाइयों का सामना करने पर भी वे अपनी विनोदप्रियता और उत्साह की रक्षा कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दी में हास्यरस का अभाव है लेकिन हिन्दी का शायद ही कोई लेखक हो जो व्यंग्य विनोद से पूरी तरह बचकर सदा गम्भीर बना रहा हो। गम्भीर आलोचक रामचन्द्र शुक्ल तक 'रीतिवादी कवियों की चर्चा होने पर अपनी विनोद-प्रियता का दमन न कर पाते थे। छायावादी लेखक निरालाजी के रेखाचित्रों—'देवी', 'चतुरी चमार' आदि—और अनेक आलोचनात्मक निबन्धों—'कला के विरह में जोशीबन्धु' आदि—में उनका व्यंग्य-विनोद देखते ही बनता है। प्रेमचन्द ने कथा साहित्य में—विशेषकर उनकी कहानियों में—उनका व्यंग्य अन्तर्धारा

रे समान प्रवाहित है। हम कह सकते हैं कि जिन्दादिली हिन्दी-साहित्य की एक जातीय विशेषता है।

दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता हिन्दी लेखकों का राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन से सम्बन्ध, विशेषकर ग्रामीण जीवन से उनका गहरा सम्बन्ध है। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उनके युग के अधिकांश लेखक देश में स्वाधीनता-प्रेम और नई राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करनेवाले थे। किसान-जीवन से प्रेमचन्द का कितना गहरा सम्बन्ध था, इसे सभी लोग जानते हैं। इसी कारण वे भारतीय साहित्य में एक नये यथार्थवाद की प्रतिष्ठा कर सके। प्रसाद जैसे साहित्यकार ने भी 'तितली' में प्रेमचन्द के समान किसानों का चित्रण किया। ऐतिहासिक उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा की रचनाओं में बुन्देलखण्ड की लोक-संस्कृति का वैभव देखने को मिलता है। नागार्जुन जैसे लेखकों ने इस परम्परा को सुरक्षित रखा है। अमृतलाल नागर ने निम्न मध्यवर्ग और ध्वस्त होती हुई सामन्ती संस्कृति के अनुपम चित्र देकर इस यथार्थवाद को व्यापक और प्रशस्त बनाया है। हिन्दी साहित्य की मुख्य धारा समाज निरपेक्ष न होकर समाज से पूर्णतः सम्बद्ध है। हिन्दी साहित्य का यह यथार्थवादी पक्ष उसका सबल पक्ष है और हम उस पर उचित अभिमान कर सकते हैं।

हिन्दी साहित्य की इस प्रगति और जातीय प्रतिद्वन्द्विता में हिन्दी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई कविता से सन्तोष नहीं किया जा सकता। यह धारा अन्तर्मुखी, सामाजिक जीवन की उपेक्षा करनेवाली और बलात्मक सौन्दर्य से हीन है। हिन्दी को हास्यास्पद बनाने के लिए पाश्चात्यिक सन्दावली के कुछ नमूने और नई कविता की कुछ खडित पंक्तियाँ उद्धृत करना काफी होता है। नई कविता के समर्थक वर्तमान काल में हिन्दी के जातीय और राष्ट्रीय दायित्व को पहचानते हैं, यह नहीं कहा जा सकता। आधुनिक हिन्दी कविता को समृद्ध करने-वाले ऐसे बहुत-से कवि हैं जो नई कविता के रंग-ढंग से दूर हैं। फिर भी यह मानना होगा कि दिनकर, सुमन, नरेन्द्र के बाद के कवियों की पीढ़ी उतनी समर्थ नहीं है। आधुनिक हिन्दी कविता की तुलना में हिन्दी कथा-साहित्य आगे बढ़ा हुआ है।

हिन्दी पढ़ने-लिखनेवाले अहिन्दी-भाषियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वे जब हिन्दी पढ़ते हैं तब अपनी भाषा के साहित्य से हठात् उसकी तुलना भी करते हैं। उनका दृष्टिकोण हमसे अधिक आलोचनात्मक होता है। ऐसे लोगों की संख्या निश्चित भविष्य में और भी बढ़ेगी। इसीलिए जातीय प्रतिद्वन्द्विता के इस युग में हिन्दी लेखकों का दायित्व बहुत बढ़ गया है। साहित्य के हर क्षेत्र में उनसे असाधारण परिश्रम की अपेक्षा है। आधुनिक साहित्य के विकास में हम कुछ देर से शामिल हुए हैं। विलम्ब से होनेवाली क्षति पूरी करनी है। हमारी जाति संख्या में भारत की सभी जातियों से बढ़ी है और विश्व की तीन-चार भाषाओं में—जिनके बोलनेवालों की संख्या सबसे अधिक है—हिन्दी भी है। परिमाण से

सन्तोष न करके उसे गुणात्मक रूप से समृद्ध करना हमारा कर्तव्य है। व्यापार के प्रसार से हिन्दी में पुस्तक प्रकाशन गूब बढ़ा है। शोध प्रवन्धों से लेकर उपन्यासों तक संबन्धी पुस्तकें हर साल प्रकाशित होती हैं। जल्दी लिखने और पुस्तकें छापने का मोह अनेक लेखकों की सीखता है। साधना के बिना साहित्य का स्तर ऊँचा नहीं हो सकता। पुस्तकों की भारी सरफा साहित्य की गरिमा का प्रमाण नहीं है। यदि सम्भव हो तो प्रत्येक हिन्दी लेखक को कुछ दिन के लिए अपना प्रदेश छोड़कर किसी अन्य भाषा क्षेत्र में जाना चाहिए। वहाँ की साहित्यिक गतिविधियों से परिचित होना चाहिए, छिद्रान्वेषण के बदले वहाँ की अच्छी बातें सीखने का प्रयत्न करना चाहिए और धैर्य से हिन्दी के सम्बन्ध में अहिन्दी भाषियों की राय सुननी चाहिए। इससे आत्मगन्तोष की शलत भावना कम होगी और नई लगन से साहित्य साधना करने की प्रेरणा मिलेगी। देश की वर्तमान परिस्थितियों में केवल हिन्दी भाषी प्रदेशों तक—उनमें भी केवल बिहार या उत्तर प्रदेश तक और इनमें भी अक्सर इलाहाबाद, बनारस या पटना तक—अपना दृष्टिकोण सीमित करके साहित्यकार बिगेष प्रगति नहीं कर सकते। अपनी जातीय सत्त्वृति पर उचित गर्व करते हुए उस गर्व की अहंकार और दम्भ में परिवर्तित होने से बचाते हुए, भारत की सभी जातियों में सद्भावना और मैत्री को बढ़ाते हुए एक उदार दृष्टिकोण के आधार पर हम अपने प्रदेश के साथ सम्प्रदेश की प्रगति में सहायक हो सकते हैं।

(१९५६)

## राष्ट्रभाषा अंग्रेजी

सर्व-प्रभुत्व-सम्पन्न भारतीय गणराज्य की लोकसभा में पिछले महीने इस प्रश्न पर दिलचस्प बहस हुई कि अंग्रेजी को भारत की एक राष्ट्रभाषा माना जाय या नहीं। हिन्दी में जब हम राष्ट्रभाषा की बात करते हैं तब उसका अर्थ यह होता है कि सारे राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में परस्पर व्यवहार की भाषा। पहले अंग्रेजी भाषा के माध्यम में भारतीय समस्याओं पर विचार करनेवाले विद्वान् इसी अर्थ में (अथवा प्रायः इस अर्थ में) 'द नेशनल लैंग्वेज' की चर्चा करते थे। लेकिन अब वही या उनमें से अनेक विद्वान् 'ए नेशनल लैंग्वेज' की बात करने लगे हैं अर्थात् भारत राष्ट्र में जितनी भाषाएँ बोली जाती हैं, वे सभी राष्ट्र के अन्दर ही बोली जाने से राष्ट्रभाषाएँ हैं।

एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकें मँगाना का काम अर्थशास्त्र के एक आचार्य को सौंपा गया। वह अंग्रेजी के लिए निर्धारित खर्च भी अर्थशास्त्र की पुस्तकों के लिए खर्च कर देते थे। आपत्ति करने पर उन्होंने उत्तर दिया—आप देखते नहीं, ये अर्थशास्त्र की पुस्तकें भी तो अंग्रेजी में लिखी हुई हैं।

उसी तरह राष्ट्र में जो भाषा भी रुही बोली जाय, वह राष्ट्रभाषा है।

वस्तुतः राष्ट्र के लिए अंग्रेजी में कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेशन और नेशनल के लिए राष्ट्र और राष्ट्रीय शब्दों का प्रयोग होता है किन्तु इस प्रयोग को उचित मानें तो 'मल्टीनेशनल कंट्री' का अनुवाद बहुराष्ट्रीय राष्ट्र होगा (अर्थात् एक देश में अनेक राष्ट्र हैं)। हिन्दी में राष्ट्र शब्द देश के समकक्ष है, उससे घटकर नहीं है। यह भी हिन्दी का दोष है कि अंग्रेजी जैसी समृद्ध भाषा में हिन्दी जैसी दरिद्र भाषा के राष्ट्र शब्द का कोई नया-तुला पर्याय नहीं है। और हो भी क्यों? राष्ट्र कहते ही कुछ दकियानूसीपन की गन्ध नहीं आती क्या जैसे हिन्दी कहते ही देहातीपन की बू आने लगती है?

अंग्रेजी। इंग्लिश। नेशन। कितने साफ-मुथरे शब्द हैं। मुँह से निकलते ही चेहरा खिल उठता है। इसलिए अंग्रेजी 'ए नेशनल लैंग्वेज' भी है, 'द नेशनल लैंग्वेज' भी है। वह भारत राष्ट्र में बोली जानेवाली अनेक भाषाओं में एक है और

इन अनेक में एकमात्र नेव भाषा है।

ऐंग्लो इंडियन-कुल-कमल दिवाकर श्री फ्रैंक ऐन्टनी एम० पी० ने लोकसभा में कहा कि कुछ लोग अंग्रेजी का नाश करने पर तुले हुए हैं। इनमें अग्रगण्य वे हैं जिनकी मातृभाषा हिन्दी है। ये हिन्दी प्रेमी समझते हैं कि हिन्दी तब तक राज-वाज की भाषा न बनेगी, जब तक अंग्रेजी का नाश न किया जाएगा।

श्री ऐन्टनी ने यह नहीं कहा कि अंग्रेजी को राजभाषा बनाये रखने के लिए हिन्दी का नाश करना जरूरी है। किन्तु इससे पहले अनेक अवसरों पर वह हिन्दी के लिए लोकसभा में जिन विशेषणा का प्रयोग कर चुके हैं, उनसे यही ध्वनि निवसती है।

श्री ऐन्टनी इतिहास में भी दखल रखते हैं। उन्होंने राष्ट्रभाषा-समस्या के दायरे से बाहर निकलकर भारतीय इतिहास का विहंगावलोकन करते हुए घोषित किया, “द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिफोर द ऐडवेंचर ऑफ इंग्लिश वाज द हिस्ट्री ऑफ ट्राइबलिज्म।” (६ अगस्त, १९५६ के टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित विवरण)। अर्थात् अंग्रेजों के आने से पहले भारत का इतिहास कबीला का इतिहास था।

कबीला को शिक्षित करने, उन्हें राष्ट्रीय एकरता का पाठ पढ़ाने, उनकी आदिम बर्बरता को दूर करने का काम अंग्रेजों ने किया। अंग्रेजी शासकों को राष्ट्रीयता से इनका प्रेम था कि यहाँ से विदा होना समय वे एक के बदले दो राष्ट्र बना गए।

श्री फ्रैंक ऐन्टनी ने अपनी सहज विनम्रता से यह नहीं कहा कि सम्यता के बाहन अंग्रेज शासकों के नामलवा और पानीदेवा ऐंग्लो-इंडियन सम्प्रदाय के ऐन्टनी जैम नेता अभी वचे रह गए हैं।

लेकिन ऐन्टनी महोदय देशभक्ति में किसी में पीछे नहीं। आज जब देश के अनेक वर्णधार जनता को यह समझाते नहीं थकते कि अंग्रेजों की पुरानी अत्याचार-गाथा भूल जाओ, नये सिरे से गत्य और अहिंसा के आधार पर उनमें मैत्री-सम्बन्ध कायम करो, तब भारतीय गणतन्त्र की लोकसभा में श्री फ्रैंक ऐन्टनी ने माननीय सदस्यों को सूचित किया कि वह ऐंग्लो इंडियन सम्प्रदाय का इतिहास लिख रहे हैं और वे ही जानते हैं (उनका दिल जानता है) कि अंग्रेजी राज ने जितना नुकसान ‘ऐंग्लो-इंडियन कम्युनिटी’ का किया है, उतना और किसी का नहीं। उन्होंने संवेद निवेदन किया कि १९०६ से पहले ऐंग्लो-इंडियन कम्युनिटी के सदस्य मैनिंग और थ्रेण्टी (मर्चेंट प्रिसेज) होत थे (और इस रूप में भारत राष्ट्र की सेवा करते थे)। किन्तु १९०६ के बाद वे उस गौरवशाली स्थान से हटा दिये गए। श्री ऐन्टनी के अनुसार अंग्रेज शासकों को संदेह था कि वे हिन्दुस्तानियों में मिलकर किसी दिन विद्रोह कर देंगे।

उदारमना, मुमस्वृत अंग्रेज शासकों की राज्यसत्ता का आधार शायद इतना व्यापक था कि उन्हें भारतीय जनता से ही भय नहीं था, बल्कि उनमें भी सकट की

भाषका थी जो अपने को अंग्रेजों का वशज मानने में गर्व और गौरव का अनुभव करते थे, भले ही अंग्रेज स्वतन्त्रता-सम्मिश्रण का सन्देह धरके घृणा से मुँह फेर लेते हों। ऐंग्लो-इंडियनों से विद्रोह की शका निर्मूल थी। १८०६ के पचास साल बाद, सन् अठारह सौ सत्तावन के साल अनेक ऐंग्लो इंडियन देशभवतो ने, हैदराबाद के निजाम और नेपाल के राना जगबहादुर जैसे दूरदर्शी राजनीतिज्ञों के समान ही, प्रगतिशील अंग्रेजों की राज्यसत्ता फिर से स्थापित कराने में एड़ी-चोटी का पसीना एक कर दिया। १९३२ में हर्बर्ट ऐलिय स्टार्क नाम के एक ऐंग्लो-इंडियन सज्जन ने 'द काल ऑफ द ब्लड' (खून की पुकार) नाम की पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने १८५७ में ऐंग्लो-इंडियनों की राष्ट्र-सेवा का चित्रण किया था। इसकी भूमिका में उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया था कि १७८६ के बाद (श्री ऐन्टनी के दिए हुए सन् से कुछ वर्ष पहले) ऐंग्लो-इंडियनों को इस बात की मनाही कर दी गई थी कि वे जमीन खरीदें या फौज और सिविल सर्विस में ऊँची जगह पाएँ। फिर भी खून की पुकार तो खून की ही है, विशुद्ध अंग्रेज उसे कंसा भी खून समझें। स्टार्क ने गर्व से लिखा है कि लामार्टीनियर बॉलिव, लखनऊ के (ऐंग्लो-इंडियन) छात्रों ने रेजीडेंसी के घरे के समय अंग्रेज सैनिकों के साथ रहकर उनकी अनुपम सेवा की, उनकी जूठी रखावियाँ और गन्दे कपड़े धोय, चक्की पीसी, खाना पकाया और पखा खीचा। इस सेवा का प्रस्कार छात्रों को क्या मिला, मालूम नहीं, लामार्टीनियर के प्रिंसिपल महोदय को ताल्लुकदार अवश्य बना दिया गया।

१८५७ में भारतीय सेना के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध लड़नेवाले कुछ गोरे अपसर भी थे। उनका उल्लेख करते हुए स्टार्क ने सगर्व लिखा है—अंग्रेजों से अंग्रेज तक लड़े, नहीं लड़े तो बेबल-ऐंग्लो इंडियन।

श्री फ्रैंक ऐन्टनी भी कह सकते हैं—अंग्रेजों ने मी चाहे हिन्दी को राजभाषा स्वीकार कर लिया हो, नहीं स्वीकार किया तो उन-जैसे ऐंग्लो-इंडियनों ने।

श्री ऐन्टनी के भाषण के समय चारों ओर से सदस्यों ने उस पर आपत्ति की और अपना तीव्र विरोध प्रकट किया। किन्तु प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के भविष्य के सम्बन्ध में श्री ऐन्टनी को यथेष्ट आश्वासन दिया। कहना चाहिए, आश्वासन यथेष्ट से भी अधिक था क्योंकि प्रधानमन्त्री के भाषण के बाद श्री ऐन्टनी ने सन्तोष प्रकट करते हुए कहा कि उन्होंने जितने की आशा की थी, उससे भी अधिक प्रधान मन्त्री से उन्होंने पाया।

प्रधान मन्त्री अत्यन्त उदारचेता व्यक्ति हैं। सकीर्णता उनके स्वभाव के प्रतिकूल है। उनका अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण जितना व्यापक है, उतना ही और उससे कुछ अधिक ही व्यापक उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण है। विशेष रूप से उनका हिन्दी-सम्बन्धी दृष्टिकोण इतना व्यापक हो गया है कि अब वह कोण न रहकर रेखा बन गया है जिसमें चौड़ाई क्षीण होकर लम्बाई में परिवर्तित हो गई है।

भारत में कुछ लोग हिन्दी के हिमायती हैं, कुछ लोग अंग्रेजी के। पचशील का तकाजा है कि दोनों का शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व कायम रहे। जैसे भारत की

स्वाधीनता-रक्षा के साथ राष्ट्रीय सरकार ने देश में ब्रिटिश पूंजी के मुनाफे की रफ़ा का भार भी लिया है, उसी तरह क्या अंग्रेज़ी का राजभाषा बना रहना हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनने में सहायक नहीं हो सक्ता ? अगली चीज़ है दोनों के अलग-अलग क्षेत्रों को पहचानना। यह पहचान हासिल हो तो सघर्ष की नींव ही न आए। भाषाएँ 'ओवरलैप' करती हैं, ओवरलैप करने से प्रधान मन्त्री का आशय क्या है, यह जितना हम समझते हैं, उतना अलवार पढ़कर आप भी समझ सकते हैं। 'लैंग्वेज डू ओवरलैप'—प्रधान मन्त्री के इस भाषाविज्ञानी मूल की व्याख्या करना हमारा काम नहीं।

प्रधान मन्त्री ने बताया कि पहले अंग्रेज़ी एक लादी हुई भाषा थी। फिर भी उसने आधुनिक ज्ञान के द्वार खोल दिये। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वर्तमान समय में जो लोग उस लादी हुई भाषा का लदाव अस्वीकार करके स्वेच्छा से उसे छोड़ते हैं, वे और भी जल्दी आधुनिक ज्ञान भण्डार तक पहुँच जाएंगे। उनसे लिए द्वार खोलने का सवाल भी न उठेगा, वे सिखी या रोशनदान से ज्ञान मन्दिर के आँगन में बूढ़ पड़ेंगे।

प्रधानमन्त्री ने कहा कि ऐंग्लो-इंडियन सम्प्रदाय को पूर्ण अधिकार है कि वह अंग्रेज़ी के माध्यम से शिक्षा पाये। इसके सिवा उन्होंने एक बात मार्क्स की और नहीं—'ऐंग्लो-इंडियन मुँह की गिविन एबी पेंसिलिट्री टु डिलेप इंग्लिश लैंग्वेज।' ऐंग्लो इंडियनों को यह पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए कि वे अंग्रेज़ी भाषा को विकसित कर सकें। अभी तक हम सुनते थे कि हिन्दी को ही भाषा-रूप में विकसित करना आवश्यक है, वह पिछड़ी हुई भाषा है, उसका भाषागत अथवा साहित्यिक महत्त्व नहीं है, महज सुविधा के लिए, बोलनेवालों की विद्याल सख्या के ही कारण उस राष्ट्रभाषा या राजभाषा बनाना है, इसलिए उस विकसित करना होगा। किन्तु सर्वज्ञान समृद्ध, आधुनिकता की खान, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महाभाषा अंग्रेज़ी को 'डिवेलप' कराना जरूरी है, और वह भी भारत के ऐंग्लो-इंडियन सम्प्रदाय द्वारा—इसमें बड़ी सूझ-बूझ की बात लोकसभा में स्वयं प्रधान मन्त्री भी आगे कहेंगे, इसमें सन्देह है।

प्रधान मन्त्री ने अपनी नीति के समर्थन में कहा कि पांडिचरी प्रदेश ('पांडि-चेरी-टेरीटरी') की भाषा फ्रांसीसी है।

भले ही इन पांडिचेरी प्रदेश की भारतीय जनता की भाषा फ्रांसीसी न हो, लेकिन अगर एक यूरोपीय भाषा होने के नाते वहाँ उसे राजभाषा का पद मिल सकता है, तो सारे भारत में अंग्रेज़ी को राजभाषा—अथवा हिन्दी के साथ अतिरिक्त राजभाषा (और व्यवहार में एकमात्र राजभाषा)—का पद क्यों नहीं दिया जा सकता ?

प्रधानमन्त्री ने कहा कि जो प्रदेश पुर्तगालियों के अधिकार में है, एक दिन वह भी भारत राज्य में मिल जाएगा। तब पुर्तगाली भी 'ए लैंग्वेज ऑफ इंडिया' (भारत की एक भाषा) होगी।



इससे स्पष्ट परिणाम निकला कि संविधान में उल्लिखित भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी का नाम न होने पर भी वह है भारतीय भाषा ही !

लोकसभा के एक दक्षिण भारतीय सदस्य ने श्री ऐन्टनी के समर्थन में कहा कि दो शताब्दियों में भारत का बुद्धिजीवी वर्ग अंग्रेजी को अपनी भाषा के रूप में अपनाये हुए है। देश की एकता के लिए यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा अर्थात् अंग्रेजी हो। प्रधान मंत्री ने माननीय सदस्य की बात की चर्चा करते हुए कहा कि वह स्वयं भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम एक ही भाषा अर्थात् अंग्रेजी रहे लेकिन उन्हें किसी तरह के दबाव से नफरत है; इन सब चीजों का सहज विकास ही वाछनीय है। उन्होंने कहा कि हिन्दी के हिमायती जब दूसरों पर हिन्दी लादना चाहते हैं, तो वह भी नापसन्द है।

नतीजा यह कि इन दो नापसन्दगियों के बीच अंग्रेजी हमारी पसन्द से, बिना किसी पर लदे हुए, राजभाषा बनी रहती है।

अंग्रेजी के राजभाषा न रहने में क्या होगा ? प्रधान मंत्री के अनुसार अंग्रेजी आधुनिक ससार की ओर खुलनेवासी बड़ी खिड़की है। 'बी डेयर नॉट क्लोज दैट विण्डो। इफ बी क्लोज इट, इट इज ऐट द पेरिल ऑफ अवर प्यूचर।' (यह खिड़की हमें हर्गिज बन्द न करनी चाहिए। उसे बन्द किया तो हमारा भविष्य मकट में पड़ जाएगा।)

भारत का भविष्य यहाँ की निन्यानबे फीसदी जनता पर निर्भर नहीं है। भविष्य निर्भर है डेढ़ फीसदी अंग्रेजी जाननेवालों पर, जो इस खिड़की से आधुनिक ससार की ओर झाँकते हैं। इन डेढ़ फीसदी में भी बहुतों को खिड़की तक पहुँचने और बाहर झाँकने का सौभाग्य नहीं मिलता। अंग्रेजी व्याकरण, उसके बाद उच्चारण और उससे भी बढ़कर शब्दों के लेखन की ऐसी बाधाएँ हैं जो उन्हें झाँकने से रोकती हैं। इसी कारण कुछ प्रदेशों के मन्त्री और उपमन्त्री तक बहुधा अपने अंग्रेजीवाँ सेक्रेटरियों की पीठ का सहारा लेकर ही खिड़की से झाँकते हैं। झाँककर वे क्या पाते हैं, यह कहना कठिन है क्योंकि जनता से अधिक भाग्य-नक्षत्रों पर भरोसा होने के कारण वे ज्योतिष-शास्त्र को आधुनिक विज्ञान की चरम उपलब्धि मानते हैं।

प्रधानमन्त्री की युक्तिपूर्ण बातों कुछ समाचारपत्रों की समझ में नहीं आईं। इनमें ऐसे पत्र भी हैं जो हिन्दी के समर्थकों की आलोचना करते हैं और जिनकी भाषा अंग्रेजी है। उदाहरण के लिए, 'टाइम्स ऑफ इंडिया' ने १४ अगस्त की सम्पादकीय टिप्पणी में लिखा था, "राजभाषा के सम्बन्ध में लोकसभा की समिति ने अपने अत्यन्त तर्कसंगत विवरण में 'हिन्दी साम्राज्यवाद' के भय को निर्मूल कर दिया था। उसके बाद प्रधानमन्त्री द्वारा अधिक आश्वासन की अपेक्षा नहीं थी। जो भय दूर हो चुके थे, उन्हें फिर से दूर करने के प्रयास में श्री नेहरू ने ऐसी बातें कही जो उन चरम-पणियों के हाथ मजबूत करती हैं जो इस स्थिति को अस्वीकार करते

हैं कि हिन्दी देश की राजभाषा हो।

यह अवधार मानता है कि आधुनिक समाज का देखने के लिए अंग्रेजी बिड़की आवश्यक है लेकिन उस सेद है कि श्री नहम् आवश्यकता से अधिक आश्रयमान दे गए। और हम मद है प्रमचन्द की बुद्ध पर जो अंग्रेजी का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व न समझकर उसे राष्ट्रभाषा माननेवाले देशभक्ता के लिए वह गए थे—' वे इतनी धुन-दी पर पहुँच गए हैं कि नीचे का धून और गर्मी उन पर कोई असर नहीं कर सकती। वे मुश्किलव हवा में लटके रह सकते हैं। लेकिन हम सब तो हजार कोशिश करने पर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हम तो इसी धूल और गर्मी में जीना और मरना है। इटलीजेंगिया में जो कुछ शक्ति और प्रभाव है वह जनता ही से आता है। उससे अलग रहकर वे हाकिम की मूरत में ही रह सकते हैं। म्वादिम की मूरत में जनता के होकर नहीं रह सकते। उनके अरमान और मसूमे उनके हैं जनता के नहीं। उनकी आवाज उनकी है उसमें जनसमूह की आवाज की गहराई और गरिमा और गम्भीरता नहीं है। वह अपने प्रतिनिधि हैं जनता के प्रतिनिधि नहीं।

(१९५६)

## सोवियत संघ में भाषा-समस्या-समाधान

तोल्स्तोय ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास 'युद्ध और शान्ति' में एक क्लब की चर्चा की है जिसकी स्थापना इस उद्देश्य से की गई थी कि उसके सदस्य रूसी बोलें, जो रूसी न बोलें वह जुर्माना दे। यह संस्था राष्ट्रीयता के आवेश में तब कायम की गई थी जब नैपोलियन मास्को के निकट पहुँच गया था। एक महिला सदस्य बीच में फ्रांसीसी बोलने लगती है और फिर भूल सुधारकर कहती है, आखिर इस बात को रूसी में कैसे व्यवहृत करें। रूस के अभिजात वर्ग की यह फ्रांसीसी-भक्ति भारत के बहुत-से नौकरी-पेशा, नेता-पेशा भद्रजनों की अंग्रेजी-भक्ति से तुलनीय है। समाजवादी क्रान्ति ने यह विदेशी भाषा-भक्ति खत्म कर दी।

समाजवादी क्रान्ति के बाद साम्यवादी नेता इस बात का इन्तजार नहीं करते रहे कि रूसी भाषा विकसित होकर फ्रांसीसी या जर्मन के बराबर हो जाय तब उसे राजभाषा बनाएँगे। उन्होंने रूसी को ही राजभाषा नहीं बनाया, उक्रेनी, जार्जियाई, बेलोरूसी आदि भाषाओं को भी राजभाषा बनाया। सोवियत संघ गणराज्यों का संघ है और प्रत्येक गणराज्य की अपनी राजभाषा है। जो जातियाँ पिछड़ी हुई थी, जिनकी भाषाओं की लिपि नहीं थी, उन्हें भी लिपि-व्याकरण आदि से दूरस्त करके स्वायत्त शासन के कार्यों के लिए चालू किया गया। जैसा कि गांधीजी ने कहा था, भारतीय भाषाओं के पिछड़ेपन की दुहाई देकर अंग्रेजी को बरकरार रखना आलस्य की निशानी है।

विभिन्न जातियों के बीच आपसी व्यवहार और केन्द्रीय राजकाज के लिए कोई भाषा हो या न हो? रूस में जातीय उत्पीड़न तीव्र था, इसलिए लेनिन ने यह नारा दिया कि कोई भी अनिवार्य केन्द्रीय राजभाषा न होनी चाहिए। साथ ही लेनिन ने अपने भाषा-सम्बन्धी लेखों में यह भी कहा कि सम्यक्ष देश में लोग उस जाति की भाषा को आपसी व्यवहार के लिए स्वीकार करेंगे जिसके बोलनेवालों की संख्या ज्यादा होगी। इस तरह केन्द्रीय पार्टियों और केन्द्रीय राजकाज के लिए रूसी भाषा का व्यवहार बराबर होता रहा।

पूँजीवादी बहुजातीय देशों और सोवियत संघ में केन्द्रीय भाषा की स्थिति में

अन्तर है। सोवियत सघ में कानून से रूसी को केन्द्रीय भाषा नहीं बनाया गया, वह स्वेच्छा से स्वीकृत हुई है। स्वेच्छा से स्वीकृत होने का सामाजिक आधार यह है कि किसी जाति के पूंजीपति दूसरी जाति के अधिकारों का दमन करने को नहीं बचे। इससे अलावा रूस में गैर-केन्द्रीय भाषाओं को जितने अधिकार प्राप्त हैं, उतने किसी भी बहुजातीय पूंजीवादी देश में गैर-केन्द्रीय भाषाओं को प्राप्त नहीं हैं। प्रत्येक गणराज्य (या रिपब्लिक) में उसकी अपनी राजभाषा है। स्वायत्त शासन क्षेत्रों में अन्य छोटी जातियों की भाषाओं में राजकाज होता है। युद्धकाल में बालीनिन ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे सैनिकों से उन्हीं की भाषा में बातचीत करें, तभी उनका प्रचार-कार्य सफल होगा। यू० एन० ओ० तक में उन्नैनी सदस्य अपनी भाषा का व्यवहार कर चुके हैं।

सोवियत सघ बहुजातीय देश है किन्तु वहाँ गणराज्यों की सरकारों के अलावा केन्द्रीय सरकार भी है। देश के राजकाज का संचालन करनेवाली पार्टी है जिसका सगठन-सिद्धान्त है जनवादी केन्द्रीयता। स्तालिन जाजिया के थे लेकिन केन्द्रीय शासन और पार्टी-कार्य के लिए रूसी बोलते और लिखते थे। ए० इचेव उन्नैनी हैं लेकिन पार्टी कांग्रेसों आदि में रूसी बोलते हैं। मिर्कोयान आर्मोनियन हैं। उनकी स्थिति भी वही है। रूसी जाने और उसका व्यवहार किये बिना वहाँ कोई राष्ट्रीय नेता नहीं बन सकता। इससे जो निष्कर्ष निकलते हैं, वे भारत के प्रगतिशील नेताओं के ध्यान देने योग्य हैं।

सोवियत सघ में सौ से ऊपर जातियाँ हैं लेकिन इनके सोलह प्रजातन्त्र या गणराज्य ही हैं। प्रत्येक भाषा को लेकर एक राज्य क्यों नहीं बना? इसका कारण यह है कि रूसी नेताओं ने भाषा समस्या को मूल सामाजिक समस्या के अधीन माना है, उससे स्वतन्त्र नहीं। मूल समस्या है, किसान-भूदूरो की मुक्ति की, समाजवाद के विकास की। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से यदि किसी जाति का गणराज्य निर्बल पड़ता है तो उसे दूसरे के साथ मिलकर रहना होगा, अक्षयता उसका अपना स्वायत्त शासन-क्षेत्र होगा जिसमें उसकी अपनी भाषा का व्यवहार जायज होगा। भारत में प्रत्येक भाषा को लेकर एक राज्य बने या न बने—यह प्रश्न मूल सामाजिक समस्या से अलग रखकर हल नहीं किया जा सकता।

सोवियत सघ में प्रत्येक जाति की भाषा को विकास की सुविधाएँ प्राप्त हैं। फिर भी ये अधिकार और जातीय समानता हर जगह सौ फीसदी एक-से नहीं हैं। रूसी भाषा हर नागरिक को सीखनी होती है, रूसी-भाषियों को दूसरी भाषाएँ उसी तरह नहीं सीखनी पड़ती। गणराज्य की भाषा वहाँ के प्रत्येक नागरिक को सीखनी होती है। जिनकी वह मातृभाषा नहीं है, उन्हें भी वह सीखनी होती है। यथा उन्नैनी गणराज्य में उन्नैनी-भाषियों को मातृभाषा के अलावा रूसी सीखनी होगी; वहाँ उजबेक हो तो वे उजबेक के अलावा रूसी और उन्नैनी सीखेंगे। इस तरह हर नागरिक को एक, किसी को दो, किसी को तीन या अधिक भाषाएँ परिस्थिति के अनुसार सीखनी होती हैं।

सोवियत संघ में हर भाषा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम नहीं है। निम्नस्तर के राजकाज और सांस्कृतिक कार्यवाही के लिए मातृभाषा का ही व्यवहार किया जाता है। उच्च शिक्षा का माध्यम बनानेवाली भाषाओं की संख्या सीमित है और इनमें भी जितना उच्च अनुसन्धान और शिक्षा-कार्य रुसी में होता है, उतना अन्य भाषाओं में नहीं। इस बात को ध्यान में रखने से राजस्थानी, पंजाबी आदि भाषाओं के प्रति न्याय करने की समस्या हल की जा सकती है। साथ ही इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि सभी सोवियत विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम रुसी नहीं है। उर्बेन की विज्ञान अकादमी अपना विवरण आदि उर्बेनी में ही प्रकाशित करती है।

मुख्य बात यह है कि सोवियत-विज्ञान जनता की सेवा के लिए है, सोवियत शिक्षा जनता को सुसंस्कृत करके उसे साम्यवाद की ओर लाने के लिए है। पूँजीवादी शोषण को समाप्त कर देने से सोवियत संघ में भाषा और धर्म को लेकर दंगे नहीं होते, सभी जातियाँ परस्पर सहायता और सहयोग का जीवन बिताती हैं। इसलिए बहुराष्ट्रीय भाषा भी संतोषजनक ढंग से हल कर ली गई है।

(१९६१)

## हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता

किसी जाति की भाषा-समस्या पर विचार करते हुए हमें सबसे पहले उसके बोलचाल के रूप पर ध्यान देना चाहिए। क्या बोलचाल के रूप में भी हिन्दी-उर्दू दो भाषाएँ हैं? इसमें सन्देह नहीं कि बहुत बठिन हिन्दी और बहुत कठिन उर्दू बोली जा सकती है, लेकिन आम लोग उन्हें बोलते नहीं। इसलिए प्रेमचन्द का यह कहना ठीक था कि "बोलचाल की हिन्दी और उर्दू प्रायः एक सी है।" उर्दू हिन्दी के सर्वनाम एक है—वह, मैं, तू, हम इत्यादि। हिन्दी-उर्दू की क्रियाएँ एक ही हैं—जाना, सोना, खाना, पीना, करना, मरना, जीना, लिखना, पढ़ना इत्यादि। आजमाना, गुजरना, लरजना जैसी क्रियाएँ बहुत थोड़ी हैं, बुल मिलाकर एक दर्जन से क्यादा नहीं, जो फारसी अरबी शब्दों के आधार पर बनी हैं। वे हिन्दी में मतरुक (उपेक्षित) नहीं हैं। बोलचाल में उनका प्रयोग बराबर होता है। हिन्दी-उर्दू के सम्बन्धवाचक शब्द—मे, पर, से, का आदि—वही हैं जो हिन्दी के। दोनों का मूल शब्द भण्डार भी एक है, लेकिन यही बहुत दिनों तक फारसी के राजभाषा रहने से हिन्दी शब्दों के फारसी या अरबी पर्यायवाची शब्द प्रचलित हो गए हैं—जैसे देश मुल्क, आकाश-आसमान, धरती जमीन, भाप जवान, किसान-काश्तकार, नदी दरिया, रोगी बीमार इत्यादि।

इन शब्दों का व्यवहार बोलचाल की हिन्दी उर्दू में बिना किसी भेदभाव के होता है। देश, आकाश, धरती जैसे शब्द उर्दू-साहित्यकारों की रचनाओं में मिलेंगे और मुल्क, आसमान, जमीन जैसे शब्द हिन्दी साहित्यकारों की रचना में। इसके सिवा हल, बँल, खेत, खलिहान, बोज, जुलाई, बुवाई, बारखाना, मजदूर, काम, छुट्टी आदि हजारों ऐसे शब्द हैं जिनके पर्यायवाची शब्द बोलचाल की भाषा में व्यवहृत नहीं होते, साहित्यिक भाषा में भले होते हों। लखनऊ और हैदराबाद के हिन्दू-मुसलमान बोलचाल की भाषा में फारसी शब्दों का व्यवहार ज्यादा करेंगे, उन्हीं फारसी शब्दों की जगह बिहार और मध्य प्रदेश के मुसलमान हिन्दी या संस्कृत शब्दों का प्रयोग करेंगे। यह स्थानीय भेद हुआ, इससे दो भाषाओं का निर्माण नहीं होता। हिन्दी उर्दू का व्याकरण

एक, वाक्यरचना एक-सी, शब्द-भण्डार और क्रियाएँ एक सी—इसीलिए हिन्दी-उर्दू-भाषियों की दो कोमे नहीं है। उनकी जाति एक है और बोलचाल की भाषा एक है।

हिन्दी-उर्दू में सबसे पहला भेद लिपि का है। लिपि लिखने के काम आती है न कि बोलने के। इसलिए लिपि-भेद को हम बुनियादी भेद नहीं मानते। हिन्दी-उर्दू में दूसरा भेद है शब्द भण्डार का। यह भेद साधारण लोगो की बोलचाल में बिल्कुल नहीं है, पढ़े-लिखे लोगो में बहुत थोड़ा है और भाषा के लिखित रूपों में बहुत ज्यादा है। बोलचाल में जो शब्द सामान्य सम्पत्ति हैं, लिखते समय उनमें भी अलग-अलग करने की प्रवृत्ति देखी जाती है। घरती, आवाश, किसान, नदी, भाषा, रोगी, देश जैसे शब्द उर्दू में कम मिलेंगे, काश्तकार, दरिया, आसमान, जवान जैसे शब्द साहित्यिक हिन्दी में कम मिलेंगे।

लेकिन मूल भेद दूसरा है। दर्शन, राजनीति, साहित्य आदि में जब हमें ऐसे शब्दों की जरूरत होती है, जो किसानों-मजदूरों की बोलचाल में नहीं हैं, तब उर्दू लेखक अरबी-फारसी से उधार लेते हैं, हिन्दी लेखक संस्कृत से। राजनीति-सिपासत, साहित्य भदव, लिपि-रस्मुल्खत, भाषाविज्ञान-तलसानियात, आलोचना तनकीट, अन्तर्राष्ट्रीय वैनुलअकवामी, इतिहास-तारीख, जनतन्त्र-जम्हूरियत, कोश-लुगत—मुख्यतः इस तरह की शब्दावली हिन्दी-उर्दू में अलग-अलग उत्पन्न करती है।

पहले यह समझ लेना आवश्यक है कि हिन्दी-उर्दू का यह अलग-अलग हमारे जातीय विवास के लिए घातक है। पढ़े-लिखे लोगों की शक्ति एक जगह सिमटकर पूरी जाति को आगे बढ़ाने के बदले बिखर जाती है और लिपि के आधार पर पाठक-वर्ग दो हिस्सों में बँट जाता है। यदि भाषा और साहित्य उच्च वर्गों के थोड़े-से पढ़े लिखे आदमियों के लिए ही हो, तो वे चाहे उर्दू में मनोरंजन करें, चाहे हिन्दी में, बाकी जनता इस मनोरंजन से दूर रहेगी। लेकिन सवाल है देश के साधारण लोगो का मेहनत से अन्न पैदा करनेवालों और पंचवर्षीय योजनाएँ पूरी करनेवालों का। भाषा और साहित्य इनके लिए हैं। समाजवादी व्यवस्था में सबसे पहले इन्हीं के लिए परिवर्तन होंगे। तब यह भाषा और लिपि का बँटवारा कब तक चलेगा?

समाजवादी व्यवस्था के निर्माण के लिए जनता का संगठन, उसकी शिक्षा और आन्दोलन जरूरी हैं। यदि एक ही कारखाने के मजदूर दो लिपियों से काम लेते हैं तो इससे उनकी शक्ति कम होगी, उनकी संस्कृति में दरारें पड़ेंगी। इसके सिवा हिन्दुस्तानी जाति दुनिया की सबसे बड़ी जातियों में है। अंग्रेजी बोलनेवाले बहुत हैं, लेकिन वे अनेक जातियों के हैं। एक ही भाषा बोलनेवालों की जाति हमसे सख्या में बड़ी हो सकती है, तो चीनी है। भारत की सभी जातियों में हमारी जाति सबसे बड़ी है, यह निर्विवाद है। ऐसी स्थिति में हमारी भाषा का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व है। स्पष्ट है कि हमारी भाषा अपनी

पूरी ताकत से तभी प्रगति कर सकती है, जब उसमें जाति के सभी तत्वों का सहयोग हो।

हिन्दी उर्दू को एक होना चाहिए—यह हमारे ऐतिहासिक विकास की माँग है। इसके लिए आवश्यक सांस्कृतिक आधार यह है कि साधारण जनता की बोलचाल की भाषा एक है। हमें इस एकता की ओर बढ़ने के लिए मजबूर करनेवाला सामाजिक कारण देश का पिछड़ापन, जनता की गरीबी, समाजवादी निर्माण की आवश्यकता है। इसके सिवा यह भी याद रखना चाहिए कि भारत के हर प्रदेश का सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन अलग अलग रहकर विकसित नहीं होता, वह अखिल भारतीय जीवन प्रवाह की एक धारा है। और उस प्रवाह के साथ ही आगे बढ़ता है। यहाँ की भाषाएँ भी एक-दूसरे को प्रभावित करती रही हैं और करेंगी। भारत के हर जातीय प्रदेश की भाषा और लिपि एक हो, लेकिन हिन्द प्रदेश की दो लिपियाँ और दो भाषाएँ हो, यह सम्भव नहीं है।

उर्दू अलग किसी कोम की भाषा नहीं है, इसलिए उसे इलाकाई जवान मनवाने के आन्दोलन का विरोध करना उचित है। किन्तु वह सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों की साहित्यिक भाषा है, इसलिए उसे पढ़ने-पढ़ाने और उसका व्यवहार करने की सुविधा मिलनी चाहिए। राजभाषा के रूप में हिन्दी होनी चाहिए, राजकाज के लिए दो लिपियाँ और उनमें लिखी हुई दो भाषाएँ नहीं हो सकती। हिन्दी-उर्दू के शब्द-भण्डार में काफी आदान प्रदान की गुजाइश है। हिन्दी में बोलचाल के बहुत से शब्द साहित्यिक कृतियों में छोड़ दिये जाते हैं। बहुत से मुहावरे, कहावतें, बोलचाल के शब्द ऐसे हैं जो उर्दू में हैं, लेकिन जिनका प्रयोग हिन्दी में नहीं होता, कम होता है या गलत भी होता है। यह सब उर्दू से हिन्दी में आएगा। हमारी साहित्यिक भाषा ज्यादा सरल और मुहावरेदार होगी।

उर्दू में संस्कृत शब्दों से जो परहज है, उसे कम हाना है। भारत की भाषाओं के लिए अरबी फारसी का वही महत्व नहीं है, जो संस्कृत का है। व्याकरण और मूल शब्द-भण्डार की दृष्टि से उर्दू संस्कृत परिवार की भाषा है, न कि अरबी-परिवार की। इसलिए अरबी में पारिभाषिक शब्द लेने की नीति गलत है, केवल अरबी से शब्द लेने और संस्कृत शब्दों को मनस्क समझन की नीति और भी गलत है। भारत की भाषाएँ प्रायः संस्कृत के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली बनाती हैं। उर्दू इन सब भाषाओं से न्यायी रहकर अपनी उन्नति नहीं कर सकती। जहाँ तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, यह याद रखना चाहिए कि वहाँ की भाषाएँ सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बंगला आदि हैं। उर्दू उनके अधिकार छीननेवाली राजभाषा है। पाकिस्तान में उर्दू का सामाजिक आधार बहुत ही सुकुश्चित है। इसमें जरा भी सन्देह न होना चाहिए कि सिंध, पंजाब, पूर्वी बंगाल आदि प्रदेशों की जनता अपनी भाषाओं की रक्षा करेगी

हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता /



घोर उन्ही के माध्यम से अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति करेगी। इसलिए यदि कोई यह सोचे कि पाकिस्तान उर्दू की रक्षा करेगा, तो यह उसका भ्रम है। पाकिस्तान बनने से उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की न सामाजिक समस्याएँ हल हुईं, न उनकी भाषा-समस्या हल हो सकती है। इसीलिए उर्दू की समस्या का हल वही है, तो इसी हिन्द प्रदेश में है, जहाँ की जनता में उसका बोलचाल का रूप कायम है।

शब्द भण्डार में आदान प्रदान सम्भव है लेकिन लिपि में इसकी सम्भावना बिलकुल नहीं है। उर्दू से अलिफ और हिन्दी से 'इ' लेकर कोई नई लिपि नहीं बनाई जा सकती। रोमन लिपि का सवाल नहीं है। हम अपनी लिपि छोड़कर रोमन लिपि न अपनाएँगे। यदि रोमन लिपि कोई बहुत पूर्ण और वैज्ञानिक लिपि होती, तो उस पर विचार भी किया जाता। हिन्दी-उर्दू के लिपि-भेद को दूर करने के लिए रोमन लिपि को अपनाना धीसे ही है, जैसे हिन्दी तमिल, मराठी गुजराती या बँगला असमिया के भगड़ो को दूर करने के लिए अंग्रेजी की यह राजभाषा बनाये रखना।

उर्दू लिपि के व्यवहार के लिए पूर्ण स्वाधीनता देते हुए प्रगतिशील विचारकों को चाहिए कि उर्दू-भाषियों को देवनागरी लिपि सिखाएँ। देवनागरी लिपि में उर्दू की जितनी कितायें छप रही हैं, उन्हें देखते हुए यह अनुमान होता है कि आगे चलकर देवनागरी लिपि में ही उर्दू के लेखकों की रचनाएँ छपेंगी। साक्षरता-प्रसार के साथ और दक्षिण में हिन्दी-प्रचार के साथ हिन्दी पुस्तकों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार तैयार हो गया है। यह नामुमकिन है कि उर्दू के होशियार पंजाबी लेखक इस स्थिति से फायदा न उठाएँ। सीधी मुनाफ की बात है उर्दू में किताब छपेगी कम बिकेगी, हिन्दी में छपेगी ज्यादा बिकेगी। यह एक तरह का आर्थिक दबाव है जिससे देवनागरी लिपि को उर्दू लेखक अपनाएँगे।

इस प्रकार सामाजिक जीवन की परिस्थितियाँ हिन्दी उर्दू को बराबर एक दूसरे के नजदीक लाती रही हैं। सिनेमा और रंगमंच के लिए लिखनेवाले शुद्ध हिन्दी उर्दू का खयाल रखें तो उनकी रचनाएँ असफल हों। किसानों और मजदूरों में राजनीतिक काम करनेवालों को मजबूरत ऐसी सरल भाषा का प्रयोग करना पड़ता है जिसे हिन्दू-मुसलमान दोनों समझे। जन आन्दोलन का एकाता हिन्दी उर्दू के रूपों पर बराबर असर डाल रही है, और इसीलिए हमें यह दृढ़ विश्वास है कि ये दोनों रूप अपने अन्धे तत्वों से एक ही साहित्यिक भाषा के विकास में सहायता करेंगे।

(१९६१)

## राष्ट्रीय एकता और अंग्रेजी

राष्ट्रभाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे देश की बहुसंख्यक जनता जानती हो और जो लोग उसे न जानते हो, वे उसे आसानी से सीख सकें। यह दृष्टिकोण राष्ट्रीय ही नहीं जनताधिक भी है क्योंकि बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली-समझी जानवाली भाषा के पक्ष में दिये जानेवाले तर्कों के पीछे भावना यह है कि राष्ट्रीयता मुट्ठी भर अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों की बपौती नहीं है, उसका सम्बन्ध देश की बहुसंख्यक जनता से है।

५० जवाहरलाल नेहरू ने बीस-बाईस साल पहले लिखा था, 'प्रान्तीय भाषाभाषा के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का जरा भी उल्लंघन किये बिना हमारे लिए आवश्यक है कि अखिल भारतीय व्यवहार की एक सामान्य भाषा हो। कुछ लोग साबते हैं कि अंग्रेजी ऐसी भाषा बन सकती है, एक हद तक हमारे उच्च वर्गों के लिए और अखिल भारतीय राजनीतिक कार्यों के लिए अंग्रेजी ऐसी भाषा बनी भी है। किन्तु यदि हम आम जनता को ध्यान में रखकर सोचें तो यह बात स्पष्ट ही प्रसङ्गमय प्रतीत होगी। हम करोड़ों लोगों को एक नितान्त विदेशी भाषा द्वारा शिक्षित नहीं कर सकते।' (नैशनल लैंग्वेज फॉर इंडिया—ए सिम्पोजियम, इलाहाबाद, १९४१, पृ० ४६-५०)

यदि राष्ट्रीयता उच्च वर्गों तक सीमित कर दी जाय, यदि जनतंत्र का उद्देश्य मुट्ठी भर लोगों का ऊँची सरकारी नौकरियाँ पाना हो, तो अवश्य अंग्रेजी ही राष्ट्रभाषा रहगी जैसे कि वह पिछले पन्द्रह वर्षों (या और भी पहले से) रही है। अंग्रेजी को हटाने और हिन्दी को व्यवहार में राष्ट्रभाषा बनाने का प्रश्न राष्ट्रीयता को व्यापक बनाने, राज्यसत्ता को जनताधिक रूप देने का प्रश्न है। जितने ही दिन अंग्रेजी अमली राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित रहती है, उतने ही दिन राष्ट्रीयता का आधार नमशः सङ्कुचित होता जाएगा, राज्य सत्ता जनता का विशद सम्पर्क और समर्थन खोती जाएगी। अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाये रखने का अर्थ है, निश्चित रूप से जनतंत्र के आधार को सङ्कुचित करते जाना और अन्त में उसे निर्मूल कर देना।

पराधीन भारत में ऊँची सरकारी नौकरियाँ पाने का अर्थ होना था, जनता पर हुकूमत करना। स्वाधीन भारत में सरकारी नौकरियों का अर्थ होना चाहिए जनता की सेवा करना। जिस भाषा को देश की जनता का एव प्रतिष्ठित भाग समझता है, उससे विज्ञान जनता की सेवा कैसे हो सकती है ? आज भी बंगाल, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में—पंजाब और कश्मीर की तो बात ही क्या—जितने लोग हिन्दी समझते हैं, उतने अंग्रेजी नहीं। अंग्रेजी न जाननेवाले इन करोड़ों अहिन्दी भाषियों की सेवा ऊँची सरकारी नौकरियाँ पानेवाले सज्जन हिन्दी के माध्यम से अधिक कर सकते हैं या अंग्रेजी द्वारा ?

कुछ लोग राष्ट्रीय एकता—या भावात्मक एकता—अंग्रेजी के माध्यम से दृढ़ करने का स्वप्न देखते हैं। यदि राष्ट्रीय एकता का अर्थ मुट्ठी-भर अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोगों की एकता है तो सम्भव है, वह अंग्रेजी से दृढ़ हो यद्यपि अंग्रेजीवादी नेताओं की कलह देखकर यह सम्भावना भी बहुत विष्वसनीय नहीं जान पड़ती। किन्तु यदि राष्ट्रीय एकता का अर्थ जनसाधारण की एकता है तो उसे दृढ़ करने में अंग्रेजी बाधक ही हो सकती है, साधक नहीं।

राष्ट्रीय गौरव की भावना के बिना भावात्मक एकता की कल्पना नहीं की जा सकती। जिस राष्ट्र की अपनी भाषा न हो, जो राष्ट्र भाषा के पद पर एक विदेशी भाषा को बिठाये हो, उसके नागरिकों में राष्ट्रीय गौरव की भावना कैसे दृढ़ हो सकती है ?

अंग्रेजी के पक्ष में जो मुख्य तर्क दिया जाता है कि अंग्रेजी एक विकसित और समृद्ध भाषा है किन्तु हिन्दी तथा अन्य सभी भारतीय भाषाएँ अविकसित और दरिद्र हैं—वह राष्ट्रीय गौरव की भावना पर कुठाराघात है। अंग्रेजी के विकास और समृद्धि के गीत गाकर राष्ट्रीय गौरव को जगाने और भावात्मक एकता दृढ़ करनेवाले मेधावी लोग विपणन करके अमर होने का स्वप्न देख रहे हैं। यदि सुब्रह्मण्य भारती, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बल्लत्तोल, प्रेमचन्द आदि साहित्यकार अंग्रेजी की समृद्धि से इसी तरह आतंकित होते तो भारतीय साहित्य का बड़ा संभ्रमण में कभी का डूब चुका होता।

हम न दूसरों की तुलना में अपने को अकारण बड़ा बताकर डींग हाँकते हैं, न दीनभाव में अकारण अपने को सबसे पिछड़ा हुआ मानने को तैयार हैं। पश्चिमी यूरोप ने विज्ञान में अधिक उन्नति की है किन्तु साहित्य में हम यूरोप से बढ़कर नहीं तो घटकर भी नहीं हैं। विशेषकर पिछले सौ वर्षों में भारतीय साहित्य ने जो उन्नति की है, वह पश्चिमी यूरोप के किसी भी देश के लिए स्पर्हीय हो सकती है।

वास्तव में समस्या साहित्यिक समृद्धि की नहीं है, समस्या है राष्ट्रीय आत्मसम्मान और जनता की सेवा-भावना की। मिस्र देश हमसे अधिक विकसित नहीं है किन्तु वहाँ की राष्ट्रभाषा अरबी है। सोवियत संघ में कजाख, उजबेक, ताजिक आदि भी अपनी भाषाओं का शिक्षा, राजनीतिक कार्यों आदि

के लिए प्रयुक्त करने हैं। चीन तक ने चीनी को राष्ट्रभाषा बना रखा है। ससार में सबसे प्राचीन संस्कृति का घनी भारत स्वाधीन होने पर भी अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाये रहे, इससे अधिक लज्जास्पद बात और क्या हो सकती है ?

यह ध्यान देने की बात है कि जो लोग अंग्रेजी को विकसित और समृद्ध बहकर उसे राष्ट्रभाषा बनाये रखना चाहते हैं, वे न केवल हिन्दी को, बरन् सभी भारतीय भाषाओं को न्यूनधिक दरिद्र और अविकसित मानते हैं। हिन्दी के लिए हमारा सघर्ष, अंग्रेजी के विरुद्ध, सभी भारतीय भाषाओं के अधिकारों के लिए सघर्ष है। अंग्रेजी भारत में साम्राज्यवादी ढंग में प्रतिष्ठित है। वह प्रत्येक प्रदेश में वहाँ की भाषा के अधिकार छीनती है, उसे उच्च शिक्षा का माध्यम बनने से रोक्ती है; राजकाज में, उच्च न्यायालयों में वहाँ की भारतीय भाषा को अपदस्थ करती है। अंग्रेजी की यह साम्राज्यवादी स्थिति सारे देश में देखी जा सकती है; बाजार पर कुछ भी लिखा हो, व्यवहार की बात दूसरी ही है।

इसने विपरीत हिन्दी के समर्थकों का कहना है कि प्रत्येक प्रदेश में वहाँ की भाषा को उचित अधिकार मिले, वहाँ वे समस्त राजकाज में, शिक्षा-केन्द्रों, न्यायालयों आदि में वह प्रयुक्त हो, केवल विभिन्न प्रदेशों में आणसी व्यवहार के लिए, केन्द्रीय राज्यसत्ता और उसकी संस्थाओं के लिए हिन्दी का व्यवहार हो। यह स्थिति साम्राज्यवादी नहीं है, बरन् जनतांत्रिक और राष्ट्रीय है। प्रत्येक प्रदेश की भाषा को अंग्रेजी के स्थान पर राजनीतिक सांस्कृतिक कार्यवाही का माध्यम बनाना जनतन्त्र की भावना के अनुकूल है। इन विभिन्न प्रदेशों के बीच तथा केन्द्र में हिन्दी का व्यवहार करना राष्ट्रीयता की भावना के अनुकूल है। भाषागत साम्राज्यवाद अंग्रेजी का है, न कि हिन्दी का। विभिन्न भारतीय भाषाओं के अधिकारों को इस समय पदचलित कर रही है अंग्रेजी, न कि हिन्दी। अंग्रेजी की वास्तविक साम्राज्यवादी स्थिति को भुलाकर जो लोग कल्पित हिन्दी-साम्राज्यवाद से जनता को आतंकित करते हैं, वे राष्ट्रीय एकता दृढ़ करने के बड़ने राष्ट्रीय विघटन को जबर्दस्त प्रोत्साहन देते हैं।

अंग्रेजी से सभी भारतीय भाषाओं के हित टकराते हैं, हिन्दी से किसी भी भारतीय भाषा के हित नहीं टकराते, अंग्रेजी के आनने-समझनेवाले मुट्ठी-भर हैं, हिन्दी बोलने समझनेवाले करोड़ों हैं; अंग्रेजी कायम रखने में जनता पर द्रुकूमत करनेवालों का निहित स्वार्थ है; हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने से विनाश जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है; अंग्रेजी राष्ट्रीय शौर्य की भावना पर कुठाराघात करती है, हिन्दी राष्ट्रीय आत्मसम्मान को जाग्रत और पुष्ट करती है। इसलिए हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि अंग्रेजी अनिविचल काल के लिए एकमात्र या सह-राष्ट्रभाषा नहीं रहेगी, निरिच्छत और सीमित अवधि में ही उसे अपना स्थान छोड़ना होगा।

राष्ट्रभाषा हिन्दी के विरुद्ध जितने तर्क दिये जाते हैं, उनमें जरा भी गौनियता नहीं है, ये पराधीन भारत में भी दिये जाते थे, अन्तर केवल इतना है कि तब ऐसे तर्क देनेवालों को अराष्ट्रीय कहा जाता था। अंग्रेजों के चले जाने पर मुसलमानों और अछूतों को सबर्ण हिन्दू सा जाएँगे, दक्षिणवालों पर उत्तरवाले अपना आतंक फैलाएँगे, हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने से भारत की सांस्कृतिक उन्नति रुक जाएगी—ये सब तर्क ऊँची सरकारी नीकरियों के अंग्रेज-भक्त उम्मीदवार पहले भी दिया करते थे। अब इस तरह के तर्क अंग्रेजी-भक्त शासक या शासकपद के उम्मीदवार दिया करते हैं। इन सब तर्कों का सारतत्त्व यह है कि साहब का बेटा भी साहब होगा, कॉन्वेंट में पढ़ेगा और अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोलेगा, वर्गविपुलर बोलनेवालों पर हुकूमत करेगा।

अंग्रेजी-प्रेमी शामकी को भय है कि अंग्रेजी के राजभाषा न रहने पर राज्य-सत्ता उनके हाथ में न रहेगी। यह वर्ग इस समय बाकी प्रभावशाली है किन्तु देश की विशाल जनता के सामने उसकी शक्ति नगण्य है। जो लोग भी अपनी मातृभाषा से प्रेम करते हैं, उनकी मातृभाषा चाहे हिन्दी हो, चाहे कोई अहिन्दी-भाषा, उनका कर्तव्य है कि विभिन्न प्रदेशों में अंग्रेजी की जगह वहाँ की प्रादेशिक भाषाओं को प्रतिष्ठित करें और केन्द्रीय भाषा के रूप में अंग्रेजी की जगह हिन्दी का व्यवहार करें।

हिन्दी पिछड़ी हुई भाषा है इसलिए उसे विकसित होने का अवसर देना चाहिए, यह आलसियों का तर्क है। हिन्दी में कितने आवश्यक शब्द हैं तथा कितने और होने चाहिए—इस समस्या की कोई वैज्ञानिक जाँच-पड़ताल अभी तक नहीं हुई। यदि भारत की किसी भी भाषा को समृद्ध माना जाय तो हम उससे पारिभाषिक शब्द लेने को तैयार हैं क्योंकि जो श्रोत हमारे पारिभाषिक शब्दों का है, वही उसके शब्दों का होगा—अर्थात् सस्कृत (उर्दू को छोड़कर)।

हिन्दी पिछड़ी हुई भाषा है, यह तर्क वे लोग देते हैं, जो भारत की प्रत्येक भाषा को पिछड़ा हुआ मानते हैं। राष्ट्र के लिए इससे अधिक अपमानजनक दूसरा दृष्टिकोण हो नहीं सकता। आज से पैंतीस वर्ष पहले अंग्रेज भाषाविद् ग्रियर्सन ने हिन्दी के बारे में अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लिंग्विस्टिक सर्वे' की भूमिका में लिखा था, "इट हैज़ ऐन एनारमस नेटिव वर्कबुलरी एण्ड ए कम्प्लीट अर्गैरेटस फॉर द एक्सप्रेसन ऑफ़ ऐब्स्ट्रेक्ट टर्म्स," (देशी शब्दों का उसका विशाल शब्द-भण्डार है और सूक्ष्म धारणाएँ प्रकट करने के लिए पूर्ण पारिभाषिक शब्दावली है।) ग्रियर्सन ने उन लोगों की आलोचना की थी, जो हिन्दी शब्द छोड़कर सस्कृत के कठिन और दुरूह शब्दों की ओर भागते थे और इसी प्रसंग में लिखा था—"थट इन्स्टाइट ऑफ़ हिन्दी पजेंटिंग सच ए वर्कबुलरी एण्ड ए पावर ऑफ़ एक्सप्रेसन नोट इन्फ़ीरियर टु इंग्लिश, इट हैज़ बिकम द फैशन." (यद्यपि हिन्दी के पास ऐसा शब्द-भण्डार है और व्यञ्जना-शक्ति में वह अंग्रेजी से घटकर नहीं है, फिर भी यह फैशन हो गया है...)। जो लोग

अंग्रेजियत में अंग्रेजों के कान बाटते हैं, वे यह कभी न मानेंगे कि व्यजना-रावित में हिन्दी अंग्रेजी से घटकर नहीं है।

यूरोप और अमरीका में भारतीय सभ्यता के अप्रदूत महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने गुजराती साहित्य परिषद् के छठे अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था, "आपकी सेवा में खड़ा होकर विदेशीय भाषा वहाँ यह हम चाहते नहीं। पर जिस प्रान्त में मेरा घर है वहाँ सभा में बहने लायक हिन्दी का व्यवहार है नहीं। महात्मा गांधी महाराज की भी भाषा है हिन्दी में बहने के लिए। यदि हम समर्थ होता सब इससे बड़ा आनन्द और कुछ होता नहीं। असमर्थ होने पर भी आपकी सेवा में दो बात हिन्दी में बोलूंगा।" ('प्रभा', कानपुर, मार्च, १९२५)

जो लोग उठते-बैठते गांधीजी के नाम की माला जपते हैं और जिन्होंने अखिल भारतीय पैमाने पर रवीन्द्र-जयन्ती-सामारोह संगठित किया था, वे कृपया विचार करें कि वे अपने व्यवहार में गांधी-रवीन्द्रनाथ के मार्ग से कितनी दूर था पड़े हैं। महाकवि ने अपनी असमर्थता प्रकट की, किसी भाषा को असमर्थ नहीं कहा, गांधीजी ने गुजरातियों के बीच उनसे अंग्रेजी में नहीं, हिन्दी में बोलने को कहा।

राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने का यही एक मार्ग सन् '२५ में था, वही मार्ग अब सन् '६२ में भी है। और दूसरे रास्ते सब गलत हैं। (१९६२)

## राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता

सन् '६५ में हिन्दी केन्द्रीय राजकाज की भाषा न बनेगी। क्या बनेगी, यह अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासियों की इच्छा पर निर्भर है। इस पर भी कुछ सज्जन असन्तुष्ट हैं। असन्तुष्ट इस बात पर है कि अंग्रेजी सदा-सर्वदा के लिए भारत की एकमात्र राष्ट्रभाषा घोषित नहीं की गई। हो सकता है दो-चार शताब्दियों बाद लोग हिन्दी को राष्ट्रभाषा बना दें। इस सम्भावना को रटने ही क्यों दिया जाय ?

ऐसा सोचनेवाले सज्जन अंग्रेजी के माध्यम से शासनतन्त्र पर अपना इजारा हमेशा के लिए पक्का कर लेना चाहते हैं। वे और उनके भाई भतीजे तो इस युग में शासन की बागडोर संभाले ही हुए हैं, वे चाहते हैं कि युगो-युगो तक उन्हीं की तरह उनके वंशज भी—यानी मुट्ठी-भर विदेशी भाषा के उपासक—शासन की बागडोर इसी तरह मजबूती से थाम रहे। कुछ दिन हुए ऐसे लोगों को लक्ष्य करके मद्रास में प्रधान मन्त्री ने प्रश्न किया था—क्या उनमें राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भावना का एकदम लोप हो गया है ?

इस प्रश्न से नतीजा यह निकलता है कि जो लोग थोड़े समय के लिए अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, उनमें उतने ही समय के लिए आत्मसम्मान का लोप होता है, जो लोग सदा के लिए अंग्रेजी का राष्ट्रभाषा बनाय रखना चाहते हैं, उनमें सदा के लिए आत्मसम्मान का लोप हो जाता है। सदा के लिए आत्मसम्मान खोने से अच्छा है उसे थोड़े समय के लिए खोया जाय। भले ही इस थोड़े समय की अवधि का क्रमशः विस्तार होता जाय—सन् '४६ से '६५ तक, '६५ से बीसवीं सदी के अन्त तक, बीसवीं सदी के बाद इक्कीसवीं सदी के अन्त तक, और इसी तरह अनिश्चित काल के लिए आगे भी। मुख्य बात यह है कि अनिश्चित काल को निश्चित न किया जाय, वरना राष्ट्रीय आत्मसम्मान का सापेक्ष अभाव शाश्वत और निरपेक्ष हो जाएगा।

एक बहुत दिलचस्प सवाल यह पैदा होता है कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान का यह अभाव भाषा के क्षेत्र तक सीमित है या वह देश के राजनीतिक, आर्थिक

आदि अन्य क्षेत्रों में भी है। क्या आपने सत्तार के इतिहास में किसी ऐसे देश का नाम सुना है जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूर्ण स्वाधीन रहा हो किन्तु जो आपा के क्षेत्र में परमुखापेक्षी हो ? क्या वर्तमान काल में कोई ऐसा देश है जो स्वाधीन होते हुए भी अपनी भाषा छोड़कर विदेशी भाषा का व्यवहार करता हो ? इन स्वाधीन देशों में इस बात का लेकर पचपत नहीं जुड़ती कि विश्व की सबसे समृद्ध भाषा कौन-सी है, देश की भाषा का हटाने उसके बदले विश्व भाषा का व्यवहार कब तक किया जाय ? आतिर जर्मन, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, इतालवी, स्पेनी आदि भाषाएँ समान रूप में तो समृद्ध हो रही हैं। किन्तु जहाँ ये भाषाएँ बोली जाती हैं, वहाँ यह प्रश्न कोई नहीं करता कि सबसे समृद्ध विश्व-भाषा को राजकाज की भाषा क्यों न बनाया जाय। यह प्रश्न केवल उन देशों में सामन्य होता है जो पश्चिमी राष्ट्रों के उपनिवेश हैं, या रह चुके हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दी में चिपके रहना और अंग्रेजी का विरोध करना बुरा मण्डूकता है। मालूम होता है कि अपनी भाषा से प्रेम करनेवाले तो कृषो में पड़ हैं, केवल भारत के अंग्रेजी-प्रेमी मण्डूक कुर्रों से बाहर निकलकर अपनी अपनी अंग्रेजी-ध्वनि में दसों दिशाएँ गुंजरित कर रहे हैं।

आर्थिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए तो पैसा बड़ी दरकार होता है, स्वर्ण की आवश्यकता होती है। किन्तु शब्द ब्रह्म तो अमूल्य है। बात करने में क्या खर्च होता है ? फिर भारत में सस्कृत की कृपा से किसी भी भाषा के शब्द-भण्डार का यथेच्छ भरने में विलम्ब नहीं होता। भाषा के क्षेत्र में परमुखापेक्षी होना परों गिरे की गुलामी है। जो भाषा के क्षेत्र में स्वाधीन नहीं हो सकता, वह अन्य क्षेत्रों में क्या स्वाधीन होगा ? भारतम्बु हरिदचन्द्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सुब्रह्मण्य भारती, निराला, प्रेमचन्द आदि साहित्यकारों ने देश के पराधीन रहते हुए भी भाषा के क्षेत्र में अपनी प्रभुसत्ता की रक्षा की। भाषा के क्षेत्र में भारतीय साहित्यकारों ने अंग्रेजी का प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं किया। स्वाधीनता मूर्खों की किरणों ने सबसे पहले भाषा के क्षेत्र को प्रकाशित किया। आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों के नेता साहित्यकारों के अनुगामी रहे हैं, उनके पथ निर्देशक नहीं।

आये दिन जो राजनीतिज्ञ हिन्दी प्रेमियों को सकीर्ण और अनुचित विचारवाला कहते हैं, जो हिन्दी से विमुख और अंग्रेजी के मुखापेक्षी वसुधैव कुटुम्बकम् का उपदेश देते नहीं पाते, उनसे पूछा जा सकता है—दश में अन्न का क्या हाल है ? भुखमरी से बचने के लिए आपकी अन्य राष्ट्रों का दरवाजा तो खटखटाना नहीं पड़ता ? अपनी पचपपीय योजनाओं की पूर्ति के लिए आपको विदेशी बटीखार्तों में कर्जदार बनकर नाम लिखाना तो नहीं पड़ता ? देश-रक्षा के लिए आप विदेशी अस्त्र-शस्त्रों के मोहताज तो नहीं हैं ? आपके आयात-निर्यात व्यापार में विदेशी पूँजी का लाना बाना बुना हुआ तो नहीं है ? आप विदेशी दबाव के कारण कश्मीर-जैसे किसी प्रदेश की भूमि का विनिमय

राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता /



करने की ओर तो नहीं बड़े ?

पुराने जमाने में लोग बहुत थे—अंग्रेजी हमारी गुलामी की निगानी है। ऊपर के प्रश्न पढ़कर बताइए, यह बात सही है या नहीं ? क्या आप समझते हैं कि दासता की मनोवृत्ति केवल भाषा के क्षेत्र में प्रतिबिम्बित होती है, अंग्रेजी को हटाने का प्रयास केवल एक भाषागत समस्या है ? गुलाम तो गुलाम। उसकी गुलामी न केवल उसके सोचने से प्रकट होगी बल्कि उसके हर तरह के आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार से प्रकट होगी।

राष्ट्रभाषा की समस्या कोई विगुड़ भाषा विज्ञान की समस्या नहीं है। यह मूलतः देश की प्रभुसत्ता की समस्या है। यह तो सम्भव है कि केन्द्रीय राजराज के लिए एक सार्वजनिक भाषा का व्यवहार किया जाय, किन्तु देश की प्रभुसत्ता के लिए यह असम्भव है कि सभी भारतीय भाषाओं के अधिकारों को परोक्षे तौर पर अंग्रेजी उन सबके ऊपर प्रतिष्ठित हो। जो लोग यह कहते हैं कि हिन्दी के माध्यम से बड़े-बड़े पूँजीपति छोटी छोटी अहिन्दीभाषी जातियों को दबाते हैं, वे यह भी नहीं कहते कि अंग्रेजी के माध्यम से साम्राज्यवाद भारत की सभी जातियों को दबाता है, यही की सभी भाषाओं के स्वतंत्रता का अन्वेषण करता है।

हिन्दी को केन्द्रीय भाषा बनाने में कुछ बड़े पूँजीपतियों का स्वार्थ हो सकता है, यद्यपि ऐसा नहीं जाता है कि अंग्रेजी के दैनिक पत्रों की श्रृंखलाएँ इन्हीं बड़े पूँजीपतियों के हाथ में हों। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिन्दी को केन्द्रीय भाषा बनाने में छोटे पूँजीपतियों तथा श्रमिक जनता का हित सबसे बड़ा है। हिन्दी के बिना सामान्य जनता सामन्ततन्त्र, केन्द्रीय राजराज में भाग नहीं ले सकती। यह राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यवाही का अन्वेषण के समान दूर रखी जाती है। इस तरह हमारे जनतन्त्र का आधार सङ्कुचित रहता है, हमारी राष्ट्रीयता मुट्ठी-भर अंग्रेजी पढ़े लोगों के हाथ का तिलोना बनी रहती है।

जो लोग अंग्रेजी को हटाना चाहते हैं, हिन्दी को केन्द्रीय भाषा बनाने के लिए जल्दी करते हैं, उन्हें 'हिन्दी एथूजिस्ट' आदि उपाधियों से विभूषित किया जाता है। मानो अपनी भाषा का समर्थन करना गुनाह हो, 'अंग्रेजी एथूजिस्ट' होना कोई बहुत बड़ा पुण्य हो। केन्द्रीय भाषा के पद से अंग्रेजी को हटाने में किसी एक भारतीय भाषा का स्वार्थ नहीं है। अंग्रेजी की वर्तमान स्थिति से सभी भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा को धक्का लगता है, उनकी अधिकार-मर्यादा नष्ट होती है। इसलिए अंग्रेजी के विरुद्ध संघर्ष आज सभी भारतीय भाषाओं की अधिकार रक्षा का संघर्ष है। इन भाषाओं के बीच परस्पर आदान प्रदान के लिए हम हिन्दी का व्यवहार चाहते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए, न कि उनके अधिकारों को रौंदकर। अधिकारों को रौंदने का काम अंग्रेजी कर रही है, न कि हिन्दी।

प्रत्येक जाति का यह जन्मगिद्ध अधिकार है कि वह अपनी सांस्कृतिक, राजनीतिक, हर तरह की सामाजिक कार्यवाही अपनी भाषा के माध्यम से सम्पन्न करे। हर तरह के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में अपनी भाषा का प्रयोग उसकी प्रभुसत्ता की उन्मुक्त घोषणा है। जातीय भाषा का व्यवहार राष्ट्र के स्वाधीन होने की पहचान है। भाषा के समृद्ध या दरिद्र होने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। समार के किसी देश ने किसी समय यह नियम स्वीकार नहीं किया कि विश्व की सबसे समृद्ध भाषा को वह राष्ट्रभाषा बनायेगा। ऐसा नियम होता तो सारे समार में संस्कृत, ग्रीक या लैटिन या ही प्रभुत्व होता।

हिन्दी समृद्ध है या दरिद्र है, यह तय करने के लिए कोई वैज्ञानिक कसौटी नहीं अपनायी गई। उदाहरण के लिए, हिन्दी में राजनीतिक शब्दावली कम है या पर्याप्त है, यह जानने के लिए कोई शब्द-गणना नहीं की गई। एक प्रवाद कैना दीजिए, दस राजनीतिज्ञ उस प्रवाद को दोहरा दें, अंग्रेजी अवधारणों में वह प्रवाद छप जाय, वम उसे प्रमाणित सत्य मान लिया जाएगा। देश में प्रचार के साधनों का इतना केन्द्रीकरण है कि नकाररक्षाने में हिन्दी सम्बन्धी सत्य की पुकार सूती की भावाज से अधिक कारगर साबित नहीं होती।

शामनतन्त्र चलानेवाले बुद्धिजीवी अंग्रेजी में भयवा किन्हीं देशी भाषा में अंग्रेजी शब्दों की मिलावट करके चिन्तन का काम पूरा करते हैं। उनकी अभिव्यजना का माध्यम अंग्रेजी या यह खिचड़ी भाषा होती है। आप यह न समझें कि पारिभाषिक शब्दों के अभाव के कारण वे ऐसा करते हैं। उनके बच्चे बोलना सीखते हैं, पापा, डंडी, मम्मी, अन्न, छांटी जैसे पारिभाषिक शब्दों के ज्ञान के साथ। 'जरा फादर को रिसीव करने जा रहा हूँ,' 'उसका रिमार्क ऐसा सिली था कि माई ब्लड बिगन टु बॉयल', 'भाजकल आप पोलिटिकल ऐक्टिविटी से इतने इण्डिफरेंट क्यों रहते हैं', 'एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है कि छाड़िनरी एप्लीकेशन लिखने में एम० ए० पास लोग मिस्टेक करते हैं'—इस तरह के वाक्य उत्तर भारत के अनेक शहरों में आप सुन सकते हैं। इन वाक्यों में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग पारिभाषिक शब्दों की कमी के कारण नहीं है। मानसिक क्षमिलता, अंग्रेजी शब्दों का मोह, अपनी भाषा के प्रति अवज्ञा-सूचक दृष्टिकोण—इन कारणों से उस तरह के भोड़े वाक्यों की रचना होती है। इन्हीं कारणों से अंग्रेजी प्रेमी बुद्धिजीवियों को यह तय करने में देर नहीं लगती कि अंग्रेजी समृद्ध है, हिन्दी दरिद्र है।

एक समिति में लोग आलोचना सम्बन्धी शब्द-सूची एकत्र कर रहे थे। समिति के अधिकांश सदस्य न हिन्दी के आलोचक थे, न हिन्दी आलोचना से परिचित थे। फिर भी वे इस काम में लगे हुए थे क्योंकि वे समिति के सदस्य बना दिये गए थे। शब्द संग्रह करने का तरीका क्या था? आप शायद सोचें कि हिन्दी की आलोचना पुरतकों से अथवा संस्कृत के सिद्धान्त ग्रन्थों से ऐसी शब्द-सूची मकलित की जा रही थी। समिति के मामले का दूसरा था। काम हिन्दी-

शब्दों की सूची बनाना न था, काम था अंग्रेजी शब्दों के हिन्दी पर्याय निश्चित करना। इस तरह की सूची बनाने की जरूरत क्यों हुई? इसलिए कि अंग्रेजी का आलोचना-शास्त्र अधिक समृद्ध है, उसके शब्द-भण्डार के अनुरूप हिन्दी पर्याय स्थिर करके ही राष्ट्रभाषा को समृद्ध किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं, समिति में इस पद्धति का विरोध करनेवाले को किसी का समर्थन प्राप्त न हुआ होगा।

प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिस्थितियाँ, दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ विभिन्न देशों में बहुत-बहुत समान हैं। इसलिए उनके शब्द-भण्डार में अर्थ-सम्बन्धी बहुत बड़ी समानता है। किसी भी भाषा के हजारों शब्दों के लिए दूसरी भाषा में उन्हीं के समानार्थी शब्द मिल जाते हैं। यातायात के माधनों में प्रगति होने से, व्यापार, उद्योग धंधों और विज्ञान में उन्नति होने से (और उन्नति करने के लिए) अनेक देश एक-दूसरे के अधिक निकट आये हैं। इसलिए ऐसे शब्दों की संख्या बहुत बढ़ी है जो रूप में भिन्न होते हुए भी अर्थ में समान हैं। हिन्दी में भी उद्योग, व्यापार, राजनीति आदि से सम्बन्धित हजारों शब्द प्रचलित हैं जो उसी कोटि के अंग्रेजी या जर्मन शब्दों के समानार्थी हैं।

इसके साथ यह भी सही है कि प्रत्येक देश के प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिस्थितियों, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की अपनी विशेषताएँ हैं। इसलिए प्रत्येक भाषा में हजारों शब्द ऐसे मिलेंगे जिनके ठीक समानार्थी शब्द दूसरी भाषाओं में दुर्लभ होंगे। किन्तु भाषा प्राकृतिक या सामाजिक परिवेश का दर्पण मात्र नहीं है। भाषा प्रत्येक जाति की विशिष्ट चिन्तन प्रक्रिया, उसके रसबोध, भाव-सम्बन्धी प्रतिक्रिया का दर्पण भी होती है, इस दृष्टि से विचार करने पर पता चलेगा कि कोई भी भाषा किसी से घटकर नहीं है, प्राणि-जगत् की प्रत्येक जीव यानि के समान ससार की प्रत्येक भाषा की अपनी विशेषता है।

इस देश के लोगो ने अनेक शताब्दियों तक मनुष्य के मन पर, उसकी चेतना पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। दर्शन और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में अनेक धारणाओं का जैसा सूक्ष्म भेद संस्कृत शब्द प्रकट करते हैं, वैसा ससार की कोई भाषा प्रकट नहीं करती, कम-से-कम ग्रीक, लैटिन और इनसे प्रभावित यूरोप की भाषाएँ तो अवश्य नहीं करती। संस्कृत की वह शब्द-सम्पदा भारत की समस्त भाषाओं की सामान्य सम्पत्ति है। उन लोगो के सांस्कृतिक पतन का अनुमान कीजिए जो 'मेडिटेशन' के लिए अपनी शब्द-सूची में 'ध्यान' शब्द बिठाकर यह समझ लेते हैं और दूसरों को समझाते भी हैं कि 'ध्यान' अब 'स्टैण्डर्ड' शब्द हो गया, 'मेडिटेशन' का पर्याय बनकर। इसके बाद वे कहते हैं कि जो पुस्तकें लिखी जाएँ या अनुवादित की जाएँ, उनमें 'ध्यान' शब्द उसी अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए जिसमें अंग्रेजी का 'मेडिटेशन' शब्द प्रयुक्त होता है। और 'समाधि' के लिए अंग्रेजी का कोई पर्याय न हुआ तो वह बेचारा स्टैण्डर्ड-च्युत होकर शब्द-संग्रह के बाहर पड़ा रह गया।

भारतीय शब्द 'राष्ट्र' का ठीक समानार्थी अंग्रेजी शब्द 'नेशन' नहीं है। सोवियत सभ में एक से अधिक 'नेशन' हैं किन्तु वह 'राष्ट्र' एक है, अनेक नहीं। 'राष्ट्र' से केवल मनुष्यों का बोध नहीं होता जैसा कि 'नेशन' से होता है। 'नेशन' किसी देश की भूमि को नहीं कह सकते, किन्तु 'राष्ट्र' से भूमि का बोध भी होता है। जे० डी० वेट की 'ए डिक्शनरी ऑफ द हिन्दी सेंग्वेज' में राष्ट्र का भूमि वाला अर्थ दिया है—'ऐन इनहेरिटेड कण्ट्री, ए रेलम, किंगडम, एम्पायर, रीजन।' अन्त में मनुष्यों से भी सम्बन्धित एक शब्द जोड़ दिया गया है, 'पब्लिक'। इससे उन कोशकारी की कठिनाइयों का अनुमान किया जा सकता है जिन्हें हिन्दी शब्दों के अंग्रेजी पर्याय ढूँढ़ने पड़ते हैं। बचारे 'राष्ट्र' के लिए 'पब्लिक' लिखकर सन्तोष कर लेते हैं। प्रसिद्ध कोशकार मोनियर विलियम्स को अपने महान् संस्कृत अंग्रेजी कोश की भूमिका में कैफियत देनी पड़ी थी कि उन्होंने एक एक संस्कृत शब्द के अनेक अंग्रेजी पर्याय बयों दिये हैं। इसका एक कारण और भी था जिसका उल्लेख उन्होंने नहीं किया। वह यह कि किसी एक संस्कृत शब्द का ठीक समानार्थी शब्द अंग्रेजी में मिलता न था; इसलिए उसके अर्थ के निकट पहुँचनेवाले अनेक शब्द देने पड़ते थे, जिसमें अंग्रेजी जानने-वाला विद्यार्थी उन सभी की सहायता से अर्थ बोध कर सके। यथा 'समाधि' के लिए 'इण्टेन्स ऑप्लीकेशन ऑर फिक्सिंग द माइण्ड ऑन, इण्टेण्टनेस, अटेन्शन, कन्सन्ट्रेशन ऑफ द थॉट्स, प्रोफाउण्ड ऑर ऐंस्टरूक्ट मेडिटेशन, इण्टेन्स कन्टेम्प्लेशन ऑफ ऐनी पर्टीकुलर ऑब्जेक्ट (सो एंज टू आइडेण्टीफाई द कन्टेम्पेटर विद द ऑब्जेक्ट मेडिटेटेड अपॉन)'। 'समाधि' का समानार्थी शब्द अंग्रेजी में है नहीं। यह भी स्पष्ट है कि 'अटेन्शन', 'कन्टेम्प्लेशन', 'मेडिटेशन' आदि शब्द समाधि के निदिष्ट अर्थ के निकट पहुँचते हैं किन्तु उसे प्रकट नहीं कर पाते। वास्तव में 'समाधि' की अपेक्षा वे 'ध्यान' के अधिक निकट हैं।

मोनियर विलियम्स ने भारतीय वाङ्मय के बारे में लिखा था, "कुछ विषयों में, विशेषकर प्रकृति और पारिवारिक प्रेम के कवित्वमय वर्णनों में वह ग्रीस और रोम की सर्वश्रेष्ठ कृतियों के मुकाबले हेटा नहीं सिद्ध होता और ज्ञान की गरिमा और नैतिक विचारों की सूक्ष्म बृक्ष में वह अद्वितीय है।" वैज्ञानिक विषयों का उल्लेख करते हुए उन्होंने आगे उसी भूमिका में लिखा था, "इससे भी बढ़कर यह कि हिन्दुओं ने खगोल विज्ञान, गणित, बीजगणित, वनस्पति-विज्ञान और औषध में काफी प्रगति की थी, व्याकरण में उनकी श्रेष्ठता का उल्लेख करना अनावश्यक है; और यह सब उस समय जब यूरोप की प्राचीनतम जातियों में भी इनमें से कुछ विज्ञान विवक्षित न हुए थे।" मोनियर विलियम्स ने मस्त्रुत के शब्द-भण्डार की बहुविषयक समृद्धि को लक्ष्य करके लिखा है कि उसका कोश बनानेवाले को लगभग सर्वज्ञ होना चाहिए। उनके अनुसार इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी शिक्षा प्राप्त तरुण सरवृत्त की "वैज्ञानिक शब्दावली की सही सही व्याख्या नहीं कर सकते।" मोनियर विलियम्स ने यह

और जोड़ दिया है कि यदा-कदा यह वैज्ञानिक शब्दावली सस्त्रुत में यूनानियों से उधार ली गई है। किन्तु यहाँ इस पर विवाद नहीं करना कि भारत में यूनान से पहले अनेक विज्ञान विकसित हुए, फिर भी यहाँ के शब्द यहाँ वालों ने क्यों उधार लिए। मुख्य बात यह है कि यूरोप की नवीन और प्राचीन भाषाओं के महापंडित कोशकार मोनियर विलियम्स को यह स्वीकार करना पड़ा था कि इंग्लैंड की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों के तरुण ग्रेजुएट—भारत में जिनके रोबदाब की सीमा नहीं है—सस्त्रुत की वैज्ञानिक शब्दावली ('द साइटीफिक एक्सप्रेसन') की बारीकियों को समझने में असमर्थ थे। आज मालूम होता है, मोनियर विलियम्स प्रभृति विद्वानों द्वारा अभिनन्दित हमारा वह महान् रिक्थ कहीं खो गया है। सरकारी कोशकार हिन्दी में यूरोप की अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली से पारिभाषिक शब्द उधार लेने की बात करते हैं यद्यपि वे जो विदेशी शब्द लेते हैं, वे निरपवाद रूप से अंग्रेजी के ही होते हैं (अर्थात् ऐसे शब्द होते हैं जो ग्रीक लैटिन के आधार पर गढ़कर अंग्रेजी में चलाये गए हैं)। ये सामान्य सरकारी कोशकार वह अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली प्रकाशित कर दें तो यूरोप के भावार्थक एकीकरण में बड़ी सहायता मिले।

एक समय था जब स्वामी विवेकानन्द जैसे भारतीय सस्कृति के प्रतिनिधि गरजकर मदान्ध यूरोप से कहते थे . स्वार्थ-लिप्सा ने तुम्हें पतन के गर्त में ढकेल दिया है, आओ, इस गर्त से बाहर निकलो, ज्ञान की दीक्षा भारत से लो।

विवेकानन्द और रवीन्द्रनाथ का वह भारत आज परमुखापेक्षी है, न केवल आर्थिक सहायता के लिए वह पश्चिमी राष्ट्रों का द्वार खटखटाता है वरन् शब्दावली के लिए भी वह उनका मुँह जोहता है, वह अंग्रेजी के बिना अपनी भाषा-समस्या हल नहीं कर सकता।

(१९६२)

## हिन्दीभाषी प्रदेश में हिन्दी-प्रचार की आवश्यकता

हम हिन्दी-भाषियों में अधिकांश जनो की धारणा यही है कि हिन्दी यदि अभी तक राष्ट्रभाषा नहीं हो पाई तो इसका मुख्य कारण अहिन्दी-भाषियों का अंग्रेजी-प्रेम अथवा हिन्दी विरोध है। हिन्दी पत्र-पत्रिकाओं में इस विषय पर जो लेख निकलते हैं, उनसे यह प्रकट नहीं होता कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सर्वाधिक उत्तरदायित्व हमारा है और हम उसे निवाह नहीं रहे हैं।

हमारे देश में एक पूरा वर्ग है, जो राष्ट्रभाषा के पद पर अंग्रेजी को प्रतिष्ठित रखना चाहता है। यह वर्ग किसी प्रदेश-विशेष में सीमित नहीं है बल्कि हमारे देश में फैला हुआ है, अमर-जेल की तरह वह विशाल हिन्दीभाषी प्रदेश में भी फैला है। आये दिन अपने प्रदेश के शिक्षित जनो के व्यवहार में हम अंग्रेजी का यह महत्व देख सकते हैं। हिन्दीभाषी प्रदेश में इस वर्ग के लोग उतने मुखर नहीं हैं जितने उनके महयोगी अन्य प्रदेशों में हैं। फिर भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रदेशों के अंग्रेजी प्रेमी एक-दूसरे की सहायता करते हैं।

पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों में भावात्मक एकता पर राज नीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के नेताओं ने भाषण किये, अनेक मिथा-संस्थाओं में परिसंवाद आयोजित किये गए। आगरा और मेरठ की दो ऐसी गोष्ठियों में मैंने देखा कि अधिकांश भाषण अंग्रेजी में हुए। ये नेतागण अवश्य ही मन में सोचते होंगे कि अंग्रेजी ही उनके उच्च विचारों का वाहन हो सकती है अंग्रेजी द्वारा ही वे देश में राष्ट्रीय एकता दृढ़ कर सकते हैं। अभी पिछले महीने चीनी आक्रमण के विरोध में विद्यार्थियों की सभाओं में अध्यापकों के प्रोत्साहन-प्रद भाषण भी अंग्रेजी में हुए। यदि हमारे प्रदेश के शिक्षा-विचारक भी नवयुवकों को देश रक्षा का महत्व समझाने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, तब अन्य प्रदेशों में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की माँग हम किम भूँह में कर सकते हैं ? सभी शिक्षित जनो का व्यवहार ऐसा नहीं होगा, काफी लोग ऐसे हैं, जो ऐसे घरसरो पर गचेत ढंग से हिन्दी का ही व्यवहार करते हैं। फिर भी यह मानना होगा कि हिन्दी क्षेत्र के शिक्षित जनो में अंग्रेजी का चयन आवश्यकता के

अधिक है।

हिन्दी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में शिक्षा का सामान्य माध्यम अंग्रेजी है। कुछ विषयों में जहाँ-तहाँ हिन्दी द्वारा शिक्षण भी होता है किन्तु कुल मिलाकर शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का स्थान गौण है, अंग्रेजी का स्थान प्रमुख है। इसी प्रकार शासन-संस्थाओं की कार्यवाही के लिए अंग्रेजी का व्यवहार प्रचुर मात्रा में होता है। जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की शासन-संस्थाओं में अमली रूप से हिन्दी राजभाषा नहीं बन जाती, तब तक समूचे देश में उसका राष्ट्रभाषा बनना स्वप्नवत् ही रहेगा।

हिन्दी-भाषी प्रदेश के शिक्षित जन बंगाल या तमिलनाडु के लोगों पर अक्सर भाषागत सकीर्णता या प्रान्तीयता का दोष लगाते हैं। वास्तविकता यह है कि बंगाल या तमिलनाडु के शिक्षित जन अपनी भाषा से जितना प्रेम करते हैं अपने सामाजिक जीवन में उसका जितना प्रयोग करते हैं, उतना हम नहीं करते। अन्य प्रदेशों के शिक्षित-जन यदि अपने यहाँ के साहित्य से अपरिचित हो तो उन्हें शर्म आयेगी। हमारे प्रदेश के शिक्षित जन हिन्दी-साहित्य से अपरिचित होने में गर्व का अनुभव करते हैं। अपने अज्ञान पर गर्व करते हुए वे पिछले तीस वर्षों से लगातार एक ही प्रश्न दोहराते चले आए हैं— हिन्दी में है ही क्या ?

हिन्दी-भाषी प्रदेश की जनता से बोट लेना और उसकी भाषा और साहित्य को गालियाँ देना कुछ नेताओं का दैनिक व्यवसाय है। हमारे प्रदेश के शिक्षित जनो में जातीय भावना की कमी है। वे हिन्दी के प्रति उदासीन हैं, इसीलिए वे कुछ राजनीतिज्ञों की अपमानजनक बातों का समुचित उत्तर नहीं दे पाते। यहाँ का राजनीतिज्ञ राजनीति के अलावा अंग्रेजी-भक्ति में जनता का नेतृत्व करता है। अंग्रेजी में जितनी पुस्तकें केवल उत्तर प्रदेश के राजनीतिज्ञों ने लिखी हैं, उतनी शेष भारत के सारे राजनीतिज्ञों ने नहीं लिखी। अन्य प्रदेशों के नेताओं में एक पुस्तक अंग्रेजी में लिखी तो दो अपनी भाषा में भी लिखी। यहाँ का राजनीतिज्ञ यदि देवनागरी में हस्ताक्षर कर दे तो समझता है कि उसने हिन्दी को कृपाएँ कर दिया।

यह किसी नेता-विशेष का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है एक समूचे अंग्रेजी-प्रेमी वर्ग का, जो प्रदेश का शासक है या शासक बनना चाहता है। राजनीतिज्ञ इसी वर्ग का प्रतिनिधि है। एक नेता हट जाएगा तो दूसरा आ जाएगा क्योंकि उसे जन्म देनेवाला वर्ग मौजूद है। इसीलिए हिन्दी-भाषी प्रदेश में हिन्दी-प्रचार की आवश्यकता है, हिन्दी-प्रचार द्वारा शिक्षित जनो का दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है, उनके सामाजिक व्यवहार में, सांस्कृतिक जीवन में, शिक्षा-संस्थाओं के अन्तर्गत उनकी कार्यवाही में अंग्रेजी की जगह हिन्दी को प्रतिष्ठित कराने की आवश्यकता है।

मिथ्या जातीय अहंकार हानिकार होता है। अपनी भाषा और साहित्य को

ही ध्येष्ठ समझता और दूसरो की भाषा और साहित्य को सदा हीन समझता मूर्खता है। किन्तु जातीय भावना से हीन होकर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का मन्त्र जपना भी कोई बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता का चिह्न नहीं है। हमारा राष्ट्र अपनेक भाषाएँ बोलनेवाली जातियों से मिलकर बना है। राष्ट्रीय एकता के लिए इन जातियों की एकता आवश्यक है। सभी जातियाँ मिलकर राष्ट्र को दृढ़ करें, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक जाति अपने भीतर दृढ़ हो, अपने-आपमें एकताबद्ध हो। कोई भी जाति अपने भीतर शिथिल होकर राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने में उचित योग नहीं दे सकती।

हिन्दी भाषी जाति विभिन्न राज्यों में बँटी हुई है। हिन्दी-भाषी प्रदेश की सीमाएँ अनिश्चित हैं। यही नहीं, भाषागत विवाद जितने यहाँ हैं, उतने किसी अन्य प्रदेश में नहीं हैं। दूसरी जगह विवाद होगा तो बँगला-असमिया या गुजराती-मराठी जैसी दो भिन्न भाषाओं को लेकर। यहाँ के विवाद एक ही भाषा-क्षेत्र के अन्तर्गत हैं।

मिथिला के कुछ राजनीतिज्ञ हिन्दी को अपनी जातीय भाषा नहीं मानते। पिछले चुनाव में उन्होंने अपने राजनीतिक प्रचार के पर्व में मैथिली और उर्दू में छपवाये। हिन्दी का बहिष्कार किया। भोजपुरी क्षेत्र में जन्म लेनेवाले कुछ हिन्दी के आचार्य भाषा-विज्ञान पर अन्य लिखकर यह सिद्ध करते हैं कि भोजपुरी हिन्दी से स्वतन्त्र भाषा है। जिन्हें हम हिन्दी की बोलियाँ कहते हैं, उनके क्षेत्रों में हिन्दी प्रचार आवश्यक है, जिससे वहाँ के शिक्षित-जन का वह भाग, जो अपनी बोली को स्वतन्त्र भाषा मानता है, जातीय भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करे। जब तक साधारण जनता के सामने यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि हिन्दी प्रदेश की सीमाएँ कौन-सी हैं, उसमें कौन-सी बोलियों का चलन है, उन्हें अब स्वतन्त्र भाषा न मानना चाहिए, तब तक मसूचे देश में तथा अपने ही प्रदेश में हिन्दी को उसका उचित स्थान दिलाने के लिए यह विनाश जनता सत्रिय नहीं हो सकती। हिन्दी प्रचार का एक लक्ष्य होना चाहिए। जातीय प्रदेश का गठन, उसमें सर्वत्र जातीय भाषा के रूप में हिन्दी का चलन।

जातीय भाषा और राष्ट्रभाषा में अन्तर है। महाराष्ट्र, बंगाल या तमिलनाडु के लोगों की जातीय भाषा मराठी, बँगला या तमिल है, हिन्दी नहीं। हिन्दी इन लोगों की राष्ट्रभाषा है, जो पारस्परिक आदान प्रदान का माध्यम बनती है। हिन्दी भाषियों के लिए हिन्दी जातीय भाषा है जैसा महाराष्ट्र के लोगों के लिए मराठी जातीय भाषा है। जातीय भाषा होने के साथ-साथ हम हिन्दी-भाषियों के लिए हिन्दी राष्ट्रभाषा भी है। मिथिला के कुछ शिक्षित-जन हिन्दी को राष्ट्रभाषा तो मानते हैं किन्तु अपनी जातीय भाषा नहीं मानते। मराठी के समान वे मैथिली को हिन्दी न स्वतन्त्र भाषा मानते हैं।

मनेज महिन्दी भाषी अंग्रेजी-श्रेणी विद्वान् इसी तर्क का आग्रह लेते हैं और कहते हैं कि हिन्दी अपने ही क्षेत्र में दूसरों पर सारी गई भाषा है। यह प्रचार



करते हैं कि ब्रज, ध्रुवधी, भुन्देलखण्डी, भोजपुरी आदि सब स्वतन्त्र भाषाएँ हैं जिन पर कृत्रिम साहित्यिक हिन्दी जबरदस्ती लादी गई है। ये लोग भूल जाते हैं कि इंग्लैण्ड, रूस, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों में अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, जर्मन आदि भाषाओं की वैसे ही बोलियाँ हैं जैसे हिन्दी की। इन सब भ्रान्तियों के निवारण के लिए हिन्दी-भाषी प्रदेश में हिन्दी-प्रचार आवश्यक है।

हिन्दी-उर्दू समस्या को अधिकांश हिन्दी-प्रेमी भूल-से गए थे। रेडिया द्वारा हिन्दी के सरलीकरण ने उन्हें नौद से जगा दिया। भारतेन्दु से लेकर प्रेमचन्द तक हिन्दी के तमाम लेखक अपनी भाषा को बठिन बनाते रहे, जिससे जनता उनका साहित्य समझ न पाये, अब उस हिन्दी को सरल बनाने का बीड़ा उठाया है आकाशवाणी ने। यह सरलीकरण का प्रश्न उस समय उठाया गया जिस समय अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए राजभाषा घोषित किया गया। हिन्दी-उर्दू के भगड़े में फिर से जान डालकर राष्ट्रभाषा के रूप में अंग्रेजी को नवजीवन दिया गया।

हिन्दी के कुछ विद्वान् मानते हैं कि मुसलमानों की भाषा उर्दू है, जो हिन्दी से स्वतन्त्र है। बंगाल के मुसलमानों की बंगला से स्वतन्त्र कोई भाषा क्यों नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर वे नहीं देते। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हमारे देश की श्रमिक जनता में कहीं भी धर्म के आधार पर भाषागत विभाजन नहीं दिखाई देता। बानपुर, सखनऊ, पटना आदि के हिन्दू-मुसलमान मजदूर आपस में एक ही सामान्य भाषा का व्यवहार करते हैं। जो लोग हिन्दुओं और मुसलमानों की दो भाषाएँ मानते हैं, जो हिन्दी और उर्दू को मूलतः दो भाषाएँ मानते हैं, उन्हें यह समझाना चाहिए कि भाषा की आधारभूमि कोटि कोटि श्रमिक जनता है, न कि मुट्ठी-भर पढ़े-लिखे लोग।

उर्दू प्रेमियों में इस बात का प्रचार करना आवश्यक है कि उनकी भ्रलष कीम नहीं है, वे विशाल हिन्दी भाषी जाति का अंग हैं, प्रत्येक जाति की एक ही भाषा होती है दो नहीं, हिन्दी-उर्दू मूलतः एक ही भाषा हैं, इसलिए उनका साहित्यिक रूप दो न होकर एक ही होगा, हिन्दी-उर्दू के भ्रलषाव से हमारी जातीय सस्कृति पूरी शक्ति से विकसित नहीं हो पाती। उर्दू-प्रेमी कबीर, जायसी, रसखान, रहीम आदि की साहित्यिक परम्परा से अपना सम्बन्ध जोड़ें, भारत की अन्य भाषाओं के विकास के अनुकूल उर्दू को मोड़ें, इससे तुरन्त नहीं किन्तु कुछ समय बाद हमारी सामान्य साहित्यिक परम्परा विकसित होगी। उर्दू-प्रेमियों के साथ इस तरह का प्रचार उन हिन्दी-प्रेमियों में भी करना आवश्यक है, जो हिन्दुओं और मुसलमानों को दो भिन्न जातियाँ मानते हैं।

हिन्दी भाषी जनता की शक्ति अपार है किन्तु वह असंगठित और बिलरी हुई है। हिन्दी-भाषियों के जातीय हित में इस शक्ति को संगठित करना आवश्यक है। समूचे राष्ट्र को एकताबद्ध और दृढ़ करने के लिए हिन्दी भाषी जाति की एकता आवश्यक है। इस एकता के मार्ग में पहली बाधा है अंग्रेजी प्रेम।

दूसरी बाधा है आंचलिक बोलियों को स्वतन्त्र भाषा मानने की भ्रान्ति । तीसरी बाधा है हिन्दी-उर्दू प्रेमियों का दो खेमों में बँटकर जातीय सस्कृति को कमजोर करना । इन तीनों बाधाओं के फलस्वरूप अपनी जातीय शक्ति के उपयोग द्वारा हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के अपने उत्तरदायित्व को हम निवाह नहीं पाते ।

यदि ममस्त हिन्दी-भाषी प्रदेश में शिक्षा-संस्थाओं, न्यायालयों, राजकीय कार्यों में हर स्तर पर हिन्दी का व्यवहार होने लगे, यदि विधान-परिषदों के सदस्य प्रतिज्ञा करें कि वे अपना सार्वजनिक कार्य हिन्दी में ही करेंगे, यदि लोकसभा के सदस्य तय कर लें कि वे राजभाषा के रूप में हिन्दी का ही व्यवहार करेंगे तो क्या इसमें किसी को मन्देह हो सकता है कि समूचे राष्ट्र का वातावरण बदल जाएगा और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनते जरा भी देर न लगेगी ?

हम हिन्दी-भाषी किसी पर हिन्दी लादना नहीं चाहते । जो अंग्रेजी ही बोलना पसन्द करे उससे जबरदस्ती हिन्दी बोलवाना नहीं चाहते । किन्तु हमें भी अंग्रेजी बोलने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता । लोकसभा और राज्य-सभा के वे सदस्य और मन्त्री, जो हिन्दी-भाषी प्रदेश से चुने गए हैं, जिस दिन तय कर लेंगे कि अंग्रेजी के बदले हिन्दी का ही प्रयोग करेंगे, उसी दिन हिन्दो व्यवहारत राष्ट्रभाषा बन जाएंगी । यदि ऐसा नहीं होता तो कमजोरी हमारी है । हमें हिन्दी प्रचार द्वारा स्वयं अपने प्रदेश की जनता को जाग्रत करना है, अपने प्रदेश के नेताओं में हिन्दी की उपेक्षा दूर करनी है, स्वयं अपने प्रतिनिधियों को बाध्य करना है कि वे राजकाज में और सर्वत्र हिन्दी का व्यवहार करें । इस तरह के प्रचार और संगठन द्वारा ही अपनी जातीय शक्ति के अनुरूप हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का अपना गहन उत्तरदायित्व पूरा कर सकते हैं ।

(१९६२)

## सरकारी कोशकार और राष्ट्रभाषा

तीस से अधिक वर्ष हुए, जनवरी, १९३२ की 'मुष्पा' में अंग्रेजी-हिन्दी कोश-सम्बन्धी एक टिप्पणी प्रकाशित हुई थी। टिप्पणी के अनुसार श्री सुखसम्पति-राय भण्डारी ने 'विद्वान् और विशेषज्ञों की सहायता से' लगभग बीस हजार रुपये खर्च करके प्रायः डेढ़ लाख शब्दों का यह कोश तैयार किया था जिसकी प्रशंसा प्रयाग विश्वविद्यालय के बाइस चासलर डॉ० गगनाश भा, पंजाब विश्व-विद्यालय के बाइस चासलर डॉ० ए० सी० बूलनर, डॉ० राधाबुमुद मुबर्जी, डॉ० बेनीप्रसाद, डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी आदि विद्वानों ने की थी और सर पी० सी० राय ने इसे महान् प्रशंसनीय साहित्यिक कार्य कहते हुए, बंगाली, मराठी और गुजराती भाषा-भाषियों के लिए भी अत्यन्त उपयोगी बतलाया था।

हिन्दी-भाषी विद्वान् इस बात की ओर बहुत पहले से सचेत रहे हैं कि हमारी भाषा आधुनिक विज्ञान तथा सस्कृति से सम्बन्धित विचारों को प्रकट करने में सक्षम हो। सरकार की सहायता के अभाव में, अक्सर प्रच्छन्न सरकारी विरोध का सामना करते हुए सुखसम्पतिराय भण्डारी जैसे विद्वानों ने घोर परिश्रम करके पारिभाषिक शब्दों की कमी को पूरा किया। नागरी-प्रचारिणी सभा जैसी संस्थाओं ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। डॉ० सत्यप्रकाश जैसे विद्वानों ने वैज्ञानिक विषयों पर लेख लिखकर और दूसरों से लिखाकर पारिभाषिक शब्दों के प्रचार में सहायता की। भारत के स्वाधीन होने पर जब अंग्रेजी को हटाने, भारतीय भाषाओं को उनका स्वत्व देने और परस्पर व्यवहार तथा केन्द्रीय राज-काज के लिए हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सवाल सामने आया तब हिन्दी से नितान्त अनभिज्ञ, देवनागरी में बठिनाई से हस्ताक्षर कर पानेवाले देश के अनेक सम्मान्य राजनीतिज्ञों ने घोषित किया कि हिन्दी को विकसित होने, आधुनिक विचारों की अभिव्यक्ति के योग्य बनने के लिए अभी और समय देना चाहिए। संविधान में इस बात को दर्ज कर दिया गया कि हिन्दी को विकसित किया जाय और सस्कृत तथा अन्य भाषाओं से आवश्यकतानुसार शब्द लेकर (या नये शब्द गढ़कर) उसे समृद्ध किया जाय।

भारत सरकार ने १९५० में विज्ञान-सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द-संग्रह के लिए एक समिति स्थापित की। शिक्षा मन्त्रालय के तत्वावधान में हिन्दी को विकासमान और समृद्ध करने का बृहत् कार्य बारह साल तक चलता रहा और १९६२ में 'पारिभाषिक शब्द-संग्रह' नामक सरकारी कोश प्रकाशित हो गया।

भूमिका में सरकारी नीति स्पष्ट कर दी गई है। शिक्षा मन्त्रालय के तत्वावधान में दस वर्षों की अवधि में जितने पारिभाषिक शब्द रचे गए, उन्हें कोशबद्ध किया गया। अंग्रेजी में श्री आर० पी० नायक लिखित इस भूमिका में 'इवोल्व' और 'इवोल्यूशन' शब्दों का अनेक बार प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का आशय यही है कि हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों का अभाव था, इसलिए शिक्षा मन्त्रालय द्वारा संचालित हिन्दी निदेशालय में नवीन शब्दावली रची गई। एक जगह यह स्पष्ट लिखा है कि १९६१ के मध्य तक विशेषज्ञ-समितियों की संख्या २६ हो गई थी और 'नव-निर्मित' शब्दों की संख्या लगभग तीन लाख तक पहुँच गई थी (द टर्म्स क्वायण्ड वेम टु नियरली थी लैक्स)। ये शब्द 'क्वायन' किये गए थे, हिन्दी में ये नहीं, उसे विकसित करने के लिए निदेशालय में ये तीन लाख शब्द ढाले गए थे।

अधिकांश भारतीय राजनीतिज्ञों के लिए जीवन के अनेक स्वीकृत मूल्यों के समान हिन्दी की दरिद्रता भी स्वयंसिद्ध सत्य है जिसे प्रमाणित करने के लिए किसी आयोग या समिति की जरूरत नहीं है। अंग्रेजी की समृद्धि उसी प्रकार दूसरा ध्रुव सत्य है जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। इन दो ध्रुवों की धुरी पर भारतीय जनतन्त्र की राजनीति अनवरत घावर्तन करती है।

यदि इस सरकारी कोश के सभी या अधिकांश शब्द नये सिरे से गढ़े गए हों, तो वे हिन्दी-भाषी बुद्धिजीवियों के लिए अपरिचित होंगे, कोश के पन्ने पलटने पर ऐसा लगेगा कि हम शब्दों की नई दुनिया में घ्रा गए हैं, जिनके रूप और अर्थ स हमारा पहली बार साक्षात्कार हो रहा है। वैसे तो किसी अपारिभाषिक कोष में भी साधारण पाठकों को हजारों शब्द मिल जाएँगे जिनसे वे परिचित न होंगे। इसलिए पारिभाषिक कोश में अजनबी लगनेवाले शब्दों का होना आश्चर्यजनक नहीं है। आश्चर्यजनक बात यह है कि हर पृष्ठ पर अनेक ऐम शब्द मिल जाते हैं जिनसे साधारण पाठक अच्छी तरह परिचित है और जिन्हें नायक साहब के अनुसार 'क्वायन' किया गया है।

एक निगाह इन शब्दों पर डालिए वायुमण्डल, उपलब्धि, आक्रमण, ध्यान, प्रायश्चित्त, मन्त्रिमण्डल, नैतिक, उपहाम, त्वचा, बुद्धि, आशय, अभिप्राय, सौन्दर्यशास्त्र, रसायन, विनिमय, द्रव्य, पदार्थ, विषयवस्तु, मनोविज्ञान, मनो-विश्लेषण, सापेक्ष, नीतिशास्त्र, पुरातत्व, प्रतियोगिता, घनत्व, प्रत्याख्यान, प्रत्यक्ष, परोक्ष, उद्योग, सक्रमण, भावपूर्ण, विकर्षण इत्यादि। इस तरह के हजारों शब्द इस कोश में हैं जो हिन्दी में वर्षों से प्रचलित हैं और जिनके लिए कोई यह दावा भी नहीं कर सकता कि उन्हें नये सिरे से गढ़ा गया है। इनके

लिए यह दावा भी नहीं किया जा सकता कि वे अन्य कोशों में नहीं हैं। किन्तु हिन्दी को समृद्ध करने, उसे राष्ट्रभाषा पद के योग्य बनाने के लिए शिक्षा मन्त्रालय और विशेषज्ञ समितियों ने जो धोर परिश्रम किया, उसमें इस तरह के शब्दों का संग्रह भी शामिल है।

इनके अलावा इस कोश में हिन्दी के ऐसे हजारों अतिप्रचलित शब्द हैं जिन्हें साधारण बुद्धि के लोग पारिभाषिक स्वीकार ही न करेंगे। प्रचलित शब्द भी पारिभाषिक हो, इस पर आपत्ति नहीं है। प्रश्न दूसरा है। क्या ये शब्द गढ़े गए हैं? क्या ये पहले से हिन्दी में या हिन्दी कोशों में थे नहीं? कपूर, अलाप, डेरा कमरा, सरीसरी, सदी शताब्दी, खतरा निश्चित, जादू टोना, जादूगर, छपाई जुड़ाई, उपाय, रोप, याद, माफी, धमा पुनर्विवाह प्रभावित, विनाश भ्रजवायन सौंफ, सुपारी, उधार, शोरा, मदिरा, अदली, चपरासी, विराया रोजगार, कार्यालय दफ्तर, मुठभेड़, तैरना, छाधुनिक वैश्यालय चकला, हिलवा, मामले, दितराना मरम्मत करना, प्रयत्न करना, चिपकाना, पर्याप्त, काम रोकना, दायध दिलाना स्तन, साँस, से, परे, ठीक है, धर्म, छूट देना, छट्टी पाना, जरा हट के, गिर गया दौड़ते हुए, इस हालत में, इत्यादि। इस तरह के शब्दों को देखकर यह प्रस्ताव करने की इच्छा होती है कि कोश के द्वितीय संस्करण में खाना, पीना, उठना बैठना, चलना, सोना, घरती, आकाश, पानी हवा, धूल, आलू मटर, टमाटर बैंगन, गाजर, मकान, छत, फस, दरवाजा, सिडकी, पिता, पुत्र, बहन, भाई चाचा, ताऊ आदि-आदि शब्दों को भी पारिभाषिकों में गिन लेना चाहिए और भूमिका में आगले दस वर्षों के समृद्धीकरण-प्रोग्राम की सफलता के रूप में उन्हें पेश कर देना चाहिए। किन्तु सम्भव है, इनमें और इन जैसे अनेक शब्द इस कोश में पहुँचे न ही हों और मैंने उन पर ध्यान न दिया हो। जो भी हो, जब तक ये शब्द सरकारी कोश में दर्ज नहीं हुए, तब तक हिन्दी दरिद्र थी। दर्ज होने के बाद भी हिन्दी समृद्ध होकर राष्ट्रभाषा नहीं बनी—वह प्रश्न भलग है।

यह कहा जा सकता है कि ऊपर जिन तरह के शब्दों का उल्लेख किया गया है, वे हिन्दी में थे जल्द किन्तु अर्थ निश्चित नहीं था, पारिभाषिक शब्द संग्रह करनेवालों ने हिन्दी की यह सेवा की है कि अस्थिर अर्थवाले शब्दों को अंग्रेजी पर्यायों के माध्यम से निश्चित ढंग में नष्ट कर दिया है। भूमिका में भारतीय कोशकारों के प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए शब्दों के अरथ की चर्चा की गई है जहाँ लेखकों और ग्राहकों दोनों को रास्ता नहीं भ्रमता। किन्तु इस कोश के पन्ने पलटने पर यह समझने में दिगी को देर न लगेगी कि यहाँ हजार अंग्रेजी शब्द ऐसे हैं जिनके एक में अधिक हिन्दी-पर्याय दिये गए हैं। उदाहरण के लिए, ग्याप क्षेत्र में ऐंजार्ड शब्द के लिए—विनियोग करना, प्रयोग करना नाग करना, आवेदन करना, प्रार्थनापत्र देना, जीव विज्ञान के अन्तर्गत 'लैरिक्स' के लिए—कण्ट, स्वरयन्त्र, लैरिक्स। 'डम्क' शब्द के आगे यह नहीं

लिखा कि वह किस क्षेत्र का पारिभाषिक शब्द है, किन्तु उसके तीन पर्याय दिये गए हैं—गोधूलि, घुरी (?) , साँक। भ्रमशास्त्र के प्रचलित शब्द 'मचेंट' के लिए—सोदागर, सायंवाह, व्यापारी, वणिक्। प्रचलित शब्द 'रिलीव' के लिए—छुट्टी देना, छुट्टी पाना (!), छुट्टी मिलना (नौकरी &), भारमुक्त करना, भ्रममुक्त करना। 'यूनिट' शब्द के भागे भी सचेत नहीं है कि वह किस क्षेत्र का पारिभाषिक है। उसके पर्याय—मात्रक, एक्क, (इ) काई, दल, एकाग, एकाश, यूनिट, एकाक !

सरकारी कोश के सरक्षवर्ण स्वयं देख सकते हैं कि शब्दों की बहुलता कम नहीं हुई, उसमें कुछ इजाफा ही हुआ है। पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि इस शब्द-संग्रह में गोधूलि, साँक, सोदागर जैसे शब्द ही हैं तो उनके संग्रह के लिए इतना परिश्रम क्यों ? नहीं, साँक, गोधूलि और सोदागर तो सरकारी संपर्क से पारिभाषिक बन गए हैं। इनके अलावा ऐसे भी हजारों शब्द हैं जिन्हें देखते ही कोई कह देगा कि वे पारिभाषिक हैं। उदाहरण के लिए, ससक्ति, नम्यता, भविलेयता, गलनाक, वाष्पायन, ऊष्मा, सघनन, विकिरण, प्रच्छाया, उपच्छाया, परावर्तन, भवतल, उत्तल, प्रक्ष, भण्डाशय, अपचय, प्रमल, क्षार, भणु, परमाणु, चाप, समीकरण, समायवी, भ्रवक्षेपण, द्रव, ज्वलनशील, भौतिकी, भौतिकी इत्यादि—ये सब शब्द आपको इस कोश में मिलेंगे। किन्तु आप यदि थोड़ा-सा परिश्रम करें तो आप देखेंगे कि ये शब्द विद्यार्थियों की उन पाठ्य-पुस्तकों में भी प्रयुक्त हुए हैं जो इस कोश निर्माण से पहले प्रकाशित हुई थीं। इन्हें 'इचौत्व' करने या 'ववायन' करने का दावा इस कोश के सम्पादक लोग नहीं कर सकते।

इस सरकारी कोश में ऐसे भी हजारों शब्द हैं जिन्हें तीस वर्ष पहले ही श्री सुखसम्पतिराय भण्डारी और उनके सहयोगियों ने 'ववायन' या 'इचौत्व' कर लिया था। इनमें भणु, परमाणु, धूमकेतु, निरपेक्ष, भ्रमूर्त, सूत्र, मताधिकार, निर्वाचन-क्षेत्र, राष्ट्रीयकरण, समाजवाद, लोकतन्त्र जैसे शब्द हैं। ऐसे शब्द साधारण हिन्दी गद्य में बराबर प्रयुक्त होते रहे हैं। इनके अतिरिक्त विज्ञान-सम्बन्धी शब्द भी हैं, जिनका व्यवहार वैज्ञानिक पुस्तकों में होता है। 'डिफरेंशल इक्वेशन'—भ्रवकल समीकरण; 'डिफ्रैक्शन'—विवर्तन; 'माइसोमेरिज्म'—समावयवता, 'लेटरल'—पार्श्विक, 'वेन'—क्षिरा, 'वर्टीब्रा'—कशेरुका; 'यूटेरस'—गर्भाशय; 'लैरिक्स'—स्वर-यन्त्र, 'अपेण्डिक्स'—परिशिष्ट; 'काटिलेज'—उपास्थि; 'क्लैविकल'—प्रक्षक; 'कोर्टेक्स'—वल्क; 'डक्ट'—वाहिनी; 'कोन'—शकु; 'कौपंस कैलोसम'—महासंयोजक; 'रेडिएशन'—विकिरण; 'मैग्नेटिज्म'—चुम्बकत्व; 'लोगैरियम'—लघुगणक; 'कैलकुलस'—कलन; 'हिप्नोटिज्म'—सम्मोहन; 'इनहिबिशन'—भ्रवरोध; 'साइको-एनैलिसिस'—मनोविव्लेषण; 'एनालीजी'—सादृश्य; 'एल्ड्रिज्म'—परायंवाद; 'ऐनाबोलिज्म'—चय; 'भॉकलिटिज्म'—गुहाविद्या; 'स्प्लीन'—प्लीहा, 'डेंसिटी'—घनत्व इत्यादि।

इस तरह के हजारों शब्द भण्डारी-कोश और उनके तीस साल बाद के

लिए यह दावा भी नहीं किया जा सकता कि वे धन्य बोधो में नहीं हैं । किन्तु हिन्दी को समृद्ध करने, उसे राष्ट्रभाषा-पद के योग्य बनाने के लिए शिक्षा मन्त्रालय और विशेषज्ञ समितियों ने जो घोर परिश्रम किया, उसमें इस तरह के शब्दों का संग्रह भी शामिल है ।

इनके अलावा इस कोश में हिन्दी के ऐसे हजारों अतिप्रचलित शब्द हैं जिन्हें साधारण बुद्धि के लोग पारिभाषिक स्वीकार ही न करेंगे । प्रचलित शब्द भी पारिभाषिक हों, इस पर आपत्ति नहीं है । प्रश्न दूसरा है । क्या ये शब्द गढ़े गए हैं ? क्या ये पहले से हिंदी में या हिन्दी बोधो में थे नहीं ? बपूर, अलाप, डेरा, कमरा, खरीदारी, सदी शताब्दी, खतरा निश्चित, जादू टोना, जादूगर, छपाई, जुड़ाई, उपाय, रोप याद, माफी, धमा पुनर्विवाह प्रभावित, विनाश अजवायन, सीफ, मुपारी, उधार, शोरा, मदिरा, अदंली, चपरासी, विराया रोजगार, कार्यालय, दपतर, मुठभेड़, तैरना, आधुनिक वेध्यालय चक्का, हिलवा, मामले, दितराना, मरम्मत करना, प्रयत्न करना, चिपकाना, पर्याप्त, काम रोकना, शपथ दिलाना, स्तन, साँस, से, परे, ठीक है, धर्म, छूट देना, छट्टी पाना, जरा हट के, गिर गया, दीड़ते हुए, इस हालत में, इत्यादि । इस तरह के शब्दों को देखकर यह प्रस्ताव करने की इच्छा होती है कि कोश के द्वितीय सस्करण में खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, सोना, धरती, आकाश, पानी हवा, धूल, भालू, मटर, टमाटर, बैंगन, गाजर, मकान, छत, पर्श, दरवाजा, खिड़की, पिता, पुत्र, बहन, भाई, चाचा, ताऊ आदि-आदि शब्दों को भी पारिभाषिकों में गिन लेना चाहिए और भूमिका में अगले दस वर्षों के समृद्धीकरण-प्रोग्राम की सफलता के रूप में उन्हें पेश कर देना चाहिए । किन्तु सम्भव है, इनमें और इन जैसे अनेक शब्द इस कोश में पहले से ही हों और मैंने उन पर ध्यान न दिया हो । जो भी हो, जब तक ये शब्द सरकारी कोश में दर्ज नहीं हुए, तब तक हिन्दी दरिद्र थी । दर्ज होने के बाद भी हिन्दी समृद्ध होकर राष्ट्रभाषा नहीं बनी—वह प्रश्न अलग है ।

यह कहा जा सकता है कि ऊपर जिस तरह के शब्दों का उल्लेख किया गया है, वे हिन्दी में थे जल्द किन्तु अर्थ निश्चित नहीं था, पारिभाषिक शब्द-संग्रह करनेवालों ने हिन्दी की यह सेवा की है कि अस्थिर अर्थवाले शब्दों को अंग्रेजी पर्यायों के साथ निश्चित ढंग से नत्थी कर दिया है । भूमिका में भारतीय कोश-कारों के प्रयत्नों का उल्लेख करते हुए शब्दों के अरण्य की चर्चा की गई है, जहाँ लेखकों और साधारण जनों को रास्ता नहीं सूझता । किन्तु इस कोश के पन्ने पलटने पर यह समझने में किसी को देर न लगेगी कि यहाँ हजारों अंग्रेजी शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक हिन्दी पर्याय दिये गए हैं । उदाहरण के लिए, न्याय क्षेत्र में 'ऐप्लाइड' शब्द के लिए—विनियोग करना, प्रयोग करना, लागू करना, आवेदन करना, प्रार्थनापत्र देना, जीव विज्ञान के अन्तर्गत 'लैरिक्स' के लिए—कण्ठ, स्वरयन्त्र, लैरिक्स । 'डस्क' शब्द के आगे यह नहीं

लिखा कि वह किस क्षेत्र का पारिभाषिक शब्द है, किन्तु उसके तीन पर्याय दिये गए हैं—गोधूलि, धुरी (?), सॉफ़। भ्रयंसास्त्र के प्रचलित शब्द 'मर्बेन्ट' के लिए—सौदागर, सार्यबाह, व्यापारी, वणिक्। प्रचलित शब्द 'रिलीव' के लिए—छुट्टी देना, छुट्टी पाना (१), छुट्टी मिलना (नौकरी ८), भारमुक्त करना, भ्रवमुक्त करना। 'यूनिट' शब्द के आगे भी सकेत नहीं है कि वह किस क्षेत्र का पारिभाषिक है। उसके पर्याय—मात्रक, एकक, (इ) काई, दल, एकाग, एकाश, यूनिट, एकाक।

सरकारी कोश के सारक्षकगण स्वयं देख सकते हैं कि शब्दों की बहुलता कम नहीं हुई, उसमें कुछ इजाफा ही हुआ है। पाठक प्रश्न कर सकते हैं कि इस शब्द-संग्रह में गोधूलि, सॉफ़, सौदागर जैसे शब्द ही हैं तो उनके संग्रह के लिए इतना परिश्रम क्यों ? नहीं, सॉफ़, गोधूलि और सौदागर तो सरकारी सम्पर्क से पारिभाषिक बन गए हैं। इनके अलावा ऐसे भी हजारों शब्द हैं जिन्हें देखते ही कोई कह देगा कि वे पारिभाषिक हैं। उदाहरण के लिए, ससक्ति, नम्यता, भविलेयता, गलनाक, वाण्यायन, ऊष्मा, सघनन, विविरण, प्रच्छाया, उपच्छाया, परावर्तन, प्रवतल, उत्तल, भक्ष, भण्डाराय, अपचय, घम्ल, क्षार, भणु, परमाणु, चाप, समीकरण, समायोज, भ्रवक्षेपण, द्रव, ज्वलनशील, भौतिकी, भौतिकी इत्यादि—ये सब शब्द आपको इस कोश में मिलेंगे। किन्तु आप यदि थोड़ा-सा परिश्रम करें तो आप देखेंगे कि ये शब्द विद्यापियों की उन पाठ्य-पुस्तकों में भी प्रयुक्त हुए हैं जो इस कोश निर्माण से पहले प्रकाशित हुई थी ! इन्हें 'इश्वरत्व' करने या 'व्यायन' करने का दावा इस कोश के सम्पादक लोग नहीं कर सकते।

इस सरकारी कोश में ऐसे भी हजारों शब्द हैं जिन्हें तीस वर्ष पहले ही श्री सुखसम्पतिराय भण्डारी और उनके सहयोगियों ने 'व्यायन' या 'इश्वरत्व' कर लिया था। इनमें भणु, परमाणु, धूमकेतु, निरपेक्ष, भ्रमूर्त, सूत्र, मताधिकार, निर्वाचन-क्षेत्र, राष्ट्रीयकरण, समाजवाद, लोकतन्त्र जैसे शब्द हैं। ऐसे शब्द साधारण हिन्दी गद्य में बराबर प्रयुक्त होते रहे हैं। इनके प्रतिरिक्त विज्ञान-सम्बन्धी शब्द भी हैं, जिनका व्यवहार वैज्ञानिक पुस्तकों में होता है। 'डिफरेंशल इक्वेशन'—भ्रवजन समीकरण, 'डिफरेंशन'—विवर्तन; 'साइसोमेरिज्म'—समाव-यवता, 'लेटरल'—पार्श्विक; 'वेन'—शिरा, 'वर्टीका'—क्षेपिका; 'यूटेरस'—गर्भाशय; 'लैरिक्स'—स्वर-यन्त्र, 'अपेण्डिक्स'—परिशिष्ट; 'कार्टिलेज'—उपास्थि; 'क्लैविकल'—घशक; 'कौटैक्स'—वल्क; 'इक्ट'—वाहिनी; 'कोन'—शकु; 'कौपंस कैलोसम'—महासंयोजक, 'रैडिएशन'—विकिरण; 'मैग्नेटिज्म'—चुम्बकत्व; 'लोमैरिफम'—लपूगणक; 'कैन्कुलस'—कसन; 'हिप्नोटिज्म'—सम्मोहन; 'इनहिबिशन'—ध्वरोध; 'साइको एनेलिसिस'—मनोविश्लेषण; 'एनालोजी'—सादृश्य; 'ऐल्ड्र-इज्म'—परार्थवाद; 'ऐनाबोलिज्म'—वृद्धि; 'मॉकलिटिज्म'—गुहाविद्या; 'स्प्लीन'—प्लीहा, 'डेंसिटी'—घनत्व इत्यादि।

इस तरह के हजारों शब्द भण्डारी-कोश और उसके तीस साल बाद के



सरकारी कोश में ज्यो-जे-त्यों विद्यमान हैं। इनके मित्रा ऐसे भी सँवहो शब्द हैं जिनमें सरकारी कोश ने नाममात्र का परियन्तन किया है। 'डायलेटेडान' के लिए भण्डारी के 'विस्तारन' को यहाँ 'विस्तारण' कर दिया गया है, 'न' का 'ण' ! अथवा 'सिस्टोल' के लिए भण्डारी-श्रुत 'भाक्चन' सरकारी कोश में 'प्रकुचन' हो गया। 'थोरेंसिक' के लिए भण्डारी ने लिखा 'वदा-सम्बन्धी'; सरकारी कोश में उसे 'वक्षीय' कर दिया गया ! 'माइसोटोप' के लिए भण्डारी ने लिखा 'समस्थानीय', सरकारी कोश ने उसे किया 'समस्थानिक'।

इस सरकारी कोश के सम्पादकों-सरक्षकों से यह पूछना अनूचित न होगा कि आखिर वे शब्द कौन-से हैं जिन्हें दस साल में आप लोगो ने 'इवोन्व' किया है, या 'ववायन' किया है, जिनके प्रभाव में हिन्दी राष्ट्रभाषा न बन सकती थी, दरिद्र थी, प्राधुनिक जीवन से सम्बन्धित विचारों को प्ररट करने में अक्षम थी ? प्रत्येक हिन्दी-प्रेमी को सरकार और उसके मुलाजिमों से यह प्रश्न करना चाहिए कि दस साल से लगातार हिन्दी के जिन प्रभावों की आप घोषणा कर रहे थे, वे कौन-से हैं, किन शब्दों की रचना करके आपने उन प्रभावों की पूर्ति की है ? अपार धन व्यय करके आपने जिस कोश की रचना की है, स्पष्ट बताइए कि इसमें कितने शब्द ऐसे हैं जो हिन्दी में पहले से विद्यमान न थे ?

मेरा अनुमान है कि कोश में नये गढ़े हुए शब्दों को बहुत परिश्रम से ढूँढ़ निकाला जाय तो छपने पर वे पन्द्रह-बीस पृष्ठों से ज्यादा जगह न घेरेंगे। यह बात सही हो तो सरकार ने फी साल केवल डेढ़ या दो पृष्ठों की नवीन सामग्री प्रस्तुत की।

यदि किसी को विद्वान हो कि नवनिर्मित शब्दों की राख्या पन्द्रह-बीस पृष्ठों से अधिक परिमाण की होगी, तो उससे प्रार्थना है कि वह ऐसे शब्दों का सग्रह कर छासे, उसे प्रकाशित कर दे, यह हिन्दी की बहुत बड़ी सेवा होगी, एकदम वैज्ञानिक ढंग से पता चल जाएगा कि हिन्दी की भाषागत समृद्धि में ठीक-ठीक कितने शब्दों का इजाफा किया गया है।

इस कोश निर्माण के लिए आई० सी० एस० आफिसर, शिक्षा मन्त्रालय के स्पेशल आफिसर भॉन ड्यूटी, मद्रास, मँसूर, बँगलोर, पूना, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली से निकट और दूर के, नगरों से बीसियों विशेषज्ञों का पचासो बार आवा-गमन, उनके टी० ए० बिल, दिल्ली में ठहरने का भत्ता, एक स्थायी कार्यालय और उसके कर्मचारी—आप हिसाब लगाएँ, फी शब्द सौ टके से कम नहीं पड़ा। पहले तीन लाख शब्द गढ़े या इकट्ठे किये गए। उनमें बहुत-से शब्द दुहराये-तिहराये गए थे। मनोविज्ञान के शब्द दर्शन में भी आ गए और भौतिकी के शब्द रसायन में। इन फालतू शब्दों की छँटाई के बाद इस कोश में एक लाख से कुछ ऊपर शब्द बच रहे हैं। कोश पर करोड़ों रुपये खर्च हुए। इतना धन व्यय करने के बाद भी पता नहीं चलता कि नवनिर्मित शब्द दरअसल कितने हैं। शिक्षा मन्त्रालय के उच्च अधिकारियों ने सम्भवतः कोश को पन्ने पलट-

कर देता भी नहीं है। सरना श्री आर० पी० नायक तीन लाख 'नये शब्द गढ़ने' की बात न लिखते। बोश में प्रकाशित एक ग्रन्थ भण्डारी लेख में उन सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है जिनके अनुसार शब्द-संग्रह का कार्य सम्पादित किया गया है। इस लेख में बताया गया है कि सम्पादकों ने हिन्दी में पहले से प्रचलित शब्द-राशि से लाभ उठाया है। इस लेख में लाखों नये शब्द गढ़ने का दावा नहीं किया गया। इसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय साहित्य से शब्द लेने की बात भी बड़ी गई है। सरकारी भूमिका में नये शब्द गढ़कर हिन्दी की दरिद्रता दूर करने का जो दावा किया गया है, वह इस लेख की बातों से कट जाता है।

इस लेख में शब्दों के अर्थ निश्चित करने के बारे में कुछ बातें कही गई हैं, जो सतत हैं। जिन प्राचीन शब्दों को खोज निकालने का दावा किया गया है, उनमें 'कलकुलस' का पर्याय 'कलन' भी है। यह शब्द भण्डारीजी के कोश में विद्यमान है। इसी तरह 'हीट' के लिए 'ऊष्मा' को निश्चित करने की जो बात कही गई है, वह सही नहीं है। भौतिकी-पुस्तकों में 'हीट' के लिए ऊष्मा का प्रयोग काफ़ी पहले से होने लगा था। कोश में कुछ प्रचलित शब्दों को छोड़कर नये शब्द गढ़े गए हैं। यह गड़बड़ अक्सर भोड़ी हो गई है। 'नर्व' के पर्याय-रूप में 'स्नायु' हिन्दी का प्रचलित शब्द था। उसे हटाकर 'तन्त्रिका' शब्द स्थापित किया गया है। 'स्नायु-तन्त्र' सुनने में थच्छा लगता है। उमके बदले इस कोश के अनुसार 'तन्त्रिका-तन्त्र' का चयन होना चाहिए। 'डिप्लोमसी' के लिए हिन्दी में 'कूटनीति' शब्द प्रचलित है। इस कोश में उसके लिए नया शब्द दिया है—'राजनय'। 'अग्नीस्तोतिस्म' का पर्याय दिया गया है 'अग्नीस्वरवाद', जो असत्य है। इसके विपरीत भण्डारीजी के कोश में सही शब्द दिया गया है—'अग्नेयवाद'। 'स्पेस' या 'आउटर स्पेस' का समानार्थी हमारा प्राचीन शब्द है 'अन्तरिक्ष'। उसे कोश में जगह नहीं मिली। 'नेशनैलिटी' का समानार्थी प्रचलित शब्द है—'जाति'। सरकारी कोश में भोड़ी गड़बड़ की है—'राष्ट्रवत्ता'।

एक विचित्र बात यह है कि एक ही शब्द से सम्बन्धित शब्द-समूह में पर्यायों की यथेष्ट भिन्नता दिखाई देगी। 'स्पेस टाइम' के लिए 'दिक् काल' किन्तु 'स्पेस टाइम नर्व' के लिए 'अवकाश समय वक्र'। ऐसे भी सैकड़ों शब्द हैं जो कोश में नहीं आए—जथा 'एरजॉन्टेसन', 'पैन्थोइडम', 'ईस्थेसिया', 'बीस्मोनॉट', 'अन्तरल स्ट्राइक' इत्यादि।

ज्यादा अच्छा होता कि सरकार ज्ञान विज्ञान के समस्त क्षेत्रों में हिन्दी का समुद्ध करने का ठेका न लेती। यह शासन-व्यवस्था, न्याय, व्यापार आदि उन क्षेत्रों के शब्दों का ही संग्रह करता जो जितने उसे आए दिन साबिका पड़ता है। आखिर लोकसभा के सदस्य या मन्त्रीगण अपनी राजनीतिक हैसियत से भौतिकी, रसायन या जीवविज्ञान पर तो ग्रन्थ रचेंगे नहीं। हिन्दी की केन्द्रीय राजकाज की भाषा बनाने के लिए देखना यह चाहिए था कि उसमें राजकाज के शब्द हैं

या नहीं। यह सीधा-सादा छह महीने में खत्म होनेवाला काम न करके सरकारी ने दो पंचवर्षीय योजनाओं का समय लगा दिया, समस्त विषयों के इस शब्द-संग्रह में।

शब्द-संग्रह तैयार हो गया। धन, समय और शक्ति के अपव्यय के बावजूद यह लाख से ऊपर शब्दों का संग्रह प्रस्तुत है। भारत के डेढ़ फी सदी अंग्रेजीदाँ बुद्धिजीवी जो पहले अंग्रेजी में सोचते हैं, फिर अपने सोचने का पल किसी भारतीय भाषा में प्रकट करते हैं, इस कोश की सहायता से हिन्दी में अब अपने प्रमूल्य विचार प्रकट कर सकते हैं। क्या अब केन्द्रीय राजकाज अंग्रेजी के बदले हिन्दी में होने लगा है? नहीं, इसके विपरीत अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा घोषित कर दी गई है।

दो निष्कर्ष स्पष्ट हैं—

(१) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दों के अभाव की बात राजनीतिज्ञों का झूठा प्रचार है। सरकारी शब्द संग्रह के ६६ फी सदी शब्द हिन्दी पुस्तकों और कोश में पहले से विद्यमान हैं।

(२) कोश निर्माण द्वारा हिन्दी को समृद्ध करने, उग राजभाषा पद के योग्य बनाने की सारी प्रक्रिया एक राजनीतिक चाल है, जिसका उद्देश्य है हिन्दी भाषियों तथा समस्त राष्ट्रभाषा-प्रेमियों की आँखों में धूल भोक्ना।

राष्ट्रीयता और जनतन्त्र का आधार सङ्कुचित करके अंग्रेजी पढ़े लिखे मुट्ठी-भर लोग जो भारत के शासन-तन्त्र का संचालन करते हैं, वे अपना निहित स्वार्थ छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उनकी धारणा है कि अंग्रेजी के बिदा होने पर उन्हें भी भारतीय रणमंच से बिदा लेनी होगी। हिन्दी-भाषी तथा समस्त भारतीय जनता का हित इसी में है कि अंग्रेजीदाँ नौकरशाहों का यह वर्ग जल्दी-से-जल्दी शासन-तन्त्र से दूर हो, सभी देश की समस्त भाषाएँ जनता की सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति का साधन बनेंगी और भारत अपनी प्रमुखता को पूरी तरह चरितार्थ करेगा।

(१९६३)

## वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम का मसौदा (भाषा-सम्बन्धी नीति की आलोचना)

वामपंथियों के कार्यक्रम के मसौदे में भारतीय भाषाओं की समानता के बारे में बहुत-सी और बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही गई हैं। लेकिन वहीं यह नहीं बताया गया कि भारत की सभी भाषाओं पर अपना प्राधिपत्य जमाये हुए जो अंग्रेजी बेंटी हुई है, उसके बारे में वामपंथी कम्युनिस्ट क्या करने जा रहे हैं। मसौदे में यह सराहनीय बात कही गई है कि विभिन्न राज्यों तथा वहाँ की जनता के बीच भाषिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देकर भविष्य में बापम होनेवाली जनता की जनवादी सरकार भारत की एकता को दृढ़ करेगी। यह एकरा दृढ़ करने का काम अंग्रेजी के द्वारा होगा या किसी भारतीय भाषा के द्वारा ?

जहाँ तक हिन्दी का सम्बन्ध है, मसौदे में कहा गया है कि प्रखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी का व्यवहार अनिवार्य न होगा लेकिन विभिन्न राज्यों की सरकारों के बीच सम्पर्क भाषा बनने के लिए हिन्दी को प्रोत्साहन दिया जायगा।

हिन्दी का व्यवहार अनिवार्य न होगा। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हिन्दी के व्यवहार को अनिवार्य बनाना जनतन्त्र-विरोधी कार्य होगा। लेकिन अंग्रेजी को हटाना अनिवार्य क्यों न कर दिया जाय ? मातृभाषाओं के व्यवहार पर सही जोर, लेकिन प्रखिल भारतीय स्तर पर हिन्दी के व्यवहार को लेकर आगा-पीछा—ऐसा क्यों ? जनता की जनवादी सरकार हिन्दी के व्यवहार को प्रोत्साहन देगी। मानो विभिन्न प्रदेशों की जनता ने अभी तक परस्पर आदान-प्रदान की आवश्यकता का अनुभव ही न किया हो। मानो वह अभी तक राह देख रही हो कि जनता की जनवादी सरकार बन जाय, तब वह आपसी सम्पर्क का काम शुरू करे। और विभिन्न राज्यों की सरकारों के ही परस्पर सम्पर्क के लिए हिन्दी को प्रोत्साहन क्यों दिया जायगा ? क्या अन्तर्प्रदेशिक सम्पर्क की आवश्यकता केवल सरकारों को पड़ती है ? जनता की जनवादी सरकार कायम होने पर जनता को इस सम्पर्क की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं ? भारत की

सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक एकता दृढ़ करने में जनता का भी कुछ हिस्सा होगा या नहीं ?

जनता के बाएँ और साम्राज्यवाद के दाएँ—वामपंथी मसौदे का सारतत्व यही है। जोरो से हिन्दी की अस्वीकृति और अंग्रेजी की स्वीकृति, आज के लिए भी और बल के लिए भी—यह है मसौदे की नीति। सत्रह साल से कांग्रेस जिस नीति पर चलती आई है, उससे इस वामपंथी नीति में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देता।

साम्राज्यवादी अंग्रेजी के प्रसार और शिक्षण पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं। भारत के सबसे बड़े 'राष्ट्रीय' अखबार अंग्रेजी में निकलते हैं और उनके मालिक बड़े पूंजीपति हैं। इनमें अहिन्दी और हिन्दी दोनों तरह के पूंजीपति हैं। मध्यवर्ग के पढ़े-लिखे लोग नौकरशाही मशीन चलाते हैं और उन्हीं में से भारत की राजनीतिक पार्टियों के नेता भी बनते हैं। इन पार्टियों का राजनीतिक काम अंग्रेजी में होता है। इनमें से अनेक पार्टियाँ चाहती हैं कि अंग्रेजी जाय लेकिन वे अपना अन्तर्प्रदेशिक काम करती हैं अंग्रेजी में। सरकार से यह कहना कि यह करो, वह करो, तब तक बिलकुल फिजूल है जब तक राजनीतिक पार्टियाँ अखिल भारतीय कामों के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना नहीं छोड़ती। वामपंथी कार्यश्रम के मसौदे में कहा गया है कि पार्लियामेंट के सदस्य अपनी-अपनी भाषा में बोल सकेंगे और भाषणों के सभी भाषाओं में अनुवादित होने की व्यवस्था होगी। वामपंथी कम्युनिस्ट अपनी पार्टी कांग्रेस में इस प्रस्ताव पर अमल करके खुद अपने अन्दर अंग्रेजी का व्यवहार खत्म क्यों नहीं कर देते ? भारतीय जनता के किसी भी हिस्से को अंग्रेजी के कायम रहने से लाभ नहीं है। श्रमिक आन्दोलन में विभिन्न जातियों के मजदूर परस्पर सम्पर्क के लिए हिन्दी का व्यवहार करते हैं।

आज भारतीय जीवन में मुख्य अन्तर्विरोध हिन्दी और अहिन्दी भाषाओं में नहीं, अंग्रेजी तथा समस्त भारतीय भाषाओं में है। हिन्दी-अहिन्दी भाषाओं में जो भी अन्तर्विरोध हो, उसे गौण मानकर पहले मुख्य अन्तर्विरोध को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। बड़े समाचारपत्रों की भाषा अंग्रेजी, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में अंग्रेजी, विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी, विज्ञान-सम्बन्धी प्रकाशन के लिए अंग्रेजी, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर केन्द्रीय सरकार की व्यवहार-भाषा अंग्रेजी, राज्यों में सरकारी भाषा अंग्रेजी। अब बताइए, अहिन्दी जातियों की प्रगति के लिए खतरा हिन्दी साम्राज्यवाद से है या अंग्रेजी साम्राज्यवाद से ?

अहिन्दी जातियों के अधिकारों के लिए लड़ना और इस बात को भूल जाना कि अंग्रेजी सब पर हावी है, इस नीति का एक ही कारण है—प्रलम्ब की भावना। आप प्रादेशिक स्तर पर जातियों के गठन की माँग करते हैं, उनकी भाषाओं के लिए समस्त अधिकारों की माँग करते हैं। लेकिन अखिल भारतीय

स्तर पर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए आप किसी भारतीय भाषा के लिए अधिकार नहीं मांगते। आप सहारा लेते हैं अंग्रेजी का जिसका मतलब है डेढ़ फी सदी भारतवासियों की एकता को सुदृढ़ करना। इसका मतलब है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रतिल भारतीय धारा से तटस्थ हो जाना। आप इस विकास को अंग्रेजी तक सीमित कर देते हैं। आप अपने प्रदेश की ही भाषा और संस्कृति के विकास की बात सोचते हैं। यही है भ्रमगाव की भावना। अंग्रेजी का सूत्र बहुत कमजोर है और जरा से मटके से टूट सकता है। आपके लिए मजबूत सूत्र है प्रादेशिक भाषा जो आपको प्रदेश से बांधती है। लेकिन दूसरे प्रदेशों से जो आपको बांधे वह सूत्र कौन-सा है? तब क्या आश्चर्य कि द्रविड वल्लभ भ्रमगाव तमिल राज्य बनाने की मांग करता रहा है, नागा जनो के लिए फिजो महाशय भ्रमगाव राज्य चाहते हैं, शेख अब्दुल्ला कश्मीर के लिए आत्मनिर्णय का अधिकार चाहते हैं। राजाजी, फील्ड-मार्शल अय्यब खाँ, चाऊ-एन-लाई और अंग्रेजी-भाषी जननन्त्रों के ब्रिटिश अमरीकी नेता सभी आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते हैं।

भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में भ्रमगाव से केवल साम्राज्यवाद का हित होता है। इसीलिए राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना सभी देश-प्रेमियों का सर्वोपरि कर्तव्य है।

आत्मनिर्णय की मांग सार्थक तब होती है जब साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघर्ष करती हुई जनता अपनी स्वाधीनता के लिए आत्मनिर्णय की मांग करे। जारगाही रूस में यह मांग सार्थक थी क्योंकि रूसी पूँजीपति गैर-रूसी जातियों का उत्पीड़न करते थे। भारत में यह मांग निरर्थक है। जो लोग शेख अब्दुल्ला को प्रोत्साहन देते हैं या जमकर उमका विरोध नहीं करते, वे देश के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं।

अंग्रेजी के कायम रहने से प्रादेशिक भाषाओं को ही नुकसान होता है। फिर किसी भी प्रदेश की भाषा और संस्कृति का विकास भ्रमगाव की हालत में नहीं हुआ। प्रत्येक भाषा में उसके साहित्य की विषयवस्तु का आधार है देशभक्ति, न कि भ्रमगाव-वर्षी प्रादेशिकता। इसलिए अपने प्रदेश और उसकी भाषा पर ही जोर देना और राष्ट्रीय एकता की बात भूल जाना हानिकारक है।

वामपंथी कम्युनिस्ट राष्ट्र के अस्तित्व की स्वीकार करते हैं। मसौदे में कहा गया है कि छुटपुट सघर्ष बढ़ते-बढ़ते राष्ट्रीय (नेशनल) विद्रोह का रूप ले लेते, मसौदे में राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे आदि का उल्लेख है। इस राष्ट्र की एकता अंग्रेजी से दृढ़ नहीं हो सकती।

वामपंथी मसौदे में यह मांग की गई है कि भाषावार राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी की जाय। राज्य का गठन इस बात को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए कि जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में सुविधा हो। हर भाषा की लेकर केवल राज्य के लिए राज्य बनाना बचकानापन है।

“यह सम्राटो द्वारा शासित द्वीप”

यह मध्य प्रदेश, यह घरती, यह राज्य, यह इग्लड,

यह महाराजाधो का गर्मस्थल, यह उनकी घरित्री,

उनके जन्म लेने से प्रसिद्ध, उनके वश के कारण शत्रु में भय उत्पन्न करने वाला ।’

फिर कोई भारतीय कवि किसी गुप्त-सम्राट् की प्रशस्ति के गीत क्यों न गाये ? किन्तु महाभारत के कवि ने भारतवर्ष की प्रशस्ति लिखी है, राजाधो और सम्राटो की नहीं । राजाधो और सम्राटो के लिए लिखा है कि वे भूमि के लिए वैसे ही लड़ते हैं जैसे मांस के लिए कुत्ते ।

देवमानुषकायानां काम भूमि परायणम् ।  
अन्योन्यस्यावलुम्पन्ति सारमेया यथामिषम् ॥  
राजानो भरतश्रेष्ठ भोक्तुकामा वसुधराम् ।  
न चापितृप्ति कामाना विद्यतेऽद्यापि कस्मचित् ॥  
तस्मात् परिग्रहे भूमेर्यतन्ते कुरुपाण्डवा ।  
साम्ना भेदेन दानेन दण्डेनैव च भारत ॥  
पिता भ्राता च पुत्राश्च ख द्यौश्च नरपुंगव ।  
भूमिर्भवति भूताना सम्यगच्छिद्रदशेना ॥

(देव-शरीरधारी प्राणियों के लिए और मानव-शरीरधारी जीवों के लिए यथेष्ट फल देनेवाली यह भूमि उनका परम आश्रय होती है । जैसे कुत्ते मांस के टुकड़े के लिए परस्पर लड़ते और एक दूसरे को नोचते हैं, उसी प्रकार राजा लोग इस वसुधा को भोगने की इच्छा रखकर आपस में लड़ते और लूटमार करते हैं किन्तु भ्राज तक किसी को अपनी कामनाओं से तृप्ति नहीं हुई । इस अतृप्ति के ही कारण कौरव और पाण्डव साम, दाम, भेद और दण्ड के द्वारा सम्पूर्ण वसुधा पर अधिकार करने के लिए यत्न करते हैं । यदि भूमि के यथार्थ स्वरूप का सम्पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाय तो वह परमात्मा से अभिन्न होने के कारण प्राणियों के लिए पिता, भ्राता, पुत्र, भ्राकाशवर्ती पुण्यलोक तथा स्वर्ग भी बन जाती है ।)

यूरोप के प्राचीन साहित्य में इस मानवतावाद का जबाब नहीं है । शेक्सपियर की राष्ट्रीय गौरव-भावना से यह घरती-प्रेम बहुत ऊँचा है । इसलिए भारतवर्ष की प्रशस्ति सम्राटो की वन्दना नहीं, भारत-भूमि और उसकी जनता की वन्दना है वह हमारी प्राचीन राष्ट्रीय भावना की द्योतक है । ‘रामायण’, ‘मेघदूत’ और ‘कुमारसम्भव’ में इसी प्रकार राष्ट्रीय चेतना के दर्शन होते हैं ।

माक्सवाद के अनुसार जातियाँ (नेशन) पूँजीवादी युग की देन हैं । लेकिन पूँजीवाद है क्या ? पूँजीवाद उत्पादन की एक पद्धति है । तब क्या शेक्सपियर के समय में उत्पादन की पद्धति बदल चुकी थी ? यदि हाँ, तो पगार पानेवाला सर्व-

द्वारा वर्ग नहीं था ? १८४४ में एंगेल्स ने अपने समय के इंग्लैंड के बारे में— 'इंग्लैंड के मजदूर-वर्ग की दशा' नामक पुस्तक में—लिखा था, "इंग्लैंड के सर्वहारावर्ग का इतिहास पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध से आरम्भ होता है।" अठारहवीं सदी से पहले इंग्लैंड में सर्वहारा-वर्ग नहीं था। उत्पादन की पद्धति में कोई बुनियादी परिवर्तन न हुआ था। जुलाहे खेती भी करते थे। धरती से उनका सम्बन्ध टूटा न था। वे घुमन्तू सौदागरो को अपना माल बेचते थे। लेकिन वे अभी बाजार में अपनी श्रमशक्ति बेचने को बाध्य न थे। यदि पूँजीवाद केवल उत्पादन की पद्धति है, तो सोलहवीं सत्रहवीं सदी के अंग्रेज जाति के रूप में संगठित न हो सकते थे। लेकिन मिल्टन ने १६४४ ई० में क्रोमवेल की विजय के बाद लिखा था, "मुझे अपने मनोबल में दिखाई दे रहा है कि एक शक्तिशाली जाति (नेशन) नींद से उठे हुए मनुष्य के समान अपने बेशुद्ध भटक रही है।"

हम में पूँजीवादी उत्पादन उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में आरम्भ हुआ, किन्तु लैनिन के अनुसार रूसी जाति का निर्माण सत्रहवीं सदी में हुआ। लैनिन ने रूस के सामाजिक विकास का विश्लेषण करके दिखाया था कि व्यापारियों ने रूस में एक देशव्यापी बाजार कायम किया था। यह समझना चाहिए कि पूँजीवाद केवल उत्पादन की पद्धति नहीं, वितरण की पद्धति भी है। मार्क्सवादी भारतीय इतिहास का नव तक सही तौर से न समझ सकेंगे जब तक वे सामाजिक विकास में वितरण की भूमिका का महत्व स्वीकार न करेंगे।

एंगेल्स ने एण्टो ड्यूयिंग में लिखा था कि उत्पादन और विनिमय अर्थतन्त्र की दो धुरी हैं दोनों के नियम बहुत-कुछ स्वतन्त्र हैं और वे दोनों एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। एंगेल्स ने इस बात पर जोर दिया था कि प्रत्येक समाज-व्यवस्था का आधार उत्पादन और वितरण दोनों हैं। पूँजी के तीमरे खण्ड में मार्क्स (अथवा एंगेल्स) ने बताया था कि औद्योगिक पूँजी का निर्माण तभी होता है जब उससे पहले सौदागरी पूँजी का निर्माण हो चुका हो। मार्क्स ने लिखा था कि सोलहवीं सत्रहवीं सदी में सौदागरी पूँजीवाद के विकास के साथ भारी क्रान्तियाँ हुईं और सामन्ती उत्पादन से पूँजीवादी उत्पादन के बीच संक्रमण की यह सबसे महत्वपूर्ण बड़ी थी। मार्क्स ने लिखा था, व्यापार में क्रान्ति होने से विश्व-बाजार कायम हुआ। आश्चर्य की बात होगी, विश्व-बाजार तो कायम हो जाय, जातीय बाजार (नेशनल मार्केट) कायम न हो।

सोलहवीं-सत्रहवीं सदियों में भारत विश्व-बाजार का बहुत महत्वपूर्ण अंग था। हमारे यहाँ यूरोप का माल बिकन आता था, यहाँ का माल वहाँ बिकने जाता था। एडम स्मिथ ने लिखा था कि उन दिनों यूरोप का मुख्य व्यापार यह था कि पश्चिमी देश अपनी घनगढ़ चीजें देकर अधिक सम्य देशों का बढ़िया माल लाते थे। आश्चर्य की बात होगी यदि असम्य देशों में तो राष्ट्रीय या जातीय चेतना फैल गई हो और सम्य देशों में उसका अभाव रहा हो।



माक्स ने लिखा था कि “प्राचीन काल की व्यापारी जातियाँ ऐपीक्यूरोस के देवताओं की तरह ग्रहाण्ड के मध्यलोक में रहती थी। अथवा यों कहें जैसे पोलैंड के समाज में यहूदी भीतर पैठ गए थे।” माक्स ने व्यापारी जातियों (ट्रेडिंग नेशन्स) का उल्लेख किया है। इसका अर्थ यह है कि व्यापारी पूँजीवाद का विकास सोलहवीं सत्रहवीं सदी से पहले प्राचीन काल में भी हुआ था। जातियों का उद्भव आधुनिक पूँजीवाद के जन्म से बहुत पहले हो चुका था। ‘अर्थशास्त्र की आलोचना’ नामक ग्रन्थ में माक्स ने प्राचीन काल की जातियों की चर्चा की थी। उन्होंने लिखा था कि प्राचीन काल की व्यापारी जातियों में धन (मनी) की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है।

गुप्त-युग में भारत के जनपदों में परस्पर आर्थिक विनिमय बढ़ा, उस समय के व्यापारी भारतवर्ष से बाहर निकलकर दक्षिण पूर्वी एशिया और यूरोप तक अपना व्यापार करते रहे। जनपदों में परस्पर सांस्कृतिक सम्पर्क बढ़ा, संस्कृत द्वारा वे एक-दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते रहे। तब क्या आश्चर्य कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ और महाभारत में उसे अभिव्यक्ति मिली ?

प्राचीन यूनान का उदाहरण लीजिए। यह देश छोटे-छोटे राज्यों (जनपदों) में बँटा हुआ था। एथेन्स के लोगों में बड़े-बड़े व्यापारी थे। इन्होंने यूनानी लोगों में राष्ट्रीय चेतना उभारने में बड़ा योगदान किया। यूनान के प्राचीन नाटकों—विशेषकर ईरानियों से सम्बन्धित ईस्कुलस के नाटकों में—यह चेतना उभरकर आई है। एथेन्स का नेता पेरिकलीज अपने नगर को हेलास (यूनान) का शिक्षक कहता था। प्रसिद्ध इतिहासकार थ्यूसीडाइडीज ने पेलोपनीसस के युद्ध पर अपने ग्रन्थ में बारम्बार राष्ट्रीय भावना का उल्लेख किया है। ग्रन्थ के दूसरे खण्ड के छठे अध्याय में उसने लिखा है, “पेलोपनीसस और एथेन्स दोनों में ऐसे नौजवान भरे हुए थे जो भावहीनता के कारण हथियार उठाने को बड़े उत्तावले थे। बाकी हेलास अपने प्रमुख नगरों के सघर्ष को देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था।” यहाँ पेलोपनीसस और एथेन्स को एक ही राष्ट्र हेलास का अंग माना गया है। ये दोनों राज्य हैं, परस्पर स्वतन्त्र हैं, फिर भी जनता की चेतना में—विनिमय की बढ़ती के कारण और अन्य महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक और भाषागत तत्वों के कारण—वे अपने से बड़ी इकाई के भाग हैं। लैंकेडिमोन (पेलोपनीसस) का राजदूत मेलेसिप्पस पेरिकलीज से मिलने की अनुमति न पाकर कहता है, “यह दिन हेलास के महादुर्भाग्य के आरम्भ का दिन है।” ईसा से चार सौ साल पहले यूनान में यह राष्ट्रीय चेतना फैल सकती थी तो क्या ईसा से चार सौ साल बाद भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार असम्भव माना जाएगा ?

बहस करनेवाले कह सकते हैं कि प्राचीन यूनानियों में राष्ट्रीय चेतना इसलिए फैली कि उन्हें ईरानियों से मुकाबला करना था। ऐसा ही सही। तब

प्राचीन भारत में राष्ट्रीय चेतना शक्ति और हठों का मुकाबला करने के लिए पैदा हुई । कारण चाहे जो बताया जाय, प्राचीन यूनान और प्राचीन भारत में राष्ट्रीय चेतना के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

फिर भी रुढ़िवादी भावसंवादी कहेंगे, 'नेशन' उसे कहते हैं जिसकी भाषा एक हो । यूनान में मिलती जुलती बोलियाँ बोली जाती थी । लेकिन यहाँ तो भाषाएँ और द्रविड एकदम भिन्न भाषा-परिवार थे । फिर भारत राष्ट्र कैसे हुआ ?

प्राचीन भारत में अनेक भाषाएँ थी किन्तु शिक्षित-जन संस्कृत द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर आपस में सम्पर्क बनाये हुए थे । आर्यावर्त से सबसे ज्यादा दूर बंगाल और केरल थे, फिर भी इनकी भाषाओं में संस्कृत के शब्द अपेक्षाकृत अधिक हैं । इससे संस्कृत के देशव्यापी प्रभाव का पता चलता है । प्रकाण्ड पंडित शंकराचार्य केरल ही के थे । बंगाल के न्यायशास्त्री दूर-दूर तक विख्यात हुए । फिर भी प्रश्न बना रहता है कि क्या एक से अधिक भाषाएँ बोलनेवालों को राष्ट्र की सजा दी जा सकती है ?

स्तालिन ने नेशन की जो प्रसिद्ध व्याख्या की थी, उसमें एक से अधिक भाषा की गुंजाइश नहीं है । ब्रिटिश जाति और फ्रांसीसी जातियों की एक-एक भाषा है अंग्रेजी और फ्रांसीसी । फिर भी भावसंवादी लेखक 'नेशनल फ्रीडम मूवमेंट' की बात करने हैं, सीमाव्य से वे उसे 'इंटरनेशनल फ्रीडम मूवमेंट' नहीं कहते ।

अंग्रेजी का 'नेशन' शब्द बड़ा भ्रामक है । भारतीय भाषाओं में दो शब्द हैं—राष्ट्र और जाति । भारत राष्ट्र, हिन्दी भाषी जाति । ब्रिटेन राष्ट्र, ब्रिटिश जाति । ब्रिटेन राष्ट्र में एक ही भाषा है । भारत में अनेक भाषाएँ हैं । जाति की भाषा एक ही होती है । राष्ट्र में एक जाति, एक भाषा तथा अनेक जातियाँ, अनेक भाषाएँ हो सकती हैं । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 'जातीय संगीत' में जाति शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में किया था ।

अंग्रेजी का 'पेट्रियोटिज्म' शब्द राष्ट्रीयता के बहुत निकट है किन्तु उसके मूल लैटिन शब्द 'पात्रिआ' का अंग्रेजी में चलन नहीं है । राष्ट्र को पात्रिआ कह सकते हैं, नेशन नहीं । राष्ट्र के लिए 'नेशन' को पर्यायवाची मानें तो 'भारत बहु-जातीय राष्ट्र है'—इस वाक्य का अनुवाद होगा—'इडिया इज ए मल्टीनेशनल नेशन' ।

बहुजातीय राष्ट्र में राष्ट्रीयता का आधार क्या है ? उदाहरण के लिए, सोवियत राष्ट्रीयता (सोवियत पेट्रियोटिज्म) का आधार क्या है ? यह राष्ट्रीयता केवल भावजगत् की वस्तु नहीं है । भावसंवाद के अनुसार जाति की तरह बहु-जातीय राष्ट्रीयता का भी प्राथमिक आधार होना चाहिए । क्या इसका आधार समाजवाद है ? सोवियत संघ के अनेक समाजवादी पक्षीसी हैं किन्तु उनकी राष्ट्रीयता या देशभक्ति सोवियत राष्ट्रीयता या सोवियत देशभक्ति से भिन्न है । राष्ट्र

की अनेक जातियाँ सामान्य आर्थिक सम्बन्धों, सामान्य देश में निवास, सामान्य ऐतिहासिक परम्पराओं और सामान्य सांस्कृतिक सूत्रों के कारण परस्पर सम्बद्ध होती हैं। भारत देश में निवास करनेवाली जातियों की भाषाएँ, प्रदेश, आर्थिक सम्बन्ध, साहित्य और संस्कृति अलग अलग हैं। फिर भी उन सबका देश एक है, उन सबका राष्ट्रीय इतिहास एक है, उनकी मिली-जुली परस्पर सम्बद्ध साहित्यिक परम्परा है, उनके आर्थिक सम्बन्ध पहले की अपेक्षा आज और भी दृढ़ हैं। इसलिए जो लोग भारत की तुलना यूरोप से करते हैं, जो देश को उप-महाद्वीप कहते हैं, वे एक ऐतिहासिक सत्य से इन्कार करते हैं। राष्ट्रीयता के विकास में केवल आर्थिक सम्बन्धों की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती। ऐसा होता तो चेकोस्लोवाकिया, रूमानिया और पोलैंड सोवियत राष्ट्र के अन्तर्गत होते। उनकी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परम्पराएँ हैं जो उनकी राष्ट्रीयता निर्धारित करती हैं।

कहा जा सकता है कि इस तरह की बहुजातीय राष्ट्रीयता समाजवाद के अन्तर्गत ही सम्भव है, पूँजीवाद में तो जातियाँ, पूँजीपतियों के प्रभाव के कारण, परस्पर लड़ा करती हैं। यह बात सही नहीं है। पूँजीवाद के अन्तर्गत 'जाति' का निर्माण होता है या नहीं? यह जाति सर्वहारा वर्ग और पूँजीपतियों के बीच संघर्ष के कारण विभाजित रहती है या नहीं? विभाजित रहती है किन्तु पूँजीपति और भूजद्वर एक ही उत्पादन-वितरण व्यवस्था में काम करते हैं, इसलिए जाति सम्बद्ध भी रहती है। इसी तरह पूँजीवाद के अन्तर्गत एक ही राष्ट्र की अनेक जातियाँ आपस में स्पर्धा करती हैं, साथ ही राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में एक-दूसरे से सम्बद्ध भी रहनी है। इससे अलावा सभी लोग मानते हैं कि देश की विभिन्न जातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध 'राष्ट्रीय' आन्दोलन चलाया था। इसका अर्थ यह है कि विशेष परिस्थितियों में जातियों का आपसी तनाव कम हो जाता है और उनकी राष्ट्रीय एकता उभरकर सामने आ जाती है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि समाजवादी व्यवस्था में जातीय और राष्ट्रीय अलगाव की भावनाएँ कभी कभी बड़ा उग्र रूप धारण करती हैं। सोवियत संघ से यूगोस्लाविया, रूमानिया और चीन के सम्बन्ध इस सत्य को उजागर करते हैं।

भारत एक राष्ट्र है। हमारी राष्ट्रीयता केवल अंग्रेजों का विरोध करने के लिए—नकारात्मक रूप से—किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न नहीं हो गई। उसकी जड़ें हमारी ऐतिहासिक और आर्थिक परम्पराओं में बहुत गहरी पड़ी हुई हैं। आज की परिस्थिति में लोग चाहे जिस प्रदेश में रहें हों, उनकी आर्थिक, राजीनतिक और सांस्कृतिक प्रगति राष्ट्रीय एकता के बिना असम्भव है। किसी एक प्रदेश की उन्नति सारे देश की उन्नति पर निर्भर है।

भारत राष्ट्र से प्रेम है तो अंग्रेजी का मोह छोड़ना होगा। अंग्रेजी का प्रभुत्व राष्ट्र के लिए अपमानजनक है। विदेशी भाषाओं के साथ अंग्रेजी का अध्ययन भी किया जाएगा किन्तु वह भारतीय भाषाओं के हक भारकर यहाँ

नहीं रह सकती। सभी प्रदेशों की जनता को अंग्रेजी हटाने के लिए मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। जो लोग हिन्दी साम्राज्यवाद का भय दिखाते हैं, वे अंग्रेजी का साम्राज्यवाद सुरक्षित रखते हैं।

१९६४

## ‘अन्तर्राष्ट्रीय’ वैज्ञानिक शब्दावली

बुद्धिजीवियों में, वे चाहे मार्क्सवादी हों चाहे गैर-मार्क्सवादी, ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो समझते हैं कि विज्ञान में कोई अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली प्रचलित है। उनका तर्क यह है कि वर्तमान युग में विज्ञान अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है, इसलिए उसकी शब्दावली भी अन्तर्राष्ट्रीय हो गई है। हिन्दी में यदि यह अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली अपना ली जाय, तो पारिभाषिक शब्दावली की समस्या हल हो जाय ।

स्थिति यह है कि यूरोप की भाषाओं में बहुत-से पारिभाषिक शब्द सामान्य हैं। सैंटिन-ग्रीक के आधार पर बनाये हुए ये शब्द एक ही रूप में या थोड़े से रूप-परिवर्तन के बाद विभिन्न यूरोपीय भाषाओं में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे शब्दों को अपनाने में कोई हानि नहीं है। भारत सरकार की ओर से १९६२ में जो पारिभाषिक शब्दकोश प्रकाशित हुआ है, उसमें लगभग हर पृष्ठ पर इस श्रेणी के कुछ शब्द दिए हुए हैं। कोबाल्ट, उरेनियम, उरेनस, उरेडियम, उरेमा, ग्राँवसीजन, ग्राँवसीनाइट्रेट, यूकलिप्टस, अलकोहल, एथीलीन आदि ऐसे ही शब्द हैं।

इस तरह की सामान्य शब्दावली सीमित है। सीमित सख्या में ही उससे शब्द लिये जा सकते हैं। यूरोप की भाषाओं में प्रयुक्त होनेवाले सभी वैज्ञानिक शब्द अन्तर्राष्ट्रीय नहीं हैं। मास्को से वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों के कई कोश प्रकाशित हुए हैं। जो लोग वैज्ञानिक शब्दावली की अन्तर्राष्ट्रीयता पर बड़ी दृढ़ता से विश्वास करते हैं, उन्हें ये कोश अवश्य देखने चाहिए ।

उदाहरण के लिए, हवाई जहाजों की उड़ान से सम्बन्धित एक अंग्रेजी-रूसी कोश है। जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली की आवश्यकता अधिक हो। लेकिन अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द अक्सर प्रचलित शब्दों के आधार पर बनाये गए हैं और रूसी से भिन्न हैं। अंग्रेजी में एक प्रचलित शब्द है ‘कौक’। इसको आधार मानकर एयर कौक, एयर एस्केप कौक, बैलेंस कौक, कंट्रोल कौक, ड्रेन कौक, पम्पल कौक, घोट-

लिंग कौक, आदि पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई है। रूसी कौक शब्द का प्रयोग नहीं करते। इसलिए वे दूसरी तरह के शब्दों का व्यवहार करते हैं। अंग्रेजी में प्रचलित शब्द है, कंट्रोल। इसे आधार मानकर सर्कुलेशन कंट्रोल, डेप्य कंट्रोल, डिस्टेन्स कंट्रोल, इलेक्ट्रिक पलाइट कंट्रोल, ऐलिवेटर कंट्रोल, इमर्जेंसी कंट्रोल, पलाइट कंट्रोल, ग्राउंड कंट्रोल, आदि शब्दावली बनाई गई है। इसी तरह लैंडिंग के आधार पर त्रिसविड लैंडिंग, डेड-एजिन लैंडिंग, फोस्ड लैंडिंग, रनअवे लैंडिंग आदि, एयरक्राफ्ट के आधार पर कम्बैट एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट, सिविल एयरक्राफ्ट, जेट एयरक्राफ्ट आदि शब्दावली निमित्त हुई है। इनके रूसी पर्यायवाची बिल्कुल भिन्न हैं जैसे कंट्रोल के लिए रूसी शब्द है उप्रावलेनिय, एयरक्राफ्ट के लिए सामत्योत इत्यादि।

भास्को से कुछ पारिभाषिक शब्दकोश ऐसे प्रकाशित हुए हैं जिनमें सात भाषाओं के पर्यायवाची शब्द एक साथ दिए हुए हैं। इस तरह के कोशों का प्रकाशन ही मिद्धकरता है कि यूरोप में कोई सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्दावली नहीं है। अंग्रेजी में प्रयुक्त जो शब्द कुछ लोगों को बहुत अन्तर्राष्ट्रीय लग सकते हैं उनके लिए भी यूरोप की भाषाओं में भ्रमण शब्द हैं। जेट के लिए रूसी में स्त्रूया शब्द है; कार्बन, कार्बन-डाईऑक्साइड, टैंडन, योरेक्स, लेबियम, गैस्ट्रिक, प्रोवरी, ग्लेड, एल्कली, और न्यूक्लिअर के लिए रूसी में प्रमश, उल्गेरोद, उल्गेकीस्लुइ गाज, सुलोभीलिये, गूदा, गवा, ऊँ उदोन्चुइ, याइन्चिब, ऊँ लेजा, इचेलोच और यादेर्नया शब्द हैं। ऑक्सीजन के लिए रूसी और जर्मन के अपने शब्द किसेलरोद और जावर स्टीक हैं। नाइट्रोजन के लिए इतालवी, फ्रांसीसी और रूसी में अजोत शब्द का प्रयोग होता है। फोस्फोर के लिए ल्यूमिनो-फोर सुक्सतान्तिमया, लायस्टस्टीफ आदि शब्द हैं। डच और जर्मन भाषाएँ एक दूसरे से बहुत मिलती हैं। ग्रिड के लिए उनके भिन्न शब्द हैं—रोस्टर और गिटर। इग्नाइटर के लिए डच में ओटस्टेकर, जर्मन में ल्यूटस्टिपट शब्द हैं।

इस विवरण से स्पष्ट है कि भारतीय भाषाओं को अपने पारिभाषिक शब्दों का निर्माण और व्यवहार करने की पूर्ण स्वाधीनता है। वे सीमित संख्या में यूरोपीय भाषाओं से शब्द ले सकती हैं। सर्वमान्य वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली का अस्तित्व कहीं नहीं है।

## संस्कृति और भाषा.

भाषा को आप चाहे संस्कृति का ही भग मान चाहे उससे भिन्न, दोनों के अनिष्ट सम्बन्ध को अस्वीकार नहीं किया जा सकता । वाक्य रचना की पद्धति हमारी चिन्तन पद्धति पर निर्भर होती है । आप अपनी भाषा में कर्म की क्रिया के पहले बिठाते हैं या बाद को, यह आपकी परम्परागत जातीय चिन्तन प्रक्रिया पर निर्भर है । आप अपनी भाषा में किस तरह के विदेशी शब्द कितने परिमाण में ग्रहण करते हैं, यह आपके जातीय चरित्र पर निर्भर है । आप अपनी भाषा का सम्मान करते हैं, दैनिक जीवन में उसका व्यवहार करते हैं अथवा उसे पैरो तले रौंदते हैं और किसी अन्य भाषा को सिर चढ़ाते हैं, यह आपकी राष्ट्रीय सम्मान की भावना पर निर्भर है ।

किसी भी देश में उसकी भाषा या भाषाओं की स्थिति विशुद्ध भाषा-विज्ञान के नियमों से सम्बन्ध में नहीं आ सकती । वह स्थिति देश की भौतिक और बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर है । आज सत्तर के बहुत बड़े हिस्से में अंग्रेजी का बोलवाला है । ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दो देश ऐसे हैं जो अन्य देशों को पूँजी का निर्यात करते हैं, जो प्रच्छन्न और प्रकट रूप से उपनिवेशवाद का पोषण करते हैं, जो अपने प्रभाव को साम-दाम-दण्ड-भेद की बहुरंगी नीति से सुरक्षित करके और व्यापक बनाने में लगे हुए हैं । राजनीति से लेकर शिक्षा और संस्कृति तक जिस देश में जैसा बन पड़ता है, वे घुसने पँठने, अपनी जड़ जमाने की कोशिश करते हैं । इनकी एक भाषा-सम्बन्धी स्पष्ट नीति है, पहले के समान यहाँ की भाषाओं का दबाकर रखना, उन सबके ऊपर शीर्ष स्थान पर अंग्रेजी को जमाकर रखना । इससे लाभ यह होता है कि आपके मर्मस्थल पर प्रहार करके आपको कमजोर बनाकर वे आपको अपनी स्वार्थ नीति की ओर आसानी से खींच सकते हैं । मर्मस्थल है, जातीय भाषा के प्रेम का स्थल, जातीय संस्कृति के प्रेम का स्थल, राष्ट्रीय धारम गौरव का स्थल । आदमी को इस स्थल पर मारिए, उसे भीतर से निर्वीर्य कर दीजिए फिर उस बलि-यशु को चाहे जिस छूटे से बांध कर उसका वध कर दीजिए ।

भाषा उस देश की दशा पर विचार कीजिए जो भ्रष्ट से लेकर भ्रष्ट-शस्त्र तक परमुखापेक्षी है, जो अपनी स्वाधीनता की रक्षा के लिए उन्हीं लोगों का मुँह जोहता है जो अब तक उसे गुलाम बनाए हुए थे। इसी नीति के अनुरूप भाषाक्षेत्र में भी हमारे देश के नेता परमुखापेक्षी हैं। जिस अंग्रेजी भाषा ने विदेशी राज्यकाल में यहाँ की भाषाओं को पदमर्दित किया, यहाँ की संस्कृति और साहित्य के सहज विकास को कुण्ठित किया, अंग्रेजी के जिस आधिपत्य के विरुद्ध भारतीय मनीषियों ने सतत संघर्ष किया, उस अंग्रेजी को हटाकर भारतीय भाषाओं को उनका स्वत्व देने में सामक और शिक्षामन्त्री हिचकिचा रहे हैं।

हमारी सांस्कृतिक पराधीनता भाषा के क्षेत्र में अनेक रूपों में प्रकट होती है। हमारे संविधान में लिखा है कि हिन्दी भाषा को विकसित होने के लिए समय दिया जाय। हिन्दी को विकसित करने के लिए एक विशाल निदेशालय चालू है। हिन्दी में क्या कमी है, कमी है या नहीं, है तो उसे कैसे पूरा किया जाय, हिन्दी और भारतीय भाषाओं को देखते 'विश्वभाषा' अंग्रेजी में भी कोई कमी है या नहीं, है तो उसे कैसे दूर किया जाय—इस सबका निदान करने के लिए कोई आयोग नहीं बनाया गया, भाषा की सिद्धि समृद्धि जाँचने का योग सत्रह साल में नहीं आया। करोड़ों रुपये इस स्वतः सिद्ध सत्य पर खर्च हो गए हैं कि 'विश्वभाषा' अंग्रेजी विकसित और समृद्ध है और भावी राष्ट्रभाषा हिन्दी अविकसित और दरिद्र है।

समृद्धि का कार्य कोष निर्माण द्वारा सम्पादित होता है। कोष निर्माण के लिए अंग्रेजी शब्द पहले हैं, हिन्दी बाद की। हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकता के लिए कौन से शब्द आवश्यक हैं, यह विषय प्रगोचर ही रहता है। कोष निर्माताओं में अनेक जन अंग्रेजी से जितना आतंकित रहते हैं, उतना ही हिन्दी की प्रकृति से अनभिज्ञ भी। वे ऐसे 'स्थितित' और 'गति' ऊर्जा वाले शब्द गढ़ते हैं कि 'तत्प्रकाशत्र' भट्ट हो उठता है और उनकी 'राष्ट्रवृत्ता' को देखकर साधारण पठित जन यही सोचते हैं कि इससे तो अंग्रेजी भली। हिन्दी को समृद्ध करने के नाम पर भ्रष्टाभाविक, उच्चारण में दुष्कर शब्दों का निर्माण भाषा के प्रति भ्रष्टाचार का परिचायक है, भ्रष्टाचार का तो है ही।

सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में जहाँ हिन्दी बोलना चाहिए, वहाँ हम अंग्रेजी से काम लेते हैं। परिवार के भीतर वचन से अपनी सन्तान को हम डंडी, मम्मी, अब्बा कहना सिखाते हैं माना यहाँ भी पारिवारिक शब्दों की कमी हो। हमारे उच्च मध्यवर्ग के लोगों की बहुत बड़ी आकांक्षा यह रहती है कि बेटा कॉन्वेंट में पढ़े, परीटे से अंग्रेजी बोले, मजिस्ट्रेट बनकर लोगों पर हुकूमत करे। जिसका विभाव, जिसके गांधी और बुद्ध। खाने के दाँत और, दिखाने के और।

जहाँ तक मुझे मालूम है, इस देश की राजनीतिक परिस्थिति अपना केन्द्रीय



राजनीतिक कार्य, अपने केन्द्रीय मुखपत्र अंग्रेजी में चलाती हैं। हम विश्वभाषा के नाम पर अंग्रेजी पढ़ने पर जोर देते हैं। जहाँ फ्रांस का राज्य था या है, वहाँ विश्वभाषा का दर्जा फ्रांसीसी को मिला है। किस पिछड़े हुए देश ने यूरोप की किस भाषा को विश्वभाषा माना है, यह इस पर निर्भर है कि उस पर यूरोप के किस देश का आधिपत्य था या है।

हमारे अनेक युगान्तरकारी साहित्यकार अपनी वाक्य-रचना में अंग्रेजी शब्दों की ऐसी भरमार करते हैं मानो हिन्दी में सोचना उन्होंने बन्द कर दिया है। वे न हिन्दी में सोचते हैं, न अंग्रेजी में वरन् इन दोनों से मिली हुई एक नई इंग्लिशतानी भाषा में, जो उनके लिए बहुत स्वाभाविक है किन्तु जो देश की जनता के लिए, हमारे समग्र सामाजिक विकास के लिए घातक है। अनेक लेखक अंग्रेजी मुहावरों का अनुवाद करके अपनी जातीय भाषा की सजाते हैं। अंग्रेजी के शब्दों, उद्धरणों और अनुवादित मुहावरों से वे अपनी—भाव-विचार-अनुभव की—दरिद्रता छिपाते हैं। अपनी सांस्कृतिक परम्परा के लिए, भारतीय भाषाओं और उनके साहित्य के लिए उनके हृदय में अनादर की भावना है। उनमें बड़ी उत्सुकता होती है कि नई अंग्रेजी पुस्तकों की चर्चा करके अपने सुसंस्कृत होने का परिचय दें। वे साधारणतः यूरोप की भाषाओं से अपरिचित होते हैं और यूरोप के साहित्य को अंग्रेजी निगाहों से ही देखते हैं।

हिन्दी के अनेक समर्थ साहित्यकार इस भाषा-सम्बन्धी पराधीनता से मुक्त हैं। कुल मिलाकर हिन्दी साहित्य अपने स्वस्थ जातीय मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि छापे की सुविधा से लाभ उठाकर बहुत से लेखक ऐसी भाषा का प्रयोग करने लगे हैं जो हिन्दी के सहज विकास के लिए घातक है।

इनसे भिन्न श्रेणी का एक लेखक समुदाय और है जो अंग्रेजी के माध्यम से ही अपनी कलात्मक प्रतिभा का परिचय देता है। वे किसान-देश की संस्कृति का उद्धार कर रहे हैं, अंग्रेजी में उपन्यास, कहानियाँ, कविताएँ लिखकर। माना कि अंग्रेजी विश्वभाषा है और उसमें लिखने से अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति जल्दी मिलती है किन्तु नाबें, डेनमार्क, इटली, स्पेन, जैसे छोटे देशों के लेखक इस विश्वभाषा को नहीं अपनाते, उसे अपनाने का ठेका हमारे महान् देश के लेखकों ने लिया है।

हमें अपनी भाषा के जातीय रूप की रक्षा करनी चाहिए। उसमें अघाघुष्य अंग्रेजी शब्दों की भर्ती हमारे राष्ट्रीय सम्मान के विपरीत है। हिन्दी की शक्ति उसे अपनाने, प्यार करनेवाली जनता की शक्ति है। दुर्बोध, उच्चारण के लिए विकट शब्दावली से उसे भरसक बचाना चाहिए अर्थात् हमें भरसक अपनी गैली सुगम बनानी चाहिए और वैज्ञानिक शब्दावली में भी भरसक हिन्दी की शक्ति का ध्यान रखना चाहिए। हमारा साहित्य इस देश की जनता के लिए है। इसलिए इंग्लिशतानी के बदले हिन्दी का ही प्रयोग करना चाहिए। अंग्रेजी

के माध्यम से प्राप्त अन्तराष्ट्रीय ख्याति अस्थायी है। रवीन्द्रनाथ और प्रमचन्द ने अपनी भाषाओं के माध्यम से जो ख्याति पाई, वही स्थायी है। जातीय संस्कृति से भाषा का घनिष्ठ सम्बन्ध है, यह ध्यान में रखकर हमें अपने व्यवहार में सतर्क रहना चाहिए।

(१९६४)

## भाषा की समस्या—अति आवश्यक

देश की राजनीतिक परिस्थिति की एक विशेषता यह है कि कांग्रेस को मिलनेवाले बोट दिन-पर-दिन कम होते जा रहे हैं और उसी परिणाम में वाम-पक्षी पार्टियाँ और उनका संयुक्त मोर्चा समर्थ होकर जनता के सामने नहीं आ रहे। पिछले दिनों कम्युनिस्ट पार्टी में विघटन के कारण वामपक्ष और भी कमजोर हो गया है। हिन्दी-भाषी प्रदेश में विशेष रूप से दक्षिणपक्षी दल शहजोर है। चूँकि भारत में हर समस्या अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल ही हल नहीं होती, इसलिए हर जागरूक नागरिक को फासिस्ट तानाशाही की संभावना के प्रति सतर्क रहना चाहिए।

जर्मनी के अनुभव से हमें मालूम है और अपने देश का अनुभव भी यही बतलाता है कि फासिस्ट दल संस्कृति के प्रश्न लेकर जनता को गुमराह करते हैं। हिटलर मध्यवर्ग ही नहीं, मजदूर वर्ग के भी एक भाग को गुमराह करने में सफल हुआ था। हमारे देश में साम्प्रदायिक दल संस्कृति के प्रश्न विशेष रूप से जनता के सामने रखते हैं। वे अपने को भारतीय संस्कृति का एकमात्र रक्षक मानते हैं। संस्कृति को ढाल बनाकर वे अपनी गलत राजनीति के अस्त्र जनता पर चलाते हैं।

कुछ प्रगतिशील लोग समझते हैं कि यदि वे भी संस्कृति की बात करेंगे तो उनमें और साम्प्रदायिक दलों में कोई अन्तर न रह जायगा। आजकल हिन्दी भाषा के सवाल को लेकर हिन्दीभाषी क्षेत्रों में बड़ी सरगमी है। कुछ प्रगतिशील नेता समझते हैं कि अंग्रेजी को व्यवहार में लाना, अंग्रेजी में अपने दस्तावेज तैयार करना, अंग्रेजी में अपने राजनीतिक सम्मेलनों की कार्यवाही सम्पन्न करना, व्यावहारिक राष्ट्रभाषा के रूप में अंग्रेजी को प्रतिष्ठित रखना बहुत बड़ा साम्राज्यवाद-विरोध है, राष्ट्रियता और जनतंत्र के हित में है और साम्यवाद के अनुकूल है। इसके विपरीत अखिल भारतीय स्तर से अंग्रेजी को हटाने की माँग करना, हिन्दी को केन्द्रीय राजकाज की भाषा बनाने के लिए आन्दोलन करना साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देना है।

कोई भी प्रगतिशील दल भाषा और संस्कृति के मामलों में कितना दखल देता है, यह उसके व्यवहार से जाना जाता है। मिसाल के लिए यह विचारणीय है कि मैसिलीशरण गुप्त के निधन पर बिन राजनीतिक दलों ने कहाँ कहाँ शोक प्रस्ताव पास किये। व्यवहार के भलावा विभिन्न दलों के कार्यक्रम प्रस्ताव आदि दर्शनीय हैं यह जानने के लिए कि उन्होंने सांस्कृतिक समस्याओं पर कितना विचार किया है।

माना कि सांस्कृतिक समस्याएँ बहुत उलझी हुई हैं। यह भी माना कि राजनीतिक समस्याएँ सुलझाने में ही बहुत से नेताओं की सारी ताकत खर्च हो जाती है। किन्तु भाषा की समस्या बरौडों आदिमियों को प्रभावित करती है। यह ध्वापक सामाजिक समस्या बन गई है। उस पर सही दृष्टिकोण अपनाना और सही नीति के अनुसार आन्दोलन करना प्रगतिशील जनो का कर्तव्य है।

सवाल यह नहीं है कि जब कांग्रेसी सरकार के बदले हमारे मन-मुनाबिक दूसरी हुकूमत बनेगी तब हम अंग्रेजी को जल्दी हटायेंगे या धीरे-धीरे, देर में हटायेंगे। सवाल यह है कि अभी हम क्या करने जा रहे हैं। और अभी जो कुछ करते हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर है कि भविष्य में यहाँ जनता की सरकार बनेगी या फासिस्ट तानाशाही की।

जब अंग्रेजी राज कायम था तब भाषा की समस्या सभी साम्राज्य-विरोधी दलों और उनके नेताओं के सामने उलझी हुई नहीं थी। एक बात पर सभी सहमत थे कि अंग्रेजी जाय, उसके बने रहने से देश की शक्ति और धन का नाश होता है। आजकल अनेक साम्राज्यविरोधी योद्धा इस बात पर एकमत दिखाई देते हैं कि कागज पर चाहे जो छपा रहे, व्यवहार में अंग्रेजी ही राष्ट्र-भाषा बनी रहे।

हिन्दी भाषी प्रदेश में कोई भी दल भाषा के सवाल को नजरअंदाज करके शक्तिशाली नहीं बन सकता। अंग्रेजी को हटाने और हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने की माँग जनता की न्यायपूर्ण साम्राज्यविरोधी राष्ट्रीय माँग है। प्रगतिशील नेताओं को उसका समर्थन ही न करना चाहिए, आगे बढ़कर उसके लिए आन्दोलन करना चाहिए। वे लोग ही विभिन्न भाषाओं के उचित अधिकारों की रक्षा करते हुए हिन्दी के लिए सही आन्दोलन कर सकते हैं। वे अपना उत्तरदायित्व न निबाहेंगे तो दक्षिणपथी ताकतों को अवसर मिलेगा कि वे सही माँग के लिए गलत ढंग से आन्दोलन चलाएँ, जातीय और साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाएँ और जनवादी पार्टियों के दमन के लिए आवश्यक तैयारी करें। जो प्रगतिशील नेता अब भी बेछवर रहते हैं, वे वस्तुगत रूप से जनतंत्र का नाश करने और तानाशाही को लाने के लिए जिम्मेदार होंगे। (१९६५)

शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगी। क्या यह भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी लादना नहीं है? अंग्रेजी को लादना तो राष्ट्रीय एकता के लिए हितकर बताया जाता है, अंग्रेजी की जगह हिन्दी के चलन की बात भी करना साम्राज्यवाद है! तमिल की जगह तमिलनाडु में ही अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनी रहता तो इससे राष्ट्र का विकास होता है, यदि केन्द्रीय राजकाज के लिए—तमिलनाडु में नहीं, केवल केन्द्रीय राजकाज के किसी अत्यन्त सीमित दायरे में—हिन्दी चलन की बात की जाय तो साम्राज्यवाद हो जाता है।

देश का भला चाहनेवाले अनेक नेताओं और पत्रकारों ने लिखा है, वक्तव्य दिये हैं कि दक्षिणवालों का भय जायज है और उसे दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। यह भय क्या है? भय यह है कि हिन्दी के राजमापा होने से अखिल भारतीय सरकारी नौकरियाँ हिन्दीवाले हथिया लेंगे, दक्षिणवाले टापते रह जायेंगे। राष्ट्रीय एकता और तमिल-प्रेम का सम टूटता है नौकरियों के मसल पर। किसी समय भारत का उच्च वर्ग अंग्रेजों से माँग करता था कि सरकारी नौकरियाँ उस भी दी जाएँ, अंग्रेजों के लिए सुरक्षित न रहें। इस उच्च-वर्ग का भारत की स्वाधीनता की चिन्ता नहीं थी, उसकी लड़ाई थी सरकारी नौकरियों के लिए। तमिलनाडु और अन्य प्रदेशों के अंग्रेजी-प्रेमी नेताओं को रोटो रोऊ का मसला हल करने की, देश के आर्थिक विकास की चिन्ता नहीं है। उनका सबसे बड़ी चिन्ता है सरकारी नौकरियों की। ठीक है। सरकारी नौकरियों की चिन्ता कीजिए। लेकिन राष्ट्रीय एकता के सबादे से इस स्वार्थ को मत ढँकिए। मातृभाषा-प्रेम की पवित्र भावना जगाकर नौकरियों के इस सघर्ष में भोली-भाली जनता को पुलिस-फौज की गोलियों का शिकार न बनाइए।

अखिल भारतीय नौकरियों के लिए जो परीक्षाएँ होती हैं, उनमें अंग्रेजी और हिन्दी की स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि अभी तक इन परीक्षाओं का एकमात्र माध्यम है अंग्रेजी। इस माध्यम का हटाने की कोई भी योजना नहीं है, कागजों और तौर पर भी नहीं है। सबकुछ केवल यह है कि केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्रदेशों के मुख्य मन्त्रियों की राय से एक प्रयोग करने का निश्चय किया है। वह प्रयोग यह है कि यदि हिन्दी को भी अंग्रेजी के साथ—अंग्रेजी की जगह नहीं—कुछ विषयों में (सभी विषयों में नहीं) परीक्षा का माध्यम बनाया जाय तो इससे अंग्रेजी माध्यमवाले घाटे में तो नहीं रहेंगे। यह प्रयोग हुआ नहीं है। उसका होने की बात है। उस प्रयोग से जब अहिन्दी-भाषी भी सन्तुष्ट हो जायेंगे कि अंग्रेजी का व्यवहार करने पर उन्हें घाटा नहीं होगा, तब उनके सहमत होने पर कुछ विषयों में अंग्रेजी के साथ हिन्दी भी एक ऐच्छिक माध्यम हो सकती है। अंग्रेजी के लिए इतना ही सकट उत्पन्न हुआ है।

प्रधानमन्त्री ने कहा है कि हिन्दी-प्रेमियों का अंग्रेजी हटाने में जल्दी न करनी चाहिए। स्वराष्ट्र-मन्त्री ने कहा है, हमें इस मामले में जल्दी न करना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने सरकार को सत्ताह दी है कि हिन्दी को

राजभाषा बनाने में जल्दी न करनी चाहिए। आखिर वह बोन-सी तब रफ्तार की और किस क्षेत्र में थी, जिससे हिन्दी राजभाषा बनी जा रही थी? आजादी पाने के छठारह साल बाद जो सरकार मिली भारतीय नौकरियों के लिए हिन्दी को केवल ऐच्छिक माध्यम बनाने के प्रयोग की बात बग़ती है, उसमें भी कुछ बुद्धिमानों की तेज़ रफ्तार की शिकायत होती है।

हिन्दी तो एक दिन राजभाषा होगी, लेकिन धीरे-धीरे—ऐसा कहनेवाले वास्तव में अंग्रेज़ी की हिमायत करते हैं। इसका प्रमाण यह है कि अपना मिलित भारतीय राजनीतिक कार्य में नेता और उनकी पार्टियाँ अंग्रेज़ी में करती हैं। व्यवहार में अंग्रेज़ी, हिन्दीभाषी जनता के बोट लेने के लिए भविष्य में हिन्दी को राजभाषा बनाने के वादे। यह दुरणी नीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी।

कुछ दूसरे लोग हैं जो माँग करते हैं कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने अंग्रेज़ी के सम्बन्ध में जो वादे किये थे, वे सविधान में दर्ज हो जान चाहिए। यद्यपि वर्तमान प्रधानमंत्री ने उन आश्वासनों को दुहराया है, किन्तु बहुत-से दशम्वत्ती के लिए इतना काफी नहीं है। वे चाहते हैं कि सविधान में उन आश्वासनों को दर्ज कर दिया जाय।

अनेक स्थानों में यह नया नारा सुनने को मिलता है—‘हिन्दी नेवर, इंग्लिश एवर।’ हिन्दी कभी न आण, अंग्रेज़ी हमेशा बनी रह। दक्षिण में जो उच्चकाटि के प्रतिक्रियावादी नेता हैं, वे यही नारा दे रहे हैं कि भारत की एकमात्र राजभाषा अंग्रेज़ी हो। अपने आन्दोलन के जरिये व सबसे पहले तमिल की जड़ बाट रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तमिलनाडु में तमिल उच्चशिक्षा का माध्यम नहीं बनी। इसके बाद वे विशाल हिन्दीभाषी प्रदेश पर—तथा अन्य अहिन्दी राष्ट्रभाषा प्रेमी जनता पर—सदा के लिए अंग्रेज़ी का प्रभुत्व कायम रखने का पटवन्त्र कर रहे हैं। अंग्रेज़ी के इस वास्तविक साम्राज्यवाद को देश की जनता कभी सहन न करेगी।

यह ध्यान देने की बात है, हिन्दी विरोधी आन्दोलन ने भयानक उदगार का रूप केवल तमिलनाडु में लिया है। अंग्रेज़ी प्रेमी नेता अन्य प्रदेशों में भी हैं, किन्तु उन्होंने कोई उग्र आन्दोलन नहीं चलाया। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि अंग्रेज़ी प्रेमी नेता जानते हैं कि वास्तव में अंग्रेज़ी के लिए कोई खतरा नहीं है, हिन्दी को व्यावहारिक राजभाषा होने में बहुत देर है। इसलिए गर्म या नर्म किसी तरह के आन्दोलन को वे अनावश्यक समझते हैं। दूसरा कारण यह है कि तमिलनाडु का भारत से अलग करने के लिए जैसा आन्दोलन उस प्रदेश में हुआ है, वैसा आन्दोलन अन्य किसी प्रदेश को अलग करने के लिए नहीं हुआ। विघटन के इस प्रचार की राजनीतिक दलों ने सगठित किया। भाषाशास्त्र और इतिहास की भूठी गवाही से उस विघटन की भावना को वर्षों तक फैलाया। केन्द्रीय या तमिलनाडु का शासन अथवा कोई भी राजनीतिक दल उसका समर्थन प्रतिवाद नहीं कर पाया। यही कारण है कि हिन्दी-विरोधी

आन्दोलन ऐसा विनाशक रूप केवल तमिलनाडु में ले सका । । ।

इसका अर्थ यह है कि हिन्दी विरोध एक नकाब है, जिसके नीचे विघटन का देव छिपा हुआ है । नौकरी न मिलेगी यह भय दिखलाकर स्वार्थी नेताओं ने छात्रों को उभारा है और स्वतन्त्र द्रविड राज्य वायम करने के लक्ष्य के लिए उनका उपयोग किया है । देश की स्थिति ऐसी है कि कश्मीर, नागालैण्ड या तमिलनाडु कोई भी प्रदेश अलग होता है, तो उसकी हिमायन के लिए साम्राज्यवादी आगे आते हैं । वे अपने फौजी भ्रष्टा का स्वप्न देखते हैं, भारत का जो हिस्सा मिले उसका उपयोग अपनी समर योजनाओं के लिए करना चाहते हैं । कुछ विदेशी पत्रों ने तमिलनाडु के हिन्दी-विरोधी आन्दोलन को लेकर तमिल की लिपि, तमिल भाषा की व्यञ्जना शक्ति की बड़ी प्रशंसा की है और हिन्दी को तमिल से नीचा ठहराया है । इस प्रचार का उद्देश्य भारत में गृहयुद्ध की आग सुलगाना है ।

भारत से अलग होकर तमिलनाडु या कोई भी प्रदेश न तो साम्राज्यवाद से मुक्त रह सकता है, न अपना आर्थिक और सांस्कृतिक विकास कर सकता है । विग्रहकारी आन्दोलन से सर्वप्रथम उस प्रदेश का अहित होता है जहाँ ऐसा आन्दोलन चलाया जाता है । उसके बाद समूचे देश का अहित होता है । अंग्रेजी की सुरक्षा का यह आन्दोलन देश के विघटन का आन्दोलन है । समस्या हिन्दी और तमिल की नहीं है, समस्या तमिलनाडु को भारत का अभिन्न अंग बनाये रखने की है ।

यह सम्भव है कि भारत सरकार अंग्रेजी प्रेमियों के दबाव से अंग्रेजी की सुरक्षा के लिए कुछ और नियम कायदे बना दे या सविधान में तब्दीली कर दे । इससे अंग्रेजी की वास्तविक स्थिति में कोई अंतर न पड़ेगा । अंग्रेजी तो राज भाषा के रूप में सुरक्षित है ही । भारतीय भाषाओं को उनके उचित अधिकार दिलाने के लिए यह जरूरी है कि सबसे पहले हिन्दीभाषी प्रदेश में अंग्रेजी को राजभाषा और सांस्कृतिक भाषा के पद से पूर्णतः हटा दिया जाय, विश्वविद्यालयों में पूर्णतः हिन्दी को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय, यहाँ के न्यायालयों का सारा काम हिन्दी में हो, सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन में अंग्रेजी का व्यवहार खत्म किया जाय । इसके बाद जिस दिन हिन्दीभाषी जनता संगठित होकर अपने लोक-सभा के प्रतिनिधियों को हिन्दी में बोलने और सारा राजकाज हिन्दी में करने के लिए बाध्य करेगी, उस दिन अंग्रेजी का साम्राज्यवाद खत्म हो जाएगा, उस दिन तमिलनाडु में तमिल भी अपना पूर्ण स्वंत्व प्राप्त करेगी और राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने में हिन्दीभाषी जनता अपनी भूमिका पूरी करेगी । अंग्रेजी को हटाने और राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने का भार अब हिन्दीभाषी प्रदेश पर है ।

(१९६५)

## भाषा की समस्या और राष्ट्रीय विघटन

जिस समय भारत की संविधान सभा ने यह निश्चय किया कि राष्ट्रभाषा हिन्दी हो और तुरन्त नहीं, पन्द्रह साल बाद सन् '६५ में हो, उस समय इस फैसले के पक्ष में बोट देनेवाले उत्तर के लोग भी थे, दक्षिण के भी, हिन्दी-भाषी इलाकों के नेता भी थे और अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के भी। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि यह फैसला हिन्दीवालों ने दक्षिण या बंगाल पर लादा था।

जैसे-जैसे सन् '६५ निकट आता गया वैसे-वैसे उस फैसले को टालने के लिए भी कोशिशें होने लगीं। संसद ने एक कानून बना दिया जिसके अनुसार सन् '६५ के बाद भी अंग्रेजी सह-राजभाषा बनी रह सकती है। इस फैसले से हिन्दी को घक्का लगा, यह माना जा सकता है। किन्तु उससे किसी अहिन्दी भाषा को हानि हुई यह दावा कोई नहीं करता।

इसके बाद भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि अहिन्दी-भाषियों की भर्जों के बिना अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा। इस साल २६ जनवरी से दिल्ली सरकार ने अपना राजकाज हिन्दी में नहीं शुरू किया, किसी अफसर को हिन्दी न जानने के कारण निकाला नहीं गया, अखिल भारतीय नौकरियों के लिए परीक्षाएँ हिन्दी में नहीं होने लगीं, न अंग्रेजी को हटाकर उन परीक्षाओं के लिए हिन्दी को एकमात्र माध्यम बनाने का फैसला किया गया, उत्तर-दक्षिण के विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हिन्दी नहीं बनी, किसी भी केन्द्रीय मन्त्रालय ने अपने कार्यालय-पत्र हिन्दी में तैयार करना नहीं शुरू किया, न इस तरह के कार्यालय-पत्र केन्द्र से राज्यों को भेजे गए, तमिलनाडु या बंगाल से अंग्रेजी में लिखकर भेजा हुआ कोई कार्यालय दिल्ली से वापस नहीं किया गया, कांग्रेस के प्रधान श्री कामराज के तमिल में ही बोलने पर कहीं हिन्दी-जनता ने प्रदर्शन नहीं किया, फिर भी तमिलनाडु में उत्पात मचा हो गया।

केन्द्रीय सरकार में उत्तर-दक्षिण, हिन्दी-अहिन्दी सभी प्रदेशों के लोग हैं। इस सरकार का कोई भी काम सिर्फ हिन्दीभाषी जनता का काम नहीं माना



जाना। फिर भी अगर कोई ऐसा काम हुआ हो जिससे अंग्रेजी की गौरवमय स्थिति को धक्का लगा हो तो मैं जानना चाहता हूँ कि वह काम कौन-सा है। सन् '६५ में हिन्दी को—बागज पर, दिखावे के लिए—राष्ट्रभाषा बनाने का फैसला सोलह साल पहले किया गया था। फैसला करनेवाले उत्तर-दक्षिणवाले दोनों थे। फिर अचानक अहिन्दी भाषियों पर हिन्दी भाषा कैसे लाद दी गई?

कुछ लोगो का कहना है कि भारत ने सभी राज्यों की भाषाओं को बराबरी का दर्जा दे दिया जाय। मैं कहता हूँ शोक से दीजिए। लेकिन भाषा जिस पार्टी में भी हो, उसका राजनीतिक काम दस बारह भाषाओं में करके दिखाइए। जो पार्टियाँ अपना केन्द्रीय काम एक भाषा में करती हो, उन्हें कोई हक नहीं है कि वे केन्द्र में दस भाषाएँ चलाने की बात करें।

कुछ बुद्धिमान नेता यह राय देते हैं कि राज्यों में वही की भाषाएँ चलें लेकिन केन्द्र में अंग्रेजी चने क्योंकि हिन्दी को अभी और विकसित होना है। इसका मतलब यह हुआ कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि के राजकाज के लिए तो हिन्दी विकसित है, केवल केन्द्रीय राजकाज के लिए वह अविकसित है। मैं जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और केन्द्र के राजकाज में वह कौन-सा गुणात्मक अन्तर है जिससे हिन्दी एक जगह विकसित मानी जाती है और दूसरी जगह अविकसित।

अमलियत यह है कि अंग्रेजी को देश में कायम रखने के लिए हर दलील जायज है। अंग्रेजी के जरिये हमारा अफसर वर्ग साहब बनकर जनता पर हुकूमन करता है। और हर पार्टी के अन्दर अंग्रेजी के कारण एक ऊँचे पाये का नेता है जिसे अपने महान् विचार प्रकट करने में किसी भारतीय भाषा को माध्यम बनाते हुए बड़ी कठिनाई होती है। दूसरा नेता छोटे दर्जे का केवल भारतीय भाषाएँ जाननेवाला है। अंग्रेजी के जरिये अफसर और जनता, साहब और गुलाम, बड़ा आदमी और छोटा आदमी—दो वर्गों में सारे देश को बाँटने में सहाय्य होती है। जो लोग कहते हैं कि अंग्रेजी के रहने से राष्ट्रीय एकता कायम रहती है, उनका मतलब यही होता है कि उसके जरिये काले साहबों की एकता कायम रहती है। इस एकता के कारण ग्राम जनता और हुकूमत के बीच कितना बड़ा फासता कायम रहता है, इसकी चिन्ता उन्हें नहीं होती।

अब यह बिलकुल स्पष्ट है कि लडाई तमिल या बंगला के अधिकारों के लिए नहीं है। लडाई है अंग्रेजी के बेजा अधिकारों की रक्षा के लिए। तमिलनाडु के जिन विद्यालयों में तमिल की शिक्षा का माध्यम बनाया गया उन्हें बन्द कर देना पड़ा। आंध्र के शासकों का कहना है कि तेलुगु को राजभाषा बनाने में दस साल लगेंगे। इसमें क्या सार्वभित होता है? क्या हिन्दी राष्ट्रभाषा बनकर तमिल और तेलुगु के अधिकार छीने ले रही है? हकीकत यह है कि आंध्र और तमिलनाडु में राजभाषा अंग्रेजी है और उसे हटाने के बदले प्रदेश प्रेमी सज्जन हिन्दी-विरोधी आन्दोलन चला रहे हैं।

केन्द्र में अंग्रेजी और प्रदेश में अंग्रेजी—दोनों जगह के तार भाषण में जुड़े हुए हैं। जो केन्द्र में अंग्रेजी हटाने का विरोधी है वह प्रदेश में भी उसे नहीं हटाना चाहता। बात बिल्कुल स्वाभाविक है। तमिलनाडु में रहनेवाला जो मूढ़स्थ अपने बेटे को अंग्रेज इडिया सबिन्स में भ्रमण बनाना चाहता है वह उसके लिए तमिल की शिक्षा का माध्यम क्यों बनाए ? प्रदेश में हर स्तर पर वहीं की भाषा चालू हो जाय तो होनहार नौजवानों को अंग्रेजी निखने-बोलने में कठिनाई न होगी ? अंग्रेजी बोल ज्यादा अच्छी बोलेंगे—वह जिसकी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रही है या वह जो शिक्षा प्रादेशिक भाषा में पाता रहा है ? इसीलिए गुजरात में आन्दोलन हो रहा है कि अंग्रेजी की शिक्षा को बड़ी दर्जा दिया जाय जो और राज्यों में उसे प्राप्त है।

जब तक केन्द्र की राजभाषा अंग्रेजी है तब तक प्रदेशों में वहाँ की भाषाएँ पूरी तरह राजभाषा बन नहीं सकती। बेटा इंजीनियर बनेगा, लोकसभा का सदस्य बनेगा, वही का राज्यपाल बनेगा, कलक्टर या कमिश्नर बनेगा। यह सब बनने-बनाने का काम अंग्रेजी से होगा या तमिल और मराठी से ? होनहार नौजवानों के माता-पिता क्या मुर्त हैं जो प्रादेशिक भाषा में शिक्षा देकर उनका अखिल भारतीय भविष्य नष्ट करेंगे ?

इसलिए वे नेकदिन नेता, जो भाषा-समस्या सुलझाने के लिए यह सुभावेष कर रहे हैं कि राज्यों में तुरन्त वहाँ की भाषाओं को राजभाषा बनाया जाय और केन्द्र में अंग्रेजी को बहुत धीरे-धीरे हटाया जाय, बहुत भारी भ्रम में हैं। स्वाधीन भारत में शिक्षा का महान् उद्देश्य अब भी अखिल भारतीय नौकरियाँ प्राप्त करना है। बेटों का ब्याह भाई० ए० एस० अफसर से हो, मध्यवर्गीय बाप की यह सबसे बड़ी तमन्ना होती है। प्रदेशों में शिक्षा का संगठन इन्हीं अखिल भारतीय नौकरियों को लक्ष्य बनाकर होना है। इसलिए जब तक केन्द्र में अंग्रेजी रहेगी जब तक अखिल भारतीय स्तर पर अंग्रेजी का मौजूदा रोबदार रहेगा, तब तक प्रदेशों में भी अंग्रेजी हटाई न जाएगी। जो सचमुच अंग्रेजी हटाकर प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा बनाना चाहते हैं, वे केन्द्र में अंग्रेजी के समर्थक हो ही नहीं सकते।

सरकार की बात जाने दीजिए। मैं उन अखिल भारतीय पार्टी का नाम जानना चाहता हूँ जिसकी प्रादेशिक शाखाएँ अपना सारा काम भारतीय भाषाओं में करती हैं और जो केन्द्र में अंग्रेजी हटाकर धीरे-धीरे हिन्दी लाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

भाषावार राज्यों के पुनर्गठन का आन्दोलन चला। इस आन्दोलन में यह जोरदार आवाज नहीं सुनाई दी कि प्रदेशों में अंग्रेजी हटाई जाय, प्रादेशिक भाषा को राजभाषा बनाया जाय। इसका क्या कारण है ? कारण यह है कि भाषावार राज्य बनाने में प्रादेशिक पूँजीपतियों का भी स्वार्थ था, वे अपने लिए अपने बाजार कायम करना चाहते थे, उन्हें प्रादेशिक भाषाओं के कोई मत

मोहब्बत न थी। प्रगतिशील नेताओं ने उनका साथ दिया, ठीक किया। लेकिन प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाय, इसके लिए वे कोई सशक्त आन्दोलन नहीं कर सके। क्यों ? आज भी प्रस्ताव पास करने के अलावा प्रदेशों में अंग्रेजी हटाने के लिए कोई आन्दोलन नहीं चलाया जा रहा, न कोई आन्दोलन चलाने का कार्यक्रम है। क्यों ? प्रदेशों में अंग्रेजी हटाने के लिए भाषावार प्रान्त आन्दोलन जैसी कोई चीज सामने क्यों नहीं है ? इसलिए कि प्रादेशिक पूँजीपतियों का साथ देते हुए बहुत से प्रगतिशील नेता भी भटकाव के शिकार हो गए हैं। उन्होंने प्रादेशिक भाषाओं के लिए आन्दोलन नहीं किया, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं के लिए मरे खपे। उन्होंने प्रादेशिकता के आन्दोलन में राष्ट्रीय एकता की भावाज्ज वुलन्द नहीं की। उसी का नतीजा है कि आज वे प्रदेशों में तो अंग्रेजी हटाने की बात करते हैं लेकिन केन्द्र में काफी दिन तक अंग्रेजी कायम रखने की बात सोचते हैं। नतीजा यह होता है कि अंग्रेजी न केन्द्र से हटती है, न प्रदेशों से। हिन्दी के लिए जो सही माँगें हैं उन्हें पेश करने का काम उन्होंने श्री मुरारजी भाई और जनसंघ के नेताओं को सौंप दिया है। उनकी ढिलाई से प्रतिक्रियावादी नेता फायदा उठा रहे हैं, यह देखने के बदले वे प्रसन्न होकर फतवा देते हैं—तुरन्त अंग्रेजी हटाने का नारा मुरारजी और सधियों का है। आश्चर्य की बात है कि संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन में जनसंघ के साथ काम करते हुए अनेक प्रगतिशील नेताओं को जरा भी तकलीफ नहीं हुई। अब केन्द्र से अंग्रेजी हटाने के सवाल पर वे जनसंघ का होवा खड़ा करते हैं।

कुछ दिन पहले बंगाल में प्रगतिशील और अप्रगतिशील सभी दलों ने हिन्दी चालू न करने के लिए एकमत होकर प्रस्ताव पास किया। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम से लेकर केन्द्र-मन्त्रियों तक अंग्रेजी की सुरक्षा के लिए एकमत हैं। केरल में 'राइवन कम्युनिस्ट' श्री नम्बूद्रीपाद मुस्लिम लीग से साँठ गाँठ करने में दक्षिण हैं। भाषा के प्रश्न पर जहर उगलनेवाले श्री फ्रैंक ऐन्टनी के साथ कुछ प्रगतिशील नेताओं ने एक ही बयान पर हस्ताक्षर किये हैं। प्रदेशों में अंग्रेजी के पक्ष में प्रगतिशील अप्रगतिशील एक हो सकते हैं। केवल केन्द्र में अंग्रेजी हटाने के सवाल पर मुरारजी भाई और जनसंघ में सावधान रहना चाहिए।

तमिलनाडु में भाषा का आन्दोलन प्रतिक्रियावादियों के हाथ में था। उन्होंने जनता के तमिल प्रेम से लाभ उठाकर पुस्तकालयों, स्टेशनों और डाकखानों में आग लगाई। खूब समझ लीजिए यह गृहयुद्ध की आग है। उत्तर में मुरारजी भाई आदि अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन अपने हाथ में ले रहे हैं। प्रगतिशील नेता टुकुर-टुकुर देख रहे हैं। अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन अपने हाथ में लेकर वे उसे प्रतिक्रियावादियों को सौंप रहे हैं।

प्रगतिशील नेता बहुत नैक सर्लाह देते हैं कि हिन्दी भाषी जनता को अन्य राष्ट्रवाद का शिकार न होना चाहिए। सही बात है। हिन्दी जनता का राष्ट्रवाद कैसे जाहिर होता है ? जो लोग समझते हैं कि सारे देश में हिन्दी वैसे ही

चलेगी जैसे ब्रिटेन में अंग्रेजी चलती है, यानी जो भारतीय भाषाओं को मिटाना चाहते हैं और राष्ट्रीय एकता का मतलब यह लगाते हैं कि और सब भारतीय भाषाएँ मिट जाएँ, उनकी जगह हिन्दी ही रहे, वे अन्ध राष्ट्रवादी हैं। किन्तु हिन्दी प्रदेशों में किसी ने यह माँग नहीं की कि तमिलनाडु में तमिल को शिक्षा का माध्यम न बनाया जाय, यह माँग नहीं की कि वहाँ या बंगाल या महाराष्ट्र में हर स्तर पर हिन्दी चलाई जाय। इसके विपरीत दुआ यह है कि सभी दलों के नेता प्रादेशिक भाषाओं को उनके पूर्ण अधिकार देने के पक्ष में हैं। माँग है अंग्रेजी को हटाने की, न कि अहिन्दी भाषाओं को दबाने की। इसलिए केन्द्र से अंग्रेजी को हटाने के सवाल पर हिन्दी साम्राज्यवाद का भय दिखाना वास्तव में अंग्रेजी की सुरक्षा के लिए बहुत घटिया विस्म की बकालत करना है।

सरकार क्या करेगी और दूसरी पार्टियाँ क्या करेंगी, ये बड़ी-बड़ी बातें हैं जिन पर इस लेख में कुछ नहीं कहना। मेरी माँग भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से है। आप अपना सारा प्रादेशिक काम भारतीय भाषाओं में कीजिए, एक महीने के अन्दर प्रदेशों में अंग्रेजी की जड़ काट दीजिए। केन्द्र में अपना काम चाहे हिन्दी में कीजिए चाहे हिन्दी को बिल्कुल न रखिए बल्कि वह काम दस बारह-चौदह अहिन्दी भाषाओं में कीजिए, अगले छह महीनों में अपने केन्द्र से अंग्रेजी का पूर्ण बहिष्कार कीजिए। ऐसा आप कर लें तो मैं समझूँगा कि भारत की भाषा-समस्या हल करने में आपन बहुत बड़ी सक्रिय सहायता दी है। वरना देश जिम विघटन की ओर बढ़ रहा है, उसमें सबसे पहली चोट आप पर होगी और आप यह कहने की हालत में भी न होंगे कि चोट गसत पड़ी।

मध्यवर्ग का सहारा लेने के लिए फासिस्टवाद भाषा और संस्कृति का रक्षक बनकर सामने आता है। हिटलर जर्मन भाषा और जर्मन संस्कृति का बहुत बड़ा समर्थक बनकर रंगमंच पर आया था। तमिलनाडु में तमिल-रक्षा का भार द्रविड मुन्नेत्र कळगम पर, उत्तर में हिन्दी-रक्षा का भार जनसंघ पर और दोनों की रक्षा का भार महान् गणराज्य संयुक्त राष्ट्र अमरीका पर। भारत का भावी मानचित्र आपको कैसा दिखाई देता है ?

पहले एक देश में दो देश बने, भारत और पाकिस्तान। अब भारत में दो नये राष्ट्रों का निर्माण होगा, एक हिन्दी राज्य, दूसरा अहिन्दी-राज्य। लेकिन विघटन यही समाप्त न होगा। असम में दगे हिन्दी-भाषियों के खिलाफ न हुए थे। बम्बई में संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन के दौरान अन्ध राष्ट्रवादियों का क्रोध हिन्दी भाषियों पर न बरसा था। मारे गये थे बंगाली और गुजराती, दोनों अहिन्दी भाषी। तमिलनाडु और आन्ध्र के अनेक शिक्षित जनों में एक-दूसरे के प्रति वही भाव है, जो असमी-बंगालियों, गुजराती-मराठी-भाषियों में है। कश्मीर और नागा प्रदेश में अलगाव के आन्दोलन से सभी लोग परिचित हैं। द्रविड मुन्नेत्र कळगम मूलतः तमिलनाडु को अलग करने का आन्दोलन करता रहा है, हिन्दी विरोध को मढ़काने और उससे लाभ उठाने की सूझ-बाद की है। मुस्लिम

लीग के 'डायरेक्ट ऐक्शन' से त्रस्त होकर देशप्रेमी नेताओं ने देश का विभाजन स्वीकार किया। उससे साम्प्रदायिक समस्या सुलभ गई? साम्राज्यवाद को अपने पौजी अड्डे बनाने का मौका नहीं मिला? दोजिए तमिलनाडु को आत्म-निर्णय का अधिकार! कीजिए कश्मीर और नागा प्रदेश को भारत से अलग! कहिए कि भारत की अखंडता का नारा जनसंघ का नारा है! आपके आत्म-निर्णय के अधिकार से साम्राज्यवाद को लाभ होता है या भारत की जनता को?

भारत के मजदूर वर्ग का संगठन प्रदेशों में घटेंगा नहीं, वह अग्रिम भारतीय स्तर पर होगा। विकास की पंचवर्षीय योजनाएँ अखिल भारतीय स्तर पर बनेंगी और उसी पर सफल होगी। केरल में अन्न की कमी या बेकारी अन्य राज्यों और केन्द्र के सहयोग से ही दूर होगी। राष्ट्रीय विघटन का धर्म है सबकी हानि, साम्राज्यवाद का लाभ। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है सबका लाभ, साम्राज्यवाद की हानि।

यह राष्ट्रीय एकता अब अंग्रेजी जाननेवाले डेढ़ फी सदी लोगों के सहारे कायम नहीं रह सकती। अगर केन्द्र में हिन्दी चलाना साम्राज्यवाद है तो अंग्रेजी कायम रखना और भी बड़ा अन्याय है। हिन्दी भाषी जनता इसे कभी सहन न करेगी। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के चाहे जितने आश्वासनों को कानून का रूप दे दीजिए, वे अंग्रेजी की रक्षा नहीं कर सकते।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का आन्दोलन यहाँ उन्नीसवीं सदी से हो रहा है। गांधीजी ने हिन्दी-प्रचार को राष्ट्रीय आन्दोलन का अभिन अंग बनाया। भारत को स्वाधीन हुए अठारह साल हो गए। अब और कितने धीरे? कुछ रपतार निश्चित कर दीजिए। मालूम तो हो जाय कि अठ्ठाईस कोस नीं दिन में तै करने हैं या अठारह दिन में।

एक अजीब बात हिन्दी के पिछड़ेपन के बारे में है। लेनिन ने जारशाही रुस की भाषाओं को पिछड़ा हुआ न पाया। उन्होंने गैर रूसी भाषाओं को राजकाज के लिए माध्यम बनने दिया। चीनी भाषा पिछड़ी हुई नहीं है, माओत्से तुंग और चीनी सरकार के काम आती है। सिर्फ हिन्दी ऐसी पिछड़ी हुई भाषा है और भारत के बुद्धिजीवी ऐसे महान् चिन्तक हैं कि अंग्रेजी के बिना न तो केन्द्रीय सरकार का काम चल सकता है, न किसी पार्टी का अपना राजनीतिक कार्य, विशेषकर उसका केन्द्रीय राजनीतिक कार्य! यह पिछड़ेपन की दलील न केवल हिन्दी भाषी जाति का अपमान है बल्कि अंग्रेजी की गुलामी का सजीव प्रमाणपत्र है।

राज्यों में प्रादेशिक भाषाएँ और केन्द्र में हिन्दी—ये दोनों लक्ष्य एक ही साथ सिद्ध होंगे। ये दोनों लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं यदि राजनीतिक पार्टियाँ अपने व्यवहार में इस नीति को अपना लें। कयनी और करनी में भेद होने में कोई समस्या हल नहीं हो सकती। जितना ही विलम्ब होगा, उतना ही विघटन

बढ़ेगा। इसलिए सही नीति के लिए हिम्मत से ग्रान्दोलन करने का समय अभी है, कल न रहेगा।

हिन्दी के लिए धीरे चलो, यह ग्रन्त है। कहना चाहिए, धीरे तेज चलो। केन्द्र और राज्यों से एक साथ अंग्रेजी हटाओ—यही नारा सही है।

केन्द्र में आप हिन्दी नहीं चाहते, न रखिए। लेकिन अंग्रेजी न चलेगी। उसकी जगह भारत की एक भाषा चलाइए, चाहे दस भाषाएँ। केन्द्रीय सरकार में जो भाषा-नीति आप चलाना चाहते हों, उसे अपनी पार्टी के व्यवहार में लाइए। इसी से हमें विश्वास होगा कि आप ईमानदारी से भाषा-समस्या हल करना चाहते हैं। वरना बातें बनानेवाले नेताओं की इस देश में कमी नहीं है।

(१९६५)

## भाषा की समस्या और मज़दूर वर्ग

समाज की और दूसरी समस्याओं की तरह भाषा की समस्या पर भी साम्राज्यवादियों, भारतीय पूँजीपतियों और मज़दूर वर्ग के विचार अलग-अलग हैं।

अंग्रेजों ने इस देश को जीता। लोगों की इच्छा के विरुद्ध शिक्षा और शासन में अंग्रेजी चलाई। भारतीय भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं, वे न शासनतंत्र के योग्य हैं, न उनमें आधुनिक शिक्षा दी जा सकती है—यह स्थापना ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के प्रतिनिधि लार्ड मैकाले ने शिक्षा सम्बन्धी अपने प्रसिद्ध लेख में की। अंग्रेजों ने विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाली जातियों को आपस में लड़ाया। इस लड़ाई से लाभ उठाकर उन्होंने सभी के ऊपर अंग्रेजी का प्रमुख कायम रखा। अंग्रेजी की यह गुलामी राजनीतिक पराधीनता का ही एक हिस्सा थी।

राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भ काल से अंग्रेजी हटाने की माँग स्वाधीनता आन्दोलन का अभिन्न अंग बन गई। गांधीजी ने सितम्बर, १९२१ के 'यंग इंडिया' में लिखा था कि उनके हाथ में तानाशाह की ताकत होती तो वह उसी दिन अंग्रेजी में शिक्षा देना बन्द करा देते और जो अध्यापक इस हुक्म को न मानता, उसे वह नौकरी से हटा देते।

अंग्रेजी से किसी एक भाषा का नहीं, सारे राष्ट्र का अहित होता है। इस बारे में गांधीजी ने ५ जुलाई, १९२८ के 'यंग इंडिया' में लिखा था कि अंग्रेजी ने राष्ट्र की शक्ति का नाश कर दिया है और अंग्रेजी बनी रही तो राष्ट्र की आत्मा का नाश हो जायगा।

भारत में प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन के जन्मदाता महान् उपन्यासकार प्रेमचन्द्र ने भाषा की गुलामी के बारे में लिखा था, 'जबान की गुलामी ही मसली गुलामी है।' (प्रेमचन्द, कुछ विचार, पृ० २२१)।

भारत विभाजित हुआ और स्वाधीन हुआ। राजाजी मिले एक ही महीना हुआ था कि गांधीजी ने केन्द्र और प्रान्तों से एक साथ अंग्रेजी हटाने की माँग की। २१ सितम्बर, १९४७ के 'हरिजन' में उन्होंने लिखा कि "प्रान्तीय सरकारों २१२/भारत की भाषा-समस्या -

के लिए ऐसे कर्मचारी रखना बिलकुल प्रासान होना चाहिए जो प्रान्तीय भाषाओं और नागरी या उर्दू लिपि में लिखी जानेवाली अन्तर्प्रान्तीय भाषा हिन्दुस्तानी में सारा काम कर सकें।”

गांधीजी की नीति थी कि केन्द्र और राज्यों से तुरन्त और एक साथ अंग्रेजी हटाई जाय। इसलिए उन्होंने प्रान्तीय सरकारों को सलाह दी थी कि वे ऐसे कर्मचारी रखें जो प्रान्तीय भाषा के साथ हिन्दुस्तानी में भी काम कर सकें।

अंग्रेजी हटाने का काम पन्द्रह साल के लिए टाल दिया जाय, इस नीति के वह विरुद्ध थे। जब अंग्रेजी से नुकसान होता है, तब उस क्यों मालभर भी चलने दिया जाय? उनकी राय थी, “इस आवश्यक तब्दीली में, जो एक-एक दिन बीतता है, उससे राष्ट्र की सांस्कृतिक हानि होती है।”

जो लोग कहते थे कि तुरन्त परिवर्तन सम्भव है उनके बारे में गांधीजी का मत यह था, “हमारे सेप्टेरेरियो में भी, कुछ समय बीतने पर तब्दीली होगी, दिमागी काहिली के अलावा और कुछ नहीं है।”

गांधीजी की सलाह थी—दिमागी काहिली खत्म करो, प्रान्तों और दिल्ली से अंग्रेजी को निवालो, भारतीय भाषाओं का व्यवहार करो।

प्रान्तीय सरकारें केन्द्र से अंग्रेजी द्वारा सम्पर्क कायम न रखेंगी, इस बारे में उन्होंने लिखा था, “प्रान्तों का केन्द्र से काम पड़ेगा। यह काम के अंग्रेजी में करने की हिम्मत न करेंगे। केन्द्र में यह जल्द समझने की बुद्धि होनी चाहिए कि वह सांस्कृतिक रूप में राष्ट्र पर मुट्ठी भर भारतवासियों का बोझ न डालेगा। ये लोग इतने धालसी हैं कि उस भाषा को सोखते नहीं जो प्रासानी से सारे भारत की आम भाषा बन सकती है और जिससे जनता के किसी हिस्से या पार्टी को नाखुशी न होगी।”

गांधीजी की भाषा-सम्बन्धी नीति का निचोड़ यह था, ‘अंग्रेजी ने जो सांस्कृतिक डकैती की है, उसे खत्म किया जाय।’

केन्द्र और प्रान्तों से तुरन्त अंग्रेजी हटाने के बारे में गांधीजी की जोरदार आवाज हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की सच्ची और सही आवाज थी। वह मजदूर वर्ग के हित में थी।

लेकिन सांस्कृतिक डकैती जारी तभी रह सकती थी जब एक और जनता को तसल्ली दी जाय कि अंग्रेजी हटा दी जाएगी, दूसरी ओर कुछ ऐसे कारण बूँद निकाले जाएँ जिससे अंग्रेजी कायम रहे। भारतीय पूँजीवाद एक और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के आर्थिक और राजनीतिक दबाव का विरोध करता था, दूसरी ओर अपने विकास के लिए उससे सहायता भी चाहता था। भारत में ब्रिटिश पूँजी की आमद और ज्यादा हुई, मुनाफा गया बिलायत को, साथ ही देश में उद्योग धंधों का निर्माण भी हुआ। पूँजीवाद की इस दुस्सी नीति के अनुरूप उसकी भाषा नीति थी। भारतीय पूँजीवाद की प्रमुख पार्टी—कांग्रेस

भाषा की समस्या और मजदूर वर्ग



—नै यह नीति निकाली कि अंग्रेजी हटाने का बराबर दम भरते रहो लेकिन अमल में किसी-न-किसी बहाने अंग्रेजी कायम रखो ।

पहला बहाना यह था कि हिन्दी पिछड़ी हुई भाषा है । वह अंग्रेजी की जगह ले, इसके लिए उसे विकसित होने का अवसर देना चाहिए । विकास के लिए पन्द्रह साल का अवसर दिया गया ।

यह शुद्ध बहाना था । लोकसभा में सदस्यों को जीव-विज्ञान या भौतिकी पर बहस न करनी थी । लेकिन हिन्दी को समृद्ध करने के लिए बड़े-बड़े कोश रचे जाने लगे । किसी ने यह न देखा कि इन कोशों में कितने पुराने ऐसे शब्द दोहराए जा रहे हैं जो हिन्दी में सन् '४७ से पहले ही प्रचलित थे । किसी ने लोकसभा में यह भांग न की कि हिन्दी कितनी पिछड़ी हुई है, इसकी जाँच के लिए कम-से-कम एक कमीशन तो बिठा दिया जाय ।

अंग्रेजी कायम रखने के लिए दूसरा कारण यह खोज निकाला गया कि वह आधुनिक ज्ञान-विज्ञान की भाषा है । अंग्रेजी चली गई तो देश आर्थिक और वैज्ञानिक प्रगति में पिछड़ जाएगा ।

अंग्रेजी कायम रखने के पीछे एक जानी-बूझी वर्ग-नीति थी । इसे जनता के गले उतारने का काम किया भारत के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय प० जवाहरलाल नेहरू ने । अंग्रेजी को निकालने और साथ ही कायम रखने की नीति उन्होंने सितम्बर, १९४६ में संविधान सभा में इस तरह पेश की

“अंग्रेजी चाहे जितनी महत्वपूर्ण भाषा हो, हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे देश में कुछ तो अंग्रेजी पढ़े-लिखे शरीफ लोग हों और आम जनता अंग्रेजी से महसूस रहे । इसलिए हमारी अपनी भाषा होनी चाहिए । लेकिन आप इस बात को प्रस्ताव में चाहे लिखें, चाहे न लिखें, अंग्रेजी लाजमी तौर से भारत में बहुत महत्वपूर्ण भाषा बनकर रहेगी जिसे बहुत-से लोग सीखेंगे और शायद उन्हें उसे जबरन सीखना होगा ।”

पाठक १५ सितम्बर, १९४६ के अखबारों में नेहरूजी का यह भाषण पढ़ सकते हैं ।

नेहरूजी ने अपने भाषण में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के भाषा-सम्बन्धी विचारों की भूरि-भूरि प्रशंसा की । फिर अंग्रेजी हटाने की गांधी-नीति से ठीक उल्टी दिशा में चल दिए ।

नेहरूजी भारी जनतन्त्रवादी थे । बेरत की जनताधिक साम्यवादी सरकार के खिलाफ जेहाद की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी ।

नेहरूवाद और मार्क्सवाद पर्यायवाची शब्द नहीं हैं ।

भारतीय पूँजीवाद की पार्टी—कांग्रेस—न तो राज्यों से, और न केन्द्र से अंग्रेजी हटाने में समर्थ हुई । उल्टा उसकी नीति स अंग्रेजी और अंग्रेजियत की जड़ें पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गईं ।

भारत में भाषावार राज्य बनाने का आन्दोलन चला, हर प्रदेश में उसकी

शिक्षा और संस्कृति का विकास उमड़ी भाषा के माध्यम से हो, यह माँग सही थी। लेकिन आन्दोलन में जितना जोर राज्यों की सीमाओं और क्षेत्रफल पर दिया गया, उतना प्रादेशिक भाषाओं पर नहीं। यह भी पूँजीवादी नीति का ही फल था। नतीजा यह हुआ कि भाषावार राज्य बन गए और इन राज्यों में अंग्रेजी कायम रही।

भाषावार राज्यों का आन्दोलन इस तरह चला कि लोगों के सामने प्रादेशिकता मुख्य और राष्ट्रीय एकता गौण हो गई। इस झलगाव की भावना से लाभ हुआ अंग्रेजी को। गुजराती और मराठी-भाषी भाषा में लड़े, अंग्रेजी के समर्थन में दोनों के नेता—विशेष रूप से वामपंथी नेता—एक साथ रहे। प्रथम में भाषा के सवाल को लेकर भयानक दंग हुए। लंदन में हुई प्रसमिया-बैंगला में। दोनों के ऊपर कायम रही अंग्रेजी।

अंग्रेजी कायम रखने के लिए एक नया बहाना और मिला हिन्दीवाले अहिन्दीवालों को दबाना चाहते हैं। द्रविड बळगम ने नारा दिया कि तमिलनाडु भारत से अलग हो। उसने प्रचार किया कि २६ जनवरी, १९६५ से हिन्दी राष्ट्रभाषा हो जाएगी और तमिल का नाश कर देगी। तमिलनाडु के प्रतिनिध्यावादी नेताओं ने जनता के सहज तमिलप्रेम से लाभ उठाकर आपत्त बरपा कर दी। जनतन्त्र और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए अंग्रेजी को कायम रखना आवश्यक हो गया।

सन् '६५ में अंग्रेजी हट न जाय, इसलिये दिल्ली सरकार ने यह कानून बना दिया था कि अंग्रेजी का भी चलन रहेगा। व्यवहार में देखा यह गया कि अंग्रेजी का ही चलन रहेगा। इस तरह भारत की संविधान सभा के फैसले को बड़े वैधानिक ढंग से भारत के जनतन्त्र-प्रेमियों ने पैरों तले रौंदा।

पूँजीपतियों ने अलग, अपने प्राथमिक और राजनीतिक हितों के अनुकूल, भाषासमस्या पर मजदूर वर्ग का अपना दृष्टिकोण होना चाहिए। मजदूर वर्ग समाज का सबसे शान्तिकारी वर्ग है। उसे साम्राज्यवादी विरासत और हमारी गुलामी की प्रतीक अंग्रेजी के खिलाफ सबसे आगे बढ़कर लड़ना चाहिए। अंग्रेजी को हटाने के मामले में वह पूँजीपतियों की टालमटोल नीति का अनुसरण नहीं कर सकता। वह इस दुरंगी नीति पर नहीं चल सकता कि मुँह से कह, 'अंग्रेजी हटाओ', प्रेम में उसे कायम रखे। वह इस दलील को नहीं मान सकता कि भारत की भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं, इसलिये अंग्रेजी कायम रहनी चाहिए। उसके सामने लेनिन की मिसाल है जिन्होंने रूसी साम्राज्यवाद का दबाव खत्म करने के लिए खुद अपनी मातृभाषा रूसी को राजभाषा पद से हटा दिया था। फिर विदेशी भाषा अंग्रेजी को हटाने में किसी को सकोच क्यों हो?

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी ने किसी जाति की भाषा को पिछड़ा हुआ न माना। उसने सोवियत प्रजातन्त्रों में और रूसी भाषाओं को राजभाषा

बनाया। हिन्दी पिछड़ी हुई है, उसे अभी विकसित होना है या जनता के निक्ट पहुँचना है, यह माक्सवादियों का तर्क नहीं हो सकता।

मजदूर वर्ग अखिल भारतीय स्तर पर अपनी एकता अंग्रेजी के माध्यम से कायम नहीं कर सकता। यह एकता किसी भारतीय भाषा के द्वारा ही कायम हो सकती है। वह भारतीय भाषा मजदूर वर्ग के नेताओं के अनुसार हिन्दी है। मजदूर वर्ग की एकता खुद उसके लिए ही नहीं, सारे राष्ट्र के लिए जरूरी है। बंगाल-असम में भगड़े बराते हैं पूँजीपति। उनमें एकता स्थापित करता है मजदूर वर्ग। हिन्दी-अहिन्दी के संपर्क को रोकने की ताकत मजदूर वर्ग में ही है।

मजदूर वर्ग के साथी है किसान। किसान-मजदूर-एकता ही वह शक्तिवारी शक्ति है जो देश को सामाजिक प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकती है। किसान अपना अखिल भारतीय संगठन अंग्रेजी के द्वारा मजबूत नहीं कर सकते। कम्युनिस्ट पार्टी खुद अपने अन्दर बहुत-से किसान-मजदूरों को जगह नहीं दे सकती, क्योंकि अंग्रेजी का प्रभुत्व रहने पर वे न तो पार्टी की ऊँची समितियों के सदस्य हो सकेंगे, न उनकी बहस में ठीक से भाग ले सकेंगे।

इसीलिए मजदूर वर्ग के हित में एक ही भाषा-नीति हो सकती है—राज्यो से और केन्द्र से, दानो जगह से एक साथ अंग्रेजी हटाओ।

इस नीति पर मजदूर वर्ग सारे देश को तभी चला सकता है, जब उसकी अपनी पार्टी—कम्युनिस्ट पार्टी—के दफ्तरों से अंग्रेजी निकले। अंग्रेजी का जुआ खुद अपने बन्धो पर लादकर कम्युनिस्ट पार्टी देश को अंग्रेजी की गुलामी से आजाद नहीं करा सकती।

अब देखना चाहिए कि मजदूर वर्ग की पार्टी और उसके द्वारा संचालित जन-संगठनों में अंग्रेजी की हैसियत क्या है।

स्वर्गीय कामरेड अजय घोष ने सरकारी भाषा-आयोग की रिपोर्ट पर एक नोट लिखा था। उसमें उन्होंने अंग्रेजी की हैसियत के बारे में ये बातें लिखी थीं—

“आज अधिकांश अखिल भारतीय संगठनों का काम अंग्रेजी में होता है। इनमें किसानों और मजदूरों के संगठन भी शामिल हैं। इसका लाजमी नतीजा यह होता है कि मध्यवर्ग और उच्च मध्यवर्ग के सुशिक्षित लोग ही अखिल भारतीय स्तर पर इन संगठनों के बहस-मुवाहसे में भाग ले सकते हैं। अमल में यही लोग इन संगठनों की अखिल भारतीय कार्य-समितियों के सदस्य बन सकते हैं। जिस किसी को भी जन आन्दोलन का जरा भी तजुर्बा होगा, वह जानता होगा, इससे कितनी कठिनाई पैदा होती है।”

इससे स्पष्ट है कि अंग्रेजी के रहते न तो मजदूर संगठन शक्तिशाली हो सकते हैं, न किसान-मजदूर एकता दृढ़ की जा सकती है।

सांस्कृतिक क्षेत्र में पार्टी के वर्तमान बसलात हुए अजय घोष ने लिखा था,

“देश के सभी भागों में जनता को किसी एक भारतीय भाषा का अल्पतम आवश्यक ज्ञान कराना होगा जिससे वह भाषा जल्दी-से-जल्दी केन्द्र (यूनिफन) की भाषा बन सके और विभिन्न प्रदेशों की जनता के बीच भी परस्पर आदान-प्रदान का साधन बने। भारत की भाषाओं में जो भाषा सबसे अधिक बोली और समझी जाती है, वह हिन्दी है और इसी के द्वारा यह काम हो सकता है।”

मजदूर वर्ग और उसकी पार्टी का हित इस बात में है कि केन्द्र और प्रदेशों से अंग्रेजी को निवाला जाय। जल्दी-से-जल्दी हिन्दी को भारत सरकार की भाषा तथा पार्टी द्वारा संचालित प्रखिल भारतीय जन संगठनों की भाषा बनाया जाय।

दो वर्ग, दो उद्देश्य, दो भाषा-नीतियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। उनका भेद आसानी से देखा जा सकता है।

इस समय कम्युनिस्ट पार्टी की नीति क्या है? राज्यों से अंग्रेजी हटाओ, केन्द्र में आगे चलकर हिन्दी होगी लेकिन किलहाल वहाँ अंग्रेजी चलने दो।

मालवहादुर शास्त्रीजी और गुलजारीलाल नन्दाजी क्या कहते हैं? वे भी यही कहते हैं। हिन्दी धीरे धीरे आएगी। आएगी जरूर लेकिन अभी तो अंग्रेजी चलने दो। राज्यों में प्रादेशिक भाषाओं के व्यवहार के लिए उन्होंने संविधान बनने के समय से ही पूरी छूट दे रखी है। अब राज्य उस सुविधा का उपयोग न करे तो इसमें शास्त्रीजी और नन्दाजी का क्या दोष।

इस समय भाषा के सवाल पर कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी कोई स्वतन्त्र नीति नहीं है। यह पूँजीवादी पार्टी—काप्रेस—का पिछलगुआ बनकर चल रही है। योगीन्द्र शर्माजी जैसे कम्युनिस्ट नेता इस पिछलगुएण की नीति को पार्टी की स्वतन्त्र नीति कहकर हमस उस पर गर्व करने को कहते हैं। मुझे तो अंग्रेजी कामम रखने की इस मजदूर-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी नीति पर घमं आती है, उसमें गर्व करने की कोई बात नहीं दिखाई देती।

इसके विपरीत अपने एक लेख में मैंने यह नीति रखी है कि पार्टी को केन्द्र और राज्य दोनों से अंग्रेजी हटाने का आन्दोलन करना चाहिए।

योगीन्द्र शर्माजी का कहना है कि यह जोर-अबर्दस्ती वाला हिन्दी राष्ट्रवादी नारा है। वह कहते हैं कि भाषा की समस्या का जनैतांत्रिक समाधान होना चाहिए।

जनैतांत्रिक समाधान वही है जिसे सन् '४६ में भारत सरकार ने प्रमल में लाती रही है। यानी भविष्य में हिन्दी, वर्तमान में अंग्रेजी। योगीन्द्रजी भी कहते हैं, भविष्य में हिन्दी ही केन्द्रीय राजभाषा होगी लेकिन अभी अंग्रेजी चलने दो। वह प० जवाहरलाल नेहरू की तरह अंग्रेजी की निन्दा भी करते हैं। कहते हैं—अंग्रेजी के जरिये जो राष्ट्रीय एकता कायम की जाती है, वह अंग्रेजी के समय की औपनिवेशिक एकता से बढ़कर नहीं है। लेकिन उनका प्रमली

नारा है अंग्रेजी के जरिये अभी यह एकता कायम रहने दो ।

जैसे सन् '४७ से पहले सर तेजबहादुर सप्रू कहते थे कि अंग्रेजी राज तो खत्म होना चाहिए लेकिन राजे महाराजे नहीं मानते, अछूत और मुसलमान नहीं मानते, एंग्लोइंडियन नहीं मानते, इसलिए फिलहाल तो अंग्रेजी राज रहेगा ही—वैसे ही सन् '६५ में यह 'फिलहाल' अंग्रेजी चलाने की नीति है ।

यदि यह मान लें कि अहिन्दी भाषी जनता अंग्रेजी को नहीं छोड़ना चाहती, तो भी अंग्रेजी का कायम रहना जनतांत्रिक नहीं कहा जा सकता । यदि अंग्रेजी को हटाना अहिन्दी-भाषियों के साथ अन्याय है, तो उसे कायम रखना हिन्दी-भाषियों के साथ अन्याय है । जनतन्त्र का मतलब यह नहीं है कि अहिन्दी भाषियों की राय सी जाय और हिन्दी-भाषियों को पूछा ही न जाय ।

अहिन्दी भाषियों की राय भी किस जनतांत्रिक उपाय से मालूम की गई ? क्या बसें तोड़ना और स्टेशन जलाना लाकमत्त सग्रह का बहुत कारगर तरीका है ?

ब्रिटिश बळगम और स्वतन्त्र पार्टी के लोगो ने धुम्राधार प्रचार किया कि देश के लिए सबसे बड़ा खतरा हिन्दी में है । हिन्दी साम्राज्यवाद का होवा खड़ा करके बौशल से उन्होंने अंग्रेजी के साम्राज्यवाद की रक्षा की । लेकिन भारतीय भाषाओं को दबानेवाली भाषा हिन्दी नहीं अंग्रेजी है ।

इस सम्बन्ध में अजय घोष ने अपने उसी नोट में लिखा था "आज जब लोग कहते हैं कि इस या उस भाषा से खतरा पैदा हो गया है, तब वे भूल जाते हैं कि देश में जिस भाषा का सचमुच प्रभुत्व रहा है, वह अंग्रेजी है । यह प्रभुत्व न केवल राजनीतिक क्षेत्र में रहा है, वरन् सांस्कृतिक क्षेत्र में भी रहा है । वे भूल जाते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र में यह प्रभुत्व अब भी बना हुआ है । वे भूल जाते हैं कि भारत के सांस्कृतिक विकास में, हर भारतीय भाषा के विकास में यह प्रभुत्व ही सबसे बड़ी बाधा है और इसलिए उसे दूर करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है ।"

इससे ठीक उल्टी राय योगीन्द्र शर्माजी की है । उनकी दलील है कि अंग्रेजी की जगह हिन्दी आई तो भारतीय भाषाओं का दमन होगा । उन्होंने जोशीले ढंग से अपने लेख में पूछा है—

"क्या कोई भी सच्चा देशभक्त, सच्चा जनतन्त्र प्रेमी इसको स्वीकार कर सकता है जिस तरह अभी तक—अंग्रेजी भारत की तमाम भाषाओं का दमन और दहन करती रही, उसी तरह उस काम को अब हिन्दी करे ?"

उन्होंने यह नहीं बताया कि सविधान की किस धारा के अनुसार हिन्दी तमिलनाडु से तमिल को बाहर कर देगी ।

उनकी राय है कि अंग्रेजी की तरह हिन्दी भी तमाम भाषाओं का दमन न करे, इसलिए अंग्रेजी को ही यह दमन करने दिया जाय ।

हिन्दी से भारतीय भाषाओं को खतरा है, यह साबित करने के लिए उन्होंने

‘कम्युनिस्ट’ में प्रवासित सन् ‘४६’ वाले मेरे पुराने लेख को ढूँढ़ निवाला है। इस लेख को उन्होंने प्रतिवादी और अराजकतावादी कहा है और उसी से उन्होंने हिन्दी का खतरा भी साबित कर दिया है !

सन् ‘४८’ में कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में भारत के बड़े पूँजीपतियों को उत्पीड़क वर्ग कहा था। उस स्थापना से यही नतीजा निकलता था कि बड़े पूँजीपतियों की सरकार केन्द्रीय राजभाषा के जरिये प्रदेशों का दबाना चाहती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने यह मान्यता बदल दी है। क्या योगीन्द्र शर्माजी अभी भी समझते हैं कि सरकार बड़े पूँजीपतियों की सरकार है और ये बड़े पूँजीपति साम्राज्यवादी हैं ? यदि नहीं तो बतलाएँ कि हिन्दी के खतरे का ठोस सामाजिक आधार क्या है।

अंग्रेजी हटाने का विरोध साम्राज्यवाद के खुले और छिपे समर्थक स्वतन्त्र पार्टी और द्रविड़ कळगम के नेता करते हैं। हिन्दी द्वारा अहिन्दी भाषाओं के दमन का होना वे खड़ा करते हैं। योगीन्द्र शर्माजी भी उनमें प्रचार में शामिल हो गए हैं।

अंग्रेजी कायम रखने के लिए एक विचित्र ढंग से विशाल राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा बन गया है। इस मोर्चे में स्वतन्त्र दल के नेता हैं, द्रविड़ कळगम वाले हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक नेता भी इसमें हैं। लेकिन यह मोर्चा बना है बालू की भीत पर। उससे पीछे भारत के किसानों और मजदूरों की ताकत नहीं है। वह ज्यादातर बाबू लोगों का संयुक्त मोर्चा है। इनमें कुछ तो अंग्रेजी पढ़े हैं और बाकी बिना पढ़े ही उसका समर्थन करते हैं। खास बात यह है कि कम्युनिस्ट पार्टी की दोनों शाखाएँ इस संयुक्त मोर्चे में शामिल हैं।

अहिन्दी-भाषी क्षेत्र के बाबूओं का डर है कि अंग्रेजी चली गई तो अखिल भारतीय नौकरियाँ हिन्दीवाले हथिया लेंगे। अखिल भारतीय नौकरियों की समस्या पूरे मध्यवर्ग की समस्या नहीं है। कुछ थोड़े-से तेज लोग—जो हर मानी में तेज होते हैं—ये नौकरियाँ पाते हैं। बाकी उम्मीदवार नाउम्मीद होकर कहीं मास्टरी या क्लर्क करते हैं या बेकारी में अण्डले चटवाते हुए घूमते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी अपनी भाषा नीति इन मुट्ठी-भर पढ़े-लिखे बाबूओं की राय से निर्धारित नहीं करती। उसके सामने होना चाहिए किसानों और मजदूरों का हित।

वास्तव में मध्यवर्ग का हित भी अंग्रेजी कायम रखने में नहीं है। निम्नान्वे की सदी अंग्रेजी-पढ़े बाबूओं को छोटी मोटी नौकरियों से ही संतोष करना पड़ता है। लाखों की तादाद में वे हर साल अंग्रेजी के कारण फेल होते हैं। अंग्रेजी के कारण शिक्षा उनके लिए हर तरह से महँगी पड़ती है। अखिल भारतीय नौकरियों के लिए अंग्रेजी आवश्यक है, इसलिए राज्यों में भी अंग्रेजी चलती है। फल भुगतना पड़ता है तमाम निम्न मध्यवर्ग की गरीब जनता को।

जब तक केन्द्र में अंग्रेजी चलती है, तब तक राज्यों से अंग्रेजी की जड़ नहीं कट सकती। राज्यों में अंग्रेजी की पत्तियाँ मोचने से उसकी केन्द्रीय जड़ पर कोई असर न पड़ेगा। पिछले सोलह साल का अनुभव यही सिद्ध करता है। केन्द्र के कारण ही राज्यों में अंग्रेजी का प्रभुत्व है। इससे तमिलनाडु में अभी तक तमिल उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बन पाई।

जो लोग अखिल भारतीय नौकरियों के उम्मीदवार हैं, उनका भय आसानी से दूर किया जा सकता है। यह नियम बनाना चाहिए कि अखिल भारतीय नौकरियों के लिए एक अहिन्दी भाषा सीखना अनिवार्य होगा। अहिन्दी भाषा का समुचित ज्ञान अनिवार्य कर देने से हिन्दीवालों को कोई विशेष सुविधा न मिलेगी। पार्टी इस नियम के लिए और अंग्रेजी हटाने के लिए एक साथ आन्दोलन कर सकती है। लेकिन नौकरियों की समस्या हल न कर पाने के कारण केन्द्र में अंग्रेजी कायम रखने की बात करना मार्क्सवाद को ठुकराकर मध्यवर्ग के बाबुओं का दृष्टिकोण अपनाता है।

अंग्रेजी कायम रखने में भारत के किसी वर्ग का हित नहीं है—न मजदूर वर्ग का, न किसानों का, न शहरों के मध्यवर्ग का। अंग्रेजी से न अहिन्दी प्रदेश का हित होता है, न हिन्दी प्रदेश का। उससे केवल साम्राज्यवादियों का हित होता है। ब्रिटिश और अमरीकी पूंजीपति हमारे अर्थतन्त्र पर हर तरह से प्रभाव डालते हैं। उनके आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को रद्द करने का साधन है—अंग्रेजी का प्रभुत्व। वे करोड़ों रुपये तब तक हर तरह से यहाँ अंग्रेजी के प्रचार और प्रसार पर खर्च करते हैं। अंग्रेजी को कायम रखना 'जनतन्त्र' के नाम पर साम्राज्यवाद की सेवा करना है।

अंग्रेजी हटाने का सवाल राष्ट्रीय एकता के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है। भारत बहुजातीय राष्ट्र है। भारतीय भाषाएँ बोलनेवाली विभिन्न जातियाँ ब्रिटेन और फ्रांस की तरह एक-दूसरे से अलग स्वतन्त्र जातियाँ नहीं हैं। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक सूत्रों से बंधी हुई वे एक ही राष्ट्र का अविभाज्य अंग हैं। जिस तरह हर प्रदेश में उसकी अपनी भाषा को सभी अधिकार मिलने चाहिए, वैसे ही इन सबको जोड़नेवाली राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी केन्द्र में पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए।

जो लोग अंग्रेजी हटाने का विरोध करते हैं, वे राष्ट्रीय एकता का विरोध करते हैं। विभिन्न प्रदेशों की जनता एक-दूसरे के नजदीक हिन्दी के जरिये ही आ सकती है। अंग्रेजी के जरिये पढ़-लिखा बाबूवर्ग दिन-पर-दिन साधारण जनता से दूर होता जा रहा है।

पिछले पन्द्रह साल में अंग्रेजियत बढ़ी है और उसके साथ भारतीय भाषाओं की उपेक्षा आम तौर से, और हिन्दी की उपेक्षा खास तौर से, बढ़ी है। यह उपेक्षा हिन्दी और अहिन्दी दोनों क्षेत्रों में है। डेंडी, मम्मी और अकलजी का चलन हिन्दी बाबुओं के घर में पिछले वर्षों ज़्यादा हुआ है। अमरीकी-

साहित्य के नक्कालों की हिन्दी में अंग्रेजी के अपभ्रंश शब्दों की बाढ़ आ गई है।

हिन्दी की उपेक्षा कांग्रेस में ही नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी में भी है—हमारे इस कटु सत्य का सामना करना चाहिए। आज में इक्तीस साल पहले प्रेमचन्द ने हमारे नेताओं के अंग्रेजी-प्रेम की अगली तरह परखा था और उसकी तीखी आलोचना की थी। बम्बई के राष्ट्रभाषा-सम्मेलन में उन्होंने कहा था—

“हमारी कौमी सभाओं में सारी कार्रवाई अंग्रेजी में होती है, अंग्रेजी में भाषण दिये जाते हैं, लेख लिखे जाते हैं, प्रस्ताव पेश किये जाते हैं, सारी लिखा-पढ़ी अंग्रेजी में होती है, उस संस्था में भी, जो अपने को जनता की संस्था कहती है। यहाँ तक कि सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट भी, जो जनता के खामुलखास फूँडे-बरदार हैं, सभी कार्रवाई अंग्रेजी में करते हैं।”

प्रेमचन्द की आलोचना का कोई असर कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर नहीं हुआ। वे जहाँ सन् '३४ में थे, वहीं सन् '६५ में हैं। इस स्थिति पर कौन गव्वे कर सकता है ?

प्रेमचन्द ने बहुत सही सवाल उठाया था कि पार्टियाँ अपनी कार्रवाई किस भाषा में करती हैं। यही सवाल अपने एक लेख में मैंने भी उठाया था।

मेरा अनुभव है कि राज्यों में कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता अपने मसौदे अंग्रेजी में तैयार करते हैं। अक्सर राज्यों के पत्रों में उनके अंग्रेजी लेखों के अनुवाद छपते हैं। योगीन्द्र शर्माजी का कहना है कि राज्यों में पार्टी का सारा काम प्रादेशिक भाषाओं में होता है। उसका स्वागत करता हूँ। पार्टी के नेताओं को बधाई देता हूँ कि कम-से-कम राज्यों में उन्होंने पहल की और दूसरी पार्टियों के सामने एक आदर्श रखा।

लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी अपने केन्द्रीय दफ्तर से अंग्रेजी क्यों नहीं निकाल पाती ? इसका मूल कारण है, स्वयं पार्टी के नेताओं में हिन्दी के प्रति उपेक्षा का भाव।

यदि अखिल भारतीय स्तर पर मजदूर वर्ग की एकता हिन्दी के जरिये ही कायम हो सकती है, तो हिन्दी की यह उपेक्षा मजदूर वर्ग की ही उपेक्षा है।

बामरेड गोपालन लोकसभा से बाहर चले गए क्योंकि कोई मन्त्री हिन्दी में बोला था। उनका मजदूर-प्रेम हिन्दी से चिढ़ता है, अंग्रेजी की सिर चढ़ाता है। बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी की दोनों शाखाओं ने विधान सभा में कांग्रेस के साथ मिलकर हिन्दी के विरुद्ध प्रस्ताव पास किया, केन्द्र में अंग्रेजी उन्हें सप्रेम स्वीकार है !

पार्टी के नेता जो सिर्फ राज्यों से अंग्रेजी हटाने की बात करते हैं, इसका नाराण हिन्दी के प्रति यही उपेक्षा-भाव है। मराठी, बंगला, तमिल के चलन की बात तो वे कर सकते हैं, हिन्दी के चलन की बात कैसे करें ?

कहा जा सकता है कि हिन्दीभाषी क्षेत्र में कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर है, इसलिए पार्टी-केन्द्र में हिन्दी का चलन नहीं है।



लेकिन भारत का वह अंग्रेजी भाषी क्षेत्र कौन सा है जहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन मजबूत होने से पार्टी केन्द्र में अंग्रेजी चलती है ? वह अंग्रेजी-भाषी क्षेत्र ऊपर के कुछ नेताओं तक सीमित है । भारत की घरती से उखड़ा हुआ यह क्षेत्र त्रिशकु की तरह आसमान में लटका हुआ है । इस हवाई क्षेत्र की भाषा—अंग्रेजी—पार्टी केन्द्र में चल सकती है । भारत की एक तिहाई जनता की भाषा हिन्दी नहीं चल सकती ।

कम्युनिस्ट पार्टी के वोटरो में जो पिछतर की सदी अहिन्दी भाषी हैं, उनमें अंग्रेजी जाननेवाले एक की सदी भी नहीं हैं । फिर भी पार्टी केन्द्र में चलेगी अंग्रेजी ।

हमारे आन्दोलन के विकास और फैलाव की वह कौन-सी विशेषता है जिससे अंग्रेजी भाषी न होते हुए भी हमारे नेता बंदरिया के मुँह बच्चे की तरह अंग्रेजी को छाती से चिपकाये हुए हैं ? वह विशेष अवस्था है, हिन्दी की उपेक्षा ।

इस स्थिति से लाभ उठाते हैं जनसंघ के नेता । वे जनता की सही माँगों का समर्थन करके अपनी जन-विरोधी नीति के लिए लोकप्रियता हासिल करते हैं । उनका उद्देश्य होता है, पूँजीवाद को मजबूत करना, तटस्थता की नीति खत्म करके भारत को साम्राज्यवादी खेमे में ढकेल देना ।

केन्द्र में अंग्रेजी कायम रखना समस्त भारतीय जनता के साथ अन्याय है, हिन्दी भाषी जनता के साथ विशेष अन्याय है । अंग्रेजी चालू रखने की नीति का समर्थन करके कम्युनिस्ट पार्टी हिन्दी-भाषी जनता में अपना प्रभाव बढ़ाएगी, कम्युनिस्ट आन्दोलन को आवश्यकतानुसार शक्तिशाली नहीं बना सकती ।

पिछले वर्षों का अनुभव बतलाता है कि जनता के असन्तोष से लाभ उठाकर प्रतिक्रियावादी दलों ने अपनी ताकत जितना बढ़ाई है, उतना कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं । तब कम्युनिस्ट पार्टी संयुक्त थी, अब विभक्त है । सोच लीजिए, क्या नतीजा होगा ।

अंग्रेजी के विरुद्ध हिन्दी जनता के असन्तोष को दक्षिण और बंगाल की ओर मोड़ना बहुत आसान है । जैसे कुछ लोग तमिल-प्रेम को हिन्दी विरोध का रूप देते हैं, वैसे ही हिन्दी प्रेम को तमिल विरोध का रूप देना मुश्किल नहीं है । गृहयुद्ध की इस परिस्थिति में अंग्रेजी के बल पर राष्ट्रीय एकता की रक्षा नहीं की जा सकती ।

समस्या का एक ही हल है केन्द्र में हिन्दी हो, राज्यों में प्रादेशिक भाषाएँ ।

इस पर भी यदि कोई कहे कि अंग्रेजी हटाने से अहिन्दी भाषाओं का दमन होता है तो निवेदन है, लोकसभा में सभी भाषाएँ चलाईएँ । हमें इस बात का मोह नहीं है कि भारत सरकार का काम हिन्दी में हो । घृणा इस बात से है कि उसका काम अंग्रेजी में होता है । केन्द्र में चाहे एक भारतीय भाषा चलाईएँ, चाहे दस, विदेशी भाषा अंग्रेजी को निकालिए ।

मैंने योगीन्द्र शर्माजी से पूछा था, 'पार्टी दफ्तर में सभी भारतीय भाषाओं

का चलन करने में क्या व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं ?”

उन्होंने उत्तर दिया है, “पार्टी के केन्द्रीय दफ्तर में अंग्रेजी की जगह सभी भारतीय भाषाओं को बराबर जगह देने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ अवश्य हैं। व्यावहारिक कठिनाइयों में मुख्य कठिनाई है बहुभाषी स्टाफ कायम करने की—तमाम भारतीय भाषाओं से अनुवाद करने की व्यवस्था की।”

पार्टी-केन्द्र में हिन्दी इसलिए नहीं चलती कि हिन्दीप्रदेश में कम्युनिस्ट भ्रान्दोलन बमजोर है। अनेक भारतीय भाषाएँ इसलिए नहीं चल सकती कि उपयुक्त स्टाफ नहीं है। इसलिए अंग्रेजी की गुलामी से पार्टी-केन्द्र मुक्त नहीं हो सकता।

योगीन्द्रजी ने मुझे आश्वासन दिया है कि लोगों को तमाम भाषाओं में बोलने की आजादी है। केन्द्रीय दफ्तर में तमाम भाषाओं में चिट्ठियाँ, रिपोर्टें आदि आती हैं। भविष्य में पार्टी केन्द्र की भाषा हिन्दी ही होगी लेकिन जहाँ तक वर्तमान का सम्बन्ध है, उन्हीं के शब्दों में—“तमाम भारतीय भाषाओं की इस आजादी और बराबरी के बावजूद ‘फिलहाल’ अंग्रेजी प्रधान और सम्पर्क-भाषा है।”

असली समस्या इसी ‘फिलहाल’ की है।

पार्टी के जो नेता अपने केन्द्र से अंग्रेजी निकालने में असमर्थ हैं, वे भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व कभी खत्म नहीं कर सकते।

हिन्दी-भाषी जनता से भड़कानेवाले कहते हैं, यह उत्तर और दक्षिण की लड़ाई है। दक्षिणवाले हिन्दी नहीं चाहते तो उन्हें उत्तर भारत से निकाल दो।

इस गृहयुद्ध की नीति के खिलाफ ‘धर्मयुग’ के अपने लेखों में मैंने हिन्दी-भाषी जनता के सामने यह कार्यक्रम रखा है लड़ाई तमिल हिन्दी की नहीं है, लड़ाई तमाम भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी की है। इस संघर्ष में हम हिन्दी-भाषियों को पहल करनी चाहिए। हम अपने हिन्दी भाषी राज्यों में हर जगह, हर स्तर पर हिन्दी को प्रमत्त में राजभाषा बनाना चाहिए। हमें अपने नेताओं को बाध्य करना चाहिए कि वे लोकसभा में हिन्दी में बोलें। भारत की एक-तिहाई जनता के प्रतिनिधि केन्द्र और राज्यों में अपना सारा काम हिन्दी में करेंगे तो हिन्दी बहुत जल्दी राष्ट्रभाषा बन जाएगी।

इस कार्यक्रम के विपरीत हिन्दीभाषी जनता से कहना कि केन्द्र में अंग्रेजी कायम रहने दो, उसे तमिल-विरोध की ओर बढ़ने की राह देना है। कांग्रेस सरकार की भाषा-नीति से क्षुब्ध हिन्दी-भाषी जनता के सामने जब अंग्रेजी से लड़ने की नीति न रहेगी, तब वह अहिन्दी-भाषियों के खिलाफ जरूर भड़काई जाएगी।

मैं हिन्दी क्षेत्र के नेताओं से भी लोकसभा में हिन्दी बोलने को कहता हूँ तो योगीन्द्र शर्माजी को लगता है कि मैं अहिन्दी भाषियों पर हिन्दी लादने की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजी को हटाने की सलाहकार उन्हें गृहयुद्ध की सलाहकार

मालूम होती है ।

लोकसभा में अहिन्दी-भाषी नेता शौक से अपनी अपनी भाषाएँ बोल । हिन्दी-भाषी नेता हिन्दी में बोलें । कम्युनिस्ट सदस्य लोकसभा में अपने व्यवहार से इस नीति की मिसाल कायम करें ।

लेकिन हमारे पार्टी-नेता अंग्रेजी में बोलना पसन्द करते हैं । लोकसभा में सभी भारतीय भाषाओं में बोलने की सुविधा के लिए नहीं लड़ते । लड़ें कैसे जब उनके अपने केन्द्र में अंग्रेजी चलती है ।

साम्राज्यवादी प्रचारक कहते थे कि भारतीय भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं, इसलिए अंग्रेजी चलेगी । इस प्रचार का नया रूप यह है हिन्दी जनता से दूर चली गई है, पड़िताऊ हो गई है, रघुवीरी है, इसलिए अंग्रेजी चलेगी ।

यदि मान भी लें कि डॉ० रघुवीर इतने बड़े सूरमा थे कि भारतेन्दु से लेकर अमृतलाल नागर तक चली आती हिन्दी की प्रशस्त धारा को मोड़कर उन्होंने उसे पड़िताऊ बना दिया तो क्या इससे अंग्रेजी का कायम रहना उचित हो जाएगा ?

मजे की बात यह है कि राज्यों में हिन्दी चल सकती है । कठिनाई पैदा होती है, उसके दिल्लीवाले दफ्तरों में घुसने पर ।

साम्राज्यवादी प्रचारक हिन्दी-उर्दू को लड़ाकर अंग्रेजी का पाया मजबूत करते थे । उस नीति का नया रूप यह है हिन्दी ने अपनी बहन और सहेली उर्दू का दमन किया है, उसे अपने ही घर से निकाल दिया है । इसलिए केन्द्र में अंग्रेजी चलनी चाहिए ।

'जनशक्ति' और 'जनयुग' के उर्दू-संस्करण निकालिए । इच्छा हो तो दोनों में एक ही भाषा 'हिन्दुस्तानी' चलाइए । पटना और लखनऊ के पार्टी-दफ्तरों में हिन्दी-उर्दू दोनों को बराबर जगह दीजिए । लेकिन उर्दू-दमन के विरोध के नाम पर अंग्रेजी चलाने की कोशिश मत कीजिए ।

केन्द्र और राज्यों से एक साथ अंग्रेजी हटाने की माँग करना उग्र हिन्दी राष्ट्रवाद के उन्माद में आत्मविभोर होना नहीं है । उग्र हिन्दी राष्ट्रवाद का नारा है एक भाषा, एक राष्ट्र । मेरी नीति इससे बिल्कुल उल्टी है । उस नीति का मूल सूत्र यह है भारत बहुजातीय राष्ट्र है । बहुजातीय है, इसलिए राज्यों में वहाँ की भाषाएँ राजभाषा होंगी, राष्ट्र है, इसलिए सब जातियों को मिलानेवाली केन्द्रीय भाषा हिन्दी होगी । इन दोनों बातों में किसी एक को भूल जाना राष्ट्रीय विघटन को बुलावा देना होगा । (१९६५)

## भारत की राजभाषा अंग्रेजी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा

योगीन्द्र शर्माजी ने ठीक लिखा है कि सिद्धान्त और नीति की जो बातें मैंने उठाई हैं, उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती और वे बातें अपने-आप में भी महत्वपूर्ण हैं। इस विषय पर मैं जो कुछ आगे लिख रहा हूँ, पाठक उसे नीति और सिद्धान्त का आवश्यक विवेचन समझकर पढ़ेंगे।

### अंग्रेजी के प्रभुत्व से हानियाँ

योगीन्द्र शर्माजी मानते हैं कि अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रहने में हानि होती है। इस हानि से देश को कितने बड़े सकट का सामना करना पड़ सकता है, मजदूर वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टी से इस हानि का सम्बन्ध क्या है, इस बारे में उनका और मेरा विस्तरेण एक-सा नहीं है।

उनका कहना है, “अंग्रेजी के आधार पर भारत की एकता बँसी ही होगी जैसी अंग्रेजी सामन के मातहत थी।”

इतना कहना काफी नहीं है। अंग्रेजी के आधार पर आज भारतीय पूँजीवाद औपनिवेशिक एकता भी कायम नहीं रख सकता।

साम्राज्यवाद फौज, पुलिस और अंग्रेजी जाननेवाले नौकरशाह वर्ग के द्वारा जनता का शोषण करने के लिए उपनिवेश भारत की एकता कायम किये हुए था। अब नौकरशाह वर्ग का मानिक है भारतीय पूँजीवाद जिसमें बाजारों के लिए सटनेवाले विभिन्न प्रदेशों के पूँजीपति हैं तथा इनमें कुछ इजारेदार हैं, शेष गैर-इजारेदार पूँजीपति हैं। इन अन्तर्विरोधों से पीड़ित पूँजीवाद औपनिवेशिक एकता की रक्षा नहीं कर पा रहा है। उसकी प्रतिल भारतीय पार्टी में भयानक गुटबन्दी है और उसका सामाजिक आधार दिन-पर-दिन सकुचित होता जा रहा है।

योगीन्द्र शर्माजी जानते हैं कि भारत का पूँजीपति वर्ग “विभिन्न भाषा-समूहों में बँटा हुआ है, विभिन्न जातियों में विभक्त है। यह एक-दूसरे की नीमत पर अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता है।” इसीलिए वह अंग्रेजी के सहारे

देश की पुरानी औपनिवेशिक एकता को भी बचा नहीं पा रहा ।

देश की एकता पूँजीपति वर्ग के हित में है । योगीन्द्रजी का कहना है, "पूरे देश के बाज़ार और राजशक्ति की आवश्यकता उनको राष्ट्रीय एकता का हिमायती बनाती है ।" भारतीय इतिहास के अनुभव को सभी लोग जानते हैं कि यहाँ के पूँजीपति वर्ग ने साम्राज्यवादी योजना स्वीकार की और 'पूरे देश के बाज़ार' को अपने वर्ग-हितो के विरुद्ध, बँट जाने दिया ।

देश की एकता की रक्षा के लिए पूँजीपति वर्ग की एकता का भरोसा न करके श्रमिक जनता की एकता दृढ़ करनी चाहिए । यह एकता अंग्रेज़ी के ज़रिये दृढ़ नहीं की जा सकती । अंग्रेज़ी का प्रभुत्व इस एकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है । अंग्रेज़ी के बापम रहने से भारतीय जनतंत्र का आधार सङ्कुचित होता है और फासिस्टवाद का खतरा बढ़ता है ।

'भाषा और समाज' में मैंने लिखा था •

"एक छोटा सा वर्ग जो अंग्रेज़ी भ्रष्टाचार पढ़ता है, अंग्रेज़ी के माध्यम से नौकरी पाता है अंग्रेज़ी के माध्यम से पार्लामेन्टरी डिमोक्रेसी और सोशलिस्ट पैटर्न के प्रयोग करता है वही 'नेहरू के बाद क्या होगा'—यह समस्या उठाकर परेशान भी हो लेता है" जनतन्त्र का यह सङ्कुचित वर्ग-आधार खुद तो नष्ट होगा ही, खतरा यह है कि अपने विनाश के साथ वह देश की बागडोर किसी अग्र्युब खाँ को न सौंप दे ।" (पृ० ४१५)

इस देश में हर चीज़ के लिए आन्दोलन होते हैं । भाषावार राज्यों के आन्दोलन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी । केवल केन्द्र से अंग्रेज़ी हटाने का आन्दोलन नहीं होता, केवल इस तरह का आन्दोलन पार्टी के नेताओं को पसन्द नहीं है । इसका कारण यह है कि संयुक्त महाराष्ट्र या विशाल आन्ध्र के निर्माण को वे जितना आवश्यक समझते थे, उतना अंग्रेज़ी के प्रभुत्व को खत्म करना नहीं ।

मैंने लिखा था, "अंग्रेज़ी सीखना और बात है, उसे सीखकर लाभ उठाया जा सकता है लेकिन उसे सभी भारतीय भाषाओं के ऊपर केन्द्रीय और सांस्कृतिक भाषा बनाने से ऐसे वर्ग का ही सृजन होगा जो जनता से दूर होगा, जो अंग्रेज़ी ज्ञान के बल पर—न कि ईमानदारी, देशभक्ति, कार्यक्षमता के बल पर—शासनकार्य चलाएगा । इससे देश की अपार क्षति होगी और हो रही है ।" (उप०, पृ० ४५३)

स्पष्ट है, अंग्रेज़ी से होनेवाली हानि के बारे में योगीन्द्रजी के और मेरे विचारों में अन्तर है ।

## कांग्रेस और अंग्रेज़ी

दश में जो भाषा-सम्बन्धी द्वेषभाव फैला है, उसके लिए सबसे पहले कांग्रेसी नेता जिम्मेदार हैं । उन्होंने भाषावार राज्यों का विरोध किया और अपने वक्ताओं

मे प्रादेशिक भाषाओं को उचित महत्त्व नहीं दिया—यह स्थिति का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि सन् '४६ से अब तक तरह-तरह के बहाने करके वे अंग्रेजी का प्रमुख कायम बिये हुए हैं। इस दूसरे पहलू पर योगीन्द्रजी का ध्यान कम जाता है।

मुख्य अन्तर्विरोध हिन्दी और अहिन्दी भाषाओं में नहीं, अंग्रेजी तथा समस्त भारतीय भाषाओं में है। कांग्रेसी नेताओं ने जहाँ भी केन्द्र में हिन्दी चलाने की बात की, योगीन्द्रजी उनकी सख्त भालोचना करते हैं। वे अठारह साल से अंग्रेजी चला रहे हैं, इसकी मस्त भालोचना वह नहीं करते।

उन्होंने लिखा है, “केन्द्रीय सरकार ने २६ जनवरी से हिन्दी को ‘राष्ट्रभाषा’ बनाने की जो पाखण्ड और उकसावे की घोषणा की, उससे गैर-हिन्दीभाषी लोगों में, विशेषकर तमिलनाडु में विरोध का तूफान पैदा हो गया।”

कांग्रेस के वर्णधार चाहते हैं कि अंग्रेजी न भाज हटे, न कल। हिन्दी-भाषी जनता से ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं। उसे खुश करने के लिए वे राष्ट्रभाषा की बातें करते हैं, हिन्दी को समृद्ध करने के लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं। उनके इस पाखंड पर योगीन्द्रजी को विशेष क्रोध नहीं आता।

योगीन्द्र शर्माजी के विपरीत हर मजिल पर मैंने कांग्रेसी नेताओं के इस पाखण्ड की बराबर भालोचना की है।

सन् '४६ में मैंने लिखा था -

“भारतीय जनता न माँग की थी कि शिक्षा, अदालत-कचहरी शासन इत्यादि में अंग्रेजी की जगह उसकी अपनी भाषा चल। यह बिल्कुल न्यायपूर्ण माँग थी। राष्ट्रीय नेताओं से आशा की जाती थी कि सन् '४७ में आजादी पाने के बाद इस माँग को वे पूरा करेंगे। लेकिन विभिन्न कारणों में वे उसे पूरा नहीं कर सके—दस साल तक उद्योग-धन्यो का राष्ट्रीयकरण न होगा। वैसे ही पाँच या दस साल तक ग्राम जनता की उच्च शिक्षा, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यवाही उसकी अपनी भाषा में न होगी” (‘कम्प्युनिस्ट’)

पाँच साल बाद राजभाषा के सवाल पर मैंने एक पुस्तिका लिखी जो पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस द्वारा प्रकाशित हुई। उसमें कांग्रेसी नेताओं की दुरगति नीति के बारे में मैंने लिखा था, ‘कांग्रेसी नेताओं की कोई मशा नहीं थी कि अंग्रेजी हटाने के लिए जमकर कोशिश करें। उन्होंने स्पष्ट ही अपने सामने यह सभावना रखी थी कि पन्द्रह साल के बाद भी अंग्रेजी जारी रहेगी, शायद उसके अगले पन्द्रह साल तक जारी रहेगी, हो सकता है इसके आगे भी जारी रहे।”

सन् '६५ में बिल्कुल यही स्थिति हमारे सामने है।

नेहरूजी के अंग्रेजी समर्थन की चर्चा करते हुए उसी पुस्तिका में लिखा था, “सविधान सभा में बहुमती तमाम सरगर्मों के पीछे यह निर्णय निश्चय साफ दिखाई देता है कि समस्त भारतीय भाषाओं की हानि करते हुए अंग्रेजी को अनिवार्य राजभाषा के रूप में चालू रखा जाय। श्री नेहरू ने बड़ी स्पष्टता से

कहा है कि 'भाषा इस बात को प्रस्ताव में लिखें, चाहे न लिखें, अंग्रेजी लाजमी तौर से भारत में बहुत महत्वपूर्ण भाषा बनकर रहेगी जिसे बहुत लोग सीखेंगे और शायद उन्हें उसे जबरन सीखना होगा।' लोग इन तमाम वपों में अंग्रेजी जबरन सीखते आए हैं। अब उनके सामने एकमात्र यह सभावना पेश की गई है कि अंग्रेजी के बिना हमारी कला और विज्ञान का पतन हो जाएगा और देश का विघटन होगा, उसका नाश हो जाएगा।"

'भाषा और समाज' में मैंने जहाँ भाषावार राज्य घान्दोलन के दमन की निन्दा की है, वहाँ अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाये रखने की कांग्रेसी नीति की प्रालोचना भी की है। लिखा था :

"अंग्रेजी भारत की राष्ट्रभाषा रहे तो सबसे अच्छा। दूसरे देशों के सामने शर्म के मारे उसे राष्ट्रभाषा न बहू सकें और भूल मारकर हिन्दी का व्यवहार करना पड़े तो अंग्रेजी और हिन्दी दोनों को राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। यदि हिन्दी को ही राष्ट्रभाषा रखने की प्रतिज्ञा करनी पड़े तो भी जहाँ तक हो सके, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यों के लिए अंग्रेजी का व्यवहार होना ही चाहिए" भारत को आजाद करने की मुख्य प्रेरणा अंग्रेजी से ही मिली लेकिन आजादी पाने के लिए भी अंग्रेजी की उतनी आवश्यकता न थी जितनी अब समाजवादी भारत के निर्माण के लिए है।" (पृ० ४१३)

पिछले अठारह साल में कांग्रेस की जो नीति रही है, उसी का अनुसरण करते हुए उसने नेताओं ने नया प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रादेशिक भाषाएँ पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं का ऐच्छिक माध्यम बनेंगी, अखिल भारतीय नौकरियों का अनिवार्य माध्यम रहेगी अंग्रेजी।

गांधीजी भाषाओं के आधार पर प्रान्तों के नवनिर्माण के पक्ष में थे। नेहरूजी भाषावार राज्य बनाने के प्रबल विरोधी थे। गांधीजी केन्द्र से अंग्रेजी हटाने के पक्ष में थे, नेहरूजी उसे वहाँ जमाये रखने के पक्ष में थे। केन्द्र और राज्य—दोनों जगह गांधीजी और नेहरूजी की भाषा-नीति में अन्तर था। नेहरूजी ने देश के लिए बहुत से अच्छे काम किए लेकिन उनकी अंग्रेजी कायम रखने की नीति गलत थी। देश में अंग्रेजी कायम रखने के लिए जिम्मेदार है कांग्रेस।

## भाषागत द्वेष और गृहयुद्ध की सम्भावना

ज़ारशाही रूस में रूसी पूँजीवाद ने साम्राज्यवाद का रूप ले लिया था। रूसी पूँजीपति गैर-रूसी इलाकों का शोषण करते थे, वहाँ की भाषाओं का दमन करते थे। सन् '४८ में कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में भारत को भी ज़ारशाही रूस की तरह जातियों का कारागार मान लिया था। इसीलिए उत्पीड़क पूँजीवादी गुट के विरुद्ध केरल, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों के लिए आत्मनिर्णय की माँग की गई थी।

प्रस्ताव में कहा गया था, 'कांग्रेसी नेतृत्व ने अपनी समझौतावादी नीति

के कारण आत्मनिर्णय के अधिकार का विरोध करने की वजह से देश का धार्तक विभाजन करा दिया है। आज इण्डियन यूनियन में वह फिर वही अपराध कर रहा है, उत्पीडक पूँजीपति वर्ग के हित में वह महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु आदि जातीय प्रदेशों के आत्मनिर्णय का अधिकार अस्वीकार करता है।"

भारतीय परिस्थितियों में आत्मनिर्णय की यह बात गलत थी और आज भी है। आत्मनिर्णय की माँग की जाती है साम्राज्यवाद के खिलाफ, उन प्रदेशों के लिए जहाँ विदेशी पूँजीपतियों ने अपने उपनिवेश कायम किये हो।

भारत में अहिन्दी भाषाओं के दमन की आशंका कुछ लोगों के मन में है, लेकिन दमन का कोई ठोस सामाजिक आधार नहीं है। यदि हिन्दीभाषी क्षेत्र का पूँजीवाद साम्राज्यवाद का रूप ले रहा हो, यदि किसी एक प्रदेश के पूँजीपतियों ने अन्य प्रदेशों को अपना उपनिवेश बनाना आरम्भ कर दिया हो तो मानना होगा कि अहिन्दी भाषाओं के दमन का वास्तविक खतरा है। ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए शक शुबहे की बात की जा सकती है, भाषाओं के दमन की बात करना जनता में हिन्दी के प्रति द्वेष फैलाना है।

योगीन्द्रजी ने शक-शुबहे और वास्तविक खतरे को मिलाकर एक कर दिया है। उन्होंने आरशाही रूस और भारत के पूँजीवाद का फर्क नहीं देखा। वह अहिन्दी भाषाओं के दमन की बात इस तरह करते हैं मानो दिल्ली सरकार केवल हिन्दी क्षेत्र के पूँजीपतियों की सरकार हो। उन्होंने पूछा है, "१९४६ में दक्षिण भारत की जनता हिन्दी को एक दबानेवाली भाषा के रूप में देखती थी या नहीं?" इसका उत्तर है कि कुछ लोग दक्षिण में हिन्दी को दबानेवाली भाषा के रूप में देखते थे। यह उनकी आशंका थी। उस आशंका के कारण थे। लेकिन हिन्दी दबानेवाली भाषा न तब थी, न आज है। दबानेवाली भाषा वास्तव में अंग्रेजी थी, आज भी है।

योगीन्द्रजी ने पूछा है कि पार्टी ने अपनी गलत नीति सुधार ली, तब सन् '६१ में मैंने वही गलत बात क्यों दुहराई।

उन्हे भ्रम है कि सन् '६१ में मैंने सन् '४६ की बातें दुहराई है। सन् '४६ में मैंने केन्द्रीय राजभाषा का विरोध किया था, सन् '६१ में उसका समर्थन किया था। सन् '४६ में जातीय उत्पीड़न का वास्तविक खतरा है, मैं यह मानता था। सन् '६१ में शक-शुबहे की बात थी, भाषाओं के वास्तविक दमन की बात नहीं थी। इन शक-शुबहे का सम्बन्ध मुख्यतः नौकरीपेशा मध्यवर्ग के लोगों से है। इनके बारे में 'भाषा और समाज' में मैंने लिखा था

'देश के विभिन्न वर्गों का जैसा सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, उसी के अनुकूल वे भाषा समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। इनमें सबसे पहले 'चहू वर्ग' है जो साम्राज्यवादी व्यवस्था में शिक्षा के कारण ऊँची नौकरियाँ पा सका था और अब स्वाधीन भारत में वह उसी शिक्षा के आधार पर अपने लिए उन नौकरियों को बरकरार रखना चाहता है। इनमें विभिन्न प्रदेशों के उच्च मध्य-



वर्गीय शिक्षित लोग हैं जो समझते हैं कि अंग्रेजी के न रहने से हिन्दीवाले बाजी मार ले जाएंगे। इनकी तो मातृभाषा हिन्दी है, दूसरों को उसी की सीखना पड़ेगा। इस तरह के तर्क साम्राज्यवादी अवशेषों को जाहिर करते हैं।”

(पृ० ४४३)

इस भय को दूर करने का उपाय मैंने यह बताया था ‘ऊँची नौकरियों के लिए हिन्दी-भाषियों को तभी लेना चाहिए जब उन्हें एक अहिन्दी भाषा का अच्छा ज्ञान हो।”

(पृ० ४५७)

‘जनशक्ति’ में यही प्रस्ताव मैंने दोहराया था, “अहिन्द भाषा का समुचित ज्ञान अनिवार्य कर देने से हिन्दीवालों को कोई विशेष सुविधा न मिलेगी।”

जो लोग सचमुच अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म करना चाहते हैं, वे इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार करेंगे। जो हठ धर्मी से केन्द्र में अंग्रेजी चालते रहने के पक्ष में हैं, वे उसके बारे में चुप रहेंगे।

तमिलनाडु में जो आन्दोलन चला उसमें शक-शुबहो से लाभ उठाया गया, तिल का ताड़ बनाकर जनता को गुमराह किया गया। आन्दोलन के सूत्रधार वे थे जो द्रविड भारत या तमिलनाडु का अलगाव चाहते हैं, जो कश्मीर से लेकर नागालैंड तक अलगाव के हर आन्दोलन का साथ देते हैं।

भारत में गृहयुद्ध का खतरा पैदा होता है उन लोगों से जो देश के नये विभाजन के लिए प्रयत्नशील हैं। भाषाओं के दमन की बात वे अपना असली उद्देश्य छिपाने के लिए करते हैं। उनकी इस नीति का पर्दाफाश करके जनता को उनके प्रभाव से निकालना चाहिए, न कि उनके मुर में मुर मिलाकर बहना चाहिए कि हिन्दी भाषा अहिन्दी भाषाओं का दमन कर रही है।

अपने धर्म से प्रेम करना बुरा नहीं है। मुस्लिम लीग ने कहा—इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों को हिन्दू खा जाएंगे। लीग ने ‘डायरेक्ट ऐक्शन’ का रास्ता अपनाया। आत्मनिर्णय के नाम पर देश का विभाजन हुआ।

अपनी भाषा से प्रेम करना बुरा नहीं है। द्रविड मुन्नेत्र कळगम ने कहा—तमिल खतरे में है; तमिल-भाषियों को हिन्दीवाले गुलाम बना लेंगे। कळगम ने ‘डायरेक्ट ऐक्शन’ का रास्ता अपनाया। हिन्दी तमिल का दमन न करे इसलिए केन्द्र में अनिश्चित काल के लिए अंग्रेजी कायम रहेगी।

## केन्द्र और राज्य—पहले और बाद का सवाल

योगीन्द्रजी ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि पहले राज्यों से अंग्रेजी हटाना जरूरी है। राज्यों के विश्वविद्यालयों, सरकारी दफतरो आदि में पूरी तरह प्रादेशिक भाषाओं का चलन हो जाने के बाद ही केन्द्र से अंग्रेजी हटाने की बात की जा सकेगी। उन्होंने गांधीजी का यह कथन उद्धृत किया है, “सबसे पहले उन समृद्ध प्रादेशिक भाषाओं को पुनर्जीवित करना है जो भारत को सुलभ हैं।”

इसका अर्थ उन्होंने यह लगाया है कि जब तक राज्यों से अंग्रेजी निकल

न जायं, तब तक केन्द्र में अंग्रेजी चलती रहे !' इसके विपरीत गांधीजी ने प्रस्ताव किया था कि प्रान्तों में ऐसे वर्मचारी रखे जाएं जो प्रान्तीय भाषा के साथ केन्द्रीय भाषा भी जानते हों। इसीलिए उन्होंने लिखा था कि "प्रान्तों को केन्द्र से काम पड़ेगा। यह काम वे अंग्रेजी में करने की हिम्मत न करेंगे।"

'भाषा और समाज' में गांधीजी के बारे में मैंने लिखा था, "वह भारतीय भाषाओं के समर्थक थे। वह न इन भाषाओं पर हिन्दी लादना चाहते थे, न हिन्दी लादने का हीवा खड़ा करके अंग्रेजी बनाये रखने के पक्ष में थे।" (पृ० ४१३) गांधीजी की भाषा-नीति की यही व्याख्या मैं अब भी करता हूँ।

योगीन्द्रजी ने 'भाषा और समाज' से वे अंश उद्धृत किये हैं जहाँ भाषावार राज्यों के विरोध की निन्दा की गई है, जहाँ इस विरोध के कारण कुछ अहिन्दी-भाषी लोगों में हिन्दी के प्रति भय उत्पन्न होने की बात बही गई है, जहाँ राज्यों से अंग्रेजी हटाकर इस भय को दूर करने की बात की गई है। उन्होंने वे अंश छोड़ दिये हैं जहाँ मैंने लिखा था कि इस भय को बहाना बनाकर केन्द्र में अंग्रेजी कायम रखना गलत है।

मैंने स्पष्ट लिखा था, "भाषावार राज्यों के निर्माण का विरोध करके कांग्रेसी नेतृत्व ने काफी हद तक यह भय उत्पन्न किया है। इसका यह अर्थ नहीं कि अहिन्दी-भाषी अंग्रेजी की शरण लें।" (पृ० ४६६-६७)

मातृभाषाओं की दुहाई देकर अंग्रेजी की शरण लेनेवालों के बारे में मैंने लिखा था, "अहिन्दी क्षेत्रों के लोग अंग्रेजी से चिपके रहना चाहते हैं, वे मातृभाषाओं की सेवा नहीं करते। उन्हें हर बात में अंग्रेजी अपनी मातृभाषाओं से श्रेष्ठ लगती है। इसलिए उसे वे केन्द्र में ही नहीं अपने यहाँ भी सबसे ऊँचे आसन पर बिठाये रखना चाहते हैं..." मातृभाषाओं की दुहाई देकर अंग्रेजी का प्रभुत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता।" (पृ० ४५५)

गांधीजी के लेख को प्रकाशित हुए अठारह साल हो गये। योगीन्द्रजी के लिए अभी 'समृद्ध' प्रादेशिक भाषाओं को 'पुनर्जीवित' करने का सवाल बना हुआ है ! तमिल, तेलुगु, मराठी आदि भाषाओं के आधार पर तमिलनाडु, आन्ध्र, महाराष्ट्र आदि राज्य बन्ने के बन गये। योगीन्द्रजी समझते हैं कि भाषावार राज्यों के विरोध से जो भय उत्पन्न हुआ था, उसे दूर करना अभी बाकी है ! तमिलनाडु में तमिल माध्यमवाले विद्यालय खोले गये। छात्रों के अभाव में उन्हें बन्द कर देना पड़ा। इसलिए कि दिल्ली सरकार हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहती थी !

ध्यान देने की बात है कि तमिलनाडु में भाषावार राज्य बनाने के लिए कोई आन्दोलन नहीं हुआ। आन्दोलन हुआ आन्ध्र और केरल में जहाँ तमिलनाडु की तरह तोड़-फोड़ की कोई आवश्यकता नहीं हुई। भाषावार राज्य-आन्दोलन का दमन किया गया महाराष्ट्र और गुजरात में जहाँ हिन्दी-विरोधी

ग्रान्दोलन का प्रभाव है। ग्रहिन्दी-भाषी प्रदेशों में महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहाँ हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए जोरदार आवाज उठी है।

भाषावार राज्यों के ग्रान्दोलन में कम्युनिस्ट पार्टी ने सक्रिय भाग लिया था। तमिलनाडु के हिन्दी-विरोधी ग्रान्दोलन को प्रेरणा देनेवाले दो मुख्य दल थे—स्वतन्त्र पार्टी और द्रविड कळगम। भाषावार राज्यों के ग्रान्दोलन के दमन से ग्रहिन्दी भाषियों में हिन्दी के प्रति भय उत्पन्न हुआ है, इस सूत्र का आज की परिस्थितिसे कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

आज यह बिलकुल स्पष्ट है कि राज्यों की सरकारों के सामने प्रादेशिक भाषाओं के व्यवहार को रोकनेवाली कोई भी वैधानिक कठिनाई नहीं है। केन्द्रीय नौकरियों में अंग्रेजी चलती है। इनके प्रभाव से राज्यों के शिक्षाक्रम में अंग्रेजी की पढाई अनिवार्य हो जाती है।

‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ के विशेष सवाददाता ने उस पत्र के ७ जुलाई के अंक में लिखा है कि राजस्थान सरकार ने अनेक विभागों में हिन्दी के व्यवहार का निर्देश किया है किन्तु योजना सचिवालय जैसे विभागों को छोड़ दिया गया है। “जब तक योजना आयोग (प्लानिंग कमीशन) ही हिन्दी के व्यवहार का फैसला नहीं करता, तब तक राज्य को मजबूर होकर अंग्रेजी का व्यवहार जारी रखना पड़ेगा। इस पृष्ठभूमि में यह महसूस किया जा रहा है कि यदि अंग्रेजी की पढाई पर जोर कम दिया जाएगा तो राजस्थान और उसके नौजवानों के हितों की हानि होगी।”

जब राजस्थान का यह हाल है तब ग्रहिन्दीभाषी राज्यों की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। कौन राज्य नहीं चाहता कि उसके नौजवान ज्यादा-से-ज्यादा सख्या में केन्द्रीय सेवाओं में लिये जाएँ? इन केन्द्रीय सेवाओं के लिए अंग्रेजी का ज्ञान अनिवार्य है। इसलिए केन्द्रीय सेवाओं का भेदा लूटने के लिए राज्य एक-दूसरे से होड़ करते हैं कि कौन अंग्रेजी ज्यादा पढाता है।

इसीलिए आज की परिस्थिति में केन्द्र से अंग्रेजी हटाये बिना राज्यों में अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म नहीं किया जा सकता।

यद्यपि योगीन्द्र शर्माजी ने अपने लेख में राज्यों में पहले अंग्रेजी हटाने पर बहुत जोर दिया है किन्तु केन्द्र में उतने परिवर्तन की बात उन्होंने मान ली है जितना कांग्रेस को स्वीकार है। कांग्रेस का कहना है कि केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाओं को ऐच्छिक माध्यम बनाया जाय। योगीन्द्रजी इसे स्वीकार करते हैं। जब तक राज्यों से अंग्रेजी हट न जाय तब तक केन्द्र में कोई परिवर्तन न हो—यह सिद्धान्त उन्होंने खुद काट दिया। मेरा भी कहना है, केन्द्र और राज्य—दोनों जगह से अंग्रेजी हटाई जाय।

योगीन्द्रजी जब केन्द्र में इतना परिवर्तन मान लेते हैं—कि परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषाएँ ऐच्छिक माध्यम हो, तब दो कदम आगे और बढ़ें और यह माँग करें—केन्द्र में अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं का व्यवहार हो, अंग्रेजी

का चलन सतम करने की अवधि निश्चित हो।

केन्द्र में अंग्रेजी चलती है, इस कारण राज्यों में भी उसकी जड़ जमी हुई है। जो भी प्रादेशिक भाषाओं का हित चाहता है, वह केन्द्र से अंग्रेजी हटाने की माँग का समर्थन करेगा।

## कम्युनिस्ट पार्टी और अंग्रेजी

कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को कोई लालच नहीं है कि केन्द्रीय सरकारी नीतियाँ उन्हें भी मिल जाएँ। उन्हें कोई भय नहीं है कि पार्टी केन्द्र में हिन्दी का चलन हुआ तो राज्यों में पार्टी कार्य के लिए प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार न हो पाएगा। फिर भी पार्टी-केन्द्र की भाषा अंग्रेजी है।

योगीन्द्र शर्माजी के अनुसार राज्यों का मातृ पार्टी-कार्य प्रादेशिक भाषाओं में होता है। जहाँ तक पार्टी का सम्बन्ध है, राज्यों में अंग्रेजी हटाने का कार्यक्रम पूरा हो गया है। फिर भी पार्टी केन्द्र से अंग्रेजी नहीं निकाली जा रही। इसके कारण ख़तरा होगा लेकिन जो कारण कम्युनिस्ट पार्टी के सामने हैं उनमें तगड़े कारण काफ़ी हैं। राज्यों में अंग्रेजी विराधी आन्तिम घाप पूरी कर लेंगे और उसके बाद उस आन्तिम का मण्डा केन्द्र में गड़ेंगे—यह बात मैं कैसे मान लूँ ?

ब्रिटिश राज में कम्युनिस्ट पार्टी पर यह पाबन्दी न थी कि वह अपनी काम अंग्रेजी में करे। ब्रांपेयी राज में भी उस पर कोई ऐसी पाबन्दी नहीं रही। उसका जन्म हुए चालीस वर्ष हो गये, कानूनी जीवन बिताते हुए बीस साल में ऊपर हुए। वह गरीब जनता की पार्टी है, श्रमिकबर्ग की पार्टी है। योगीन्द्र शर्माजी के अनुसार वह सांस्कृतिक क्रान्ति की पार्टी है। लेकिन पार्टी के नेता अभी तक अपनी केन्द्र भूमि में इस सांस्कृतिक क्रान्ति का बीजारोपण नहीं कर सके। वे पार्टी केन्द्र से अंग्रेजी की विय नना की जड़ नहीं खोद पाये। सब पूँजीवादो पाटियो से क्या आशा की जाय ?

भारत की राजभाषा हिन्दी और राष्ट्रीय जनताधिक मोर्चा। मुनने में बहुत अच्छा सपना है। लेकिन सोचन की बात है जब पार्टी के नेता खुद अपने लिए हिन्दी को सम्पूर्ण भाषा नहीं बना पाये, तब राष्ट्रीय जनताधिक मोर्चे में उसका प्रवेश के किस द्वार से कराएँगे ? मोर्चा घोषित करेगा कि भविष्य में भारत की राजभाषा होगी हिन्दी लेकिन वर्तमान काल में खुद मोर्चे की भाषा होगी—अंग्रेजी।

अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत बनाने के लिए आई० सी० एस० अफसरों के लिए हिन्दुस्तानी सीखना अनिवार्य कर दिया था। मेरा प्रस्ताव है कि देश की सेवा के लिए—मजदूर वर्ग की एकता दृढ़ करने के लिए—कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कौंसिल के सदस्य हिन्दी सीखें। यह नियम बना दिया जाय कि जिसे हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान न होगा, वह राष्ट्रीय कौंसिल का सदस्य न

भारत की राजभाषा अंग्रेजी और राष्ट्रीय जनताधिक मोर्चा।

हो सकेगा ।

योगीन्द्रजी ने 'भाषा और समाज' से एक वाक्य उद्धृत किया है जिसमें पार्टी के नेताओं द्वारा हिन्दी बोलने की तारीफ है । वाक्य है, "भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मास्को और पेरिस के कम्युनिस्ट सम्मेलनों में हिन्दी का व्यवहार कर चुके हैं ।"

यह तारीफ मैं वापस नहीं ले रहा हूँ । निवेदन यह है कि मास्को और पेरिस में ही नहीं, पार्टी के नेता दिल्ली में भी हिन्दी बोलें ।

योगीन्द्र शर्माजी 'भाषा और समाज' के इन वाक्यों पर विचार करें "जब हम बाहर जायेंगे, किसी अन्य राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे, तब (कभी कभी, हमेशा नहीं) हम हिन्दी का व्यवहार करेंगे । लेकिन अपने घर में हमारे मुखपत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होंगे, हमारी कार्यकारिणी का अधिवेशन होगा तो उसमें विचार-विनिमय अंग्रेजी में होगा, नेताओं का अन्य नेताओं और उपनेताओं से पत्र-व्यवहार अंग्रेजी में होगा ।" (पृ० ४१३)

यह आलोचना कांग्रेसी नेताओं पर ही नहीं, कम्युनिस्ट नेताओं पर भी लागू होती है ।

स्तालिन, रुश्चेव और मिकोयान की मातृभाषा रूसी नहीं थी । फिर भी सारे देश में राजनीतिक कार्यवाही के प्रचार और संगठन के लिए उन्होंने रूसी भाषा को अपनाया, इस तथ्य का उल्लेख करते हुए मैंने 'भाषा और समाज' में लिखा था, "भारत में हिन्दी का व्यवहार किये बिना कोई प्रखिल भारतीय नेता नहीं बन सकता ।" (पृ० ४१४)

और भी—'लोग कहते हैं, नेहरू के बाद कोई ऐसा नेता नहीं दिखाई देता जिसकी बात सारा देश ध्यान से सुने । इसका कारण जहाँ हिन्दीभाषी प्रदेश का राजनीतिक पिछड़ापन है, वहाँ हिन्दीभाषी नेताओं द्वारा हिन्दी के प्रति उदासीनता भी है । वे हिन्दी के माध्यम से जन-प्राधारण में राजनीतिक कार्यवाही का महत्त्व नहीं समझ पाय ।' (पृ० ४१४)

यही उदासीनता का भाव अनेक अहिन्दीभाषी नेताओं में तीव्र उपेक्षा का भाव बन जाता है । इसी उपेक्षा की निन्दा मैंने अपने एक लेख में की थी ।

कम्युनिस्ट पार्टी के सामने सबसे बड़ा सवाल श्रमिक जनता की एकात्मता का है । यह एकात्मता अंग्रेजी के माध्यम से दृढ़ नहीं हो सकती । अंग्रेजी की प्रधानता होने से खुद कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर गरीब किसान और मजदूर जिम्मेदारी के पद नहीं संभाल सकते । यह इतिहास का व्यंग्य है कि कुछ समय के लिए केन्द्र में अंग्रेजी कायम रखकर योगीन्द्रजी देश को गृहयुद्ध से बचाना चाहते हैं । लेकिन गृहयुद्ध की सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर । पार्टी बीच में टूटी, उसके दो हिस्से हो गये । इस परिस्थिति के लिए एक हद तक पार्टी के अन्दर के मध्यवर्गी तत्त्व भी जिम्मेदार हैं जो अपनी अंग्रेजियत के कारण पार्टी-नेतृत्व का दरवाजा मजदूरों के लिए बन्द किये हैं ।

यह परिस्थिति अब बदलनी चाहिए ।

कांग्रेस सरकार ने केन्द्र से अंग्रेजी हटाने के लिए पन्द्रह साल की मियाद रखी थी । उसने अपना वादा तोड़ दिया । कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने अपने केन्द्र से अंग्रेजी हटाने के लिए कोई मियाद नहीं रखी थी । इसलिए उन पर वादा तोड़ने का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता ।

नेहरूजी ने कहा—हिन्दी अविवर्धित भाषा है, पहले उसे विकसित करो । फिर यह राजभाषा बनगी । पार्टी के नेताओं ने कहा—ठीक । हिन्दी को विकसित होने दो । दूसरी प्रादेशिक भाषाएँ हैं, उनके विकास पर भी रुपये खर्च होने दो । नेहरूजी ने कहा—अहिन्दी-भाषी नहीं चाहते कि अंग्रेजी हटाई जाए । पार्टी के नेताओं ने कहा—ठीक । चारा ही क्या है ? फिलहाल केन्द्र में अंग्रेजी ही चले !

कांग्रेस कार्यसमिति ने प्रस्ताव पास किया कि पब्लिक सर्विस कमिशन की परीक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार भी हो सकता है । पार्टी के नेताओं ने कहा—बहुत अच्छा, यही तो हम भी चाहते थे ।

इन अखिल भारतीय नेताओं में अंग्रेजी का व्यवहार अनिवार्य होगा—इस बारे में वे चुप रहेंगे । अपने पिछले लेख में इस प्रस्ताव की कंफिर्मेट देते हुए योगीन्द्रजी ने अंग्रेजी का नाम ही नहीं लिया, मानो अंग्रेजी से उसका कोई सम्बन्ध ही न हो ।

हमें माँग करनी चाहिए कि हर स्वाधीन देश की तरह भारत के शिक्षाक्रम में भी अंग्रेजी की पड़ाई वैकल्पिक हो । हम माँग करनी चाहिए कि सरकार केन्द्र और राज्यों से अंग्रेजी हटाने की अवधि निर्दिष्ट करे । हिन्दी को अभी और समृद्ध करने प्रादेशिक भाषाओं को समृद्ध करने के बाद अंग्रेजी हटाने के कांग्रेसी पाखण्ड का नीग्र खण्डन करना चाहिए । यह न करके योगीन्द्रजी उसका समर्थन करते हैं । उनकी स्वतन्त्र नीति केवल इस बात में प्रकट होती है कि वे इस गलत प्रस्ताव को मन्त्री मन्त्री कमल में लाने पर जोर देंगे ।

पार्टी-केन्द्र से अंग्रेजी हटाने का सवाल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस सवाल के जवाब से ही मालूम होगा कि क्रान्तिकारी लफकाजी और क्रान्तिकारी कमल में क्या फर्क है ।

## लेकिन की सीख—फिलहाल अंग्रेजी

लेनिनवाद के अनेक भाष्य, अनेक व्याख्याएँ समारंभ में प्रचलित हैं । स्तालिन ने जो कुछ किया लेनिनवाद के नाम पर । स्ट्रुइव ने उनकी वध्व खोदी—लेनिनवादी नीति की रक्षा के नाम पर । बोभनेव और कोसीगन ने स्ट्रुइव को हराया—लेनिनवाद को ही कमल में लाने के लिए । पेर्रिंग के नेता सोवियत संघ को अमरीकी साम्राज्यवाद का समर्थक कहते हैं—महान् क्रान्तिकारी लेनिन की विरासत की रक्षा करने के नाम पर । इसलिए यदि कोई भारत में कहे कि

लेनिन की यह सीख है कि फिलहाल केन्द्र में अंग्रेजी काम रहे तो इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं है।

जाराहाही इस के अभिजात वर्ग में फ्रांसीसी भाषा का बहुत व्यवहार होता था। यूरोप की अन्तर्जातीय भाषा फ्रांसीसी थी। लेनिन ने यह नहीं कहा कि लोग केन्द्र में इसी भाषा नहीं चाहते, इसलिए फिलहाल वहाँ फ्रांसीसी भाषा चल दी जाय।

लेनिन का समाधान यह था कि किसी भी भाषा को अनिवार्य केन्द्रीय राजभाषा का पद न दिया जाय। इस समाधान को यदि भारत में लागू किया जाय तो अंग्रेजी को हटाकर उसकी जगह सभी प्रादेशिक भाषाओं को बराबरी की जगह देनी होगी।

योगीन्द्रजी इस बात की कल्पना ही नहीं करते कि केन्द्रीय राजभाषा के बिना भी काम चल सकता है। इसीलिए उन्होंने मेरे बारे में लिखा है, "किसी भाषा के जोर जबर्दस्ती लादे जाने के वे ऐसे कट्टर विरोधी थे कि उस समय के कानूनी राजभाषा के सिद्धान्त का ही विरोध करते थे" वे १९५०-५५ में भाषा के सवाल पर अराजकतावादी छोर पर थे।

केन्द्र में अनेक राजभाषाएँ चलाने का सिद्धान्त अराजकतावादी नहीं है। लेनिन ने समाजवादी प्रान्ति के बाद न तो इसी को केन्द्रीय राजभाषा बनाया न और किसी भाषा को। यह अराजकतावाद नहीं था।

यदि भारत के लिए हम कहे कि केन्द्रीय राजकर्मचारियों को समस्त प्रादेशिक भाषाएँ सीखनी हानी तो यह अराजकतावादी बात होगी। किन्तु केन्द्र में सभी भारतीय भाषाओं को समानता के अधिकार देने के और भी उपाय हैं। इनमें मुख्य उपाय है अनुवाद की व्यवस्था का।

४ जुलाई के जनयुग में श्री राही मामूम रजा ने यह प्रस्ताव रखा है, "केन्द्रीय सरकार के पास एक अनुवाद-विभाग हो। अन्य प्रान्तों से होनेवाले पत्रव्यवहार की भाषा तो हिन्दी हो जाय और प्रान्तीय सरकारों की भाषा उस समय तक उस क्षेत्र की भाषा बनी रहे जब तक कि वह क्षेत्र हिन्दी को स्वीकार न कर ले।"

यदि कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक बार यह तय कर लें कि अंग्रेजी की जगह केन्द्र में भारतीय भाषाएँ चलानी हैं तो अनुवाद की समुचित व्यवस्था क्या हो, वे यह तय कर लेंगे। केन्द्र में सभी भाषाओं को बराबरी का दर्जा देने से वे शक-शुभे बहुत जल्दी दूर हो जाएँगे जिनके मारे योगीन्द्रजी परेशान हैं। अभी उनके पास कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है जिससे हिन्दी भाषा को केन्द्र में चालू करने की स्वेच्छा अहिन्दीभाषी नेताओं में उत्पन्न हो। मेरा प्रस्ताव उस 'स्वेच्छा' को उत्पन्न करने में सहायक होगा।

केन्द्र में अनेक भाषाओं के चलन का सिद्धान्त बीजरूप में कांग्रेस ने स्वीकार किया है। उसने केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए प्रादेशिक भाषाओं

की माध्यम रूप में मान्यता दी है। योगीन्द्रजी वाग्रेम के प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। बीजरूप में अनेक राजभाषाओं के चलन की बात यह भी मानते हैं। इसलिए अंग्रेजी को हटाकर प्रादेशिक भाषाओं को केन्द्र में जगह देने की बात उन्हें प्रमान्य न होनी चाहिए।

इस समय अनेक दलों के नेताओं ने यह प्रचार कर रखा है कि केन्द्र में अंग्रेजी हटाते ही गृहयुद्ध छिड़ जायगा। इनमें कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजी अनन्त काल तक रहनी चाहिए। दूसरे कहते हैं, अनन्त काल तक नहीं, अनिश्चित काल तक रहनी चाहिए यानी तब तक जब तक अहिन्दीभाषी लोग हिन्दी की स्वीकार न कर लें।

ग्राम्भ के मन्त्री श्री भलपति बैकटरामैया ने कहा है कि "हिन्दी को अंग्रेजी की जगह लेने में पचास साल लगेंगे।" (नादरं इडिया पत्रिका, १६ फरवरी, '६५)

ये औरो में फिर भच्छे हैं। पचास साल की निश्चित अवधि की बात तो करते हैं। अनिश्चित काल वालों का राम ही मालिक है।

जनतामित्र समाधान ऐसा होना चाहिए जो हिन्दीभाषियों को भी स्वीकार हो। कुछ लोगों को हिन्दी पसन्द नहीं है, औरो को अंग्रेजी पसन्द नहीं है। हिन्दी अंग्रेजी के इस संघर्ष में तैनिनवाद का फौमला अंग्रेजी के पक्ष में न होना चाहिए। फौमला होना चाहिए भारतीय भाषाओं के पक्ष में।

योगीन्द्र शर्माजी की निगाह गृहयुद्ध की सम्भावना के एक पक्ष पर है। वह यह कि हिन्दी को राजभाषा बनाने में अहिन्दी भाषी विद्रोह कर देंगे। उन्होंने गृहयुद्ध की सम्भावना के दूसरे पक्ष पर विचार नहीं किया। हिन्दी-भाषियों की इच्छा के विरुद्ध केन्द्र में अंग्रेजी चनाते रहना अन्याय है। वे भी अंग्रेजी के चलने के विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं।

स्थिति यह है कि अंग्रेजी के प्रभुत्व के कारण दक्षिण में द्रविड कळगम और उत्तर में जनसंघ शक्तिशाली होते जा रहे हैं। इनके शक्तिशाली होने के कारण भलग भलग हैं लेकिन भाषा समस्या से उनका गहरा सम्बन्ध है। यदि केन्द्र में तमिल को हिन्दी के बराबर जगह दी जाय तो द्रविड कळगम को तमिल प्रेम का भण्डा उठाने का मौका न मिले।

वाग्रेमी और कम्युनिस्ट नेता जितने दिन केन्द्र में अंग्रेजी चालू रखने की नीति का समर्थन करते हैं, उतने ही दिन वे द्रविड कळगम और जनसंघ की भाषा विवाद से फायदा उठाकर शक्तिशाली बनने का मौका देते हैं। जनता में इन प्रतिप्रियावादी दलों के प्रभाव को खत्म करने का एक अच्छा उपाय है, केन्द्र में अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार।

यह अस्थायी समाधान है। जब तक अहिन्दीभाषी केन्द्र में हिन्दी का चलन स्वीकार न करें, तब तक यह समाधान लागू करना चाहिए।



## तर्क-पद्धति और निष्कर्ष

मैं समझता हूँ कि कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य जनवादी पार्टियाँ मिल-कर प्रयत्न करें तो अगले पाँच वर्षों में वे हिन्दी को केन्द्रीय राजभाषा बना सकती हैं। द्रविड कळगम और स्वतन्त्र पार्टी इतनी समर्थ नहीं हैं जितनी वे मालूम होती हैं। उन्होंने जनता के मातृभाषा-प्रेम से लाभ उठाकर उसे बरगलाया है। यदि उस जनता को बताया जाय कि केन्द्रीय सेवाओं के लिए अहिन्दी-भाषियों को हिन्दी सीखनी होगी और हिन्दीभाषी अफसरों को वैसे ही एक अहिन्दीभाषा का ज्ञान प्राप्त करना होगा, तो जनता के गुमराह अशो को राह पर लाया जा सकता है।

लेकिन केन्द्रीय सेवाओं के हिन्दीभाषी उम्मीदवार एक अहिन्दीभाषा का ज्ञान प्राप्त करें—मेरे इस प्रस्ताव पर योगीन्द्रजी ने ध्यान ही नहीं दिया, उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। तब कांग्रेसी नेताओं से मैं क्या आशा करूँ ?

इसलिए मैंने अपने लेख में यह विकल्प रखा है कि केन्द्र में हिन्दी के साथ अन्य भाषाओं का व्यवहार भी हो। इससे पहले भी मैंने 'जनशक्ति' में लिखा था, 'समस्या का एक ही हल है केन्द्र में हिन्दी हो, राज्यों में प्रादेशिक भाषाएँ। इस पर भी यदि कोई कहे कि अंग्रेजी हटाने से अहिन्दी भाषाओं का दमन हुआ तो निवेदन है, लोकसभा में सभी भाषाएँ चलाईएँ। हम इस बात का मोह नहीं है कि भारत सरकार का काम हिन्दी में हो। धृणा इस बात से है कि उसका काम अंग्रेजी में होता है। केन्द्र में चाहे एक भारतीय भाषा चलाईए, चाहे दस विदेशी भाषा अंग्रेजी को निकालिए।'

लोकसभा के लिए मैंने विशेष रूप में लिखा था, 'लोकसभा में अहिन्दी-भाषी नेता शौक से अपनी अपनी भाषाएँ बोलें। हिन्दी भाषी नेता हिन्दी में बोलें। कम्युनिस्ट सदस्य अपने व्यवहार से इस नीति की मिसाल कायम करें।'

मेरे यह सब लिखने पर भी योगीन्द्र शर्माजी ने बड़े आग्रह से यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मैं अहिन्दी भाषाओं को दवाना और केन्द्र में जबर्दस्ती हिन्दी चलाना चाहता हूँ।

उन्होंने १४ मार्च के भर्मुग में प्रकाशित मेरे लेख का दो बार हवाला दिया है। यह लेख उन्हे विशेष उपयोगी जान पड़ता है, उममें गृहयुद्ध की ललकार उन्हें ज्यादा स्पष्ट सुनाई पड़ती है।

मैंने लिखा था "यह संघर्ष हिन्दी-तमिल का नहीं है, अंग्रेजी और समस्त भारतीय भाषाओं का है। हिन्दी-तमिल-यिरोर के बड़े घातक परिणाम हो सकते हैं। एक बार गृहयुद्ध की आग भड़कने पर उसे रोकना सम्भव हो जाएगा।"

गृहयुद्ध की ललकार का इससे अधिक पुष्ट प्रमाण और क्या होगा ?

मैंने लिखा था, 'भारतीय भाषाओं को उनके उचित अधिकार दिलाने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले हिन्दी-भाषी प्रदेश में अंग्रेजी को राजभाषा और सांस्कृतिक भाषा के पद से हटा दिया जाय।'

योगीन्द्रजी का विचार है कि मैं भारतीय भाषाओं के अधिकारों को कुचल-कर हिन्दी को राजभाषा बनाने के पक्ष में हूँ !

मैंने लिखा था, “इसके बाद जिस दिन हिन्दीभाषी जनता संगठित होकर अपने लोकसभा के प्रतिनिधियों को हिन्दी में बोलने और सारा राजकाज हिन्दी में करने के लिए बाध्य करेगी, उस दिन अंग्रेजी का साम्राज्यवाद खत्म होगा, उस दिन तमिलनाडु में तमिल भी अपना पूर्ण स्वत्व प्राप्त करेगी और राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने में हिन्दीभाषी जनता अपनी भूमिका पूरी करेगी।”

यह वाक्य उन्होंने उद्धृत किया है लेकिन उसका वह टुकड़ा निकालकर जिसमें तमिल के पूर्ण स्वत्व प्राप्त करने की बात है। कारण स्पष्ट है। पूरा वाक्य उद्धृत करने से मुझ पर तमिल-दमन का आरोप लगाने में असुविधा होती।

वह अक्ष निकाल देने पर भी गृहयुद्ध की ललकार का आरोप लगाना सरल नहीं था। इसलिए उन्होंने ‘लेकिन यदि’ का सहारा लिया—“लेकिन यदि यही बात पूरे देश के लिए कही जाय तो...” इस तरह ‘लेकिन यदि’ लगाकर किसी भी वाक्य से कोई भी नतीजा निकाला जा सकता है।

योगीन्द्रजी ने मुझ पर यह आरोप लगाया है कि अजय घोष के लेख में मैंने वे बातें छोड़ दी हैं जो मेरी नीतियों के विरुद्ध हैं। ये कौन-सी बातें हैं ? अजय घोष के लेख से उन्होंने जो अंश उद्धृत किया है उसमें कहा गया है भाषा-आयोग के सदस्य प्रादेशिक भाषाओं को एक अभिगम के रूप में देखते हैं। वे नहीं मानते कि भारत बहुभाषी देश है। उन्होंने जनतन्त्र के इस प्रारम्भिक सिद्धान्त को विचार में बाहर रखा है कि शासन, विधि न्याय की भाषा, प्रत्येक क्षेत्र में सभी स्तरों पर वह भाषा होनी चाहिए जिसको जनता आम तौर पर बोलती और समझती है।

योगीन्द्रजी का विचार है कि मैं अजय घोष की उपर्युक्त नीति का विरोधी हूँ यानी प्रदेशों में वहाँ की भाषाओं के बदले हिन्दी का ही चलन करना चाहता हूँ।

‘जनशक्ति’ में मैंने लिखा था—

(क) “भारत में भाषावार राज्य बनाने का आन्दोलन चला। हर प्रदेश में उसकी शिक्षा और संस्कृति का विकास उसकी भाषा के माध्यम से हो, यह माँग सही थी।”

(ख) “जिम तरह हर प्रदेश में उसकी अपनी भाषा को सभी अधिकार मिलने चाहिए, वैसे ही इन सबको जोड़नेवाली राष्ट्रभाषा हिन्दी को भी केन्द्र में पूर्ण अधिकार मिलने चाहिए।”

(ग) “इस पर भी यदि कोई बहे कि अंग्रेजी हटाने से अहिन्दी भाषाओं का दमन होता है तो निवेदन है, लोकसभा में सभी भाषाएँ चलाईएँ।”

अजय घोष ने अहिन्दी भाषाओं को केवल प्रदेशों में पूर्ण अधिकार देने की

बात कही थी। मैं उन्हें केन्द्र में हिन्दी के बराबर स्थान देने की बात कहता हूँ। लेकिन विरोधी आलोचकों का मुँह बन्द करने के लिए योगीन्द्र शर्माजी ने सीधी रणनीति निकाली है। उन पर ग्रन्थ हिन्दी राष्ट्रवाद का आरोप लगा दो, केन्द्र में फिलहाल अंग्रेजी चलाने की नीति अपने प्राप सही साबित हो जाएगी।

मैंने लिखा था, “अंग्रेजी कायम रखने के लिए जो विशाल सयुक्त मोर्चा बना है, उसमें स्वतन्त्र दल के नेता हैं, द्रविड़ कळगम वाले हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के अनेक नेता भी इसमें हैं।” योगीन्द्रजी ने अनेक का अर्थ किया सम्पूर्ण और नाराज होकर लिखा, ‘इन्हीं की पक़्त में सम्पूर्ण कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को खड़ा कर देना भारतीय राष्ट्रीयता और जनतन्त्र को कलकित करना है, सच्चाई के मुँह पर तमाचा मारना है।’

१७ फरवरी, '६५ को पी० टी० आई० द्वारा नई दिल्ली से प्रसारित समाचार के अनुसार ३४ सदस्य-सदस्यों ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया था कि संविधान की वह धारा बदल देनी चाहिए जिसमें हिन्दी को राजभाषा घोषित किया गया है। पी० टी० आई० के अनुसार इन सदस्य-सदस्यों में कम्युनिस्ट पार्टी, द्रविड़ कळगम, स्वतन्त्र पार्टी, आर० एस० पी० तथा मुस्लिम लीग के नेता थे।

योगीन्द्र शर्माजी विचार करें, भारतीय राष्ट्रीयता और जनतन्त्र को कौन कलकित करता है, सच्चाई के मुँह पर तमाचा कौन मारता है।

मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं की भाषा नीति की आलाचना की थी। इसे उन्होंने ‘हिन्दी भाषा और भारत देश को शाप’ देना कहा है।

गद्य में अतिशयोक्ति अलंकार उन्हें बहुत प्रिय है और उसके व्यवहार पर वह कोई भी प्रतिबन्ध लगाना अनुचित समझते हैं।

‘भाषा और समाज’ से सम्बन्ध उद्धरण देकर उन्होंने यह नतीजा निकाला है कि पहले मैं पंडिताऊ हिन्दी का विरोधी था, अब उसका समर्थक हो गया हूँ। अपनी रणनीति के अनुसार मेरी पुस्तक के वे अंश उन्होंने छोड़ दिए हैं जहाँ मैंने सुगठ पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की प्रशंसा की थी। मैंने लिखा था—

‘लेकिन पारिभाषिक शब्दावली में ऐसे भी बहुत से शब्द हैं जो बोलने में हिन्दी प्रवृत्ति का उल्लंघन नहीं करते और जिनके लिए विश्वास से कहा जा सकता है कि वे अवश्य लोकप्रिय होंगे। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित कृपि सम्बन्धी शब्दावली से हम कुछ शब्द ले सकते हैं।’ (पृ० ४३३)

छास बात यह है कि मैंने उन लोगों का विरोध किया था जो पारिभाषिक शब्दावली को असन्तोषजनक बताकर केन्द्र में अंग्रेजी चलाने रहने का समर्थन करते थे। मैंने लिखा था—

‘हिन्दी में काफी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण हो चुका है। इनमें बहुत से अपने-अपने विषय की हिन्दी पुस्तकों में व्यवहृत भी होते हैं। जहाँ तक राजकाज

का सम्बन्ध है, इस विषय के शब्दों का निर्माण विज्ञान की सहायता से बनाने से आसान है। इसलिए विज्ञान में चाहे हिन्दी का प्रयोग कुछ दिन रुका भी रहे, राजभाषा के रूप में हिन्दी का व्यवहार रके, इसका कोई कारण नहीं है।”  
(पृ० ४३३)

योगीन्द्रजी ने इससे उल्टा निष्कर्ष निकाला है।

इस तरह की तर्क-पद्धति वे अपनाते हैं जो हठधर्मों से गलत नीति को भी सही साबित करने के लिए कसर कम सेत है। इस तरह विरोधी आलोचकों की बातों को तोड़-मरोड़कर पेश करने से जनवादी तर्कों में एकता स्थापित नहीं की जा सकती।

योगीन्द्रजी ने ग्रन्थ-राष्ट्रवाद की बात बहुत दार की है। वह 'भाषा और समाज' के इस वाक्य पर भी गौर करें—

“वर्तमान ग्रन्थ राष्ट्रवाद की विशेषता यह है कि वह दूसरी भारतीय भाषाओं के प्रति घृणा फैलाता है और अंग्रेजी को गले लगाता है।” (पृ० ४२५)

मैं चाहता हूँ कि पार्टी के नेताओं में हिन्दी के प्रति जो अपेक्षा-भाव है, वह खत्म हो। वे अपने सिद्धान्त और व्यवहार में एकता स्थापित करें। शासन-केन्द्र में चाहे एक भाषा चलाएँ चाहे अनेक, निश्चित अर्थात् में अंग्रेजी का चलन बन्द हो—यह माँग करें। अंग्रेजी को अनिश्चित काल के लिए भारत की राज-भाषा बनाकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे का निर्माण नहीं हो सकता।

(१६६५)

## देश का विघटन और अंग्रेजी

एक जमाना था जब लोग समझते थे कि अंग्रेजी सभी भारतीय भाषाओं पर साम्राज्यवादियों द्वारा लादी हुई भाषा है। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान किसी भी देशभक्त को इस बारे में शक नहीं था कि अंग्रेजी की गुलामी अंग्रेजों की ही गुलामी का एक भग है। उस समय राष्ट्रीय नेता मानते थे कि अंग्रेजी का प्रभुत्व राष्ट्रों के लिए अपमानजनक है। वे जानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण देश की शक्ति और धन का अपार अपव्यय होता है। वे कहते थे कि देश पर मुट्ठी-भर अंग्रेजी-पढ़े हूकूमत करें, यह जनतन्त्र का मजाक है। उस जमाने में राष्ट्र के नेता भाषा की समस्या पर आम जनता के दृष्टिकोण से विचार करते थे। वे घोषित करते थे कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ है भारत के करोड़ों श्रमिक जनो की एकता। यह एकता हिन्दी और केवल हिन्दी के द्वारा कायम हो सकती है।

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद वे बातें अब पुरानी हो गईं। जो अंग्रेजी की हिमायत करता है, वह उदार और प्रगतिशील माना जाता है। जो अंग्रेजी हटाने की बात करता है, वह पुराणपन्थी और हिन्दी उन्मादी कहलाता है। राष्ट्रीय एकता के लिए सबसे आवश्यक है अंग्रेजी। अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क के लिए एकमात्र विश्वभाषा है अंग्रेजी। ज्ञान-विज्ञान के लिए अनिवार्य माध्यम है अंग्रेजी।

अब राष्ट्रीय एकता का अर्थ जन-साधारण की एकता नहीं है। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है अंग्रेजी-पढ़े नेताओं और नौकरशाहों की एकता। अब राष्ट्रीय एकता का प्रश्न जुड़ा हुआ है स्थित भारतीय नौकरियों के साथ।

तमिलनाडु में इतना उत्पात हुआ, तमिल की रक्षा के लिए ? नहीं, लोगों को भय दिखाया गया कि सरकारी नौकरियाँ हथिया लेंगे हिन्दीवाने, दक्षिण-वाले टापटे रह जाएंगे। हिन्दी के अत्याचार में बचने के लिए कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि हर राज्य के लिए नौकरियों का 'कोटा' निश्चित कर दिया जाय।

पिछले छह: महीने से यह नौकरियों का सवाल अंग्रेजी-पढ़े बाबुओं के सामने है। उनके लिए यह सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय समस्या है। अंग्रेजी-पढ़ा नौकरशाह वर्ग आम जनता से कितनी दूर है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इस समुदाय के सामने भाषा-समस्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है—नौकरी !

देश की राष्ट्रीय संस्था कांग्रेस के नेता भाषा-समस्या पर विचार करते हैं तो उनके सामने मुख्य प्रश्न होता है : पखिल भारतीय नौकरियों की परीक्षाएँ कितनी भाषाओं में होगी !

यह मानते हुए कि अपनी जगह नौकरियों की समस्या का भी महत्व है, हमें राष्ट्रीय एकाता के प्रश्न को सरकारी नौकरियों के दायरे में बन्द न कर देना चाहिए। विभिन्न प्रदेशों की श्रमिक जनता की एकाता किस तरह कायम की जाय, शासन-तन्त्र में आम जनता किस तरह भाग ले, राज्यसत्ता कुछ ऊपरवाले निहित स्वार्थों के हाथ में बठपुतली बनकर न रह जाय—भाषा की समस्या पर विचार करते हुए इन प्रश्नों को हमेशा सामने रखना चाहिए।

कांग्रेस कार्यसमिति ने फैसला किया है कि अखिल भारतीय नौकरियों की परीक्षाएँ अंग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं में होगी। कुछ पर्व अंग्रेजी और हिन्दी में अनिवार्य होंगी। जिन उम्मीदवारों की भाषा हिन्दी होगी, उनके लिए एक पर्व किसी अहिन्दी भाषा में होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रत्येक राज्य की भाषा, शासन और शिक्षा का माध्यम बनेगी। हिन्दी-शिक्षण के स्तर को ऊँचा किया जाएगा। “अंग्रेजी ऐसी भाषा के रूप में पढाई जाती रहेगी, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।” तीन भाषाएँ सीखने की नीति दृढ़ता से लागू की जाएगी। हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं का विकास किया जाएगा।

जिन लोगों ने कांग्रेस कार्यसमिति के फैसले का स्वागत किया है, उनका विचार है कि अब अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषाओं का चलन हो जाएगा।

इस घोषणा का आधार क्या है ?

प्रादेशिक भाषाएँ केवल परीक्षाओं का माध्यम बनेंगी, केन्द्रीय राजकाज का माध्यम नहीं। राजकाज होगा अंग्रेजी में। अखिल भारतीय सेवाओं में यह तो होगा नहीं कि परीक्षा में जिसका माध्यम तमिल है, उसे नौकरी तमिलनाडु में ही करनी होगी। अखिल भारतीय नौकरियों का मतलब ही यह है कि किसी भी अफसर को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। तब यह विभिन्न प्रदेशों का कार्य किस भाषा में होगा ? क्या तमिलभाषी अफसर दिल्ली में अपना दफतर तमिल में चलाएगा ? या बंगलाभाषी अफसर मद्रास में अपना काम बंगला में करेगा ?

स्पष्ट है कि अखिल भारतीय नौकरियों का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगी।

कांग्रेस कार्यसमिति ने यह फैसला नहीं किया कि केन्द्रीय सरकारी नौकरियों में अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होगा। फैसला यह किया है कि परीक्षाओं में अंग्रेजी के साथ प्रादेशिक भाषाएँ भी माध्यम बन सकती हैं।

इसलिए यह भाषा समाना व्यर्थ है कि केन्द्रीय राजराज में अंग्रेजी की जगह प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होने लगेगा, या अंग्रेजी के साथ उन्हें ही बालिश भर जगह भी मिल जाएगी।

परीक्षाओं के लिए भी प्रादेशिक भाषाओं को अनिवार्य माध्यम नहीं बनाया गया। माध्यम बनने के लिए उन्हें विकसित होना है, अपने प्रदेश में राजभाषा बनना है, विश्वविद्यालयों में उच्चतम शिक्षा का माध्यम बनना है। बनने-बनाने का यह सारा क्रम अब समाप्त होगा, इसकी कोई शक निश्चित नहीं की गई।

भारत सरकार पन्द्रह साल से हिन्दी के विकास में लगी है, लेकिन अभी वही उस विकास का छोर नहीं दिखाई देता। बड़े-बड़े कोश बन जाने के बाद भी कार्यसमिति के प्रस्ताव में हिन्दी को अभी छोर विकसित करने की बात वही गई है।

यह अदभुत राष्ट्रभाषा प्रेम है ! हिन्दी के विकास से वह अभी सन्तुष्ट नहीं होता। विकास के अपूर्ण हान से वह अंग्रेजी को ही राष्ट्रभाषा बनाए रहता है।

प्रादेशिक भाषाओं के प्रमी समझ लें, उन्हें अपनी भाषाओं के विकास के लिए बिलनी सम्बन्धी प्रतीक्षा करनी होगी।

प्रादेशिक भाषाओं को पन्द्रह साल से यह अधिकार प्राप्त है कि वे उच्च शिक्षा का माध्यम बनें, प्रदेशों की राजभाषा बनें। लेकिन इस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं हुआ ? कांग्रेस के प्रस्ताव में वही इस बात की कैफियत नहीं दी गई कि, हर राज्य में शासन की भाषाओं कांग्रेस के हाथ में होने पर भी, उस अधिकार का पूरी तरह उपयोग क्यों नहीं किया गया।

जिस अधिकार का उपयोग पन्द्रह साल में नहीं हुआ, इस प्रस्ताव के बाद उसका उपयोग होगा ही, इसका क्या प्रमाण है ? इसके विपरीत उसका उपयोग आगे भी न होगा, इसका प्रमाण है।

केन्द्र में जब तक अंग्रेजी का बोलवाला रहेगा, तब तक राज्यों में प्रादेशिक भाषाओं को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं हो सकतः। अंग्रेजी पढ़ा उम्मीदवार पढ़न अखिल भारतीय अफसर बनने की कोशिश करता है। इस वाशिश में असफल होता है तब प्रादेशिक अफसर बनने का प्रयत्न करता है। यहाँ भी नाकामयाब रहा तो मास्टरी या क्लर्क करता है। स्थिति यह है कि रेल ब्रेक, डाक, तार, फौज, पुलिस, प्राइवेट फर्म—यहाँ भी मामूली वरुँ अंग्रेजी के बिना नहीं मिलती। लाखों नौजवान हर साल फेल होत हैं, अंग्रेजी की वजह से। देश में शिक्षा बेहद महँगी है अंग्रेजी के कारण।

इसलिए जो लोग धन और श्रम शक्ति के इस अपव्यय को बन्द करना चाहते हैं, जो राज्यों में प्रादेशिक भाषाओं को उनके पूर्ण अधिकार दिलाना चाहते हैं उनके सामने एक ही वर्तव्य हो सकता है—केन्द्र में अंग्रेजी के प्रभुत्व को खत्म करना।

जो लोग सोचते हैं कि केन्द्र में अंग्रेजी के हटने से नौकरियाँ हिन्दीवालों को ज्यादा मिल जाएँगी, उनका भय दूर करना कठिन नहीं है। हिन्दीभाषी उम्मीद-वारी के लिए एक प्राधुनिक अहिन्दी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर देना चाहिए। कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव में यह नियम शामिल किया गया है कि हिन्दी-भाषियों के लिए एक पचा अहिन्दी भाषा का होगा। देश की भावात्मक एकता के लिए मुख्य जोर प्राधुनिक प्रादेशिक भाषाएँ सीखने पर होना चाहिए।

किन्तु कांग्रेस के तीन भाषा वाले सूत्र में मुख्य जोर है अंग्रेजी पर। इसी-लिए उस सूत्र को प्रमल में लाना कठिन होता है। वह जिस तरह प्रमल में लाया गया है, उससे किसी को सन्तोष नहीं है। सन्तोष इसलिए नहीं है कि प्रमल में लानेवालों की निगाह अंग्रेजी पर पहले है, हिन्दी और भारतीय भाषाओं पर बाद की।

श्री सादिक अली कांग्रेस के जाने माने नेता है। कांग्रेस के संगठन-कार्य से उनका विशेष सम्बन्ध रहा है। उन्होंने कार्यसमिति के प्रस्ताव की व्याख्या करते हुए ७ जून के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तीन भाषाओं वाला फार्मूला लागू करने से अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और भी अधिक होगा।

लिखा है "सन्देहवादी लोग कह सकते हैं कि तीन भाषाओं वाले फार्मूले को कारगर तरीके से लागू करने की गुजाइश कम है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं यह जानता हूँ कि तीन भाषाओं वाले फार्मूले में अंग्रेजी वाला हिस्सा कारगर तरीके से जड़ लगाना किया जाएगा।"

अंग्रेजी, और अधिक अंग्रेजी—यह है हमारे राष्ट्रीय नेताओं का दृष्टिकोण।

श्री सादिक अली का विचार है, 'यह अच्छी बात है कि हमारे विद्यार्थियों में अंग्रेजी जानने की व्यापक इच्छा है।'

ऐसा है तो अंग्रेजी वैकल्पिक कर दीजिए। फिर देखिए, कितने लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं। आगरा विश्वविद्यालय में जब मेरी ० एस सी की परीक्षाओं में अंग्रेजी को वैकल्पिक कर दिया है, तब से लगभग नब्बे फी सदी विद्यार्थियों ने 'जनरल इग्निश' की परीक्षा देना बन्द कर दिया है।

श्री सादिक अली का मत है, "सही दृष्टिकोण यह है कि अंग्रेजी को उमका न्यायोचित स्थान (राइटफुल प्लस) दिया जाय जिसमें देश की सम्मिलित इच्छा सक्रिय व सहारे वह फले-फूले। इस तरह उसके सामने ज्यादा सुन्दर, ज्यादा महान, ज्यादा रचनात्मक भविष्य होगा।"

न्यायोचित स्थान देना है अंग्रेजी को। रचनात्मक भविष्य है अंग्रेजी का। देश की सम्मिलित इच्छासक्ति सहारा दोगी अंग्रेजी को।

शामक वर्ग अपनी भाषा-नीति किस उद्देश्य से निर्धारित कर रहा है, यह श्री सादिक अली के बकवच से स्पष्ट हो जाता है।

सार्वभौम सत्ता होगी अंग्रेजी की। प्रादेशिक भाषाएँ होंगी उसकी दासिनी।



उद्देश्य और इच्छाओं के अलावा हिन्दी अहिन्दीभाषी राज्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि जब तक विधान-सभा, लोक सभा तथा राज्य सभा में उनके प्रतिनिधि अपने भारी बहुमत से अंग्रेजी हटाने का प्रस्ताव पास न करें तब तक—यानी अनिश्चित काल के लिए—अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्रभाषा रहेगी।

इस पर भी कुछ लोगों को यह दुस्वप्न होता है कि कांग्रेस के प्रस्ताव से हिन्दी साम्राज्यवाद के लिए रास्ता साफ हो गया है। यदि लोकसभा यह प्रस्ताव पास कर दे कि भारत में सदा-सर्वदा के लिए अंग्रेजी एकमात्र राजभाषा रहेगी, तब भी ये लोग कहेंगे, उत्तरवाले दक्षिणवालों पर राज्य कर रहे हैं। जिन लोगों को नीति है कि हर बहाने 'द्विविध-भारत' को 'आर्य-भारत' से अलग कर दिया जाय, वे अंग्रेजी के बारे में किसी भी आश्वासन से सन्तुष्ट नहीं हो सकते।

अंग्रेजी की जड़ मजबूती से जमी है। कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव को कानूनी रूप देने से वह और भी पुष्टा हो जाएगी। किसी को यह भय न होना चाहिए कि प्रादेशिक भाषाओं को नये अधिकार मिल गए हैं और अब अंग्रेजी के अभाव में राष्ट्रीय एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी।

यदि अंग्रेजी से राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती थी तो भविष्य में वह और भी सुदृढ़ हो जाएगी।

किन्तु क्या सचमुच अंग्रेजी से राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती है ?

सन '४७ में जब एक राष्ट्र से दो राष्ट्र बने, तब अंग्रेजी-पढ़े लोग ही विघटनकारी प्रचार के अगुआ थे। बम्बई में संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन के दौरान गुजरातियों और मराठी-भाषियों में संघर्ष हुआ। इसके नेता भी अंग्रेजी पढ़े लोग थे। असम में बंगालियों और असमियों के बीच दंगे हुए। यहाँ भी भाषा सम्बन्धी आन्दोलन के नेता थे अंग्रेजी पढ़े भद्र लोग। तमिलनाडु में जो उत्पात हुआ, उसके सूत्रधार अंग्रेजी-प्रेमी सज्जन थे। कश्मीर में अलगाव के नेता विलायत जाकर अंग्रेजी में भाषण देनेवाले लोग हैं। नागालैण्ड के अलगाव पन्थी नेता विलायत ही में निवास करते हैं।

अंग्रेजी पढ़ा वर्ग भारत में विघटन प्रक्रिया रोकने में असमर्थ है। दिवालिये राजनीतिज्ञ राष्ट्रीय एकता कायम रखने के लिए जिनना ही इस समुदाय का भरोसा करते हैं उतना ही विघटनकारी शक्तियाँ प्रबल होती जाती हैं।

राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने का दूसरा तरीका है जन-साधारण का भरोसा करना, फौलाद ढालनेवालों और अन्न पैदा करनेवालों की एकता के बल पर राष्ट्र को मजबूत करना। इस तरह की स्थायी और अपरराज्य एकता हिन्दी से कायम हो सकती है, अंग्रेजी से नहीं।

कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव में इस तरह की एकता पर ध्यान नहीं दिया गया। उसमें भरोसा किया गया है अखिल भारतीय सेवाओं में लग हुए नौकर-शाहों का। प्रस्ताव में एकता का माध्यम हिन्दी नहीं, अंग्रेजी है। अंग्रेजी को हटाने के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं की गई। इसलिए इस प्रस्ताव का विरोध

ही किया जा सकता है, स्वागत नहीं।

समाम प्रादेशिक भाषाओं को अंग्रेजी की गुलामी से मुक्त करने के दो उपाय हैं—

(१) केन्द्र में अंग्रेजी की जगह हिन्दी हो, राज्यों में प्रादेशिक भाषाएँ राजभाषा हो,

(२) राज्यों में तो प्रादेशिक भाषाएँ राजभाषा हो ही, केन्द्र में भी अंग्रेजी की जगह उन सबका व्यवहार हो।

पहला उपाय ज्यादा व्यावहारिक है, मविधान के अनुकूल है। श्रीक राज-नीतिक दल उसका समर्थन भी करते हैं। किन्तु जब प्रश्न उठता है, कब तक अंग्रेजी हटाई जाएगी, तब परिवर्तन की अवधि अनिश्चित हो जाती है। नेताओं के सामने सीधा-सा बहाना है। अहिन्दीभाषी नहीं चाहते कि हिन्दी केन्द्रीय राजभाषा हो, इसलिए फिलहाल अंग्रेजी ही चलेगी।

ऐसी स्थिति में अंग्रेजी हटाने के दूसरे उपाय पर भी विचार करना चाहिए। यह उपाय कठिन है, व्यय-साध्य है, किन्तु असम्भव नहीं है। स्विटजरलैण्ड में जर्मन, फ्रांसीसी और इतालवी को समान अधिकार प्राप्त हैं। हमारे यहाँ भी केन्द्र में सभी भारतीय भाषाओं का चलन हो सकता है।

कांग्रेस के नेता कहते हैं जब तक अहिन्दीभाषी राज्य हिन्दी को स्वीकार नहीं करते, तब तक केन्द्र में अंग्रेजी चलेगी।

हिन्दीभाषी जनता उनसे कह सकती है जब तक अहिन्दीभाषी राज्य हिन्दी को स्वीकार नहीं करते, तब तक केन्द्र में सभी भारतीय भाषाओं का व्यवहार होने दीजिए।

यदि देश के नेताओं को प्रादेशिक भाषाओं से सच्चा प्रेम है तो वे केन्द्र में अंग्रेजी की जगह उनका व्यवहार क्यों नहीं करते ?

यदि भाषाओं के अवि सित होने का सवाल हो, तो कमीशन बिठाकर इस बात की जाँच कराएँ कि भारतीय भाषाओं के विकास में कौन-सी कमी रह गई है।

जो नेता भारतीय भाषाओं के अविकसित होने से परेशान हैं, उन्हें अपनी शिक्षा के स्तर पर भी ध्यान देना चाहिए।

विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दों से सम्बन्धित कठिनाई हो सकती है। लेकिन यहाँ सवाल राजकाज के लिए भारतीय भाषाओं के व्यवहार का है। क्या लोकसभा में आज तक कोई ऐसा भाषण हुआ है जिसके लिए अंग्रेजी ही माध्यम बन सकती थी, जिसकी विषयवस्तु प्रकट करने की क्षमता भारतीय भाषाओं में नहीं थी ? क्या इस बात पर विश्वास किया जा सकता है कि जिन भाषाओं में रवीन्द्रनाथ ठाकुर, सुब्रह्मण्य मारती, बल्लत्तोल, प्रेमचन्द आदि ने अपनी महान् साहित्यिक रचनाएँ की हैं, उनमें श्री लालबहादुर शास्त्री या श्री हीरेन मुर्जो या अन्य राजनीतिज्ञ अपना मन्तव्य प्रकट नहीं कर सकते ?

असल में बात यह है कि अधिकांश राजनीतिक पार्टियाँ अपने जन्मकाल से अब तक अपना अखिल भारतीय राजनीतिक कार्य अंग्रेजी में ही करती रही हैं। इनके नेता तरह-तरह के बहाने करते हैं, अपने अनुयायियों को तरह-तरह से बहकाते हैं। वे अपने दफ्तरों से अंग्रेजी निकाल नहीं पाते। जब तक जनता इनके दफ्तरों के सामने प्रदर्शन न करेगी, इनके केन्द्रीय भवनों से अंग्रेजी निकालने के लिए इन पर दबाव न डालेगी, तब तक ये नेता अपनी नीति से बाज न आएँगे। भारतीय जनतन्त्र के मंचालक ये ही लोग हैं। वे अपने पार्टी-कार्यों में अंग्रेजी से चिपके हुए हैं। तब सरकारी दफ्तरों और विश्व-विद्यालयों से अंग्रेजी क्या खाकर निकालेंगे ?

इस समय नेता लोग देश में हुवा बांधे हैं कि अंग्रेजी के बिना न राष्ट्रीय काम चल सकता है, न अन्तर्राष्ट्रीय। यह हुवा सिर्फ ऊपर-ऊपर है। गरीब जनता का काम तो अंग्रेजी के बिना ही चलता है। ऐसी हालत में जो राजनीतिक पार्टी अपने केन्द्रीय राजकाज में अंग्रेजी का चतन खरम करती है, वह देश की बहुत बड़ी सेवा करती है। वह लोगों में आत्मनिर्भरता की चेतना दृढ़ करती है। वह अंग्रेजी प्रेमियों को दिखता देती है कि अंग्रेजी के बिना भी काम चल सकता है।

श्री कामराज नाडार कांग्रेस के अध्यक्ष होते हुए भी तमिल में भाषण करते हैं। इसका देश में विघटन पैदा नहीं हो गया। क्या ही अच्छा हो यदि राष्ट्रसंघ में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के नेता एक बार श्री कामराज हो और वहाँ जाकर तमिल में भाषण करें।

सोवियत संघ के प्रतिनिधि मन्थूल्स्की ने एक बार राष्ट्रसंघ के सामने उक्रेनी में भाषण किया था। तब श्री कामराज वहाँ तमिल में भाषण क्यों नहीं कर सकते ? मिस्र के अध्यक्ष श्री नासिर राष्ट्रसंघ के सामने अरबी में भाषण कर सकते हैं तो हमारे सम्मान्य प्रधानमन्त्री अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन के सामने हिन्दी में भाषण क्यों नहीं कर सकते ? भारतीय भाषाओं के व्यवहार में अन्तर्राष्ट्रीय भाईचारा कमजोर नहीं होता, वरन् मित्र-देशों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। पिछले दिनों जब प्रधानमन्त्री सोवियत संघ गए, तब जगह-जगह हिन्दी वाक्यों से सजे हुए बन्दनधारों से उनका स्वागत किया गया। इससे सोवियत-भारत मैत्री कमजोर नहीं हो गई।

क्या ही अच्छा होता यदि काग्रस कार्यसमिति स्वयं अपने लिए एक प्रस्ताव पास करती कि भविष्य में उसका काम अंग्रेजी में न होगा, भारतीय भाषाओं में ही होगा।

भारतीय जनतन्त्र के कर्णधार हमारे सीमित साहित्यिक अनुभव की ओर भी दृष्टिपान कर लें।

भारतीय भाषाओं ने एक-दूसरे को प्रभावित किया है, विभिन्न प्रदेश सांस्कृतिक स्तर पर एक-दूसरे के निरुद्ध आए हैं; रवीन्द्रनाथ ठाकुर से लगभग

सभी प्राधुनिक भाषाओं के लेखक न्यूनाधिक प्रभावित हुए हैं, शरत्चन्द्र और प्रेमचन्द की रचनाओं से करोड़ों पाठक परिचित हैं—यह सब अंग्रेजी के कारण सम्भव नहीं हुआ। जो गीत श्रीनगर से कन्याकुमारी तक—और देश की सीमाएँ पार करके वेदाघर से सिहल तक—गूँजे हैं, वे अंग्रेजी के सम्पर्क-भाषा होने के कारण नहीं।

अंग्रेजी के बिना भी काम चल सकता है। अंग्रेजी के बिना ही काम चलेगा। स्वाधीन भारत में अंग्रेजी नहीं चनेगी।

भारत सरकार लोकसभा में सभी भाषाओं में बोलने और भाषणों के अनुवाद की व्यवस्था करे। लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही, कानून, मसौदे—सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हों, अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय भाषाओं का व्यवहार हो। कांग्रेस की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि इस सारे परिवर्तन का भार उठाये। अहिन्दीभाषी जनता हिन्दी नहीं चाहती, यह बहुर बह अफ़्फ़ी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती।

एक बार लोकसभा में जब हमारे प्रतिनिधि भारतीय भाषाओं में बोलेंगे, तब उनका अंग्रेजी मोह कम होगा। तब उन्हें बाध होगा कि हिन्दी से अग़्य भाषाओं का दमन नहीं होता, वरन् उनसे राष्ट्रीय एकता दृढ़ होती है। एक बार जब उन्हें विश्वास हो जाएगा कि उनकी भाषा को वही अधिकार प्राप्त है, जो हिन्दी को है, तब वे स्वेच्छा से हिन्दी बोलेंगे। जब तक अंग्रेजी अनिवार्य राजभाषा बनी हुई है, तब तक स्वेच्छा से हिन्दी बोलने की बात उनकी समझ में न आएगी।

जो लोग सचमुच चाहते हैं कि अहिन्दीभाषी राजनीतिज्ञ स्वेच्छा से हिन्दी को केन्द्रीय भाषा मानें, वे अब तक जनता के सामने कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रख सके जिससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो। वे समझते हैं कि 'फ़िलहाल' अंग्रेजी कायम रखने से अपने आप अहिन्दीभाषियों में 'स्वेच्छा' उत्पन्न हो जाएगी। पिछले पन्द्रह साल का अनुभव कुछ दूसरा है। अंग्रेजी की जड़ें और मजबूत हुई हैं। शिक्षित वर्ग के सामने से स्वेच्छापूर्वक हिन्दी अपनाने की बात दूर चली गई है। इस स्थिति का मूल कारण है अंग्रेजी की पालपोसकर मजबूत करने की नीति। अहिन्दीभाषी राजनीतिज्ञों के हिन्दी विरोध का कारण यह नहीं है कि उन पर जबदस्ती हिन्दी लादी गई है। हिन्दी विरोध का कारण यह है कि वे 'स्वेच्छा' से अपने ऊपर अंग्रेजी लादे रखना चाहते हैं।

इसी समझ का बदला है।

सभी भारतीय भाषाओं को केन्द्र में समान अधिकार प्राप्त हो—इस माग़ार पर अंग्रेजी के विरुद्ध सभी सच्चे भारतीय भाषा प्रेमियों की एकता स्थापित की जा सकती है।

राष्ट्र के नेताओं से निवेदन है जब तक अहिन्दीभाषी नेता केन्द्रीय राज-भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार नहीं करते, तब तक सभी भारतीय भाषाओं

को केन्द्रीय राजभाषा बनाए रहिए। अंग्रेजी हटाने का यह कार्यक्रम अगले पाँच वर्ष में पूरा कीजिए। पूर्व-निश्चित अवधि के पन्द्रह वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। पाँच वर्ष की अतिरिक्त अवधि काफी है। शिक्षाक्रम में अंग्रेजी को वैकल्पिक बनाइए। केन्द्रीय सेवाओं तथा विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी की अनिवार्यता पाँच साल में खत्म कीजिए।

अंग्रेजी की दासता से भारतीय भाषाओं को मुक्त करना हर देशभक्त का पवित्र कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूरा करके राष्ट्र के नेता जन्ता के श्रद्धाभाजन बनेंगे। इसके विपरीत यदि उन्होंने अंग्रेजी को राजभाषा बने रहने दिया तो भावी विघटन के लिए उन्हीं को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। (१९६५)

## प्रगतिशील साहित्यकार और भाषा-समस्या के जनतांत्रिक समाधान

प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन के आरम्भ में उसकी भाषा-सम्बन्धी मान्यताएँ वही थीं जो गांधीजी के नेतृत्व में चलनेवाले राष्ट्रीय आन्दोलन की थीं। अंग्रेजी की जगह हिन्दी या हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा होगी, हिन्दी-उर्दू मूलतः एक ही भाषा हैं और उन्हें मिलाना प्रगतिशील लेखकों का कर्तव्य है, ये मान्यताएँ प्रेमचन्द के भाषणों में थीं। उस समय हिन्दी-उर्दू हिन्दुस्तानी का लेखक औरदार बहस हाँती थी। हिन्दी-उर्दू बुनियादी तौर से एक ही भाषा हैं, इस बात को प्रायः सभी लेखक मानते थे। यह मान्यता नयी नहीं थी। बालमुकुन्द गुप्त जैसे लेखक बहुत पहले इस मान्यता को स्पष्ट शब्दों में प्रकट कर चुके थे। वहम इस चीज को लेकर थी कि हिन्दुस्तानी भाषा बन चुकी है या बनाई जाय, उसका रूप उर्दू के अधिक निकट है या हिन्दी के, हिन्दी-उर्दू को मिलाने के लिए लिपि कौन-सी हो।

हिन्दीभाषी प्रदेश में उस समय प्रगतिशील साहित्यिक आन्दोलन के संगठनकर्ता और समोजक ज्यादातर उर्दू के लेखक थे। प्रेमचन्द हिन्दी-उर्दू दोनों के लेखक माने जाते थे। सन् '३६ में, इस नये साहित्यिक आन्दोलन के आरम्भ में ही, उनका देहान्त हो गया। अब इसके नेतृत्व में ऐसा लोग रह गये जो या तो उदीयमान साहित्यकार थे जैसे श्री अली सरदार जाफरी या साहित्यकार कम और आन्दोलनकारी ज्यादा थे जैसे डॉ० अब्दुल अल्ल म और श्री सैयद सज्जाद जहीर।

'६३ में बलबत्ते में दूसरा अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक-सम्मेलन हुआ। इसमें डॉ० अब्दुल ग़ालीम ने 'हिन्दुस्तानी की समस्या' नाम से अंग्रेजी में एक निबन्ध पढ़ा। इसमें उन्होंने कहा कि हिन्दी-उर्दू दो भाषाएँ नहीं हैं बरन् वे एक ही भाषा के दो साहित्यिक रूप हैं। हिन्दुस्तानी उस प्रदेश की भाषा है जिसे पुराने जमाने में लोग हिन्दुस्तान कहते थे। इस प्रदेश के उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में पंजाब और पूर्व में बंगाल है। मुगल छावणियों की ज़बान को ज़बान ए उर्दू-ए-मुग़ल्ला, संक्षेप में उर्दू, कहा जाता था।

“इसका प्रचलित नाम हिन्दी था जो प्रारम्भिक मुस्लिम विद्वानों का दिया हुआ था और जिसका अर्थ था हिन्द की भाषा।” अब्बर के जमाने में प्राकृतों पर फारसी का असर पड़ने लगा। “यह असर डालनेवाले खत्री और कायस्थ थे जिन्होंने फारसी सीखी। फारसी राजभाषा थी। वे अपनी ग्राम बोलचान में फारसी के लफ्जों से ही इस्तेमाल करने लगे जैसे कि ज्यादातर पढ़े-लिखे लोग आजकल अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल करते हैं।” १७१६ ई० में दक्खिन के शायर बली का काव्य-संग्रह दिल्ली पहुँचा। उत्तर के प्रारम्भिक मुस्लिम कवियों ने ज्यादातर पुराने भारतीय छन्दों का प्रयोग किया था। दक्खिन के कवि फारसी की बहरेँ इस्तेमाल करते थे। “आश्चर्य की बात है कि उत्तर के शायरों की कविता का यह नया ढंग इतना अच्छा लगा कि वे दिल्ली की ज्यादा शुद्ध भाषा में (यानी उस भाषा में जो ज्यादा फारसी-मिश्रित नहीं थी) बली के रंग-ढंग की नकल करने लगे। तभी से दोनों में भेद शुरू हुआ जो अब बढ़ते-बढ़ते बहुत चौड़ी खाई बन गया है।”

डॉ० अलीम की ये स्थापनाएँ बहुत महत्वपूर्ण थीं। वह एक खास प्रदेश की भाषा को हिन्दुस्तानी कहते थे। इस प्रदेश का पुराना नाम हिन्दुस्तान था, यह उन्होंने ठीक कहा था। तुर्क लेखकों शासकों इतिहासकारों ने हिन्दुस्तान शब्द का बराबर प्रयोग किया है। डॉ० अलीम ने भाषा का सम्बन्ध किसी धर्म से नहीं जोड़ा। उन्होंने बोलचाल की भाषा में फारसी शब्दों की आमद का बहुत सही कारण बतलाया। उन्होंने हिन्दू मुस्लिम संस्कृतियों के मिल से नयी भाषा बनने की बात नहीं की। फारसी के शब्द बोलचाल की भाषा में इसलिए नहीं आए कि वे हिन्दू-मुस्लिम-मिलन के लिए आवश्यक थे। वे इसलिए आए कि फारसी राजभाषा थी और इस राजनीतिक-सांस्कृतिक प्रभाव के कारण बोलचाल की भाषा में बहुत से फारसी शब्द घुल मिल गए। लेकिन बोलचाल की भाषा का साहित्यिक रूप एक ही था। उसके दो रूप तब हुए जब बली की नकल करने-वाले उत्तर के कवियों की रचनाओं में फारसीयत का रंग गाढ़ा होने लगा। उर्दू का यह साहित्यिक विकास अठारहवीं सदी की घटना है और मुसलमानों के भारत आने में, भारत में हिन्दू-मुस्लिम संस्कृतियों के मिलन से या इस्लाम से उसका कोई सम्बन्ध न था।

यह एक सही वैज्ञानिक और साम्राज्य विरोधी दृष्टिकोण था। गिलक्रिस्ट और ग्रियर्सन उर्दू-हिन्दी का सम्बन्ध धर्म से जोड़ चुके थे। डॉ० अलीम ने उस सम्बन्ध को अस्वीकार करके भाषा-समस्या के वैज्ञानिक विवेचन और सही समाधान की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया था। धर्म को आधार मानकर कोई समस्या हल नहीं की जा सकती, न लिपि की, न शब्दों के चुनाव की। हिन्दी-उर्दू समस्या पर जो भी विचार करें, उसे शुरुआत इस सूत्र से करना चाहिए कि वे एक ही जाति की भाषा हैं, धर्म के आधार पर हिन्दू-मुस्लिम दो कौमों नहीं हैं, उर्दू और हिन्दी का बुनियादी बोलचाल का रूप एक है।

हिन्दी-उर्दू में भेद होते हुए भी उनके साहित्य में बहुत बड़ी समानता है। डॉ० अलीम के लेख में इस समानता पर जोर नहीं है। उन्होंने हिन्दी और उर्दू को कृत्रिम रूप कहकर घटा बता दी। इससे हिन्दी और उर्दू के प्रगतिशील लेखक हिन्दी-उर्दू साहित्य को प्रभावित करने के बदले उससे अपने को अलग कर सकते थे। उन्होंने भीर भ्रमन और लल्लूजी लाल के बाद नमाम साहित्यिक विकास को हिन्दुस्तान के विकास के लिए घातक बनाया। उन्होंने कांग्रेस को फटकारा कि इतने दिन से हिन्दुस्तानी की माना जयने के बाद भी उसके विकास के लिए उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने इलाहाबाद की हिन्दुस्तानी अकादमी को सुभाषा कि वह हिन्दुस्तानी के विकास की योजना बनाए। उन्होंने 'हिन्दी अथवा हिन्दुस्तानी' शब्दों का व्यवहार हानिकारक बताया (क्योंकि इसमें हिन्दुस्तानी का सम्बन्ध हिन्दी से जुड़ता था)। प्रगतिशील लेखकों से उन्होंने कहा, मुख्य समस्या यह है कि हिन्दुस्तानी अभी विकसित साहित्यिक भाषा नहीं है; भाषा लोगों को उसे विकसित कर देना चाहिए। पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी से लेने की सलाह दी जो उनकी समझ में अधिकांश सम्य देशों की भाषाओं में सामान्य थे। लिपि की समस्या, डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी की राय का समर्थन करते हुए उन्होंने रोमन लिपि अपनाकर हल करने की सलाह दी।

रोमन लिपि अपनाने में उन्हें सबसे बड़ा लाभ यह दिखाई दिया, "इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि अपनी लिपियों को छोड़ देने से अपने बहुत से पुराने साहित्य से हमारा सम्बन्ध अपने घाप टूट जाएगा। धार्मिक पुनरुत्थानवादी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोग अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं के धामूल परिवर्तन में विश्वास करते हैं। हम अपने साहित्य की बुद्धिसमन बनाने में (इन रैशनलाइजिंग अवर लिटरेचर) विश्वास करते हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसी लिपि अपनाएँ जो सबसे ज्यादा वैज्ञानिक हो और जिसे अपनाकर हम आधुनिक ससार को आवश्यकताएँ पूरी कर सकें।"

इस प्रकार डॉ० अलीम का दृष्टिकोण पुरानी साहित्यिक विरासत की तरफ बिल्कुल अस्वीकृति का था। यह दृष्टिकोण वास्तव में साम्राज्यवादी लेखकों का रहा है जो भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों की हमेशा अपमान्य करते रहे हैं। लार्ड मैकाले ने कुछ ऐसी ही बातें अपने प्रसिद्ध निबन्ध में कही थीं। डॉ० अलीम भारत की अन्य भाषाओं के साहित्य से अपरिचित थे; वह हिन्दी पढ़ लेते हैं लेकिन कम-से-कम सन् '३८ में जब उन्होंने यह निबन्ध लिखा था, तब वह हिन्दी साहित्य के विकास से अपरिचित थे। उनके मुख्य सलाहकार श्री मुल्कराज धानन्द भारतीय साहित्य की प्रगति से और भी कोरे थे। प्रेमचन्द के प्रभाव में ऐसा कोई लेखक नहीं था जो इन्हें सर्वांगतावाद में बंधाना। राष्ट्रीय धान्दोलन में आधुनिक साहित्य का सम्बन्ध न समझने के कारण उन्होंने हिन्दी-उर्दू के साहित्य के प्रति यह सर्वांग दृष्टिकोण अपनाया। राष्ट्रीय धान्दोलन और भारतीय साहित्य में नव-जागरण की न समझने के कारण वे बहुत जल्दी ऐसे

प्रगतिशील साहित्यकार और भाषा-समस्या के जनतांत्रिक समाधान / ९



नेताओं के प्रभाव में आ गए जो आत्मनिर्णय के नाम पर मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का समर्थन करते थे ।

इन नये नेताओं में श्री सैयद सज्जाद जहीर मुख्य थे । सन् '३८ में प्रखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के मंत्री डॉ० अब्दुल अलीम थे, द्वितीय महा-युद्ध के दौरान उसके मंत्री हुए सज्जाद जहीर साहब । डॉ० अलीम की तुलना में वह साहित्यकार कुछ ज्यादा थे । उनका 'लन्दन की एक रात' उपन्यास सन् '३८ के आस पास छप चुका था । सन् '४३ से सन् '४६ तक वह कम्युनिस्ट पार्टी के भूतपूर्व नेता श्री पूरन जोशी के दाहने हाथ रहे । मुस्लिम समस्या पर उन्हें सलाह देने के अलावा श्री जोशी की आत्मनिर्णय वाली नीति को वह मुसलमानों में लागू भी करते थे । उस समय कम्युनिस्ट पार्टी का नारा था, कांग्रेस लीग एक हो । यह नारा इस समय के आधार पर दिया गया था कि भारत में दो राष्ट्र या दो तरह की राष्ट्रीयता विकसित होती रही हैं—एक हिन्दुओं की, दूसरी मुसलमानों की । इन दोनों को मिलकर अंग्रेजों से सत्ता देने की माँग करना चाहिए ।

मुसलमानों की अलग कौम है, उसे आत्मनिर्णय का अधिकार यानी देश से अलग होकर अपना राज्य बनाने का हक मिलना चाहिए, इस सिद्धान्त को भाषा-क्षेत्र में लागू किया जाय तो यह नतीजा निकलेगा ही कि हिन्दुओं की भाषा हिन्दी है, मुसलमानों की भाषा उर्दू है ।

हिन्दी-उर्दू में भेद क्यों हुआ ? इसलिए कि हिन्दुओं ने उर्दू का ढाँचा लेकर उसमें उन शब्दों को भरा जिनका सम्बन्ध हिन्दू संस्कृति से था ।

हिन्दी-उर्दू-हिन्दुस्तानी समस्या का हल' नाम के निबन्ध में श्री सज्जाद जहीर ने लिखा, "आधुनिक हिन्दी ने बड़ी बोली का ढाँचा उर्दू से लिया और उसमें उसने उन शब्द-योजनाओं और परम्पराओं से उसे अनुप्राणित किया, जो हिन्दू संस्कृति के अभिन्न अंग थे ।"

आधुनिक युग में राष्ट्रीयता का अर्थ क्या है ? राजा राममोहन राय ने 'अंग्रेज ईसाई मिशनरियों के हमले से हिन्दू धर्म को बचाने के लिए' ब्राह्म-समाज की नींव डाली । इसका प्रभाव आधुनिक बंगाली संस्कृति के विकास पर पड़ा और बंगाल के 'इसी आन्दोलन से प्रभावित होकर हिन्दी साहित्य के प्रथम मजारथी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अपना आन्दोलन शुरू किया । उनकी रचनाओं ने 'मध्यवर्ग के शिक्षित हिन्दुओं के हृदय में वह नैराश्य और विपाद दूर कर दिया जो पराधीनता के कारण देश में छा गया था ।' भारतेन्दु ने 'प्राचीन हिन्दू महापुरुषों और देवताओं को रंगमंच पर लाकर हिन्दुओं को उनके विगत वैभव' की याद दिलाई, 'हिन्दू-समाज की बुराइयों' की आलोचना की ।

इस प्रकार 'हिन्दी उत्तर भारत में (विशेषकर युक्त प्रान्त, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रान्त के हिन्दुस्तानी भाग में) हिन्दू राष्ट्रीय जागरण का—जिसके विभिन्न पक्ष अथवा रूप धर्मोद्धार, धर्म-सुधार, समाज सुधार और नवीन

शिक्षा-प्रचार हैं—एक शक्तिशाली माध्यम बन गई।”

श्री मज्जाद जहीर ने भारतेन्दु युग के साहित्य में जो साम्राज्य-विरोधी तत्त्व थे, जिनका सम्बन्ध हिन्दू-समाज से ही नहीं, सारे भारत से था, उन्हें मज्जादशज किया। उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि भारतेन्दु, प्रताप-नारायण पिथ और बालमुकुन्द गुप्त जैसे हिन्दी लेखक उर्दू में भी लिखते थे। उन्होंने गिलफ्रिस्ट और ग्रिमसन से दो कदम आगे बढ़कर धर्म के आधार पर साहित्य और भाषा का बँटवारा कर दिया। जो धार्मिक भावनाएँ पुराने साहित्य में रही हैं, उन्हें उस साहित्य का एक पक्ष न मानकर, उन्होंने उन भावनाओं को राष्ट्रीय जागरण का मुख्य चिह्न मान लिया।

कही उनके दिमाग में एक पुराना बीड़ा भी रेंग रहा था। यह मुस्तक़ा जवान का बीड़ा था। हिन्दुओं और मुसलमानों के मेल-जोल से उर्दू का जन्म और विकास हुआ। इस सम्मिलित विकास को खत्म कर दिया सम्प्रदायवादी हिन्दुओं ने।

“उर्दू अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दी में उत्तर और मध्य भारत के सम्मिलित सामाजिक जीवन के सांस्कृतिक आदान-प्रदान की स्वाभाविक माध्यम बन गई थी।” उर्दू लेखकों में रतननाथ सरस्वार जैसे हिन्दू थे। पुराने पश्चिमोत्तर प्रान्त—आज के उत्तर प्रदेश—में १८६६ में चौबीस पय निकालते थे, उन्नीस उर्दू में, तीन हिन्दी-उर्दू दोनों में। इनमें अधिकांश के मालिक और सम्पादक हिन्दू थे। १८७१ में अवध में जो विद्यार्थी उर्दू पढ़ते थे, उनमें ज्यादातर हिन्दू थे। “अतः उर्दू भाषा और उसकी लिपि के विरोध और बहिष्कार को लेकर जो हिन्दी नागरी आन्दोलन आरम्भ हुआ, इसको अपने समाज और संस्कृति पर हिन्दुओं की ओर से अन्यायपूर्ण, सङ्कुचित, साम्प्रदायिक प्रहार समझना मुसलमानों के लिए स्वाभाविक था।”

हिन्दुओं और मुसलमानों के सांस्कृतिक आदान-प्रदान का माध्यम उर्दू बनी। यह कार्य भी स्वाभाविक था। हिन्दी-आन्दोलन को मुसलमानों ने अन्यायपूर्ण समझा, यह भी स्वाभाविक था। हिन्दी हिन्दुओं की सांस्कृतिक भाषा बनी, यह भी स्वाभाविक था।

ये तीन स्वाभाविक त्रिघाट एक साथ कैसे हो गई? जहीर साहब के अनुसार हिन्दुओं और मुसलमानों की मूलतः दो संस्कृतियाँ हैं। इनको आगे चलते अलग-अलग विकसित होना ही था। “आरम्भ से ही मुसलमानों के निकट हिन्दी और देव-नागरी लिपि आन्दोलन हिन्दुओं की कट्टर साम्प्रदायिकता और मुस्लिम संस्कृति-विरोध का द्योतक रहा है।” इसलिए “१९०० में जब देवनागरी भी उर्दू के समान आदेशतो में जारी हो गई, तो मर सैयद को विश्वास हो गया कि ‘अब हिन्दुओं और मुसलमानों का एक राष्ट्र होकर अपने अस्तित्व के लिए सम्मिलित प्रयत्न करना असम्भव हो गया है।’ उसी समय उर्दू-रक्षा-समिति मर सैयद के तत्वावधान में कायम हुई।”

मुसलमानों का मतलब राष्ट्र हो, उर्दू की रक्षा का प्रयत्न किया जाय—दोनों बातों का उल्लेख साथ-साथ किया गया है। श्री सज्जाद जहीर के पास हिन्दी-उर्दू विरोध का हल क्या है? या अठारह साल पहले उनके पास कौन-सा हल था? उनके पास वही हल था जो सर सैयद अहमद खाँ ने बताया था और जिसका सर मुहम्मद इकबाल ने नये सिरे से प्रचार किया था।

उर्दू हिन्दुओं और मुसलमानों की एकमात्र मिली-जुली भाषा न रह सकी। कारण था हिन्दुओं की साम्प्रदायिक कट्टरता। इसलिए हिन्दू अलग, मुसलमान अलग, एक राष्ट्र की भाषा हिन्दी, दूसरे की उर्दू।

जिसे राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान साम्प्रदायिकता कहा जाता था, उसी को श्री सज्जाद जहीर और उनके सहयोगी श्री पूरनचन्द जोशी राष्ट्रीयता कहने लगे। हिन्दू राष्ट्रवाद, मुस्लिम राष्ट्रवाद—ये दो नये ढंग के राष्ट्रवाद सामने आए। एक का प्रचार मुस्लिम लीग ने किया, दूसरे का, उससे पीछे, उसके चरणचिह्नो पर चलकर, हिन्दू महासभा और जनसंघ ने। इन्हे मार्क्सवाद के नाम पर वैज्ञानिक ठहराया श्री सज्जाद जहीर ने।

मुसलमानों ने हिन्दी-आन्दोलन का विरोध किया। 'इस व्यापक विरोध को समझने के लिए हमें यह जानना चाहिए कि मुसलमानों के लिए उस समय यह समझना कठिन था कि हिन्दी नागरी आन्दोलन हिन्दुओं के देशव्यापी सांस्कृतिक नवोत्थान का ही एक अंग था।' यह हिन्दुओं का नवोत्थान जारी रहा और उसे आगे बढ़ाया महात्मा गांधी ने।

चीकने की बात नहीं है। गांधीजी के राष्ट्रीय आन्दोलन को जिन्ना साहब हिन्दू आन्दोलन कहते थे या नहीं? फील्ड मार्शल अय्यूब खाँ हिन्दू भारत से मुस्लिम कश्मीर को आजाद कराने का जेहाद शुरू कर चुके हैं या नहीं? ब्रिटिश प्रचारक कहते हैं या नहीं कि श्री लालबहादुर शास्त्री पाकिस्तान से इसलिए लड़ रहे हैं कि वह हिन्दू हैं?

जहीर साहब के वैज्ञानिक विवेचन के अनुसार "सन् १९२० में जब राष्ट्रीय जागरण की एक नयी लहर कांग्रेस और महात्मा गांधी के नेतृत्व में उठी, तो इसके बाद हिन्दुओं में हिन्दी का और भी अधिक प्राप्ताह्न मिला। बाबू मैथिली-शरण गुप्त ने अपना सुप्रसिद्ध काव्य 'भारत-भारती' इसी युग के आस पास (सन् १९१३) में लिखा। यह कविता उन गांधीवादी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती है जो इस समय उत्तरी भारत के हिन्दुओं को आन्दोलित कर रही थी।"

सन् '२० में जो राष्ट्रीय जागरण की नयी लहर उठी, उसने सात साल पहले की रचना 'भारत-भारती' को प्रभावित किया और इसमें वे गांधीवादी भावनाएँ हैं जो उस समय के हिन्दुओं को आन्दोलित कर रही थी।

उधर 'हिन्दुओं के ही समान उत्तरी भारत के मुसलमानों में राष्ट्रीय जागरण' की लहर उठ रही थी। इस राष्ट्रीय जागरण का सम्बन्ध गांधीजी के आन्दोलन से नहीं है। बीसवीं सदी के आरम्भ में 'राजनीति' जागरण के

साथ साथ स्वतन्त्रता का भाव भी मुसलमानों में जागने लगा ।” राजनीतिक जागरण ? क्या यह गांधीजी के आन्दोलन से बाहर कोई जागरण था ? स्वतन्त्रता का भाव ? किससे ? अंग्रेजों से या हिन्दुओं से या दोनों से ? उर्दू साहित्य ने नई करवट ली “और शिवली जफर अली खाँ, अबुल कलाम और अन्त में इकबाल ने मुसलमानों के नवीन जागरण को व्यक्त किया ।”

अबुल कलाम आजाद मुसलमानों के ‘राष्ट्रीय’ जागरण के नेता कंसे बने, यह नहीं बताया गया । मुझे याद है, सन् ‘४७ के आस-पास इस तरह के ‘राष्ट्रीय’ जागरण की चर्चा करनेवाले सम्भते थे कि कांग्रेस और गांधीजी का साथ देने-वाले मुसलमान गुमराह हैं, वे मुस्लिम इत्तहाद को तोड़नेवाले लोग हैं । मुसलमानों के असली नेता कायदे आज़म जिन्ना और अन्य मुस्लिम लोगी हैं । किंतु इकबाल ने राष्ट्रियता के साथ सहारी करके साम्प्रदायिकता को अपनाया, स्वभावतः उसकी आलोचना श्री जहीर के लेख में नहीं है यद्यपि बहुत से उर्दू लेखकों ने इसके लिए इकबाल की आलोचना की थी ।

नतीजा यह कि “आधुनिक उर्दू की तरक्की हिन्दुस्तानी मुसलमानों के विगत सौ वर्षों के राष्ट्रीय जागरण से सम्बद्ध है ।” राष्ट्रीय जागरण से सम्बद्ध है तो नया राष्ट्र बनेगा ही, जहीर साहब के अनुसार उर्दू का सारा विकास पाकिस्तान की ओर—भारत के विभाजन की ओर—सकेत करता था । हिन्दू सम्प्रदायवादी भी उर्दू के दमन के पक्ष में यही तर्क देते थे । मुश्किल यह थी कि उर्दू के लेखकों में प्रेमचन्द भी थे, वह दाना राष्ट्रीय जागरणों में हिस्सा बँटा रहे थे । क्या कारण है कि किसान जीवन के अमर चित्रकार प्रेमचन्द के सामने होते हुए श्री सज्जाद जहीर जैम मार्क्सवादी हिन्दी उर्दू साहित्य का सम्बन्ध हिन्दू और मुस्लिम राष्ट्रवाद यानी सम्प्रदायवाद से जोड़ने लगे ? कारण है ग्राम जनता से अलगत्व । उनका जन्म अभिजात वर्ग में हुआ । अपने वर्ग के संस्कार मिटाने के लिए उन्हें ग्राम जनता से जैसा सम्पर्क कायम करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया । ग्राम जनता में काम किए बिना ही वह बहुत जल्दी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बन गए । श्री पूरनचन्द जोशी हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहे हैं जो आला खानदान के हो, बिलायत जाकर पढ़े हो, दिमाग के बच्चे हो जिसमें कि उनकी नयी-नयी स्थापनाएँ आसानी से मान लें । श्री सज्जाद जहीर बहुत अच्छे लेखक, बहुत अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता बन सकते थे यदि श्रीमान् पूरनचन्द जोशी ने उन्हें बिगाड़ा न होता ।

इसलिए ‘गोदान’ की तारीफ करने के बाद इस सम्प्रदाय के तरक्की पसन्द भदीब कहते थे कि जब प्रेमचन्द तरक्की पसन्द बन रहे थे, तभी वह स्वर्गवासी हो गए । प्रेमचन्द के विश्वास को वे झिलझिल न समझते थे । उनका साहित्य हर तरह के सम्प्रदायवाद पर कितना अवदस्त प्रहार है यह उन्हें बिल्कुल दिखाई न देता था । एक मित्र ने छह-सात साल पहले अपने एक भाषण में कहा था कि प्रेमचन्द हिन्दुओं की आलोचना तो कर लेते थे, मुसलमानों की आलोचना करते

जैसे उन्हें डर लगता था। मैंने 'समालोचक' में इन हिन्दी लेखक मित्र के आरोप का विस्तार से जवाब दिया था। उन्हीं की तरह '४३-'४७ में बम्बई के कुछ राज-नीतिज्ञ प्रेमचन्द के बारे में कहते थे कि वह महज हिन्दू समाज-सुधारक थे।

दिलचस्प बात है कि 'भारत-भारती' पर जहीर साहब ने स्वर्गीय रामचन्द्र शुक्ल की सम्मति उद्धृत की है। इस सम्मति में कहा गया है, "सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यतावाद, विश्वप्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान, सबकी भूलक हम पाते हैं।"

इमें भी उन्होंने हिन्दुओं को आन्दोलित करनेवाली गांधीवादी भावनाओं के प्रमाणस्वरूप पेश किया है।

आधुनिक उर्दू साहित्य में फिराक गोरखपुरी, कृष्णचन्दर, राजेन्द्रसिंह बेदी जैसे गैर-मुसलमान लेखक भी हैं। सम्प्रदायवादी बहते हैं कि ये आधे मुसलमान हैं। जहीर साहब की राय यह थी कि "उर्दू साहित्य का अधिकांश पहले भी, और आज और भी अधिकतर मुसलमानों से सम्बन्ध रखता है, और इसी कारण उर्दू साहित्य ने अधिकांश भाग पर मुसलमानों की सम्यता और संस्कृति की छाप है। बिल्कुल ऐसा ही हिन्दी के अधिकांश भाग पर हिन्दू सम्यता के प्रभाव स्पष्ट हैं।" इस तरह प्रेमचन्द, फिराक, बेदी, कृष्णचन्दर वगैरह-वगैरह के बाव-जूद श्री सज्जाद जहीर ने साहित्य को हिन्दू-मुस्लिम सम्यता के आधार पर दो हिस्सों में बांट दिया।

उनके दिमाग पर धार्मिक पुनरुत्थानवाद का इतना गहरा रंग चढ़ा हुआ था कि हिन्दी-उर्दू साहित्य में उन्हें हिन्दू-मुस्लिम सम्यता के अलावा और कुछ दिखाई ही न देता था।

हिन्दू सम्प्रदायवादियों से जब कोई कहता है कि आप हिन्दू धर्म का प्रचार करते हैं, धार्मिक सकीर्णता फैलाते हैं, तो वे जवाब देते हैं कि हमारा तात्पर्य धर्म से नहीं है, हिन्दुत्व एवं जीवन-पद्धति है, वह इस देश की जीवन-पद्धति है, जो उसे माने वह हिन्दू।

जहीर साहब ने लिखा था, "जब मैं हिन्दू संस्कृति या मुस्लिम संस्कृति का नाम लेता हूँ तो मेरा तात्पर्य उनके धार्मिक भेदों से नहीं है। भारतीय सम्यता को हम देश के विभिन्न भागों में विभिन्न रूप से देखते हैं, और इनमें हमें अनगिनत समानताएँ मिलती हैं। फिर भी उन इलाकों में जहाँ उर्दू या हिन्दी आम तौर से बोली जाती है, हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति का भेद, हमें उर्दू और हिन्दी के साहित्यिक रूपों में स्पष्ट दिखाई देता है।"

हिन्दू सम्प्रदायवादी बहते हैं कि सारे भारत में एक ही संस्कृति है, हिन्दू संस्कृति। जहीर साहब बहते हैं, एक नहीं, दो संस्कृतियाँ हैं। हिन्दू संस्कृति तो है ही, एक मुस्लिम संस्कृति भी है।

मुस्लिम संस्कृति किन इलाकों में है? उन इलाकों में जहाँ उर्दू बोली जाती है। क्या सिन्ध और पूर्वी बंगाल की भाषा उर्दू है? नहीं। फिर भी मुस्लिम

संस्कृति के नाम पर भारत का वह सारा हिस्सा अलग किया गया जहाँ किसी की भी मातृभाषा उर्दू नहीं है। जिनकी मातृभाषा उर्दू है वे भारत में ही हैं, इसलिए इलाकाई अजान की समस्या फिर भी बनी रह गई।

उर्दू में श्रव भी बहुत से अक्षरों से निकलते हैं जिनमें धुआंधार हिन्दू सम्प्रदायवाद का प्रचार होता है। जो उर्दू में जिसे वह भाषा मुसलमान हो जाय, यह आवश्यक नहीं है। एक ही भाषा में हर तरह के विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। भाषा और धर्म दो अलग चीजें हैं। उर्दू में फारसी के जो शब्द आए हैं वे ईरान के सांस्कृतिक प्रभाव के कारण, धर्म के कारण नहीं। फारसी मुसलमानों की धार्मिक भाषा नहीं है। उनका धर्मग्रन्थ अरबी में है। वह अरबी इस्लाम में पढ़ते भी थी, उसका जन्म इस्लाम के साथ नहीं हुआ। धर्म धर्मग्रन्थ व्यक्ति ही धर्म के साथ भाषा का सम्बन्ध जोड़ सकता है। उर्दू के इन रक्षकों को यह नहीं दिखाई देता कि कश्मीरी, सिन्धी, बंगला आदि भाषाएँ बोलनेवाले लाखों मुसलमान हैं जिनका उर्दू से कोई सम्बन्ध नहीं है।

और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जिन्होंने हिन्दी आन्दोलन और हिन्दू राष्ट्रवाद को जन्म दिया, कैसी हिन्दी लिखते थे? क्या उनकी भाषा में सभी शब्द हिन्दू होते थे?

जहीर साहब ने भारतेन्दु की भाषा शैली का बहुत सही वर्णन किया है। लिखा है "भारतेन्दुजी की भाषा पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो उसमें प्रवाह और श्रव के साथ साथ यह भी देखते हैं कि वह अपनी हिन्दी में अरबी और फारसी के प्रचलित शब्द निरसकोच प्रयोग करते हैं। उनकी रचना हिन्दी होती है उसमें संस्कृत का मिश्रण होना है, और वह राज और श्रवणी की परम्पराओं का भी दायन नहीं छोड़ती। इस दृष्टि में इसमें और सप्रति प्रचलित उर्दू गद्य की शैली में काफी अन्तर है।"

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों को छोड़ा नहीं, उनकी भाषा में संस्कृत शब्द भी होते हैं राज, श्रवणी आदि की जनपदीय और साहित्यिक परम्पराएँ उसमें जुड़ी हुई हैं—क्या हिन्दी-उर्दू की मिनी जुली साहित्यिक परम्परा इस गिन्न किमी और तरह की भाषा अपना सकती है? इस तरह की भाषा पर हिन्दू राष्ट्रवाद का कौन-सा ठप्पा लगा हुआ है? इस भाषा में उर्दू की रक्षा का मतलब क्या होना है? संस्कृत शब्दों का विलोपन, सांस्कृतिक शब्दावली केवल अरबी-फारसी से ले जाय, जनपदीय बोलियों और हिन्दी की पुरानी साहित्यिक परम्परा में अन्याय। यह उर्दू की रक्षा का नहीं, उसके विनाश का मार्ग है।

दो तरह की संस्कृतियों, दो तरह के 'राष्ट्रीय' जागरणों की मान्यताएँ प्रस्तुत करने के बाद भी जहीर साहब ने किस्मों में और मजबूर नेताओं के भाषणों में हिन्दी उर्दू का मिना-जुला रूप देखा, यह उनकी धरापत थी। जब संस्कृतियाँ हिन्दू और मुस्लिम धर्मों में विभाजित थीं, तब यह मिनी-जुली भाषा

बौद्ध-गी संस्कृति को प्रतिबिम्बित करती थी, जो न हिन्दू थी, न मुगलमान—यह उन्होंने नहीं बनाया।

बाप्रेस सींग एक हो, यह नारा भाषा के क्षेत्र में लागू करते हुए उन्होंने राय दी—“भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी और उर्दू दोनों हों।”

उन्होंने उदारता से लिखा, “उर्दू और हिन्दी के भाषा के पापेंक्य को स्वीकार करते हुए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि यह पापेंक्य कम हो।

“इसलिए आवश्यक है कि इन समय हिन्दी और उर्दू का यह भाषा-क्षेत्र जो समान रूप से दोनों का एक है, जिसे सरम उर्दू, सरम हिन्दी या हिन्दुस्तानी का नाम दिया जाता है, कायम रहे और उसकी सीमा बराबर बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय।”

हिन्दी और उर्दू युनियादी रूप में एक हैं; उनके साहित्यिक, लिप्य रूप में भाषा भेद है, उसे दूर करना चाहिए। दोनों का भाषा क्षेत्र एक है। दोनों का सामाजिक परिवेग एक है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यदि श्री जहीर ने जानि की भाषमंवादी व्याख्या पर विचार किया होता तो वह इस मनीजे पर अवश्य पहुँचते कि हिन्दी-उर्दू एक ही जानि की भाषा है, दोनों का साहित्य एक ही जानि का साहित्य है, उनमें एक ही राष्ट्रीय जागरण की भनक है, दो राष्ट्रों के जागरण की नहीं। भाषमंवाद में कहीं भी इसका प्रमाण नहीं है कि धर्म के आधार पर भाषा या जानि का निर्माण स्वीकार किया गया हो।

यदि हिन्दी-उर्दू का इलाका एक था, तो बंगाल और सिन्ध में आरमनिर्णय का अधिकार किसके लिए? फिर पाकिस्तान का समर्थन क्यों?

इन प्रश्नों का उत्तर यह है इलाका तो एक है लेकिन “उसकी सीमा बराबर बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय”।

जहीर साहब के दिमाग में नक्शा यह है कि मुसलमानों की एक भाषा है उर्दू। जो मुसलमान उर्दू नहीं बोलते, वे भी आगे चलकर उर्दू बोलने लगेंगे। मुस्लिम सस्कृति में उर्दू का सम्बन्ध जोड़ने का एक ही मतीजा होगा। भारत के सभी मुसलमानों की भाषा उर्दू हो। इसीलिए धीरे धीरे इलाका बढ़ाते जायेंगे, एक दिन सब मुसलमान उसमें सिमट आएँगे। उधर हिन्दुओं की राष्ट्रभाषा होगी हिन्दी। हिन्दू सस्कृति से हिन्दी का सम्बन्ध है, इसलिए हिन्दू मात्र की एक भाषा होगी हिन्दी। हिन्दू राष्ट्र में बंगला, मराठी तमिल आदि भाषाएँ कायम रहें तो वे राष्ट्र को खण्डित करेंगी—यही सम्प्रदायवादियों का दृष्टिकोण रहा है।

श्री सज्जाद जहीर की भाष्यताओं को श्री शिवदानसिंह चौहान ने और भी पुष्पित और पल्लवित किया।

‘राष्ट्रभाषा विवाद और समाधान’ नाम के निबन्ध में शिवदानसिंहजी ने पहले तो सम्प्रदायवादियों को फटकार बताई, कहा कि १४० साल से यह हिन्दी-उर्दू की बहस राजनीतिक उत्तेजना और ‘धार्मिक-साम्प्रदायिक उन्माद के बाता-’

बना रखा है', उन्होंने सावधान किया कि वे दिन गये जब "आर्य-भाषा" हिन्दी के समर्थक उसे हिन्दुओं की परम्परागत भाषा कहकर उसका चलन बचहरियो और दपतरो मे कराना चाहते थे, उन्होंने किंचित् खेद प्रकट किया कि "हिन्दी का नेतृत्व विशेषकर हिन्दू राष्ट्रवादियों के हाथ मे है," उधर "उर्दू का नेतृत्व विशेषकर मुस्लिम राष्ट्रवादियों के हाथ मे है।" इसके बाद उन्होंने प्रगतिवादियों की खबर ली जिन्होंने मिली-जुली भाषा हिन्दुस्तानी का समर्थन किया, "इससे उन्हें राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर गहराई से सोचने से जैसे छुट्टी मिल गई और सरल समाधानों को ही स्वीकार कर उन्होंने अपनी इतिवृत्तव्यता मान ली।"

भाषा-समस्या पर गहराई से विचार करके, सरल समाधानों को रास्ते से हटाकर सश्लिष्ट समाधानों की ओर साहम से कदम उठाते हुए श्री चौहान ने अपनी ये मान्यताएँ प्रस्तुत की—

—“सर्वप्रथम यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि हिन्दी और उर्दू दो भिन्न भाषाएँ हैं।”

—“हिन्दी और उर्दूवालों को यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये दोनों अलग अलग स्वतन्त्र भाषाएँ हैं।”

—“ये दोनों पृथक् भाषाएँ खड़ी बोली की जमीन पर संस्कृत और फारसी के खाद बीज से उत्पन्न दो पौधों के समान हैं, अतः दो भिन्न संस्कृतियों हिन्दू और मुस्लिम की प्रतीक हैं।”

ये मान्यताएँ नई नहीं हैं। हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदायवादी यही बातें कहते रहे हैं। लेकिन यह श्री शिवदानमिह चौहान का ही वृत्त था कि वह हिन्दू राष्ट्रवादियों की निन्दा करते हुए उन्हीं की स्थापनाओं को अपने जनवाद के नाम पर दोहराते चले।

उनका जनवाद धन्य है क्योंकि “हम जनवाद के उन सिद्धान्तों के आधार पर इस प्रश्न का समाधान करना चाहते हैं जिनका आधार अखंड हिन्दुस्तान अथवा विभाजित हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकारों को भी लेना पड़ेगा।”

श्री चौहान ने जनवाद पर इतनी गहराई से विचार किया था कि उन्होंने अखंड और खण्डित दोनों तरह के देश के लिए अपना अचूक समाधान प्रस्तुत किया था—

“इस समय देश में ‘पाकिस्तान’ और ‘अखंड हिन्दुस्तान’ का विवाद छिड़ा हुआ है। हमने अपने विवेचन में अखंड अथवा विभाजित भारत को लक्ष्य में रखकर कोई समाधान निकालने की चेष्टा नहीं की, क्योंकि हमारी दृष्टि में अखंड हिन्दुस्तान ही अथवा पाकिस्तान और हिन्दुस्तान अलग-अलग हो, दोनों दशाओं में राष्ट्रभाषा का वही समाधान होगा जिस पर हम अभी विचार करेंगे।”

असली चीज है जनवादी दृष्टि प्राप्त करना। गुरु-गुरु के लिये वह दृष्टि



प्राप्त हो जाती है, उसके लिए जैसे पाकिस्तान, वैसे अखंड भारत । गुरु श्री गजराज जहोरी की कृपा से यह दृष्टि मुरीद श्री चौहान को प्राप्त हो गई ।

“इस जनवादी उदार दृष्टि को प्राप्त करने पर राष्ट्रभाषा के प्रश्न का समाधान स्वतः स्पष्ट हो जाता है ।”

अब देखिए इस उदार दृष्टि के प्राप्त होने से भूत, भविष्यत् और वर्तमान तीनो कालो मे सत्य कैसा स्पष्ट दिखाई देने लगता है ।

पहले अतीत के दृश्य देखिए । भारत मे मुसलमान आए । जब ताजे थे, तब तो हिन्दू-मुस्लिम सस्कृतियों का मेल हा गया, जब यहाँ रहते रहते यही वे हो गये, तब उनकी सस्कृतियों मे भेद हा गया । और यह भेद करनेवाले थे ब्रज और अवधी के दो कवि—सूरदास और तुलसीदास ।

मुनिए हिन्दी साहित्य के विकास का यह अभिनव जनवादी विश्लेषण ।

“इसमे सन्देह नहीं कि भारत मे मुसलमानो के आगमन के पश्चात् हिन्दू-मुस्लिम सस्कृतियों मे एक लम्बी अवधि तक मुख्य आदान प्रदान और मिश्रण होता रहा ।”

ईरानियों की सस्कृति, अरबो, पठानो, उजबको की सस्कृति—सब एक-सी, सब इस्लामी सस्कृति ।

निर्गुणपथिया और प्रेम मार्गियो ने हिन्दू और मुस्लिम सस्कृतियों को मिलाया । ‘ इस संयुक्त विचार-परम्परा की कविताएँ यद्यपि सत्रहवीं शताब्दी तक होती रही परन्तु स्वामी रामानुजाचार्य के अनुयायी रामानन्द और श्री चेल्लभाचार्य ने राम और कृष्ण की सगुणोपासना की ओर परिपाटी चलाई उसने तुलसी और सूर जैसे महाकवियों को जन्म दिया जिन्होंने अवधी और ब्रज की काव्यधारा को खरीर और जायसी की हिन्दू-मुस्लिम सस्कृतियों की सम्मिलित परम्परा से एकदम अलग कर दिया । अवधी और ब्रज की काव्य परम्परा हिन्दू सस्कृति की प्राचीन काव्य-परम्पराओं की उत्तराधिकारिणी बन गई । यह हिन्दू जातीयता की नवचेतना का परिणाम था ।”

मुसलमानो के आने पर पहले तो सम्मिलित सस्कृति की धारा चली, फिर उसे सूरदास और तुलसीदास ने तोड़ दिया । यह भी अच्छा हुआ क्योंकि सत्रहवीं सदी से हिन्दू जातीयता का अस्तित्वान्धारम्भ हो गया था । इन महाकवियों ने उसे पहचाना और उसे अपने साहित्य मे अभिव्यक्त किया ।

रीति और भक्ति की काव्यधाराओं मे भले ही बहुत से मुसलमानों ने योग दिया हो, श्री चौहान के अनुसार “ये काव्यधाराएँ हिन्दू जातीयता के नवोन्मेष की प्रतीक हैं ।” इनके भाव-विचार ही नहीं, “सौन्दर्य मूल्य, छन्द रचना, ध्वनि-योजना, अलंकार-विधान” भी “संस्कृत साहित्य और हिन्दू-आर्य सस्कृति से प्रभावित और निरूपित हैं ।” चौहान ने यह नहीं बताया कि जिन कवियों ने हिन्दू-मुस्लिम सस्कृतियों का मेल किया था, उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम छन्दों का मेल कैसे किया था ।

धार्मिक हिन्दी के युग में आये। हिन्दू सस्कृति की यह परम्परा आगे भी बरकरार रही। लिखा है— सूरदास और तुलसीदास के समय में भारतभर कास तब ब्रज और मथुरा की वास्तव परम्परा में यह विचारधारा ही सर्वप्रथम बनी रही।”

धार्मिक सही बोली ने अपने से पहले की सांस्कृतिक परम्पराओं से सम्बन्ध बना जोड़ा—“सही बोली हिन्दी ने सम्स्कृत, प्राकृत और अपभ्रंशों से अपना सीधा सम्बन्ध जोड़कर शीतल, मागधी आदि अपभ्रंशों की अन्य भाषाओं के प्राचीन साहित्य को अपना प्राचीन साहित्य घोषित करके अपने को आर्य-हिन्दू परम्परा का उत्तराधिकारी सिद्ध किया। इस प्रकार हिन्दू जातीयता और तदनन्तर हिन्दू राष्ट्रियता ने अपनी जायति, मजबूत और विकास के लिए सही बोली हिन्दी के द्वारा अपना मार्ग प्रशस्त किया अपना कहें कि इस पुनरुत्थान और राष्ट्रिय चेतना में हिन्दुओं के लिए सही बोली हिन्दी माध्यम और वाहक बनी। हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों ने इस तथ्य को मुक्त बंध से स्वीकार किया है।”

शिवदानसिंहजी ने उदारतावश हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों का उल्लेख कर दिया है। वरना पहले हिन्दू जातीयता, तदनन्तर हिन्दू राष्ट्रियता के विकास का मूलम भेद किसने किया है? साधारण पाठक इस भेद को समझ भी नहीं सकते। हिन्दू जातीयता हिन्दी-भाषी क्षेत्र तक सीमित थी, इसके प्रचारक-प्रसारक सूरदास और तुलसीदास थे। सही बोली सारे भारत में फैल गई, यह हिन्दुओं की नयी भारतव्यापी राष्ट्रियता का चोख हई। इसलिए लिखा कि पहले हिन्दू जातीयता, तदनन्तर हिन्दू राष्ट्रियता का विकास हुआ। यदि यह व्याख्या गलत हो तो भाई शिवदानसिंह उस दुरस्त करके अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर दें।

लेकिन ‘अपभ्रंशों की अन्य भाषाओं’ से उनका क्या तात्पर्य है, यह मैं बहुत बोलिया करने पर भी नहीं समझ पाया। खैर, अपने जो कुछ भी हो, “अपभ्रंशों की अन्य भाषाओं के प्राचीन साहित्य को अपना प्राचीन साहित्य”—यह टुकड़ा अपनी ‘ध्वनि-योजना’ में निश्चय ही हिन्दू राष्ट्रवादी है!

हिन्दी-साहित्य के इतिहासकारों ने ज्यादातर भारतीय साहित्य, भारतीय सस्कृति की बात की है। चौहान ने भारतीय शब्द की व्याख्या करके उसका सांस्कृतिक अर्थ स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने लिखा है—“धार्मिक हिन्दी के साहित्य के यदि सभी ग्रंथों को निरीक्षण करें (कितना धैर्य चाहिए इस कार्य के लिए! साहित्य उस मर्मभेदी दृष्टि को जो अपने ही नहीं, अपांगों तक का निरीक्षण कर लेती है!) तो उससे निर्विवाद सिद्ध हो जायगा कि हिन्दी साहित्य में भारतीय साहित्य, सस्कृति, विचारधारा तथा राष्ट्रियता आदि जिन शब्दों के आगे ‘भारतीय’ विशेषण निर्वाच प्रयोग होता है वह वास्तव में मुसलमानों के योग से विकसित एक समुक्त अखिल भारतीय सस्कृति अथवा विचार-

धारा का घातन नहीं करता। इन प्रयोगों में 'भारतीय' केवल हिन्दू-आर्य सस्कृति और हिन्दू राष्ट्रियता का अर्थवाची है।"

भाषाविज्ञान और समाजशास्त्र दोनों ही की दृष्टि से श्री चौहान की यह खोज अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि हिन्दी लेखक भारतीय शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में करते हैं जिसमें भारतीय जनसंघ के नेता करते हैं।

जिन निर्गुणपथी सन्तों के बारे में चौहानजी की राय है कि उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम सस्कृतियों का मेल किया था, उनके लिए हजारीप्रसाद द्विवेदीजी ने लिखा है कि उनके काव्य की बाहरी रूपरेखा 'सम्पूर्णतः भारतीय' है ('हिन्दी साहित्य की भूमिका,' पृ० ३१)। शायद उनका मतलब है कि बाहर से पूरे हिन्दू हैं, भीतर से आधे मुसलमान। लेकिन उसी वाक्य में बौद्धों को भी लाकर 'भारतीय' के विशुद्ध अर्थ को खडित कर दिया है—“बौद्ध धर्म के अन्तिम सिद्धों और नाथपथी योगियों के पदादि से उसका सीधा सम्बन्ध है।"

'काव्य में प्राकृतिक दृश्य' नाम के अपने निबन्ध में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा था "आजकल के पार्कों में हम भारतीय आदर्श की छाया देखते हैं।" अर्थात् ये पार्क हिन्दू हैं, मुस्लिम नहीं।

श्री हरिशंकर शर्मा ने उर्दू-साहित्य के इतिहास में जोश मलीहाबादी की राष्ट्रीय कविताओं का उल्लेख किया है; श्री गोपीनाथ ग्रन ने 'उर्दू और उसका साहित्य' में चकवस्त की राष्ट्रीय कविताओं की चर्चा की है। चकवस्त तो हिन्दू थे ही, जोश भी कुछ समय के लिए हिन्दू राष्ट्रियता के गीत गान लगे, वरना आर्यसमाजी विद्वान् श्री हरिशंकर शर्मा उनकी राष्ट्रियता की प्रशंसा कैसे करते।

फिराक साहब ने उर्दू की प्रगतिशील कविताओं के संग्रह 'जजीरें टूटती हैं' की भूमिका में इनके रचयिताओं के लिए दावा किया है कि 'आदिकाल से अब तक की भारतीय सस्कृति उनकी जागीर है।' चूंकि यह जागीर हिन्दुओं की है, इसलिए फिराक गोरखपुरी का तो उसमें थोड़ा-बहुत हिस्सा हो भी सकता है, लेकिन मखदूम मुहीउद्दीन, राही मासूम रजा, वामिक जौनपुरी, अली सरदार आफरी वगैरह भी हिस्सेदार हो जायें, यह बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

बंगालियों ने शब्दों का अर्थ अलग भ्रष्ट कर दिया है। प्राचीन सस्कृति के सबसे बड़े जागीरदार श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने कबीर, नानक, दादू आदि को पहले तो भारतीय साधक कहा, फिर उनका सम्बन्ध राममोहन राय से जोड़ा, राममोहन राय का सम्बन्ध आधुनिक साहित्य से जोड़कर हिन्दू-मुस्लिम विवास के तमाम इतिहास का ही सत्यानाश कर दिया। (देखिए दादू ग्रन्थावली की भूमिका)

भारत के आधुनिक विकास की विशेषता क्या है? श्री चौहान कहते हैं, "वस्तुतः हमारे देश के ऐतिहासिक विकास-क्रम की ही यह विशिष्टता है कि

राष्ट्रीय चेतना ने हिन्दू राष्ट्रीयता और मुस्लिम राष्ट्रवादिता का रूप ग्रहण किया।"

जिसे राष्ट्रवादी लोग साम्प्रदायिकता कहते थे, वही सच्ची राष्ट्रीयता है; जिसे वे राष्ट्रीयता कहते थे, वह "पाँच-सात सौ वर्ष के ऐतिहासिक जीवन की स्मृतियों तक को उन्मूलन करने की असम्भव चेष्टा" है।

हिन्दुओं और मुसलमानों की एक राष्ट्रीयता? असम्भव। यह सम्प्रदाय-वाद है, जनतन्त्र की हत्या है। उदार जनवादी दृष्टि ने विचार कीजिए तो पता चल जाएगा कि इस 'द्वैत को स्थायित्व प्रदान' करने में अंग्रेजी शासन का भी हाथ भले रहा हो, "राष्ट्रीय जागरण ने इस भेद चेतन्य को और भी निखारा है।" चेतन्य महाप्रभु के बाद गौरांग महाप्रभु की कृपा से ये नये भेद चेतन्यजी प्रकट हुए।

इन भेद चेतन्यजी के प्रकट होने का फल यह हुआ कि एक ओर हिन्दू संस्कृति को प्रतिबिम्बित करनेवाला हिन्दी साहित्य विकसित हुआ, उसी तरह मुस्लिम संस्कृति को प्रतिबिम्बित करनेवाला उर्दू-साहित्य भी संवर्धित हुआ।

'हिन्दी (संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक बोली) के समानान्तर (अरबी-फारसी-निष्ठ) साहित्यिक खड़ी बोली का विकास मुस्लिम संस्कृति के प्रभाव में हुआ।"

संस्कृत के शब्द प्रायः हिन्दू हैं, फारसी के शब्द मुसलमान हैं, इसलिये जहाँ संस्कृत के शब्द ज्यादा हो वहाँ हिन्दू संस्कृति जीती, जहाँ अरबी-फारसी के शब्द ज्यादा हो वहाँ इस्लाम जीता।

"राष्ट्रीय जाग्रति के साथ-साथ हिन्दी और उर्दू का भेद और भी बढ गया।" पहले प्रगतिशील लेखक यह भेद देखकर परेशान होते थे, उसे दूर करने की कोशिश करते थे। चौहान ने बताया कि परेशानी की कोई बात नहीं है, "दोनों भाषाओं ने अपनी प्रकृति के अनुकूल पर्याप्त विकास किया" और "राष्ट्रीय जाग्रति के बिना इन दोनों भाषाओं का ऐसा अपूर्व विकास असम्भव होता।"

इस राष्ट्रीय जाग्रति से शायद गांधीजी का भी कुछ सम्बन्ध था। उन्होंने जीवन-भर प्रयत्न किया कि यह भेद मिटे और हिन्दी-उर्दू एक-दूसरे के नजदीक आएँ। वे हिन्दू-मुसलमानों तथा हिन्दी-उर्दू के भेदभाव से दुःख थे। इसका कारण यह था कि उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राधुनिक इतिहास को समझा न था, उसका निर्माण भले ही किया हो। श्री चौहान के शब्दों में "हिन्दी और उर्दू के स्वतन्त्र विकास से केवल ऐसे ही लोग विशुद्ध हैं जो अपने अनेतिहासिक दृष्टिकोण और इस बढभूल धारणा के कारण कि हिन्दू मुस्लिम एकता अथवा समस्त भारत की एकता के लिए एक ही राष्ट्रभाषा का होना अनिवार्य है, भारत की विविध वस्तुस्थिति को समझ नहीं पाते।"

यह हुई विशुद्ध समाजशास्त्र की बात। भाष पूछ सकते हैं, किसी भाषा के शब्द-भण्डार या व्याकरण-व्यवस्था से धर्म का क्या सम्बन्ध है। भाष न जानते।

होगे कि ससार के तमाम ईसाइयों की भाषाओं का व्याकरण एक सा है, तमाम मुसलमानों की भाषाओं का व्याकरण एक सा है। जब इस्लाम भारत में आया तब उसने न केवल यहाँ की भाषाओं के शब्द-भण्डार में भारी उथल-पुथल की, उसने इन भाषाओं के व्याकरण में भी राष्ट्रीय और जनवादी क्रांति कर दी।

चौहान ने लिखा—“हिन्दी और उर्दू की भिन्नता केवल शब्दों के संस्कृत या फारसी प्रयोग तक ही सीमित नहीं है। उनके व्याकरण, पिगल वाक्य-विन्यास आदि में भी मौलिक भेद उत्पन्न हो गया है।” क्लिष्ट शब्द तो दोनों में होते ही हैं, “परन्तु इसमें भी अधिक खड़ी बोली के व्याकरण का शुद्ध पालन न हिन्दी में किया जाता है, न उर्दू में। हिन्दी व्याकरण पर संस्कृत व्याकरण का प्रभाव स्पष्ट लक्षित है और उर्दू व्याकरण पर फारसी और अरबी व्याकरण की गहरी छाप पड़ गई है।”

सम्भवतः अरबी और फारसी—दो भिन्न कुलों की भाषाओं—का व्याकरण एक-सा है क्योंकि दोनों का प्रभाव मुसलमानों की खड़ी बोली पर पड़ा है। आश्चर्य की बात है कि मराठी, हिन्दी और बँगला—तीनों के व्याकरण पर संस्कृत का प्रभाव पड़ा लेकिन मराठी में तीन लिंग हैं, हिन्दी में दो, बँगला में एक भी नहीं। गम्भीरता से विचार कीजिए तो आपको ज्ञात हो जायगा कि मराठी पर संस्कृत का प्रभाव सबसे ज्यादा है, इसलिए उसके बोलनेवाले सब हिन्दू हैं या हिन्दू राष्ट्रवादी हैं, हिन्दी में दो ही लिंग हैं, इसलिए यहाँ हिन्दुत्व कमजोर रहा, मुसलमान हिन्दू राष्ट्रवादी न हुए, उल्टा अपना राष्ट्रवाद विकसित करते रहे। बँगला में एक भी लिंग नहीं, संस्कृत का प्रभाव सबसे कम, इसलिए बंगाल के दो टुकड़े हो गए।

यहाँ तक तो हुई भूत और वर्तमान की बात।

अब लीजिए भविष्य की बात। चौहानजी ने गुरुजी को समझाया कि आप यह भ्रम त्याग दीजिए कि भविष्य में कभी हिन्दी-उर्दू मिलकर एक हो जाएंगी। “यह कहना कि राष्ट्रीय भावना ज्यो-ज्यो व्यापक होती जाएगी त्यो त्यो हिन्दी-उर्दू का भेद कम होता जाएगा, केवल भ्रान्त धारणा है। यथार्थ सत्य तो यह है कि ज्यो-ज्यो राष्ट्रीय भावना व्यापक होती गई है, दोनों भाषाओं के पृथक् विकास की गति भी उतनी ही तीव्र होती गई है।”

अन्त में समाधान यह रहा कि “मुस्लिम-प्रधान प्रान्तों में राजकीय कार्यों में उर्दू भाषा का प्रयोग होगा,” इसी प्रकार “मध्यदेश (हिन्दू-प्रधान प्रान्तों) में राजकीय कार्यों में हिन्दी भाषा का प्रयोग होगा।” दोनों इलाकों के अल्प-संख्यक अपनी-अपनी भाषा का व्यवहार भी कर सकेंगे। चौहानजी यह मानकर चले थे कि पूर्वी बंगाल के मुसलमान उर्दू का व्यवहार करने को बहुत उत्सुक हैं। हिन्दू भारत में एक द्विविध प्रदेश है। उसके बारे में वह अधिक सतर्क थे। उन्होंने अवरन राष्ट्रभाषा लादने का विरोध करते हुए सुझाया—“सम्भव है कि वे अपनी ही किसी भाषा को अपने प्रान्तों की राष्ट्रभाषा बनाना चाहें।”

इस तरह भाषा समस्या का जनवादी समाधान यह हुआ कि द्रविड प्रान्तों की अपनी राष्ट्रभाषा, मुस्लिम प्रान्तों की राष्ट्रभाषा उर्दू, द्रविड़ों से भिन्न धार्मिक-हिन्दू भारत की राष्ट्रभाषा हिन्दी । तीन राष्ट्र और राष्ट्रभाषाएँ ।

यह तो राष्ट्रभाषा की समस्या का समाधान हुआ । हिन्दी प्रान्तों की एक विशेष समस्या की ओर भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया । हिन्दी प्रान्तों में “लगभग बीस भाषाएँ और बड़ी बोलियाँ बोलੀ जाती हैं ।” उनके आधार पर “हिन्दी प्रान्तों का भी पुनर्विभाजन करना होगा ।” इस तरह हिन्दीभाषी प्रदेश को मिलान के बदले चौहानजी ने बीस नये प्रान्त बनाने की नज़ाह दी ।

‘जनपदीय भाषाओं का प्रदन’ नाम कलम्बे निबन्ध में उन्होंने गहलुगी की मातृभाषा-सम्बन्धी माग्यनाओं का और भी संवारकर पदा किया । ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अंग्रेज़ों को अनिवार्य राजभाषा बनाकर यहाँ की भाषाओं का दमन किस तरह किया इसका विवेचन न करके, साम्राज्यवाद की भूमिका को मूलावर थी शिवदानसिंह ने खड़ी बोली हिन्दी के साम्राज्यवाद पर आश्रमण किया । यह साम्राज्यवाद हिन्दी क्षेत्र की बोलियों का दमन कर रहा था ।

उन्होंने लिखा, “अबेली खड़ी (हिन्दी-उर्दू) न लगभग पन्द्रह करोड़ ब्यासी लाख व्यक्तियों को अपनी मातृभाषाओं में शिक्षा पाने से वंचित कर रखा है । इससे सिद्ध है कि भारत भी ‘भाषाओं का विशाल कारागार’ है ।”

भारत कारागार ब्रिटिश साम्राज्य के कारण नहीं है, यहाँ की भाषाएँ अंग्रेज़ों के कारण कारागार में बन्दी नहीं हैं, उन्हें कारागार में डाला है खड़ी बोली ने ।

भारत को उपनिवेश ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने नहीं बनाया, यहाँ उपनिवेश कायम किये हैं हिन्दी साम्राज्य ने ।

चौहान अपने अद्भुत भाषाशास्त्र की दृष्टि “ ‘हिन्दी-साम्राज्य’ के विभिन्न ‘भाषा-उपनिवेशों’ की आन्तरिक परिस्थिति पर” डालते हैं । वह इस नतीजे पर पहुँचते हैं, “हिन्दी का वर्तमान साम्राज्य ‘ताश के घर’ से अधिक मजबूत नहीं है ।” बोलियों के उपनिवेश टूट जाएँगे, “किर खड़ी बोली को अपने साम्राज्य का पश्चिमी हिन्दी के क्षेत्र में भी विघटन करके अपने जनपद में ही सन्तोष करना पड़ेगा ।”

चौहान का विचार था कि अंग्रेज़ों और अंग्रेज़ी का साम्राज्य चाहे बाद में खत्म हो, हिन्दी का साम्राज्य पराधीन भारत में ही खत्म हो जाना चाहिए । “यदि वर्तमान आधार को हटाकर न्याय, समानता और स्वतन्त्रता का नया आधार न प्रदान किया गया तो भारत के स्वतन्त्र होने पर हिन्दी के साम्राज्य को दृष्टे देर न लगेगी ।”

भारत स्वतन्त्र हो गया; हिन्दी का ‘साम्राज्य’ न ढहा । बोलियों के उपनिवेश न टूटे । हिन्दी प्रान्तों में नये बीस प्रान्त न बने । इसलिये अठारह लाख तक हिन्दी-साम्राज्य के ढहने की राह देखने के बाद चौहानजी ने स्वयं स्वयं

उठाये और घालोचना न० ३४ (जुलाई, '६५; सितम्बर में प्रकाशित) में भारत की एकता के नाम पर इस साम्राज्य पर हल्ला बोल दिया।

चौहान के पहले के लेखों में जैसे अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म करने पर जोर नहीं है, वैसे ही इस लेख में अंग्रेजी को अनिवार्य राजभाषा के पद से हटाने का आग्रह नहीं है। श्री सज्जाद जहीर ने आत्मनिर्णय के सिद्धान्त को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध, सारे देश की स्वाधीनता के लिए न लागू करके, उम्मेद राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध, जनतन्त्र के नाम पर, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित में लागू किया था। इस समय उन्हें उर्दू के संरक्षण की जितनी चिन्ता है, उतनी अंग्रेजी हटाने की नहीं। उन्हीं की तरह श्री चौहान ने उर्दू की रक्षा का नारा लगाया है लेकिन वह दूसरों की स्थापनाओं को दोहराते-भर नहीं हैं। वह योग्य शिष्य हैं, इस नाते उन्होंने आत्मनिर्णय का अधिकार हिन्दी के उपनिवेशों पर लागू किया है।

अवध, बुन्देलखण्ड, वज्ज, भोजपुरी क्षेत्रों के जो लेखक हिन्दी को अपनी मातृभाषा कहते हैं, उनकी निन्दा करते हुए श्री चौहान ने प्रश्न किया है कि जब अंग्रेजी में साहित्य रचनेवाले मुल्कराज आनन्द, भवानी भट्टाचार्य, और के० नारायणन अंग्रेजी को अपनी मातृभाषा नहीं कहते, तब प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला, वृन्दावनलाल वर्मा, रामचन्द्र शुक्ल ही हिन्दी को अपनी मातृभाषा क्यों बहे? हिन्दी साहित्य का सारा इतिहास चौहानजी को विकृत दिखाई देता है; इसके रचनेवालों की मातृभाषा हिन्दी थी ही नहीं, जैसे मुल्कराज आनन्द और भवानी भट्टाचार्य की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। यशपालजी की मातृभाषा हिन्दी नहीं है। “इस दृष्टि से उनकी और डा० मुल्कराज आनन्द की स्थिति में विशेष फर्क नहीं है। यह बात भारतेन्दु से लेकर मोहन राकेश तक की नई पीढ़ी के निन्यानवे फी सदी हिन्दी लेखकों और हिन्दी-आन्दोलन के सुभट योद्धाओं के बारे में भी सच है।”

मुल्कराज और यशपाल की स्थिति में विशेष फर्क न हो, थोड़ा बहुत फर्क तो है ही। चौहान हिन्दी के निन्यानवे फी सदी लेखकों को मातृघाती कहते हैं क्योंकि उनकी समझ में इन लेखकों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है। लेकिन अंग्रेजी में उपन्यास-कहानियाँ लिखनेवाले मुल्कराज आनन्द को मातृघाती कहने का साहस उनमें नहीं है। कारण, इससे विश्वभाषा अंग्रेजी के प्रति सकीर्णता प्रकट होती है और ‘ऐफो-एशियन-सौलिडैरिटी’ को धक्का लगता है। भारत में इस सौलिडैरिटी के तीन स्तम्भ हैं—मुल्कराज आनन्द, सैयद सज्जाद जहीर और शिवदान-सिंह चौहान।

भारतेन्दु से लेकर मोहन राकेश तक हिन्दी के निन्यानवे फी सदी लेखक अपनी मातृभाषाएँ छोड़कर हिन्दी की सेवा क्यों करते रहे हैं? अर्थ और यश-लाभ के लिए! देशभक्त बनने का सुख अलग से! इन मातृघातियों से मातृभाषाओं की रक्षा करने के लिए खड्ग लेकर उठ खड़े हुए हैं, श्री शिवदानसिंह

चौहान ।

जनतात्रियता की होड में सभी भारतीय लेखकों को पछाड़ते हुए उन्होंने लिखा है, "भाज की 'हिन्दी' हम सबने अपनी मातृभाषाओं को त्यागकर स्कूलों में किताबों में ही सीखी-पढ़ी है, जिस तरह अंग्रेजी स्कूलों में किताबों से सीखी-पढ़ी है । इसे आप क्या कहेंगे, मातृघात या कुछ और, मैं यह तो नहीं जानता, क्योंकि जब हम लोगों ने शिक्षालयों में प्रवेश किया, उस समय हिन्दी या उर्दू के अलावा अपनी मातृभाषाओं में पढ़ने का कोई विकल्प ही नहीं था । भाज भी नहीं है । लेकिन यह सच है कि एक समय जो विद्यार्थी था, वह बालिग होने पर अर्थ और यशस्वी और देशभक्ति के रूप में प्रसिद्धि पाने का नुस्खा साबित हुई, इसलिए अपनी मातृभाषाओं के प्रति अपना कर्तव्य मुला देना ही हम सबके आगे सबसे सुविधाजनक मार्ग था ।"

सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला हुआ नहीं करते । चौहान अब समझ गए हैं कि अर्थ और यश के लिए हिन्दी-सेवा करना अनुचित है । उन्होंने स्वयं बाकी यश अर्जित कर लिया है, अर्थ भी 'मालोचना' से ऐसा क्या मिलता होगा ? उन्हें चाहिए कि वह हिन्दी के मातृघाती लेखकों के सामने अपने त्याग से एक मिसाल कायम करें । अब उन्हें हिन्दी लिखना घन्द कर देना चाहिए और जिन्दगी के बाकी दिन मातृभाषा की सेवा में लगाने चाहिए । सम्भवतः उनकी मातृभाषा ब्रज है, उसकी सेवा करें । अभी तो उनका कोई लेख, कोई पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी हुई देखने को नहीं मिली । ब्रजभाषा में अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय देकर वह ब्रज और हिन्दी दोनों का उपकार करेंगे । मातृभाषा ब्रज न हो तो जो भी मातृभाषा हो, उसकी सेवा करें । उनके पिताजी ने एक बार आगरे में दर्शन दिए थे । पुलिस के आदमी थे । उन्होंने अपने पुत्रों की चर्चा करते हुए बहुत मुहावरेंदार खड़ी बोली का व्यवहार किया था । उनके धाराप्रवाह वाक्य मुझे अभी तक याद हैं यद्यपि उन्हें लिखकर प्रकाशित करने का साहस मुझमें नहीं है । बहरहाल सवाल मातृभाषा का है, पितृभाषा का नहीं ।

फायद ने ईडीएम वाम्प्लेकम ईजाद करके सभी किशोरों और शिशुओं को सम्भाव्य पितृघाती सिद्ध कर दिया था । शिवदानसिंहजी ने पितृघात की बात पुरानी पड़ जाने से उसे त्यागकर अधिक वैज्ञानिक इस मातृघाती काम्प्लेक्स का आविष्कार किया है । अब देखिए, इससे कभी जटिल ग्रन्थियाँ लोगों के मन में पड़ जाती हैं ।

वहते हैं, "अपनी मातृभाषाओं के प्रति अपनी उपेक्षा की हम मातृघात कहें या नहीं, यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन इनका जानता हूँ कि हिन्दी के तत्त्व और छान्दोलनकारी नेताओं के अन्तर्मन में कहीं कोई अपराध-भावना की ग्रन्थि जरूर पड़ गई है जिसका कारण वे अपने अपराध पर परदा डालने के लिए इतिहास को तोड़-मोड़कर यह सिद्ध करने की काशिश करते रहते हैं कि मयिस्त्रों,

प्रगतिशील साहित्यकार और भाषा समस्या के जनतात्रियता के अन्तर्गत /



राजस्थानी अवधी वगैरे प्रादि वस्तुतः स्थलानुसार भाषाएँ नहीं हैं 'हिन्दी' (संस्कृत-निष्ठ साहित्यिक खड़ी बोली) की ही स्थानीय बोलियाँ हैं और जनगणना प्रादि के मीकी पर हिन्दी प्रचारक और जनसघ के अन्ध-हिन्दूराष्ट्रवाद से प्रभावित सरकारी अमला इन भाषाओं का बोलनवाली जनता पर दबाव डालते हैं कि वे मातृभाषा के स्थान में राजस्थानी या मैथिली न लिखवाकर हिन्दी लिखवाएँ, यानी वे उत्तर भारत की समूची जनता का अपन अपराध में सांभोदार बना लेना चाहते हैं।

इस अपराध भाषा से बचने में लक्ष्य मुक्त हैं जिन्होंने खड़ी बोली के उर्दू रूप का अपनाया है। खड़ी बोली यदि मातृभाषा है तो उर्दू-रूप में, हिन्दी रूप में नहीं। यह नयी मान्यता है जाँची चौहान के पुराने निबन्धा की मान्यता से बहुत आगे बढ़ गई है। अब उन्होंने सीधे-सीधे उर्दू को मुस्लिम राष्ट्रवाद की भाषा कहना छोड़ दिया है, अब वे हिन्दी का ही सम्बन्ध हिन्दू राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं। उर्दू हिन्दुओं और मुसलमानों की मुश्तक़ाबान है।

लिखा है, 'माँ के घटनों पर बैठकर हम में से किसी ने 'हिन्दी' नहीं भीखी जिस तरह कि अधिक पुरानी शैली (१) उर्दू को दिल्ली लखनऊ, हैदराबाद अनेक सांस्कृतिक केन्द्रों के बच्चे हज़ारा हिन्दू और मुसलमान परिवारों में पुस्तक-दर-पुस्तक अपनी माताओं की गोद में ही सीखते आए हैं।

वया कारण है कि दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के हिन्दू मुसलमान तो पुस्तक-दर-पुस्तक अपनी माताओं की गोद में ही उर्दू सीखते आए हैं लेकिन इलाहाबाद, बनारस और पटना के हिन्दू मुसलमान अपनी माँ की गोद में हिन्दी नहीं सीख पाए? कारण यह है कि चौहान की समझ में उर्दू मुख्यतः मुगलमानों की भाषा है, दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद में मुसलमान काफी बड़ी संख्या में हैं, बनारस पटना और इलाहाबाद में वे इतनी बड़ी संख्या में नहीं हैं इसलिए खड़ी बोली के प्रसार का एक नियम लागू होता है मुस्लिम प्रधान शहरों में दूसरा नियम लागू होता है हिन्दू प्रधान शहरों में—इस कारण खड़ी बोली का उर्दू-रूप तो मातृभाषा है उसका हिन्दी रूप नहीं है। शिवदानसिंह चौहान ने भाषाओं का विभाजन फिर उसी पुराने साम्प्रदायिक आधार पर किया है। उनके जनतांत्रिक आडम्बर के नीचे वही साम्प्रदायिकता का चोर छिपा हुआ है।

यदि यह मान भी लें कि दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद के हिन्दुओं और मुसलमानों की मातृभाषा उर्दू है तो भी यह बात साफ नहीं होती कि चौहान उर्दू के उन तमाम लखवों को मातृभाषा क्यों नहीं कहते जो इन शहरों में दूर-दूर अजब अवध, पंजाब या भोजपुरी क्षेत्रों के रहनेवाले थे। उर्दू के दो सवने बड़े शाहर गालिब और मीर आगरे में पैदा हुए थे। सीदा के बाप ईरानी थे। इकबाल पंजाबी थे। सादिक लुधियानवी, हफीज जालन्धरी, जोश मलसियानी, जगन्नाथ आज़ाद अहमद नदीम कासिमी फ़ैज, राजेन्द्रसिंह बेदी, कृष्ण चन्दर आदि पंजाबी हैं। ये सब मातृभाषा है या नहीं? जोश मलीहाबादी, किराक

गोरखपुरी, मजरूह सुल्तानपुरी, फानी वदायूनी, शाद अजीमाबादी, अक्बर इलाहाबादी वगैरह मातृघाती क्यों नहीं हैं ?

दरअसल चौहान अंग्रेजी और उर्दूवालों के सामने खीसें निपोरते हैं, अर्थ और यशस्वता के लिए नहीं, विशुद्ध जनतन्त्र की रक्षा के लिए, हिन्दीवालों पर गुराँते हैं क्योंकि जिस पत्तल में खाना, उमी में छेद करना उनकी न्यायप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण होगा। इसलिए भारतेन्दु में लेकर मोहन राकेश तक के हिन्दी-लेखकों को बोलने में उन्हें जरा भी झिझक नहीं होती, लेकिन उर्दू भाषा और साहित्य के लिए वह नियम-ब्यादे दूसरे बना लेते हैं।

उन्हें यह नहीं मालूम कि उर्दू के बहुत से लेखक आज भी अपने घरों में अक्की या भोजपुरी बोलते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि उर्दू के बहुत से कवियों की भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव नज़ीर की कविताओं में सबसे ज्यादा स्पष्ट है। उन्हें यह तो जरूर मालूम होगा कि उर्दू के पंजाबी लेखक आपस में पंजाबी बोलते हैं। पंजाब, अवध और ब्रज के उर्दू लेखकों को निकाल दीजिए। तीन-चौपाई उर्दू-साहित्य का सफाया हो जाएगा। चौहान को यह नहीं मालूम कि हैदराबाद में हिन्दुओं और मुसलमानों की जो बोलचाल की भाषा है, व पुरानी खड़ी बोली का वह रूप है जिसे उत्तर भारत के लोग यहाँ से अपने साथ ले गए थे और जिस पर मराठी-तेलुगु आदि भाषाओं का प्रभाव पड़ा है।

बोलचाल की दकनी में 'भूलना' नहीं, 'नामई च नहीं लेते', 'साठे नौ बज कूँ धाए' जैसे प्रयोग होते हैं। (देखिए, श्रीराम शर्मा का सफलन 'दक्खिनी व गद्य और पद्य', पृ० ४५६)। हैदराबादी बन्धु 'क' या 'क' की जगह 'ख' काँ बोलते हैं, इससे बहुत स लतीफें मशहूर हैं। चौहानजी इन सब बातों से बेखबर हैं। 'उल्टा चोर कोतवाल को डाटे' की मसल चरितार्थ करते हुए फर्माते "जब कोई व्यक्ति, वर्ग या समुदाय जीवन की वास्तविक परिस्थिति को खुद आँखों में देखने में असमर्थ हो जाता है और इस तरह की अमूर्त मिथिक पर्व कल्पनाएँ गढ़कर उनके चश्मे से जीवन-वास्तव को देखने लगता है, तब उस तर्क, विवेक और औदार्य की अपेक्षा नहीं की जा सकती।"

वास्तविक परिस्थिति क्या है ? हैदराबाद में लोगों की बोलचाल की ज़बान दिल्ली की उर्दू है या उससे भिन्न दकनी ? उर्दू के पंजाबी लेखकों की घर की भाषा उर्दू है ? मलीहाबाद, अजीमाबाद, गोरखपुर, इलाहाबाद के लोगों की बोलचाल की भाषा साहित्यिक उर्दू है ? तथ्यों में कौन आँखें चुराता है ?

वास्तविक स्थिति यह है कि हर भाषा की अपनी बोलियाँ होती हैं। अंग्रेजी, फ़ारसी, उर्दू की तरह बंगला, मराठी, हिन्दी, तमिल आदि भाषाओं की भी अपनी बोलियाँ हैं। इस बारे में बहस हो सकती है कि कोई बोली स्वतन्त्र भाषा है या नहीं, लेकिन किसी भाषा की बोलियाँ ही न हो, ऐसा नहीं होता। पूँजीवाद के विकास के साथ जब विनिमय के बड़े-बड़े केन्द्र नगरों के रूप में स्थापित होते हैं, तब उनमें अनेक बोलियों के क्षेत्र—अनेक जनपदों—में सिमटकर लोग

प्रगतिशील साहित्यकार और भाषा-समस्या के जनतांत्रिक **उपाय** \*

घाते हैं। दिल्ली और आगरा में बहुत से परिवार पूरब से आकर बस गए। इनके यहाँ लोग अब भी घर में अवधी बोलते हैं। इनमें मुस्लिम परिवार भी हैं।

हिन्दी-भाषी जाति के विकास और गठन में दिल्ली, आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद और पटना मुख्य सांस्कृतिक केन्द्र बने। यहाँ खड़ी बोली का प्रसार हिन्दुआ और मुसलमानों दोनों ने किया। इनकी बोलचाल की भाषा में धार्मिक आधार पर कोई फर्क नहीं है। साथ ही इन शहरों के बहुत से हिन्दू और मुसलमान अपने घरों में खड़ी बोली से भिन्न अपनी पुरानी बोली का भी व्यवहार करते रहते हैं। इसलिए यह कहना कि उर्दू तो मान-भाषा है, हिन्दी नहीं है, गलत है। दिल्ली, आगरा, लखनऊ आदि शहरों में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने माँ की गोद में खड़ी बोली सीखी है और हजारों ऐसे हैं जिन्होंने मोहल्ले के दोस्तों से खड़ी बोली सीखी है। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत बोझिल करने पर भी खड़ी बोली नहीं सीख पाए, न उसका हिन्दी रूप, न उर्दू रूप।

कानपुर, लखनऊ, पटना आदि शहरों में मजदूरी और नौकरी के लिए जो अवधी, भोजपुरी बुन्देलखण्डी आदि बोलियों का व्यवहार करने वाले लोग एकत्र होते हैं, अपने सामाजिक कार्यों के लिए वे खड़ी बोली अपनाते हैं। इसे हम जातीय निर्माण की प्रक्रिया समझें या बोलियों के दमन की प्रक्रिया। दिल्ली से पटना तक और पटना से भोपाल उज्जैन तक कोई ऐसा शहर नहीं है जिसमें विभिन्न जनपदों के लोग एकत्र न हुए हों। इन लोगों ने अपने राजनीतिक-सांस्कृतिक कार्यों के लिए खड़ी बोली को अपनाया है। अब छोटे छोटे कस्बों तक में एक ही देहाती बोलनेवाले नहीं रह गए हैं। लेकिन जातीय निर्माण की यह सारी प्रक्रिया न समझकर, बोली और भाषा का भेद न समझकर, जातीय प्रदेश और सामन्ती युग के जनपदों का भेद न समझकर, स्तानिन की 'नशन' की परिभाषा आखिरी मूंदकर जनपदों पर लागू करके, भाषावार प्रान्त निर्माण की माँग को हास्यास्पद बनाते हुए श्री चौहान ने माँग की है कि हिन्दी क्षेत्र में 'दस पन्द्रह नये राज्यों का निर्माण' कर दिया जाय। 'सोलह-सत्रह तो इस समय भी हैं। और इससे देश का विघटन नहीं हुआ तो दस-पन्द्रह और भाषावार राज्य बना देने से आसमान नहीं फट पड़ेगा।'

अहिन्दी प्रदेशों में जो लोग हिन्दी के विराधी हैं, वे यह तर्क देते हैं कि हिन्दी कृत्रिम भाषा है। उसकी कृत्रिमता सिद्ध करने के लिए वे हिन्दी की बोलियों का हवाला देते हैं, उन्हें स्वतन्त्र भाषाएँ कहकर हिन्दी को साम्राज्यवादी उत्पीड़क भाषा मानते हैं। यदि कोई हिन्दी प्रेमी मराठी, बंगला या तमिल के लिए कहे कि वे हिन्दी की बोलियाँ हैं या यह कि भारत में एक राष्ट्रभाषा रहेगी, और सब भाषाएँ मिटा दी जाएँगी, तो यह जरूर साम्राज्यवादी उत्पीड़न की बात होगी। लेकिन लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, दिल्ली में जो लोग मेहनत मजदूरी करने आते हैं, वे खड़ी बोली का व्यवहार

न करें तो बेमौत मरें। दिल्ली और बानपुर के सूती मिल-मजदूर खड़ी बोली का व्यवहार न करें तो उनका ट्रेड यूनियन आन्दोलन ठप हो जाय। मजदूर वर्ग को अपने संगठन के लिए जातीय भाषा की जरूरत होती है जो अलग-अलग बोलियाँ बोलनेवाले मजदूरों को एकजुट करे। चौहान के मार्क्सवाद में मजदूर वर्ग को स्थान नहीं है। यदि हो तो एक भी मिल, एक भी कारखाने, एक भी उद्योग का नाम बतान की कृपा करें जहाँ सिर्फ मैथिली, सिर्फ भोजपुरी, सिर्फ भवधी या अन्य कोई जनपदीय बोली बोलनेवाले ही काम करते हों।

चौहान ने बुद्धिस्त समाजशास्त्र की काफी निन्दा की है। लेकिन उनके बुद्धिहीन विगुह समाजशास्त्र में कहीं पूँजीवादी विकास के अन्तर्गत नये विनिमय केन्द्रों में विभिन्न जनपदों में एकत्र होनेवाले मध्यम और श्रमिक वर्गों का उल्लेख नहीं है।

जातीय भाषा का प्रसार सामाजिक विकास का परिणाम है, इसलिए उसका विभाजन धर्म के आधार पर नहीं होता। भारतीय बुद्धिजीवियों पर अंग्रेजी का प्रभाव है, वे 'मिथिक' परिवर्तनाओं की बात करत हैं अंग्रेजी शब्दों और मुहावरों का गलत अनुवाद करके अपनी हिन्दी को सजात है (जैसे 'कोस्टली' के लिए 'कीमती' शब्द का व्यवहार—'कीमती किन्तु अनुपयोगी प्रयोग', "यह प्रयोग शायद बहुत कीमती भी साबित हो।") तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वे ईसाई हो गए हैं या उन पर ईसाइयत का प्रभाव है। बोलचाल की खड़ी बोली में हिन्दू और मुसलमान साधारणजन भरबी-फारसी या संस्कृत के कठिन शब्दों का व्यवहार नहीं करते। यह है बुनियादी बात। यहाँ धर्म के आधार पर कोई विभाजन नहीं है। लोग फारसी या संस्कृत के शब्दों का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो इसका प्रधान कारण सांस्कृतिक है, धार्मिक नहीं।

उस विशाल क्षेत्र में, जिसके नगरीय के हिन्दू और मुसलमान, विभिन्न जनपदों में घाये हुए मजदूर और नौकरीपेदा लोग, निष्कृष्ट भाषा के रूप में खड़ी बोली का व्यवहार करते हैं सभी की जाति, बौध्द या नेशन एक है, यहाँ दस या पन्द्रह प्रान्त बनाने की बात करना हिन्दीभाषी जनता की जातीय एकता को तोड़ने का प्रयास करना है। इस क्षेत्र की बोलचाल की भाषा में हिन्दी-उर्दू का भेद नहीं है, इसलिए उर्दू को क्षेत्रीय भाषा कहना गलत है। यदि बोलचाल की उर्दू और हिन्दी में एक ही जन-कारखाने में काम करने वाले मजदूर भेद करते तो उर्दू को क्षेत्रीय भाषा मानना उचित होना। लेकिन ग्राम जनता बोलचाल में ऐसा कोई भेद नहीं करती। यह भेद निष्कृष्ट भाषा के रूप और लिपि को लेकर है। अधिकांश जनता देवनागरी लिपि का व्यवहार करती है और निष्कृष्ट भाषा के लिए अधिकतर शब्द संस्कृत में लेती है। एक अल्पमध्यम समुदाय ऐसा है जो फारसी लिपि का व्यवहार करता है और अपनी निष्कृष्ट भाषा में भरबी फारसी से शब्द लेता है। इस समुदाय में मुसलमानों के साथ हिन्दू भी हैं, इसलिए उस सांस्कृतिक अल्पमत कहना चाहिए। इन सांस्कृतिक

अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर करते हुए उनकी लिपि और शिष्ट भाषा की रक्षा करनी चाहिए लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि हम दो कौमो के सिद्धान्त के आधार पर दो भाषाएँ स्वीकार कर लें। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ साहित्यिक उर्दू बोलचाल की भाषा हो या जहाँ उर्दू की बोलचाल का रूप वही की हिन्दी के बोलचाल के रूप से भिन्न हो। बोलचाल की खड़ी बोली के दो साहित्यिक रूप हैं—हिन्दी और उर्दू। उर्दू को हिन्दी की शैली कहने से बुरा लगता हो तो उस खड़ी बोली की शैली कहिए, हिन्दी को भी खड़ी बोली की एक शैली कहिए। लेकिन सांस्कृतिक बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों का भेद याद रखिए। यह जान लीजिए कि बहुत से उर्दू लेखक और लेखिकाएँ—जिनमें श्रीमती रजिया सज्जाद जी भी हैं—अपनी रचनाएँ उर्दू की इबारत में कोई फेर बदल किये बिना, देवनागरी में छपवाती हैं। यह स्वाभाविकता जा रहा है कि प्रसिद्ध उर्दू लेखकों की रचनाएँ देवनागरी लिपि में पहले छपें, फारसी लिपि में बाद की। इससे हिन्दी उर्दू साहित्य को देवनागरी के माध्यम से पढ़ने-वालों की एक मिली जुली जमात बनती है। यह जमात अपनी एकता, अपनी रूचि का असर लेखकों पर, उनकी हिन्दी उर्दू शैली पर डालकर एक ही शैली के विकास में सहायक होती है। जो लोग दो कौमो के सिद्धान्त पर विश्वास नहीं करते, वे इस एकता के नये मिलसिले से खुश होंगे।

राजपाल एण्ड मन्ज ने लोकप्रिय उर्दू शायरों की मिरीज निकालकर लाखों हिन्दी-भाषियों तक इनकी रचनाएँ पहुँचाईं उन्हें दरअसल लोकप्रिय शायर बनाया। इससे उर्दू का नाश नहीं हो गया। देवनागरी लिपि में 'उर्दू साहित्य', 'डगर' जैसे पत्र निकलते हैं जिनमें उर्दू की रचनाएँ देवनागरी लिपि में छपती हैं। ख्वाजा महमूद अब्बास और उनके साथियों ने 'सरगम' निकाला था जिसमें देवनागरी लिपि सरल उर्दू रचनाएँ छपती थी। हिन्दी 'डिलट्ज' की भाषा, 'जनयुग' और 'आलोचना' में भिन्न, आसान उर्दू होती है जिसमें बहुत थोड़े पारिभाषिक शब्द संस्कृत के होते हैं। इस तरह हिन्दी-भाषियों ने उर्दू को अपनाया है, उसका दमन नहीं किया। देवनागरी के माध्यम से उन लोगों तक उर्दू साहित्य पहुँचा है जो पहले उससे कोसों दूर थे। जो लोग अपने को मार्क्सवादी कहते हैं, बोलचाल की भाषा और उसके साहित्यिक रूप में बुनियादी भेद नहीं मानते, उन्हें सांस्कृतिक विकास के इस मिलसिले में खुश होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा मुहरंभी मूरतें वही लागू बनाय हुए हैं जो अपने को मार्क्सवादी लेखकों का रहनुमा समझते हैं। कोई भूल हड़ताल की धमकी देता है तो कोई नरसे देखकर वह इलाका तय करने में लगा है जहाँ हिन्दी से अलग लोगों की मातृभाषा उर्दू है। कुछ अन्य मिन सांस्कृतिक बहुसंख्यक-अल्पसंख्यक का भेद न समझकर दिल्ली या अन्य राज्यों में हिन्दी के बराबर उर्दू को राजभाषा बनाने का स्वागत् देख रहे हैं। और इन सबमें कोई भी यह माँग नहीं करता कि भारत की सभी भाषाओं का दमन करनेवाली विदेशी भाषा अंग्रेजी

का प्रभुत्व प्राप्त हो ।

जहाँ तब राजस्थानी और पंजाबी का सम्बन्ध है, उनके लिखने ढोलने-वाले तब करें कि वे हिन्दी अपनाएँगे या पंजाबी राजस्थानी का स्वतन्त्र विकास करेंगे । यदि उत्तर प्रदेश की सरकार या दिल्ली सरकार उन पर किसी तरह का दबाव डालेगी कि वे हिन्दी का ही व्यवहार करें, तो मैं इसका विरोध करूँगा । साथ ही उपेन्द्रनाथ अश्व और यशपाल हिन्दी लिखते हैं तो मैं इसे मातृभाषा न कहूँगा ।

हिन्दी भाषा जातीय विकास के परिणामस्वरूप विशाल हिन्दी क्षेत्र की भाषा बनी है । इस विकास को न समझन से भारतेन्दु से लेकर मोहन रावदा तक हिन्दी के सैकड़ों लेखक साम्राज्यवादी या ध्वंसवादी दिखाई देते हैं । इस विशाल क्षेत्र में बानियों के दमन की बात वे कहते हैं जो भारत में अंग्रेजी को राजभूषण या बनाय रखना चाहते हैं । अंग्रेजी की रक्षा उस 'जनतन्त्र' का यह बुरा पट्टावर नहीं की जा सकती ।

जैसे-जैसे अंग्रेजी का हटाने का समय नजदीक आया, वैसे-वैसे उर्दू के संरक्षण की माँग भी जोर पकड़ती गई । छेद की बात है कि कुछ गुमराह भावसंवादी नेता हिन्दी पर उर्दू के दमन का अपराध लगाकर 'किलहाल' अंग्रेजी कायम रखने की नीति का प्रचार करते हैं । उर्दू के लेखक और उर्दू साहित्य के प्रेमी पाठन उनकी रक्षा हिन्दी नेत्रों और हिन्दीभाषी जनता के सहयोग में ही कर सकते हैं । उन्हें इस हिन्दीभाषी जनता के साथ मिलकर अंग्रेजी को हटाने और सभी भारतीय भाषाओं को अंग्रेजी की दामनी से मुक्त कराने के लिए सघर्ष करना चाहिए । वस्तुस्थिति को पहचानते हुए वे सांस्कृतिक सम्पत्तियों के रूप में अंग्रेजों के लिए लड़ें, हिन्दी-भाषी जनता उनका साथ देगी । उनका अलगवाह का खर्चा सम्प्रदायवाद की उपज है और उन्हीं के लिए हानिकारक है ।

चौहान न फातिश और हिटलर की उच्चतर आर्य जाति-सम्बन्धी परिवर्तन की निन्दा की है । वह कृपा करके अपने पुराने राष्ट्रभाषा वाचक निबन्ध में देख जायें, उन्होंने कितनी बार आर्य हिन्दुआ और हिन्दू राष्ट्रवाद की चर्चा की है और उसका आधार पर हिन्दी के विकास का विस्लेषण किया है । उन्होंने ध्वंस हिन्दू राष्ट्रवाद का नाम लेना बन्द कर दिया है लेकिन हिन्दू-मुस्लिम सस्कुनियों अभी सरकार है । उन्होंने लिखा है कि "विभिन्न बीमा की जनता (विशेषकर उत्तर भारत की जनता) ने हिन्दू और मुस्लिम सस्कुनियों के योगदान से दिल्ली के घास घान बोनी जानेवाली खड़ी बाली की भूमि पर एक अपनी ही सम्पूर्ण भाषा उर्दू का विकास किया ।"

चौहान ने यह नहीं बताया कि बंगाल, कश्मीर, सिन्ध आदि में हिन्दू-मुस्लिम सस्कुनियों के योगदान से किसी नयी सम्पूर्ण भाषा का विकास क्यों नहीं हुआ । वह यह नहीं जानते कि ईरानी, अरब, पठान, उज्बेक मुसलमानों की

संस्कृति एक नहीं है, न तमिलनाडु, बंगाल और गुजरात की संस्कृति एक है। और सारे हिन्दुओं की एक संस्कृति हो भी तो उनकी एक भाषा कैसे हो जायगी ? भारत में आनेवाले तुर्क, पठान और ईरानी मुसलमानों की भाषा कैसे एक हो जायगी ?

गुप्ती वही पुरानी है। वह समझते हैं कि संस्कृत के शब्द हिन्दू हैं और फारसी के शब्द मुसलमान ! दोनों के मिलने से उर्दू का विकास हुआ।

और हिन्दी का विकास कैसे हुआ ?

“हिन्दू समाज में उठे सुधार-आन्दोलनों और कई दूसरी ऐतिहासिक परिस्थितियों के प्रभाव से उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में खड़ी बोली की ही जमीन पर उर्दू के मुकाबले में एक संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक रूप हिन्दी का विकास हुआ।”

वही बात है जो श्री सज्जाद ज़हीर ने अपने निबन्ध में लिखी थी और जिसे चौहानजी ने अपने पुराने निबन्ध में पल्लवित किया था। हिन्दी का विकास हिन्दू-समाज में उठे सुधार आन्दोलनों के कारण हुआ। वह हिन्दुओं की भाषा है। उर्दू मुख्यतः मुसलमानों की भाषा है जिनके साथ कुछ शरीफ हिन्दू भी हैं।

चौहान को यह नहीं मालूम कि जितनी संस्कृतनिष्ठ हिन्दी (उन्हे छोड़कर) हिन्दी के आसत लेखक लिखते हैं, उसमें ज्यादा संस्कृतनिष्ठ बंगला पूर्वी पाकिस्तान के ढाका रेडियो से बोली जाती है वैसे ही संस्कृतनिष्ठ मलयालम केरल के ईसाई लिखते और बोलते हैं। भाषा में धर्म का घट्टट सम्बन्ध होता तो हर प्रदेश में नयी-नयी सम्पर्क भाषाएँ बन गई होती।

चौहान के विचार से “संस्कृतनिष्ठ हान के कारण ‘‘हिन्दी ने उर्दू के मुकाबले में ‘ राष्ट्रीय आन्दोलन को एकजुट करने में अधिक व्यापक योग दिया।” होना यह चाहिए था कि जो सहज सम्पर्क भाषा बनी थी, वही राष्ट्रीय आन्दोलन को एकजुट करती। लेकिन यह काम दिया संस्कृतनिष्ठ—हिन्दू समाज की भाषा—हिन्दी ने। यह भी उसी पुरानी स्थापना का नया रूप है; गांधीजी ने जो राष्ट्रीय आन्दोलन चलाया, वह मूलतः हिन्दू राष्ट्रवाद का आन्दोलन था।

अब बच गए मुसलमान। वे अलग राष्ट्र की माँग तो कर चुके। अब उर्दू को क्षेत्रीय भाषा बनाने के अलावा और किम चीज की माँग करें ?

इस प्रकार चौहान का यह नया लेख भी उनकी पुरानी हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति की सम्प्रदायवादी—माकर्मवाद-विरोधी—समझ के आधार पर लिखा गया है। वह वस्तुगत रूप में अंग्रेजी का समर्थन करता है, अंग्रेजी को राजभाषा बनाये रखनेवालों के तर्क दोहराता है। उनकी एक भी स्थापना हिन्दी के लेखक शीघ्र सतर्क न मानें तो वह स्वाभाविक है, इस पर उन्हें खफा न होना चाहिए।

(१९६५)

## हिन्दी के आधुनिक विकास-सन्दर्भ में ब्रजभाषा की भूमिका

भारत की अन्य भाषाओं की तरह हिन्दी भी विकासमान भाषा है।

पिछले पच्चीस वर्षों में हिन्दी भाषी प्रदेश के नगरों का रूप काफी बदल गया है। अवध के प्रसिद्ध नगर लखनऊ पर भोजपुरी छाप है। दिल्ली तीन चौथाई पंजाबी शहर है। फरीदाबाद जैसे व्यापार और उद्योग धन्धों के नये केन्द्र कायम हो गये हैं। कलकत्ता और बम्बई जैसे महानगरों में लाखों नये घादमी निमग्न-कर इकट्ठा हो गये हैं। इन सब केन्द्रों में जिम भाषा का व्यवहार होता है, वह छापे की परिनिष्ठित हिन्दी नहीं है।

इस हिन्दी की विशेषता है, उस पर जनपदीय बोलियों अथवा हिन्दी की पड़ोसी भाषाओं का प्रभाव। दिल्ली की हिन्दी पंजाबी प्रभावित है, बनारस की हिन्दी भोजपुरी प्रभावित, कलकत्ते की हिन्दी बंगला-प्रभावित, बम्बई की हिन्दी मराठी-प्रभावित। ध्यान देने की बात है कि हिन्दी दूसरों पर लादी गई होती तो दूसरों का प्रभाव ग्रहण करके नये नये स्थानीय रूप धारण न करती। उसका प्रसार और विकास सहज है, इसीलिए वह स्थानीय प्रभाव से अपना रूप बदल लेती है। यह भी ध्यान देने की बात है कि इस विकासमान भाषा की हिन्दी-उर्दू की विभाजन रेखा खींचकर दो हिस्सों में बाँटा नहीं जा सकता।

हिन्दी प्रदेश में ब्रज एक प्रसिद्ध जनपद की बोली है। ब्रजभाषा का ध्वनि-तन्त्र इस ढंग का है कि आगरे से पटना तक उसके शब्दों को मुँह से निवालने में किसी को कठिनाई नहीं होती। कोई भाषा अपने क्षेत्र में और पड़ोसी प्रदेशों में लोकप्रिय हो, इसके लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि वह लोगों की बोलने में सुगम जान पड़े। जिन कवियों ने शताब्दियों तक ब्रजभाषा की सँवारा, उसे गुजरात से बंगाल तक, पंजाब में केरल तक संगीत और साहित्य के माध्यम से लोकप्रिय बनाया, वे इस बात की अच्छी तरह समझते थे। वे ब्रजभाषा का स्वभाव पहचानते थे, उन्हें यह भ्रम न था कि ब्रजभाषा संस्कृत की बेटी है, इसलिए उसमें जितना ही तत्सम शब्द होंगे, उतना ही लोक-प्रिय होकर वह सारे भारत की राष्ट्रभाषा बन जायेगी। उन्होंने ब्रजभाषा में

हिन्दी के आधुनिक विकास-सन्दर्भ में ब्रजभाषा की भूमिका / ३९



वैसे शब्द लिये जैसे उसमें खप जात थे । इसलिए रेडियो और समाचार पत्रों की सहायता के बिना, किसी केन्द्रीय निदेशालय द्वारा मूत्र-मदान के बिना, विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का अङ्ग हुए बिना यह हमारी प्रिय व्रजभाषा जनता का कठहार बन गई । आज का हिन्दी लेखक उस मारे विकास को देखकर विनम्रता से सर झुका ले तो अच्छा है, स्पर्धाभाव से उस विकास को तुच्छ ठहराने का फल उसी के लिए अहितकर होगा ।

पिछले पच्चीस वर्षों में हिन्दी का तेजी से प्रसार हुआ है, इस प्रसार के साथ उस पर जनपदीय बोलियों और पड़ोसी भाषाओं का गहरा असर पड़ा है । बोलचाल की हिन्दी का यह प्रसार, उस पर जनपदीय बोलियों और पड़ोसी भाषाओं का गहरा प्रभाव उसका विकास है, उसका ह्रास या उसके रूप का बिगड़ना नहीं है । यह बोलचाल की हिन्दी हमारी जातीय भाषा है, वही सारे देश के लोगों की राष्ट्रभाषा है । उसके विकास और प्रसार को रोकना किसी राजनीतिज्ञ के वश में नहीं है, उस हिन्दी-उर्दू के दो रूपों में बाँटना किसी संप्रदायवादी के हाथ में नहीं है ।

हिन्दी का यह आधुनिक विकास उसे व्रजभाषा के समीप लाता है और संस्कृत-गर्भित परिनिष्ठित हिन्दी (तथा फारसी-अरबी-गर्भित उर्दू) से दूर ले जाता है । ऐसा होना स्वाभाविक है । अवधी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, मैथिली आदि व्रजभाषा की तरह तद्भव रूप अपनाती है, संयुक्त वर्णों वाले, उच्चारण में क्लिष्ट, तत्सम रूप नहीं । जनपदीय बोलियों के तद्भव रूपों में आज की हिन्दी जितना ही प्रभावित होगी, उतना ही वह व्रजभाषा के अनु रूप बनेगी; क्योंकि यह व्रजभाषा भी तद्भव प्रधान है । अथ व्रजभाषा चाहे साहित्य की हो, चाहे बोलचाल की, उसके रूप में विशेष अन्तर नहीं पड़ता । कुछ विद्वान् कहते हैं, साहित्य की भाषा और बोलचाल की भाषा में हमेशा बड़ा अन्तर रहता है । वे व्रजभाषा का विशाल साहित्य देखें और बतायें कि वह बोलचाल की व्रजभाषा से मूलतः कहीं भिन्न है । आज की हिन्दी अंग्रेजी मुहावरों, अंग्रेजी वाक्य विन्यास से निरन्तर प्रभावित होकर अपना रूप बिगाड़ रही है, फारसी से प्रभावित होकर व्रजभाषा ने अपना रूप नहीं बिगड़ने दिया । अपनी शिष्टता और विद्वत्ता प्रकट करने के लिए हम आज की हिन्दी में ज़िम ढग से नये गढ़े हुए शब्द भरते हैं, उस तरह व्रजभाषा के कवियों ने नहीं भरे । व्रजभाषा की ध्वनियाँ, उनके शब्द रचने का ढग बोलचाल में वही है जो साहित्य में है । साहित्य की व्रजभाषा और बोलचाल की व्रजभाषा में वंसा अन्तर नहीं है जैसा बोलचाल की हिन्दी और साहित्य की हिन्दी में आज है ।

यह दुर्भाग्य की बात है कि व्रजभाषा और खड़ी बोली के विवाद में पढ़कर बहुत स लेखकों ने अपनी हिन्दी को व्रजभाषा की राह से हटाकर संस्कृत की ओर मोड़ा । यदि हम भारनेन्दु, प्रतापनारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बाल-मुकुन्द गुप्त जैसे पुराने लेखकों के गद्य पर ध्यान दें तो विदित होगा कि उनका

खड़ी बोली गद्य व्रजभाषा से प्रभावित है, या उसके अनुरूप है। उसकी मर-  
मना और सजीवता का यह बहुत बड़ा कारण है। प्रेमचन्द या घमूतनाल नागर  
का बहुत-सा गद्य-लेखन जनपदीय बोलियों में प्रभावित हान के कारण उसी पर-  
परा में जुड़ा हुआ है। हिन्दी लेखकों के लिए भाषा और साहित्य की मजसे बड़ी  
विरामत व्रजभाषा में सुरक्षित है। वह विरासत घर बैठे मुनभ है, उस अपना-  
कर हम अपनी भाषा को समर्थ बनायें, कमजोर नहीं। अनेक क्रियापद जनपदीय  
बोलियों के नित व्यवहार की चीज हैं, अपनी परिनिष्ठित हिन्दी से हम उन उन्हें  
निकाल दिया है। वे सब व्रज साहित्य में सुरक्षित हैं। उनके लिए हिन्दी का  
द्वार खोल देना चाहिए। हिन्दी में नये तद्भव रूपों का बतना बन्द हो गया  
है, नये रूप बनाना दूर, पुराने तद्भवी से हम अपने को भरमर बचाते हैं। उर्दू  
की सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह जनपदीय बोलियों से दूर होती गई,  
इस बात में हिन्दी उसका अनुसरण क्यों करे? हिन्दी की शक्ति इस बात में  
थी कि वह जनपदीय बोलियों से जुड़ी हुई थी। उस अपनी शक्ति का यह  
आधार न छोड़ना चाहिए।

जनपदीय बोलियों में व्रजभाषा पर ही विशेष ध्यान क्यों दिया जाय, इसके  
बड़े कारण हैं। पहला कारण यह कि भाषा को निखारने, सँधारने का काम  
जितना व्रज में हुआ है, उतना अन्य किसी बोली में नहीं। यहाँ लेखकों के लिए  
वे आदर्श रूप तैयार कर दिये गये हैं, जिनके अनुकरण से वे खड़ी बोली को  
अधिक लोकप्रिय बना सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि साहित्य की व्रजभाषा  
ने सीमित व्रज क्षेत्र की भाषा मपदा से ही अपना ठाठ नहीं रचा है, उसमें अनेक  
जनपदों के महत्वपूर्ण भाषा तत्व भी समेट लिये गये हैं। ऐसा होना अनिवार्य  
था क्योंकि व्रजभाषा के अविभाज्य भाग व्रज प्रदेश के रहन वासे नहीं थे। नये  
मिरे से मेहनत करके विभिन्न जनपदों से भाषातत्व समेटकर अपनी जातीय  
भाषा को पुष्ट करने के बदले हिन्दी लेखक व्रजभाषा-साहित्य के अध्ययन से ही  
अपनी खड़ी बोली में उन बहुत से भाषातत्वों का समावेश कर सकते हैं। तीसरा  
और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि हरियाणा की गद्दी बानी ने आधुनिक  
हिन्दी उर्दू का रूप ही व्रजभाषा के प्रभाव से ग्रहण किया है। व्रजभाषा का रस  
उसकी छट्टी में उसे पिलाया गया था। इसलिए व्रजभाषा की अनुकूलता हिन्दी  
के विकास का ऐसा नियम है जो निमग्न-सिद्ध है और उसका आधुनिक रूप की  
चसोटी है।

इस तीसरे कारण पर थोड़ा और विचार करना उचित होगा।

कहते हैं कि उर्दू देहली की जवान है। इस जवान का देहली के आसपास  
के गाँवों से क्या सम्बन्ध है?

कहते हैं कि हिन्दी दिल्ली और मेरठ की भाषा है। दिल्ली और मेरठ के  
जनपद अर्थात् हरियाणा से इस भाषा का क्या सम्बन्ध है?

हिन्दी और उर्दू का व्याकरण तब मूलतः वही है जो हरियाणा की बोली

का है। ब्रजभाषा की तरह 'खाऊगो' या अवधी की तरह 'खाब,' 'खइवे' रूप हिन्दी में नहीं चलते। 'खाऊगा' रूप हरियाणा की देन है। हिन्दी-उर्दू ने अपना व्याकरण-तंत्र हरियाणा की जनपदीय खड़ी बोली (अथवा बांगरू) से पाया है, उसका ध्वनितंत्र ब्रजभाषा की देन है। दीर्घ स्वर के बाद सयुक्त व्यंजनो का प्रयोग बांगरू की विशेषता है। रोट्टी, टेसण, वेलण (वेलन) जैसे ध्वनिबन्ध हिन्दी-उर्दू के लिए (और ब्रज से लेकर मैथिली तक जनपदीय बोलियों के लिए) अस्वाभाविक हैं। बांगरू में लकार की भरमार है। घाळी, हपेळी, बाळक; हिन्दी-उर्दू (तथा ब्रज से लेकर मैथिली तक जनपदीय बोलियों) में इसका पूर्ण बहिष्कार है। बांगरू के ध्वनितंत्र की ऐसी अनेक विशेषताएँ हैं जिनका हिन्दी में अभाव है। उन सब की चर्चा करना यहाँ अनावश्यक है। एक अन्य विशेषता की ओर ध्यान दिलाना काफी होगा। अपनापण, निणापण, दाणा, पाणी, जाना, आणा, कितणा, सुणना जैसे रूपों में मूर्धन्य अनुनासिकों की बहुतायत ब्रज तथा अन्य पूर्वी जनपदीय बोलियों को अग्राह्य है। हिन्दी में तो संस्कृत के प्रभाव से तत्सम रूपों में णकार लिखा भी जाता है (बोलने में उसकी निरन्तर अवहेलना होती है) किन्तु उर्दू में तो उसे पढ़ने की अनुमति ही नहीं मिली। है न आश्चर्य की बात! बांगरू जनपद का मुख्य नगर दिल्ली और उसकी भाषा में णकार का अभाव। दिल्ली के उत्तर और पश्चिम में णकार प्रेमी पंजाबी और राजस्थानी बोलियों का प्रसार, पूरब और दक्खिन में बांगरू, फिर भी णकार का अभाव! अपने चारों ओर विरोधी ध्वनितंत्र के समुद्र में दिल्ली शहर एक द्वीप के समान था जिस पर ब्रजभाषा के ध्वनि-तंत्र की पताका फहराती थी। जातीय भाषा के रूप में हिन्दी के प्रसार का एक प्रमुख कारण उसमें हरियाणा के व्याकरण तंत्र और ब्रजभाषा के ध्वनितंत्र का चमत्कारी समन्वय है। व्याकरण तंत्र स हिन्दी पछाही बोलियों को अपनी ओर खींचती है, ध्वनितंत्र से (बुन्देलखड़ी-वधेली आदि के साथ) पूर्वी बोलियों को। यूरप और भारत की आधुनिक भाषाओं ने प्रायः किसी एक बोली के आधार पर ही अपना आधुनिक रूप विकसित किया है। व्याकरण तंत्र एक बोली का, ध्वनितंत्र दूसरी बोली का, ऐसा सामञ्जस्य अन्यत्र दुर्लभ है। हिन्दी जो पूर्वी और उत्तर पश्चिमी जनपदों को सामान्य जातीय जीवन में बाध सकी है, उसका एक ऐतिहासिक कारण यह अनुपम सामञ्जस्य है।

दिल्ली से भिन्न आगरा नगर ब्रज जनपद का प्रमुख केन्द्र है। इस नगर के उत्तर, दक्खिन, पूरब, पच्छिम चारों ओर ब्रजभाषा को छोड़कर दूसरी बोली की पैठ नहीं है। खड़ी बोली की एक टकसाल आगरे में भी थी। अकबर और शाहजहाँ के जमाने में आगरा एशिया में व्यापार की सबसे बड़ी मंडी था। दिल्ली और हरियाणा समेत अनेक नगरों और जनपदों के व्यापारी और कारीगर यहाँ इकट्ठे हुए थे। ब्रजभाषा के परिवेश में ये खड़ी बोली का व्यवहार करते थे, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वे रोट्टी को रोटी कहें, टेसण को

टेसन, बाळक को बालक, घाणा-जाणा को घाना-जाना ।

---

१६०० से १८०० ई० तक खड़ी बोली के विकास का यह स्वर्ण युग है जब उस पर ब्रजभाषा का गहरा असर पड़ा। इस खड़ी बोली पर आगरे की छाप है। आगरे की खड़ी बोली का एक खास सर्वनाम रूप है— विस, 'इसका बहुवचन हुआ—विन। सल्लूजी साल आगरे के, उनकी खड़ी बोली में 'विस' का आना लाजमी था। "विसका सार ले, यामनी भाषा छोड़, दिल्ली आगरे की खड़ी बोली में वह नाम प्रेमसागर धरा" (दिल्ली मेरठ की खड़ी बोली नहीं, दिल्ली आगरे की खड़ी बोली।), "विन्हें देख परीछित मन में कहने लगे"। राजा शिवप्रसाद ने 'गुटका' में "सल्लूजी की बोली" के जो नमूने इकट्ठे किये, उनमें 'विस' और 'विन' भी थे। किन्तु इनका सम्बन्ध सल्लूजी की किसी व्यक्तिगत बोली से नहीं, आगरे की बोली से था। ये रूप सदल मिथ के नासिकेतो-पाख्यान में भी हैं, "और वेद की आज्ञा से सतान के लिए पत्नी सो भोग करना उचित है, नहीं तो विस विन क्या कभी क्रिया सिद्ध होती है", "और जिस जिस के लाने को धर्मराज विन को बरजते हैं"। गिनक्रिस्ट के हिन्दुस्तानी भाषा के व्याकरण (सन् १७९६) में एक मसिया है जिसमें विस और विन का प्रयोग किया गया है।

दिखला वे विन बच्चों को विस के लहू की नाली

तेगो को लाके विन पर बच्चे को फिर सँभाला।

यह मसिया गोपीचंद नारंग ने अपनी छोटी किन्तु सारगर्भित पुस्तक "करखन्दारी डायनेक्ट ऑव डेलही" में उद्धृत किया है। करखन्दारी डायनेक्ट यानी पारखाने के मजदूरों की बोली। इन मजदूरों की बोली में—दिल्ली की परिनिष्ठित उर्दू से भिन्न—आगरे की खड़ी बोली के वे रूप आज भी कायम हैं जिन्हें उनके बाप दादे अपने साथ दिल्ली ले गये थे। "विसी की तो बान कर रिया हू", "विनो ने झुटिया भर के विन के आगे करी"—यह दिल्ली के जनसाधारण की खड़ी बोली है और यह आगरे की खड़ी बोली भी है। भूमतलाल नागर ने आगरे के लोगों से सुनकर और सीखकर इस बोली का प्रयोग 'सेठ बकिमल' में किया है : "विन्ने रो-रो के वही कि प्यारी रो मती। हाय, तेरी भावो का सुरमा बहा जाय है। जे बहके विस कलेजे से लगा लीना", "इत्ता बहना या मयो कि विसकी आखें उलटने लगी। विन्ने दो बार भल्ला भल्ला करके चोला छोड़ दीना।"

हिन्दी के पुराने व्याकरणों और कोशों में ये रूप बराबर मिलते हैं। हिन्दी-उर्दू के विकास में आगरे के महत्वपूर्ण योगदान का यह प्रमाण है।

पुरानी हिन्दी में देखियो, करियो, लाइयो जैसे क्रिया रूपों की भरमार है। ये कविता में, भाषा को आकर्षक बनाने के लिए ब्रजभाषा से उधार लेकर नहीं रख दिये गये। ये दिल्ली और आगरे की ब्रजभाषा प्रभावित खड़ी बोली के अपने रूप हैं। मजीर भकवरावादी ने कन्हैया जी के जन्म का वर्णन करते हुए

हिन्दी के आधुनिक विकास-सन्दर्भ में ब्रजभाषा की भूमिका १/२६

लिखा :

ये सोच हुआ मन बीच उन्हें पैंर इस जल में कैसे धरिये ।

है रैन धँधेरी सँग बालक इस विपता में अब क्या करिये ।

मीर का शेर है

दादो फरियाद जावजा करिये,

शायद उसके भी दिल में जा करिए ।

और गालिब •

पड़िये गर बीमार तो कोई न हो तीमारदार,

और अगर भर जाइये तो नौहूँवा कोई न हो ।

गालिब और मीर दोनों आगरे के थे, आगरे से जाकर दिल्ली बसे थे ।

फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने शिक्षा-विभाग के माध्यम से हिन्दी-उर्दू को दो दिशाओं में विकसित करने का संगठित प्रयास किया । हिन्दुओं के बच्चे चाहे एक बार उर्दू पढ़ लें, मुसलमानों के बच्चे हिन्दी नहीं पढ़ेंगे; इतिहास और भूगोल की स्कूली किताबों में हिन्दी की पारिभाषिक शब्दावली अलग, उर्दू की अलग । फोर्ट विलियम कालेज से पहले मुसलमानों ने चाहे पंजाबी लिखी हो, चाहे ब्रजभाषा या बँगला, उसमें अरबी-फारसी के लिए वह आग्रह नहीं है जो उर्दू में है । फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना से पहले खड़ी बोली में जो भी साहित्य लिखा गया है, वह शब्दावली के आधार पर हिन्दी-उर्दू के दो भिन्न रूपों में नहीं बाँटा जा सकता । दिल्ली और आगरे के मुसलमानों की इस पुरानी खड़ी बोली पर ब्रज 'भाषा' का हों नहीं, उसकी साहित्यिक परंपरा का भी गहरा असर है । मेरठ-निवासी मुहम्मद अफ़जल उर्फ़ शाह अफ़जल ने "विकट कहानी-बारह मासा" में जिस भाषा का प्रयोग किया है, उसे डा. नमूद हुसैन खा और डा. विद्यासागर ने अपनी भूमिका में उचित ही सोलहवीं सदी की खड़ी बोली हिन्दी का नमूना स्वीकार किया है ।

किनारे लग रही पिउ बिन अकेली,

भई है ज़िदगी मुझ पर दुहेली ।

तुम्हीं टुक कर पकड़ समझाय कहियो,

पगल पर सीस धर कर लाय कहियो ।

अगर मैं जानती यह बेवफ़ाई,

खुदा की सौं न करती आशनाई ।

अरे ऊधो सुनो यह दुख हमन सूं,

कहो टुक जाय परदेसी सजन सूं ।

सोलहवीं सदी में—फारसी के राजभाषा बने रहने पर भी—हिन्दुओं और मुसलमानों की जातीय भाषा को साहित्य में जो सहज सरस रूप मिला था, वह ऐसा था । मुगल साम्राज्य के विघटन के समय, और फोर्ट विलियम कालेज

की स्थापना के बाद विकास का यह सहज क्रम टूट गया। जहाँ से यह क्रम टूटा था, सन ४७ में फिर से उसे जोड़ना पड़ा। किन्तु राजनीतिज्ञों ने स्वराज्य आन्दोलन के समय किये हुए और वादों की तरह हिन्दी-उर्दू की एकता वाली पुरानी बात भी उठाकर ताक पर रख दी। वे कहते हैं, हिन्दी वाले एक और उर्दू को दबाते हैं, दूसरी ओर हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के उत्साह में दक्षिण के लोगों के मन में भय उत्पन्न करते हैं। एक राजनीतिज्ञ ने पिछले महीने लखनऊ की एक सभा में यहाँ तक कहा—याहिया खाँ ने पाकिस्तान में उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाना चाहा, क्या नतीजा हुआ? पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गये। क्या आप चाहते हैं कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हम दक्षिण में फौज भेजें और भारत के दो टुकड़े हो जाने दें?

सुना है स्वाधीन बंगला देश में वहाँ की राजभाषा बंगला है। पश्चिमी बंगाल की राजभाषा अंग्रेजी है। यदि कोई कहे कि पूर्वी बंगाल की तरह पश्चिमी बंगाल में भी बंगला को राजभाषा बनाइये तो राजनीतिज्ञ कहेंगे, पूर्वी बंगाल जैसे पाकिस्तान से अलग हुआ, वैसे ही पश्चिमी बंगाल को तुम भारत से अलग करना चाहते हो?

यानी हर परिस्थिति में, हर तर्क-योजना के अंत में आप पहुँचेंगे एक ही लक्ष्य तक—भारत में अंग्रेजी वायम रहनी चाहिए।

इस लक्ष्य सिद्धि के लिए इनके पास तीन दाँव हैं।

पहला—हिन्दी और अहिन्दी भाषियों को एक दूसरे से लड़ाना, इनके परस्पर भय और रागद्वेष से लाभ उठाकर समस्त भारतीय भाषाओं को दबाकर रखना,

दूसरा—हिन्दी और उर्दू के भेद को गहरा करना, हिन्दी उर्दू को दबाये है, एक महत्वपूर्ण भाषा नेस्तनाबूद होने को है, इसलिये हिन्दी भाषी प्रदेश में भी हिन्दी को अपना स्वत्व न मिलना चाहिए।

तीसरा—हिन्दी और उसकी जनपदीय बोलियों को एक दूसरे से लड़ाना, साहित्य अकादमी द्वारा अनेक बोलियों का मान्यता दिलाकर उनको हिन्दी से स्वतंत्र भाषा करार देना, क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ावा देकर पहले से ही चेंटे हुए हिन्दी प्रदेश को और भी छोटे-छोटे टुकड़ों में बाटना।

दिवालिया शासक वर्ग इस कूटनीति द्वारा जनता को डगने के अलावा और कर ही क्या सकता है?

किसे फुसंत है यह देखने की कि फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना से पहले हिन्दी उर्दू का भेद था या नहीं और उस समय की खड़ी बोली पर ब्रजभाषा का प्रभाव गहरा था या उबला?

हिन्दी लेखकों का कोई जातीय भय नहीं है। इसलिए उपर्युक्त कूटनीति का कोई उत्तर हिन्दी की ओर से नहीं दिया जा रहा है। किन्तु भारत की जनता अपने ढंग से, परिस्थितियों को साफ-साफ न पहचानते हुए, फिर भी निरन्तर

उनसे प्रेरित और प्रभावित होकर, इस कूटनीति का उत्तर दे रही है।

पहले दांव का उत्तर यह है कि अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी का प्रसार ही नहीं हो रहा, वह अहिन्दी भाषाओं से प्रभावित होकर नये-नये स्थानीय रूप भी ग्रहण कर रही है। अंग्रेजों ने अठारहवीं सदी में मद्रास की सेना के अंग्रेज अफसरों के लिए दक्कनी हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया था, उस समय हैदराबाद की हिन्दी दक्षिण भारत में प्रचलित हिन्दी का एक मात्र रूप थी। इस समय हैदराबादी दक्कनी के अलावा, चार प्रमुख द्रविड़ भाषाओं का प्रभाव ग्रहण करती हुई हैदराबाद के दक्षिण में कन्याकुमारी तक, हिन्दी के एक नये रूप का चलन हो रहा है, जिसे हम द्राविडी हिन्दी कह सकते हैं। इसका व्यवहार द्रविड़ भाषा भाषी सामान्य जन उत्तर भारत के आर्य भाषा भाषियों से संपर्क होने पर ही करें, यह आवश्यक नहीं है, स्वयं आपस में एक दूसरे की बात समझ पाने के लिए, अंग्रेजी का ज्ञान न होने पर, उन्हें हिन्दी का सहारा लेना पड़ता है। हिन्दी का व्यवहार सबसे पहले और सबसे अधिक अहिन्दी भाषियों के आपसी संपर्क के लिए जरूरी है। हिन्दी के प्रसार का यह वस्तुगत कारण है। इसके लिए हिन्दी भाषी उत्तरदायी नहीं है। दरअसल पिछले बीस वर्षों में हिन्दी का प्रसार कार्य बिल्कुल ढीला हो गया है, जनता का पैसा सरकार के माध्यम से चाहे जितना बांटा गया हो, पर यह सच है कि प्रचार जितना ही कम हुआ, प्रसार उतना ही ज्यादा हुआ। कारण वही है, स्वाधीन भारत की अहिन्दी भाषी जनता के आपसी संपर्क की उत्कट आवश्यकता। विदेशी राज्या द्वारा करोड़ों रुपये (भारतीय शासन द्वारा लाखों रुपये) अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने पर खर्च किये जाने पर भी संपर्क की इस आवश्यकता को अंग्रेजी पूरा नहीं कर सकती।

द्राविडी हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा का दक्षिणी रूप है, नये स्वाधीन भारत का अकाद्य यथार्थ है। इस यथार्थ को देखने के लिए मद्रास जाना आवश्यक नहीं है, दिल्ली या आगरे में भी उसके दर्शन हो सकते हैं।

दूसरे दांव का उत्तर यह है कि हिन्दी भाषी प्रदेश के हिन्दू और मुसलमान, गांवों के करोड़ों किसान और नये औद्योगिक विकास के साथ नये नये लाखों मजदूर—हिन्दू और मुसलमान—एक सा जातीय जीवन बिता रहे हैं। उन्हें आपसी व्यवहार के लिए दुभाषिये की जरूरत नहीं पड़ती, न वे राष्ट्र के सूत्रधारों की तरह देश-जनता-राजनीति जैसे शब्द कहकर मुल्क अक्वाम सियासत के द्वारा अपनी बात का अनुवाद करते हैं। बंगला और तमिल फिल्म बंगाल और तमिल-नाडु के बाहर दिखाना हो तो उसके सबादों का हिन्दी रूपान्तर जरूरी होता है। किसी हिन्दी फिल्म का उर्दू रूपान्तर या उर्दू फिल्म का हिन्दी रूपान्तर अभी तक देखने-सुनने में नहीं आया। जनता की इस सामान्य भाषाई एकता का आधार छोड़कर जो भी भ्रमलाप का हवामहल बनायगा, वह उस हवामहल की तरह खुद भी एक दिन इस धरती से हवा हो जायगा।

तीसरे दौब के उत्तर में हिन्दी प्रवेश के जनपदों ने आपसी एकता को और दृढ़ किया है। जयपुर, मथुरा, फरीदाबाद, झारसी, पटना—कहीं कोई ऐसा कारखाना, कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान ऐसा नहीं है जिसमें एक ही जनपद के लोग काम करते हों, जिसमें वे आपस में किसी एक जनपदीय बोली का ही व्यवहार करते हों। श्रमिक जनता की यह एकता हमारी जातीय एकता की धुरी है। जो लोग जनपदीय झलगाव को बढ़ावा देते हैं, वे इस धुरी पर ही प्रहार करते हैं। इससे उन्हीं के सर में चोट लगेगी। जनपदीय बोलियाँ हिन्दी को निरन्तर प्रभावित करती हुई उस क्षेत्रीय रूप देकर उसे स्थानीय जनता के अनुरूप बना रही हैं।

इस परिस्थिति में—हिन्दी के इस आधुनिक विकास सन्दर्भ में—हमें ब्रजभाषा की भूमिका पर विचार करना चाहिए। हिन्दी प्रदेश के सभी जनपदों में ब्रजभाषा का साहित्य ही सबसे विशद है, अन्य जनपदों में यह साहित्य आज भी लोकप्रिय है, नये तद्भव गढ़ने और तद्भवों में तत्समों को खपाने की कला के श्रेष्ठ उदाहरण इसके साहित्य में हैं, अन्य जनपदों की बहुत सी भाषा-संपदा साहित्यिक ब्रजभाषा में पहले ही सिमट आई है, हरियाणा की खड़ी बोली को हिन्दी-उर्दू का सरस, सामान्य रूप देने का श्रेय ब्रजभाषा को है, हिन्दी से उसका सम्बन्ध जन्मजात है, तब उसके विकास में ब्रजभाषा का योगदान ऐतिहासिक रूप से आवश्यक है। आज की लिखित हिन्दी के स्वभाव को ब्रजभाषा के अनुकूल बनाना विकास की उन कड़ियों को फिर से जोड़ना है जो फोटे विलियम कालेज की स्थापना के बाद टूट गई थी।

आज की लिखित हिन्दी जितना ही ब्रजभाषा के अनुकूल होगी, उतना ही वह हिन्दी जनपदों में लोकप्रिय होगी, उतना ही वह हिन्दी-उर्दू का भेद मिटाने में समर्थ होगी, उतना ही वह अहिन्दी प्रदेशों, विशेषकर दक्षिण भारत में, लोकप्रिय होगी। याद रखना चाहिए कि द्रविड भाषाएँ सब्बों संस्कृत रूपों को निरन्तर तद्भव बनाती रही हैं। तमिल 'क्वचाड' हिन्दी 'क्वछा' के अनुरूप है, संस्कृत 'क्वथा' के नहीं, वन्नड 'वट्टि' हिन्दी 'भट्टा' के अनुरूप है, संस्कृत 'भ्राष्ट्र' के नहीं, 'श्री' का तत्सम उच्चारण द्रविड भाषियों के लिए बँसा ही कठिन है जैसा ब्रजवासियों के लिए, तिरुपति से लेकर 'तिरुमनन्तपुरम्' (ट्रिवेण्ड्रम्) तक सब कहीं 'श्री' के तद्भव रूप 'तिरु' की ही शोभा है। वरुण नहीं, वरुणम्, अरुण्य नहीं, अरुणिगर, अरुंत नहीं, अरुहन्, क्षेप नहीं, चेमम्, स्थान नहीं, तानम्; ऐसी सब्बों मिसालें हैं जिनसे यह समझते देर न लगेगी कि अस्तित्व तमिल भाषी के लिए ब्रजभाषा के तद्भव रूप ही सुगम हैं, लिखित हिन्दी (खास तौर से सरकारी हिन्दी) के तत्सम रूप नहीं।

चाहे जनपदीय स्तर पर विचार करें, चाहे प्रादेशिक स्तर पर, यह निष्कर्ष अनिवार्य है कि आज की लिखित हिन्दी मित्र की ब्रजभाषा के अनुरूप ढालकर ही अपने ऐतिहासिक विकास की मजिल तक पहुँच सकती है। १९७५

हिन्दी के आधुनिक विकास सन्दर्भ में ब्रजभाषा की भूमिका



## हिन्दीभाषी प्रदेश—बहुभाषाभाषी प्रदेश ?

कुछ दिन पहले एक भारतमित्र विदेशी विद्वान् क० मु० विद्यापीठ द्वारा पधारे थे। वह भारत में काफी दिन रह चुके हैं, बहुत अच्छी हिन्दी बोलते हैं और हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में बहुत कुछ ज्ञान भी चुके हैं। इस समय वह हिन्दी भाषी प्रदेश की भाषाई स्थिति पर शोध कार्य कर रहे थे। उनकी धारणा यह थी कि हिन्दी प्रदेश बहुभाषाभाषी प्रदेश है और इस प्रकार भारत या पूरुष के भाषाई क्षेत्रों से इसकी स्थिति भिन्न है। अपनी धारणा के प्रमाणस्वरूप उन्होंने इन तथ्यों का हवाला दिया। हिन्दी प्रदेश में काफी लोग सामाजिक और पारिवारिक जीवन में अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं। भाषा में हिन्दी बोलते हुए भी बीच बीच में अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं। इसके अनिश्चित हिन्दी और उर्दू दो भिन्न भाषाएँ हैं, इसमें संदेह ही क्या है, और इन दोनों का मुख्य व्यवहार क्षेत्र एक ही प्रदेश यानी हिन्दी भाषी प्रदेश है। उर्दू के अलावा अनेक सांस्कृतिक कार्यों में, विशेष अवसरों पर धार्मिक कृत्यों में, संस्कृत का व्यवहार होता है। मुसलमान लोग अरबी का व्यवहार करते हैं। संभव है, कुछ लोग फारसी का व्यवहार भी करते हों। धर्म-विशेष के लोग पालि और प्राकृत में पवित्र वचनों का पाठ करते हैं। हिन्दी प्रदेश में जहाँ भी जाते हैं वहाँ देहात में हिन्दी में अलग बोली सुनाई देती है। कहीं लोग भोजपुरी बोलते हैं कहीं मैथिली, वही अजभाषा कहीं कोई अन्य बोली। व्याकरण उच्चारण आदि के विचार से ये बोलियाँ एक दूसरे से बहुत भिन्न हैं और स्वतंत्र भाषाओं जैसी लगती हैं। देहात के अलावा शहरों में भी अलग-अलग ढंग की हिन्दी सुनाई देती है। कलकत्ता, बम्बई, हैदराबाद, पटना और दिल्ली की हिन्दी में काफी अन्तर है। हिन्दी प्रदेश में ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहाँ द्रविड और मुंडा परिवारों की भाषाएँ बोली जाती हैं। इन सारे तथ्यों को देखने से यह प्रमाणित होता है कि हिन्दी-भाषी प्रदेश एक भाषा का प्रदेश नहीं है, यहाँ अनेक भाषाओं का व्यवहार होता है। उस बहुभाषाभाषी प्रदेश कहना अधिक युक्तिसंगत है।

उस मोड़ी में उक्त स्थापना के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ कहा, उसका सारांश

इस प्रकार है ।

आदरणीय विद्वान् ने हिन्दी प्रदेश की भाषाई स्थिति के बारे में जो कुछ कहा है, वह सभी लोगों के ध्यान देने योग्य है । उन्होंने हिन्दी-भाषी प्रदेश की चर्चा करते हिन्दी के जातीय क्षेत्र की स्वीकार किया है । जहाँ की भाषा-समस्या का अध्ययन वह कर रहे हैं, वह हिन्दी प्रदेश है, वह हिन्दी भाषा का जातीय क्षेत्र है, हिन्दी जाति का अपना प्रदेश है, वह हिन्दी-उर्दू-अंग्रेजी-संस्कृत-अरबी प्रदेश नहीं कहलाता । मूल बात यह है कि हिन्दी बोलने वालों की एक जाति है, यह जाति अनेक भाषाओं के व्यवहार के कारण विभाजित नहीं है, इस जाति के सदस्यों को जोड़ने वाली भाषा हिन्दी है, हिन्दी छोड़कर अन्य कोई भाषा यह कार्य नहीं करती । मुख्य स्थान इसी हिन्दी भाषा का है, अन्य भाषाएँ, उपभाषाएँ, बोलियाँ, विदेशी भाषाएँ, प्राचीन भाषाएँ आदि गौण स्थान पर हैं । वे विभाजित भले करती हों, जोड़ती नहीं हैं, जोड़ने का काम केवल हिन्दी करती है । यह भी स्पष्ट है कि जोड़ने की प्रक्रिया ऊपर है, अधिक शक्तिशाली है, तोड़ने की प्रक्रिया नीचे है और निरबल है । ऐसी बात न हो तो हिन्दी भाषी प्रदेश जैसे किसी प्रदेश की कल्पना ही न की जाय, उसकी भाषाई स्थिति की चर्चा का अवसर ही न पाये । हिन्दी प्रदेश वैसे ही यथार्थ इकाई है जैसे अंग्रेजी भाषा या रूसी भाषा का प्रदेश यथार्थ इकाई है । राजनीतिक रूप से यह प्रदेश अनेक राज्यों में बँटा हुआ है । जर्मनी, कोरिया, वियतनाम, बंगाल दो राज्यों में बँटे हुए हैं, इससे जर्मन, कोरियाई, वियतनामी, बंगाली जातियाँ और भाषाएँ विभाजित नहीं हो जाती । आदरणीय विद्वान् हिन्दी प्रदेश का अस्तिरत्व स्वीकार करते हैं, उनकी और मेरी स्थापनाओं की यह सामान्य आधारभूमि है ।

अब देखना चाहिए कि इस तरह की स्थिति केवल हिन्दी प्रदेश में उत्पन्न हुई है या इससे मिलती जुलती स्थिति अन्य देशों में भी है अथवा कभी रही है ।

विदेश में जो भी विद्वान् हमारे प्रदेश में आता है, उसे यहाँ के पञ्च-विध लोगों में अंग्रेजी का व्यापक व्यवहार देखकर आश्चर्य होता है । अंग्रेजी का व्यवहार इसलिए नहीं होता कि यहाँ तमिल या तेलुगु बोलने वालों से हिन्दी-भाषियों को सम्पर्क काममें करना है, और वे हिन्दी नहीं जानते, इसलिए अंग्रेजी का व्यवहार करना है । हिन्दी-भाषी लोग ही आपस में अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं, विश्वविद्यालयों में इसी प्रदेश के अध्यापक इसी प्रदेश के छात्रों को अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा देते हैं, यहाँ के राजकीय अराजकीय कार्यालयों में अंग्रेजी का काफी व्यवहार होता है । इसका कारण हमारी राजनीतिक और सांस्कृतिक पराधीनता के अवशेष हैं । किन्तु इस तरह की स्थिति हमारे प्रदेश अथवा समस्त भारत देश के लिए घनोष्ठी नहीं है । किसी समय इंग्लैंड पर नार्मन लोगों का प्रभुत्व था । उस समय इंग्लैंड का अभिजात वर्ग सामाजिक और पारिवारिक जीवन में व्यापक रूप से फ्रांसीसी भाषा का व्यवहार करता था । १६वीं सदी में रूस का अभिजात वर्ग इसी फ्रांसीसी भाषा का व्यवहार करता था ।

यद्यपि नपोलियन और उसकी फ्रांसीसी सेना को रूसियों ने पराजित किया था, फिर भी सांस्कृतिक रूप से रूसी अभिजात वर्ग पर फ्रांस की भाषा और संस्कृति का बड़ा गहरा प्रभाव था। यह स्थिति ताल्स्तोय के उपन्यासों में बहुत अच्छी तरह चित्रित की गई है। फ्रांसीसी भाषा के प्रभाव से रूसी अभिजात वर्ग जर्मन भाषा का व्यवहार भी करता था। मध्य यूरोप के देशों में जर्मन का व्यवहार और भी व्यापक था जैसे कि चेकोस्लोवाकिया में। माक्स के समय में यह प्रभाव इतना अधिक था कि माक्स समझते थे कि चेक और स्लोवाक भाषाओं का अस्तित्व न रहेगा और उनकी जगह जर्मन भाषा का ही व्यवहार होगा। इन तथ्यों पर ध्यान देने से विदित होता है कि विशेष सामाजिक कारणों से अनेक देशों में जातीय भाषा के साथ उच्चवर्गों में विजातीय भाषा का व्यवहार भी हो सकता है और हुआ है। जब कोई जाति अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास करती है, अपनी आन्तरिक एकता सुदृढ़ करती है, तब वह विजातीय भाषा का प्रभाव उतार फेंकती है। ऐसा इंग्लैंड और रूस में हुआ है, चेकोस्लोवाकिया में हुआ है। हिन्दी प्रदेश और भारत में अंग्रेजी का जो व्यवहार दिखाई देता है, वह अस्थायी है। जब हिन्दी जाति सुगठित होगी, अपना सामाजिक सांस्कृतिक विकास करेगी, तब अंग्रेजी का व्यापक व्यवहार बन्द हो जायेगा। जब सारा देश राष्ट्रीय स्तर पर सुगठित होगा, तब अंग्रेजी का यह अखिल भारतीय महत्व समाप्त होगा। अभी यह अखिल भारतीय महत्व अन्य प्रदेशों की तरह हमारे प्रदेश को भी प्रभावित करता है। यह बात याद रखनी चाहिए कि अंग्रेजी का व्यापक प्रभाव भारत के बहुत थोड़े से पढ़े-लिखे लोगों के समुदाय में सीमित है उसकी व्यापकता अत्यन्त सापेक्ष है। हिन्दी प्रदेश में जनसाधारण के बीच व्यापक रूप से हिन्दी का ही व्यवहार होता है।

हिन्दी के साथ उर्दू का व्यवहार हमारे यहाँ का एक अनोखा व्यापार प्रतीत होता है। किन्तु हिन्दी उर्दू दो भिन्न भाषाएँ नहीं हैं, वे मूलतः एक ही भाषा है। इनके सर्वनाम, क्रियापद, मूल-शब्दभंडार एक ही हैं। ससार में कोई दो भाषाएँ ऐसी नहीं हैं जिनके सर्वनाम और क्रियापद सौपीसदी सामान्य हों। रूसी और उर्दू की भाषाएँ एक-दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं पर उनमें भी ऐसी समानता नहीं है। उर्दू की भिन्नता का कारण उसकी संरचना, उसकी मूल भाषाई सम्पदा नहीं है। उसकी भिन्नता का कारण अरबी फारसी शब्दावली का विशिष्ट व्यवहार है।

बहुत समय से जर्मनी में यहूदी लोग रहते आए हैं। इनकी धर्मभाषा हीब्रू है। हीब्रू उनकी बोलचाल की भाषा नहीं है, वह उनकी धार्मिक अथवा सांस्कृतिक भाषा है। जर्मन भाषा में यहूदिया ने हीब्रू शब्दावली मिलाकर एक भाषा गढ़ी जो यिद्दिश कहलायी। आइन्स्टाइन और फ्रायड जैसे यहूदियों ने अपनी जातीय भाषा जर्मन का ही व्यवहार किया, फिर भी बहुत से यहूदी अपने धर्म से हीब्रू भाषा का विशेष सम्बन्ध जोड़ने के कारण यिद्दिश को अपनाए

रहे। बहुत से जर्मन यहूदी रुस में जा बसे। वहाँ भी उन्होंने यिद्दिश चलाई। इस भाषा में उन्होंने अपने समाचार पत्र निकाले। मौस्को में इस भाषा में रचे जाने वाले नाटक खेलने के लिए एक विशेष नाट्यशाला बनायी गई। रुसी भाषा के विशाल जातीय प्रदेश में यिद्दिश का व्यवहार करने वाले यहूदियों का एक स्वायत्त क्षेत्र भी है। पर यहूदियों की कोई जाति नहीं है। रुसी, प्रासोसी, जर्मन आदि की तरह कोई यहूदी जाति नहीं है। धर्म अलग-अलग हैं पर ईसाई और यहूदी जर्मनो, ईसाई और यहूदी अंग्रेजों, ईसाई-यहूदी-ता-मजहब सभी तरह के रुसियों की जाति एक ही है। यिद्दिश में जैसे हीब्रू के बहुत से शब्द मिला दिये गये हैं, वैसे ही उर्दू में बहुत से अरबी-फ़ारसी शब्द मिला देने से उर्दू का अलगवाव पैदा हुआ है। जैसे बंगाल के हिन्दुओं और मुसलमानों की एक ही भाषा बंगला है, वैसे ही हिन्दी प्रदेश के हिन्दुओं और मुसलमानों की एक ही भाषा हिन्दी है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होने तक हमारे प्रदेश के मुसलमान अपनी भाषा को हिन्दी ही कहते थे। दोनों के बीच का फासला अंग्रेजी राज्य में ही बढ़ा है। उस राज्य के खत्म होने पर वह फासला कम हो गया है। जब हिन्दी प्रदेश की बहुसंख्यक किसान जनता साक्षर होगी, उसमें शिक्षा-प्रसार होगा, तब यह फासला पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। कबीर, मलिकमुहम्मद जायसी, दादू, रज्जब, रहीम, रसखान की परंपरा फिर जीवित होगी और यहाँ के हिन्दू और मुसलमान एक ही साहित्यिक भाषा के माध्यम से अपनी जातीय संस्कृति और साहित्य को समृद्ध करेंगे। जनसाधारण के निरक्षर और पिछड़े होने से, पुरानी रुढ़ियों के प्रभाव से, धर्म-विशेष के लोग अपनी जातीयता न पहचानकर उस धर्म-विशेष की भाषा से अपना सम्बन्ध जोड़ लेते हैं, उस भाषा का व्यवहार दैनिक जीवन में सभव नहीं होता, अतः उसके अधिक से अधिक शब्द जातीय भाषा में ठूसकर वे अपना अलगवाव कायम रखना चाहते हैं। हिन्दू-उर्दू का मुख्य भेद फारसी शब्दों के कारण नहीं है, अरबी शब्दों का लेकर है। फ़ारसी आर्यपरिवार की भाषा है, इसके सँकड़ो शब्द संस्कृत के तद्भव रूपों जैसे हैं। किन्तु अरबी सामी परिवार की भाषा है। इसके बहुत से शब्द तुर्की में आ गये थे। क़मालपाशा के समय में, और उसके बाद, तुर्कों ने अपनी भाषा को अरबी प्रभाव में मुक्त किया। उसी प्रकार नवजाग्रत ईरान के लोग आधुनिक फारसी को अरबीप्रभाव में मुक्त कर रहे हैं। इसलिए मेरा विदवास है कि हिन्दी प्रदेश में भी अरबी प्रभाव के कारण हिन्दी-उर्दू में जो भेद पैदा हुआ है वह अस्वास्थ्य है और कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा।

हिन्दी प्रदेश में विशेष अवसरों पर धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यों में संस्कृत, अरबी आदि प्राचीन भाषाओं का व्यवहार होता है। यह व्यवहार क्षेत्र अत्यन्त सीमित है और इससे जातीय भाषा का अस्तित्व क्षति नहीं होता। यूरूप के देशों में जहाँ ईसाइयों का रोमन कैथलिक सम्प्रदाय है, वहाँ गिरजाघर में

लैटिन का व्यवहार होता है। आगरे के एक गिरजाघर में अपने एक हिन्दी-भाषी रोमन कैथलिक बन्धु की बहन के विवाह में मैं उपस्थित था। वहाँ मैंने देखा कि जैसे हिन्दू विवाह में संस्कृत मंत्र पढ़े जाते हैं, वैसे ही यहाँ प्रार्थना या मंत्र पाठ लैटिन में हो रहा है। इंग्लैंड में ईसाइयों का प्रोटेस्टेंट मत फैलने पर अंग्रेजी का व्यवहार होने लगा, फिर भी अनेक पवित्र कार्यों के लिए लैटिन का स्थान सुरक्षित रहा। लन्दन का वेस्टमिनिस्टर गिरजाघर बड़ा पवित्र स्थान है। वहाँ देश के महान् पुरुष दफनाये जाते हैं। १८वीं सदी के प्रसिद्ध अंग्रेज लेखक डा० जानसन से उनके मित्रों ने मजाक किया, उनके सामने एक प्रार्थना-पत्र रखा कि वह कवि गोल्डस्मिथ का समाधि लेख अंग्रेजी में लिख दें तो उसे उनकी कब्र पर पत्थर में अंकित कराया जाय। डा० जानसन ने हँसते हुए कहा कि समाधि-लेख लैटिन में ही होगा, वेस्टमिनिस्टर गिरजाघर को अंग्रेजी के व्यवहार से अपवित्र नहीं किया जा सकता।

अंग्रेज कवि चौसर ने एक पादरी का वर्णन किया है कि जब वह होश में होता था, तब अंग्रेजी बोलता था, जब नशे में होता था तब केवल लैटिन बोलता था। नशा कई तरह का होता है। बहुत से लोग अब भी समझते हैं, ईश्वर उनके धर्म-विशेष की भाषा बोलता था और उसका व्यवहार न करने पर धार्मिक-सांस्कृतिक अनुष्ठानों की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। जहाँ धर्म में ईश्वर को जगह नहीं मिली, वहाँ उसकी जगह कोई सिद्ध पुरुष प्रतिष्ठित हुआ। उसकी यथार्थ या कल्पित वाणी को लोग धर्म की पवित्र भाषा मानने लगे। स्पष्ट है कि धर्म-भाषाओं का व्यवहार हिन्दी प्रदेश की विशेषता नहीं है। अन्यत्र भी ऐसा होता है और हुआ है किन्तु जातीय भाषाओं से भिन्न ऐसी धर्म-भाषाओं का व्यवहार-क्षेत्र निरन्तर संकुचित होना गया है।

यह बात सही है कि हिन्दी प्रदेश में बहुत सी बोलियों का व्यवहार होता है। यह स्थिति हिन्दी प्रदेश के लिए अनोखी नहीं है। भारत या यूरोप की कोई भाषा ऐसी नहीं है जिनकी अनेक बोलियाँ न हों। इंग्लैंड में उत्तर और दक्खिन के गाँवों की बोलियों में बड़ा अन्तर है। लन्दन शहर की अपनी बोली है जो परिनिष्ठित अंग्रेजी से भिन्न है। कुछ लोग वेल्स और स्कॉटलैंड की भाषाओं को अंग्रेजी की बोली मानते हैं पर वे अंग्रेजी से उतना ही भिन्न हैं जितना हिन्दी से तमिल। आधुनिक जातीय प्रदेश पुराने जनपदों के आधार पर बनते हैं, जातीय भाषा का निर्माण और प्रसार इन्हीं जनपदों की भाषाओं के बीच होता है। इस विकास की यह विशेषता होती है कि उद्योग-धन्यो और व्यापार के केन्द्रों में जातीय भाषा का व्यवहार होता है, विभिन्न जनपदों के लोग परस्पर सम्पर्क के लिए उसी जातीय भाषा का व्यवहार करते हैं। हिन्दी प्रदेश में कोई ऐसा नगर नहीं है जहाँ हिन्दी से अलग किसी जनपदीय भाषा का ही व्यवहार होता हो। कानपुर एक बड़ा औद्योगिक नगर है। यहाँ दूर-दूर के जनपदों से आकर मजदूर काम करते हैं। इनकी सम्पर्क भाषा हिन्दी है, अपने घर में वे चाहे

कनीजी बोलें चाहे बुन्देलखण्डी । ब्रज प्रदेश के नगर आगरे की सामान्य भाषा ब्रज नहीं है बुन्देलखण्ड के नगर भागी की सामान्य भाषा बुन्देलखण्डी नहीं है, भोजपुरी क्षेत्र के नगर बनारस की सामान्य भाषा भोजपुरी नहीं है । हर जगह मजदूरों व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगों की भाषा हिन्दी है । अब मान लीजिए, बनारस के किसी कारखाने में केवल भोजपुरी का व्यवहार हो, कानपुर में केवल कनीजी का व्यवहार हो, दिल्ली में बागरू का व्यवहार हो, तो सामाजिक विकास की सारी प्रक्रिया ठप हो जाएगी । सामाजिक विकास-प्रक्रिया के अनुरूप सारे प्रदेश में शिक्षा का माध्यम हिन्दी है । यदि शिक्षा के जनपदीय माध्यम बनाये जायें, भाँसी में शिक्षा का माध्यम बुन्देलखण्डी हो, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम भोजपुरी हो, प्रलीगढ़ विश्वविद्यालय में शिक्षा ब्रजभाषा के माध्यम से दी जाय, लखनऊ विश्वविद्यालय में अवधी के माध्यम से दी जाय, तो यह सम्भवे देर न लगेगी कि सारा सांस्कृतिक विकास तहसलहस हो जाएगा । इसके अलावा मध्याह्न जीवन में भाषाओं की जो स्थिति है, यह कार्य उससे त्रिलकुल उल्टा होगा ।

हिन्दी प्रदेश की एकता, इस प्रदेश में हिन्दी के व्यवहार का प्रश्न, राष्ट्रीय एकता के प्रश्न के साथ जुड़ा हुआ है । जो लोग यह चाहते हैं कि भारत में अंग्रेजी का पुराना गौरवपूर्ण स्थान बना रहे, वे हिन्दी के कृत्रिम हाने का शोर सबसे ज्यादा मचाते हैं । वे कहते हैं, देखो, हिन्दी न ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी आदि आदि स्वतंत्र भाषाओं को दबा रहा है । उत्तर भारत में ही हिन्दी ने अपना साम्राज्यवाद कायम कर रखा है, उसी का प्रसार हिन्दी वाले बंगाल, महाराष्ट्र, दक्षिण के प्रदेशों में भी करना चाहते हैं । इसलिए अंग्रेजी का व्यवहार निरन्तर करते जाना चाहिए ।

हिन्दी प्रदेश वैसे ही एक राज्यों में बँटा हुआ है । अन्य प्रदेशों में भारत के राजनीतिक दल भाषावर राज्य बनाने का आन्दोलन चला चुके हैं । हिन्दी प्रदेश में राज्य न तो जनपदीय भाषाओं के आधार पर बने हैं और न जातीय भाषा के आधार पर । यहाँ राज्यनिर्माण का कोई भी सिद्धान्त लागू नहीं होता और राजनीति-विशारद इस समस्या की चर्चा भी नहीं करते । इसलिए जनपदों की भाषाएँ हिन्दी से स्वतंत्र भाषाएँ हैं, यह स्थापना हमारी जातीय एकता को खण्डित करती है, यह राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है, और अंग्रेजी के प्रभुत्व को कायम रखती है । इस स्थापना को दोहराते समय बहुत सतर्क रहना आवश्यक है ।

हिन्दी में लिखा हुआ बहुत-सा साहित्य अब गाँवों में किसान पढ़त हैं । कचहरी अदालत में उनका काम हिन्दी से चलता है । पाठशालाओं में उनके बच्चे हिन्दी पढ़ते हैं । बहुत से विमान गरीबी के कारण गाँव छोड़कर शहर में मजदूरी करने आते हैं । उनका काम हिन्दी में चलता है । इस तरह जिन आर्थिक और सांस्कृतिक सूत्रों से शहर के लोग बँधे हुए हैं, उनमें पूर्णतः नहीं

सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करने की पूरी स्वाधीनता होनी चाहिए। बड़े जातीय क्षेत्रों में जहाँ पुराने कबीले या लघुमुख्यक जातियाँ रहती हैं वहाँ उनके सामाजिक विकास की समस्याएँ हल करने में दो तरीके महत्वपूर्ण होते हैं। एक तरीका यह है कि बड़े जातीय क्षेत्रों के अन्तर्गत इन्हें स्वायत्त शासन की सुविधा प्रदान की जाय। दूसरा तरीका यह है कि जहाँ अधिक रूप से इनका राज्य आत्मनिर्भर हो सके, वहाँ उनका राज्य बना दिया जाय। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक आदिवासियों के क्षेत्र फैले हुए हैं। ये लोग सामाजिक विकास की विभिन्न मजिलों में हैं। इनका प्रदेश किसी एक ही जाति या एक ही भाषा का प्रदेश नहीं है। यहाँ द्रविड और कोल परिवारों की अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। इनके अलावा छोटा नागपुर में आदिवासियों की भाषा से प्रभावित हिन्दी का व्यवहार भी व्यापक रूप से होता है। जैसे शहरों में हिन्दी के अनेक रूप हैं, वैसे ही छोटा नागपुर के आदिवासी क्षेत्र में हिन्दी का अपना बोली रूप है। इससे मिलती-जुलती स्थिति भारत के अन्य प्रदेशों में भी है। केरल, तमिल-नाडु आदि के द्रविड प्रदेशों में तो अन्य द्रविड भाषाएँ बोलने वालों के ही विशेष क्षेत्र हैं। इन्हें स्वायत्त शासन वा अधिकार मिलना चाहिए। सोवियत संघ में सो से अधिक भाषाएँ बोली जाती हैं, वहाँ सो से अधिक जातियाँ निवास करती हैं। वहाँ केवल सोलह प्रजातन्त्र हैं। सोवियत संघ इन्हीं राज्यों का संघ है। प्रत्येक राज्य में अनेक स्वायत्तशासन के क्षेत्र हैं, सबसे अधिक रूसी प्रजातन्त्र में है। ब्रिटेन में एक ही राज्य है परन्तु यहाँ भी वेल्श और गैलिक के अलग क्षेत्र हैं।

हिन्दी प्रदेश की भाषाई स्थिति के बारे में जो विशेषताएँ बतायी गयी हैं, उनमें कुछ ऐसी हैं जो सभी भाषाक्षेत्रों में पाई जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो थोड़े से भाषा-क्षेत्रों में मिलती हैं पर ऐसी कोई विशेषता नहीं है जो कहीं भी न मिलती हो। कहा जा सकता है, दो चार विशेषताएँ इधर-उधर मिल सकती हैं पर ऐसा भाषा क्षेत्र कौन सा है जहाँ ये सभी विशेषताएँ एक साथ मिलती हो? मेरा उत्तर है, ऐसा भाषा क्षेत्र रूस है, वहाँ तथाकथित बहुभाषा भाषी हिन्दी प्रदेश की सभी विशेषताएँ प्राप्त हुई हैं।

सबसे पहले विजातीय भाषा का व्यवहार। हिन्दी प्रदेश में अंग्रेजी का व्यवहार होता है, रूस में फ्रांसीसी भाषा का व्यवहार होता था। अब वहाँ नहीं होता क्योंकि समाजवाद की एक उपलब्धि विजातीय भाषा का प्रभाव समाप्त करना है। पूँजीवादी रूस में बीसवीं सदी के प्रथम चरण तक फ्रांसीसी भाषा की गौरव का स्थान प्राप्त था। भाषाई स्थिति का सम्बन्ध समाज-व्यवस्था से बड़ा गहरा है। जब हिन्दी प्रदेश में समाजवादी व्यवस्था कायम होगी, तब अंग्रेजी का यह गौरवपूर्ण स्थान भी समाप्त हो जाएगा। विजातीय भाषा का प्रभाव एक विरल विशेषता है क्योंकि इसका कारण किसी अन्य जाति का राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक प्रभाव है। विरल होने पर भी यह विशेषता बहुत से देशों में मिलती

है क्योंकि विश्वसाम्राज्यवादी व्यवस्था के अन्तर्गत एशिया और अफ्रीका के बोनियो देन इस तरह के प्रभाव में रहे हैं। इसमें यह भी समझना चाहिए कि हिन्दी प्रदेश की यह विशेषता धर्म्याई है जैसे कि वह रूस में अस्थाई सिद्ध हो चुकी है। एशिया के देशों में वियतनाम फ्रांस का उपनिवेश रह चुका है। वहाँ कभी फ्रांसीसी भाषा का वैसे ही व्यवहार होता था जैसे भारत में अंग्रेजी का होता है। अब वहाँ सर्वोपरि स्थान वियतनामी भाषा का है।

हिन्दी-उर्दू का भेद हिन्दी प्रदेश की अपनी विशेषता माना जाता है। रूस में यिद्दिश भाषा का व्यवहार वैसे ही होता है जैसे यहाँ उर्दू का। यहूदी एक धर्म है, जाति नहीं है जैसे कि ईसाई एक धर्म है, जाति नहीं है। रूस में यहूदी हीब्रू को अपनी धर्मभाषा मानते हैं, हीब्रू मिश्रित भाषा को अपनी खास भाषा मानते हैं। इस भाषा में जर्मनभाषातत्त्व इसलिए हैं कि रूस के यहूदी वहाँ जर्मनी से पहुँचे हैं। जैसे आगरे का कोई मुसलमान कलकत्ते में जाकर उर्दू बोले, वैसे ही जर्मनी के यहूदी रूस में जाकर हीब्रू मिश्रित जर्मन अर्थात् यिद्दिश का व्यवहार करते हैं। न तो रूस में सभी यहूदी यिद्दिश का व्यवहार करते हैं, न हिन्दी प्रदेश में सभी मुसलमान उर्दू का व्यवहार करते हैं। कुछ शहरो को छोड़कर गाँवों के मुसलमान, खासकर बिहार और मध्यप्रदेश के मुसलमान, हिन्दी या स्थानीय जनपदीय बोली का व्यवहार करते हैं। रूस के बाहर यिद्दिश का व्यवहार बहुत कम होता है, यद्यपि ब्रिटेन और अमरीका में यहूदी भरे पड़े हैं। वैसे ही हिन्दी प्रदेश के बाहर, कश्मीर, बंगाल या सिन्ध में, धर्म के कारण हिन्दुओं से मुसलमानों की कोई अलग भाषा नहीं है। अतः हिन्दी प्रदेश की इस विशेषता को भी धर्म्याई मानना चाहिए।

अब रही परिनिष्ठित भाषा के साथ जनपदीय उपभाषाओं के व्यवहार की बात। यह एक व्यापक विशेषता है जो हर भाषा क्षेत्र में मिलती है। इसका कारण यह है कि जनपदों का अलग-अलग खरम ढाने पर जातीय प्रदेश निमित्त होता है, कोई एक जनपदीय भाषा जातीय भाषा बनती है और अन्य जनपदीय भाषाओं के तत्त्व अपने भीतर समेटती है। आधुनिक उद्योगधन्दा के विकास के साथ, साक्षरता और शिक्षाप्रसार के कारण, जनपदीय भाषाओं का व्यवहार निरन्तर कम होता जाता है परन्तु पूरी तरह समाप्त नहीं होता। परिनिष्ठित रूसी भाषा, की बोलियाँ पूँजीवादी व्यवस्था में थी, समाजवादी व्यवस्था में भी हैं। हिन्दी प्रदेश में अनेक जनपदीय भाषाओं में विपुल साहित्य-राशि है। ऐसा रूस में नहीं है पर इससे वहाँ जनपदीय भाषाओं का अस्तित्व अस्थिर नहीं होता। -

जनपदीय उपभाषाओं के अलावा परिनिष्ठित भाषा के ही बोली-रूप होते हैं। जनपदीय उपभाषाएँ सामन्ती व्यवस्था के युग की स्वतंत्र भाषाएँ हैं, परिनिष्ठित भाषा के बोली-रूप उन स्वतंत्र भाषाओं के अवशेष नहीं हैं। ये रूप जातीय भाषा पर जनपदीय उपभाषाओं अथवा अन्य जातीय भाषाओं का प्रभाव



पड़ने से बनते हैं। जनपदीय उपभाषाओं का मुख्य व्यवहार क्षेत्र गाँव होते हैं; परिनिष्ठित भाषा के मुख्य व्यवहार क्षेत्र शहर होते हैं। ऊपर दिग्नी, सम्बद्ध-कलकत्ता आदि शहरों की जिस हिन्दी का उल्लेख है, उसमें यह तथ्य प्रमाणित होता है। परिनिष्ठित भाषा के बोली रूपों के व्यवहार के व्यापक सामाजिक कारण हैं। मत यह विशेषता चाहे रूसी हो, चाहे अंग्रेजी, चाहे तमिल हो, चाहे बंगला, सर्वत्र दिखाई देनी है।

अनेक भाषा-क्षेत्रों में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कारणों में किसी धर्म-भाषा का व्यवहार होता है अथवा ऐसी रिक्त भाषा का व्यवहार होना है जिसे लागू अपनी सांस्कृतिक विरासत से विशेष रूप में सम्बद्ध मानते हैं। हिन्दी प्रदेश में इस स्तर पर संस्कृत का व्यवहार होता है। रूस में एक धर्मभाषा का व्यवहार होता था जिसे पश्चिम के भाषा वैज्ञानिक चर्चस्लावोनिच कहते हैं। यह गिरजाघरों की पुरोहित-भाषा है जो अब ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों का स्रोत है। वास्तव में यह पुरानी बुल्गर भाषा है। वह रूसी से भिन्न है। आधुनिक रूस में उसका व्यवहार बहुत कम हो गया है किन्तु पुरानी धार्मिक रूढ़ियाँ मानने वाले लोग वहाँ अब भी हैं, इसलिए उसका थोड़ा बहुत व्यवहार वहाँ अब भी होता होगा। पहले होना था, इसमें सन्देह नहीं। रूस में ईसाइयों के अनेक सम्प्रदाय हैं। इनमें एक ग्रीक ग्रीगोरीडोव्स चर्च अथवा सनातनपन्थी यूनानी सम्प्रदाय है जो शायद ग्रीक भाषा का व्यवहार करता होगा। ईसाइयों के अलावा रूस में लाखों मुसलमान हैं। इनमें काफी लोग अभी नमाज पढ़ते हैं और उनकी नमाज अरबी में ही होती है। यहूदियों के अपने उपासना-स्थान हैं। उनमें निःसन्देह हीब्रू का व्यवहार होता होगा। कुछ बौद्ध मंदिर भी हैं। अवश्य ही ये लोग पालि भाषा में धम्मपद का पाठ करते होंगे। कुल मिलाकर धर्मभाषाओं या रिक्त भाषाओं की स्थिति रूस में वैसी ही है जैसी हिन्दी प्रदेश में। यह विशेषता सर्वत्र समान रूप से व्यापक नहीं है। इसका एक कारण यह है कि सामाजिक जीवन में धार्मिक रूढ़ियों का स्थान निरन्तर गौण होता जाता है। दूसरा कारण यह है कि अनेक देशों में समाज सुधारकों ने धार्मिक कार्यों में जातीय भाषा के व्यवहार पर जोर दिया और इस जातीय भाषा ने पुरानी धर्मभाषा का स्थान ले लिया। धर्म से भिन्न अन्य सांस्कृतिक कार्यों में रिक्त भाषा का व्यवहार निरन्तर क्षीण होता गया है। कुल मिलाकर जातीय भाषा का स्थान सर्वोपरि होता है, अन्य सभी भाषाएँ गौण स्थान प्राप्त करती हैं। यही स्थिति हिन्दी प्रदेश की है।

जातीय भाषा के साथ विजातीय भाषा का व्यवहार केवल उच्चवर्गों और शिक्षित जनो में होता है जनसाधारण में नहीं। जातीय भाषा के साथ रिक्त भाषा या धर्म भाषा का व्यवहार पुरोहित वर्ग के लोग विशेष अवसरों पर ही करते हैं। इसका व्यवहार क्षेत्र विजातीय भाषा की तुलना में और भी संकुचित होता है। रिक्त भाषा या धर्मभाषा के कुछ तत्व जातीय भाषा में मिलाकर

उर्दू या पश्चिम जैसी मिश्रित भाषा बनती है। इसे जातीय भाषा की एक बोली विशेष कह सकते हैं। इसका व्यवहार अधिकतर धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय करते हैं। जातीय गठन और विकास के साथ इसके व्यवहार का अल्पसंख्यक क्षेत्र क्रमशः जातीय भाषा के वृहत्तर व्यवहार क्षेत्र में विलीन हो जाता है।

जातीय भाषा के साथ जनपदीय उपभाषाओं का व्यवहार शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक होता है। उक्त तीन कोटि की भाषाओं की तुलना में इनका व्यवहार क्षेत्र अधिक टिकाऊ और व्यापक होता है। साथ ही ये उपभाषाएँ जातीय भाषा को समृद्ध करने का साधन भी हैं। जातीय भाषा के परिनिष्ठित रूपों के साथ उसके बोली-रूपों का व्यवहार और भी टिकाऊ, और भी व्यापक होता है। ये बोली रूप जातीय भाषा के प्रसार के अनिवार्य परिणाम होते हैं।

हिन्दी प्रदेश में अनेक भाषाओं का प्रयोग इस प्रदेश की विलक्षणता नहीं है। ऐसा अन्यत्र भी हुआ है और हो रहा है। मुख्य बात यह है कि हिन्दी के माध्यम से एक विशाल प्रदेश में भारत की एक महान् जाति सुगठित हो गई है और उसके आर्थिक सांस्कृतिक विकास को रोक रखना संभव नहीं है। बहु-भाषावाद की समस्या पर इसी परिप्रेक्ष्य में विचार करना उचित है। १९७७



परिशिष्ट-१



## भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उन्नीसवीं सदी में हिन्दी-आन्दोलन

"हिन्दी नई चाल में डमी, सन् १८७३ ई०।"  
इस नई चाल की हिन्दी ने एक ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति की।  
उसने हिन्द प्रदेश की जनता को राजनीतिक और सांस्कृतिक जागरण की बाणी  
नी।

गिलश्राइस्ट और ग्रियर्सन आदि अंग्रेज विद्वानों की फेलाई हुई एक भ्रान्त  
धारणा अब भी लोगों में मिल जाती है कि उर्दू से भरबी फारसी के शब्द निकाल-  
कर और उनकी जगह सस्कृत शब्द डालकर इस भाषा का निर्माण हुआ।  
भारतेन्दु का गद्य देखने से यह धारणा निर्मूल सिद्ध होती है। उनके निबन्धों  
में हुज्जत, जमाना, वयान, सफर, मुर्दे, नलम, रिवाज, तलाश, दरख्त, सबूत,  
गरख आदि जैसे शब्द निहायत बेतकलुफी से इस्तेमाल किये गए हैं। यही  
हाल बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुन्द गुप्त, राधाचरण गोस्वामी आदि लेखकों का  
भी है। कुछ लेखक ऐसे जरूर थे जो प्रचलित भरबी फारसी के शब्द निकालकर  
उनकी जगह सस्कृत-शब्दावली रखकर शुद्ध हिन्दी लिखने के पक्षपाती थे।  
लेकिन भाषा की समस्या प्रचलित शब्दों की न थी।

समस्या यह थी कि जहाँ अप्रचलित शब्दों की जरूरत पड़े, यानी साधारण  
बोलचाल से भ्रमण जहाँ गैर-युनियादी शब्द-भण्डार की जरूरत पड़े, वहाँ भरबी-  
फारसी से शब्द लिये जाएँ या सस्कृत में। बोलचाल की भाषा के आधार पर  
जिस साहित्यिक उर्दू का विकास हुआ, उसका इम्मान गैर-युनियादी शब्द-  
भण्डार के लिए सस्कृत के बढने भरबी फारसी की तरफ जाने का था। उर्दू  
की भी दो शैलियाँ थी, एक वह जिसमें बोलचाल की हिन्दी के शब्द निकालकर  
उनकी जगह भी भरबी-फारसी के शब्द डाले जाते थे, गैर युनियादी हिस्से में  
तो उनकी भरमार रहती ही थी। दूसरी शैली वह थी जिसमें बोलचाल की  
हिन्दी के शब्दों का बायबाट न किया जाता था और गैर युनियादी हिस्से में भी  
भरबी-फारसी की बेजा भरमार न की जाती थी।  
बोलचाल की भाषा एक ही थी, हिन्दी उर्दू का युनियादी शब्द-भण्डार पर

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उन्नीसवीं सदी में हिन्दी आन्दोलन / ३०१

ही था। लेकिन साहित्यिक शैली का निर्माण उन लोगों के हाथों हुआ जो अरबी-फारसी के विद्वान् थे ही, संस्कृत के भी विद्वान् थे। इन लोगों ने गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार के लिए अरबी-फारसी या संस्कृत का सहारा लिया।

यदि गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार के लिए अरबी-फारसी का सहारा लेने की नीति हमारे जातीय विकास की ऐतिहासिक आवश्यकताएँ पूरी कर सकती तो 'नई हिन्दी' के चलन का सवाल न उठता, सवाल उठने पर भी उसमें सफलता न मिलती। कचहरियो, पुलिस विभाग आदि में उर्दू चालू थी। जनता का समर्थन मिलने पर उसका प्रचार इतना व्यापक हो जाता कि कोई भाषा-शैली उससे होड़ करने की जुर्रत न करती। लेकिन गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार के लिए सिर्फ अरबी फारसी का सहारा लेने की नीति भारत की किसी भाषा में न अपनायी थी। कारण यह था कि यहाँ की भाषाओं का जो सम्बन्ध संस्कृत से था, वह अरबी-फारसी से न था। हिन्दी की क्रियाएँ—चलना, लिखना, हँसना, रोना, खाना, पीना, मरना, जीना, आदि आदि—संस्कृत की क्रियाएँ भी हैं। इस तरह अरबी-फारसी की क्रियाएँ बोलचाल की हिन्दी में बहुत कम हैं। इसलिए इस तरह की क्रियाओं से बनेवाले शब्द भी अरबी-फारसी की क्रियाओं से बनेवाले शब्दों की अपेक्षा बोलचाल की हिन्दी में कहीं ज्यादा हैं। बोलचाल की हिन्दी में तद्भवों की भरमार है। उतने तद्भव अरबी-फारसी से नहीं बने, यद्यपि बोलचाल की भाषा में आये हुए अरबी-फारसी के शब्दों का रूप और कभी-कभी अर्थ भी एक हद तक बदला है।

बोलचाल की हिन्दी की तरह भारत की अन्य भाषाओं में भी अरबी-फारसी के सैकड़ों शब्द घुल-मिल गए। इसका सबब यह नहीं था कि मुसलमानों की भाषा अरबी-फारसी थी और हिन्दुओं की भाषा संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश थी। बाबर वगैरह की ज़बान दरअसल तुर्की थी। कुछ ईरानियों के अलावा उच्च वर्ग के मुसलमानों के घरों में भी फारसी न बोली जाती थी। लेकिन सैकड़ों साल तक फारसी उत्तर भारत की राजभाषा रही थी। सैकड़ों अरबी के शब्द फारसी के जरिये यहाँ आये। इसके अलावा शिक्षित मुसलमानों के लिए धर्मग्रन्थ की भाषा अरबी थी। बोलचाल की हिन्दी में फारसी शब्दों के घुलने-मिलने का मुख्य कारण फारसी का राजभाषा होना था।

फिर भी हिन्दी-भाषी प्रदेश की-सी समस्या कश्मीरी, बँगला, मराठी आदि भाषाओं में नहीं पैदा हुई। इसके कई कारण थे। राजभाषा फारसी के केन्द्र हिन्द प्रदेश ही में थे। अगर और दिल्ली मुगलों की राजधानी रह चुके थे। यहाँ के शिक्षित वर्ग में फारसी का प्रचार भारत के दूसरे नगरों और प्रांतों के मुकाबले में ज्यादा था। १८३६ ई० तक यहाँ राजभाषा फारसी रही और उसके बाद कचहरियो, पुलिस विभाग आदि में जो भाषा चली, वह अरबी-फारसी शब्दों से लदी हुई थी।

अंग्रेजों ने यहाँ की सामन्तशाही को अपना मित्र और चाकर बनाया।

नवाबों के दरबार जन-संस्कृति के केन्द्र न थे। जनता से उनका भलगाव उनके संरक्षण में चलनेवाली भाषा-नीति पर भी पड़ा। लखनऊ, रामपुर, हैदराबाद के दरबार एक खास तरह की शैली और कविता के केन्द्र बन गये। अंग्रेजों ने दो लिपियों और दो शैलियों के चलन को प्रोत्साहन दिया और भाषा-सम्बन्धी विवाद उनकी 'फूट डालो और राज करो' नीति का ज़रूरी हिस्सा बन गया। लेकिन यह समझना बहुत बड़ी भूल होगी कि समूचा उर्दू साहित्य सामन्ती संस्कृति में प्रभावित है। उर्दू का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामन्त-विरोधी और राष्ट्रीय है। उससे हिन्दी के लेखक बहुत कुछ सीख सकते हैं और पिछले हिन्दी लेखकों ने बहुत कुछ सीखा है। उसमें बोलचाल की हिन्दी का बहुत ही सुन्दर और सँवारा हुआ रूप मिलता है।

भारतेन्दु के समय तक—और एक हद तक अब भी—शिक्षा पर पड़ितों और मौलवियों का इजारा था। इसका एक फल यह हुआ कि हिन्दी-उर्दू की दो लिपियों का चलन हुआ। इससे साहित्य के पाठक दो हिस्सों में बँट गये और अबसर उन्हें पता न रहता था कि दूसरी लिपि में क्या लिखा जा रहा है। जनसाधारण की भाषागत एकता साहित्य की शैली पर अपना असर न डाल पाई। फिर भी लिपि-भेद से ही हिन्दी-उर्दू का भेद इस हद तक नहीं बढ़ा। जायसी के 'पद्यावत' के फारसी लिपि में लिखे जाने से वह उर्दू का ग्रन्थ नहीं हो गया। मूल प्रश्न गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार का था। उन्नीसवीं सदी के अनेक उर्दू-लेखक अपनी भाषा को सरल करने का प्रयत्न कर रहे थे और उसमें अरबी-फारसी की अनावश्यक भरमार कम कर रहे थे। फिर भी ज़रूरत पड़ने पर बोलचाल की शब्दावली से बाहर वे अरबी-फारसी का ही सहारा लेते थे।

भारतेन्दु ने कोई नयी भाषा नहीं चलाई। उन्होंने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। उनके पक्ष में तीन बातें महत्वपूर्ण थीं। उनकी भाषा-सम्बन्धी नीति वही थी जो अवधी और वज्र के पुराने हिन्दू-मुसलमान कवियों की थी। उर्दू के बवि—कुछ अपवाद छोड़कर—तुलसी, मूर, मीरा, रहीम, रसखान, अलम, शेख, पजनेस, जायसी, पद्माकर, भूषण आदि की परम्परा से प्रेरित थे। इस परम्परा और उसकी भाषानीति को भारतेन्दु ने अपनाया। यह भाषा-नीति यह थी कि तत्सम संस्कृत के मुकाबले में तद्भव शब्दों का प्रयोग करना, बोलचाल के अरबी फारसी शब्दों का बहिष्कार न करना, गैर-बुनियादी शब्द-भण्डार के लिए संस्कृत का सहारा लेना। दूसरी बात उनके पक्ष में यह थी कि उन्होंने ग्रामीण या जनपदीय बोलियों का स्वभाव पहचाना और अपनी हिन्दी को गाँव के साधारण पढ़े लिखे लोगों के लिए सुलभ बनाने की कोशिश की। तीसरी बात उनके पक्ष में नागरी लिपि थी। सैंकड़ों साल तक फारसी के राजभाषा बने रहने पर भी नागरी का लोप न हुआ। गाँव के लोग ज्यादातर नागरी ही काम में लाते थे। इस लिपि के जरिये भारतेन्दु जनता के



उस तमाम हिस्से को बटोर सके जो उर्दू न जानता था या जिसकी जातीय आवश्यकताएँ उर्दू से पूरी न होती थी ।

उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में भाषा-सम्बन्धी बहस में हिस्सा लेनेवालों ने यह सब विकास-क्रम न समझा था । उर्दू के समर्थकों को हिन्दी प्रतिद्वन्द्वी के रूप में दिखाई दी । कुछ मुसलमान लेखकों को यह अपनी सस्कृति पर ही हमला दिखाई दिया । अंग्रेजों ने अपनी भाषा-नीति से बहस को बढावा दिया और उसमें दोनों तरफ से ऐसी बातें कही गईं जो उचित न थीं । इसी बहस की गर्मी में भारतेन्दु ने 'उर्दू का स्यापा' लिखा था ।

है है उर्दू हाय हाय ! कहां सिधारी हाय हाय ॥

और भागे चलकर बालमुकुन्द गुप्त ने 'उर्दू को उत्तर' लिखा था ।

न बीबी बहुत जी में धबराइये,

सम्हलिये जरा होश में आइये ।

लेकिन उर्दू सिधारी नहीं । इसका कारण उसका बुनियादी शब्द-भण्डार था जो बोलचाल की हिन्दी का ही था । वह दूसरी लिपि के माध्यम से— दरबारी और दरबारी साहित्य के अलावा—साधारण जनता के एक हिस्से की सेवा करती रही । इसलिए प्रेमचन्द, पद्मसिंह शर्मा आदि लेखकों का मत था कि क्रमशः साहित्य में एक मिली-जुली शैली का विकास होगा और वह उर्दू को हटाकर या दबाकर न होगा बल्कि उससे बहुत कुछ लेकर होगा ।

भारतेन्दु ने बहस के दौरान कुछ तेज बातें जरूर लिखी, लेकिन वह न उर्दू से नफरत करते थे, न उर्दू के प्रचलित शब्दों का बहिष्कार करते थे । यही नहीं, वह उर्दू में गद्य-पद्य खुद भी लिखते थे । भारतेन्दु को जब व्याख्यान देने के लिए बलिया बुलाया गया था, तब विज्ञापन में उन्हें 'शायरे मारुफ बुलबुले हिन्दुस्तान' कहा गया था । वाजिद अली शाह के शायर मिर्जा आविद ने 'बागे आलम में मोतदिल है हवा' आदि उन पर कसीदा लिखकर भेजा था । श्री रामशंकर व्यास ने लिखा था कि उन्हें बजीर और अनीस का काव्य विशेष प्रिय था । १७ सितम्बर, १८७२ की 'कविवचन-सुधा' में एक दिलचस्प विज्ञापन छपा था । यह विज्ञापन उर्दू के साप्ताहिक पत्र 'कासिद' के बारे में था जिसे भारतेन्दु निकालनेवाले थे ।

“कासिद !

सातएँ दिन आवैगा ॥

नये हितकारी और विचित्र समाचार कहैगा ॥॥

यह एक साप्ताहिक उर्दू पत्र निकलैगा इसमें अनेक हित की, नये उद्गार की, साम्प्रत समयानुसार लोक वृद्धि की और अनेक शुभ समाचार की बातें

रहेंगी—यह पत्र बहुत उत्तम बड़-बड़े पृष्ठों में स्वच्छ अक्षरों में छपेगा मूल्य—  
१०) बापिक ।

हरिश्चन्द्र

उद्यमकर्त्ता ।”

भारतेन्दु ने उर्दू के प्रति द्वेषभाव होता तो वह ‘कासिद’ निकालने की बात कभी न सोचते ।

भारतेन्दु ने हिन्दी के माध्यम से जिस जातीय संगठन में योग दिया, उसमें भवध, ब्रज, मुन्देलखण्ड, भोजपुर आदि जनपदों की जनता शामिल थी । यदि महापंडित राहुल साह्यायन की यह स्थापना सच मानी जाय कि भवधी, ब्रज, मुन्देलखण्ड, भोजपुरी बोलनेवाले अलग-अलग जानियों के लोग हैं, तो भारतेन्दु का यह काम इतिहास-विरोधी ठहरेगा । भारतेन्दु भोजपुरी क्षेत्र के निवासी थे । भोजपुरी जानते भी अच्छी तरह थे । लेकिन उन्होंने भोजपुरी में न लिखकर हिन्दी को अपना साहित्यिक माध्यम बनाया जैसे कि आगे प्रेमचन्द और प्रसाद ने किया । इतिहास-विरोधी काम भारतेन्दु का नहीं था, इतिहास-विरोधी स्थापना महापंडित राहुल और उन जैसे विचारकों को है । यद्यपि राहुलजी स्वयं हिन्दी के लेखक हैं—और अपना जीवनचरित उन्होंने भोजपुरी में लिखना उचित नहीं समझा—फिर भी वह हिन्दीभाषी जनता का एक प्रान्त बनाने की मांग करने के बदले बोलियों के आधार पर हिन्द प्रदेश के तेरह टुकड़े करने का सुभाव पेश करते हैं । सन् १९५३ की ‘आलोचना’ (दिल्ली) में इस आशय का उनका एक लेख छपा था । सोलहवीं सदी के आस पास ही व्यापार के प्रसार के साथ भोजपुरी आदि के क्षेत्रों में खड़ी बोली फैलने लगी थी । व्यापार के क्षेत्रों में एक ही बोली बोलनेवाले लोग इकट्ठा हों, ऐसा नहीं होता । उद्योग-धन्धे और व्यापार सहरों में विभिन्न बोलियाँ बोलनेवाले लोगों को बटोरते हैं और उनमें किसी एक बोली का व्यवहार ‘शिष्ट’ लोग करते हैं । बनारस आदि पूर्वी नगरों में खड़ी बोली व्यापारी लोगों के साथ आई । २ अक्टूबर, १८७२ की ‘कविवचन-सुधा’ में भारतेन्दु का ‘हिन्दी भाषा’ नाम का निबन्ध छपा था । यह निबन्ध ऐतिहासिक महत्त्व का है । इसमें भारतेन्दु ने बनारस की बोलियों का अध्ययन किया है और यह दिखाया है कि शिष्टजनों की भाषा हिन्दी है ।

बनारस के लोगों की बोली के बारे में वह कहते हैं, “इसी बनारस में जो बनारस के पुराने रहवासी हैं उनके घर में विचित्र-विचित्र बोलियाँ बोली जाती हैं जैसा पुरवियों की बोली तों आइला जाइला प्रसिद्ध ही है परन्तु यहाँ के पुराने निवासी कसैरे लोग ‘बाट’ शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं जैसा ‘भावत ह्रस्व’ के स्थान पर ‘भावत बाटी’, ‘का करत होव’ वा ‘का करलः’ के स्थान पर ‘का करत बाट्य’ वा ‘बाटों’ वा ‘बाट.’ ।”

बनारस में इन बोलियों के एकत्र होने और उन सबके ऊपर हिन्दी के

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र और उन्नीसवीं सदी में हिन्दी-प्रान्तीयन / ३३३

चलन का कारण क्या है ? इसका कारण व्यापार का प्रसार, भौद्योगिक और व्यापारी केंद्रों का निर्माण, सामन्ती सम्बन्धों के भीतर पूँजीवादी सम्बन्धों का पनपना और विभिन्न बोलियाँ बोलनेवालों का जातीय गठन है । 'प्रेमजोगिनी' में भूपटिया 'मिसरो नहीं आए' कहता है लेकिन जलघरिया 'मुत्तल थोड़े रहली' और 'कधा छिला जाला' कहता है । और शिष्ट लोग खड़ी बोली का व्यवहार करते हैं ।

बनारस की विभिन्न बोलियों का उल्लेख करने के बाद भारतेन्दु 'हिन्दी भाषा' वाले निबन्ध में कहते हैं, "जो हो यह तो सिद्धान्त है कि जो यहाँ के शिष्ट लोग बोलते हैं यह परदेसी भाषा है और यहाँ पश्चिम से आई है ।"

पछाँह से यह बोली किसके साथ आई, इस प्रश्न का उत्तर भारतेन्दु के इस वाक्य से मिलता है . "अब पश्चिमोत्तर देश में घर में बोलने की भाषा कौन है यह निश्चय नहीं होता क्योंकि दिल्ली प्रान्त के वा अन्य नगरों में भी खन्निषो वा पछाँही अग्रवालों वा और पछाँही जातियों के अतिरिक्त घर में हिन्दी कोई नहीं बोलते वरन् यहाँ तो कोस-कोस पर भाषा बदलती है ।" दिल्ली के अलावा अन्य नगरों में भी खड़ी बोली खन्निषो, पछाँही अग्रवाल आदि के जरिये फैली जिनका मुख्य पेशा व्यापार था । आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि मुगल-साम्राज्य के ध्वंस के बाद "दिल्ली के आस-पास के प्रदेशों की हिन्दू व्यापारी जातियाँ (अग्रवाल, खत्री आदि) जीविका के लिए लखनऊ, फैजाबाद, प्रयाग, काशी, पटना आदि पूरबी शहरों में फैलने लगी । उनके साथ-साथ उनकी बोलचाल की भाषा खड़ी बोली भी लगी चलती थी ।"

वास्तव में यह क्रम मुगल-साम्राज्य के ध्वंस से पहले ही शुरू हो चुका था । शुक्लजी ने व्यापारियों द्वारा खड़ी बोली के प्रसार का तथ्य बहुत सही दिया है । इन व्यापारियों में मुसलमान भी थे । इसके सिवा सोलहवीं से उन्नीसवीं सदी तक एक बोली बोलनेवालों का दूसरी बोली के क्षेत्र में जाकर बसने का क्रम बराबर चलता रहा । अवध के जो मुसलमान मिथिला में जाकर बस गए और वहाँ एक नये ढंग की हिन्दुस्तानी का व्यवहार करने लगे, वह कार्य भी इसी क्रम का अन्तर्गत हुआ ।

जो लोग समझते हैं कि खड़ी बोली केवल सम्य व्यवहार या साहित्य की भाषा है, उन्हें इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली के अलावा अन्य नगरों में वह बहुत से लोगों की मातृभाषा थी और है । इस सिलसिले में भारतेन्दु ने लिखा था, "ऐसे ही पश्चिमोत्तर देश में अनेक भाषा है पर उनमें ऐसे नगर थोड़े हैं जिनमें अवाल-वृद्ध-बनिता सब खड़ी भाषा बोलते हो अतएव यद्यपि काशी एवं पूर्वी प्रदेशों की मातृभाषा वा घर के बोलचाल की भाषा हिन्दी है यह तो हम नहीं कह सकते पर हाँ यह कह सकते हैं कि इसी पश्चिमोत्तर

देश में कई नगर ऐसे हैं जहाँ यही खड़ी बोली मातृभाषा है।"

इस बोलचाल की भाषा में हिन्दी उर्दू का भेद न था। यह विभिन्न बोलियों बोलनेवाली जनता की नई जातीय भाषा थी जो उसे एक सूत्र में बाँध रही थी। गिलग्राइस्ट से ही इस बात का सूत्रपात हो चुका था कि मुसलमानों की शिष्ट बोली और होगी और हिन्दुओं की और। लेकिन भारतेन्दु बोलचाल की भाषा में भेद न मानते थे। हिन्दी-उर्दू का भेद अरबी फारसी या संस्कृत से शब्द लेने के कारण था। ८ सितम्बर, १८७३ की 'कविवचन सुधा' में हिन्दी-उर्दू के बारे में एक लेख छपा था जिसका अंग्रेजी में शीर्षक है, "Hindi Versus Urdu, Philologically Hindi और उर्दू।" इसमें हिन्दी उर्दू के भेद के बारे में यह स्थापना है, "हिन्दी और उर्दू में अन्तर क्या है हम बिना संकोच के उत्तर देते हैं कि भाषाओं में कुछ अन्तर नहीं है क्योंकि व्याकरण की विभक्तियाँ और नियम दोनों के एक हैं पर इतना ही अन्तर है कि हिन्दी में जिसके लिए हिन्दी शब्द नहीं मिलता वहाँ संस्कृत शब्द काम में आते हैं और उर्दू में सहज हिन्दी शब्द होने पर भी और जहाँ शब्द नहीं मिलते हैं वहाँ तो अवश्य ही अरबी और फारसी के शब्द लिखे जाते हैं, यही दोनों में अन्तर है।"

भारतेन्दु ने हिन्दी के नई चाल में ढलने का वर्ष १८७३ लिखा था। वास्तव में १८६८ में ही 'विद्यासुन्दर' के प्रकाशन और 'कविवचन सुधा' के निकलने से हरिश्चन्द्री हिन्दी का चलन शुरू हो गया था। लेकिन हरिश्चन्द्र ने न तो कोई नई भाषा चलाई थी, न व्याकरण आदि में ही कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन किया था। उनकी हिन्दी की विशेषता उनकी बोली थी। 'विद्यासुन्दर' में 'समाचार लेने के हेतु', 'यह पौन हमारी प्राणप्यारी प्रभुवनमोहनो का अग्र स्पर्श करके आता है', 'पुरस्कार के हेतु', 'बस अब बहुत भई', 'सब काम सिद्ध भया', 'बिना कुछ भए', 'ऐसी दशा शत्रु की होय', 'और जो वह सन्यासी हमी होय', 'जो यह बात सच होय' आदि प्रयोग मिलते हैं। 'कर्पूरमञ्जरी' में "महाराज, कहिये और क्या होय?" 'मुद्राराक्षस' में "जो कोई सुतनेवाला और समझने-वाला होय।" 'वैदिकी हिसा' में "बड़ा आनन्द भया"। 'सत्य हरिश्चन्द्र' में "बेटा, साँझ भई", "ठीक है, लेव सोना"। 'विपश्य विषमोपघम' में "तो क्या हुआ है, होय।" 'वैष्णवता और भारतवर्ष' में "स्नान आदि भी वहाँ तक रहै", "भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है" में "खराबी जो बीच में भई है।"

भाषा के परिवार की दृष्टि से भारतेन्दु का काम युगान्तरकारी नहीं कहा जा सकता। उनके पहले—उर्दू गद्य को छोड़ भी दें तो— रामप्रसाद निरंजनी, सदानुसलाल, राजा लक्ष्मणसिंह आदि समर्थ हिन्दी-लेखक हो चुके थे। लल्लूजी साहनी भाषा की तुलना में भारतेन्दु की भाषा युगान्तरकारी मालूम हो सकती है लेकिन हिन्दी गद्य के विकास में लल्लूजीलाल का जो महत्व प्रियसंग ने घोषित किया है, वह इतिहास में सिद्ध नहीं होता।

बोली को माध्यम बनाने के लिए एक लम्बा मंथन चला। 'हिन्दी भाषा' वाले निबन्ध में उन्होंने अपना यह मत प्रकट किया है कि "पश्चिमोत्तर देश की कविता की भाषा ब्रजभाषा है यह निर्णीत हो चुकी है।" अपने अनुभव के बारे में लिखा है - "मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊँ पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं बनी, इससे यह निश्चय होता है कि ब्रजभाषा में ही कविता करना उत्तम होता है और इसी से सब कविता ब्रजभाषा में ही उत्तम होती हैं।" खड़ी बोली में कविता मोठी क्यों नहीं होती, इसका "सबसे बड़ा कारण यह जान पड़ा कि इसमें क्रिया इत्यादि में प्रायः दीर्घ मात्रा होती है इससे कविता अच्छी नहीं बनती।"

वास्तव में खड़ी बोली की कविता में मिठास के अभाव के लिए कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है। कारण कवियों में अभ्यास की कमी ही हो सकता है। ब्रजभाषा में पद्य का एक बना-बनाया रास्ता था, कविता की अपनी शब्दावली थी। खड़ी बोली में यह सब गढ़ना था।

खड़ी बोली बनारस और दूसरे पूर्वी जिलों में शिष्ट लोगों की बोलचाल की भाषा के रूप में फैल रही थी। इसलिए भारतेन्दु जैसे कवि का उससे प्रभावित न होना असम्भव था। उनकी एक तरह की शैली वह है जिसमें ब्रजभाषा खड़ी बोली के साथ घुलती मिलती दिखाई देती है। जैसे 'प्रेमतरंग' के इस गीत में—

किन वे रुठाया मेरा यार।

कहाँ गया, क्यों छोड़ गया मोहिं, तोड़ गया क्यों प्यार।

या

नशीली छाँखोवालो सोए रहो अभी हैं बड़ी रात।

मगरी रैन मेरे सग जागत रहे करत रंगीली बात ॥

दूसरी तरह की शैली उनकी लावनियों की है जिसमें प्रचलित फारसी के शब्द भी आते हैं और जिनकी भाषा धामतीर से शुद्ध खड़ी बोली होती है। सूफी कवियों के रंग में भारतेन्दु खड़ी बोली की कितनी सरस कविता कर सकते थे, इसका सबूत इन पक्तियों में मिलेगा—

श्री राधा माधव जुगल चरन रस का अपने को मस्त बना।

पी प्रेम पियाला भर भर कर कुछ इस में का भी देख मजा ॥

यह वह मैं है जिसके पीने से और ध्यान छूट जाता है।

अपने में भी दिलवर में फिर कुछ भेद नहीं दिखलाता है ॥

इसके मुँह से मस्त हरेक अपने को नजर बस आता है।

फिर धीरे हवस रहती न जरा कुछ ऐमा मजा दिखाता है ॥

टुक मान मेरा कहना दिल की इस मँखाने की तर्फ भुवा।

पी प्रेम पियाला भर भर कर कुछ इस में का भी देख मजा ॥

लावनीवाजों ने खड़ी बोली कविता की एक सजीव परम्परा कायम की थी।

उनके लिए दीर्घ ह्रस्व मात्राओं से खड़ी बोली के मीठे, बड़े बने का सवाल न था। उनके यहाँ खड़ी बोली एक बहुत ही लचीला माध्यम बन गई थी और भारतेन्दु ने जब उस परम्परा का सहारा लिया, तब उन्होंने खड़ी बोली में बहुत ही सरस कविता की। यह सही है कि यह कविता पत प्रसाद की शैली से बहुत दूर है लेकिन वह जन-काव्य की परम्परा के बहुत निकट है।

जनसाधारण के कवियों ने पद्य में खड़ी बोली की परम्परा बहुत दिन से चला रखी थी। उन्हें यह विदवास दिलाने की जरूरत न थी कि ब्रजभाषा छोड़कर खड़ी बोली में लिखने से साहित्य और जल्दी उन्नति करेगा। कवियों के सामने प्रश्न यह था कि वे इस सजीव परम्परा से नाता जोड़ेंगे या नहीं। भारतेन्दु के नाटकों में खड़ी बोली के गीतों आदि का धाना यह साबित करता है कि जनता में खड़ी बोली के पद्य प्रचलित थे। 'वैदिकी हिंसा' में राजा गाता है: 'पीले अवधू के मतवाले प्याना प्रेम हरी रस का रे।' 'सत्य हरिश्चन्द्र' में धर्म कहता है—

हम चौधरी डोम सरदार। धर्मल हमारा दोनों पार।

और पिशाचों-हाकिमियों का गीत—

हम सजसे बजके बजके चलेंगे धमकेंगे धम धम धम।

'भारत-दुर्दशा' में भालस्थ का गीत है—

दुनिया में हाथ-पैर हिलाना नहीं अच्छा।

'अधेर-नगरी' में धासीराम का 'चने जोर गरम' खड़ी बोली की अपनी चना-जोर शैली में है। ऐसे ही चूरनवाले का लटका है—

चूरन धमनबेद का भारी। जिसको खाते कृष्णमुरारी।

मेरा पाचक है पचलोना। जिसको खाता श्यामलोना ॥

भाम जनता में खड़ी बोली के पद्यों के चलन का मतलब यह था कि कविता में भी खड़ी बोली की माध्यम बनाने की ऐतिहासिक आवश्यकता पैदा हो गई थी।

भारतेन्दु की उपर्युक्त शैलियों के प्रभावों उनको उर्दू शैली की रचनाएँ हैं। 'रसा' नाम से वह गायरी करते थे और धामतीर में उनकी भाषा सरल उर्दू होती है। यथा—

दिल मेरा ने गया दया करके।

बिषपा हो गया वषा करके ॥

शेस्तो बीन मेरी तुबंत पर,

रो रहा है 'रमा रमा' करके।

भारतेन्दु की समूची खड़ी बोली की कविता परिमाण में कम नहीं है। उन्होंने खड़ी बोली की सरल भोजप्रिय कविता से सहायता पाई थी। लेकिन ब्रजभाषा में त्रिम पुरानी शैली पर वह शृंगार-रस के पद्य बनाते थे, उस शैली

भाषा के परिष्कार की दृष्टि से भारतेन्दु के गद्य में बहुत सी खामियाँ थीं, लेकिन उनका युगान्तरकारी काम यह था कि उन्होंने बोलचाल की भाषा की प्रकृति पहचानी, उसकी मिठास को साहित्य में जगह दी, उस भाषा को सभी तरह के साहित्य का समर्थ माध्यम बनाया। वह समझते थे कि गद्य के लिए ब्रजभाषा ही उपयुक्त है, फिर भी उन्होंने स्वयं खड़ी बोली में कम गद्य नहीं रचा जो उनके ब्रजभाषा में लिखे हुए गद्य से बढ़कर है। जनता में खड़ी बोली कविता की अपनी एक परम्परा कायम हो चुकी थी। भारतेन्दु ने इसे पहचाना और उसके अनुकूल गद्य भी रचे। वास्तव में खड़ी बोली (हिन्दी) में गद्यरचना के लिए ऐतिहासिक आवश्यकता कभी की पैदा हो चुकी थी।

भारतेन्दु ने उन लोगों का विरोध किया जो यह दावा करते थे कि हिन्दी में विज्ञान की किताबें लिखी ही नहीं जा सकती या हिन्दी में विज्ञान की शिक्षा न देनी चाहिए। उनके सामने शिक्षा और विज्ञान का उद्देश्य समूचे देश की उन्नति करना था और यह काम देशी भाषाओं द्वारा ही हो सकता था।

इस तरह भारतेन्दु ने हिन्दी को नई चाल में ही नहीं ढाला बल्कि उसके चौमुखी विकास के लिए सधर्प भी किया। (१६५३)

## गांधीजी और भाषा-समस्या

अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ से ही गांधीजी ने भाषा-समस्या पर सोचना और लिखना आरम्भ कर दिया था। सत्य, अहिंसा, स्वराज्य, सर्वोद्योग—किसी भी अन्य विषय पर उनके विचार आज के लिए इतने उपादेय नहीं हैं, जितने भाषा-समस्या पर। अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं, राष्ट्रभाषा हिन्दी और हिन्दी-उर्दू की समस्या पर उन्होंने जितनी बातें कही हैं, वे बहुत ही मूल्यवान हैं। किसी राजनीतिक नेता ने इन समस्याओं पर इतनी गहराई से नहीं सोचा, किसी पार्टी और उसके नेताओं ने भाषा-समस्या के सैद्धान्तिक समाधान को अपनी नीतिप्रति की दायेंवाही में इस तरह धमली जामा नहीं पहनाया, जैसे गांधीजी ने। उनकी नीति के मूल सूत्र छोड़ देने से यह समस्या दिन-पर-दिन उभरती जा रही है। जो लोग उसे उलझा रहे हैं, वे गांधीजी की जय बोलते हुए, गांधीवाद की जय बोलते हुए, गांधीवाद की दुहाई देते हुए ऐसा कर रहे हैं।

गांधीजी का भाषा नीति का पहला सूत्र है, भाषा-समस्या का समाधान जनता के हित में हो।

नेता अंग्रेजी में भाषण दें, जनता समझे नहीं। ऐसे नेता न तो देश में कोई बड़ा परिवर्तन कर सकते थे, न उनकी राजनीति जनता की राजनीति बन सकती थी। जो नेता अंग्रेजी में ही बोलने की जिद करते थे और हिन्दी सीखने से इन्कार करते थे, उनके लिए गांधीजी ने सन '२७ में लिखा था, "वास्तव में ये अंग्रेजी में बोलनेवाले नेता हैं जो आम जनता में हमारा काम जल्दी आगे बढ़ने नहीं देते। वे हिन्दी सीखने से इन्कार करते हैं जबकि हिन्दी द्रविड प्रदेश में भी तीन महीने के अन्दर सीखी जा सकती है, अगर सीखनेवाले इसके लिए तीन घंटे हर रोज दें।" (फॉट्स ऑन नेशनल संग्रेज, नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, पृ० २६)।

गांधीजी ने नेताओं का अंग्रेजी बोलना छुड़ाया। उनके सपने के फलस्वरूप कम-से-कम अब अपने प्रदेशों में वे जनता के वास्तविक अंग्रेजी में बोलना नहीं करते।



लेकिन उनका राजनीतिक-सांस्कृतिक कार्य अब भी बहुत कुछ अंग्रेजी में होता है। अब राज्यसत्ता कांग्रेसी नेताओं के हाथ में है। यह राज्यसत्ता, उसे चलाने-वाला नौकरशाही वर्ग किसके लिए है? स्वराज्य किसके लिए है? सन् '३१ में गांधीजी ने लिखा था, "यदि स्वराज्य अंग्रेजी-पढ़े भारतवासियों का है और केवल उनके लिए है, तो सम्पर्क भाषा अवश्य अंग्रेजी होगी। यदि वह करोड़ों भूखे लोगों, करोड़ों निरक्षर लोगों, निरक्षर स्त्रियों, सताये हुए अछूतों के लिए है तो सम्पर्क भाषा केवल हिन्दी हो सकती है।" (उप० पृ० ३१)

इसलिए यदि जनतन्त्र जनता का है और जनता के लिए है तो उसमें अंग्रेजी के लिए जगह न होनी चाहिए। अंग्रेजी को अपनानेवाले वे लोग हैं जो भाषा-समस्या पर जनता के हितों को ध्यान में रखकर विचार नहीं करते। उन्होंने लिखा था, 'कुछ लोग जो अपने दिमाग से जनता की बात एकदम निकाल देते हैं, वे यही नहीं कहते कि अंग्रेजी भी सम्पर्क भाषा हो सकती है, वे कहते हैं कि अंग्रेजी ही एकमात्र सम्पर्क भाषा हो सकती है।' (उप० पृ० ३०)

जो राजनीतिज्ञ जनता-जनता सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं, वे अपनी राजनीतिक कार्यवाही में इसी जनता की उपेक्षा करते हैं। गांधीजी मार्क्सवादी-लेनिनवादी नहीं थे लेकिन लेनिन की भाषा सम्बन्धी नीति का सारतत्त्व उन्होंने ग्रहण कर लिया था। उन्होंने भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अंग्रेजी के व्यवहार की आलोचना करते हुए सन् '३७ में लिखा था, उनके लेख अंग्रेजी न जाननेवालों के लिए गुप्त खजाना (सील्ड बुक) हैं। लेकिन रूस का हाल देखिए। वहाँ क्रान्ति से पहले ही तमाम पाठ्य पुस्तकें (वैज्ञानिक पुस्तकों समेत) रूसी में छपती थीं। दरअसल इसी बात ने लेनिन की क्रान्ति के लिए मार्ग तैयार किया। हम ग्राम जनता से सच्चा सम्पर्क तब तक कायम नहीं कर सकते, जब तक कांग्रेस यह फैसला नहीं करती कि उसका सारा विचार-विमर्श हिन्दी में होगा और उसके प्रान्तीय संगठनों का काम प्रान्तीय भाषाओं में होगा।" (उप० पृ० ५३)

विभिन्न प्रदेशों के बीच विदेशी भाषा को अपनी सम्पर्क-भाषा बनाकर कोई भी देश जन-क्रान्ति नहीं कर सकता। क्रान्ति का अर्थ मुट्ठी भर आदमियों द्वारा खूनखराबी करना नहीं होता। क्रान्ति का अर्थ है, समाज-व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन लाना। इस तरह के परिवर्तन ग्राम जनता के सहयोग के बिना कभी नहीं लाये जा सकते। जो देश पराधीन हैं, वे ग्राम जनता के संघर्ष के बिना स्वाधीन नहीं हो सकते, और जो देश स्वाधीन हैं, वे ग्राम जनता की दृढ़ एकता और समर्थ राजनीतिक कार्यवाही के बिना अपनी स्वाधीनता की रक्षा नहीं कर सकते।

कुछ लोग समझते हैं कि सम्पर्क भाषा तो मन्त्रियों, नेताओं, बड़े बड़े अफसरों वगैरह के लिए ही जरूरी है। ग्राम जनता अपनी प्रादेशिक भाषाएँ बोलती ही है; उसे सम्पर्क भाषा से क्या लेना-देना है? ऐसा सोचनेवाले अपने को शासक और जनता को शासित समझते हैं। उनके लिए नौकरशाह

जनता के नोकर नहीं हैं, वे उससे आदरार्ह हैं। जिन पार्टियों के हाथ में राज्य-सत्ता नहीं है जिनके नेता निवृत्त भविष्य में मन्त्री बनने के उम्मीदवार हैं, वे भी जनता के अपने को जनता का मेवक नहीं हुकमरान समझने लगे हैं। इसलिए वे अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा बनाकर चैन से अपनी गद्दियों पर बैठे हुए हैं।

इन सबसे भिन्न गांधीजी का मत था कि सम्पर्क नेताओं में ही नहीं, विभिन्न प्रदेशों की आम जनता में होना चाहिए। उन्होंने लिखा था, "आप और हम चाहते हैं कि करोड़ों आदमी अन्तर्प्रान्तीय सम्पर्क कायम करें। स्पष्ट है कि अंग्रेजी के द्वारा, बर्ड पीटियाँ गुजर जाने पर भी वे परस्पर सम्पर्क स्थापित न कर सकेंगे।" (१९२७, ३७० पृ० ४८)। यदि हमारे देश के जनवादी, समाजवादी, मार्क्सवादी-लेनिनवादी राजनीतिज्ञ गांधीजी की इस बात को मानें कि करोड़ों जनता की आपस में राष्ट्रीय स्तर पर सम्पर्क कायम करना है, तो वे सबसे आगे बढ़कर हिन्दी प्रचार के काम में हिस्सा बँटाएँ, वे अंग्रेजी की छतरी के नीचे बैठकर दूर से हिन्दी की मुक्ताचीनी न करते रहें।

देशव्यापी सम्पर्क जनता का, स्वराज्य करोड़ों अनिश्चित और निर्धन लोगों के लिए, नेता और जनता के बीच सबसे बड़ी दीवार अंग्रेजी—यह हुआ गांधीजी की भाषानीति का पहला सूत्र।

गांधीजी के लिए भाषा-समस्या कोई शुद्ध भाषा विज्ञान की समस्या नहीं थी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के सन्दर्भ में ही उस पर विचार किया था। अंग्रेज़ों ने भारतीय जनता को गुलाम बनाने के साथ उसकी भाषाओं का दमन किया उस पर अंग्रेज़ी लादी। अंग्रेज़ों का चलन राजनीतिक सांस्कृतिक पराधीनता का अंग था, उसे सम्पर्क भाषा के पद से हटाना राजनीतिक-सांस्कृतिक स्वाधीनता के लिए आवश्यक था। अंग्रेज़ी की जगह भारतीय भाषाओं का व्यवहार राष्ट्रीय आत्मसम्मान को रक्षा का प्रश्न था।

उनकी भाषा नीति का दूसरा सूत्र है राष्ट्रीय आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अंग्रेज़ी का प्रभत्व खत्म करो।

१९०६ में गांधीजी ने लिखा था, 'क्या वे लोग जो अपनी मातृभाषा का अपमान करते हैं, वही देश का भला कर सकते हैं? मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता कि गुजरात के लोग अपनी मातृभाषा छोड़कर अंग्रेजी कोई भाषा अपना लें। ऐसा ही तो यह करने में ज़रा भी प्रतिशयोक्ति न होगी कि जो लोग अपनी भाषा छोड़ देते हैं वे देशद्रोही हैं और जनता के प्रति विश्वासघात करते हैं।' (३७० पृ० १८६)

जा लोग अंग्रेज़ी में उपयाम और कहानियाँ निरन्तर अन्तराष्ट्रीय स्तर पर अर्जित करते रहे हैं, वे गांधीजी के इन वाक्यों पर गम्भीरता से विचार करें।

गांधीजी ने गुजराती भाषी शिक्षित जनता में मातृभाषा का प्रेम जगाया, अंग्रेज़ी जानने पर उनकी सानत मलामत को। गुजरात के नवीन साहित्यिक अग्रगण्य में उनका योगदान अनुपम है। दिसम्बर, १९१४ में सधामपुर, मूरत

के जैन विद्यार्थियों ने गांधीजी को अपने पुस्तकालय का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। गांधीजी के बोलने की बात सुनकर वहाँ बड़ा जन-समुदाय एकत्र हो गया। एक विद्यार्थी ने अंग्रेजी में भाषण किया। दूसरा खड़ा हुआ, उसने अंग्रेजी में निबन्ध पढ़ा। गांधीजी ने इन अंग्रेजी बोलनेवालों को लक्ष्य करके कहा, “यदि अंग्रेजी जाननेवाले मुट्ठीभर लोगो को हम देश मान लें तो कहना होगा कि देश शब्द का अर्थ नहीं समझा।” उन्होंने उन लोगो को फटकारा जो कहते थे कि वे मातृभाषा में अपने विचार अच्छी तरह प्रकट नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, “जो युवक यह कहते हैं कि हम अपने विचार मातृभाषा द्वारा नहीं प्रकट कर सकते, उनमें मैं यही निवेदन करूँगा कि आप मातृभाषा के लिए भार-रूप है। मातृभाषा की अपूर्णता दूर करने के बदले उसका अन्याय करना—उसमें हाथ ही धो बैठना—किसी सच्चे सपूत को शोभादायक नहीं।”

यह फैसला अभी तक बना हुआ है कि जिनके पास कहने को कुछ नहीं है वे भी करण कठ संक्षमा याचना करत हुए जनता न कहते हैं, हम हिन्दी में अपने विचार पलुएटली प्रकट नहीं कर सकते। मातृभाषा की अपूर्णता दूर करना इनके वश की बात नहीं, वे अंग्रेजी के भारवाही बनकर मातृभाषा और मातृ-भूमि के लिए केवल भार-रूप हैं।

गांधीजी गुजराती के, समस्त भारतीय भाषाओं के सम्मान के लिए लड़े। उनके इस संघर्ष का आदर करनेवालों में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी भी थे। उन्होंने गांधीजी का उपयुक्त भाषण मार्च, १९१६ की ‘सरस्वती’ में छपा था। भाषण को हिन्दी में अनुवादित करके भेजा था गुजराती सज्जन श्री मणिभाई व्यास ने।

दिसम्बर, १९१६ में गांधीजी ने देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा के प्रचार पर लखनऊ में भाषण दिया। आठ-दस हजार श्रोताओं के बीच उन्होंने यह भाषण हिन्दी में दिया। अपने हिन्दी सीखने और हिन्दी के लिए अपमानित होने के बारे में उन्होंने ये मर्मस्पर्शी शब्द कहे थे—

“जिन प्रान्तों में हिन्दी का प्रचार कम है वहाँ हिन्दी पढ़नेवालों की बड़ी कमी है। मैं स्वयं हिन्दी सीखना चाहता था। पर अहमदाबाद में कोई हिन्दी-ज्ञाता शिक्षक न मिला। मिला बेचारा एक गुजराती भाषाभाषी, जिसने पन्द्रह-बीस वर्ष काशी में रहकर टूटी-फूटी हिन्दी सीखी थी। उसी से मैंने हिन्दी सीखी। सम्मेलन यदि अन्य भाषा-भाषी प्रान्तों में आदमी भेजे तो बहुत से लोग हिन्दी सीख जाएँ।”

हिन्दी की दरिद्रता के गीत गाते अंग्रेजी-प्रेमी भारतवासी थकते नहीं हैं। पता नहीं इनकी संख्या पहले ज्यादा थी या अब है। गांधीजी ने इन लोगो को लक्ष्य करके कहा था, “लोग कहते हैं कि हिन्दी में कुछ नहीं है—हिन्दी साहित्य खोखला है—अतएव अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। कभी-कभी तो अंग्रेजी न जानने के कारण लोगो को बूढ़ा ही बहुत कष्ट उठाना पड़ता है।

यह मैं भी मानता हूँ। यहाँ तक कि मुझ-जैसे लोगों को, हिन्दी का व्यवहार करने के कारण—हिन्दी बोलने के कारण—रेलवे इत्यादि में घबके भी खाने पड़ते हैं। अंग्रेज़ी से हिन्दी कितना ही पीछे क्यों न हो, हमें उसका गौरव बढ़ाना ही पड़ेगा।”

राष्ट्र के जो नेता आज हवाई जहाज़ों और ‘एयर कंडीशन्ड’ गाड़ियों में सफ़र करते हुए अंग्रेज़ी को सम्पर्क भाषा का गौरव प्रदान करते हैं, क्या वे कभी याद करते हैं कि अंग्रेज़ी रेलों के यात्री मोहनदास करमचन्द गांधी को हिन्दी बोलने के कारण घबके खाने पड़े थे? वे राष्ट्रपति की जय बोलते हैं, राष्ट्रपिता के नाम पर जनता को अध्यात्मवाद के उपदेश देते हैं, राष्ट्र के नाम पर सन्देश प्रसारित करते हैं, उस भाषा में जिसका व्यवहार गांधीजी राष्ट्र-सम्मान के प्रतिकूल समझते थे।

गांधीजी न अंग्रेज़ों के सामने, उच्चतम अंग्रेज़ पदाधिकारियों के सामने, महा-प्रतापी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रतिनिधि वाइसराय के सामने भारतीय भाषाओं के गौरव की रक्षा की। उसी भाषण में उन्होंने कहा था, “सरकारी कमिशनरों में अंग्रेज़ी की पूछ है—उसी का विशेष आदर है। लोग कहते हैं कि वाइसराय इत्यादि अंग्रेज़ी के अतिरिक्त और कोई भाषा नहीं समझते। अतएव अंग्रेज़ी का ही उपयोग करना आवश्यक है। पर मैं कहता हूँ कि यदि मैं बोलना जानता हूँ और मेरे कथन में कोई बात ऐसी है जिससे वाइसराय लाभ उठा सकें तो अवश्य मेरी बातें, हिन्दी में होने पर भी, सुनेंगे। आपको जरा दृढ़ता और मनोयोग से काम लेना चाहिए। आत्मबलबलव बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता।”

अब अंग्रेज़ वाइसराय नहीं हैं। लेकिन मनोवृत्ति वही है। अंग्रेज़ी बोलने में लोग गौरव का अनुभव करते हैं। इसमें राष्ट्रीय आत्मसम्मान की भावना क्षीण होती है। अंग्रेज़ वाइसराय एक बार किसी को हिन्दी में बोलने की अनुमति भी दे दे लेकिन यदि स्वाधीन भारत की लोकसभा में कोई मन्त्री हिन्दी में बोले तो महाक्रान्तिकारी कामरेड गोपानन ‘वाक आउट’ कर देते हैं। गांधीजी ने केवल दूसरों को वाइसराय के सामने हिन्दी बोलने का उपदेश न दिया था; उन्होंने माहम से अपने उपदेश के अनुसार आचरण भी किया था।

१९३१ में मधुवन भारत के चेम्बर ऑफ कॉमर्स का अधिवेशन कराची में हुआ। उसमें विभिन्न प्रान्तों के सेठ और व्यापारी मौजूद थे। अंग्रेज़ भी थे। किन्तु गांधीजी ने अपना भाषण हिन्दी में दिया। इस भाषण में उन्होंने बताया कि सन् ‘१८ में वाइसराय के सामने वह हिन्दी में बोले थे। सन् ‘१८! अंग्रेज़ वाइसराय! अंग्रेज़ और अंग्रेज़ियत का वह आतंक! उस बलावरण में वाइसराय के सामने हिन्दी बोलने खड़े हुए कर्मवीर गांधी।

कराचीवाले भाषण में उन्होंने कहा था, “मेरे अंग्रेज़ मित्र मुझे क्षमा करेंगे कि जो कुछ मुझे कहना है, वह मैं राष्ट्रभाषा में कहूँगा। इस अवसर पर मुझे उस सभा की याद आती है जो यही १९१८ में बुलाई गई थी। बहुत बहस-मुवाहसे के

वाद जब मैं इस सभा में आने को तैयार हुआ तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे हिन्दी या हिन्दुस्तानी में बोलने की अनुमति दी जाय। मैं जानता हूँ कि इसके लिए प्रार्थना करना जरूरी नहीं था, फिर भी सम्यता का तकाजा था; वरना वाइसराय को बुरा लगता। उन्होंने तुरन्त मुझे अनुमति दे दी और तब से इस मामले में मेरी हिम्मत और खुल गई है। और आज फिर मैं उसी जगह अपने उस अमल को दोहराने जा रहा हूँ। और इस चेम्बर के सदस्यों से मैं विनम्र कहूँगा कि आपका यह कर्तव्य है कि अपना सारा काम राष्ट्रभाषा में करें। इस सगठन में आपको अपनी जनता से ही वास्ता पड़ता है। देश का वातावरण भी इस समय ऐसा है कि उसका प्रभाव आप पर भी जरूर पड़ेगा।” (उप० पृ० २४)

आज किसी अखिल भारतीय सगठन में लोगो से कहा जाय कि अपना काम राष्ट्रभाषा में कीजिए तो बहुत से देशभक्त कह उठेंगे—हम पर हिन्दी लादी जा रही है! उन पर अंग्रेजी पहले से लदी हुई है, यह वे भूल जाते हैं। अंग्रेजी के लिए स्वेच्छा, हिन्दी के लिए अनिच्छा—यह है उनकी देशभक्ति।

५ जुलाई, १९२८ के ‘यंग इंडिया’ में गांधीजी ने अंग्रेजी के प्रभुत्व से होनेवाली देश की हानि के बारे में लिखा था, हजारों नवयुवक अपना कीमती समय इस विदेशी भाषा को सीखने में नष्ट करते हैं जब कि उनके दैनिक जीवन में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है, अंग्रेजी सीखने में समय लगाते हुए वे मातृ-भाषा की उपेक्षा करते हैं, वे इस अन्धविश्वास के शिकार होते हैं कि ऊँचे दर्जे के विचार अंग्रेजी ही में प्रकट किए जा सकते हैं, अंग्रेजी के लाने जाने से राष्ट्र की शक्ति सूख गई है, विद्यार्थियों की आयु क्षीण हो गई है, ग्राम जनता से वे दूर जा पड़े हैं, शिक्षा पाना बड़े खर्च का काम हो गया है। ‘यदि यही सिल-सिला जारी रहा तो बहुत सम्भव है कि राष्ट्र की आत्मा का नाश हो जाय।’

और सब तरह की हानि तो होती ही है, खर्च ज्यादा होता है, उन्नत कम होती है, मातृभाषा की उपेक्षा होती है, गांधीजी के लिए सबसे बड़ा खतरा यह था कि अंग्रेजी का प्रभुत्व राष्ट्र की आत्मा का नाश कर देगा। वह ऐसा क्यों सोचते थे? इसलिए सोचते थे कि वह स्वाधीनता-आन्दोलन के सन्दर्भ में भाषा-समस्या पर विचार करते थे। उनके लिए प्रश्न यह नहीं था कि अंग्रेजी विश्व-भाषा है और हिन्दी दरिद्र है, प्रश्न यह था कि विदेशी भाषा के व्यवहार से राष्ट्रीय चरित्र पर असर क्या पड़ता है। इसलिए वह तुरन्त अंग्रेजी को विदा करने के पक्ष में थे। लेकिन जिसे गांधीजी राष्ट्र की आत्मा कहते थे, उसे अंग्रेजी-प्रेमी नेता मानसिक सर्कीलता कहते हैं।

गांधीजी अंग्रेजी पढ़ने के विरुद्ध नहीं थे। वह उसे वाणिज्य और कूटनीति की भाषा मानते थे। किन्तु वह यह सहन न कर सकते थे कि वह किसी भारतीय भाषा के हक मारे। वह बहुत अच्छी तरह जानते थे कि अंग्रेजी का विश्व-महत्व ब्रिटिश साम्राज्य के कारण है। उन्होंने १९१८ में ही घोषित किया

था, "हमें ऐसी हालत पैदा कर देनी चाहिए कि हमारे राजनीतिक या सामाजिक सम्मेलनों में, कांग्रेस तथा प्रांतीय सभाओं आदि में अंग्रेजी का एक शब्द भी न सुना जाय। अंग्रेजी का व्यवहार हमें पूरी तरह बन्द कर देना चाहिए। अंग्रेजी ने विश्वभाषा की जगह पा ली है लेकिन यह इसलिए कि अंग्रेज सारी दुनिया में फैल गए हैं और हर जगह अपने पैर उन्होंने जमा लिये हैं। जब उनकी यह स्थिति नहीं रहेगी, तब अंग्रेजी का प्रसार भी सङ्कुचित हो जाएगा।" (उप० पृ० ६)

साम्राज्यवाद के पतन के साथ अंग्रेजी के प्रसार का दायरा कम हो गया है। अंग्रेजी भाषाएँ विश्व स्तर पर अंग्रेजी से स्पर्धा करती हैं। बोलनेवालों की संख्या की दृष्टि से संसार की तीसरी भाषा हिन्दी भी विश्वभाषा के रूप में अंग्रेजी का महत्व कम कर सकती है, विश्वभाषा के रूप में उससे स्पर्धा कर सकती है यदि अंग्रेजी प्रेमी भारतवासी अपने देश को अंग्रेजी की गुलामी से आजाद कर दें।

सन् '४७ से पहले हर देशभक्त मानता था कि अंग्रेजी का व्यवहार, शिक्षा संस्थाओं, राजनीतिक संगठनों आदि में अंग्रेजी का चलन मानसिक पराधीनता का लक्षण है। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक समझते थे कि भारत की राष्ट्रभाषा अंग्रेजी हो जाएगी। ६ जून, १९६५ के 'न्यू एज' (माप्ताहिक) में डी० सी० होम नाम के संपन्न ने लिखा है कि उन्नीसवीं सदी के मध्य में जब भारत में नया औद्योगिक युग शुरू हो रहा था, तब भारत के प्रमुख नागरिकों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए खूब जोरदार आंदोलन किया। राजा राममोहन राय ने इनका नेतृत्व किया।

दिलचस्प बात है कि जो भी अंग्रेजी को भारत की अमली राष्ट्रभाषा मानता है, वह किसी-न-किसी रूप में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की प्रगतिशील भूमिका भी मानता है। डी० सी० होम के अनुसार "प्लासी के सत्तर वर्ष बाद, यानी जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद की वस्तुगत रूप से प्रगतिशील भूमिका का एक चक्कर पूरा हो गया था तब क्या इससे यह पता नहीं चलना कि समाज में नये कार्य पूरा करने की उत्सुकता पैदा हो गई थी?"

जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हर देश में समाजवाद अपने ढंग से आता है और उसका अपना रूप होता है वैसे ही क्या अजब जो हर देश में पूंजीवाद भी अपने ढंग से आए और उसका अपना रूप हो। भारतीय पूंजीवाद की विशेषताएँ क्या हैं? इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्रारम्भ से ही अंग्रेजी बोलता रहा है। आखिर देश की एकता तो कायम रखनी ही थी, यहाँ संस्कृत राष्ट्रभाषा बन न सकती थी। प्रादेशिक भाषाएँ बोलियाँ थीं नहीं कि वे किसी एक राष्ट्रभाषा के नीचे दब जाती। द्रविड और संस्कृत भाषा-परिवारों का भेद अलग। अंग्रेजी के सिवा भारतीय पूंजीवाद कौन-सी भाषा बोलता? इसलिए जिन लोगों ने लाड मँकाले के लिए रास्ता साफ किया, जिन्होंने मँकाले

की भाषानीति का समर्थन किया, वे सब प्रगतिशील थे ! जिन्होंने अंग्रेजी का विरोध किया, वे सब दक्षिणानूसी और प्रतिक्रियावादी थे !

संस्कृत और द्रविड परिवारों में ऐसी भयानक शत्रुता है तो मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं में संस्कृत के इतने शब्द कैसे पहुँच गए ? द्रविड देश के शंकराचार्य ने संस्कृत में अपने विचार क्यों प्रकट किए ? क्या उस समय तक कोई द्रविड भाषा उत्पन्न ही न हुई थी ? वह तमिल वहाँ थी जो प्राचीनता में समक्ष नहीं जाती है ?

वास्तव में यहाँ तमिल भी थी, अनेक द्रविड और गैर द्रविड भाषाएँ भी थीं। फिर भी शिक्षितजन संस्कृत का व्यवहार करते थे क्योंकि सामन्ती व्यवस्था के बावजूद, डी० सी० होम सम्प्रदाय की अपेक्षा उनमें राष्ट्रीयता का बोध ज्यादा था।

जनता के दृष्टिगोचर सन मोचन पर आज के गुमराह प्रगतिशील विचारकों को पूँजीवाद और समाजवाद दोनों के विकास के लिए अंग्रेजी आवश्यक दिखाई देती है।

श्री मोहनकुमार मगलम ने भारत का भाषा-संकट नामक पुस्तक में लिखा है, 'हम यह याद किये बिना नहीं रह सकते कि महान् राजा राममोहन राम उम दिन का स्वप्न देखते थे, जब भारत की भाषाएँ रगमच से हट जाएँगी और अंग्रेजी यहाँ की करोड़ों जनता की सामान्य भाषा हो जाएगी।' (पृ० ४)

लार्ड मैकाले और इन महान् समाज सुधारकों का सम्बन्ध इस प्रकार है, "इस तरह इन प्रारम्भिक समाज सुधारकों ने भी अंग्रेजी को उठाने और भारतीय भाषाओं का विकास रोकना लार्ड मैकाले के प्रयत्न में मदद दी।" (पृ० ५)

भारत की भाषाओं और संस्कृति की हालत उस समय क्या थी ? "भारत और पूर्व की संस्कृति अधिक प्राचीन थी परन्तु इस समय वह ठहराव की हालत में (स्टैगनेंट) थी। वह पश्चिम के शक्तिशाली सांस्कृतिक उभार के सम्पर्क में आई।"

भले ही शेली, मैथ्यू आर्नेल्ड, वेट्स आदि लेखक भारतीय संस्कृति से प्रभावित रहे हों, श्री मोहनकुमार मगलम के लिए यहाँ की संस्कृति गतिरुद्ध ही थी। इसलिए आज राजभाषा के पद के लिए तमिल को योग्य बनाना उन्हें हिमालय पहाड़ उठाने जैसा लगता है। (उप० पृ० ६८)

होम और मोहन कुमारमगलम दोनों का मत है कि भारत में संस्कृत के बाद कोई भी सम्पर्क भाषा नहीं थी। इसलिए अंग्रेजी सम्पर्क भाषा के रूप में स्वाधीनता-प्राप्ति के पहले भी जरूरी थी और आज भी जरूरी है। भारतीय इतिहास के ये विशेषज्ञ भूल जाते हैं कि अंग्रेजों का राज कायम होने से पहले यहाँ सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार और प्रसार सर्वत्र था। इसीलिए अंग्रेजों ने अपने अफसरों के लिए हिन्दुस्तानी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया था।

दिल्ली के असिस्टेंट रेजिडेंट मेटकाफ ने २६ अगस्त, १८०६ को हिन्दुस्तानी

वे अपने शिक्षक गिलक्रिस्ट के नाम एक पत्र में लिखा था, "भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमाऊँ के पहाड़ों से नमदा तक, झकगानो, मराठो, राजपूतो, जाटो, सिखों और उन प्रदेशों के सभी कबीलो में जहाँ मैंने यात्रा की है, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी थी। अपने अनुभव से और दूसरों से सुनी हुई बातों के बल पर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक या आवा से मिथु के मुहाने तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हिन्दुस्तानी बोल लेते होंगे।" (जे० बी० गिलक्रिस्ट, ए वार्कबुलरी, हिन्दुस्तानी एण्ड इंग्लिश, इंग्लिश एण्ड हिन्दुस्तानी, एडिनबरा में उद्धृत)

राजा राममोहन राय ने अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मेमोरेंडम पेश किया, होम-सम्प्रदाय को यह तो दिखाई देता है लेकिन जिस भाषा को कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की करोड़ों जनता अपनी सम्पर्क भाषा बना रही थी, वह उन्हें बहुत आँखें मझार देखने पर भी नहीं दिखाई देती।

गांधीजी न लाहं मैकाले के रोत्र में थे, न राजा राममोहन राय के। उन्होंने सन् '२० में लिखा था, "हम अपने विचार से अपने राष्ट्रीय जीवन में प्रादेशिक भाषाभाषा (वर्नाक्युलर्स) को उनका उचित स्थान दे रहे हैं। भाग्य राजा राममोहन राय की हम भविष्यवाणी का साथ नहीं दे रहा कि भारत एक दिन अंग्रेजी भाषी देश हो जाएगा। लेकिन उन महान् समाज-सुधारक का भूत अब भी कुछ लोग पर सवार है। कुछ प्रमिद्ध आदमी बहुत जल्दी यह पंमत्ता दे देते हैं कि राष्ट्र की सम्पर्क भाषा अंग्रेजी होगी।" (थॉट्स ऑन नेशनल लैंग्वेज, पृ० १७)

गांधीजी का सम्बन्ध भी भारतीय पूँजीवाद के विकास से रहा है। उनके स्वदेशी आन्दोलन में भारतीय पूँजीपतियों को अपने उद्योग-धन्धे विकसित करने में सहायता मिली। बिहला जैसे उद्योगपति गांधीजी के नज़दीकी लोगों में थे। होम महानग्य को सन् बीस के बाद का पूँजीवादी विकास नहीं दिखाई देता क्योंकि तब अंग्रेजी का विराघ और भारतीय भाषाओं का समर्थन होने लगा था।

गांधीजी को ज़रूर मैकाले-भक्तों से बराबर सावका पड़ा होगा। ये लोग सीधे मैकाले का नाम न लेकर राजा राममोहन राय की दुहाई देते रहे होंगे। इसीलिए राममोहन राय का नाम अक्सर उनके लेखों में आता है। सन् २१ में उन्होंने इस बात पर दृढ़ प्रकट किया था कि अंग्रेजी ने प्रांतीय भाषाभाषा की जगह ले ली है। उन्होंने कहा था कि राजा राममोहन राय और भी बड़े समाज-सुधारक हात यदि उन्हें अंग्रेजी में साचने और उसी में अपने विचार प्रकट करने की अस्वाभाविक श्रिया न करनी पड़ती। (उप० पृ० २०१)

अंग्रेजा न आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका आदि



भरसक वहाँ की भाषाओं का नाश किया। लाखों नीग्रोजन अपनी भाषाएँ छोड़कर—गुलाम बनाए जाकर—अंग्रेजी-भाषी हो गए। भारतीय जनता ने १८५७ में अंग्रेजों को इस जन-घाती, भाषा घाती नीति पर चलने का मजा चला दिया। सन् १८५७ से पहले भी महाराष्ट्र के शिक्षा-शास्त्रियों ने जमकर मँकाले की भाषा नीति का विरोध किया। वहाँ के समाज-सुधारक डी० सी० होम एण्ड कम्पनी को नहीं दिखाई देते। 'दिये लोभ चसमा चखनि लघु पुनि बडो दिखाय।' अंग्रेजियत के चश्मे से अंग्रेजी परस्त तो बहुत बड़े समाज-सुधारक मालूम होते हैं, अंग्रेजी के विरोधी इतने छोटे हो जाते हैं कि उनके अस्तित्व का उल्लेख भी आवश्यक नहीं होता।

गांधीजी ने राजा राममोहन राय के साथ लोकमान्य तिलक का नाम भी लिया था और कहा था कि यदि उनकी शिक्षा-दीक्षा कम अस्वाभाविक व्यवस्था में हुई होती तो जनता पर उनका प्रभाव और भी गहरा पड़ा होता।

लोकमान्य तिलक मराठी के समर्थ लेखक थे। वह भारतीय भाषाओं का स्थान अंग्रेजी को देने के पक्ष में नहीं थे। इसके अलावा राजा राममोहन राय के विपरीत वह हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानत थे। कानपुर में जनता ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि वह हिन्दी में भाषण नहीं कर सकते। "यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और जिनका विचार है कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। मैं हिन्दी समझ सकता हूँ और टूटी फूटी बोल भी सकता हूँ, व्याख्यान नहीं दे सकता।" ('सरस्वती', फरवरी, १९१७)

इस विचार को अमली रूप देने के लिए उन्होंने 'केसरी' का एक हिस्सा हिन्दी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया था।

लोकमान्य तिलक जैसे समाज सुधारक होम-जैसे अंग्रेजी प्रेमियों की दृष्टि से अशुभ रहते हैं।

स्वाधीनता प्राप्ति में साल भर पहले गांधीजी ने उस दिमागी गुलामी की निन्दा की थी जो अंग्रेजी को अपनी राजभाषा बनाने के लिए नेताओं को मजबूर करती है। मोरारजी सच बी मिमाल देते हुए उन्होंने लिखा था, "रूस ने अपनी सारी वैज्ञानिक प्रगति अंग्रेजी के बिना ही की है। यह हमारी दिमागी गुलामी है जो हम कहते हैं कि अंग्रेजी के बिना काम नहीं चल सकता। मैं इस पराजयवादी मत को कभी स्वीकार नहीं कर सकता।" (उप० पृ० २०१)

स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद गांधीजी ने २१ सितम्बर, १९४७ के 'हरिजन' में 'दिमागी बाहिनी' की निन्दा की जिसमें प्रेरित होकर अफमर और नेता बहते थे कि शिक्षा और धामन में अंग्रेजी ही चलेगी।

गांधीजी ने अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ में लेकर भारत के स्वाधीन होत के बाद तक, अपने जीवन की आखिरी घड़ियों तक अंग्रेजी का विरोध किया, अंग्रेजी के ऊपर निर्भर रहने की आदत को राष्ट्र के लिए हानिकार

बताया, अंग्रेजी की हिमायत को राष्ट्रीय चरित्र के लिए घातक बताया। जो लोग अंग्रेजी कायम रखकर भाषा-समस्या का समाधान खोजते रहे हैं, उनमें राष्ट्रीय धारममम्मान की कमी है।

राष्ट्रभाषा की समस्या राष्ट्रीय चेतना के आधार पर ही हल हो सकती है। जो लोग भाषा-समस्या को साम्राज्य-विरोधी सघर्ष के मन्दर्म से अलग हटाकर हल करना चाहते हैं, वे समस्या को बराबर उनभाते जाएंगे, उसे मुलभाना उनके लिए सम्भव न होगा। यह गांधीजी का दूसरा मूल दृष्टा।

गांधीजी का तीसरा मूल है—भारतीय जनता की प्रमानी राष्ट्रभाषा हिन्दी है।

यदि राजनीतिज्ञ जनता के व्यवहार को देखें, इस बात को समझें कि अंग्रेजी न जाननेवाले साधारण जनो को भी परस्पर सम्पर्क के लिए एक सामान्य भाषा की जरूरत होती है, तो उन्हें यह दिखाई देने लगे कि जनता के अन्तर्प्रदेशिक सम्पर्क की भाषा कौन-सी है। महा-राष्ट्र-गुजरात पंजाब के लोग आपस में हिन्दी की सम्पर्क भाषा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसे बहुत से लोग मानते हैं। सवाल है दक्षिण भारत का। क्या वहाँ के साधारण लोग भी हिन्दी की सम्पर्क भाषा के रूप में अपनाते हैं?

गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका के अपने इस अनुभव का उल्लेख किया था कि वहाँ तमिल और तेलुगु बोलनेवाले लोग परस्पर सम्पर्क के लिए हिन्दी काम में लाते हैं। जो कार्य वे दक्षिण अफ्रीका में करते थे, उस वे दक्षिण भारत में भी अवश्य करते रहे होंगे। वास्तव में तमिल-तेलुगु-भाषियों को उत्तर भारत से सम्पर्क कायम करने के लिए ही हिन्दी की जरूरत नहीं होती, उन्हें आपस में सम्पर्क-भाषा के लिए भी जरूरत हिन्दी की होती है।

एक मित्र ने अदमान से मुझे वहाँ की भाषा-स्थिति के बारे में यह लिखा है, "अधिकतर वहाँ बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड और मलयालम बोली जाती है। आपस में व्यवहार की भाषा हिन्दी है जो 'हम बोलता है, आप करना माँगता है' पद्धति से बोली जाती है। हिन्दी ही राष्ट्रभाषा है वहाँ स्वतः सिद्ध हो जाता है। तमिल तेलुगु से हिन्दी में ही बात कर पाता है। इसी प्रकार अन्य भाषा-भाषी।"

दक्षिण भारत में गांधीजी का अनुभव ऐसा ही था, "यह कहना सही नहीं है कि मद्रास में अंग्रेजी के बिना काम नहीं चलता। मैंने अपने सारे कामों के लिए वहाँ सफलतापूर्वक हिन्दी का व्यवहार किया है। मैंने रेल में मद्रासी मुसाफिरों को दूसरों से हिन्दी में बातें करते सुना है।" (उप० पृ० ६)

सी० एफ० एण्ड्रूज का अनुभव भी यही था। उनकी मातृभाषा अंग्रेजी थी लेकिन उन्हें हिन्दी बोलने में उतना कष्ट न होता था जितना राज्यसभा या लोकसभा के कुछ भारतीय सदस्यों को। 'द टू इंडिया (१९३६) पुस्तक में उन्होंने लिखा था, "कल एक व्यक्ति मुझसे मिलने आया था, उसने जब मैंने

अंग्रेजी में बातचीत करने की कोशिश की तो उसने कहा, 'कृपा करके हिन्दुस्तानी में बातचीत कीजिए।' और जब मैं उस भाषा में बोला तो वह मेरी बात आसानी से समझ गया।"

राजनीतिज्ञों को उत्तर-दक्षिण में सम्पर्क के लिए नई भाषा गढ़ना नहीं है, वह भाषा जनता में पहले से प्रचलित है, उसे केवल सरकारी स्तर पर सम्पर्क-भाषा के रूप में स्वीकार करना है। जहाँ तक बंगाल का सम्बन्ध है, वहाँ की भाषा हिन्दी के बहुत ही नजदीक है। इस नजदीकीपन के अलावा कलकत्ता की लगभग आधी आबादी हिन्दुस्तानी है। इस आबादी में ज्यादातर लोग मेहनत-मजदूरी करके गुजर करनेवाले हैं। उनके मालिकों का उनसे हिन्दी में ही बात करनी होती है। गांधीजी ने लिखा था कि "उत्तर भारत का जो मिया बम्बई के सेठ के यहाँ दरबानगीरी करता है, वह गुजराती नहीं बोलता, उसका मालिक सेठ ही मजदूर होकर उससे टूटी-फूटी हिन्दी में बातचीत करता है" (उप० पृ० ६)। यही स्थिति बंगाल की है। वहाँ न जाने कितने 'हिन्दुस्तानी' दरबान का काम करते रहे हैं। उनके मालिक उनसे टूटी-फूटी हिन्दी में ही बातें करने को बाध्य हुए हैं।

डॉ० सुनीतिकुमार घटर्जी ने पहले हिन्दी इसी तरह के लोगों से सीखी थी। "कलकत्ता में अपने बचपन में ही लेखक ने हाट गजारी में तथा घर के बिहारी नौकरों से बंगाल में प्रयुक्त 'बाजारू हिन्दी' कहलानेवाली भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लिया था।" (भारतीय धर्म भाषा और हिन्दी, पृ० २४५)। यद्यपि डॉ० सुनीतिकुमार भाषा को धर्म में और धर्म का सङ्कलित से जोड़कर यह नतीजा निकालते हैं कि 'हिन्दी के सङ्कलित उपादान को क्रमशः कम करने की प्रवृत्ति भारतीय परम्परा एवं भारतीय सङ्कलित पर प्रत्यक्ष आघात-मा है" (उप० पृ० २३८), फिर भी वह मानते हैं कि "हिन्दी (हिन्दुस्तानी) के साठे चौबीस करोड़ बोलने या समझनेवालों में से लगभग बीस करोड़ हिन्दुस्तानी का यही सहज रूप बोलते हैं" (उप० पृ० २०६), मोनवी, मुशी और मुल्ला लोग "फारसी भरी उर्दू का निर्माण एवं बढान करते रहे। उसी प्रकार पंडित लोग तथा अन्य लेखक लोग सङ्कलित भरी हिन्दी का निर्माण करते रहे। परन्तु आधारेण जनो का हिन्दुस्थानी के विषय में एक ही रुख रहा, इनमें पश्चिमी पञ्जाब से लगाकर पूर्वी बंगाल तक के हिन्दू मुसलमान सभी थे। वे अब भी, आधारेण जीवन में अपने सभिन्न भाषावाला से बातचीत करना चाहते हैं तो प्रचलित हिन्दुस्थानी का ही व्यवहार करते हैं।" (उप० पृ० २०६)

पश्चिमी पञ्जाब से पूर्वी बंगाल तक, जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जन-सम्पर्क की भाषा बोलचाल की हिन्दी है। व्याकरण के अनुसार शुद्ध रूप में, सङ्कलित शब्दों से सजाकर जनता इसे नहीं बोलती। उसके स्थानीय भेद हैं जैसे ब्रिटेन, अमेरिका और आस्ट्रेलिया की अंग्रेजी में भेद हैं। बोलचाल की हिन्दी बंगाल में भी समझी जाती है और जनता के व्यवहार में आती है। फिर भी

बंगाल में हिन्दी का तीव्र विरोध है, सभी लोगो में नहीं किन्तु मध्यवर्ग और पढ़े-लिखे लोगो में है इसमें कोई सन्देह नहीं।

गांधीजी ने सन् २१ में 'यंग इंडिया' में लिखा था कि बंगाल के लोग अपने पूर्वाग्रह के कारण भारत की और कोई भाषा सीखना नहीं चाहते (थाँस प्रॉन नेशनल लैंग्वेज, पृ० १६)। हिन्दी-प्रचार के काम में बंगाली विद्वानों ने महत्वपूर्ण योग दिया है। हिन्दी के समर्थकों में डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी जैसे भाषाविद् रहे हैं। उन्होंने भारतीय भाषाओं के लिए—विशेषकर बंगला और हिन्दी के लिए—बहुत काम किया है। आज वह हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के विरुद्ध अंग्रेजी का समर्थन करते हैं, इससे उनका पहले किया हुआ काम निरर्थक नहीं हो जाता। उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करना धर्म है। उनसे पहले बकिमचन्द्र चटर्जी के समय में 'बगदर्शन' पत्र में लिखा था, "हिन्दी भाषा साहाय्ये भारतवर्षे विभिन्न प्रदेशे मध्य जाहारा ऐक्यबन्धन स्थापन करिते पारिवेन ताहाराईप्रकृत भारतवन्धु नामे अभिहित हृद्वार योग्य।" (बालमुकुन्द गुप्त द्वारा उद्धृत, बालमुकुन्द गुप्त निबन्धावली, बलकृष्ण, पृ० १५६)

फिर भी बंगाल में ऐसे बुद्धिजीवी बहुतायत में हैं जो किसी भी भारतीय भाषा को सीखना अपने लिए हेठो की बात समझते हैं। डॉ० सुनीतिकुमार चटर्जी ने ही लिखा है, "कोई भी महाराष्ट्रीय या बंगाली व्यक्ति इस बात का अनुभव नहीं करता कि अपनी मातृभाषा की अपेक्षा नागरी हिन्दी या उर्दू के माध्यम द्वारा उच्चतर सस्ट्रनि की प्राप्ति हा सकती है, बाज़ार हिन्दी का तो प्रश्न ही दूर है।" (भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, पृ० २१५)

इसी तरह तमिलनाडु के श्री मोहनकुमार मगलम न यह राय जाहिर की है कि "स्वाधीनता-प्राप्ति के समय हिन्दी शायद सबसे कम विकसित भाषा थी।" (भारत का भाषा-मकट, पृ० ३१)। दाव्य में शायद उन्होंने गालीनतावश लगा दिया है, वरना हिन्दी का पिछड़ी हुई भाषा कहना प्रत्येक भारतवासी का नावैधानिक अधिकार है।

तमिलनाडु और बंगाल के अंग्रेजी प्रेमी बुद्धिजीवियों को एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थिति ध्यान में रखनी चाहिए। किसी समय प्रसम, उडोमा, बिहार आदि प्रदेश समुक्त बंगाल के अन्तर्गत थे। इसी प्रकार केरल और घाघ्र तमिलनाडु के भाग जुड़े हुए थे। इन बड़े बड़े प्रान्तों में तमिल और बंगाली बुद्धिजीवी अंग्रेजी के कारण सरकारी नौकरियाँ पाते थे, अफसर बनकर दूसरों पर हुक्मन करते थे, बकील, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के पेशों में इन्हीं का बोलबाला था। मद्रास प्रेसीडेन्सी टूट गई, रह गया तमिलनाडु। उडोमा, प्रसम और बिहार अलग हो गए, रह गया विभाजित बंगाल। प्रसम में बंगालियों और प्रसमियों के बीच दंगे हुए। पौरो कारणों के अलावा दंगों के पीछे दोनों जातियों के बीच पुराना सनातन भी काम कर रहा था। तमिलनाडु और घाघ्र के शिक्षितजनों में उससे

कार्यवाही की भाषा हिन्दी होनी चाहिए ।

यह बात देखने में बहुत साधारण मालूम होती है लेकिन वास्तव में है सबसे महत्वपूर्ण । भारत की राजनीतिक पार्टियाँ भाषा-समस्या पर प्रस्ताव करके दूसरों की सिखाती रही हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए । वे स्वयं अंग्रेजी हटाने के लिए क्या करने जा रही हैं, इसकी सूचना वे दूसरों को कम देती हैं । आप कल्पना कीजिए, यदि कांग्रेस का सारा राजकाज हिन्दी में हुआ करता तो क्या हुकूमत की बागडोर संभालते ही अंग्रेजी हटाने में कांग्रेसी नेताओं को साल-भर से ज्यादा देर लगती ? ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट नेता जो पहले कांग्रेस के ही सदस्य थे, स्वाधीनता-प्राप्ति के दो साल पहले तक जो कांग्रेस में थे, क्या उससे अलग होने पर अपने यहाँ भी हिन्दी का व्यवहार न करते ? यदि ये विभिन्न पार्टियों के नेता अंग्रेजी के बिना अपना काम चलाने के आदी होते, तो क्या संविधान सभा में हिन्दी अंग्रेजी को लेकर इतनी बहस होती ? क्या संविधान सभा हिन्दी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने के बाद पन्द्रह साल तक अंग्रेजी को चालू रखने का नियम बनाती ? क्या पन्द्रह साल बीतने से पहले अंग्रेजी को आगे भी सह-राजभाषा—अमल में एकमात्र केन्द्रीय राजभाषा—बनाए रखने का कानून पास होता ? क्या पन्द्रह साल बीतने पर अंग्रेजी को अनिश्चित काल तक कायम रखने की नीबट आती ?

इसमें आप समझ लीजिए कि कांग्रेस के अन्दर से अंग्रेजी हटाने का सघर्ष कितना महत्वपूर्ण था और यह सघर्ष चलाकर गांधीजी ने कितनी बड़ी वीरता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था । उन्हें अपने सघर्ष में सफलता नहीं मिली, इसमें यह भी समझ लीजिए कि अंग्रेजी के हिमायती इस देश में कितने शक्ति-शाली हैं । गांधीजी को हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायवाद खत्म करने में सफलता नहीं मिली, उन्हें देश का विभाजन रोकने में सफलता नहीं मिली, उन्हें सरकार और कांग्रेस के अन्दर से अंग्रेजी हटाने में सफलता नहीं मिली । इन तमाम असफलताओं को लिए हुए वह भारतीय प्रतिक्रियावाद की गोली खाकर सत्तार से चले गए । लेकिन रास्ता वही है जिस पर वह चले थे और उस रास्ते पर चलकर भारत एक दिन अवश्य विजयी होगा ।

दिसम्बर, १९१६ । लखनऊ में कांग्रेस का इकतीसवाँ अधिवेशन । गांधीजी हिन्दी में बोलना शुरू करते हैं । 'इग्लिश प्लीज' की आवाजें आती हैं । वह सदस्यों से कहते हैं—साल-भर में हिन्दी अवश्य सीख लीजिए । अगले साल की कांग्रेस में अंग्रेजी न चलनी चाहिए ।

१९१८ । वह कहते हैं, "हमारी राष्ट्रीय सस्थाओं में हिन्दी का ही व्यवहार होना चाहिए । कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इन दिशा में बहुत-कुछ कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए । मैं चाहता हूँ कि यह सम्मेलन (हिन्दी साहित्य-सम्मेलन) कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के समय उसके सामने इस आशय का प्रस्ताव रखे ।" (याँटम, पृ० १२)

१९२१ वह बंगाल और दक्षिण के लोगों से खास तौर से कहते हैं, "मैं आशा करता हूँ कि बंगाली और द्रविड़ लोग दूसरी कांग्रेस में (यानी कांग्रेस के अगले अधिवेशन में) काम लायक हिन्दी सीखकर आएँगे। हमारी यह महानुसमा जनता की शिक्षक तब तक नहीं बन सकती जब तक वह ऐसी भाषा में न बोले, जिसे ज्यादा-से-ज्यादा जनता समझती हो।" (उप०, पृ० १६)

१९२५. कांग्रेस का नया विधान धारा ३३—"जहाँ तक सम्भव होगा कांग्रेस की कार्यवाही हिन्दुस्तानी में होगी। यदि कोई हिन्दुस्तानी न बोल सके या जरूरत पड़े तो अंग्रेजी तथा प्रान्तीय भाषा का व्यवहार भी किया जा सकेगा।" इस प्रस्ताव में अंग्रेजी-प्रेमियों पर तगड़ी पाबन्दी न लगाई गई थी, फिर भी जो लोग हिन्दी-हिन्दुस्तानी का व्यवहार करना चाहें, उनके लिए छूट थी।

१९२८ : गांधीजी ने श्री विजयरामवाचारी के इस कथन का उल्लेख किया कि "हम लोग उत्सुकता से उस दिन की राह देख रहे हैं जब हम हिन्दुस्तानी पहले होंगे, मद्रासी या बंगाली बाद को। वह दिन जल्दी आएगा यदि मद्रासी, जो इस मामले में सबसे ज्यादा गायिल हैं, बड़ी तादाद में हिन्दी सीखने लगे।" इसके बाद गांधीजी ने 'यंग इंडिया' में लिखा, "दक्षिण के लोगों को हिन्दी-प्रधार सभा के कारण हिन्दी सीखने के लिए हर तरह की सुविधा है। यदि भारत के लिए हमारे हृदय में वैसे ही मक्का प्यार है जैसे अपने प्रान्तों के लिए है तो हम अवश्य ही जल्दी सीख लेंगे और हमें यह अपमानजनक दृश्य न देखना पड़ेगा कि अतिव भारतीय कांग्रेस समेटी की कार्यवाही—पूरी-की-पूरी नहीं तो अधिकांश—अंग्रेजी में हो रही है।" (उप०, पृ० २६)

१९३१ : "दक्षिण के लोग वादा कर चुके हैं कि अगले साल की कांग्रेस के लिए वे ऐसे प्रतिनिधि भेजेंगे जो हिन्दी में बोलेंगे और हिन्दी समझेंगे। हम अस्वाभाविक परिस्थितियों में न रहते होते तो दक्षिण के लोगों को हिन्दी सीखना बिल्कुल न मालूम होता, व्यर्थ की बात तो और भी नहीं।" (उप०, पृ० ३०)

१९३७ : मद्रास में हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के मंच से उन्होंने यह प्रस्ताव पेश किया कि सम्मेलन कांग्रेस में हिन्दी का व्यवहार करने की प्रार्थना करता है। उन्होंने प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा, "हम राष्ट्रभाषा हिन्दी के समर्थन में प्रस्ताव पास करते रहे और कांग्रेस पुरानी सीक पर चलती रहे तो हमारे काम की रचना बहुत धीमी होगी। इस प्रस्ताव में कांग्रेस से अपील की गई है कि वह अन्तर्प्रान्तीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का बहिष्कार करे। इसके अनुसार अंग्रेजी को न तो प्रान्तीय भाषा, न हिन्दी की जगह देनी चाहिए।" (उप०, पृ० ५२)

धन में अपने और अन्य गृहयोगियों के मुदीर्ष प्रयत्नों का निर्व्याकरण करते हुए उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम चरण में लिखा—

गांधीजी

ने अपने बानपुर-अधिवेशन के प्रसिद्ध प्रस्ताव में इस अखिल भारतीय भाषा को हिन्दुस्तानी कहा। तब से कम से-कम कहने-भर को हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा हो गई है। कहने-भर को इसलिए कि कांग्रेसियों ने भी उस प्रस्ताव पर उस तरह अमल नहीं किया जैसे उन्हें करना चाहिए था। १९२० में जबकि यह बोधिशुरू हुई कि आम जनता की राजनीतिक शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं का महत्व पहचाना जाय, साथ ही एक अखिल भारतीय सामान्य भाषा का महत्व पहचाना जाय, जिसे राजनीति में प्रबुद्ध भारत आसानी से बोल सके और जिसे विभिन्न प्रान्तों के सदस्य कांग्रेस के अखिल भारतीय अधिवेशनों में सम्मिलित सकें। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि बहुत से कांग्रेसी जनो ने उस प्रस्ताव पर अमल नहीं किया। और इसलिए यह दृश्य उपस्थित होता है जो मेरी समझ में शर्मनाक है कि कांग्रेसमैन अंग्रेजी बोलने की जिद करते हैं और दूसरों को भी अपनी खातिर अंग्रेजी बोलने पर मजबूर करते हैं। अंग्रेजी का जादू अभी खत्म नहीं हुआ। उस जादू के असर से हम देश को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकते हैं। जनता के लिए हमारा प्रेम एकदम सतही है यदि हम हिन्दुस्तानी सीखने के लिए उतने महीने भी नहीं देना चाहते जितने साल हम अंग्रेजी सीखने में लगाते हैं।" (उप०, पृ० ६२)

भारत स्वाधीन हुआ। गांधीजी ने चेतावनी दी कि "सरकार और सेक्रेटैरियट सावधान न रहे तो सम्भव है कि अंग्रेजी हिन्दुस्तानी की जगह ले ले। इससे भारत की करोड़ों जनता का वेहद नुकसान होगा जो अंग्रेजी समझ न पाएंगी।" (उप०, पृ० १६८)। उन्होंने प्रान्तीय भाषाओं को पुनर्जीवित करने की सलाह दी, साथ ही यह सुझाव रखा कि प्रान्तीय सरकारें ऐसे कर्मचारी रखें जो प्रान्तीय भाषा के साथ अन्तर्प्रान्तीय भाषा हिन्दुस्तानी भी जानते हों।

यह सब न हुआ क्योंकि जिन लोगों के हाथ में शासन की बागडोर थी, वे अपने राजनीतिक संगठन में अंग्रेजी का व्यवहार करते थे। जो विरोधी दल संसद् में भारतीय लोकतन्त्र के संचालन में शामिल हुए, वे भी अखिल भारतीय सम्पर्क के लिए अंग्रेजी का ही व्यवहार करते थे।

इसलिए जो लोग चाहते हैं कि स्वाधीन भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म हो, उन्हें पहला कदम यह उठाना चाहिए कि भारत के राजनीतिक दलों के केन्द्रीय दफ्तरों से अंग्रेजी निकालें, इनके अखिल भारतीय अधिवेशनों में अंग्रेजी का व्यवहार बन्द कराएँ, उनका अखिल भारतीय प्रचार कार्य अंग्रेजी के माध्यम से बन्द कराएँ। सबसे मुश्किल यह पहला कदम ही है। यदि एक बार भारतीय जनता यह कदम उठाने के लिए पार्टियों के नेताओं को बाध्य करे तो दूसरे कदम उठाना बहुत आसान हो जाएगा।

पहले पार्टियों के अन्दर से अंग्रेजी की जड़ काटिए।

फिर लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों को भारतीय भाषाओं में बोलने— और अंग्रेजी छोड़ने—पर मजबूर कीजिए।

इसके बाद नौकरशाही पर दबाव डालिए कि वे दफतरो से अंग्रेजी निकालें। जब नेता लोग अंग्रेजी का बहिष्कार कर देंगे तब मन्त्रीजी के सामने कोई फाइल अंग्रेजी में न आएगी। अफसर लोग लोकसभा का अनुसरण करेंगे। इस समय विश्वविद्यालय अखिल भारतीय सेवाओं से नर्तकी हैं। शिक्षा का एक उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य अफसर तैयार करना है। जब आई० ए० एस० में अंग्रेजी का चलन न होगा, तब विश्वविद्यालयों में भी अंग्रेजी का प्रभुत्व न रहेगा।

पार्टी—लोकसभा—नौकरशाही—युनिवर्सिटियाँ, इस क्रम से अंग्रेजी के ज़िलो पर हमला करना चाहिए।

गांधीजी की भाषा-नीति का पाँचवाँ सूत्र है—भारत का विकास और राष्ट्रीय एकता की रक्षा प्रादेशिक भाषाओं को दबाकर नहीं, उनके पूर्ण विकास से ही सम्भव है।

गांधीजी ने अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ से ही अंग्रेजी का विरोध किया और प्रान्तीय भाषाओं की हिमायत की। १९०६ में ही उन्होंने प्रान्तीय भाषाओं और राष्ट्रभाषा का सम्बन्ध अच्छी तरह समझ लिया था। उन्होंने लिखा था, “हिन्दुस्तान में आजकल हिन्दू, मुसलमान, पारसी वगैरह ‘अपने देश’ की बात करने लगे हैं। इस समय मैं इस बात पर राजनीतिक दृष्टि से विचार नहीं कर रहा हूँ। भाषा की दृष्टि से यह जरूरी है कि इसके पहले कि हम अपने देश को अपना कहें, हमारे दिलों में अपनी भाषाओं के लिए प्रेम और आदर पैदा होना चाहिए। ऐसा मालूम होता है कि सारे भारत में लोग अपनी भाषाओं की ओर ध्यान देने लगे हैं। यह प्रगति की बात है।” (उप०, पृ० १-८)

इस लेख में गुजरातियों को अंग्रेजी बोलने पर उन्होंने फटकारा। उन्होंने इस बात पर हर्ष प्रकट किया कि लोग गुजराती, मराठी, बँगला, उर्दू आदि की प्रगति के लिए संस्कार बना रहे हैं।

सन् १५ में सशागपुर के विद्यालयों के सामने मापण (जिसका उल्लेख पहले हो चुका है) करते हुए उन्होंने मानुभाषा की अवज्ञा करनेवालों की निन्दा की।

सन् २७ में जब हिन्दी प्रचार आन्दोलन शक्तिशाली होने लगा था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि “हिन्दी या हिन्दुस्तानी या उद्देश्य यह नहीं है कि वह प्रान्तीय भाषाओं की जगह ले ले। वह अनिश्चित भाषा होगी और अन्तर्प्रान्तीय सम्पर्क के काम आएगी।” (उप०, पृ० २६)

१९३५ में जब बारा बानेलजर ने गांधीजी को बताया कि लोग यह कहने लगे हैं कि हिन्दी प्रचार का उद्देश्य प्रान्तीय भाषाओं का दमन है तब गांधीजी ने साहित्य-सम्मेलन के मंच से घोषित किया, ‘मगर कहना बराबर यही रहा है कि प्रान्तीय भाषाओं का जरा भी घटित हम नहीं करना चाहते, उनका दमन या



नाश करना तो दूर की बात है।" (उप०, पृ० ३८)

गांधीजी स्वयं गुजराती के ध्येष्ठ लेखक थे। उनकी प्रेरणा से गुजराती बुद्धि-जीवियों ने अंग्रेजी का मोड़ छोड़ा और मातृभाषा की सेवा की। गुजराती भाषा के सेवक अंग्रेजी की गुलामी में मुक्त होने के कारण हिन्दी के समर्थक हुए। हिन्दी भाषी प्रदेशों के नेता, विशेषकर उत्तर प्रदेश (भूतपूर्व समुक्त प्रान्त) के अविभाजित काशी और कम्युनिस्ट नेता गांधीजी की तरह मातृभाषा के सेवक नहीं थे। अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रखने में उनका बहुत हाथ रहा है। गांधीजी स्वयं गुजराती के समर्थ लेखक थे, इसलिए वह प्रान्तीय भाषाओं और हिन्दी का सम्बन्ध अच्छी तरह समझते थे।

सन '३६ में उन्होंने बंगलोर में कहा था, "लोगों ने एक हीबा खड़ा कर रखा है जिसे मैं आप लोगों के दिमाग में निवास देना चाहता हूँ। क्या हिन्दी की शिक्षा कन्नड़ को हटाकर दी जाएगी? क्या यह सम्भावना है कि वह कन्नड़ की जगह ले ले? इसके विपरीत मेरा कहना है कि हम जितना ही हिन्दी प्रचार करेंगे उतना ही अपनी मातृभाषाओं के अध्ययन का और सशक्त बनाएँगे, इन भाषाओं की शक्ति और सामर्थ्य को और भी बढ़ा सकेंगे। मैं विभिन्न प्रान्तों में अपने अनुभव के आधार पर यह कहता हूँ।" (उप०, पृ० ५०)

गांधीजी खूब जानते थे कि प्रादेशिक भाषाओं का मुख्य अन्तर्विरोध अंग्रेजी से है, न कि हिन्दी से। उन्होंने मद्रास में कहा था, 'अगर अंग्रेजी ने जनता की भाषाओं की जगह न ले ली होती तो आज वे अत्यन्त समृद्ध अवस्था में होती।' (१९३७, पृ० ५२)

गांधीजी की नीति स्पष्ट थी किन्तु कांग्रेस के कुछ नेता, विशेषकर उत्तर प्रदेश के नेता, यह कहते थे कि उच्च शिक्षा और शासन व्यवस्था में अंग्रेजी की तरह हिन्दी भी प्रादेशिक भाषाओं की जगह लेगी। इससे अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं का मुख्य अन्तर्विरोध गौण हो जाता था, और हिन्दी ग्रहिन्दी भाषाओं का नया अन्तर्विरोध सामने आ जाता था। हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के जो हिमायती प्रादेशिक भाषाओं के हक मारकर उसे अंग्रेजी की जगह देने की बात कहते रहे हैं, वे हिन्दी के मार्ग में बाँटे बिछाते रहे हैं और इससे लाभ हुआ है अंग्रेजी को।

गांधीजी जानते थे कि भारत ऐसा राष्ट्र है जिसमें अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं। वह ब्रिटेन या फ्रांस की तरह एक भाषावाला राष्ट्र नहीं है। इसलिए वह इस पक्ष में थे कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो जिससे प्रदेशों का राजकाज वहाँ की भाषाओं में हो सके। गांधीजी के कहने से जातीय इलाकों के आधार पर कांग्रेस कमेटीयों का संगठन किया गया था। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद गांधीजी ने लिखा, 'प्रान्तीय भाषाओं को अपना पूर्ण विकास करना है तो भाषा के आधार पर प्रान्तों का पुनर्गठन आवश्यक है। हिन्दुस्तानी राष्ट्रभाषा हमी लेकिन वह प्रान्तीय भाषाओं की जगह न लेगी। वह प्रान्तों में

शिक्षा का माध्यम न होगी—अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो, इसका मवाल नहीं है। हिन्दुस्तानी का उद्देश्य यह होगा कि वह लोगों को महसूस कराए कि वे भारत के अभिन्न अंग हैं। बाहर के लोग हमें गुजराती, महाराष्ट्री, तमिल आदि कहकर नहीं जानते हैं। उनके लिए हम सब हिन्दुस्तानी हैं। इसलिए हमें सभी विषयनकारी प्रवृत्तियों को दृढ़ता से रोकना चाहिए। इस मुख्य बात को ध्यान में रखते हुए हम मानेंगे कि भाषावार प्रान्त बनाने में शिक्षा और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा।" (१९४८, पृष्ठ २०२)

केन्द्रीय सरकार ने भाषावार प्रान्त बनाने का प्रश्न विरोध किया। तमिलनाडु और गुजरात के बड़े पूंजीपति यह नहीं चाहते थे कि उनके विद्याल प्रान्त खण्डित हो। इनके अंग्रेजी अलवारों ने भाषावार प्रान्त-निर्माण का जोरों से विरोध किया। गांधीजी ने कहा था कि भाषावार प्रान्त बनाने से शिक्षा और व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा। गांधीजी की निगाह छोटे व्यापारियों और पूंजीपतियों पर थी जो बड़े प्रान्तों में उदीयमान इजारेदारों से पीड़ित थे। लेकिन दिल्ली की सरकार इन इजारेदारों की बात ज्यादा सुनती थी, गांधीजी और मध्यम पूंजीपतियों की कम। यही कारण है कि उसने प्राणपन से महाराष्ट्र और आंध्र के नये प्रान्त बनाने के आन्दोलन का विरोध किया।

गांधीजी के नाम पर जनता में घोट लेनेवाला, गांधीवाद विरोधी दिल्ली का सरकारी कांग्रेस-नेतृत्व भाषावार प्रान्त-निर्माण का विरोध करके हिन्दी का अहित और अंग्रेजी का हित कर रहा था। कुछ अहिन्दी-भाषियों में यह भय उत्पन्न हुआ कि उनकी भाषाओं का दमन किया जाएगा और उन पर हिन्दी लादी जाएगी। इधर दिल्ली सरकार के नेता जानते थे कि अंग्रेजी न भाज जाने-वाली है न बल। फिर भी वे बराबर हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का दावा करते जाते थे क्योंकि इसके बिना विद्याल हिन्दी-भाषी क्षेत्र में उन्हें खोत न मिल सकते थे।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भाषावार प्रान्त-निर्माण का विरोध करने में दिल्ली सरकार ने बड़े पूंजीपतियों के दबाव में सरकार अपनी नीति निर्धारित की। इन बड़े पूंजीपतियों की माँठ गाँठ ब्रिटेन के इजारेदारों से भी थी। दिल्ली सरकार भारत के बड़े पूंजीपतियों के अलावा जब-तब ब्रिटेन के इजारेदारों का हल देखकर भी काम करती थी। ब्रिटिश पूंजीपति चाहते थे कि भारत में अंग्रेजी रहे। इसमें एक तो भारत सांस्कृतिक रूप से ब्रिटेन के साथ नटवी रहता है, दूसरे अंग्रेजी किताबों की बिक्री के लिए इतना बड़ा बाजार ब्रिटिश प्रकाशकों के हाथ में बना रहता है। इसीलिए जो लोग भाषावार प्रान्त बनाने के विरोधी थे, वे अंग्रेजी का बहुत बड़े समर्थक थे। दिल्ली सरकार न तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की दुनाम थी, न वह केवल भारत के बड़े पूंजीपतियों की प्रतिनिधि थी। उसने भारत के उद्योगीकरण में, विशेषकर सरकारी उद्योग-धन्यो के निर्माण में, भारत की स्वतन्त्र विदेश-नीति निर्धारित करने में और

समाजवादी देशों से मंत्री-सम्बन्ध कायम करने में बहुत बड़ा योग दिया। फिर भी उसने भारत और ब्रिटेन के बड़े पूंजीपतियों के हित में कुछ गलत कदम उठाए।

कुछ प्रगतिशील विचारक भाषावार प्रान्त-निर्माण के पक्ष में गांधीजी के विचार बड़े गर्व से उद्धृत करते हैं किन्तु गांधीजी ने अंग्रेजी हटाने के बारे में जो कुछ कहा था, उसे वे बड़े प्रेम से नजरअन्दाज कर देते हैं। ये विचारक उन मध्यवर्गी बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधि हैं जो केन्द्र में अंग्रेजी चालू रखकर अखिल भारतीय नीकरियों के उम्मीदवार हैं।

गांधीजी के नाम की दुहाई देकर केन्द्र में 'फिलहाल' अंग्रेजी चलाते रहने की बात करना हास्यास्पद है।

प्रान्तीय भाषाओं के सम्बन्ध में गांधीजी का यह उदार दृष्टिकोण ध्यान देने योग्य है कि अंग्रेजी की जगह जहाँ अन्तर्प्रान्तीय सम्पर्क के लिए लोग हिन्दी न बोल सकें, वहाँ वे प्रान्तीय भाषा का ही व्यवहार करें।

१९४२ में बनारस विश्वविद्यालय में गांधीजी ने हिन्दी में भाषण करते हुए कहा था, 'यहाँ मंच पर एक के बाद दूसरा वक्ता भाषा और मैं अधीरता से राह देखता रहा कि कोई हिन्दी या उर्दू या हिन्दुस्तानी में, या संस्कृत में ही भाषण करे, यह न सही तो मराठी में या और किसी भारतीय भाषा में बोले। लेकिन मुझे यह सौभाग्य प्राप्त न हुआ। क्यों? इसलिए कि हम गुलाम हैं और उन्हीं की भाषा को छाती से चिपकाये हुए हैं जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है।'

विद्यार्थियों को लक्ष्य करके उन्होंने कहा, "ये जरा-जरा-सी बात पर हड़ताल कर देते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं। ये राष्ट्रभाषा में शिक्षा पाने के लिए क्यों नहीं लड़ते? मुझे बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के ढाई सौ विद्यार्थी हैं। उन्हें सर राधाकृष्णन् के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए कि विश्व-विद्यालय में एक आन्ध्र विभाग खोला जाय। वे राष्ट्रभाषा नहीं सीखना चाहते तो तेलुगु के माध्यम से शिक्षा पाने की माँग करें।" (उप० पृ० ६२-६३)

"राष्ट्रभाषा नहीं सीखना चाहते तो तेलुगु के माध्यम से शिक्षा पाने की माँग करें", इस सूत्र को आज की परिस्थितियाँ में लागू करें तो हम नेताओं में कहेंगे कि आप हिन्दी नहीं बोल सकते तो अपनी मातृभाषा में भाषण कीजिए। श्री कामराज नाडार इसी नीति का पालन करते हैं और तमिल में बोलते हैं। अनुवाद की व्यवस्था करके उन लोगों की कठिनाई दूर की जा सकती है जो हिन्दी का व्यवहार नहीं कर सकते या जान बूझकर नहीं करना चाहते।

गांधीजी भरिया गए। सभा में हजारों मजदूर थे। गांधीजी का अभिनन्दन अंग्रेजी में किया गया। इस पर उन्होंने 'यंग इंडिया' में लिखा, 'अधिकांश श्रोता आसानी से हिन्दी समझ लेते और काफी लोग बँगला समझ लेते। उस सच के

पदाधिकारी बंगाली थे। अगर उन्होंने अंग्रेजी का व्यवहार मेरे लिए किया तो बिल्कुल अनावश्यक था। वे अभिनन्दन (या भाषण) बंगला में लिख सकते थे और मुझे उसका हिन्दी-अनुवाद दे देते। अंग्रेजी में भी अनुवाद करके दे सकते थे। लेकिन उत्तरी बड़ी सभा पर अंग्रेजी घोषणा उसका अपमान करना था।”

इसके आगे दक्षिण भारत को लक्ष्य करके उन्होंने लिखा, “यह घटना सभाएं संगठित करनेवालों के लिए हर जगह चेतावनी का काम करे, खास तौर से आंध्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सभा-संयोजकों को सावधान कर दे, यह मैं चाहता हूँ। मैं उनकी कटिनाई समझता हूँ। लेकिन छह साल से उनके बीच हिन्दी-प्रचार सभा (जोरो) से काम कर रही है। उनके भाषण प्रान्तीय भाषाओं में होने चाहिए और मेरी सुविधा के लिए उनके हिन्दी अनुवाद दे देने चाहिए।” (उप०, पृ० २२-२३)

गांधीजी ने यह सब सन् '२७ में लिखा। तब से अब तक हिन्दी-प्रचार सभा लाखों छात्रमियों को हिन्दी सिखा चुकी है। फिर भी वे या अन्य अहिन्दी-भाषी राष्ट्रभाषा का व्यवहार न कर सकें या न करना चाहें तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलना चाहिए और उनके भाषण के अनुवाद की व्यवस्था होनी चाहिए।

२७-२८ जून को इस साल बरेली में साहित्य-सम्मेलन का जो अधिवेशन हुआ, उसके प्रस्ताव में कहा गया है, “केन्द्रीय सरकार और हिन्दी-भाषी राज्य-सरकारों से उत्तर प्रदेश सरकार केवल हिन्दी में सम्पूर्ण पत्र-व्यवहार करे तथा इतर भाषी राज्य सरकारों से पत्र-व्यवहार मूल रूप से हिन्दी में करे और साथ में तत्क्षेत्रीय भाषा में रूपान्तर सलग्न कर दिया करे।” (राष्ट्रभाषा सन्देश, इलाहाबाद, ८ जुलाई, १९६५)

गांधीजी की नीति को वर्तमान परिस्थिति में बस धमती रूप दिया जाय, सम्मेलन का सुभाव इसकी बहुत अच्छी मिसाल है। प्रस्ताव में यह नहीं कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार अन्य प्रदेशों की सरकार से केवल हिन्दी में पत्र-व्यवहार करे, या हिन्दी के साथ अंग्रेजी में अनुवाद भेजे, प्रस्ताव में अंग्रेजी के मुकाबले प्रान्तीय भाषाओं को ऊँचा आसन दिया गया है। इस प्रकार अनुवाद की व्यवस्था करके अन्य प्रदेशों की सुविधा का ध्यान रखते हुए अंग्रेजी को हटाया जा सकता है।

गांधीजी ने कहा था कि आंध्र के विद्यार्थी राष्ट्रभाषा के माध्यम से शिक्षा पाना नहीं चाहते तो वे तेलुगु में शिक्षा पाने की माँग करें। वे उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक केन्द्र काशी में प्रादेशिक भाषा तेलुगु और हिन्दी को समान अधिकार देने के लिए तैयार थे। पाठक विचार करें, समुक्त राष्ट्र सघ का काम कैसे चलता है। वह विश्व सत्ता है। उसके सेक्रेटेरियट में न जाने कितनी भाषाओं में बोलनेवालों की बातों का हिसाब-किताब रखना पड़ता है। सेक्रेटेरियट में

दुनिया की सभी भाषाओं में वारंवाई नहीं दर्ज की जाती; न संयुक्त राष्ट्रमण्डल ने अंग्रेजी को विश्व-भाषा मानकर केवल उसी में दफ्तर चलाने का नियम बनाया है। उसने अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, चीनी और स्पेनी को बराबर अधिकार देकर उन्हें अपने काम-काज की भाषा बनाया है। हर भाषण का अनुवाद इन भाषाओं में एवं साथ किया जाता है।

भारत में जब तक अहिन्दी प्रदेशों के नेता स्वेच्छा से हिन्दी स्वीकार नहीं करते, तब तक यदि हिन्दी, बंगला, तमिल, तेलुगु और मराठी को समान रूप से केन्द्रीय भाषा मान लिया जाय, तो क्या यह समाधान हिन्दी-अहिन्दी नेताओं को मान्य न होता चाहिए ?

यदि विश्व-मस्था का दफ्तर एक से अधिक भाषाओं में चल सकता है तो क्या हम लोकसभा में एक से अधिक भाषाओं में बोलने और पाँच स्वीकृत भाषाओं में भाषण के अनुवाद की व्यवस्था नहीं कर सकते ? इसी तरह केन्द्रीय सरकारी दफ्तरों का काम एक से अधिक भाषाओं में हो सकता है।

गांधीजी ने लिखा था, 'दक्षिण प्रम्रीका जैसे देश में अंग्रेजी और बड़ भाषाओं की टक्कर थी। अन्त में फैसला यह हुआ कि दोनों भाषाओं को बराबरी का दर्जा देना चाहिए।' (थॉट्स, पृ० २४)

इसी तरह कनाडा में अंग्रेजी-फ्रांसीसी, बेल्जियम में फ्रांसीसी-फ्लेमिश, पाकिस्तान में उर्दू-बंगला, लका में सिंहली-तमिल भाषाओं की टक्कर है। इन देशों में भाषा-समस्या का एक ही समाधान है कि दो भाषाओं को बराबर अधिकार देकर उन्हें केन्द्रीय भाषाएँ माना जाय।

औ लोग यह समझते हैं कि अंग्रेजी हटाने की माँग दूसरी भाषाओं पर जबर्दस्ती हिन्दी लादने की माँग है, उनके विचार और चिन्तन के लिए मेरा उपर्युक्त प्रस्ताव है। इसमें न तो केन्द्रीय सेवाओं के लिए सभी से एक भाषा सीखने का आग्रह है, न भारत की सभी भाषाओं को केन्द्रीय भाषा बना देने की माँग है। यह मध्यमार्गी प्रस्ताव है और अमल में लाया जा सकता है बशर्त कि पहले कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी तथा अन्य दल अपने केन्द्रीय दफ्तरों से अंग्रेजी निकाल दें।

गांधीजी की भाषा-नीति का अन्तिम सूत्र है—हिन्दी-उर्दू बुनियादी तौर से एक ही भाषा हैं और आगे चलकर उनका एक ही सम्मिलित साहित्यिक रूप होगा।

हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता के बारे में उन्होंने लिखा था, 'हिन्दी और उर्दू या हिन्दुस्तानी में कोई भी फर्क नहीं है। दोनों का व्याकरण एक है। फर्क केवल लिपि का है। विचार कीजिए तो मालूम होगा कि हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी—इन तीन शब्दों से एक ही भाषा का बोध होता है। इनके शब्दकोश देखें तो पता चलेगा कि अधिकांश शब्द एक-से हैं।' (उप०, पृ० ५०)

गांधीजी ने जो कुछ लिखा था, वह बोलचाल की भाषा की दृष्टि से सही

था। हिन्दी-उर्दू मूलतः एक ही भाषा है और ग्राम जनता उनके व्यवहार में कोई भेद नहीं करती।

गांधीजी ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि उर्दू भाषा और लिपि केवल मुसलमानों की सम्पत्ति नहीं है। "ऐसे काफी हिन्दू और अन्य धर्मों के लोग भी हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू है और जो केवल उर्दू लिपि जानते हैं।" (उप०, पृ० १७५)

इतने जो नतीजा निकलता है, वह यह कि उर्दू धार्मिक अल्पसंख्यकों की भाषा न होकर मातृवर्तित अल्पसंख्यकों की भाषा है। वह स्वतन्त्र भाषा नहीं, इसलिए उसकी तब तक रक्षा करनी चाहिए जब तक एक ही बोलचाल की भाषा के दोनों निष्ठ रूप धूल-मिलकर एक न हो जाएँ।

देग में हिन्दू-मुस्लिम समस्या अंग्रेजों के हाथ में बहुत बड़ा हथियार थी जिसे वे राष्ट्रीय आन्दोलन को लोडने के लिए इस्तेमाल करते थे। उर्दू का सम्बन्ध मुसलमानों के विशेषाधिकारों से जुड़ गया। उर्दू की रक्षा का प्रश्न—विशेष रूप से उसकी लिपि की रक्षा का प्रश्न—धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा का प्रश्न बन गया। गांधीजी ने हिन्दी-हिन्दुस्तानी का नारा देकर हिन्दुओं और मुसलमानों को मिलाने का भगीरथ प्रयत्न किया। किन्तु भाषा केवल बहाना थी; धनगाव के कारण दूसरे थे। बंगाल में उर्दू लिपि की रक्षा का प्रश्न न था; फिर उसका विभाजन हुआ। मिथी भाषा के लिए फारसी लिपि का ही समोचित रूप काम में आता था। फिर भी मिथी पाकिस्तान में गया। जिनकी भाषा उर्दू थी, वे यही रहे। उर्दू के दमन का नारा लगाकर मुस्लिम जनता को भड़काया गया, साम्राज्यवादियों और उनके माध्यमिक सहायकों ने भाषा समस्या में काम उठाकर राष्ट्रीय आन्दोलन को कमजोर किया।

इस परिस्थिति को बदलने का एक ही तरीका था, साम्राज्यवाद के खिलाफ ग्राम जनता का संगठन किया जाय। उत्तर भारत में किसान-संगठनों और मजदूर-संगठनों में एक ही भाषा का व्यवहार किया जाय, इन जन-संगठनों में फारसी, मस्जुत गद्दी के व्यवहार पर रोक न लगाकर एक ही लिपि देवनागरी के व्यवहार पर जोर दिया जाय। एक लिपि के माध्यम में जो किसान-मजदूर अपनी राजनीतिक-सांस्कृतिक काम करते, वे फारसी-मस्जुत के शब्दों की छंटाई खुद कर लेंगे। वे लेंगे जो मार्क्सवाद में प्रभावित थे, हिन्दी-उर्दू साहित्य का प्रकाशन एक ही लिपि देवनागरी में करने दोनों के बीच का कामना काम करने में मदद दे सकते थे। गांधीजी गुजराती थे। वह प्राथमिक हिन्दी साहित्य से बहुत काम परिचित थे, उर्दू-साहित्य के विज्ञान से और भी कम परिचित थे। उत्तर प्रदेश के प्रगतिशील लेखक गांधीजी को बहुत बड़ी मदद कर सकते थे। लेकिन इन लेखकों की भाषा-नीति में आमिषा थी जिनकी चर्चा अन्य निबन्ध में है।

हिन्दी उर्दू का भेद महत्व नहीं था। बख्ताऊ हिन्दी और मौलवियाना उर्दू

की शिक्षा करके वह भेद समाप्त न किया जा सकता था। दोनों में एक-दूसरे को मान-दो मान में एक सामान्य सिद्ध था। गांधीजी भारत की समाज भाषाओं के लिए एक विधि के व्यवहार पर जोर देने में। हिन्दु राष्ट्रभाषा हिन्दुभाषी के लिए एक दोषा विधि का व्यवहार व्यवहार बनाने में। वह जानने के लिए बहुत से विद्वानों की विधि व्यवहार के लिए है। और ऐसे व्यवहार की होती। उर्दू विधि और उर्दू-भाषा की गुरुशिष्य रगने की बात गयी थी। हिन्दु यदि एक ही विमान-भाषा में वचन भाषा हिन्दी में बनना काम करने है और हम भाषा उर्दू में, तो हमने विमानों का वर्ग-महान कामचोर होता है। गारे देश में राष्ट्रभाषा की शक्ति होती है, तो हमने गारे देश का काम बहिन हो जाता है। गारे देश व शिक्षा लोग दोनों विविध लोग, राष्ट्रभाषा दोनों ही विधियों में विनीत, वह बात समझ-सारिख थी।

व्यावहारिक बात यह भी कि हिन्दी-उर्दू की विधियों की बनावटी का दर्जा न देकर एक की प्रमाण और प्रादेशिक व्यवहार के लिए स्वीकार किया जाय और दूसरी की व्यवहार्यता के लिए व्यवहार्य मातृभाषा सराफ प्रमाण दिया जाय। यदि उर्दू की सुगमताओं की विधि मात्र ही दिया जाय तो भी वह व्यवहार्यता की विधि होगी, उसे देवनागरी का दर्जा देना समझ था।

हिन्दू और मुस्लिम साम्राज्यवादियों में भिन्न गांधीजी हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता में विश्वास करने के और समझने के कि जब साम्राज्यिक तनाव कम हो जाएगा, तब दोनों विधियाँ पुनः मिलकर एक हो जाएँगी। उन्होंने मनु '२७' में लिखा था, "जब तक हिन्दू-मुस्लिम तनाव बना हुआ है, तब तक वह कभी पारसी-घरबी दादो से लड़ी हुई पारसी विधि में मिली जानेवाली उर्दू का रूप लेता है, कभी मल्लू दादो से लड़ी हुई देवनागरी विधि में मिली जानेवाली हिन्दी का रूप लेता है। जब दोनों के दिल मिलेंगे तब एक ही भाषा के दो रूप पुनः मिलकर एक हो जाएँगे और हम भाषा में मल्लू, पारसी, घरबी या अन्य भाषाओं के उतने ही दाद होने मिलेंगे उनके पूर्ण विश्वास और पूर्ण व्यवहार-विधि के लिए दरबार होगा।" (उप०, पृ० २६-२७)

इन बातों में जोर भाषा की मूल प्रवृत्ति पर है। जिसने दाद विभिन्न भाषा में मिले जाएँगे, वह भाषा के अपने विश्वास पर, उसके बोधनेवालों के विश्वास पर निर्भर है, इसका फेसला बोलकार नहीं कर सकते। लेकिन दोनों मिलेंगी जरूर, गांधीजी का यह दृढ़ विश्वास था। उनका यह विश्वास विमल सही था। बंगाल के विभाजन से बंगला के दो रूप नहीं हो गए, पञ्जाब के बँटवारे से दो पञ्जाबी भाषाएँ नहीं बन गईं। भाषाओं के विश्वास के नियम साम्राज्यवादी योजनाओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं। उर्दू पाकिस्तान की नहीं हिन्दुस्तान की है। हम उसका सरक्षण करेंगे, साथ ही हिन्दी-उर्दू का भेद मिटाने का भी करेंगे। हिन्दी-उर्दू लिखने बोलनेवालों का प्रदेस एक, जाति एक,

आर्थिक सम्बन्ध एवं । बोलचाल की भाषा के दोनों साहित्यिक रूपों को एक दिन मिलना ही होगा ।

गांधीजी की भाषा-नीति के ये छह महत्वपूर्ण सूत्र हैं जिन्हें आज की परिस्थितियों में विवेक से लागू करके हम भाषा-समस्या के भली समाधान की ओर बढ़ सकते हैं ।

(१९६५)



सबका है।

ग्रन्थ भाषा-भाषियों की मुन्नता के लिए एक नई कल्पना बढ़ाने के लिए '३५' के 'हम' में उन्होंने लिखा है, "इनका अर्थ रचना करने वाला है, और उनका चाहे बिना भी लिखार है, इनको इन भाषाओं की एक होनी आवश्यक है।" इन शब्दों में उन्होंने अपने अर्थ-व्यवस्था के अनुसार और चिन्तन का गार रक्त दिया है।

सरन भाषा लिखने के पक्षपाती होते हुए भी प्रेमचन्द साहित्यिक की कठिनाइयों को जानते थे। उन्होंने स्वीकार किया है, अपने, विज्ञान आदि में और कथा-साहित्य में भी जहाँ वह विवेचनात्मक हो जाता है, जन-साधारण की भाषा से अलग कठिन शब्द अपनाते पड़ते हैं। भाषा-काव्य के विरुद्ध कुछ लोगों की तरह भाषा न उठाकर प्रेमचन्द ने जन-साधारण में ही अधिकारिक भाषा और साहित्य के प्रचार पर जोर दिया है। जो लोग उच्चकोटि का यन्त्रीय साहित्य रचनेवालों की भाषा-सम्बन्धी कठिनाइयों को न समझकर उस पर गुर्रत ही दुरुहता, अस्वामाविकता आदि का आरोप कर बैठते हैं, उन्हें प्रेमचन्द के इन शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए— 'जब तक जनता में शिक्षा का अच्छा प्रचार नहीं हो जाता, उसकी व्यावहारिक शब्दावली बड़ नहीं जाती, हम उसके समझने सायक भाषा में तात्त्विक विवेचनाएँ नहीं लिख सकते।' शिक्षा का प्रचार होने पर वही कठिन शब्द "जिन्हें देखकर आज हम भयभीत हो जाते हैं, जब अभ्यास में आ जाएँगे तो उनका हीवापन जाता रहेगा।" ('हम, जनवरी, १९३५)

राष्ट्रभाषा के राजनीतिक महत्व को वह पूरी तरह स्वीकार करते थे और इसके लिए उन्होंने नेताओं पर यह दोष भी लगाया है कि वे इस सम्बन्ध में अधिक सचेष्ट नहीं रहे। "जब हमारे नेता हिन्दी-साहित्य से बेखबर से हैं, जब हम लोग बोझी-सी अंग्रेजी लिखने की सामर्थ्य होते ही हिन्दी को कुछ और प्रामीणी की भाषा समझने लगते हैं, तब यह कैसे प्राप्ता की जा सकती है कि हिन्दी में ऊँचे दर्जे के साहित्य का निर्माण हो।" ('हम', जनवरी, १९३६) फिर भी उनका विचार था देश का साहित्य यदि उन्नति कर सकता है तो राष्ट्रभाषा के द्वारा ही, अन्य उपभाषाओं से नहीं, राष्ट्रभाषा का साहित्य अन्त-में ठहर सवेगा, दूसरा नहीं। "यह स्वप्न देखना कि भारत की समुन्नत भाषाओं के बराबर हो सकती है, लेकर अन्तर्राष्ट्रीय संधों के सामने खड़ा

प्रेमचन्द कितना महत्वपूर्ण

## प्रेमचन्द और भाषा-समस्या

प्रेमचन्द ने भाषा के सम्बन्ध में काफी विचार किया था और उसके सम्बन्ध में लिखा भी काफी है। जब उन्होंने उर्दू छोड़कर हिन्दी में लिखना शुरू किया था तब भी उनके सामने भाषा का प्रश्न महत्वपूर्ण होकर आया था। इसी-लिए 'सेवासदन' में भी हम उन्हें इस विषय पर सोचते-विचारते देखते हैं। डॉ० श्यामाचरण मोटर से उतरकर अंग्रेजी में अपने देर होने की समा चाहते हैं, तब कुँवर साहब उन्हें याद दिलाते हैं, "डॉक्टर साहब, आप मूलते हैं, यह वाले आदमियों का समाज है।" डॉक्टर साहब अंग्रेजी को देश की सिंगुला फाका मानते हैं, परन्तु कुँवर साहब इसका कारण देश के कुछ अंग्रेजी-मक्ती को बताने हैं। अंग्रेजी से कुँवर साहब को "ऐसी ही घुणा होती है जैसी किसी अंग्रेज के उदारे कपड़े पहनने में।"

उर्दू और हिन्दी का प्रश्न प्रेमचन्द के सामने लाजा था। उसके बारे में कुँवर साहब कहते हैं—“फारस और बाबुल के पूर्व सिपाहियों और हिन्दू व्यापारियों के समागम से उर्दू जैसी भाषा का प्रादुर्भाव हो गया। अगर हमारे देश के भिन्न-भिन्न प्रान्तों के विद्वज्जन अपनी ही भाषा में सम्भाषण करते तो अब तक कभी एक सार्वदेशिक भाषा बन गई होती।” दिसम्बर, १९३१ के 'हंस' में एक पुस्तक की आलोचना करते हुए प्रेमचन्द ने लिखा था, “साहित्य-मंडल ने उर्दू के केन्द्र दिल्ली में हिन्दी-प्रकाशन का भार उठाया है, यह उद्योग प्रशंसनीय है।” प्रेमचन्द हिन्दी-उर्दू का भेद पिटाने के पक्ष में थे क्योंकि वास्तव में भाषाएँ दोनो एक हैं। इसके लिए वह बाज़ी उदारता से काम लेता चाहते थे, भाषा शुद्ध ही हो, इसके वह कामत न थे। परन्तु राष्ट्रभाषा को कुछ गिने-बुने आदमियों की न होकर देश के समूह की गमक में आनीवासी होना चाहिए। जैसा उन्होंने 'हंस' में लिखा था, “राष्ट्रभाषा केवल रईमों और अमीरों की भाषा नहीं हो सकती। उसे विमानों और मजदूरों की भाषा बनना पड़ेगा।” बीजली भाषा विमानों और मजदूरों की भाषा बन सकती है—  
कहानियों और उपन्यासों के ही विमान-मजदूरों की भाषा।

सबता है।

अन्य भाषा-भाषियों की सुगमता के लिए वह हिन्दी का शब्दकोश बढ़ाना चाहते थे परन्तु वह ऐसे शब्द लेने के पक्ष में न थे जिनसे हिन्दी हिन्दी न रहे। नवम्बर, '३५ के 'हस' में उन्होंने लिखा था, "इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि अपना कोप बढ़ाने की धुन में वह अपना रूप ही न खो बैठे...हिन्दी की एक मर्यादा है, और उसका चाहे जितना भी विस्तार हो, उसकी इस मर्यादा की रक्षा होनी आवश्यक है।" इन शब्दों में उन्होंने अपने जीवन-पर्यन्त के अनुभव और चिन्तन का सार रख दिया है।

सरल भाषा लिखने के पक्षपाती होते हुए भी प्रेमचन्द साहित्यिक की कठिनाइयों को जानते थे। उन्होंने स्वीकार किया है, दर्शन, विज्ञान आदि में और कथा-साहित्य में भी जहाँ वह विवेचनात्मक हो जाता है, जन-साधारण की भाषा से अलग कठिन शब्द अपनाने पड़ते हैं। भाषा-काठिन्य के विरुद्ध कुछ लोगों की तरह भाषाज्ञ न उठाकर प्रेमचन्द ने जन-साधारण में ही अधिकाधिक भाषा और साहित्य के प्रचार पर जोर दिया है। जो लोग उच्चकोटि का गम्भीर साहित्य रचनेवालों की भाषा-सम्बन्धी कठिनाइयों को न समझकर उस पर तुरन्त ही दुरुहता, अस्वाभाविकता आदि का आरोप कर बैठते हैं, उन्हें प्रेमचन्द ने इन शब्दों को ध्यान में रखना चाहिए— 'जब तक जनता में शिक्षा का अच्छा प्रचार नहीं हो जाता, उसकी व्यावहारिक शब्दावली बढ़ नहीं जाती, हम उसके समझने लायक भाषा में तात्त्विक विवेचनाएँ नहीं लिख सकते।' शिक्षा का प्रचार होने पर वही कठिन शब्द "जिन्हें देखकर भाज हम भयभीत हो जाते हैं, जब अभ्यास में आ जाएँगे तो उनका होवापन जाता रहेगा।" ('हस', जनवरी, १९३५)

राष्ट्रभाषा के राजनीतिक महत्व को वह पूरी तरह स्वीकार करते थे और इसके लिए उन्होंने नेताओं पर यह दोष भी लगाया है कि वे इस सम्बन्ध में अधिक सचेष्ट नहीं रहे। "जब हमारे नेता हिन्दी-साहित्य से देखबर से हैं, जब हम लोग थोड़ी-सी अंग्रेजी लिखने की सामर्थ्य होते ही हिन्दी को तुच्छ और ग्रामीणों की भाषा समझने लगते हैं, तब यह कैसे भाषा की जा सकती है कि हिन्दी में ऊँचे दर्जे के साहित्य का निर्माण हो।" ('हस', जनवरी, १९३६)

फिर भी उनका विचार था देश का साहित्य यदि उन्नति कर सकता है तो राष्ट्रभाषा के द्वारा ही, अन्य उपभाषाओं से नहीं, राष्ट्रभाषा का साहित्य अन्तराष्ट्रीय प्रतिद्वन्द्विता में ठहर सकेगा, दूसरा नहीं। "यह स्वप्न देखना कि भारत की सभी प्रान्तीय-भाषाएँ ससार की समुन्नत भाषाओं के बराबर हो सकती हैं, भूल है। एक राष्ट्र एक ही भाषा को लेकर अन्तराष्ट्रीय सभा के सामने खड़ा हो सकता है।" ('हस', नवम्बर, १९३५)

इससे मालूम होता है, राष्ट्रभाषा के प्रदन को प्रेमचन्द कितना महत्वपूर्ण समझते थे और उसके साहित्य की उन्नति के लिए उनमें कौसी उत्कट अभिलाषा

थी। उसी लगन से साहित्य रचकर उन्होंने राष्ट्रभाषा का भस्तव भी ऊँचा किया है।

लिपि के सम्बन्ध में उन्होंने विशेष कुछ विवेचनात्मक नहीं लिखा, परन्तु जैसे भाषा के सम्बन्ध में उनकी पहली कसौटी बोधगम्यता की है, उसी प्रकार लिपि के लिए उन्होंने पहले पहल उसका सरल और सुबोध होना आवश्यक समझा है। इसलिए उन्होंने देवनागरी लिपि का ही मर्मर्यन किया था, "हिन्दुस्तानी भाषा के लिए हिन्दी लिपि रखना ही सुविधा की बात है।" ('हस', नवम्बर, १९३५) (१९४०)

## २

प्रेमचन्द ने साहित्यकारों के लिए लिखा था कि उन्होंने कौम की तारीख बनाई है, उसकी सस्कृति बनाई है। प्रेमचन्द किस कौम की तारीख बनानेवाले साहित्यकार थे? वैसे तो उनके साहित्य का आधार सारे हिन्दुस्तान में हुआ है लेकिन वह खास तौर से हिन्दीभाषी जाति के लेखक थे। वह हिन्दुस्तानी कौम की तारीख बनानेवाले साहित्यकार थे। उन्होंने हिन्दी और उर्दू दोनों ही में रचनाएँ कीं। हिन्दी और उर्दू के लेखकों को नज़दीक लाने में, हिन्दी और उर्दू के सामन्ती साहित्य का मुकाबला करने में, हिन्दी और उर्दू के नये साहित्य में आजादी और जनतन्त्र व भाव और विचार भरने में प्रेमचन्द ने हमारी जाति की अद्वितीय सेवा की है। तुलसीदास के बाद हिन्दी के वह सबसे बड़े साहित्यकार थे जिन्हें हमारी किसान जनता ने अपनाया। जहाँ-जहाँ हिन्दी-उर्दू पढ़नेवालों ने प्रेमचन्द की रचनाओं में रस लिया, वहाँ-वहाँ जातीय एकता का भाव और मजबूत हुआ।

हिन्दुस्तानी कौम की एकता में हिन्दी-उर्दू का विवाद एक बहुत बड़ी बाधा बना हुआ था। प्रेमचन्द इसके लिखनेवालों को दो कौमों का लेखक न मानते थे। वह उन्हें नज़दीक लाना चाहते थे जिससे कि एक मिली-जुली साहित्यिक भाषा का चलन हो सके। दिल्ली में हिन्दुस्तानी सभा के स्थापित होने पर उन्होंने उसका स्वागत किया था क्योंकि उसमें हिन्दी और उर्दू के लेखक एक साथ बैठते और बहस करते थे। हिन्दी उर्दू के लेखकों का परस्पर मिलना जुलना और एक साथ भाषा और साहित्य की समस्याओं पर विचार करना उनकी नज़र में कितना जरूरी था यह 'हिन्दुस्तानी सभा' पर उनकी टिप्पणी से जाहिर होता है। इसमें उन्होंने लिखा था, "जब उर्दू का अदीब अपनी कोई रचना ऐसी समाज के सामने पढ़ेगा, जिसमें हिन्दी के लेखक भी शरीक हैं, तो वह ऐसी भाषा लिखने की कोशिश करेगा जो हिन्दीवालों की समझ में आए। इसी तरह हिन्दी का लेखक उर्दू के अदीबों की मण्डली में अपनी भाषा को सुबोध रखने पर मजबूर होगा।" इस तरह वे परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान से वह एक मिली जुली साहित्यिक शैली के विकास की आशा करते थे।

इस तरह के प्रयोग की सफलता एक दूसरी बात पर भी निर्भर है और वह

यह कि इस तरह की सभाओं में शामिल होनेवाले लेखक किस हद तक जनता के लिए लिखते हैं और किस हद तक अपने जीवन में जनता के नज़दीक हैं। जनता के लिए न लिखने पर साहित्यकार उसी पुरानी सफाजी और उन्हीं पुराने झलकारों की दुनिया में चक्कर लगाता रहता है और तब हिन्दी और उर्दू के लेखक एक-दूसरे से सीखने के बदले एक-दूसरे के कठिन शब्दों को ढूँढ़ने में लग जाते हैं। एक मिली-जुली साहित्यिक भाषा के जरिये कोम की सेवा करने और उसको संगठित करने का सवाल पीछे पड़ जाता है। जहाँ पर हिन्दी-उर्दू लेखकों के मिलकर काम करने और सभाएं चलाने के बाम पूरी तरह सफल नहीं हुए वहाँ असफलता का मुख्य कारण जनता से लेखकों के अलगाव को समझना चाहिए।

एक साहित्यिक शैली गढ़ने के पक्ष में होते हुए भी प्रेमचन्द उसे गढ़ने की कठिनाइयों को जानते थे। 'भारतीय साहित्य परिषद्' में हिन्दुस्तानी को जगह न देने पर मौलाना अब्दुल हक की आलोचना का जवाब देते हुए उन्होंने जून, सन् '३६ के 'हस' में लिखा था, "और जो हिन्दुस्तानी अभी व्यवहार में नहीं आई, उसके और ज्यादा हिमायती नहीं निकले तो कोई ताज्जुब नहीं। जो लोग हिन्दुस्तानी का बकालतनामा लिये हुए हैं, और उनमें एक इन पक्तियों का लेखक भी है वे भी अभी तक हिन्दुस्तानी का कोई रूप खड़ा नहीं कर सके। केवल उसकी कल्पना-मात्र कर सके हैं, यानी वह ऐसी भाषा हो जो उर्दू और हिन्दी दोनों ही के संगम की सूरत में हो जो सुबोध हो और आम बोलचाल की हो।"

इससे नतीजा यही निकलता था कि एक मिली जुली साहित्यिक शैली के लिए वक्त की जरूरत थी। हिन्दी को बहुत ज्यादा संस्कृतमय और उर्दू को फारसी-अरबीमय बनाने का विरोध करना सही था लेकिन हिन्दी और उर्दू की जो दो शैलियाँ चल रही थी, उन्हें एकाएक छोड़ा नहीं जा सकता था। प्रेमचन्द हिन्दी और उर्दू दोनों में लिखते थे और उनकी हिन्दी उर्दू में भेद भी रहता था। इस पर कुछ लोगो ने उन पर यह तोहमत लगाई कि वह मुँह से तो हिन्दुस्तानी की हिमायत करते हैं, अमल में हिन्दी का प्रचार करते हैं।

'हस' के 'प्रेमचन्द स्मृति अंक' में श्री अशफाक हुसैन ने एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है। "अलीगढ़ से 'सुहेल' नाम का एक उर्दू अखबार निकलता है। उसमें छापने के लिए प्रेमचन्दजी ने अपनी दो रचनाएँ भेजी थी जिनमें एक तो हिन्दी में थी और दूसरी उर्दू में। इसके लिए एक साहब ने प्रेमचन्द के बारे में बहुत-सी उल्टी-सीधी बातें लिख डाली थी। उनकी हिन्दीवाली रचना में तो संस्कृत के कई शब्द थे और उर्दूवाली रचना में उससे भी अधिक फारसी के शब्द थे। इसकी आलोचना जिस तरह के लोगो को करनी चाहिए थी, उसी तरह के लोगो ने की थी और कहा था कि 'प्रेमचन्दजी दोहली चालें चलते हैं, दोनों तरफ मिले रहना चाहते हैं और दोनों तरफ से अच्छे बन रहना चाहते हैं।' "

भगर प्रेमचन्द का यह दावा होता कि हिन्दी-उर्दू का बायकाट करके, तुरन्त हिन्दुस्तानी राज्य की जा सकती है, तो शायद इस आलोचना में कुछ तथ्य होता। लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं, प्रेमचन्द हवाई सिद्धान्तवार नहीं थे; वह भ्रमन में तुरन्त एक मिली-जुली भाषा-शैली ईजाद करने की बठिनाइयों को जानते थे। इसलिए हिन्दी और उर्दू दोनों में कुछ हेर-फेर के साथ लिखने की उनकी नीति सही थी; बोलचाल की कौमो जवान हिन्दुस्तानी का समर्थन करना भी ठीक था।

‘प्रेमचन्द-स्मृति अंक’ में श्री मोहम्मद आकिल ने इस तरह की दूसरी घटना का जिक्र किया है। ‘इस सिलसिले में देहली के रिसाले ‘साकी’ ने जो तनवीद की थी कि प्रेमचन्दजी उर्दू के लिए मरहूम हो चुके हैं, उसके बारे में हँसकर कहने लगे कि ‘साकी’ के एडीटर को मैंने लिखा है कि मैं उर्दू के लिए न सिर्फ जिन्दा हूँ बल्कि जमादा जोरो से जी रहा हूँ।’ प्रेमचन्द उन थोड़े से लेखकों में थे जिनमें हिन्दी-उर्दू को लेकर बड़ा-चढ़ी का भाव नहीं था। यह भाव तब पैदा होता है जब लेखक के दिमाग में हिन्दी-उर्दू के पीछे हिन्दुस्तानी कौम नहीं होनी बल्कि हिन्दू धर्म और इस्लाम होता है। प्रेमचन्द ने अपने भ्रमल से दिखलाया कि साहित्य का जातीय रूप समृद्ध करने से, उसमें जनवादी विचारों का समावेश करने से भाषा की समस्या हल करने में मदद मिलती है। प्रेमचन्द के जल्दबाज आलोचक, जो तुरन्त हिन्दुस्तानी राज्य करना चाहते थे, इस दिशा में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर पाए।

प्रेमचन्द ने राष्ट्रभाषा और हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में जो भाषण दिए थे, उनमें एक तरफ तो साम्राज्यवादियों की गुलामी के हर रूप से बेहद नफरत जाहिर होती है दूसरी तरफ हर जगह उनका यह दृढ़ विश्वास भी जाहिर होता है कि हिन्दी और उर्दू एक ही कौम की जवान हैं और इनका एक होना लाजमी है।

प्रेमचन्द को देश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अंग्रेजी भाषा की प्रभुता खलती थी। यह उनकी साम्राज्य-विरोधी राष्ट्रीय चेतना, उनके आत्म-सम्मान की भावना का जबरदस्त सबूत था। किसी ने साम्राज्यवादियों की अंग्रेजी लादने की नीति के खिलाफ, बुद्धिजीवियों में इस नीति के सामने सिर झुकाने की नीति के खिलाफ इतने रोष और तर्कों के साथ बगावत न की थी जैसे प्रेमचन्द ने। सन् ‘३४ में बम्बई के राष्ट्रभाषा-सम्मेलन में उन्होंने पशुओं और मनुष्यों में यह भेद बतलाया कि मनुष्य भाषा इस्तेमाल करते हैं, पशु नहीं करते। “समाज की बुनियाद भाषा है।” इस महत्व की जगह से अंग्रेजी यहाँ की भाषाओं को हटाने की कोशिश करती रही थी। सारे देश के लोग भाषा में जिस भाषा का व्यवहार करें, इस बारे में नेताओं वगैरह की उदासीनता का जिक्र करते हुए उन्होंने इस सम्मेलन में कहा था—‘इस नगरवाही का खास सबब है—अंग्रेजी जवान का बढ़ता हुआ प्रचार और हमारे आत्म-सम्मान की

वह बर्मी, जो गुलामी की शर्म को नहीं महसूस करती।”

किसी भी देश और जाति की उन्नति में वह आत्म सम्मान की भावना जनता में जोश भर देती है, उसे सशक्ति होकर नए-नए मोर्चे फटह करने में बेहद मदद देती है। प्रेमचन्द का स्वामिमान यह देतार तिलमिला उठता था कि गुलाम देश के बुद्धिजीवी अपने मालिकों की भाषा पर अभिमान करते हैं। अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व को उन्होंने साम्राज्यवादी प्रभुत्व का ही घट्ट हिसा बतलाते हुए कहा था—“अंग्रेजी राजनीति का, व्यापार का, साम्राज्यवाद का हमारे ऊपर जैसा आतंक है, उससे बही ज्यादा अंग्रेजी भाषा का है। अंग्रेजी राजनीति से, व्यापार से, साम्राज्यवाद से तो घाय बगावन करते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा को घाय गुलामी के तौक की तरह गर्दन में डालते हुए हैं।”

प्रेमचन्द के इन उचित क्रोध से भरे हुए वाक्यों के सामने कोई दलील कारगर नहीं हो सकती। सवाल है राष्ट्रीय आत्म-सम्मान का। कौन सा देश, जो स्वाधीन है या स्वाधीनता के लिए लड़ रहा है, हमारी तरह दूसरों की ज़बान को अपने राजकाज की ज़बान बनाए हुए है? प्रेमचन्द ने उन लोगों को कड़ी फटकार बताई जो इस गुलामी पर नाज़ करते थे। उन्होंने तमाम अंग्रेजी-मक्नों पर घटो पानी उड़ेलते हुए कहा था—‘अंग्रेजी राज्य की जगह आप स्वराज्य चाहते हैं। उनके व्यापार की जगह अपना व्यापार चाहते हैं, लेकिन अंग्रेजी भाषा का सिक्का हमारे दिलों पर बैठ गया है, उसके बिना हमारा पढ़ा लिखा समाज अनाथ हो जाएगा। पुराने समय में धर्म और धनार्थ का भेद था, आज अंग्रेजीदा और गैर अंग्रेजीदा का भेद है। अंग्रेजीदा धर्म है। उसके हाथ में, अपने स्वामियों की कृपा दृष्टि की बदौलत कुछ भक्तिपार है, रोब है, सम्मान है, गैर-अंग्रेजीदा धनार्थ है और उसका काम केवल धायों की सेवा टहल करना है और उनके भोग-विलास और भोजन के लिए सामग्री जुटाना है।’ प्रेमचन्द ने भारत के अंग्रेजी प्रेमी गायों के लिए ये शब्द अठारह साल पहले कहे थे। उनका महत्व आज भी कम नहीं हुआ।

प्रेमचन्द हिन्दी-उर्दू को एक ज़बान मानते थे। राष्ट्रभाषा सम्मेलन वाले भाषण में उन्होंने हिन्दी-उर्दू का भेद संस्कृत और फारसी शब्दों के प्रयोग पर निर्भर बतलाया था। इस भाषण में उन्होंने हिन्दी की बोलियों के स्वभाव की तरफ़ ध्यान दिलाया था, कि किस तरह वे संस्कृत शब्दों को ज्यों-का-रही नहीं लेती। उन्होंने इस कुतर्क का ज़ोरो से खण्डन किया कि हिन्दी में संस्कृत शब्दों की भरमार करने से वह सभी प्रान्तों के लोगों के लिए आसान हो जाएगी।

हिन्दी-उर्दू की बुनियादी एकता के बारे में प्रेमचन्द कहते हैं—‘हमारे सूबे के देहातो में रहनेवाले मुसलमान प्रायः देहातियों की भाषा ही बोलते हैं। जो बहुत से मुसलमान देहातो से जाकर शहरों में आबाद हो गए हैं वे भी अपने घरों में देहाती ज़बान ही बोलते हैं। बोलचाल की हिन्दी समझने में न तो आधारण मुसलमानों को ही कोई कठिनाई हाती है और न बोलचाल की उर्दू

समझने में साधारण हिन्दुओं को ही। बोनबान की हिंदी और उर्दू प्रायः एक-सी है।”

यहाँ पर प्रेमचन्द ने इस ध्वैज्ञानिक निष्ठावत्ता का गण्डन किया है कि भाषा का साधारण धर्म है और इसलिए हिन्दुओं की भाषा हिन्दी है और मुसलमानों की भाषा उर्दू है। उन्होंने धर्म के नाम पर भाषा और बीम का बंटवारा करने-वाले साम्राज्यवादी और सामन्ती भाषा-वैज्ञानिकों का गण्डन किया और हिन्दुस्तानी जाति की भाषा और संस्कृति के विभाग में बहुत बड़ी मदद की। इस जाति की भाषा की निधि के लिए बहू देवनागरी लिपि के पक्षपाती थे। राष्ट्रभाषा-सम्मेलन में उन्होंने कहा था—“प्रान्तीय भाषाओं को हम प्रान्तीय लिपियों में लिखते जाते, कोई ऐतराज नहीं; लेकिन हिन्दुस्तानी भाषा के लिए हिन्दी लिपि रचना ही सुविधा की बात है, इसलिए नहीं कि हमें हिन्दी लिपि से लाभ मोह है; बल्कि हिन्दी लिपि का प्रचार बहुत ज्यादा है और उसके सीखने में भी किसी को दिक्कत नहीं हो सकती। और जो लोग उर्दू लिपि के प्रादी हैं, उन्हें हिन्दी लिपि का व्यवहार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर उबात एक हो जाय, तो लिपि का भेद कोई महत्व नहीं रखता।”

हिन्दी उर्दू को एक करने, बीम की भाषा और संस्कृति का नया विकास करने की जिम्मेदारी प्रेमचन्द घमनी पीढ़ी पर छोड़ गए थे। उनके बताये हुए रास्ते पर चलकर ही हम उस जिम्मेदारी को पूरा कर सकते हैं। (१६५२)



## उत्तर प्रदेश की सरकार और हिन्दी

१५ अगस्त, १९६५ की 'उत्तर प्रदेश पचायती राज्य' नामक पत्रिका में श्रीमती सुचेता कृपालानी का एक लेख छपा है 'उत्तर प्रदेश और राष्ट्रभाषा।' इसमें उन्होंने हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने के सिलसिले में जो बातें कही हैं, उनका सम्बन्ध राजनीतिज्ञों से अधिक साहित्यकारों से है। भाषा है, हिन्दी लेखक उन पर उचित ध्यान देंगे।

पहले तो उन्होंने यह बताया कि हिन्दी का प्रचार गलत ढंग से किया गया और वह गलत ढंग छोड़ देना चाहिए। फिर उन्होंने बताया कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सही तरीका क्या है।

जिस तरीके से हिन्दी का प्रचार हुआ, उससे अहिन्दी जनता के मन में यह प्रतिक्रिया पैदा हुई—“हम क्यों हिन्दी सीखें?”

“भाषा का प्रचार तलवार से नहीं होता।”

बिल्कुल सही बात है। राज्यसत्ता कांग्रेस के हाथ में है। तलवार का किसी ने प्रयोग किया होगा तो वह कांग्रेसी नेता ही होगा। उत्तर भारत में तमिल के विरोध में या अंग्रेज़ी के विरोध में स्टेशनों, डाकखानों वगैरह पर हमला नहीं हुआ। इस तरह की कार्रवाई तमिलनाडु में हुई। इसे तलवार का प्रयोग कहा जाय या प्रेम-प्रदर्शन, यह कांग्रेसी नेता तय करें। एक बात निश्चित है कि तलवार का प्रयोग हिन्दी जनता या हिन्दी प्रचारकों ने नहीं किया।

हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का सही तरीका उन्होंने यह बताया—

“हिन्दी भाषा को प्रगति पर लाएँ। हिन्दी को उस स्तर पर लाएँ कि हरेक हिन्दी को खुशी से सीखे।”

“अगर भाषा उन्नत हो, भाषा मधुर हो, भाषा सुन्दर हो, भाषा में इतने शब्द हो या भाषा इस स्तर में पहुँची हो कि हमारी हरेक जरूरियात को पूरी कर सके तब लोग आप-से-आप भाषा को सीख लेते हैं।”

“हिन्दी को अगर भारत की भाषा बनाना है, भारत की राष्ट्रभाषा बनाना है, तो हिन्दी-प्रेमी बैठकर खोज करें, अनुसन्धान करें, किताबें लिखें, लोगों को

बैठकर हिन्दी सिखाएँ। ऐसी सुन्दर किताबें लिखी जाएँ, ऐसी भाषा में किताबें लिखी जाएँ कि लोग उसे ग्रहण करने के लिए प्राग्रह करें।"

'हिन्दी को लोगों द्वारा ग्रहण बनाने के लिए तलवार से नहीं बल्कि साहित्य के महत्व से, साहित्य की उच्चता और सुन्दरता से और प्रचार और प्रसार करने के सुन्दर तरीके से यह होगा।'

जहाँ तक भाषा के सुन्दर और मधुर होने का सम्बन्ध है, हिन्दी जैसी है, वैसी है। हर व्यक्ति को अपनी भाषा सबसे ज्यादा मीठी लगती है। यदि वह कहे कि दूसरे की भाषा ज्यादा मीठी है तो समझना चाहिए कि उसके मस्तरों में वहीं कोई दोष है। मिठास के कारण कोई अपनी भाषा के सुकाने दूसरी भाषा को महत्व नहीं देता।

जहाँ तक भाषा में 'हरेक ज़रूरियात' के शब्द होने का सवाल है, हम मानें कि कांग्रेसी सरकार का शिक्षा-मन्त्रालय और उसके विरोध में यह काम करते रहे हैं। यदि हिन्दी अभी तक आवश्यक शब्द इकट्ठे न कर पाई, तो इसमें दोष मुचेताजी की पार्टी के नेताओं का है। लेकिन राजकाज के लिए उन तमाम शब्दों की ज़रूरत नहीं होती जिन्हें गढ़ने या इकट्ठा करने में हम साल में विरोध नग रहे हैं। राजकाज की ज़रूरियात-भर को तो हिन्दी में शब्द हैं, भले ही हरेक ज़रूरियात के लिए न हो।

जहाँ तक साहित्य की उच्चता का सम्बन्ध है, अंग्रेजी बाज़ी उच्च भाषा है। लेकिन भागरा विश्वविद्यालय की बी० एम०-बी० परीक्षाओं में अब से अंग्रेजी ऐच्छिक विषय हो गई है, तब से अंग्रेजी लेनेवाले छात्रों की संख्या लगभग आठवीं सदी कम हो गई है। जो बी० ए० में अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनका हाल मत पूछिये। किताबें पढ़े बिना ही बाज़ार से या प्रोफेसर के विषय हुए नोट पढ़कर पास होना चाहते हैं। जो छात्र एम० ए० में अंग्रेजी पढ़ते हैं, उनमें निन्यानवे की सदी ऐसे होते हैं जो किसी तरह पास होना चाहते हैं या स्वीकृत बनाना चाहते हैं। साहित्य प्रेम से उन्हें कोई वास्ता नहीं है।

अंग्रेजी के अलावा भारत की जो दूसरी मधुर भाषाएँ हैं उनके साहित्य को वे फूटी भाँखी भी नहीं देखते। भागरा और लखनऊ में ऐसी हिन्दी-भाषी छात्र कम मिलेंगे जिन्होंने रवीन्द्रनाथ की रचनाएँ बंगला में पढ़ी हों। कल्पना के बंगलाभाषी युवक सुब्रह्मण्य भारती या बल्लभराय की रचनाएँ बड़े चाव से पढ़ते हों, ऐसा भी मेरे देखने में नहीं आया।

भारत की शिक्षा व्यवस्था नौकरियों से भरी है और नौकरियों की भाषा है अंग्रेजी। इसके लिए मुचेताजी की पार्टी के नेता जिम्मेदार हैं, हिन्दी साहित्य-कार नहीं।

मान लिया कि हिन्दी भाषा सुन्दर नहीं है और उसका साहित्य बर्तन-किस्म का है। भारत की जिन भाषाओं का साहित्य—प्रबुद्धित हुए हिन्दी—अन्य प्रदेशों में बहुतायत से पढ़ा जाता है? अंग्रेजी को भारतीय जीवन में जो

महत्व दिया गया है, उससे समस्त भारतीय भाषाओं के पठन-पाठन में बाधा पड़ती है, हिन्दी के प्रचार-प्रसार में ही नहीं।

मान लिया, हिन्दी-प्रचारको के शलत उत्साह के कारण लोग अहिन्दी प्रान्तों में हिन्दी से नाखुश हो गए। बंगाल में बंगला राजभाषा क्यों नहीं है? वहाँ बंगला के व्यवहार पर किन लोगो ने प्रतिबन्ध लगाया है? तमिलनाडु में तमिल के व्यवहार पर किसने रोक लगाई है?

हिन्दी प्रचारको को दोष देना एवं बहाना है जिससे केन्द्र और प्रान्तों में अंग्रेजी का चलन बना रहे।

खुद उत्तर प्रदेश में राजभाषा हिन्दी का क्या हाल है?

‘राष्ट्रभाषा सन्देश’ (प्रयाग) ने २ सितम्बर, १९६५ के अंक में लिखा है, “वास्तविक स्थिति कम-से-कम उत्तर प्रदेश में यह है कि यहाँ निग्यामवे प्रतिशत से अधिक सरकारी काम अंग्रेजी में किया जाता है।”

उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा हिन्दीभाषी राज्य है। सारे देश में हिन्दी की स्थिति क्या होती है, यह बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में हिन्दी की स्थिति पर निर्भर है।

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपालानी ने हिन्दी भाषा में उच्च साहित्य की आवश्यकता पर जो विचार प्रकट किये हैं, वैसे विचार सन् ३६-४० में कांग्रेसी नेता पहले भी प्रकट किया करते थे। लेकिन वे हिन्दी लिख-पढ़ लेते थे। सुचेताजी ने अपने उपर्युक्त लेख में बताया है कि उन्होंने “मर-मर-कर रोज सुबह एक घंटा लगाकर ‘रामचरितमानस’ पढ़ा। उसमें उन्हें कोई चीज मिली। लेकिन मालूम होता है, लिखने में उन्हें अब भी कठिनाई होती है।

‘मैं हिन्दी लिख नहीं सकती’—श्रीमती सुचेता कृपालानी का यह वाक्य पढ़कर किसे दुःख न होगा? आशा है अगले चुनाव तक वह अपनी यह कठिनाई भी दूर कर लेंगी। तब शायद हिन्दी साहित्यकारों को वह जो उपदेश देंगी, वे और भी मधुर और लाभप्रद होंगे।

(१९६५)

## भारत का भाषा-संकट

श्री मोहनकुमार मगलम ने अंग्रेजी में एक बहुत सुन्दर पुस्तक लिखी है जिसका नाम है—‘भारत का भाषा-संकट’<sup>१</sup>। जो लोग चाहते हैं कि भारत में अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म हो, उन्हें यह पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। उत्तर भारत में लाखों आदमी ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो। वे चाहते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में वहाँ की भाषाएँ राजभाषा के शीर्षमय आसन पर प्रतिष्ठित हो। प्रश्न यह है कि वे राजभाषा क्यों नहीं बन पाती? कौन-सी शक्ति उन्हें अपने उचित आसन पर बैठने से रोकती है?

श्री मोहनकुमार मगलम की पुस्तक के छोटे अध्याय में इस विषय का विवेचन किया गया है कि तमिलनाडु में तमिल अभी तक क्यों राजभाषा नहीं बन पाई। तमिल को सरकारी तौर पर सन् १७७५-७८ में राजभाषा बना दिया गया था किन्तु इसके बाद मद्रास में अंग्रेजी का रुनवा बढ़ा है, कम नहीं हुआ। अधिकांश विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है। कुछ साल पहले अंग्रेजी की शिक्षा छोटे दर्जे में शुरू होती थी, अब वह तीसरे दर्जे से शुरू होती है। शिक्षा-केन्द्रों में अंग्रेजी का प्रभुत्व भटल है। “माता-पिता सोचते हैं कि बेटे को तरक्की करनी है तो बढ़िया अंग्रेजी सीखकर ही वह आगे बढ़ सकता है। इसलिए जिन स्कूलों में शिक्षा का माध्यम तमिल थी, उनमें छात्रों की संख्या लगातार कम होती गई और वे अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा पाने लगे।”

तमिलनाडु की जनता अपने मातृभाषा-प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। उसे अपनी भाषा की प्राचीनता और साहित्य की समृद्धि पर उचित गर्व है। फिर क्या कारण है कि स्कूलों और कॉलेजों में तमिल शिक्षा का माध्यम नहीं हो पाती? इस प्रश्न का उत्तर श्री मोहनकुमार मगलम ने बहुत स्पष्ट शब्दों में दिया है। उन्होंने लिखा है : “ऐसा इसलिए होता है कि सरकार और यूनिवर्सिटी अधिकांश लोगों ने छात्रों के सामने तब यह रखा है—“अंग्रेजी खूब अच्छी तरह सीखो

<sup>१</sup> शिक्षा का संश्लेष आदिशिव • मोहनकुमार मगलम, प्रकाशक न्यू सैम्परी बुक हाउस मद्रास पु० १२२, मु० १ रु० १।

जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर ऊँची नौकरियों के लिए होड़ कर मकी और युनियनसिटी में भी कारगर दम से शिक्षा प्राप्त कर सके।”

हमारे देश में शिक्षा-मस्याएँ नौकरियों में जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजों ने शासन-तन्त्र चलाने के लिए बर्बरक से लेकर कमिश्नर तक के लिए अंग्रेजी की शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। वही स्थिति आज भी है।

श्री मोहनकुमार मगलम ने दो साल पहले दिया हुआ श्री भवनवरसलम का भाषण उद्धृत किया है। इसमें उन्होंने कहा था, “भाता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे सरकारी नौकरियाँ पाएँ। राज्य की नौकरियों के मुकाबले में केन्द्रीय नौकरियाँ ज्यादा आकर्षक होती हैं। इसलिए माता पिता और छात्रों की भी पहली तमन्ना यह होती है कि वे आई० ए० एस० और आई० पी० एम० जैसी केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षा में बैठें।” यही कारण है कि तमिलनाडु में तमिल राजभाषा नहीं बन पाती। उस भाषा की तोर पर राजभाषा बना दिया जाता है लेकिन वास्तविक प्रभुसत्ता रहती है अंग्रेजी के हाथ में। श्री मोहनकुमार मगलम के शब्दों में—“अंग्रेजी की शिक्षा पाये बिना किसी भी तमिलभाषी के लिए केन्द्रीय नौकरी पान का सवाल नहीं उठता।”

कांग्रेसी नेताओं ने केन्द्र में अंग्रेजी का प्रभुत्व कायम रखकर राज्यों में वहाँ की भाषाओं को पददलित कर दिया है। तमिल जैसी प्राचीन और सम्पन्न भाषा अंग्रेजी की दासी बनी हुई है। मद्रास में तमिल राजभाषा नहीं बन पाई, इसका कारण यह नहीं है कि हिन्दी उसका दमन कर रही है, इसका कारण यह है कि कांग्रेसी नेताओं ने साम्राज्यवादियों की चन्पाई हुई—शासन-तन्त्र और शिक्षा के बारे में अंग्रेजी के व्यवहार की—नीति को बरकरार रखा है। इस नीति के लिए केवल हिन्दी क्षेत्र के नेता जिम्मेदार नहीं हैं—यद्यपि उन्हें ज्यादा शर्म आनी चाहिए क्योंकि वे हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का दावा भी करते हैं—अहिन्दी क्षेत्रों के नेता भी उतने ही जिम्मेदार हैं।

भारतीय भाषाओं में मुख्य अन्तर्विरोध हिन्दी अहिन्दी का नहीं है, मुख्य अन्तर्विरोध अंग्रेजी और सभस्त भारतीय भाषाओं का है। राज्यों में अंग्रेजी के प्रभुत्व का कारण है—केन्द्रीय सेवाओं में उसका व्यवहार।

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब तक केन्द्रीय सेवाओं में अंग्रेजी न हटेगी, तब तक तमिल भी मद्रास में ब्यावहारिक रूप में राजभाषा न बनेगी। इसलिए समाधान ऐसा होना चाहिए जिससे केन्द्रीय सेवाओं में अंग्रेजी का चलन खत्म हो।

श्री मोहनकुमार मगलम ने कांग्रेस के पुराने प्रस्ताव का हवाला देते हुए सभी भारतीय भाषाओं को अखिल भारतीय परीक्षाओं का माध्यम बनाने की बात कही है। उनका सुझाव सही है। कमी इतनी है कि उन्होंने केन्द्रीय सेवाओं में केवल परीक्षाओं के लिए भारतीय भाषाओं के ऐच्छिक माध्यम होने का सवाल उठाया है। जब मद्रास के छात्र तमिल में परीक्षा देकर अफसर बनेंगे,

तब वे अंग्रेजी का व्यवहार करेंगे, या भारतीय भाषाओं का—इन प्रश्न पर उन्होंने विचार नहीं किया। अखिल भारतीय सेवाओं का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगी—इसलिए सफ्ट ज्यों-का त्यों बना रहता है। परीक्षा भाषा चाहे जिसमें दे लें, काम अंग्रेजी में ही करना पड़ेगा।

श्री मोहनकुमार मगलम ने तीन भाषाओं वाले फार्मूले का समर्थन किया है। इस फार्मूल में अंग्रेजी का स्थान सुरक्षित है। अंग्रेजी का स्थान सुरक्षित रखकर अंग्रेजी का प्रभुत्व नहीं खरम किया जा सकता। फलतः तमिलनाडु में भी तमिल को राजभाषा और उच्च शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता।

अंग्रेजी की शिक्षा बंकरूप हो—यह माँग करनी चाहिए। किसी भी स्वाधीन देश के विद्यालयों में किसी विशेष विदेशी भाषा का अध्ययन सभी छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं होता। केन्द्र में अंग्रेजी का प्रभुत्व खत्म करना चाहिए। उसकी जगह हिन्दी चले या अनेक भारतीय भाषाओं का व्यवहार हो—श्री मोहनकुमार मगलम जो फंसला करेंगे, मैं उसका समर्थन करूँगा। लेकिन केन्द्र में अंग्रेजी चलाते रहने से भारत का भाषा-संकट हल न होगा, उल्टे वह और गहरा होगा और इससे तमिल की उतनी ही हानि होगी जितनी हिन्दी की।

भारतीय भाषाओं को प्रदेशों में राजभाषा का पद न दिया जाय—इसके लिए अंग्रेजी प्रेमी विद्वान तर्क देते हैं कि वे भाषाएँ पिछड़ी हुई हैं। यद्यपि किसी ने भारतीय भाषाओं में एक भाषा लेकर वैज्ञानिक परीक्षा करके यह नहीं दिखाया कि पिछड़ापन किस बात में है—फिर भी यह सर्वमान्य सत्य बन गया है कि अंग्रेजी के मुकाबले में भारतीय भाषाएँ ग्राम तोर से—और हिन्दी खास तोर से—पिछड़ी हुई हैं।

तमिल विकसित भाषा है या नहीं? उसमें मद्रास राज्य का सरकारी काम हो सकता है या नहीं? उसमें उच्च शिक्षा दी जा सकती है या नहीं?

श्री मोहनकुमार मगलम ने इन प्रश्नों के परस्पर-विरोधी उत्तर दिये हैं। उनकी समझ में भारत के भाषा संकट का मुख्य कारण यह है कि सरकारी परवरिश के कारण हिन्दी को विकसित होने का मौका मिला लेकिन अहिन्दी भाषाएँ अविकसित रह गईं। इसलिए समस्या का समाधान यह है कि पहले इन भाषाओं को राजभाषा बना दिया जाय, उन्हें विकसित होन दिया जाय, इनके बाद ही केन्द्र से अंग्रेजी हटाने का सवाल उठेगा।

उन्होंने लिखा है, 'हमें यह न भूलना चाहिए कि अपनी प्राचीनता, अपनी देन, अपने उत्कृष्ट साहित्य आदि गुणों के बावजूद वे किसी भी समय, बहुत से बहुत, एक संकुचित गुट के विचारों का बाहन ही रही हैं।'

इसका अर्थ है कि वर्तमान सम्य समाज की शिक्षा-संस्कृति राजनीति का माध्यम बनने के योग्य नहीं हैं।

उनके विचार से अंग्रेजी के आने से पहले भारत की संस्कृति प्राचीन होते

हुए भी गतिरुद्ध (स्टैगनेन्ट कल्चर ऑफ इंडिया) हो चुकी थी। अंग्रेजी के प्रभुत्व से भारतीय भाषाओं की प्रगति रुक गई थी, “अर्थात् आधुनिक भाषाओं के रूप में, आधुनिक विचारों को प्रकट करनेवाले माध्यम के रूप में विकसित होने से रोका गया।”

मैं नहीं जानता कि वे आधुनिक विचार कौन से हैं जो तमिल या हिन्दी के माध्यम से प्रकट नहीं किए जा सकते। इतना जरूर कह सकता हूँ कि आदरणीय बन्धु मोहनकुमार मगलम ने जो विचार इस पुस्तक में प्रकट किये हैं, वे किसी भी भारतीय भाषा में बखूबी प्रकट किए जा सकते हैं।

कुमारमगलमजी ने यह मत भी बड़ी स्पष्टता से प्रकट किया है कि भारतीय भाषाएँ सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप पूर्णतः विकसित हैं। उन्होंने पुस्तक के पृष्ठ ४० पर लिखा है—

“हकीकत यह है कि (आठवीं अनुसूची में उल्लिखित) सभी भाषाएँ विकसित भाषाएँ हैं। इन्हें करोड़ों आदमी बोलते हैं और मानते हैं कि उच्च शिक्षा का माध्यम बनने के लिए वे पूरी तरह विकसित हैं।”

यदि भारतीय भाषाएँ विकसित हैं तो भाषा-संकट इसलिए नहीं पैदा हो गया कि सरकार ने हिन्दी को ज्यादा विकसित कर दिया है और तमिल पीछे रह गई है। भाषाएँ अविकसित हैं—यह एक बहाना है जो हिन्दी और तमिल, सभी भारतीय भाषाओं के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। संकट का असली कारण है केन्द्र में अंग्रेजी का प्रभुत्व। इसी प्रभुत्व के कारण तमिल अपने प्रदेश में राजभाषा नहीं बनी, इसी कारण वह शिक्षा का माध्यम नहीं बनी। जो भी केन्द्र में अंग्रेजी कायम रखकर राज्यों से अंग्रेजी हटाने का सपना देखता है, वह अपने को और दूसरों को धोखा देता है। जब तक केन्द्रीय संघातों में अंग्रेजी का चलन रहेगा, तब तक मद्रास का विद्यार्थी कभी अंग्रेजी छोड़ने को राजी न होगा।

श्री मोहन कुमारमगलम कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। श्रमिक जनता के आन्दोलन से उनका गहरा सम्बन्ध रहा है। उनसे हम आशा कर सकते हैं कि वे मजदूर वर्ग की एकता और भाषा समस्या पर भी कुछ कहेंगे। लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा।

अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरों के संगठन की भाषा अंग्रेजी क्यों है? अखिल भारतीय विज्ञान-सभा के केन्द्रीय दफ्तर की कार्यवाही अंग्रेजी में क्यों होती है (या होती थी)? कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सम्पर्क भाषा के रूप में अंग्रेजी का व्यवहार क्यों करते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय दफ्तर में अंग्रेजी का व्यवहार क्यों होता है? पार्टी और जन-संगठनों में अंग्रेजी के इस प्रभुत्व से हानि होती है या लाभ? श्री मोहनकुमार मगलम ने ऐसा एक भी सवाल अपनी पुस्तक में नहीं उठाया। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है।

इस देश में जब अंग्रेज आए, तब यहाँ के राजा और नवाब, मिलकर उनसे लड़ने के बजाय, आपस में लड़ते रहे। आपस में लड़ने के लिए वे बारी-बारी

से अंग्रेजों की मदद लेते रहे और अंग्रेज बारी-बारी से उन्हें खत्म करके उनका राज्य हड़पते रहे ।

वर्तमान काल में जातीय विद्वेष और स बढ़ा है । गोष्ठा को लेकर मैसूर के मुख्यमन्त्री ने जितनी सरगर्मी महाराष्ट्र के विरुद्ध दिखाई है, उतनी सरगर्मी पुर्तगाल के खिलाफ न दिखाई थी । भाषा की समस्या जातीय समस्या का अंग है । भारतीय भाषाओं के हिमायती भाषण में लड़ते हैं और अंग्रेजी की जय बोलते हैं । जातीय विद्वेष का एक रूप भाषागत विद्वेष है । इस तरह का द्वेष पूँजीपतियों के लिए स्वाभाविक है, पूँजीवादी विचारधारा से प्रभावित मध्यवर्ग श्रेणियों के बुद्धिजीवियों के लिए यह विद्वेष बहुत कुछ मुखकर और जीवन की मुख्य प्रेरणा है । केवल मजदूर वर्ग में यह क्षमता है कि वह इस विद्वेष से ऊपर उठकर अन्तर्जातीय भाईचारे के माध्यम पर राष्ट्रीय एकता दृढ़ करे । इसीलिए अंग्रेजी और मजदूर वर्ग की अखिल भारतीय एकता का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है ।

भाषा सक्क कबो पैदा हुआ, मद्रास में अंग्रेजी कबो कायम रहती है, सविधान के निर्माताओं की कितनी गलतियों से प्रादेशिक भाषाभाषा का चलन न हुआ, यह समस्त सूक्ष्म विस्लेषण, कम्युनिस्ट पार्टी के अन्दर अंग्रेजी के व्यवहार पर नजर डालते ही, चकीलो की जिरह की तरह कानूनी तौर पर सही परन्तु न्याय के प्रतिकूल मालूम होने लगता है । भला भाषाओं के विकास में 'इम्बैलेन्स' पैदा हो जाने से कम्युनिस्ट पार्टी में अंग्रेजी का चलन कबो हो ?

भारतीय जनतन्त्र को चलाने के लिए आसमान से फरिश्ते नहीं आते । वर्तमान युग में जनतन्त्र को चलानी हैं पार्टियाँ और पार्टियों के नेता । जब तक देश की राजनीतिक पार्टियाँ अपना अखिल भारतीय काम अंग्रेजी में करती हैं, तब तक न तो वे देश की भाषा समस्या हल कर सकती हैं, न दरअसल उन्हें इस समस्या पर बोलने का नैतिक अधिकार है ।

श्री मोहनकुमार मगलम ने लिखा है कि हर नागरिक का यह अधिकार होना चाहिए कि वह लोकसभा में अपनी मातृभाषा में बोल सके ।

मैं इस माँग का समर्थन करता हूँ । हमारे साथी बोलें जो भारतीय भाषाभाषा में । फिर देखें, हिन्दी और अहिन्दी भाषियों का कैंसा जवर्दस्त अंग्रेजी विरोधी मोर्चा बनता है । लेकिन वे खुद बोलेंगे अंग्रेजी में, दूसरा के लिए मातृभाषा में बोलने का अधिकार माँगेंगे । इस तरह सात जन्म में अंग्रेजी का प्रभुत्व दूर न होगा ।

लोकसभा में भारतीय भाषाओं का व्यवहार कीजिए । जन-संगठनों का अखिल भारतीय काम देशी भाषाओं में कीजिए । अपने केन्द्रीय दफ्तर स अंग्रेजी निकालिए । भारत का भाषा सक्क हल करने का यही नारंगर तरीका है ।





